रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED NO. D. 222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1973/चैत्र 3, 1895
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1973/CHAITRA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1973

का. आ. 851.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 की धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा निम्नलिखित आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्त आरक्षण सं. 2) नियम, 1971 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्त आरक्षण (सं. 2) संशोधन नियम कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम 29 जनवरी, 1971 को लागू हुए समझे जायेंगे ।

2. निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्त आरक्षण (सं. 2) नियम, 1971 के नियम 4 के उप-नियम (1) में "जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 को अथवा इसके बाद, किन्तु 10 जनवरी, 1968 के पहले कमीशन दिया गया था" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 को अथवा उसके बाद, किन्तु 10 जनवरी, 1968 के पहले कमीशन दिया गया था अथवा जो बाद की तारीख से पहले किसी कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए थे, लेकिन उन्हें उक्त तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन दिया गया था" ।

[सं. 9/4/72-स्थापना (ग)]

जे. एस. आहलूवालिया, अवर सचिव

निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्त आरक्षण (सं. 2) संशोधन नियम, 1972 का व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्त आरक्षण नियम, 1971 के नियम 4 के अनुसार जिसे निर्मुक्त आपात्कालीन तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्त आरक्षण (सं. 2) नियम 1971 द्वारा पुनरीक्षित किया गया है, निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों को इन

नियमों के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर प्रतियोगिता करने की पात्रता केवल ऐसे आपात्कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों तक ही सीमित है जिन्हें सशस्त्र सेनाओं में 1 नवम्बर, 1962 को, अथवा उसके बाद, किन्तु 10 जनवरी, 1968 के पूर्व कमीशन दिया गया था। प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी भी उक्त आरक्षित रिक्तियों में प्रतियोगिता करने के पात्र होने चाहिएं जो आपात स्थिति समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, किन्तु जिन्हें सशस्त्र सेनाओं में वास्तव में 10 जनवरी, 1968 (अर्थात् पहली आपात स्थिति रद्द करने की तारीख) के बाद कमीशन प्राप्त हुआ था।

जब 1971 में पहली बार इन वर्गों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से संबंधित नियम जारी किए गए थे तब उनमें ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी कि आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए केवल वे अधिकारी ही पात्र हो सकेंगे जिन्हें 10 जनवरी 1968 के पूर्व कमीशन दिया गया था। यह शर्त निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्त आरक्षण (सं. 2) नियम, 1971 में इस दृष्टि से उपबंधित की गई थी जिससे आरक्षित रिक्तियां केवल उन अधिकारियों के लिए ही रखी जा सकें जिन्होंने आपात्काल में सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश करने के कारण सिविल सेवा में प्रवेश होने के अवसर खो दिए थे। जैसाकि उपर्युक्त नियमों के नियम 5 से ज्ञात किया जा सकता है, आरक्षित रिक्तियों में प्रतियोगिता करने के लिए पात्रता के संबंध में आयु तथा शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण आयोग-पूर्वप्रशिक्षण में जाने के समय अथवा कमीशन दिए जाने के समय, जबकि वहां केवल आयोग पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, की स्थिति के आधार पर किया गया था। इसी प्रकार नियम 6(1) से यह ज्ञात किया जा सकता है कि जब निर्मुक्त अधिकारी आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए जाते हैं तो उनका प्रशिक्षण का समय भी वरिष्ठता तथा वेतन निर्धारित करने के लिए गिना जाता है। इस प्रकार आयोगपूर्व प्रशिक्षण को सभी दृष्टियों तथा प्रयोजन के लिए नियमित सेवा के समान ही समझा गया है और "अवसर खो देना" की धारणा को भी आयोग-पूर्व प्रशिक्षण में, जहां ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना निर्धारित किया गया है, सम्मिलित होने की तारीख से संबद्ध किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को युक्तिसंगत विस्तार दिए जाने के कारण, संशोधित अधिसूचना को 29 जनवरी, 1971 अर्थात् निर्मुक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्ति आरक्षण (सं. 2) नियम, 1971 लागू होने की तारीख से लागू करने के लिए जारी करना आवश्यक हो गया है। उक्त नियम को पिछली तारीख से लागू करने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 24th February, 1973

S.O. 851.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) Rules, 1971, *namely:*—

1. (1) These rules may be called the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of vacancies (No. II) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 29th January, 1971.

2. In sub-rule (1) of rule 4 of the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) Rules, 1971, for the words and figures "who were commissioned on or after the 1st November, 1962, but before the 10th January, 1968", the following shall be substituted, namely:—

"who were commissioned on or after the 1st November, 1962, but before the 10th January, 1968, or who had joined any pre-commission training before the latter date, but who were commissioned on or after that date".

[No. 9/4/72-Ests(C)]

J. S. AHLUWALIA, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE RELEASED EMERGENCY COMMISSIONED OFFICERS AND SHORT SERVICE COMMISSIONED OFFICERS (ENGINEERING AND MEDICAL SERVICE) RESERVATION OF VACANCIES (NO. II) AMENDMENT RULES, 1972.

According to rule 4 of the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies Rules, 1971, as revised by the RECO's and SSCO's (Engineering and Medical Service) Reservation of Vacancies (No. II) Rules, 1971, the eligibility of the released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers for competing against vacancies reserved under these rules is restricted to those Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces on or after the 1st November, 1962, but before the 10th January, 1968. The question arises whether even those Short Service Commissioned Officers who were undergoing training before the revocation of the emergency but were actually commissioned in the armed forces after 10th January, 1968 (i.e. the date of revocation of the first emergency) should also be eligible to compete for the reserved vacancies.

When the rules relating to reservation vacancies for those categories of officers were first issued in 1971 no stipulation was made that only those who were commissioned before 10th January, 1968 would be eligible for appointment against reserved vacancies. This condition was introduced in the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) Rules, 1971 as the intention was to provide these reserved vacancies only to those who had missed chances of entering the civil service as a result of joining the armed forces during the emergency. As could be seen from rule 5 of the aforesaid rules, the eligibility with reference to age and educational qualification for competing for reserved vacancies is determined on the position at the time of joining the pre-Commission training or at the time of getting of Commission where there is only post-Commission training. Similarly, it could be seen from rule 6(1) that the period of training also counts for the purpose of seniority and pay fixation when Released Officers are appointed against reserved vacancies. Thus the pre-Commission training has been equated for all intents and purposes with regular service and the concept of 'missed opportunities' should also be related to the date of joining the pre-Commission training where such a training has been prescribed. As a logical extension of this principle, it has become necessary to issue the amending notification, to give effect to the rules with effect from 29th January, 1971, namely the date when the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) Rules, 1971, took effect. The interests of no one will be adversely affected by giving retrospective effect to the rule.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1973

का.आ. 852.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 को हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 83 कोटपाड़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कामराज माझी, ग्राम अम्बोगाम, डा. चन्दीली द्वारा कोटपाड़, जिला कोरापुट, उड़ीसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कामराज माझी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. उड़ीसा-वि.स./83/71]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th February, 1973

S.O. 852.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kama Raj Majhi, Village Ambogam, P.O. Candili, Via Kotpad, District Koraput, Orissa State, a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from 83-Kotpad Assembly Constituency, held in March, 1971, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Reperesentation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kama Raj Majhi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. OR-LA/83/71]

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1973

का. आ. 853.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 को हुए त्रिपुरा विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 18-विशालगढ़ सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कामीनी कुमार साहा, ग्राम रघुनाथपुर, विशालगढ़ वैस्ट त्रिपुरा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कामीनी कुमार साहा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[त्रिपुरा-वि.स./18/72(2).]

ORDER

New Delhi, the 13th February, 1973

S.O. 853.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kamini Kumar Saha, Village Raghunathpur, Bishalgarh, West Tripura, a contesting candidate for election to the Tripura Legislative Assembly from 18-Bishalgarh assembly constitunecy, held in March, 1972, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kamini Kumar Saha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TP/LA/18/72(2)]

आदेश

का. आ. 854.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया कि मार्च, 1972 को हुए त्रिपुरा विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 18-विशालगढ़ सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्राण बल्लव भौमिक, ग्राम जंगालिया, पो. विशालगढ़, वैस्ट त्रिपुरा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्राण बल्लव भौमिक को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[त्रिपुरा-वि.स./18/72(3).]

ORDER

S.O. 854.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pran Ballav Bhowmik, Village Jangalia, P.O. Bishalgarh, West Tripura, a contesting candidate for election to the Tripura Legislative Assembly from 18-Bishalgarh assembly constituency, held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pran Ballav Bhowmik to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TP/LA/18/72(3)]

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1973

का. आ. 855.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 को हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 82 जेयपोर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार डा. आनन्द चन्द्र मोहन्ती नुआ साही, मुकाम तथा पोस्ट जेयपोर, जिला कोरापुट, उड़ीसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त डा. आनन्द चन्द्र मोहन्ती को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. उड़ीसा-वि.स./82/71]

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1973

S.O. 855.—Whereas the Election Commission is satisfied that Dr. Anand Chandra Mohanty, Nua Sahi, At/P.O. Jeypore, District Koraput, Orissa, a contesting candidate for general election to the Orissa Legislative Assembly from 82-Jeypore Assembly Constituency, held in March, 1971, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Dr. Anand Chandra Mohanty to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/82/71]

आदेश

का. आ. 856.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 179 धनियाखाली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोकुलचन्द्र माजी, ग्राम घनश्यामपुर, पो. आ. कानानदी, पी. एस. धनियाखाली, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गोकुल चन्द्र माजी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प.बं.-वि.स./179/71(35)]

ORDER

S.O. 856.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gokul Chandra Maji, Village Ghanashyampur, P.O. Kanandi, P.S. Dhaniakhali, District Hooghly, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 179-Dhaniakhali constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gokul Chandra Maji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/179/71(35)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1973

का.आ. 857.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 78 बगदाहा (अजा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सासाधर बिस्वास, ग्राम प्रतापगढ़, पो. आ. बोंगांव, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सासाधर बिस्वास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प.बं./78/71(36)]

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1973

S.O. 857.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sasadhar Biswas, Village Protapgarh, P.O. Bongaon, District 24-Parganas, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal, Legislative Assembly from 78-Bagdaha (SC) constituency, held in March, 1971, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sasadhar Biswas to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/78/71(36)]

आदेश

का.आ. 858.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 96 कुलटाली (अजा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भारतचन्द्र हलदर, ग्राम पश्चिम जाटा, पो. आ. कंकनडीघी, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भारत चन्द्र हलदर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प.बं.-वि.स./96/71 (37)]

ORDER

S.O. 858.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bharat Chandra Halder, Village Paschim Jata, P.O. Kankandighi, District 24-Parganas, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 96-Kultali (SC) constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Repersentation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bharat Chandra Halder to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/96/71(37)]

आदेश

का.आ. 859.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 233 रानीबंध (अजजा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हेमब्रम नबीन चन्द्र, ग्राम काशीडी, पो. आ. खतरा, जिला बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हेमब्रम नबीन चन्द्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प.बं.-वि.स./233/71(38)]

ORDER

S.O. 859.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hembram Nabin Chandra, Village Kashidi, P.O. Khatra, District Bankura, West Bengal, a contesting candidate for election the West Bengal Legislative

Assembly from 233-Ranibandh (ST) constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hembram Nabin Chandra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of his order.

[No. WB-LA/233/71(38)]

आदेश

का.आ. 860.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 233 रानीबंध निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सारेन रायचरन, ग्राम रंगासोल, पो. आ. पैंरागुड़ी, जिला बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सारेन रायचरन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प.बं.-वि.स./233/71(39)]

ORDER

S.O. 860.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Saren Raicharan, Village Rangasol, P.O. Pairaguri, District Bankura, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 233-Ranibandh constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Repersentation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Saren Raicharan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/233/71(39)]

आदेश

का.आ. 861.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 262 कालना निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सारेन मधु, ग्राम चाग्राम खानपुर, पो. आ. ग्राम चाग्राम, वाया पाण्डुआ, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सारेन मधु को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प. बं.-वि. स./262/72(40)]

ORDER

S.O. 861.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Saren Madhu, Village Chagram Khanpur, P.O. Gram Chagram, Via Pandua, District Burdwan, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 262-Kalna constituency, held in March, 1972, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Saren Madhu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/262/72(40)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1973

का.आ. 862.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 को हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 110 बिंका निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ईश्वर चन्द्र पाणिग्रही, मु. बरदुली, पो. आ. बिसिमुण्डी, जिला बोलांगीर, उड़ीसा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ईश्वर चन्द्र पाणिग्रही को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. उड़ीसा-वि.स./101/71(1)]

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1973

S.O. 862.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Iswar Chandra Panigarhi, At-Bagduli, P.O. Bisimunda, District Bolangir, Orissa, a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from 101-Binka assembly constituency, held in March, 1971, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even under due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Iswar Chandra Panigrahi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/101/71(1)]

आदेश

का.आ. 863—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 110 बिंका निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भिकारी चरन मिश्र, मु. बाडगढ, पो. आ. बाडगढ, जिला सम्बलपुर (उड़ीसा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भिकारी चरन मिश्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. उड़ीसा-वि.स./101/71(2)]

ORDER

S.O. 863.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhikari Charan Mishra, At-Bargarh, P.O. Bargarh, District Sambalpur (Orissa), a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from 101-Binka assembly constituency, held in March, 1971, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhikari Charan Mishra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/101/71(2)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1973

का. आ. 864.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 261 मीमारी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जीतु मुरमु, ग्राम व पो. आ. जेमुई, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जीतु मुरमु को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प.बं.-वि.स./261/72(41)]

ORDER

New Delhi, the 21st February, 1973

S. O. 864.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jitu Murmu, Village and P.O. Jabui, District Burdwan, West Benagl, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 261-Memari constituency, held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jitu Murmu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/261/72(41)]

आदेश

का.आ. 865.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 252 फरीदपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मनोरंजन बोस, ग्राम कमलपुर, पो॰ आ. अमराई, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मनोरंजन बोस को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प.बं.-वि.स./252/72(42)]

ए. एन. सेन, सचिव

ORDER

S.O. 865.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Monoranjan Bose, Village Kamalpur, P.O. Amrai, District Burdwan, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 252-Faridpur constituency, held in March, 1972, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Monoranjan Bose to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/252/72(42)]

A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1973

का. आ. 866.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 को हुए गुजरात विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 26-जामजोधपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जादेजा बलवंतसंग भीम्भा, वल्लभ भाई पटेल रोड, जामजोधपुर, जिला जामनगर, गुजरात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जावेदा बलवंतसंग भीम्भा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. गुजरात-वि.स./26/72(4).]

बी. एन. भारद्वाज, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th February, 1973

S.O. 866.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jadeja Balvantsang Bhimbha, Vallabhbhai Patel Road, Jamjodhpur, District Jamnagar, Gujarat, a contesting candidate for the election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 26-Jamjodhpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candiate even after the due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jadeja Balvantsang Bhimbha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/26/72(4)]

B. N. BHARDWAJ, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1973

का. आ. 867.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए 42 नवादा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरेश कुमार भटट, निवासी स्टेशन रोड, पो. आ. नवादा, जिला गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियम द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुरेश कुमार भटट को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. बिहार-लो.स./42/71(4)]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th February, 1973

S.O. 867.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Suresh Kumar Bhatta, R/o Station Road, P.O. Nawadah, District Gaya (Bihar), a contesting candidate for election to House of the People from 42-Nawada parliamentary constituency (Bihar), held in March, 1971, has

failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidate, even after the due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, Therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Suresh Kumar Bhatta to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/42/71(4)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1972

आयकर

का. आ. 868.—(आई टी सी सी) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार :

श्री वी. के. बत्रा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

[सं. 248(फा. सं. 404/235/72-आई टी सी सी)]

एम. एन. नम्बियार, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 28th December, 1972

INCOME TAX

S.O. 868.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises :

Shri V. K. Batra, who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[No. 248 (F. No. 404/235/72-ITCC)]

A. K. NASTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1973

आयकर

का.आ. 869.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री टी. जी. लालवानी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

2. अधिसूचना सं. 161 (फा.सं. 404/232/72-आई टी सी सी) तारीख 21 अगस्त, 1972 द्वारा की गई श्री एम. वी. सुब्रमणियम की नियुक्ति तुरन्त रद्द की जाती है ।

3. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

[सं. 275 (फा.सं. 404/15/73-आई टी सी सी)]

New Delhi, the 29th January, 1973

INCOME TAX

S.O. 869.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of the Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises :

Shri T. G. Lalwani, who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri M. V. Subramanian under Notification No. 161 (F. No. 404/232/72-ITCC), dated 21st August 1972 is cancelled with immediate effect.

3. This Notification shall come into force with immediate effect.

[No. 275 (F. No. 404/15/73-ITCC)]

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1973

का. आ. 870.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री जी. एस. दत्ता चौधरी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1973 से प्रवृत्त होगी ।

[सं. 277 (फा. सं. 404/364/72-आई टी सी सी)]

New Delhi, the 30th January, 1973

S.O. 870.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises:—

Shri G. S. Dutta Choudhury who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from 1st February, 1973.

[No. 277 (F. No. 404/364/72-ITCC]

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1973

का. आ. 871.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री ई. सरोज को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

[सं. 292(फा. सं. 404/32/73-आई टी सी सी)]

एम. एन. नम्बियार, अवर सचिव

New Delhi, the 12th February, 1973

S.O. 871.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44 of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri E. Saroj who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with immediate effect.

[No. 292(F. No. 404/32/73-ITCC)]

M. N. NAMBIAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1973

आयकर

का. आ. 872.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री राम देव प्रसाद को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना 7 फरवरी, 1973 को प्रवृत्त होगी ।

[सं. 289(फा. सं. 404/2/73-आई टी सी)]

एस. बापू, अवर सचिव

New Delhi, the 7th February, 1973

INCOME TAX

S.O. 872.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises:—

Shri Ram Deo Prasad, who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 7th February, 1973.

[No. 289 (F. No. 404/2/73-ITCC)]

S. BAPU, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1973

आयकर

का. आ. 873.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री थीरूवातीश्वर मन्दिर त्रिपलिकेन, मद्रास-5, को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ऐतिहासिक, पुरातत्वीय महत्व का और सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य में ख्याति प्राप्त लोकपूजा का स्थान एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

[सं. 291/फा. सं. 176/94/72-आई टी. (ए.1)]

वी. बी. श्री निवासन, अवर सचिव

New Delhi, the 8th February, 1973

INCOME TAX

S.O. 873.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Sri Thiruvateeswar Temple, Triplicane, Madras-5, to be of historic, archaeological importance and to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said section.

[No. 291/F. No. 176/94/72-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Under Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th March, 1973

S.O. 874.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 3740, dated the 5th October, 1972 (relating to making of higher denomination Standard Gold Bars of Hutti Gold), published at page 5243 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th November, 1972,

(1) in the first paragraph, **for** "primary gold bars of 99.50 per mille fineness, **read** "primary gold bars of 995.0 per mille fineness"; and

(2) in clause (ii) of paragraph 2, **for** "changed at the beginning of each year calendar year", **read** "changed at the beginning of each calendar year".

[No. F. 141/10/72-GC. II]

M. A. RANGASWAMY, Gold Control Administrator and Jt. Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1973

सीमाशुल्क

का. आ. 875.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की आरा 7 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 129/72-सी.शु., तारीख 9 दिसम्बर, 1972 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, तिरूचिरापल्ली एयरपोर्ट को,

(1) श्रीलंका में बने माल और यात्रियों के सामान को उतारने के लिए, और

(2) भारत में बने माल (हीरों, बहुमूल्य रत्नों और अर्ध-बहुमूल्य रत्नों के सिवाय) और यात्रियों के सामान को चढ़ाने के लिए, सीमाशुल्क एयरपोर्ट के रूप में एतद्द्वारा नियत करती है ।

[सं. 41/73-सी.शु./फा.सं. 4/11/70-सी.शु. 7.]

New Delhi, the 24th March, 1973

CUSTOMS

S.O. 875.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 129/72-Customs, dated the 9th December, 1972, the Central Government hereby appoints the airport at **Trichirapalli** as Customs airport for (i) the unloading of goods of Sri Lanka origin and baggage; and, (ii) the loading of goods of Indian Origin (except diamonds, precious stones and semi-precious stones) and baggage.

[No. 41/73-Customs/F. No. 4/11/70-Cus. VII]

आदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1973

स्टाम्प

का. आ. 876.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस शुल्क से, जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले बयासी लाख पचास हजार रुपये के अंकित मूल्य के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्राभार्य है, एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं. 13/73-स्टाम्प/फा. सं. 471/1/73-सी. शुल्क 7]

के. शंकररामन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th March, 1973

STAMPS

S.O. 876.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds to the face value of Eighty two lakhs fifty thousand of rupees, to be issued by the Jammu and Kashmir State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 13/73-Stamps/F. No. 471/1/73-Cus. VII]

K. SANKARARAMAN, Under Secy

बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1973

30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के काम काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट

का० आ० 877.—भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के काम काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है।

1. अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां

जुलाई, 1971 से जून, 1972 तक की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि देश के व्यय में अप्रत्याक्षीत रूप से भारी मात्रा में वृद्धि होने के बावजूद उसमें लचीलापन पाया गया। मुख्य रूप से पूर्वी सीमा पार कर भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन और दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण देश के व्यय में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि, अधिक सामाजिक न्याय और बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता के विभिन्न योजनागत लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य के साथ बनायी गयी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की नीतियों का जारी रहना भी उक्त व्यय-वृद्धि का आंशिक कारण था। देश के व्यय में हुई तमाम वृद्धि के अनुरूप औद्योगिक और कृषि उत्पादनों में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि की जो मांग थी उसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई और व्यापार क्षेत्रों में अधिकतर मात्रा में घाटा हुआ। व्यापार क्षेत्र के उक्त घाटे के लिए पहले से ही उपलब्ध विदेशी सहायता का अधिक मात्रा में उपयोग कर वित्तीय व्यवस्था की गयी; उसके लिए प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधि में से कोई राशि निकाली नहीं गयी। किन्तु देशी मूल्यों में वृद्धि रोकी नहीं जा सकी, केवल उसे कम और विलंबित किया जा सका। कटाई के पहले की अवधि में सरकार के अनाज-भण्डार से अधिक मात्रा में अनाजों के निकाले जाने से अंशतः यह संभव हुआ। किन्तु इस संदर्भ में राजकोषीय और मुद्रागत क्षेत्रों में किये गये प्रयत्न प्रमुख थे जिनसे गैर सरकारी क्षेत्र के व्यय को संयमित किया जा सके जब सरकारी व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही थी। सितम्बर, 1971 और मार्च, 1972 के बीच मूल्यों में बहुत ही मामूली वृद्धि हुई। यह नियमित मौसमी स्वरूप की द्योतक थी। किन्तु उसके बाद प्रत्याशा की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई जो काफ़ी भयभीत करने वाली थी।

2. इस समग्र परिवेश में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए। इस संदर्भ में इन सभी परिवर्तनों या उनके कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता; उपलब्ध विवरणों के आधार पर उनमें से केवल कुछेक का मूल्यांकन आनुमानिक रूप से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जहां गैर सरकारी उपभोग व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां कुल मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियों से घरेलू बचतों विशेषकर वित्तीय बचतों का पूर्ण रूप से और बाजार मूल्यों की दर पर वास्तविक देशी उत्पादन की तुलना में पता लगता है। इसी प्रकार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध विवरणों से यह विदित होता है कि सरकारी क्षेत्र के उपभोग व्यय के सापेक्ष अंश में सार्वजनिक बचत के मुकाबले में बहुत अधिक वृद्धि हुई। कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि चालू मूल्यों के अनुसार देशी बचत 1971-72 में पिछले वर्ष के मुकाबले में वास्तविक देशी उत्पादन के लगभग उच्चतर अनुपात में थी; विदेशी सहायता के उपयोग की मात्रा भी इस वर्ष अधिक थी; अतः निवेशों के वित्त-पोषण के लिए उपलब्ध विदेशी वित्तीय साधनों में 1970-71 की अपेक्षा इस वर्ष वृद्धि हुई। इससे यह विदित होता है कि आलोच्य वर्ष की असाधारण परिस्थितियों के बावजूद वास्तविक देशी उत्पादन में कुल देशी निवेश का अनुपात पिछले वर्षों की तुलना में अधिक था। निम्नलिखित सारणी से इस तथ्य का पता लग सकता है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपर्युक्त वृद्धि के साथ साथ मूल्यों में भी काफ़ी वृद्धि हुई; अतः वास्तव में हमारी उपलब्धि कम महत्वपूर्ण ही थी।

3. आगे के पैराग्राफ़ों में दिये गये आंकड़ों से यह विदित होगा कि 1971-72 के दौरान देशी बचत में हुई वृद्धि के अधिकतर भाग का कारण जनता के पास रहने वाले कुल मुद्रागत साधनों में हुई अधिक वृद्धि है। आलोच्य वर्ष में जनता के पास रहनेवाली चल मुद्रा और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा राशियों में अवश्य वृद्धि हुई, किन्तु उक्त जमा-राशियों में बहुत तेजी से इतनी वृद्धि हुई जितनी इसके पहले कभी नहीं हुई थी। चालू मूल्यों के अनुसार हिसाब लगाने पर पता चलता है कि उक्त वृद्धि की मात्रा 21 प्रतिशत थी जब कि पिछले वर्ष यह 17.9 प्रतिशत थी। बैंकों की जमाराशियों के क्षेत्र में बचत और मीयादी जमा-राशियों में मांग जमाराशियों की तुलना में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। ऋण-क्षेत्र में सामान्य नीति ऋण की मात्रा पर नियंत्रण लगाने के पक्ष में थी और औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उधार लिये जाने के संदर्भ में मंदी पायी गयी; अतः जमाराशियों में हुई वृद्धि बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वृद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक थी; इस कारण बैंकों के पास भारी मात्रा में चल मुद्रा शेष थी।

4. इस प्रकार जून, 1972 के अन्त में चल मुद्रा और बैंकों की जमाराशियों के संदर्भ में जनता की स्थिति बहुत अच्छी थी, किन्तु वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में प्रवृत्ति अनुकूल नहीं थी। 89 लाख मी० टन के अनाजों के स्टाक रहने से उनके मूल्यों में और वृद्धि नहीं हुई और इसी प्रकार रूई और जूट के स्टाकों विद्यमान रहने के कारण कुछ हद तक उनके मूल्य भी नहीं बढ़े। दूसरी वस्तुओं के मामले में उनकी मांग में होनेवाली वृद्धि के अनुकूल भारी मात्रा में पूर्ति किये जाने के लिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और अच्छे मानसून की आवश्यकता है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आयातित कच्चे माल और पूंजीगत माल की मात्रा में भले ही वृद्धि न की जाए, किन्तु उनका उचित अनुरक्षण किया जाए।

5. देश के भीतर हुई इन घटनाओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यापक परिवर्तन हुए जिनसे भारत का व्यापार और विदेशी अदायगियां प्रभावित हुई। अगस्त, 1971 में जब अमेरिका ने डालर की परिवर्तनीयता और सममूल्यता के लिए आधिकारिक समर्थन को समाप्त कर देने का निर्णय किया तब से शुरू होने वाला यह वर्ष जून, 1972 में पौंड स्टर्लिंग जारी करने के संबंध में ब्रिटेन द्वारा किये गये निर्णय के साथ चरमसीमा पर पहुंच गया; इस प्रकार इस वर्ष विदेशी मुद्राओं के निर्धारित सममूल्यों और विदेशी मुद्राओं के पारस्परिक संबंधों के मामले में सुनिश्चित दायित्वों से संबंधित ब्रिटेन वूड्स् की व्यवस्था के संदर्भ में संपूर्ण परिवर्तन पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्थाओं में पाये गये इन उतार चढ़ावों और अनिश्चितताओं का प्रभाव व्यापार और भारत सहित विकास-मान देशों को मिलने वाली व सहायता सुविधाओं पर अनिवार्य रूप से पड़ा। भारतीय रुपये ने दिसम्बर, 1971 तक डालर के साथ अपनी सममूल्यता को बनाये रखा; तदनंतर दिसम्बर, 1971 के मुद्रागत करारों के कारण मुद्राओं के सममूल्यों का जो सामान्य पुनर्निर्धारण किया गया उसमें भारतीय रुपये ने भाग लिया और स्टर्लिंग के साथ विनिमय की अपनी केन्द्रीय दर को दोनों पक्षों में उतार-चढ़ाव के लिए 2¼ प्रतिशत के स्वीकृत मार्जिन के अधीन प्रतिष्ठित किया। पिछले जून में पौंड स्टर्लिंग के जारी किये जाने से इस संबंध में भारत की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सारणी 1 :—बाजार मूल्यों के अनुसार वास्तविक देशी उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बचत और निवेश के अनन्तिम आंकड़े

वित्तीय वर्ष	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1973–74 (मध्यावधि मूल्यांकन अनुमान)
1. देशी बचत	8.2	8.6	9.4	10.0	10.2(11.9)
2. विदेशी वित्तीय साधनों की उपलब्धि . .	1.3	0.7	1.1	1.5	0.9(1.2)
3. निवेश (1+2)	9.5	9.3	10.5	11.5	11.1(13.1)

(कोष्टकों में दिये गये आंकड़े चौथी योजना प्रलेख में उपलक्षित अनुपातों को दर्शाते हैं।)

6. विदेशी मुद्रा प्रणाली में किये गये ये परिवर्तन सीमाशुल्क और सीमाशुल्केतर अवरोधों के अतिरिक्त भारत के निर्यातों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। 1971-72 के राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान हुई निर्यात आमदनी पिछले वर्ष की कुल आमदनी की अपेक्षा केवल 32 करोड़ रुपये अथवा लगभग 2 प्रतिशत अधिक थी।* इस वर्ष के अधिकांश भाग में बंगला देश में मिलों के बंद रहने के कारण भारतीय जूट निर्यातों को काफी अधिक लाभ होने के बावजूद यह स्थिति उत्पन्न हुई। जहां निर्यातों की वृद्धि दर में हुई थोड़ी सी कमी उपर्युक्त विदेशी परिस्थितियों के कारण हुई वहां देशी अर्थव्यवस्था के भीतर भी उत्पादन में कमी और लागत व मूल्यों में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी वजह से कतिपय पण्यों के निर्यात कम हो गये थे।

7. यदि भविष्य में विदेशी सहायता पर अनुचित रूप से निर्भर रहे बिना अथवा प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों से अनुचित मात्रा में आहरण किये बिना अर्थव्यवस्था की आयात संबंधी अपेक्षाओं की पर्याप्त मात्रा पूर्ति करनी हो तो निश्चित रूप से 1971-72 की अपेक्षा अधिक मात्रा में निर्यातों में वृद्धि करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए कि देशी वस्तुओं के मूल्यों में और वृद्धि न हो और निर्यात पहले से अधिक मात्रा में हों, नीति इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि देशी व्यय की वृद्धि और कुल उत्पादन की वृद्धि के बीच का संबन्ध अधिक व्यावहारिक हो। आगामी वर्षों में सरकारी क्षेत्र के योजनागत और योजनेतर परिव्ययों के कारण अधिकांश देशी व्यय बढ़ेगा अतः वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक होता है कि घाटे की अर्थव्यवस्था का न्यूनतम आश्रय लेनेवाली नीति का पालन किया जाए। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक होगा कि बैंकिंग संघटन के भीतर संचित अतिरिक्त जमाराशियों का उपयोग अधिकतर उत्पादन और नियोजन की व्यवस्था के लिए किया जाए। यह आशा की जाती है कि पिछले वर्ष की गतिविधियों से उत्पन्न इन परिणामों को पांचवीं योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा।

उत्पादन, मूल्य और नीति संबंधी उपाय

राष्ट्रीय आय

8. अब हम जुलाई, 1971–जून, 1972 की अवधि की गतिविधियों पर विचार करेंगे। अर्थव्यवस्था की उत्पादन संबंधी प्रवृत्तियों से पता चलता है कि 1971-72 के राजकोषीय वर्ष में वास्तविक राष्ट्रीय आय (1960-61 के मूल्यों के अनुसार) में हुई वृद्धि लगभग 4 प्रतिशत कम थी जबकि उसमें 1969-70 और 1970-71 में क्रमशः 5.3 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में हुई इस वृद्धि के साथ, यदि उक्त योजना के लिए अभिकल्पित लक्ष्य (5.5 प्रतिशत वार्षिक) तक पहुंचना हो तो राष्ट्रीय आय में शेष दो वर्षों में लगभग 7 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होनी चाहिए।

कृषि उत्पादन और पूर्ति

9. राष्ट्रीय आय की वृद्धि में पायी गयी मंदी दोनों पण्य क्षेत्रों की वृद्धि-दरों में हुई कमी के कारण हुई। पिछले दो वर्षों में जहां कृषि उत्पादन में औसतन 7 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई थी वहां 1971-72 में बहुत कम वृद्धि होने की संभावना है। बाजरे के उत्पादन में लगभग 27 लाख मी० टन की कमी हो जाने के कारण मोटे अनाजों के उत्पादन की मात्रा प्रमुख अनाजों के उत्पादन की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं रह सकी है। दालों के उत्पादन में हुई कमी के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि अनाजों के उत्पादन की मात्रा पिछले वर्ष के 1080 लाख मी० टन के स्तर के बराबर नहीं होगी। विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि इस वर्ष के दौरान अधिक उपजवाली किस्मों के कार्य-क्रमों के अधीन आनेवाले क्षेत्र को विस्तारित किया गया, यह स्थिति कुछ हद तक शोचनीय है।

10. वर्तमान उत्पादन में स्थिरता के बावजूद 1971-72 के दौरान अनाजों की पूर्ति की स्थिति सरकार के पास रहनेवाले स्टाकों के कारण संतोषजनक थी। अनाजों के आयातों में जो कमी हुई उसे देश के भीतर उपार्जित किये जाने वाले अनाजों की मात्रा में भारी वृद्धि कर संतुलित किया गया; इससे अनाजों के स्टाकों का वर्षान्त में रहनेवाला स्तर बढ़ गया था। अनाजों के स्टाक जून, 1972 के अन्त में 89 लाख मी० टन थे जब कि पिछले वर्ष वे 84 लाख मी० टन थे। कुल स्टाकों में चावल और गेहूं का अंश क्रमशः 25 लाख मी० टन और 61 लाख मी० टन था। यह स्थिति आगामी वर्ष की खाद्यान्न व्यवस्था के लिए सुविधाजनक प्रारम्भिक चरण है, इससे यह भी संकेत मिलता है कि अनाजों के स्टाक से पर्याप्त मात्रा में अनाज निकाले नहीं गये जिससे कि पिछले कुछ महीनों में अनाजों के मूल्यों में हुई वृद्धि कम हो सके।

11. वाणिज्यिक फ़सलों की स्थिति भी मिश्रित है एक ओर रूई और जूट के उत्पादन में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर तिलहनों और गन्ने के उत्पादन में कमी हुई है। व्यापार क्षेत्र ने 1971-72 में 70 लाख गांठों से अधिक रूई का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। उक्त मात्रा उत्पादन का एक नया कीर्तिमान है। इस वर्ष के दौरान इस संदर्भ में जो वृद्धि हुई उसे व्यापार क्षेत्र द्वारा 1970-71 के लिए अनुमानित 57 लाख गांठों के कम स्तर के उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जूट और मेस्ता

*ये आंकड़े वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों पर आधारित हैं। जैसा कि आगे पैराग्राफ 80 में स्पष्ट किया जाएगा, 1970-71 में निर्यातों की अभिलेखन प्रणाली में किये परिवर्तन के लिये समायोजन किया जाए तो 1971-72 में निर्यातों में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 प्रतिशत से अधिक होगी।

के उत्पादन में 6 लाख गांठों की वृद्धि हुई जिससे कुल उत्पादन 68 लाख गांठों तक पहुंच गया। इसके विपरीत जहां पांच प्रमुख तिलहनों के उत्पादन की मात्रा बढ़कर 1970-71 में 92 लाख मी० टन तक पहुंच गई थी वहां आलोच्य वर्ष में उक्त मात्रा में लगभग 10 लाख मी० टन की कमी होने की आशा है। मूंगफली के उत्पादन की मात्रा जहां पिछले वर्ष 61 लाख मी० टन थी वहां इस वर्ष कम होकर 57 लाख मी० टन हो गयी। गन्ने के उत्पादन की मात्रा 1969-70 में 138 लाख मी० टन के उच्चतम स्तर पर थी, किन्तु वह 1970-71 में कम होकर 132 लाख मी० टन हो गयी और 1971-72 में यह प्रत्याशा है कि वह और कम होकर 128 लाख मी० टन हो जाएगी।

12. इन वार्षिक घट-बढ़ों के बावजूद सामान्य रूप से कृषि उत्पादन में और विशेष रूप से अनाजों के उत्पादन में 1966-67 में नयी कृषि प्रणालियों के अपनाये जाने से वृद्धि होती रही है। यह आशा की जाती है कि अधिक उपजवाली किस्मों के उत्पादन कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष के लिए निर्धारित 180 लाख हेक्टेयर भूमि के लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी जब कि 1970-71 में उक्त कार्यक्रम के अधीन 146 लाख हेक्टेयर भूमि लायी गयी थी। पिछले दो वर्षों के विपरीत 1971-72 में रासायनिक उर्वरकों के उपभोग में पर्याप्त वृद्धि पायी गयी। फिर भी उत्पादन स्थिति संतोषजनक नहीं है। जहां गेहूं के उत्पादन में निर्धारित मात्रा से अधिक तेजी से प्रगति हुई वहां अन्य अनाजों विशेषकर ज्वार, मक्के और दालों के उत्पादन में हुई प्रगति परिकल्पित मात्रा से धीमी थी। देश का अत्यंत महत्वपूर्ण अनाज चावल है; उसके उत्पादन के संदर्भ में अधिक उपजवाली किस्मों के कार्यक्रमों की सफलता के मार्ग में प्रारम्भ में जो समस्याएं बाधक थीं उन्हें अधिक उपजवाली किस्मों के बीज और कीटनाशक तथा रोगनाशक दवाइयां प्रदान कर क्रमशः दूर किया जा रहा है। इस प्रकार इस नयी व्यवस्था के संभाव्य लाभ का बड़ा अंश अभी प्राप्त होना शेष है।

13. अनाजों के सही प्रबन्धन से संबंधित एक समस्या उनके भण्डारण और परिवहन के सबंध में है। भारतीय खाद्य निगम की कुल भण्डार क्षमता 1970-71 के 72 लाख मी० टन से बढ़कर 1971-72 में 83 लाख मी० टन हो गयी (इसमें अन्य सरकारी और निजी स्रोतों से किराये पर ली गयी 42 लाख मी० टन की क्षमता शामिल है)। फिर भी भण्डारण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान भण्डारण क्षमता अपर्याप्त है और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भारी उगाही क्षेत्रों में अतिरिक्त खत्तियों का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये गये प्रयत्न इस्पात के अभाव के कारण पूर्ण सफल नहीं हो सके हैं। जहां तक अनाजों के परिवहन का संबंध है, पिछले तीन वर्षों से रेलवे की बड़ी और मीटर लाइनों पर पर्याप्त मात्रा में माल-डिब्बे न मिलने के कारण उत्पादन केन्द्रों से बड़े उपभोक्ता बाजारों तक आसानी से समय पर अनाजों को ले जाने में बाधा पड़ी है। जब इन बाधाओं को दूर किया जाएगा और शहरी बाजारों में अनाजों के भण्डारण और परिवहन की सक्षम व्यवस्थाएं निश्चित रूप से हो जाएगी तभी अनाजों की बड़ी मात्रा में उगाही और समीकरण भण्डारों का कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में अनाजों के मूल्यों में पाई जानेवाली घट-बढ़ को दूर कर उनमें समानता ला सकेगा।

औद्योगिक उत्पादन

14. पिछले तीन वर्षों से औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि कम होती रही है। 1969 में जहां उक्त वृद्धि 7.1 प्रतिशत थी वहां 1970 में कम होकर 4.8 प्रतिशत और 1971 में और कम होकर केवल 2.9 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में 8 से 10 प्रतिशत तक की जो वृद्धि दर परिकल्पित की गई थी उक्त वृद्धि उसके आधे से भी कम रह गई है।

15. औद्योगिक वर्गों का उनकी वार्षिक विकास दरों के अनुसार किये गये वर्गीकरण से यह पता चलता है कि जिन उद्योगों में उत्पादन कम होते रहे हैं उनमें जहां 1968 में 24 प्रतिशत (वजन के अनुसार) की वृद्धि हुई थी वहां 1971 में क्रमशः बढ़ते बढ़ते उक्त वृद्धि-दर 38 प्रतिशत तक पहुंच गई; किन्तु जिन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती रही उनकी वृद्धि का वजन उपर्युक्त अवधि में 74 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत हो गया।

सारणी 2 : उद्योगों का वर्गीकरण, उनकी विकास-दरों के अनुसार

विकास दरों की सीमा@	सामान्य सूचकांक में उनका वजन (1960=100)				
	1967	1968	1969	1970	1971
गुम कमी					
सामान्य : 5 प्रतिशत से कम	35.68	4.43	16.61	16.10	19.98
उल्लेखनीय : 5 प्रतिशत और उससे अधिक	25.48	19.04	12.15	13.24	17.59
उसमें से					
(i) 10 प्रतिशत और उससे अधिक	13.93	9.18	9.79	6.13	5.30
	61.16	**23.47**	**28.76**	**31.34**	**37.57**
वृद्धि					
सामान्य : 5 प्रतिशत से कम	15.34	23.81	26.69	27.78	27.99
उल्लेखनीय : 5 प्रतिशत और उससे अधिक	21.02	50.24	42.07	38.40	31.96
उसमें से					
(i) 10 प्रतिशत और उससे अधिक	13.20	25.68	28.10	22.42	15.72
	36.36	**74.05**	**68.76**	**66.18**	**59.95**
कुल वजन	97.52*	97.52*	97.52*	97.52*	97.52*

@विकास दरें संबन्धित पिछले वर्षों की तुलना में हुई वृद्धि के प्रतिशत को दर्शाती है।

*केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन उन उद्योगों के सूचकांक को नियमित रूप से प्रकाशित नहीं करते जिनके पास वजन के 2.48 प्रतिशत अंक शेष हैं।

16. 1971 में जिन उद्योगों के उत्पादन में 5 प्रतिशत और उससे ज्यादा कमी हुई वे कुल उत्पादन के वजन के लगभग 18 प्रतिशत के द्योतक हैं। सूत की कताई, औद्योगिक मशीनों, रेल-सड़क उपकरण और चीनी के उद्योग इस वर्ग में आते हैं। लोहे और इस्पात, सूती कपड़ों की कताई और मोटर-साइकिलों तथा साइकिलों के उद्योगों में 5 प्रतिशत से न्यून कमी हुई। 1971 में जिन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि पाई गई उनमें से ऐसे उद्योगों की मात्रा जिनमें 5 प्रतिशत और उससे अधिक वृद्धि हुई, 38 प्रतिशत से कम होकर 32 हो गई और ऐसे उद्योगों की मात्रा जिनमें 10 प्रतिशत और उससे अधिक वृद्धि हुई, 1970 के 22 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत हो गई। जिन उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई उनमें मूल रासायनिक पदार्थों, सीमेंट, सभी अलोह धातुओं, बिजली उत्पादन और वनस्पति के उद्योग शामिल हैं।

17. पूर्ति की दिशा में पाए गए अवरोधों और मांग में आई कमियों के कारण औद्योगिक उत्पादन की समग्र वृद्धि दर में बराबर कमी की प्रवृत्ति पाई गई। पूर्ति संबंधी बाधाओं में रूई और तिलहन जैसी कच्ची सामग्री और इस्पात तथा अलोह धातु जैसी मूल औद्योगिक वस्तुओं की कमी सम्मिलित थी। उपर्युक्त वस्तुओं की कमी के कारण अन्य उद्योगों के उत्पादन भी कम हो गए थे। तैयार इस्पात के उत्पादन की मात्रा 1970-71 के 48 लाख मी० टन से घटकर 1971-72 में 46 लाख मी० टन हो गई। यद्यपि यह कमी सामान्य थी फिर भी उससे इस्पात का उपयोग करनेवाले उद्योगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा; क्योंकि उनकी बढ़ती हुई इस्पात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति आयातों के द्वारा केवल थोड़ी सी सीमा तक की जा सकती थी। यद्यपि निर्माण-कार्यों के लिए आवश्यक सीमेंट की मांग में कमी हो जाने और धातु-कर्म संबंधी उपभोक्ताओं की तरफ़ से कोयले की मांग में कमी हो जाने के कारण सीमेंट और कोयले के उत्पादन में बाधा पड़ी फिर भी रेल-परिवहन संबंधी बाधाओं से कोयले और सीमेंट के स्टाक बहुत अधिक जमा हो गए थे। इस्पात के उद्योग, मोटर और उससे संबंधित उद्योग जैसे कुछ नाजुक क्षेत्रों में संगठन और श्रमिक संबंधों के संदर्भ में जो समस्याएं पायी गयीं उनसे भी औद्योगिक उत्पादन में मंदी आयी। इसके अलावा बिजली की कमी के कारण भी कुछ उद्योगों के उत्पादन में गंभीर रूप से बाधा पड़ी।

18. मांग में बराबर कमी होने के कारण कुछ उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हुआ। इन उद्योगों में इस्पात के नल और ट्यूब रेल डिब्बा निर्माण और सभी प्रमुख मशीन निर्माण के उद्योग (सीमेंट चाय छपाई और कपड़ा आदि के उद्योग) जैसे निवेश माल उद्योग शामिल थे। उक्त उद्योगों की क्षमता का न केवल बहुत कम उपयोग होता आ रहा है बल्कि पिछले दो वर्षों के दौरान उनके उपयोग की दर भी कम हो गयी है। इस्पात की ढलाई और मशीन उपकरणों के उद्योग जैसे कतिपय उद्योगों की क्षमता के उपयोग की दर में 1971 में निश्चित ही प्रगति हुई है फिर भी उन उद्योगों की क्षमता का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो पाया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कुछ मामलों में कच्ची सामग्री बिजली आदि की कमी के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई; किन्तु इन सभी मामलों में उत्पादन की वृद्धि में हुई कमी का प्रमुख कारण मांग में निरन्तर पायी गयी कमी थी। इसके विपरीत कुछ उद्योगों में उत्पादन की कमी मांग की कमी के कारण नहीं वरन् क्षमता के अभाव के कारण हुई। उन उद्योगों में कागज से बनी चीजों कास्टिक सोडा सोडा राख मोटर और कृषि ट्रैक्टरों के उद्योग सम्मिलित थे। इन दोनों कारणों अर्थात् निवेश माल की मांग में कमी और अपर्याप्त क्षमता से पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुल निवेश की मात्रा में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई।

19. 1972 में औद्योगिक उत्पादन की संभावना पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग अच्छी है। कुछ मामलों में कच्ची सामग्री की स्थिति में सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए रूई की स्थिति को लिया जा सकता है। वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक रूई की पूर्ति की स्थिति सुधर गयी है किन्तु भविष्य की उसकी सम्भावना पुनः अनिश्चित हो गयी है। यह आशा की जाती है कि निवेश कार्य में वृद्धि होने से औद्योगिक उत्पादों की मांग पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने भी औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। जनवरी 1972 में 54 नाजुक उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और उक्त उद्योगों को उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता के ऊपर लगभग 100 प्रतिशत तक विस्तारित कर देने के लिए व्यापक अनुमति दे दी गयी है। इस नीति का उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ेगा वह अभी प्रकाश में नहीं आया है हालांकि यह स्पष्ट है कि इन 54 उद्योगों के मामले में भी पूंजीगत उपकरणों और मशीनों की स्थापना पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण इस नीति के प्रभाव पर बाधा पड़ेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की नयी प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन और वर्तमान संयंत्रों के परिचालन में विद्यमान संगठनात्मक कमियों को दूर करने के लिए भी विशेष कदम उठाये गये हैं। इन अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद कुछ क्षेत्रों में अब भी कमियां विद्यमान रहती हैं। इसका उदाहरण वनस्पति उत्पादन उद्योग है जो तिलहनों की अपर्याप्त पूर्ति की स्थिति का सामना कर रहा है। इसी प्रकार 1972-73 में पटसन के उत्पादन में कमी होने का अनुमान है जिससे 1972 के उत्तरार्ध में जूट के वस्त्रों के उत्पादन पर 20 प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मूल्य स्थिति

20. उत्पादन की इन स्थितियों के कारण देश के भीतर मांग बढ़ जाने से सहज ही मूल्य-स्थिति बिगड़ गयी। जून 1971 और जून 1972 के बीच थोक मूल्य सूचकांक में 6.8 प्रतिशत की तेजी से वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की वृद्धि से दुगुनी से अधिक थी। एकमात्र औद्योगिक कच्ची सामग्री को छोड़कर सभी बड़े वर्गों की वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई। अनाजों के मूल्य में जहां 1970-71 (जुलाई-जून) में 2.4 प्रतिशत की कमी हुई थी वहां इस वर्ष 14 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई और निर्मित वस्तुओं के मूल्य में पिछले वर्ष हुई 8.6 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। अनाजों के वर्ग में न केवल मोटे अनाजों और दालों के मूल्य में वृद्धि हुई जिनके उत्पादन में कमी हुई थी बल्कि गेहूं के मूल्य में भी उसके उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में चावल और गेहूं के मूल्य में क्रमशः 10.1 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष उसमें क्रमशः 2.1 और 2.9 प्रतिशत की कमी हुई थी। अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं में से चीनी के मूल्य में इस वर्ष के दौरान 27.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केवल रूई के मूल्य में जहां पिछले वर्ष 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी वहां आलोच्य वर्ष में उसके समग्र उत्पादन में 26 प्रतिशत से अधिक अनुमानित वृद्धि होने के कारण 31 प्रतिशत की भारी कमी हुई। अन्य सभी औद्योगिक कच्ची सामग्री अर्थात् पटसन तिलहनों और गन्ने के मूल्य में हुई वृद्धि की दर अलग अलग थी। इसी प्रकार निर्मित वस्तुओं के वर्ग में सभी प्रमुख उत्पादनों अर्थात् सूत से बनी चीजों, जूट से बनी चीजों, रासायनिक उत्पादों, लोहे और इस्पात से बनी चीजों और कागज से बनी चीजों के मूल्य में वृद्धि पायी गयी।

21. सामान्य मूल्य स्तर में विशेषकर अनाजों और चीनी के मूल्य में हुई वृद्धि के अनुरूप औद्योगिक श्रमिक वर्ग के अखिलभारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों (आधार: 1960-100) और शहरी अमेतर कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों में भी वृद्धि हुई है। औद्योगिक श्रमिक वर्ग का औसत सूचकांक जहां 1970-71

(जुलाई-जून) में 186 था वहां 1971–72 (जुलाई-जून) में बढ़कर 195 हो गया। इस प्रकार इस वर्ष उक्त सूचकांक में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1970–71 में 1969–70 की तुलना में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। शहरी अमेतर कर्मचारियों के औगत सूचकांक में भी 1971–72 (जुलाई-जून) में 1970–71 की अपेक्षा 4.6 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई जबकि 1970–71 में 1969–70 की तुलना में 3.6 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई थी। निर्वाह व्यय में बराबर वृद्धि होते रहने से वस्तुओं की लागत पर गंभीर प्रभाव पड़ा है क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों की कई स्थापनाओं में वेतन बिल को निर्वाह व्यय में होनेवाले परिवर्तनों से संबद्ध करने की प्रणाली है।

22. जहां कई मामलों में उत्पादनों में बहुत ही कम प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई वहां मुद्रा क्षेत्र की प्रवृत्ति बिलकुल दूसरे प्रकार की थी। इस वर्ष कुल मुद्रा व्यय की मात्रा पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक बढ़ी; चाहे हम अर्थ-व्यवस्था के कुल मुद्राव्यय के सूचकांक के रूप में जनता के पास रहनेवाली मुद्रा को लें अथवा कुल मुद्रागत साधनों को वास्तव में यही स्थिति उत्पन्न होती है। पूर्ति की कमी के परिप्रेक्ष्य में मुद्राव्यय में हुई ऐसी वृद्धि उच्चतर मूल्यों के कारण ही समायोजित हो सकती है।

23. इस वर्ष भी अनाजों का उगाही-मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहा; इस कारण जब नयी रबी फ़सल बाजार में आयी तब अनाजों के मूल्य में होनेवाली कमी रोकी जा सकी। इस प्रकार जब बाजार में अनाजों की बहुत अधिक पूर्ति की स्थिति रही तब भारतीय खाद्य निगम के उगाही संबंधी कार्यकलापों से किसान के बिक्री मूल्य को एक आधार मिला। अतः जब बाजार में पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलने लगे तब शहरी उपभोक्ताओं को कम मूल्य से कोई फायदा नहीं हो सका और उनके संदर्भ में हाल ही में स्थिति और खराब हो गयी है। हाल ही के सप्ताहों में अधिकांशतः मोटे अनाजों की कम पूर्ति की स्थिति और सूखे से वर्तमान वर्ष की खरीफ़ फ़सल की संभावनाओं को थोड़ी सी क्षति होने के कारण गेहूं और दूसरे अनाजों के बाजार मूल्य में उगाही मूल्य से थोड़ी अधिक वृद्धि हुई है। यह उल्लेखनीय है कि जिन छोटे किसानों के पास बिक्री के लिए बहुत कम अनाज थे या अतिरिक्त अनाज नहीं थे या जिन छोटे किसानों को पहले अपने उत्पादन के एक अंश को बेच देने के कारण उस समय अनाज खरीदने पड़े जब मूल्य में वृद्धि हो गयी थी उन किसानों को इस परिस्थिति में कोई लाभ नहीं मिल सका। इस पृष्ठभूमि में और हाल ही में हुई मूल्यवृद्धि को देखते हुए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि नियमित माध्यमों से अधिक मात्रा में अनाज उपलब्ध करायें ताकि उपभोक्ता मूल्य को और बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा उगाही मूल्य के वर्तमान स्तरों को बनाये रखने से फ़सलों के बीच असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गयी है; इसके फलस्वरूप हाल ही में दालों और रुई जैसी कतिपय नकदी फसलों की उत्पादन भूमि के क्षेत्रफल में कमी आ गयी है; यह स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

24. इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जहां उत्पादन की कमी के फलस्वरूप तत्काल मूल्य में वृद्धि हो जाती है किन्तु उत्पादन की वृद्धि के फलस्वरूप उपभोक्ता को उसके अनुरूप लाभ नहीं मिलता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रुई और पटसन जैसी नकदी फ़सलों के उत्पादन और मूल्य में तेजी से जो घटबढ़ होती है उसका बुरा प्रभाव औद्योगिक उत्पादन और भुगतान शेष पर भी पड़ता है। अतः विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित नीति के मूल में स्पष्ट रूप से मूल्य को स्थायी स्तरों पर बनाये रखने का उद्देश्य होना चाहिए; किन्तु यह निर्धारित करने के लिए कि वे स्तर क्या हों किसानों की आय संबंधी अपेक्षाओं और उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

बजट संबन्धी गतिविधियां*

केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त स्थिति

25. अब हम कुल राष्ट्रीय व्यय के घटकों की प्रवृत्तियों पर विचार करें उक्त घटकों में हुई वृद्धि के कारण उपर्युक्त मूल-स्थिति उत्पन्न हुई। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कार्यकलापों के संदर्भ में, उनके बजट में 1971-72 में समग्ररूप से 631 करोड़ रुपयों** का घाटा@ पाया गया ; यह 1970-71 (लेखे) की स्थिति की तुलना में इस वर्ष स्थिति के बहुत अधिक बिगड़ जाने का संकेत है। क्योंकि 1970–71 के समग्र घाटे की राशि 431 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष बजट के अनुमानों की तुलना में 1971-72 के घाटे की राशि 244 करोड़ रुपये अधिक थी। इस प्रकार प्रत्याशित परिमाण में जो अंतर पाया गया उसका कारण यह नहीं था कि कुल प्राप्तियों में कमी हुई, किन्तु उसका कारण यह था कि मूलतः बजट की गयी राशि की अपेक्षा अधिक मात्रा में राशि वितरित की गयी। वित्तीय साधन जुटाने के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त उपायों से प्राप्त होने वाली राशि को हिसाब लेने पर 1972–73 के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त रूप से समग्र घाटे की राशि 212 करोड़ रुपये होगी (सारणी 3) ।

वितरणों की प्रवृत्तियां†

26. केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वितरित की गई कुल राशि (जिसमें ऋण और अग्रिम शामिल हैं) में जहां 1969-70 और 1970-71 में क्रमशः 11.4 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां 1971-72 में 16.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि 1971-72 में बढ़कर 10,481 करोड़ रुपये हो गयी । 1971-72 के बजट में यह प्रत्याशा की गयी थी कि विकास परिव्यय में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, किन्तु वास्तविक वृद्धि 17.4 प्रतिशत थी। किन्तु विकासेतर परिव्यय में और तेजी से वृद्धि हुई ; उसमें 1.7 प्रतिशत की वृद्धि होने के बजाय 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विकासेतर परिव्यय में यह वृद्धि प्रमुख रूप से रक्षा, शरणार्थी सहायता और अकाल सहायता पर हुए अतिरिक्त व्यय के कारण हुई, इस प्रकार मूल रूप से की गयी व्यवस्था की अपेक्षा जो अधिक वृद्धि हुई उसमें से 560 करोड़ रुपयों की वृद्धि उपर्युक्त संदर्भ में हुई। 1972-73 के बजट अनुमानों में विकास परिव्यय में 10 प्रतिशत की वृद्धि और विकासेतर परिव्यय में लगभग 1 प्रतिशत की कमी की व्यवस्था की गयी है। 1972-73 के बजट में निर्धारित विकास परिव्यय में वृद्धि का जो कम प्रतिशत पाया गया उसका प्रमुख कारण यह था कि राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा, कृषि, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए कि गयी व्यवस्थाओं में केवल न्यूनतर वृद्धि हुई है।

---

* यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो इस खंड में दिये हुए आंकड़े राजकोषीय वर्षों के हैं ; 1971–72 के आंकड़े परिणोधित अनुमान हैं।

** अंतिम लेखों के आधार पर घाटा और अधिक था।

@केन्द्रीय सरकार के घाटे के उपर्युक्त आंकड़े बजट के दस्तावेजों में दिये गये आंकड़ों के आधार पर हैं। राज्य सरकारों के घाटे के संबंध में पैराग्राफ़ 28 की पाद टिप्पणी देखें।

इस पैराग्राफ़ के आंकड़े शेयरों के रूप में ऋणों के परिवेशन और भारत की आकस्मिकता निधि में अंतरण के लिए समायोजित किये गये हैं। (पृ. 6 की सारणी 3 की पाद टिप्पणियां 2 देखें)।

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

27. प्राप्तियों के संदर्भ में कर और पूंजीगत प्राप्तियों के अधीन भारी वृद्धि हुई। कर की कुल प्राप्तियों में जहां 1969-70 और 1970-71 में क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां 1971-72 में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केन्द्रीय करों (राज्यों के हिस्से को मिलाकर) में 1971-72 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राज्यों के अपने कर राजस्व में हुई 10.2 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक थी।

राज्य सरकारों के 1971-72 के बजट संबन्धी कार्यकलाप

28. सभी राज्यों में 1971-72 में संयुक्त रूप से 246 करोड़ रुपये का घाटा* था जो प्रत्याशित घाटे से 92 करोड़ रुपये से अधिक था (सारणी 4)। यह स्थिति इस तथ्य के बावजूद हुई कि राज्यों की कुल प्राप्तियों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् राज्यों की प्राप्तियों की राशि बढ़कर 6313 करोड़ रुपये हो गयी। उक्त वृद्धि बजट में प्रत्याशित वृद्धि की अपेक्षा 7 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक थी। जहां राज्यों की अपनी राजस्व प्राप्तियां बजट में प्रत्याशित मात्रा से केवल थोड़ी सी अधिक थी वहां केन्द्रीय सरकार से अंतरित किये गये वित्तीय साधन (कुल ऋणों के साथ) बहुत अधिक थे। इस स्थिति का एक कारण यह था कि केन्द्रीय सरकार ने कतिपय राज्यों को विशेष सहायता प्रदान की थी। फिर भी घाटे में वृद्धि हुई, क्योंकि जहां बजट में यह प्रत्याशा की गयी थी कि कुल 5,745

* नकदी शेष से आहरण, राज्यों द्वारा अपने नकदी शेष निवेश लेखे में रखी गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक बिक्री, राज्यों की प्रारक्षित राजस्व निधियों के वास्तविक अंतरण और अर्थोपाय अग्रिमों और रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये ओवर ड्राफ्ट की वास्तविक वृद्धि के बजट आंकड़े।

सारणी 3 :—केंद्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और वितरण (राशि करोड़ रुपयों में)

	1970-71 (लेखे)		1971-72 (बजट अनुमान)*		1971-72 (परिशोधित अनुमान)		1972-73 (बजट अनुमान)*	
	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)
I. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	8564	+4.1	9432	+10.1	10132 (9850)	+18.3 +(15.0)	10581 (10651)	+4.4 +(8.1)
(अ) राजस्व प्राप्तियां	5958	+10.5	6665	+11.9	7043	+18.2	7842	+11.3
उनमें से								
कर प्राप्तियां	4735	+13.2	5261	+11.1	5516	+16.5	6322	+14.6
(आ) पूंजीगत प्राप्तियां	2606	+8.1	2767	+6.2	3089 (2807)	+18.5 +7.7	2739 (2809)	—11.3 (+0.1)
II. कुल वितरण	8995	+9.5	9819	+9.2	10763 (10481)	+19.7 (+16.5)	10823 (10893)	+0.6 (+3.9)
उनमें से								
विकास परिव्यय (क+ख)	3590	+14.3	4148	+15.5	4427 (4215)	+23.3 (+14.4)	4638	+4.8 (+10.0)
(क) राजस्व	2400	+14.0	2754	+14.8	2825	+17.7	3123	+10.5
(ख) पूंजीगत	1190	+15.0	1394	+17.1	1602 (1390)	+34.6 (+16.8)	1515	—5.4 (+9.0)
विकासेतर परिव्यय (क+ख)	3675	+12.1	3739	+1.7	4472 (4472)	+21.7 (+19.8)	4292 (4362)	—4.0 (—0.9)
(क) राजस्व	3366	+6.6	3593	+6.7	4204	+26.7	4216	—1.1
(ख) पूंजीगत	309	+153.3	146	—52.9	208 (138)	—32.7 (—55.3)	76 (146)	—65.5 (+5.8)
III. समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—) (I—II)	—431		—387		—631		—242	

नोट : 1. आंकड़े अंतर सरकारी अंतरणों के लिए समायोजित किये गये हैं। किन्तु समग्र संयुक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों में ऋणों को शेयर पूंजी में परिवर्तित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में 212 करोड़ रुपयों और भारत की आकस्मिकता निधि के अधीन (1971-72 और 1972-73 के दौरान) 70 करोड़ रुपयों की सैद्धांतिक पूंजीगत प्राप्तियां/वितरण शामिल नहीं हैं।

3. कुल प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों और समग्र अधिशेष/घाटे के जो आंकड़े इस सारणी में और सारणी 4 में दिये गये हैं वे पिछली वार्षिक रिपोर्टों में दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाएंगे, क्योंकि इस वर्ष के प्रारंभ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त शुद्ध अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों को (राज्य बजटों के अनुसार) वित्तपोषण के रूप में माना जाता है न कि पिछले वर्षों की तरह पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में।

*बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं।

सारणी 4:—राज्यों की समग्र बजट स्थिति

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1970–71 (लेखे)	1971–72 (बजट अनुमान)†	(1) की तुलना में (2) में हुई वृद्धि का प्रतिशत	1971–72 (परिणोधित अनुमान)†	(1) की तुलना में (3) में हुई वृद्धि का प्रतिशत	1972–73 (बजट अनुमान)*	(2) की तुलना में (4) में हुई वृद्धि का प्रतिशत
(I) कुल प्राप्तियां (अ+आ) . . .	52,14	55,91	+7.2	63,13	+12.1	65,26 (66,43)	+3.4
(अ) राजस्व प्राप्तियां (i+ii) . . .	35,19	40,26	+14.4	42,25	+20.1	44,62 (45,79)	+5.6
(i) राज्यों की निजी राजस्व प्राप्तियां .	21,97	24,17	+10.0	24,24	+10.3	24,46 (27,15)	+9.2
उनमें से							
कर प्राप्तियां . . .	15,28	16,42	+7.5	16,84	+10.2	18,53 (19,17)	+10.0
(ii) केन्द्रीय सरकार से अन्तरित किये गये वित्तीय साधन (क+ख) . .	13,22	16,09	+21.7	18,01	+36.2	18,16 (18,64)	+0.8
(क) करों का हिस्सा . .	7,56	9,01	+19.2	931	+23.1	10,10 (10,58)	+8.5
(ख) केन्द्रीय सरकार से अनुदान .	5,66	7,08	+25.1	870	+53.7	806	—7.4
(आ) पूंजीगत प्राप्तियां (i+ii) . . .	16,95	15,65	—7.7	20,88	+23.2	20,64	—1.1
(i) राज्यों की निजी पूंजीगत प्राप्तियां .	6,90	7,54	+9.3	771	+11.7	862	+11.8
उनमें से :							
बाजार ऋण (कुल) . .	1,65	1,52	—7.9	175	+6.1	188	+7.4
(ii) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण (कुल) .	10,05	8,11	—19.3	13,17	+31.0	12,02	—8.7
II. कुल वितरण	53,60	57,45	+7.2	65,59	+22.4	66,33	+1.1
उनमें से :							
(क) विकास परिव्यय	25,75	29,70	+15.3	30,65	+19.0	33,41	+9.0
(ख) विकासेतर परिव्यय . . .	15,19	16,50	+8.6	19,85	+30.7	19,20	—3.3
(ग) केन्द्रीय सरकार के ऋणों का भुगतान . .	6,34	5,64	—11.0	813	+28.2	785	—3.4
(घ) अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम . .	4,91	4,37	—11.0	581	+18.3	453	—22.0
(ङ) बाजार ऋणों का भुगतान . . .	59	75	+27.1	77	+30.5	84	9.1
III. समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—) (I—II) .	—1,46	—1,54		—246		—107 (+10)	

नोट : (1) यहां दिये गये आंकड़े बजट दस्तावेजों में दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते, क्योंकि यहां कतिपय समायोजन किये गये हैं। (2) सारणी 3 की पाद टिप्पणी (3) देखें ।

†इसमें बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है ।

*कोष्ठकों के आंकड़े 1972–73 के दौरान बजट प्रस्तावों से राज्यों को प्राप्त होनेवाली अनुमानित राशि और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त कराधान से राज्यों को मिलनेवाले हिस्से का हिसाब में लेने के बाद निकाले गये हैं ।

करोड़ रुपये की राशि का वितरण होगा वहां उसमें वास्तव में 814 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि कतिपय राज्यों को अकाल राहत के लिए (126 करोड़ रुपयों का) जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ा उससे विकासेतर परिव्यय में 335 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि हो गयी थी। छः राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने इस उद्देश्य के लिए 110 करोड़ रुपये खर्च किये। इसके विपरीत विकास परिव्यय में 95 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी। अन्य वितरणों में बजट अनुमानों की अपेक्षा 384 करोड़ रुपये की वृद्धि पायी गयी ; उक्त वितरण मुख्यतः केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों के शोधन (249 करोड़ रुपये) और दूसरी पार्टियों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों (144 करोड़ रुपये) के अधीन हुए ।

राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट

29. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया से निरन्तर ओवर ड्राफ्ट लिये जाने का उल्लेख किया गया था। 1971–72 (जुलाई-जून) के दौरान इस संबंध में स्थिति और बिगड़ गयी। 28 जून 1971 को राज्यों के बकाया ओवरड्राफ्टों की राशि 371 करोड़ रुपये थी (जब कि 27 जून 1970 को 6 राज्यों के नाम 82.7 करोड़ रुपयों के ओवरड्राफ्ट बकाया थे) और उक्त राशि अप्रैल 1972 के अंत में 642 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। 12 राज्यों ने अपने लेखों पर अधिक राशि ली थी। यद्यपि यह वृद्धि कुछ हद तक राज्यों द्वारा पिछले वर्षों के ओवरड्राफ्टों का शोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से लिये गये अर्थोपाय अग्रिमों की चुकौती का परिणाम थी फिर कुल राशि में और वृद्धि होना चिन्ताजनक था; क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले अनिधिकृत और अनियमितउधारों का व्यापक प्रभाव अर्थव्यवस्था के वित्तीय संतुलन पर पड़ता है। इसके साथ ही, राज्य सरकारों की वास्तविक आवश्यकताओं पूर्ति करने की, विशेष रूप से वित्तीय साधनों को बढ़ाने की उनकी सीमित क्षमता को देखते हुए व्यवस्था करनी पड़ी। केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को राज्यो द्वारा लिये जानेवाले भारी ओवरड्राफ्टों की समस्या और उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने संबंधित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों से इस मामले पर विचार विमर्श किया। इन विचार विमर्शों के

बाद और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से ओवरड्राफ्टों के संदर्भ में एक नयी नीति बनायी गयी ।

30. पहली मई 1972 से प्रभाव में लायी गयी नयी योजना के अधीन यह उपेक्षा की गयी कि अप्रैल 1972 के अंत से ओवरड्राफ्टों को समाप्त कर दिया जाए । राज्य सरकारों के बजट संबंधी लेनदेनों की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए रिजर्व बैंक से प्राप्त होनेवाले निर्बंध या गैर जमानती अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाओं को उक्त तारीख से पिछले स्तरों से चार गुना बढ़ा दिया गया। यह वृद्धि उस राशि के अतिरिक्त है जो उन्हें जमानती अग्रिमों से प्राप्त हो सकती है । 30 अप्रैल 1972 को कारोबार समाप्त होते समय रिजर्व बैंक की बहियों में विद्यमान बारहों राज्यों के ओवरड्राफ्टों का शोधन कर दिया गया । केन्द्रीय सरकार ने दस राज्यों को उनके ओवरड्राफ्टों के शोधन के लिए कुल 416 करोड़ रुपयों के विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किये और शेष राशि का समायोजन योजनागत सहायता (32 करोड़ रुपये) और आय कर में राज्यों के हिस्से के लिए 30 अप्रैल 1972 तक अदा की जानेवाली राशि (195 करोड़ रुपये) के संदर्भ में कर दिया गया

31. नयी नीति के अधीन रिजर्व बैंक केवल अधिक से अधिक 7 दिन की अस्थायी अवधियों को छोड़कर अन्यत्र ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं देता । यदि किसी राज्य सरकार का ओवरड्राफ्ट सात दिन से आगे जारी रहे तो ऐसी व्यवस्था की गयी है कि संबंधित राज्य की ओर से की जाने वाली अदायगी स्वयं ही बंद हो जाए। राज्यों पर खजाना संबंधी नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाये गये इन कदमों से यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारों का योजनागत और योजनेतर व्यय उपलब्ध वित्तीय साधनों के भीतर सीमित रह जाएगा ।

32. पहली मई 1972 से कोई भी राज्य सरकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास रहनेवाले अपने लेखे पर सात दिन से अधिक अवधि के लिए लगातार ओवरड्राफ्ट नहीं लेती रही है और उक्त अवधि के भीतर भी समय समय पर वास्तव में ली गयी ओवरड्राफ्ट राशि सामान्य ही थी । सामयिक रूप से लिये गये इन ओवरड्राफ्टों का कारण यह था कि संबंधित राज्य सरकारों को जो राशि वितरित करनी पड़ी उसका सही पूर्वानुमान नहीं किया जा सका । फिर भी सात दिन की समय सीमा के भीतर बिना किसी अपवाद के उन सभी ओवर ड्राफ्टों का शोधन कर दिया गया । इस प्रकार नयी नीति सफल और प्रभावकारी रही, फिर भी राज्यों की वित्तीय स्थिति में स्थायी रूप से सुधार लाने की व्यवस्था करना भी आवश्यक होगा । कुछ राज्यों ने हाल ही में अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिए आवश्यक उपायों की भी घोषणा की है ।

33. राज्यों की वित्तीय समस्याओं पर योजनागत और योजनेतर परिव्ययों के संदर्भ में विचार करना होगा । जून 1972 के अंत में नियुक्त किया गया छठा वित्त आयोग इससे संबंधित सभी प्रश्नों की जांच पड़ताल करेगा । आयोग के विचारणीय विषय पहले से अधिक व्यापक हैं । आयोग से की जाने वाली अपेक्षा का एक उदाहरण इस प्रकार है : आयोग 1973–74 के वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्यों के योजनेतर पूंजीगत वित्तीय साधनों राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन के परिशोधन से उत्पन्न भार और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किये गये ऋणों के शोधन व्यय का मूल्यांकन करेगा । यह भी आशा की जाती है कि आयोग प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित राज्यों के राहत-व्यय से संबंधित नीति और व्यवस्थाओं का भी पुनरीक्षण करेगा । अक्तूबर 1973 के अन्त तक आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध होने की आशा है ।

केंद्रीय सरकार की बजट संबंधी गतिविधियां—1971-72

34. केन्द्रीय सरकार के 1971-72 के बजट से सम्बन्धित गतिविधियों के संदर्भ में कुल व्यय में तेजी से वृद्धि हुई। कुल व्यय में इस वर्ष के दौरान 1146 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात उसकी राशि बढ़कर 6722 करोड़ रुपये* हो गयी (सारणी 5) । इस व्यय-वृद्धि की पूर्ति करने की दृष्टि से अक्तूबर और दिसंबर 1971 में नये कराधान की व्यवस्था कर अतिरिक्त व्यय वित्तीय साधन जुटाने के कई प्रयत्न किये इसके परिणाम स्वरूप सरकारी प्रशासन को प्राप्त 3819 करोड़ रुपयों की कुल राजस्व राशि बजट में अनुमानित राशि से 11 प्रतिशत अधिक थी । इस राशि में से कर राजस्व की राशि 2881 करोड़ रुपये थी । जो बजट अनुमान की अपेक्षा 181 करोड़ रुपये (या 6.7 प्रतिशत) अधिक थी । शरणार्थी सहायता के लिए प्राप्त विदेशी सहायता बजट अनुमान से लगभग 100 करोड़ रुपये अधिक थी ।

35. प्राप्तियों में एक ओर जहां यह सुधार हुआ तो वहां दूसरी ओर विकासेतर व्यय में प्रत्याशित 6 प्रतिशत की कमी के विपरीत पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इससे दोनों प्रायः संतुलित हो गये । उक्त व्यय-वृद्धि शरणार्थियों और रक्षा पर हुए व्यय तथा कतिपय राज्य सरकारों को विशेष रूप से अकाल-राहत के लिए दी गयी अतिरिक्त सहायता के कारण हुई । इसके विपरीत विकास व्यय में बजट अनुमान के मुकाबले में थोड़ी सी कमी हुई । उक्त कमी राज्य सरकारों की स्थिति के विपरीत थी जिसका विकास व्यय बजट अनुमानों से अधिक था । पूंजी निर्माण की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के वास्तविक परिव्यय की राशि बजट में व्यवस्थित राशि से 42 करोड़ रुपये कम थी । सरकारी प्रशासन की बचत राशि अर्थात् राजस्व प्राप्तियों और चालू व्यय के बीच का अंतर-केवल 95 करोड़ रुपये थी जब कि बजट में 242 करोड़ रुपयों की प्रत्याशा की गयी थी (सारणी 6) । इन सभी समायोजनों के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार की बजट स्थिति बिगड़ गयी और समग्र घाटे में बजट में अनुमानित 233 करोड़ रुपयों के मुकाबले में भारी वृद्धि हुई ।

1972-73 का बजट केंद्रीय सरकार

36. 1972-73 के बजट का यह लक्ष्य है कि पूंजी निर्माण की राशि तथा कुल बचत कोष में सरकार के अभिदान में वृद्धि की जाए और इस प्रकार 1971-72 की स्थिति में परिवर्तन लाया जाए । सरकारी क्षेत्र के योजनागत परिव्यय में 22 प्रतिशत या 710 करोड़ रुपयों की वृद्धि होने वाली है जिससे उसकी राशि बढ़कर 3973 करोड़ रुपये होगी । केन्द्रीय बजट में योजना के लिए की गयी 2569 करोड़ रुपये की व्यवस्था** से यह प्रत्याशा की जाती है कि उसमें 1971-72 के बजट अनुमानों की अपेक्षा 14.7 प्रतिशत वृद्धि होगी । सरकारी प्रशासन की बचतों में भी चार गुनी वृद्धि होने की आशा की जाती है ; विकासेतर व्यय में 7.6 प्रतिशत की कमी और विकास व्यय में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में 1971-72 में कुल व्यय में विकास व्यय का भाग जहां लगभग 47 प्रतिशत था वहां 1972-73 में यह आशा की जाती है कि उक्त व्यय 52 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा । योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार समाज सेवाओं (अर्थात् ग्रामीण नियोजन, ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण आवास आदि से सम्बन्धित समाज कल्याण योजनाएं) के व्यय का कुल व्यय अनुपात में 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो जाएगा । यह आशा की जाती है कि पूंजी निर्माण के

*केंद्रीय सरकार के व्यय (योजना के लिए की गयी व्यवस्था को छोड़कर) और उसकी प्राप्तियों के संबन्ध में यहां दिये गये आंकड़े भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये केंद्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण पर आधारित हैं ।

**विभागीय उपक्रमों के देशी स्रोतों और अन्य स्रोतों को मिलाकर योजना के लिए व्यवस्था की गयी राशि 2844 करोड़ रुपये होगी ।

सारणी 5:—केंद्रीय सरकार का विकास और विकासोतर व्यय

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1970–71 (लेखे)		1971–72 (बजट अनुमान)		1971–72 (परिशोधित अनुमान)		1972–73 (बजट अनुमान)	
	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत
कुल व्यय (अ+आ) . . .	55,76*	+13.2	58,74	+5.3	67,22	+20.6	68,69	+2.2
अ. विकास व्यय (i+ii) . .	26,59 (47.7)	+13.0	31,36 (53.4)	+17.9	31,24 (46.5)	+17.5	35,44 (51.6)	+13.4
(i) समाज सेवाएं . .	364 (6.5)	+19.7	578 (9.8)	+58.8	495 (7.4)	+36.0	663 (9.7)	+33.9
(ii) आर्थिक सेवाएं@ . .	22,95 (41.2)	+12.0	25,58 (43.6)	+11.5	26,29 (39.1)	+14.6	28,81 (41.9)	+9.6
आ. विकासोतर व्यय (i+ii) . .	29,17 (52.3)	+13.4	27,38 (46.6)	—6.1	35,98 (53.5)	+23.3	33.25 (48.4)	−7.6
(i) सामान्य सेवाएं . .	17,77 (31.9)	+19.2	16,27 (27.7)	—8.4	18,98 (28.2)	+6.7	19,09 (27.8)	+0.6
(ii) अनिर्धारणीय . .	11,40 (20.4)	+5.5	11,11 (18.9)	—2.6	17.00 (25.3)	+49.2	14,16 (20.6)	—16.7

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल व्यय में प्रतिशत को दर्शाते हैं ।

*इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को अदा की गयी 84 करोड़ रुपयों की अनुमानित प्रतिपूर्ति की राशि और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अविनिमय ब्याजमुक्त रुपया प्रतिभूतियों के रूप में किये गये 114 करोड़ रुपयों के अनुमानित अतिरिक्त अभिदान शामिल हैं।

@इनमें थोक अनुदान और ऋण शामिल हैं ।

सारणी 6 :—केंद्रीय सरकार की बचतें

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1970-71 (लेखे)	1971-72 (बजट अनुमान)	1971-72 (परिशोधित) (अनुमान)	1972-73 (बजट अनुमान)	स्तम्भ 3 की तुलना में स्तम्भ 4 में घट बढ़ का प्रतिशत
1. सरकारी प्रशासन की राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	31,33	3451	3819	4210	+10.2
(i) कर राजस्व	23,34	27,00	28,81	33,20	+15.2
(ii) करेतर राजस्व	699	7,51	9,38	8,90	5.1
2. चालू व्यय	29,09	32,09	37,24	37,24	—
3. सरकारी प्रशासन की बचतें (1+2) . .	2,24	2,42	95	4,86	+411.6
4. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यह्रास व्यवस्था और रख लिये गये लाभ (i+ii)	1,79	1,93	2,11	2,55	+20.9
(i) मूल्यह्रास व्यवस्था	1,23	1,31	129	1,37	+6.2
(ii) रख लिये गये लाभ	56	62	82	1,18	+43.9
5. केन्द्रीय सरकार की कुल बचतें (3+4) . .	4,03	4,35	3,06	7,41	+142.2
6. नवीकरण और प्रतिस्थापनों पर व्यय . . .	91	1,00	95	1,20	+26.3
7. वास्तविक बचतें (5—6)	3,12	3,35	2,11	6,21	+194.3
8. वास्तविक निवेश	4,28	5,42	5,16	6,04	+17.1
9. वास्तविक निवेश की तुलना में वास्तविक बचतों में वृद्धि (+) या कमी (—) (7—8) .	+ 1,16	+ 2,07	+ 3,05	+17	
10. मद 3 मद 1 के प्रतिशत के रूप में . . .	7.1	7.0	2.5	11.5	

लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता सहित 2441 करोड़ रुपयों की कुल पूंजी का निर्माण 1971-72 की अपेक्षा 12 प्रतिशत अधिक होगा और उसका अंश कुल व्यय का 36 प्रतिशत होगा जब कि यह 1971-72 में 32 प्रतिशत था। 1972-73 में व्यय में प्रत्याशित वृद्धि के बावजूद यह आशा की जाती है कि वास्तविक अतिरिक्त वित्तीय देयताएं 1971-72 की अपेक्षा कम होंगी यह आशा की जाती है कि 1972-73 में होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए राजस्व प्राप्तियों में लगभग 391 करोड़ रुपयों (1971-72 से 10.2 प्रतिशत अधिक) की वृद्धि कर व्यवस्था की जाएगी, इस संदर्भ में 3320 करोड़ रुपयों के कर राजस्व की राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि और करेतर राजस्व की राशि में 5 प्रतिशत की कमी परिलक्षित होगी।

37. 1972-73 के दौरान जुटाये जाने वाले अतिरिक्त वित्तीय साधनों पर 1971-72 में लागू किये गये कर संबंधी उपायों से प्रत्याशित राजस्व के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये। 1971-72 में शुरू किये गये प्रयत्नों से कुल प्राप्ति (राज्यों के अंश और रेलवे, डाक व तार विभागों द्वारा जुटाये गये वित्तीय साधनों को मिलाकर) की राशि पूरे वर्ष में 500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है; अब तक किसी भी वर्ष में इतनी वृद्धि नहीं हुई थी। 1972-73 में किये गये उपायों से यह आशा की जाती है कि वर्तमान वर्ष में कुल प्राप्ति की राशि 650 करोड़ रुपये हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप सरकारी प्रशासन की बचतों की राशि 1972-73 में 486 करोड़ रुपये होगी अर्थात उसमें 1971-72 की तुलना में 391 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी। दूसरे शब्दों में सरकारी प्रशासन की बचत राशियों में राजस्व प्राप्तियों का 11.5 प्रतिशत अंश सम्मिलित होगा जब कि 1971-72 में उनमें उक्त अंश 2.5 प्रतिशत था। इसके अलावा यह प्रत्याशा है कि उपक्रमों द्वारा रख ली गयी लाभ राशि और मूल्य ह्रास के लिये व्यवस्था की गयी राशि 1972-73 में लगभग 255 करोड़ रुपये होगी; इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की कुल बचत राशि 1971-72 के 306 करोड़ रुपयों से बढ़कर 741 करोड़ रुपये होगी। केन्द्रीय सरकार की वास्तविक बचत राशि (कुल बचत राशि में से नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर किये जाने वाले व्यय को घटाने पर) के बारे में यह अनुमान है कि वह 1972-73 में 621 करोड़ रुपये होगी जो वास्तविक प्रत्यक्ष निवेशों की अपेक्षा 17 करोड़ रुपये अधिक होगी।

राज्य सरकारें

38. राज्य सरकारों के 1972-73 के बजटों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: (क) कुल प्राप्तियों में (कराधान की 1971-72 की दर पर) 1971-72 में हुई लगभग 21 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1972-73 में 3.4 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा की जाती है। राज्य सरकारों को उनकी अपनी कर प्रणाली से प्राप्त होनेवाली राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है, जो 1971-72 में भी उतनी ही थी। फिर भी पूंजीगत प्राप्तियों में 1.1 प्रतिशत की जो सीमान्त कमी परिलक्षित होती है उसका कारण यह है कि केंन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों में जहां 1971-72 में 312 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी वहां इस वर्ष 115 करोड़ रुपये की कमी हो गयी थी। इस कमी की आंशिक पूर्ति बाजार ऋणों में वृद्धि कर, अन्य पार्टियों से ऋणों की वसूली कर और स्थानीय निकायों से ऋण लेकर की गयी। (ख) कुल वितरणों में जहां 1971-72 में 22 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी वहां 1972-73 में उनमें 1.1 प्रतिशत की सीमान्त वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। विकास परिव्यय में 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि विकासेतर परिव्यय में लगभग 3 प्रतिशत की कमी होगी। यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारों के समग्र घाटे की राशि 107 करोड़ रुपये होगी। यदि कतिपय राज्यों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों से प्रत्याशित 69 करोड़ रुपयों और केंन्द्रीय सरकार के नये कर संबंधी प्रयत्नों से राज्य सरकारों को प्राप्य उनके हिस्से के 48 करोड़ रुपयों को हिसाब में लिया जाए तो यह समग्र घाटा 10 करोड़ रुपयों* के अधिशेष में परिवर्तित हो जाएगा।

बाजार ऋण

39. उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम होगा कि 1971-72 में व्यय में जो अपार वृद्धि हुई उसके एक बहुत बड़े भाग की पूर्ति अतिरिक्त कर जुटाकर की गयी। इस संदर्भ में केंन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ऋणों का भी उल्लेख किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार लिये गये ऋणों में से प्राप्त वास्तविक राशि 1971-72 में संयुक्त रूप से 396 करोड़ रुपये थी अर्थात यह राशि 1970-71 की राशि की अपेक्षा 161 करोड़ रुपये अधिक थी। उक्त संपूर्ण वृद्धि केंन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये वास्तविक ऋणों में हुई जब कि राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ऋणों में केवल 1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। वास्तव में, 1971-72 में केन्द्रीय सरकार ने 295 करोड़ रुपयों के वास्तविक ऋण लिये जो बजट में की गयी व्यवस्था की अपेक्षा 127 करोड़ रुपये अधिक थे। केन्द्रीय सरकार ने 1971-72 के ऋण कार्यक्रम की एक विशेषता यह थी कि दिसंबर 1971 में आपात की घोषणा किये जाने पर तीन राष्ट्रीय रक्षा ऋण जारी किये गये जिनमें केवल नकदी में अभिदान स्वीकार किये गये; उक्त अभिदानों की कुल राशि 111 करोड़ रुपये थी। केन्द्रीय सरकार के 1972-73 के ऋण कार्यक्रम में प्रारंभ में 515 करोड़ रुपयों की कुल प्राप्तियों अथवा 215 करोड़ रुपयों की वास्तविक प्राप्तियों की परिकल्पना की गयी थी। जुलाई 1972 में जारी किये गये बाजार ऋण के पहले चरण में केन्द्रीय सरकार ने 132 करोड़ रुपयों (वास्तविक) के ऋण प्राप्त किये। बैंकिंग संघटन में जमा-राशियों और अग्रिमों के संबंध में हाल ही में पायी गयी प्रवृत्तियों को देखते हुए केंन्द्रीय सरकार ने 1972-73 के कुल बाजार ऋणों को बढ़ाकर 565 करोड़ रुपये अधिसूचित करने (623 करोड़ रुपयों तक के अभिदानों को रख लेने के अधिकार के साथ) अथवा 323 करोड़ रुपयों की शुद्ध राशि तक बढ़ाने का निश्चय किया; इसका तात्पर्य यह होगा कि उक्त ऋण राशि में बजट अनुमानों की अपेक्षा लगभग 100 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। राज्य सरकारों के 1972-73 के ऋणों की राशि भी 1971-72 के 101 करोड़ रुपयों से बढ़कर 133 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। अल्प बचतों के अंतर्गत यह आशा की जाती है कि 1972-73 में 230 करोड़ रुपयों का वास्तविक संचय होगा जब कि 1971-72 में 210 करोड़ रुपयों का संचय हुआ था।

बचत और निवेश

40. पूंजीगत लेखे से प्राप्त अन्य राशियों और इन निधियों की सहायता से केंन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से तथा राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों और विभागेतर उपक्रमों को दी गयी सहायता के द्वारा 1971-72 में 2081 करोड़ रुपयों की वास्तविक पूंजी के निर्माण के लिए वित्त-पोषण कर सकी। उक्त राशि 1970-71 की तुलना में 368 करोड़ रुपये अधिक थी (सारणी 7)।

41. भारत सरकार द्वारा 1972-73 में वास्तविक पूंजी निर्माण पर किये जाने वाले इसी प्रकार के व्यय की अनुमानित राशि 2321 करोड़ रुपये होगी जो पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में 240 करोड़ रुपये अधिक होगी।

---

*यदि महाराष्ट्र द्वारा जारी किये जानेवाले बाजार ऋणों से होनेवाली प्राप्तियों को हिसाब में लिया जाए तो 1972-73 के समग्र अधिशेष की यह राशि और अधिक होगी। इस राज्य सरकार ने अपने बजट में इस मद को हिसाब में नहीं लिया है।

सारणी 7 :—भारत सरकार द्वारा पूंजी-निर्माण पर किया गया व्यय

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72 (परिशोधित अनुमान)	1972-73 (बजट अनुमान)
1. कुल पूंजी निर्माण	2,76	3,93	5,19	6,11	7,24
(क) अचल पूंजी निर्माण	4,49	4,30	4,85	5,92	7,57
(ख) स्टाक	—1,73	—37	34	19	—33
2. वास्तविक पूंजी निर्माण (अर्थात् नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर किये गये व्यय को छोड़कर)	1,93	3,18	4,28	5,16	6,04
3. पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	13,84	12,19	12,85*	15,65	17,17
(क) राज्यों, संघशासित क्षेत्रों, आदि को	7,61	7,75	8,37	10,07	10,43
(ख) विभागेतर वाणिज्यिक उपक्रमों को	6,23	4,44	4,48	5,58	6,74
(I) वित्तीय	—	42	70	71	1,03
(II) अन्य	—	4,02	3,78	4,87	5,71
जोड़ (2+3)	15,77	15,37	17,13	20,81	23,21

*राष्ट्रीयकृत बैंकों को अदा की गयी प्रतिपूर्ति की राशि को छोड़कर।

42. राज्यों की बचत राशि और उनके द्वारा पूंजी निर्माण पर किये जाने वाले व्यय के तदनुरूप आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं है; अतः सरकारी क्षेत्र के संबंध में समग्र रूप से कोई प्राक्कलन नहीं दिया जा सकता। फिर भी सारणी 4 से यह मालूम होगा कि राज्य सरकारों के कुल विकास परिव्यय (राजस्व और पूंजीगत दोनों लेखों पर) की राशि 1971-72 में पिछले वर्ष की राशि से केवल 490 करोड़ रुपये अधिक थी। चूंकि राज्य सरकारों के विकास व्यय का अधिकांश भाग लिया सार्वजनिक स्वास्थ्य, नगर निर्माण-कार्य आदि पर किये गये चालू व्यय से सम्बन्धित है, अतः इस व्यय वृद्धि का केवल एक छोटा-सा अंश पूंजी निर्माण के लिये किये गये व्यय से सम्बन्धित है। केन्द्रीय सरकार से किये गये पूंजीगत अंतरण द्वारा ऐसे अधिकांश पूंजी निर्माण का वित्त-पोषण हुआ; राज्यों ने अपनी तरफ से सरकारी क्षेत्र की अतिरिक्त बचत राशियों में वृद्धि कर संभवतः इस संदर्भ में बहुत थोड़ा ही योगदान किया।

43. हिन्दुस्तान स्टील, हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन और हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों को हुई भारी हानि को देखते हुए यह संभव प्रतीत होता है कि सरकारी बचत राशियों में समग्र रूप से और सापेक्ष रूप से भी कमी हुई होगी। फिर भी केन्द्रीय सरकार से भारी मात्रा में प्राप्त ऋणों और अनुदानों तथा ओवरड्राफ्टों के आधार पर राज्य सरकारों और विभागेतर उपक्रमों ने अपने निवेश परिव्यय को अवश्य ही बनाये रखा और संभवतः उसमें थोड़ी-सी वृद्धि भी की।

44. गैर-सरकारी क्षेत्र के संदर्भ में भी उपलब्ध विवरणों से यह विदित होगा कि 1971-72 में उनके निवेश की मात्रा संभवतः पिछले वर्ष से अधिक थी। गैर-बैंकिंग सार्वजनिक समिती कंपनियों को नये पूंजीगत शेयर जारी करने के लिये मंजूर की गयी स्वीकृतियों में भी वृद्धि हुई। ऐसे शेयरों के बाजार में जहां पिछले वर्ष मंदी पायी गयी थी वहां इस वर्ष सुधार हुआ। उनके शेयरों के प्रति जनता का रुझान संतोषजनक था और उनमें से कुछ शेयरों में अधिक अभिदान हुआ। वित्तीय ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित किये गये ऋणों में इस वर्ष के दौरान और वृद्धि पायी गयी। कृषि क्षेत्र में इस वर्ष (जुलाई 1971–जून 1972) कृषि पुनर्वित्त निगम, कृषि वित्त निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से और रिजर्व बैंक के मध्यावधि ऋणों के आहरणों तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों से निवेश के लिये उपलब्ध कुल वित्त से यह दिखाई देता है कि कृषि-निवेश की गति की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बनाए रखा गया है (सारणी 8)।

45. पिछले पैराग्राफों से उभरने वाला प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। जहां 1971-72 में सरकारी बचत पहले से कम थी वहां सरकारी निवेश व्यय में थोड़ी सी वृद्धि हुई। उपलब्ध विवरणों से यह भी पता चलता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश रूप से कृषि और लघु उद्योगों के क्षेत्र में शायद वृद्धि हुई। कंपनियों की बचतों में जो कोई थोड़ी सी वृद्धि हुई होगी उसे छोड़कर निवेशों में हुई वृद्धि के अधिकांश भाग का वित्तपोषण अंशतः विदेशी बचतों से प्राप्त राशियों से, किंतु अधिकांशतः घरेलू क्षेत्र की बचतों में विशेष रूप से वित्तीय आस्तियों के रूप में हुई वृद्धि के द्वारा किया गया।

46. वित्तीय आस्तियों के रूप में घरेलू बचतों में हुई वृद्धि जमा-राशियों, चलमुद्राओं, भविष्य निधियों और जीवन बीमा के अंशदानों, अल्प बचतों और कंपनियों के पूंजीगत शेयरों के अभिदानों में हुई वृद्धि में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। यह बात विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय है कि इससे यह द्योतित होता है कि अर्थ व्यवस्था में बचत राशियों के वितरण के संदर्भ में काफी अधिक लचीलापन विद्यमान है। इस तथ्य का और अच्छा मूल्यांकन करने के लिए मुद्रा क्षेत्र की घट-बढ़ के विवरणों पर ध्यान देना आवश्यक है।

मुद्रा और बैंकिंग सम्बन्धी गतिविधियां

मुद्रा उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां

47. 1971-72 (जुलाई-जून) की मुद्रा संबंधी प्रवृत्तियों से यह दिखाई देता है कि जनता के पास रहने वाली मुद्रा तथा कुल मुद्रागत साधनों के विस्तार की गति में तीव्रता आयी है। जनता के पास रहने वाली मुद्रा में पिछले वर्ष के 12.5 प्रतिशत की तुलना में 1971-72 में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई; कुल मुद्रागत साधनों के विस्तार की तदनुरूपी दरें क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत थीं। मुद्रा की उपलब्धि में इस वर्ष हुए विस्तार की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि पिछले वर्ष के विपरीत जमा राशि में हुई वृद्धि (592 करोड़ रुपये) चलमुद्रा घटकों में हुई वृद्धि (123 करोड़ रुपये) की अपेक्षा काफी अधिक थी।

सारणी 8 :—कृषि निवेश के लिए संस्थागत वित्त

(जुलाई–जून) (राशि करोड़ रुपयों में)

	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66
1. केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचर[1]						
(क) सामान्य डिबेंचर	9.97	10.50	19.25	23.34	34.81	43.10
(ख) ग्रामीण डिबेंचर	1.55	2.24	1.57	1.84	3.23	4.33
2. कृषि पुनर्वित्त निगम (कृपुनि)[2]						
(क) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या				3	10	24
(ख) कुल वित्तीय सहायता				2.72	20.60	17.96
(ग) कृपुनि के बायदे				2.45	16.88	14.18
(घ) वर्ष के दौरान वितरण				—	0.45	4.45
3. कृषि वित्त निगम (कृवित्नि)[3]						
(क) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या						
(ख) कुल परिव्यय						
(ग) वर्ष के दौरान वितरण						
4. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्राविनि)						
(क) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या[4]						
(ख) कुल परिव्यय						
(ग) ग्राविनि के बायदे						
(घ) वर्ष के दौरान वितरण						
5. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया—मध्यावधि ऋण						
(क) मन्जूर की गयी राशि	4.68	9.56	9.31	14.01	14.39	14.11
(ख) वर्ष के दौरान आहरण	5.69	7.39	4.18	7.45	7.91	7.45

नोट :—इस सारणी में निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये निवेश वित्त के आंकड़े शामिल नहीं हैं; क्योंकि वे उपलब्ध नहीं हैं।

(क) केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों में अभिदान और कृषि वित्त निगम के साथ सहभागिता के रूप में प्रदान किये गये वित्त को छोड़कर वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदान किया गया मीयादी वित्त।

(ख) सहकारी ऋण एजेन्सियों द्वारा उनकी अपनी निधियों से प्रदान किया गया निवेश वित्त।

1. सहकारी भूमि बंधक विकास बैंकों ने भी 1961-62 में 18.00 लाख रुपयों, 1963-64 में 5.41 लाख रुपयों, 1965-66 में 1.45 लाख रुपयों 1966-67 में 1.23 लाख रुपयों 1967-68 में 0.32 लाख रुपयों और 1968-69 में 0.18 लाख रुपयों तक के विशेष विकास ऋण जारी किये। विशेष विकास ऋणों की पहली शृंखलाएं जहां कृपुनी की स्थापना के पहले जारी की गयी थीं वहां शेष शृंखलाएं कृपुनि की योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आयीं।

2. इसके कार्यकलाप वर्ष के दौरान वापस ली गयी योजनाओं को छोड़ देने के बाद वर्ष के दौरान मंजूर की गयी योजनाओं से सम्बन्धित है।

सारणी 8 :—कृषि निवेश के लिए संस्थागत वित्त (जारी)

(जुलाई–जून)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
1. केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक/विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचर[1]						
(क) सामान्य डिबेंचर	52.05	64.51	103.42	114.82	119.49	127.81
(ख) ग्रामीण डिबेंचर	2.93	1.57	5.00	1.10	4.78	5.72
2. कृषि पुनर्वित्त निगम (कृपुनि)[2]						
(क) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या	15	89	108	142	100	269
(ख) कुल वित्तीय सहायता	10.53	68.16	79.21	92.78	62.15	154.24
(ग) कृपुनि के वायदे	8.53	58.64	69.32	70.92	53.92	135.13
(घ) वर्ष के दौरान वितरण	2.08	5.67	17.85	28.60	30.62	34.98
3. कृषि वित्त निगम (कृवित्तनि)[3]						
(क) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या			6	21	10	6
(ख) कुल परिव्यय			61.50	45.70	23.33	25.12
(ग) वर्ष के दौरान वितरण			0.96	15.77	13.24	11.22
4. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्राविनि)						
(क) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या[4]				47†	73†	127
(ख) कुल परिव्यय				30.91†	49.15†	83.65
(ग) ग्राविनि के वायदे				28.95†	48.82†	73.25
(घ) वर्ष के दौरान वितरण				—	26.09†	36.81
5. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया—मध्यावधि ऋण						
(क) मंजूर की गयी राशिएं	15.49	16.57	19.00	18.30	18.76	20.62
(ख) वर्ष के दौरान आहरण	8.37	9.12	8.98	11.48	14.20	6.15@

[3]. यहां दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान मंजूर की गयी योजनाओं से सम्बन्धित हैं, उनमें इसी वर्ष यदि कोई योजना वापस ली गयी हो परिव्यय में कोई परिवर्तन किया गया हो तो उसे हिसाब में लिया गया है परन्तु बाद में यदि कोई योजना रद्द की गयी हो और परिव्यय में कोई परिवर्तन किया गया हो तो हिसाब में नहीं लिया गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगम ने अपनी स्थापना अर्थात् 10 अप्रैल 1968 से लेकर 30 जून 1972 तक 39 योजनाएं मंजूर की हैं जिनके कुल परिव्यय की राशि 153.20 करोड़ रुपये थी और 41.19 करोड़ रुपयों का वितरण किया है।

4. इनमें से 1969-70 में तीन योजनाएं और 1970-71 में दो योजनाएं ग्रामीण विद्युत् सहकारी समितियों से सम्बन्धित हैं।

†परिशोधित।

@1971-72 में रिजर्व बैंक की मध्यावधि ऋण सीमाओं में से आहरित की गयी राशि पिछले वर्ष की राशि से कम है; इसका मुख्य कारण यह है कि परिशोधित व्यवस्था के अनुसार 1971-72 की सीमाओं में से दिसम्बर 1972 तक आहरित करने की अनुमति दी गयी है।

48. सरकार को बैंकों द्वारा दिये गये वास्तविक ऋणों में हुई 1176 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि (1970-71 के 931 करोड़ रुपयों के मुकाबले में) इस मुद्रागत विस्तार का मुख्य कारण थी। जैसा कि पिछले पैराग्राफों में कहा जा चुका है, उपर्युक्त ऋण वृद्धि सरकार के बजट में विद्यमान व्यापक खाई की परिचायिका थी।* बैंकिंग संघटन के विदेशी लेनदेनों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा आस्तियों में (जिनमें पिछले वर्ष 95 करोड़ रुपये की कमी हुई थी) 29 करोड़ रुपयों की जो वास्तविक वृद्धि हुई उसके कारण भी मुद्रा की उपलब्धि में थोड़ी-सी वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों में 788 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की वृद्धि से 67 करोड़ रुपये अधिक थी। फिर भी चूंकि वाणिज्यिक क्षेत्र को प्रदान किये गये ऋणों की राशि बैंकों द्वारा जुटाई गयी मीयादी जमाराशियों (786 करोड़ रुपये) से केवल 3 करोड़ रुपये अधिक थी अतः बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये वास्तविक ऋणों का मुद्रा-उपलब्धि पर नाममात्र का विस्तारात्मक प्रभाव पड़ा (सारणी 9)।

मौसमी प्रवृत्तियां

49. मुद्रा सम्बन्धी स्थिति की इन विशेषताओं का प्रभाव मौसमी प्रवृत्तियों में भी पाया गया। 1971 के (मई से अक्तूबर तक के) परंपरागत कम कामकाज के समय में जनता के पास रहनेवाली मुद्रा में लगातार दूसरे वर्ष भी वृद्धि हुई; 162 करोड़ रुपयों की यह वृद्धि पिछले कम कामकाज के समय की वृद्धि से कुछ अधिक थी। यह पूरी वृद्धि जमाराशियों में हुई थी जब कि चलमुद्रा घटकों में कमी दिखाई पड़ी। जैसा कि सारणी 10 में दिखाया गया है, अधिकतर बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये अतिरिक्त ऋणों और कुछ सीमा तक विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप यह वृद्धि हुई। बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये कुल ऋणों के कारण मुद्रा की उपलब्धि कमी में आयी।

50. मुद्रा की उपलब्धि में 1971-72 के अधिक कामकाज के समय (नवम्बर 1971–अप्रैल 1972) में 779 करोड़ रुपयों (10.5

*इस वर्ष के दौरान किये गये कतिपय लेखा समायोजनों के कारण 'बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण' में 1101 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जब कि उक्त वृद्धि 1970-71 में 831 करोड़ रुपये थी; किन्तु 1971-72 में वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियों में केवल 6 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। इन लेखा समायोजनों से 'मुद्रा उपलब्धि' के आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

सारणी 9 :—मुद्रा उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां (वार्षिक)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	जून के अन्त में बकाया			जुलाई–जून के दौरान घट-बढ़		
	1970	1971	1972	1969-70	1970-71	1971-72
1. जनता के पास चलमुद्रा	41,70	45,91	50,14	+3,81	+4,21	+4,23
2. मांग जमाराशियां	24,65	28,71	34,63	+2,11	+4,06	+5,92
3. मुद्रा-उपलब्धि (1+2)	66,34	74,62	84,78	+5,91	+8,28	+10,16
4. मीयादी जमाराशियां	30,98	36,60	44,46	+4,19	+562	+7,86
5. कुल मुद्रागत साधन (3+4)	93,33	1,11,22	1,29,24	+10,11	+13,89	+18,02
6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण	48,24	57,55	69,31	+2	+931	+11,76
7. बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियां	6,64	5,69	5,98	+2,64	—95	+29
8. जनता के प्रति सरकार की वास्तविक चलमुद्रा देयताएं	3,74	3,95	4,05	+20	+21	+11
9. जोड़ (6+7+8)	58,62	67,19	79,34	+2,86	+8,57	+12,15
10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण*	50,27	57,48	65,36	+7,55	+7,21	+7,88
(क) बैंकों द्वारा वाणिज्यक क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण*	19,29	20,87	20,90	+3,36	+1,58	+3
11. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की वास्तविक मुद्रेतर देयताएं (वृद्धि—)	6,40	8,17	10,66	—60	—1,77	—2,49
12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुद्रेतर देयताएं (वृद्धि—)	5,17	5,27	4,82	+29	—10	+45
13. जोड़ (9+10)	1,08,89	1,24,67	1,44,70	+10,41	+15,78	+20,03

*इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को वाणिज्य उद्देश्यों के लिए दिये अग्रिम शामिल हैं।

नोट :—इस वर्ष के दौरान किये गये कतिपय लेखा-समायोजनों के कारण "बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण" में 1101 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि उक्त वृद्धि 1970-71 के दौरान 831 करोड़ रुपये थी। इन लेखा-समायोजनों का 'मुद्रा-उपलब्धि' के आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि एक लेखे के विस्तारात्मक प्रभाव को दूसरे लेखे के संकुचनात्मक प्रभाव द्वारा संतुलित करने की दृष्टि से उक्त समायोजन किये गये हैं। फिर भी उक्त समायोजनों के कारण बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र को दिये गये वास्तविक ऋणों में 1971-72 में 75 करोड़ रुपयों और 1970-71 (जुलाई–जून) में 100 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1971-72 के दौरान 23 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की मुद्रेतर देयताएं 1971-72 में हुई 98 करोड़ रुपयों और 1970-71 में हुई 100 करोड़ रुपयों की कमी का कारण थीं।

प्रतिशत) की जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज में हुई 581 करोड़ रुपयों (8.7 प्रतिशत) की वृद्धि से काफी अधिक थी। चल मुद्रा घटकों में जहां पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, वहां जमाराशियों में हुई वृद्धि लगभग दुगनी थी। इसके अलावा, बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋणों में हुई 820 करोड़ रुपयों की वृद्धि भी पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक थी। फिर भी बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को प्रदान किये गये वास्तविक ऋणों में हुई वृद्धि पिछले अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा काफी कम थी जिसका मुख्य कारण यह था कि अनाजों की उगाही के लिए दिये गये ऋणों में 71 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी (सारणी 10)।

51. 1972 के कम कामकाज के समय के पहले दो महीनों में जनता के पास रहनेवाली मुद्रा में उसी प्रकार वृद्धि हुई जैसे पिछले कम कामकाज की तदनुरूपी अवधि में हुई थी। बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋणों में हुई भारी वृद्धि उक्त वृद्धि का प्रमुख कारण थी। बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋणों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में हुई कमी की तुलना में इस वर्ष जो थोड़ी सी वृद्धि हुई यह भी मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि का कारण थी।

मुद्रा उपलब्धि के घटकों और कुल मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां

52. पिछले तीन वर्षों की उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि मुद्रा-उपलब्धि की वृद्धि में चलमुद्रा का अनुपात घटता रहा है। इस

सारणी 10 :—मुद्रा-उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रुपयों में)

	निम्नलिखित समय के दौरान घट-बढ़			
	कम कामकाज का समय		अधिक कामकाज का समय	
	1970	1971	1970-71	1971-72
1. जनता के पास चलमुद्रा	—35	—33	+405	+442
2. मांग जमा राशियां	+178	+193	+178	+339
3. मुद्रा-उपलब्धि (1+2)	+144	+162	+581	+779
4. मीयादी जमाराशियां	+277	+435	+261	308
5. मुद्रागत साधन (3+4)	+421	+597	+842	+1087
6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण	+111	+388	+607	+820
7. बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियां	+ 36	+26	+84	+14
8. जनता के प्रति सरकार की वास्तविक चलमुद्रा देयताएं	+ 6	+ 6	+16	+7
9. जोड़ (6+7+8)	+153	+420	+539	+841
10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण*	+346	+249	+478	+433
10. (क) बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण*	+ 70	—187	+216	+126
11. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वास्तविक मुद्रेतर देयताएं (वृद्धि—)	+ 27	—101	—113	+223
12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुद्रेतर देयताएं (वृद्धि—)	—106	+ 30	— 61	+34
13. जोड़ (9+10)	+499	+669	+1017	+1274

*इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दिये गये अग्रिम शामिल हैं।

प्रकार मुद्रा-उपलब्धि की वृद्धि में 1968–69@ में चलमुद्रा का अंश 71 प्रतिशत था ; तब से यह अनुपात क्रमशः कम होता हुआ 1971–72 में 47 प्रतिशत रह गया है (सारणी 11) । यदि चलमुद्रा की वृद्धि दर की कुल मुद्रागत साधनों की वृद्धि दर से तुलना की जाए तो वहां भी यही प्रवृत्ति दिखाई देगी (सारणी 12) । एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैंकों के पास रहनेवाली कुल राशि के दो घटकों (अर्थात चालू जमाराशियों और बचत जमाराशियों में से मांग जमाराशियों का अंश) में से बचत जमाराशियों की वृद्धि दर चालू जमाराशियों की वृद्धि दर की अपेक्षा कुछ वर्षों से अधिक रही है । 1971–72 में मुद्रा-उपलब्धि की वृद्धि में बैंकों के पास रहनेवाली कुल राशि का भाग 53 प्रतिशत था ; इस वृद्धि में से बचत जमाराशियों और चालू जमाराशियों का भाग क्रमशः 35 प्रतिशत और 17 प्रतिशत था । चलमुद्रा विस्तार की जो धीमी गति पायी गयी उसके दो कारण बताये जा सकते हैं: विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि के अनुरूप चलमुद्रा के लेनदेनों से सम्बन्धित मांग में समग्र रूप से वृद्धि हुई है । इसके साथ ही और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में सामान्यतः अपनी बचतराशियों को चलमुद्रा के रूप में रखने की जो प्रवृत्ति थी वह उनमें से कुछ लोगों में नहीं रह गयी है और बैंकों में अपनी बचत राशियों को रखने की प्रवृत्ति उनमें पैदा हो गयी है । यह तथ्य बैंकों के पास रहने वाली कुल राशि के संदर्भ में बचत जमाराशियों के बढ़ते हुए अनुपात से प्रमाणित होता है । दूसरे शब्दों में, देश में बैंकिंग संबंधी सेवाओं का तेजी से विस्तार होने के कारण जनता में अपनी आस्तियों को चलमुद्रा के स्थान पर जमाराशियों के रूप में रखने की प्रवृत्ति आ गयी है । परंतु यह कहना मुश्किल है कि इसका कारण बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण उत्पन्न सुरक्षा की भावना है अथवा ब्याज से प्राप्त होनेवाली आय का आकर्षण है । शायद दोनों कारणों से जनता की प्रवृत्ति में उक्त परिवर्तन आया है और बैंकिंग संबंधी नीतियों का निर्धारण करते समय इन बातों को ध्यान में रखना होगा ।

@इस पैराग्राफ में दिये गये आंकड़े वित्तीय वर्षों से संबंधित हैं ।

सारणी 11:—मुद्रा-उपलब्धि और उसके घटकों के बीच सीमान्त सम्बन्ध

वित्तीय वर्ष	बैंकों के पास रहने वाली राशि					वृद्धि की दरें			
	मुद्रा-उपलब्धि	चलमुद्रा	जोड़	चालू जमा	बचत जमा	मुद्रा-उपलब्धि	चलमुद्रा	वाणिज्य बैंकों की चालू जमाराशियां	बचत जमा-राशियों में मांग जमा-राशियों का अंश
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(1) करोड़ रुपये								
1961–62 . .	+177(100)	58.2	41.8	18.6	19.2	6.2	4.9	6.0	18.6
1962–63 . .	+264(100)	67.4	32.6	15.9	14.0	8.7	8.1	7.2	17.1
1963–64 . .	+442(100)	51.4	48.6	9.5	36.4	13.4	9.5	6.7	63.4
1964–65 . .	+328(100)	49.7	50.3	20.7	30.2	8.7	6.3	10.2	23.9
1965–66 . .	+449(100)	59.0	41.0	12.0	29.6	11.0	9.6	7.4	25.9
1966–67 . .	+421(100)	38.7	61.3	22.6	30.6	9.3	5.4	12.1	19.9
1967–68 . .	+400(100)	44.8	55.2	18.5	30.5	8.1	5.6	8.4	15.7
1968–69 . .	+429(100)	71.3	28.7	12.4	8.6	8.0	9.1	5.5	4.1
1969–70 . .	+608(100)	53.9	45.9	24.8	24.7	10.5	8.9	15.0	16.0
1970–71 . .	+749(100)	49.3	50.7	25.0	27.0	11.7	9.2	16.1	18.6
1971–72 . .	+906(100)	47.0	53.0	17.0	34.7	12.7	9.7	11.4	24.4

नोट: 1. स्तंभ (1) में दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान हुए समग्र परिवर्तनों को दर्शाते हैं । स्तंभ (2) से (5) तक में दिये गये आंकड़े स्तंभ (1) के % हैं ।

2. बैंकों के पास रहने वाली कुल जमाराशियां चालू और बचत जमाराशियों के जोड़ से नहीं बनतीं क्योंकि रिज़र्व बैंक के पास रहने वाली "अन्य जमाराशियां" और राज्य सहकारी बैंकों की वास्तविक मांग देयताएं कुल जमाराशियों में शामिल की गयी हैं ।

सारणी 12 :—मुद्रागत साधन और चलमुद्रा

(राशि करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	मुद्रागत साधन* (पी० एल० 480 को छोड़कर)	चलमुद्रा	मुद्रागत साधनों में वृद्धि	चलमुद्रा में वृद्धि	चलमुद्रा-मुद्रागत साधन (सीमांत अनुपात) (स्तंभ (4) स्तंभ (3) के % के रूप में)
	1	2	3	4	5
1961–62	4102	2201	315	103	32.6
1962–63	4461	2379	359	178	55.2
1963–64	4976	2605	514	226	44.0
1964–65	5477	2769	501	163	32.6
1965–66	6134	3034	657	265	40.4
1966–67	6816	3196	682	162	23.8
1967–68	7460	3376	643	179	27.8
1968–69	8306	3681	845	305	36.2
1969–70	9336	4010	1030	328	31.9
1970–71	10571	4378	1234	369	29.9
1971–72	12233	4806	1661	426	25.6

*मुद्रा-उपलब्धि और बैंकों के पास रहनेवाली मीयादी जमाराशियां ।

बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियां और ऋण नीति

वार्षिक घटनाएं—जुलाई 1971–जून 1972

53. 1971–72 के दौरान हुई एक अन्य महत्वपूर्ण घटना यह थी कि बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में हुई वृद्धि की अपेक्षा उनकी जमाराशियों में अधिक तेजी से वृद्धि होने के कारण बैंक संघटन की चलमुद्रा स्थिति बहुत ही संतोषजनक थी । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में (चालू दरों पर) 1307 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात उनमें 21 प्रतिशत की अभूतपूर्व दर पर वृद्धि हुई जबकि 1970-71 में उनमें 942 करोड़ रुपये या 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । उच्चतर दर पर जमाराशियों में जो वृद्धि हुई वह अन्य कारणों के साथ 1970-71 की अपेक्षा 1971–72 में पर्याप्त अधिक मात्रा में सरकारी घाटा होने और जैसा कि इसके पहले कहा जा चुका है, आस्तियों के संदर्भ में जनता की रुचि में परिवर्तन आ जाने के कारण भी हुई ।

54. इस वर्ष अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋणों की कुल राशि में 614 करोड़ रुपयों (12.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष उसमें 550 करोड़ रुपयों (13.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । अनाजों की उगाही से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए दिये गये अग्रिमों में 1970–71 में हुई 172 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 164 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई; इसके परिणामस्वरूप अनाजों की उगाही के लिए दिए गए अग्रिमों को छोड़कर आलोच्य वर्ष में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में हुई वृद्धि पहले की अपेक्षा अधिक थी अर्थात वृद्धि की राशि पिछले वर्ष के 378 करोड़ रुपयों (9.4 प्रतिशत) के मुकाबले में इस वर्ष 451 करोड़ रुपये (10.3 प्रतिशत) थी (सारणी 13) ।

55. आलोच्य वर्ष में वाणिज्य बैंकों का केवल ऋण-जमा-अनुपात कम नहीं था बल्कि उनका नकदी अनुपात भी कम था । बैंकों के मुद्रागत साधनों की स्थिति सुधर गयी थी; अतः वे सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये जानेवाले अपने निवेशों की मात्रा को बढ़ा सके और रिज़र्व बैंक से लिये गये ऋणों को चुकाकर अपने ऋण भार को कम कर सके । इस प्रकार आलोच्य वर्ष में बैंकों ने अपने निवेशों को बढ़ाने के लिए 433 करोड़ रुपयों का उपयोग किया और इस तरह जून 1972 के अंत में उनका निवेश-जमा अनुपात बढ़कर 29.8 प्रतिशत हो गया । इसके अलावा उन्होंने रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को 165 करोड़ रुपयों के ऋण चुका दिये और इससे उनके द्वारा लिये गये ऋणों का स्तर जून 1972 के अंत में कम होकर 42 करोड़ रुपये हो गया जब कि उक्त स्तर एक वर्ष पहले 207 करोड़ रुपये था । वाणिज्य बैंकों की संतोषजनक चलमुद्रा स्थिति के परिणामस्वरूप बोली जमा दरें भी कम हो गयी । बंबई में उनकी सर्वोच्च दर पिछले वर्ष से तीन प्रतिशत से अधिक कम थी । जून 1972 के अंत में उक्त दर पिछले वर्ष के $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत के मुकाबले में $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 4 प्रतिशत के बीच थी ।

1971-72 के अधिक कामकाज के समय के लिये ऋण नीति

56. 1971 के कम कामकाज के समय में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में पहली बार 624 करोड़ रुपयों की जो भारी वृद्धि हुई, उसके कारण बैंकिंग संघटन ऋणों में 163 करोड़ रुपयों (अनाजों की उगाही के लिए दिये गये ऋणों में 156 करोड़ रुपयों) की वृद्धि होने के बावजूद, उसके बाद आने वाले अधिक कामकाज के समय (नवम्बर 1971–अप्रेल 1972) में उपयोग में लाने के लिए निधियों को सुरक्षित रख सका । बैंकों ने सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये जानेवाले अपने निवेशों में 249 करोड़ रुपयों की वृद्धि की और रिज़र्व बैंक से लिये गये ऋणों के लिए 172 करोड़ रुपये चुकाकर अपने ऋण भार को कम कर दिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से लिए गये ऋणों का स्तर उक्त समय के अन्त में पिछले वर्ष के 151 करोड़ रुपयों के मुकाबले में केवल 19 करोड़ रुपये और उनका ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात (77.0 प्रतिशत) से काफ़ी कम (73.1 प्रतिशत था। 1971-72 के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ में बैंकों की चलमुद्रा स्थिति अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक थी ; अतः बैंक ऋणों की प्रत्याशित मांग की पूर्ति करने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। फिर भी बैंकिंग संघटन के प्रति सरकार की कर्जदारी में हुई भारी वृद्धि के कारण ऋण वितरण के संदर्भ में सावधानी बरतने की आवश्यकता थी ताकि मूल्यों पर दबाव न पड़े। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की सुरक्षा

सारणी 13 :—बैंक व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों में वार्षिक घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपयों में)

	जून 1969 के अंत में	जून 1969 को समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	जून 1970 के अन्त में	जून 1970 को समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)	जून 1971 के अंत में	जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)	जून 1972 के अंत में	जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (—)
1. कुल बैंक ऋण	35,98.8	—49,5.9	42,12.7	+6,13.9	+17.1	47,62.9	+5,50.2	+13.1	53,77.1	+6,14.2	+12.9
उनमें से :											
(क) अनाजों की उगाही के लिये दिये गए ऋण	2,33.2	+41.1	2,06.7	—26.5	—11.4	3.78.8	+172.1	+83.3	542.3	+1,63.5	+43.2
(ख) दूसरे ऋण	33,65.6	+4,54.8	40,06.0	+6,40.4	+19.0	43,84.1	+3,78.1	+9.4	48,34.8	+4,50.7	+10.3
2. कुल निवेश	13,58.9	+1,98.2	15,04.2	+1,45.3	+10.7	18,06.9	+3,02.7	+20.1	22,40.1	+4,33.2	+24.0
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	11,26.3	+1,50.7	11,86.1	+59.8	+5.3	13,75.1	+1,89.0	+15.9	16,64.1	+2,89.0	+21.0
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	2,32.6	+47.5	3,18.1	+85.5	+36.8	4,31.8	+1,13.7	+35.7	5,76.0	+1,44.2	+33.4
3. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया	3,80.3	+1,10.8	3,57.6	—22.7	—6.0	4,02.9	+45.3	+12.7	4,47.4	+44.5	+11.0
4. बोली और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	88.1	+37.5	47.9	—40.2	—45.6	82.7	+34.8	+72.7	1,06.6	+23.9	+28.9
5. कुल जमा राशियां	46,45.8	+6,76.8	52,74.5	+6,28.7	+13.5	62,16.2	+9,41.7	+17.9	75,23,5	+13,07.3	+21.0
(क) मांग	21,03.5	+2,28.8	23,28.8	2,25.3	+10.7	+27,42.8	4,14.0	+17.8	32,88.6	+5,45.8	+19.9
(ख) मीयादी	25,42.3	+4,48.1	29,45.7	+4,03.4	+15.9	34,73.4	+5,27.7	+17.9	42,34.9	+7,61.5	+21.9
6. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये उधार	1,72.2	+68.7	2,91.5	+1,19.3	+69.3	2,07.2	—84.3	—28.9	42.1	—1,65.1	—79.7
7. ऋण-जमा अनुपात	77.5		79.9			76.6			71.5		
8. निवेश-जमा अनुपात	29.3		28.5			29.1			29.8		

संबन्धी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी थी और उत्पादन को बढ़ाने और वितरण को बनाये रखने के लिए सभी यथासंभव सहायताएं देने की भी आवश्यकता थी। इसके अलावा, अग्रतावाले क्षेत्रों तथा अब तक के अपेक्षित क्षेत्रों को अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने तथा बैंकिंग सुविधाओं को विस्तारित करने की भी आवश्यकता थी। 1971-72 के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ में घोषित ऋण नीति इन आवश्यकताओं के अनुरूप बनायी गयी थी।

57. ऋण नियंत्रण की आवश्यकता के संदर्भ में जो नीति बनायी गयी उसका प्रमुख आधार रिज़र्व बैंक के वित्त पर वाणिज्य बैंकों के अवलंबन को कम करना था। बैंकों को यह सलाह दी गयी कि यद्यपि रिज़र्व बैंक से अपेक्षित अधिकतम उधारों की पूर्ति करने की दृष्टि से पुनर्वित्त की पात्रता से सम्बन्धित शर्तें बनायी गयी हैं फिर भी वे ऐसे उधार केवल अल्प अवधियों के लिए लें। रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को यह सुझाव भी दिया कि उनके द्वारा रिज़र्व बैंक से लिए जाने वाले उधारों का स्तर अप्रेल 1972 के अन्त में अप्रेल 1971 के अन्त के स्तर अर्थात् 191 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं होना चाहिये। उन्हें यह सूचित किया गया कि अगस्त 1972 के पहले शुक्रवार से बैंकों की चलमुद्रागत अपेक्षा में 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी अर्थात् उसे 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 29 प्रतिशत कर दिया जाएगा; और रिज़र्व बैंक के पास सांविधिक आधार पर रखी जानेवाली 3 प्रतिशत जमाराशियां अलग रहेंगी*।

58. रिज़र्व बैंक की नीति में जहां सामान्य ऋण नियंत्रण पर जोर दिया गया वहां ऐसे कतिपय क्षेत्रों को जिन्हें ऋण की अविलंब आवश्यकता थी, वित्तीय सहायता देने के संबन्ध में प्रोत्साहन देने के निमित्त भी उपाय किये गये। पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों को, जिनमें से कतिपय यूनिटों को विशेष सहायता की आवश्यकता थी, सहायता प्रदान करने के प्राधिकारियों के प्रयत्नों के संदर्भ में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से वाणिज्य बैंकों से कहा गया कि वे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के ग्राहक यूनिटों को कार्यकारी पूंजीगत सहायता प्रदान कर निगम की मदद करें। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ये अनुदेश दिये गये कि वे कोयला उद्योग के संबन्ध में ऋण संबन्धी अपनी क्रियाविधियों को उदार बनायें ताकि उक्त उद्योग द्वारा अनुभव की गयी कठिनाईयां दूर हो सकें तथा वे वर्तमान चावल मिलों के आधुनिकीकरण और नयी मिलों की स्थापना के लिए मध्यावधि ऋण प्रदान करें।

59. अनाज, तेल और तिलहन, चीनी और गुड़ तथा रूई और कपास जैसे कतिपय संवेदनशील पण्यों पर बैंकों द्वारा दिये जानेवाले अग्रिमों से सम्बन्धित चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को स्थूल रूप से बनाये रखा गया। संवेदनशील पण्यों की पूर्ति और मूल्य की स्थिति पर निगरानी रखी गयी और ऐसे पण्यों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबन्ध में उनकी मांग, पूर्ति और मूल्य की स्थिति के अनुरूप मार्जिन और उच्चतम सीमा संबन्धी अपेक्षाओं में समायोजन किये गये (इस रिपोर्ट के भाग II में इस संबन्ध में विस्तृत दिये गये हैं)।

60. 3 दिसंबर 1971 को भारत-पाकिस्तान युद्ध छिड़ जाने के परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया कि इस नीति में कुछ रियायत की जाये ताकि वाणिज्यि बैंक रक्षा के उद्देश्यों के लिए वस्तुओं का निर्माण और पूर्ति करनेवाले उद्योग क्षेत्र की अतिरिक्त ऋण संबन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और साथ ही, वस्तुओं का सहज वितरण विशेष रूप से सीमा क्षेत्र में सुनिश्चित हो सके। बैंकों से यह कहा गया कि वे निर्माण यूनिटों और रक्षा संबन्धी आर्डरों की पूर्ति करने वाले उप-ठेकेदारों को पर्याप्त मात्रा में अविलंब रक्षा संबन्धी पैकिंग और पूर्ति ऋण प्रदान करें। उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए बैंकों द्वारा दिये गये अग्रियों के संबन्ध में उनके वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर विचार किये बिना बैंक दर पर पूरी पुनर्वित्त सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन उन्हें दिया गया। स्टाकों के जमा हो जाने और अधिक मात्रा में किये जाने वाले उत्पादन से उत्पन्न कार्यकारी पूंजी की अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन आनेवाली पार्टियों के मामले में रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना ही उनके गुण-दोषों के आधार पर 15 प्रतिशत तक ऋण सीमाओं को बढ़ाने की अनुमति बैंकों को दी गयी।

61. इन नीतियों के परिप्रेक्ष्य में 1971-72 के अधिक कामकाज के समय में ऋण राशि में 351 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में उक्त राशि में 394 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। ऋण राशि में हुई इस कम वृद्धि का कारण यह था कि अनाजों की उगाही के कार्यकलापों के लिए कम मात्रा में ऋण का उपयोग किया गया था; अर्थात् पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय में उपयोग की गयी ऋण राशि में जहां 70 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी, वहां इस वर्ष के अधिक कामकाज के समय में उसमें 76 करोड़ रुपयों की कमी हुई। अनाजों की उगाही से संबन्धित ऋण को छोड़कर शेष बैंक ऋण में 427 करोड़ रुपयों की वृद्धि दिखायी दी जबकि पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय में यह वृद्धि 324 करोड़ रुपये थी (सारणी 14)। 1971-72 के अधिक कामकाज के समय में जमाराशियों में 590 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह ऋण राशि में हुई वृद्धि की अपेक्षा काफ़ी अधिक थी; अतः इस अवधि में रिज़र्व बैंक पर बैंकों की निर्भरता पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा काफ़ी कम थी। 1971-72 के अधिक कामकाज के समय में रिज़र्व बैंक से लिये गये उधारों में जो वृद्धि हुई वह 233 करोड़ रुपयों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गयी जब कि पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय में उक्त वृद्धि 292 करोड़ रुपयों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा किये गये निवेशों में तेजी से 245 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में उनमें 115 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। अप्रेल 1972 में अर्थात् अधिक कामकाज के समय के अन्त में ऋण जमा अनुपात 72 प्रतिशत था अर्थात् उक्त अनुपात में एक वर्ष पहले विद्यमान अनुपात की तुलना में 6 प्रतिशत अंकों की कमी पायी गयी।

ऋण का क्षेत्रवार वितरण—अनाजों की उगाही और निर्यात

62. बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण के अनुमानित आंकड़े केवल दिसम्बर 1971 के अन्त तक (अर्थात् आलोच्य वर्ष की छमाही के लिए) उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों से पता लगता है कि जहां जून 1971 के अन्त और दिसम्बर 1971 के अन्त के बीच की अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की कुल राशि में 294 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि बढ़कर 5,052 करोड़ रुपये हो गयी, वहां अनाजों की उगाही के कार्यकलापों के लिए दिये गये अग्रिमों में 14 करोड़ रुपयों की कमी हुई और उनकी राशि दिसम्बर 1971 के अन्त में 365 करोड़ रुपये रह गयी। निर्यातों के लिए इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों में जहां 1971 के पूर्वार्ध में 19 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई वहां दिसम्बर 1971 के अन्त तक 77 करोड़ रुपयों की और वृद्धि अर्थात् उक्त अग्रिमों की राशि बढ़कर 459 करोड़ रुपयों तक पहुंच गयी। इस अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में जो कुल वृद्धि हुई उसमें से 26 प्रतिशत वृद्धि निर्यात क्षेत्र को दिये

*तदनुसार बैंकों को अपनी चल आस्तियों में अगस्त 172 के पहले शुक्रवार से 1 प्रतिशत की वृद्धि करने की सलाह दी गयी है।

गये ऋण में हुई जबकि 1970 की तदनुरूपी अवधि में उसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। निर्यात के विकास को प्राथमिकता दिये जाने के कारण रिजर्व बैंक बैंकों को उनके द्वारा निर्यातों के लिए दिये गये ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान करता रहा। रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिये गये कुल ऋणों में इस प्रकार दिये गये पुनर्वित्त का हिस्सा जहां जून 1971 के अन्त में 35 प्रतिशत था वहां इस वर्ष के दौरान तेजी से बढ़कर दिसम्बर 1971 के अन्त में 64 प्रतिशत हो गया। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे, निर्यात यूनिटों को पैकिंग ऋण सुविधाएं प्रदान करते समय अपनी निर्णय शक्ति से मार्जिन संबन्धी अपेक्षाओं में छूट दे सकते हैं। ब्याज उपदान योजना को भी जारी रखा गया और जुलाई 1971 से जून 1972 के अन्त तक की अवधि के दौरान 37 योग्य वाणिज्य बैंकों ने अपने द्वारा दिये गये निर्यात ऋणों के बदले में 4 करोड़ रुपयों की सीमा तक उपदान प्राप्त किया।

—अन्य अग्रता वाले क्षेत्र

63. जून 1971 के अन्त से दिसम्बर 1971 के अन्त तक की अवधि के दौरान अन्य अग्रतावाले क्षेत्रों (जिनमें कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन चालक, व्यावसायिक व्यक्ति, विनियोजित व्यक्ति, शिक्षा, फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार शामिल हैं) को दिये गये ऋणों में 77 करोड़ रुपयों अर्थात् 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में उनमें 143 करोड़ रुपयों अर्थात् 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी 15)। फलस्वरूप सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल ऋणों में अग्रतावाले क्षेत्रों को प्राप्त ऋणों का हिस्सा दिसम्बर 1970 के 22.8 प्रतिशत से घटकर दिसम्बर 1971 में 21.8 प्रतिशत हो गया।

64. यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो कृषि को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त में 27 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि परोक्ष वित्त में 14 करोड़ रुपयों की गिरावट आयी। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 1971 में समाप्त हुई छमाही के दौरान कृषि को दिये गये कुल ऋणों में केवल 13 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970 की तदनुरूपी अवधि में 58 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी लघु उद्योगों और व्यवसायिक व्यक्ति और स्वनियोजित व्यक्ति, फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार आदि जैसे अन्य अग्रतावाले क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के संदर्भ में पायी गयी प्रवृत्ति कृषि क्षेत्र की प्रवृत्तियों से भिन्न नहीं थी। जून-दिसम्बर 1971 की अवधि के दौरान लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों में 45 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970 की तदनुरूपी अवधि में उनमें 55 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। दूसरे अग्रतावाले क्षेत्रों को दिये गये ऋणों में उक्त अवधि में 19 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि उनमें 1970 की उक्त अवधि में 30 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। 1971-72 (अप्रैल से मार्च तक) के दौरान लघु उद्योगों (कारीगरों और अन्य दक्षताप्राप्त उद्यमियों को दिये गये मीयादी ऋणों और अग्रिमों को मिलाकर) को दिये गये ऋणों में 84 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात उक्त ऋणों की राशि बढ़कर 578 करोड़ रुपये* हो गयी जबकि 1970-71 में उनमें 100 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी।

*अनन्तिम।

सारणी 14 :—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में मोसमी घट-बढ़ अधिक कामकाज का समय

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	अप्रैल 1971	1971-72	अप्रैल 1972
1. कुल बैंक ऋण	+5,09.5	+4,26.8	+5,62.9	+3,94.2	46,75	+3,51.1	51,89
उनमें से :							
(क) अनाजों की उगाही के लिए दिये गए ऋण	+1,01.0	+8.3	—27.3	+70.3	2,03	—76.0	2,83
(ख) अन्य ऋण	+4,08.5	+4,18.5	+5,90.2	+3,23.9	44,72	+4,27.1	49,06
2. कुल निवेश	—1,52.7	—2.4	—51.3	+1,15.4	17,74	+2,44.6	22,68
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	—1,82.3	—43.0	—1,00.9	+39.1	13,60	+1,43.7	17,12
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	+29.6	+40.6	+49.6	+76.3	4,14	+1,00.9	5,56
3. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया	—4.2	+20.0	+7.8	+12.4	3,59	+1.9	4,19
4. बोली और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	—20.5	+6.7	—14.8	—10.7		—6.8	
5. कुल जमा राशियां	+2,21.7	+3,24.9	+3,20.9	+4,35.5	59,93	+5,90.3	72,07
(क) मांग	+1,22.1	+1,45.1	+1,71.9	+1,90.2	26,31	+2,95.7	31,28
(ख) मीयादी	+99.6	+1,79.8	1,49.0	+2,45.3	33,62	+2,94.6	40,79
6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार	+1,05.3	+70.8	2,03.0	+40.2	1,91	+4.3	23
7. ऋण-जमा अनुपात (मौसम के अंत में)	79.4	78.0	79.4	78.0	78.0	72.0	72.0
8. निवेश-जमा अनुपात (मौसम के अंत में)	29.6	28.9	28.8	29.6		31.5	

सारणी 15:—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

	बकाया			घटबढ़ (2) की तुलना में,	बकाया		घटबढ़ (5) की तुलना में
	जून 1969 में	जून 1970 में	दिसंबर 1970 में	(3) में	जून 1971 में	दिसंबर 1971 में	(6) में
	1	2	3	4	5	6	7
1. कुल बैंक ऋण	33,99	42,13	44,52	+ 2,39	47,58	50,52	+ 2,94
(उनमें निर्यातों से दिये गये ऋण)	(2,63)	(3,20)	(3,63)	(+ 43)	(382)	(4,59)	(+ 77)
2. अनाजों की उगाही के कार्यकलाप	2,33	2,07	2,17	+ 10	3,79	3,65	— 14
3. कृषि ऋण	1,88	3,42	4,00	+ 58	3,82	3,95	+ 13
उनमें से							
(क) प्रत्यक्ष वित्त	54	1,84	2,40	+ 56	2,36	2,63	+ 27
(ख) परोक्ष वित्त	1,34	1,58	1,60	+ 2	1,46	1,32	— 14
4. लघु उद्योग	2,86	4,14	4,69	+ 55	5,00	5,45	+ 45
5. फुटकर व्यापार सहित अन्य अग्रतावाले क्षेत्र	31	1,14	1,44	+ 30	1,44	1,63	+ 19
6. बड़े और मझौले उद्योगों, थोक व्यापार और दूसरों को दिये गये बैंक ऋण (@	26,61	31,36	32,22	+ 86	33,53	35,84	+ 2,31
[1—(2+3+4+5)]	(78.3)	(74.4)	(72.4)		(70.5)	(70.9)	
7. कुल उपलब्ध जमा राशियां (हाथ में नगदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया राशि, अन्य बैंकों के चालू खाते में बकाया राशि और सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों को छोड़कर)	28,33	33,50	35,30	+ 1,80	39,32	42,51	+ 3,19
8. मद 7 के प्रतिशत के रूप में मद 6	93.9	93.6	91.3	+ 47.8	85.3	84.3	72.4
9. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार	1,72	2,92	3,02	+ 10	2,07	1,71	— 36

नोट :—(i) फुटकर व्यापार सहित अन्य अग्रतावाले क्षेत्रों के संदर्भ में केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं ; इसलिए ये कुल ऋण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण के अनुपात (86 प्रतिशत) के आधार पर बहुत अधिक दिखाई पड़ते हैं।

(ii) मद 6 के सामने कोष्टकों में दिये गये आंकड़े कुल बैंक ऋण में अनुपात के द्योतक हैं।

@अनुमानित।

65. कृषि ऋणों की वृद्धि में जो कमी हुई वह अंशतः बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की गुणवत्ता और अपने द्वारा दिये गये अग्रिमों की वसूली पर जोर दिये जाने के कारण हुई और उसका आंशिक कारण यह भी था कि बैंक इस क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋणों से संबन्धित कामकाज संभालने के लिए अपने संगठन स्वरूप को मजबूत बनाने की दिशा में ध्यान देते रहे और वे रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप अपनी नीतियों और क्रियाविधियों में तालमेल बिठाने का प्रयास करते रहे। लघु उद्योगों के क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों की वृद्धि की धीमी गति का आंशिक कारण औद्योगिक क्षेत्र में पायी गयी सामान्य मंदी थी जिससे लघु उद्योगों के उत्पादन स्तर बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इसका दूसरा कारण यह भी था कि गुणवत्ता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता था। यह भी कहा जा सकता है कि 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद की अवधि में ऋण-वृद्धि की जो दर पायी गयी उसे बनाये नहीं रखा जा सका; क्योंकि इन क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋणों का आधार जहां प्रारंभिक अवधि में सीमित था वहां उसके बाद व्यापक हो गया और इस कारण ऋण-वृद्धि की दर भी निश्चित ही अपेक्षाकृत कम होगी। अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये जाने गये कुल ऋण में इन क्षेत्रों के ऋण का जो हिस्सा रहता है उसमें पायी गयी कमी पर उपर्युक्त पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिये और यह नीति में किस प्रकार के परिवर्तन का द्योतक नहीं है।

दूसरे क्षेत्रों को ऋण

66. जैसाकि सारणी 15 में दिखाया गया है, कुल ऋण में अन्य क्षेत्रों, विशेषकर सरकारी उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों सहित बड़े और मझौले उद्योगों और थोक व्यापार क्षेत्र को प्राप्त होने वाले ऋण का जो हिस्सा रहता है उसमें 231 करोड़ रुपयों तक की वृद्धि हुई और उक्त हिस्सा कुल ऋण का 70.9 प्रतिशत था जबकि जून 1971 के अन्त में 70.5 प्रतिशत था। इस तथ्य के अलावा कि बड़े और मझौले उद्योगों और थोक व्यापार के क्षेत्र हमेशा ही बैंकों से भारी मात्रा में उधार लेनेवाले रहे हैं, उद्योगों और व्यापार क्षेत्रों को इस अवधि में रक्षा और वितरण संबन्धी आर्डरों की जो पूर्ति करनी थी उसकी पृष्ठभूमि में भी इस ऋण-वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिये इसके अलावा, निर्यात व्यापार को दिया गया अधिकांश ऋण भी इन क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के आंकड़ों में शामिल किया गया है। इसलिए, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण संबन्धी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति किये जाने के मार्ग में ऋण नियंत्रण की सामान्य नीति बाधक नहीं थी। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि आलोच्य वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक की ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत बैंकों से प्राप्त 726 आवेदन पत्रों में से 1.45 करोड़ रुपयों की अल्प राशि वाले केवल 3 आवेदनपत्र अस्वीकार किये गये ; वे भी इसलिए अस्वीकार किये गये कि वे आवश्यकता पर आधारित नहीं थे।

विभेदक दरें

67. समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋण के संदर्भ में वित्तीय सहायता की अपेक्षा करने वाले कम आय वाले चुने हुए वर्गों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों लेके लिए रियायती ब्याज दरों की योजना को कार्यान्वित करने से संबन्धित सरकारी निर्णय की 25 मार्च, 1972 को वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणा उल्लेखनीय है। उक्त घोषणा के बाद योजना के अधीन ऋण दिये जाने के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान के लिए आवश्यक मानदंड निर्धारित करते हुए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा ऋण दिये जाने से संबन्धित शर्तों के विवरण बैंकों के विवरण बैंकों को भेज दिये गये हैं। उधारकर्ताओं के चुनाव के लिए दो बुनियादी मानदंड होंगे ; वे हैं उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति और उनके कार्यकलापों का उत्पादक स्वरूप। विभेदक ब्याज दर समान रूप से 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है जो बैंक दर से 2 प्रतिशत कम है। यह योजना अभी प्रारम्भिक चरण में है और यह आशा की जाती है कि इस योजना के अधीन दिये गये ऋणों की राशि पिछले वर्ष के अन्त में बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों के एक प्रतिशत की लगभग आधी होगी। यद्यपि इस योजना के अधीन दिये गये ऋणों की कुल मात्रा जैसे अनुमानतः 20 करोड़ रुपये है— अधिक नहीं होगी फिर भी इसका बड़ा लाभ यह होगा कि बैंकर ब्याज दरों को आय और संपत्ति की विषमताओं को घटाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की नीति की दिशा में उन्मुख होंगे।

हुंडी पुनर्भाजन योजना

68. नवम्बर 1970 में हुंडी बाजार के विकास को प्रोत्साहन देने के विचार से शुरू की गयी हुंडी पुनर्भाजन योजना के क्षेत्र को इस वर्ष के दौरान कुछेक संशोधनों के साथ विस्तारित किया गया है (भाग II में इसकी चर्चा की गयी है)। पुरानी हुंडी बाजार योजना के अधीन पुनर्वित किये जाने की प्रणाली को बन्द कर दिया गया है। किन्तु कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये वह प्रणाली अब भी लागू है। वे उद्देश्य इस प्रकार हैं: रक्षा पैकिंग ऋण एवं पूर्ति ऋण और अनाजों की उगाही के कार्यकलापों के लिए वित्त प्रदान करना और बैंकों को, विशेषकर ऐसे छोटे बैंकों को जो रिजर्व बैंक से लिये जानेवाले अन्य प्रकार के उधारों के लिए उपयुक्त प्रपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, दी जानेवाली वित्तीय सहायता।

69. शुरू में जुलाई और अगस्त 1971 के दौरान पुनर्भाजित हुंडियों के बकाया स्तर में गिरावट पायी गयी ; किन्तु उक्त स्तर सितम्बर 1971 के अन्त में बढ़कर 25 करोड़ रुपये हो गया जबकि जून 1971 के अन्त में यह स्तर 10 करोड़ रुपये था। 1971-72 के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ में रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्भाजित हुंडियों की राशि 14 करोड़ रुपये थी। जैसे जैसे अधिक कामकाज का समय आगे बढ़ा, बैंकों ने अधिक मात्रा में पुनर्भाजन सुविधाओं का लाभ उठाया और मार्च 1972 के अन्त तक उनकी बकाया राशि 42 करोड़ रुपये हो गयी। कम कामकाज के समय के शुरू होने वाले के साथ ही इस सुविधा का लाभ उठाने की प्रवृत्ति कम हो गयी; अतः पुनर्भाजित हुंडियों की राशि जून 1972 के अन्त में 10 करोड़ रुपये हो गयी। इस योजना के अधीन 1 जुलाई 1971 से लेकर 30 जून 1972 तक की अवधि के दौरान पुनर्भाजित हुंडियों की अधिकतम बकाया राशि 45.3 करोड़ रुपये थी।

ऋण आयोजना

70. ऋण आयोजना के मूल आधार और तत्त्व तथा समग्र आर्थिक आयोजना के संदर्भ में उसके महत्व और इस दिशा में शुरू किये गये उपायों का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया है। इसके बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक ऋण योजना तैयार करने की दिशा में एक कदम उठाया गया ; वह इस प्रकार था : 1971-72 के वित्तीय वर्ष अर्थात् 1971 के कम कामकाज के समय और 1971-72 के अधिक कामकाज के समय के संदर्भ में बैंकिंग संघटन के वित्तीय साधनों की वृद्धि और उनके वितरण के बारे में एक व्यापक प्रयोग किया गया। तत्संबन्धी अनुमानों पर पहुँचने के लिए ऐसे 31 बड़े बैंकों से जिनके पास पूरे बैंकिंग संघटन की जमाराशियों की 95 प्रतिशत जमाराशियां थीं और जिनके द्वारा दिये गये अग्रिमों की राशि पूरे बैंकिंग संघटन द्वारा प्रदत्त अग्रिमराशि का 96 प्रतिशत थी, इस उद्देश्य के लिए बनाये गये विशेष प्रपत्र में आंकड़े भेजने के लिए कहा गया था। प्रपत्र में बैंकों की कुल जमाराशियों और अग्रिमों में वृद्धि, निधियों के राज्यवार और क्षेत्रवार वितरण और क्षेत्र में शाखाओं का विस्तार करने से संबन्धित बैंकों के कार्यक्रम के विस्तृत विवरण शामिल किये गये। अलग-अलग बैंक के विवरणों पर संबन्धित बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया और जमाराशियां जुटाने और क्षेत्रवार तथा प्रदेशवार ऋणों के वितरण से संबन्धित उसके पिछले कार्य और सामाजिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में उसकी अपेक्षित भूमिका को ध्यान में रखते हुए जहां जहां आवश्यक था, प्राक्कलनों में परिशोधन किया गया। इन बैंकों से प्राप्त समेकित आंकड़ों और उत्पादन प्रवृत्तियों, मूल्यों आदि से संबन्धित उपलब्ध विवरणों का उपयोग करते हुए बैंकिंग संघटन के लिए वर्ष 1971-72 के लिए एक व्यापक ऋण योजना तैयार की गयी।

71. जूट, चाय और इंजीनियरी उद्योगों की ऋण संबन्धी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वर्ष के दौरान जूट उत्पादक संघ, इंजीनियरी संघ और चाय उद्योग से संबन्धित संगठनों से विचार-विमर्श किया गया। देश के अन्य क्षेत्रों (गैर-सरकारी और सरकारी) के प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी ऋण संबन्धी आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाने के संदर्भ में सहायता पहुंचाने के लिए इसी प्रकार के विचार-विमर्श प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

72. अप्रेल 1972 में रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित वाणिज्य बैंकों के अर्थशास्त्रियों की एक बैठक में 1971-72 की व्यापक ऋण योजना के अनुभवों और 1972-73 की ऋणयोजना के प्रपत्र पर विचार-विमर्श किया गया। योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के अलावा, अर्थशास्त्रियों से यह अनुरोध किया गया कि वे जमाराशियों और ऋण के क्षेत्रीय वितरण का अनुमान लगाने के संबन्ध में अपनायी जानेवाली अपनी अपनी प्रणालियों का विवरण रिजर्व बैंक के पास भेजें। इन बातों पर बैंकरों से अलग अलग विचार-विमर्श करना है।

प्रादेशिक ऋण आयोजना

73. यद्यपि 1971-72 की ऋण आयोजना में, जमाराशियों का वर्गीकरण और निधियों का वितरण (निवेशों को मिलाकर) राज्यवार किया गया और उनकी अन्तर्राज्यीय तुलना भी की गयी फिर भी उपयोगिता के आधार पर राज्यवार ऋण का वर्गीकरण करने की बैंकों की अपनर्यता के कारण बैंकों की निधियों के प्रादेशिक वितरण का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना संभव नहीं था। अभी देश के अनेक भागों में बैंकों को कृषि और लघु उद्योग की ऋण संबन्धी आवश्यकताओं की जानकारी नहीं है। तथापि अग्रणी बैंक योजना के अधीन वितरित किये गये जिलों में उनके द्वारा किये गये प्रभावी सर्वेक्षणों के रूप में इस दिशा में शुरुआत कर दी गयी है। 335 जिलों में से 260 की रिपोर्टें तैयार की जा चुकी हैं; इसके अलावा बैंक सुविधारहित कम बैंक सुविधायुक्त केन्द्रों का पता लगाने लगाने का प्रथम चरण भी पूरा हो चुका है। अग्रणी बैंक योजना के अधीन अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कुछ जिलों के लिए जिला स्तर पर सलाहकार समितियों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। इन समितियों से ऋण संबन्धी अन्तरालों को पाटने के लिए वित्तीय

संस्थानों की गतिविधियों में समन्वयन लाने के अलावा यह भी आशा की जाती है कि वे राज्य सरकारों से अपना संपर्क बनाए रखें। जहां बैंक जिलों की अर्थव्यवस्था से परिचित हो गये हैं, वहां स्थानीय अर्थव्यवस्था में बैंकों के योगदान में इस योजना से कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। विशेष रूप से इस योजना के अधीन अग्रतावाले क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋण के कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि बैंकों ने अभी तक अधिकांश क्षेत्रों में विभिन्न लघु उद्योगों और कृषि की ऋण संबन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई गंभीर अध्ययन नहीं किया है। इस दिशा में किये गये प्रयास अब तक अपर्याप्त हो रहे हैं। कुछ हद तक इसका कार्य करने का वह संकीर्ण आधार है, जिसे लेकर अग्रणी बैंकों ने अपने जिलों में काम करना शुरू किया है। 1972–74 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।

74. एक सार्थक ऋण कार्यक्रम बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रायः सभी बैंकों ने प्रादेशिक/प्रभागीय स्तर पर और कुछ मामलों में जिला स्तर पर विकास संबन्धी कर्मचारियों और विषय-विशेष के विशेषज्ञों को लेकर अपने कार्यालय खोले हैं। जिलों की बैंक संबन्धी योजनाओं के संबंध में, क्षेत्र की अन्य संस्थागत एजेन्सियों के सक्रिय सहयोग और राज्य सरकार की पर्याप्त सहायता के साथ ऋण संबन्धी अंतरालों का पता लगाये जाने और क्षेत्रगत अध्ययन किये जाने के कारण क्षेत्रीय ऋण आयोजना आगामी वर्षों में अधिक प्रभावी हो जाएगी।

75. देश के अल्पविकसित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने का कार्य ऋण आयोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस वर्ष के दौरान खोली गयी 1,612 शाखाओं में से 936 (53 प्रतिशत) शाखाएं अब तक के बैंक सुविधारहित केन्द्रों में खोली गयीं और 507 शाखाएं 9 अपेक्षाकृत कम बैंक सुविधायुक्त राज्यों अर्थात् असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में खोली गयी। इन नौ राज्यों और त्रिपुरा और नागालैंड, जिन्हें कम बैंक सुविधायुक्त राज्यों के रूप में माना गया है, में देश की जनसंख्या का आधे से अधिक भाग रहता है। जून 1969 के अन्त तक, इन राज्यों में कुल शाखाओं का लगभग एक चौथाई भाग मात्र विद्यमान था, किन्तु पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गयी शाखा विस्तार नीति के कारण यह अनुपात जून 1972 के अन्त तक 29 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है। वाणिज्य बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम का विस्तृत विवरण रिपोर्ट के भाग II में दिया गया है।

भुगतान शेष

76. अब हम 1971-72 (जुलाई-जून) में देश के विदेशी भुगतान शेष की स्थिति पर विचार करेंगे। इस अवधि में प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों का मूल्य 787 करोड़ रुपयों से बढ़कर 846 करोड़ रुपये हो गया। किन्तु इस वृद्धि में 16 करोड़ रुपयों की वह राशि भी शामिल है जो ऐसी मुद्राओं में, जिनकी विनियम दरों में इस वर्ष के दौरान वृद्धि हुई, रखी हुई प्रारक्षित आस्तियों के रुपया मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्राप्त हुई। इसके विपरीत, 1970-71 में प्रारक्षित निधियां 837 करोड़ रुपयों से घटकर 787 करोड़ रुपये हो गयीं। इसका प्रमुख कारण यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये पुनः क्रय और उसमें किये गये अतिरिक्त स्वर्ण अभिदान के लिए 124 करोड़ रुपये प्रारक्षित निधियों से निकाले गये थे। 1971-72 में इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं हुआ। यदि इन विशेष लेन-देनों और मूल्यों परिवर्तन को छोड़ दिया जाए तो प्रारक्षित निधियों में 1971-72 में 43 करोड़ रुपयों और 1970-71 में 72 करोड़ रुपयों की वृद्धि दिखाई पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, इस वर्ष भुगतानों की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम उल्लेखनीय थी।

77. जिन विदेशी लेन-देनों के संदर्भ में प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में अंतिम रूप से परिवर्तन हुए उनके विवरण अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। फिर भी अभी तक जो सूचना मिली है, उससे स्पष्ट है कि आयात संबंधी भुगतानों में वृद्धि हुई है। इस्पात, अलौह धातु और अनुरक्षण संबन्धी अन्य वस्तुओं के जो अधिक आयात किये गये उनका बहुत कुछ समायोजन खाद्यान्न के आयातों में हुई कमी के कारण हुआ है जो खाद्यान्न के देशी भंडारों की संतोषजनक स्थिति के कारण संभव हो सकी। इस वर्ष ऋणों का भुगतान पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक किया गया। इसका आंशिक कारण यह था कि हमारे कुछ ऋणकर्ताओं की मुद्राओं के विनियम मूल्य में वृद्धि हुई। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संबन्धी अनिश्चितताओं के संदर्भ में और विशेष रूप से जूट निर्यातों में वृद्धि होने के बावजूद निर्यात की आमदनी में समंजनः सामान्य वृद्धि हुई।

78. इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध विदेशी सहायता इस वर्ष के अन्त में पिछले वर्ष के अन्त में विद्यमान स्थिति की अपेक्षा काफी कम होगी। दिसम्बर 1971 से अमेरिका की तरफ से सहायता का कोई नया प्राधिकरण नहीं हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए निधियों की तृतीय आपूर्ति के संबन्ध में अमेरिका की निष्क्रियता के कारण उस स्रोत से भी सहायता की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था के विघटन से अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली सहायता में अनिश्चितता आ गयी।

व्यापार घाटा

79. जहां तक आयातों और निर्यातों का संबन्ध है, वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत व्यापार संबन्धी जो घाटा 1968-69 से काफी कम हो गया था वह 1971-72 में एक बार फिर बढ़ गया है। 1971-72 (अप्रैल-मार्च) में व्यापार घाटा 286 करोड़ रुपये था, जो 1970-71 के 99 करोड़ रुपयों के घाटे से अधिक अधिक था। इस तीव्र वृद्धि का यह कारण था कि आयातों में 219 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि हुई जबकि निर्यातों में केवल 32 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई।

निर्यात

80. 1971-72 के वित्तीय वर्ष में निर्यातों की विकास दर पिछले वर्ष के 8.6 प्रतिशत के मुकाबले में 2.1 प्रतिशत थी। जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया जा चुका है 1970-71 में निर्यातों में हुई वृद्धि का एक अन्श सांख्यिकीय था जो निर्यातों का रिकार्ड करने की क्रियाविधि में हुए परिवर्तन के कारण हुआ। यदि 1970-71 के निर्यात संबन्धी आधिकारिक आंकड़ों में इस आधार पर समायोजन किया जाय तो उसके परिणामस्वरूप 1970-71 के निर्यातों की वृद्धि दर में कमी होगी और तदनुसार 1971-72 की वृद्धि दर बढ़ जाएगी। ठोस आंकड़ों के अभाव में, इन समायोजित विकास दरों का निर्धारण आसानी से नहीं किया जा सकता, किन्तु यह स्पष्ट है कि असमानता योजित आंकड़ों के आधार पर वृद्धि दरों का अनुमान 1970-71 के लिए अधिक और 1971-72 के लिए कम लगाया गया है।

81. 1971-72 के निर्यातों की प्रवृत्ति को सही और साफ़ तौर पर दो अवधियों में विभाजित किया जा सकता है ; अर्थात् अप्रैल 1971 से जुलाई 1971 तक की अवधि में निर्यातों में 1970 की तदनुरूपी अवधि में हुई वृद्धि की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई और अनुवर्ती अवधि अर्थात् अगस्त 1971 से मार्च 1972 तक की अवधि में 1970-71 की तदनुरूपी अवधि में हुई वृद्धि की तुलना में उनमें 7 प्रतिशत की कमी हुई। पहले की अवधि में निर्यातों में हुई अधिक वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि बंगला देश से जूट संबंधी वस्तुओं के पोतलदानों के

बिलकुल ही बंद हो जाने के परिणामस्वरूप उनकी मांग बहुत ज्यादा हो गयी थी । जुलाई 1971 के बाद की अवधि में अन्य बातों के साथ साथ विश्व की प्रमुख मुद्राओं के चालू किये जाने और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण व्यापार क्षेत्र के अस्त व्यस्त हो जाने के फलस्वरूप निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

निर्यात पण्यवार

82. दिसंबर 1971 तक उपलब्ध निर्यातों के पण्यवार विवरण से मालूम पड़ता है कि निर्यातों की सामान्य वृद्धि दर (अप्रैल दिसंबर 1971 में 1970 की तदनरूपी अवधि की अपेक्षा 4 प्रतिशत की वृद्धि) का एक मात्र कारण जूट उत्पादनों के निर्यातों में हुई वृद्धि थी । दूसरी वस्तुओं में से, उच्चतर यूनिट मूल्यों के कारण चाय के निर्यातों में 2 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हुई । इसके विपरीत सूती कपड़ों और तागों, तेल की खली और गरम मसालों के निर्यातों में कुछ कमी आयी (सारणी 16)।

83. यदि जूट निर्यातों में हुई वृद्धि को छोड़ दिया जाय तो अप्रैल दिसबंर 1971 की अवधि में कुल निर्यातों में 36 करोड़ रुपयों की कमी दिखाई देगी । कुल निर्यातों म परम्परेतर वस्तुओं के निर्यातों का हिस्सा अप्रैल दिसंबर 1970 में जहां 24 प्रतिशत था वहां 1971 की उसी अवधि में वह घटकर 18 प्रतिशत हो गया । इस्पात के कम उत्पादन की स्थिति में उसकी बढ़ती हुई घरेलू मांग के कारण उसके निर्यात अधिशेष में पर्याप्त कमी आयी, जबकि खनिज लोहे के निर्यात में खास तौर पर विदेशी मांग की कमी होने से गिरावट आयी । इस्पात की कमी और उसकी घरेलू मांग में वृद्धि होने के कारण इंजीनियरी माल और रासायनिक पदार्थों के निर्यातों में भी कमी आयी जबकि पिछले वर्षों में इनमें वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी थी ।

निर्यात नीति

84. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में संसद म 30 जुलाई 1970 को प्रस्तुत किये गये निर्यात नीति संकल्प का उल्लेख किया गया था, जिसमें भारत की निर्यात आमदनियों को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक लाइसेंस नीति और आयात नीति को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि निर्यात अभिमुख उत्पादन में वृद्धि हो । जैसाकि पहले कहा जा चुका है, निर्यात संबंधी ऋण सुविधायें भी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रदान की गयीं।

85. मार्च 1972 में भारत और बंगला देश के बीच व्यापार करार पर हस्ताक्षर किया जाना विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना थी । इस करार के अनुसार, भारत बंगला देश को अन्य वस्तुओं के साथ साथ अनुत्पादित तमाखू, सीमेंट, कोयले और सूत के तागे का निर्यात करेगा जबकि भारत बंगला देश से अन्य वस्तुओं के साथ साथ मछली, पटसन और अखबारी कागज का आयात करेगा । उक्त करार में सीमा व्यापार संबंधी विशेष सुविधाओं की भी व्यवस्था की गयी ।

आयातों की प्रवृत्तियां

86. जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन होने के बाद पहली बार 1970-71 में आयातों में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई थी ; उनमें 1971-72 में तेजी से वृद्धि हुई । वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महा निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार उनमें 1971-72 के दौरान 219 करोड़ रुपयों (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई अर्थात् आयातों का मूल्य बढ़कर 1853 करोड़ रुपये हो गया जबकि 1970-71 में उनमें 52 करोड़ रुपयों (3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । इस वर्ष के दौरान आयातों में जो वृद्धि हुई उसका आंशिक कारण यह था कि कछ अत्यावश्यक कच्चे माल और इस्पात के उत्पादों के देशी उत्पादन में कमी हो गयी थी ; अनुरक्षण वस्तुओं के आयातों के संबंध में अपनायी गयी उदारीकृत आयात नीति के कारण भी आयातों में वृद्धि हुई ।

आयात पण्यवार

87. आयातों के पण्यवार विवरण दिसंबर 1971 तक उपलब्ध हैं । उनसे मालूम पड़ता है कि अप्रैल दिसंबर 1971 में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की अपेक्षा आयातों में हुई वृद्धि पूरी तरह खाद्येतर वस्तुओं के आयातों के संदर्भ में हुई । अप्रैल दिसंबर 1970 की अपेक्षा खाद्यान्नों के आयातों के मूल्य में 65 करोड़ रुपयों (या 38 प्रतिशत) की कमी हुई जब कि खाद्येतर वस्तुओं के आयातों के मूल्य में 247 करोड़ रुपयों (या 24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । यद्यपि लगभग सभी प्रमुख खाद्येतर वस्तुओं के आयातों में वृद्धि हुई फिर भी लोहे और इस्पात (77 करोड़ रुपये), मशीनों और परिवहन उपस्कर (75 करोड़ रुपये) और खनिज तेलों (47 करोड़ रुपये) के मामले में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई (सारणी 17)। अप्रैल 1971–मार्च 1972 की अवधि में आयात-लाइसेंसों के मूल्य में 1970-71 के दौरान हुई 36 प्रतिशत की वृद्धि से भी अधिक 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई ; इससे 1972-73 में खाद्येतर वस्तुओं के आयातों में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए ।

आयात नीति

88. 1972-73 की आयात नीति में पिछले वर्ष की नीति के बुनियादी ढांचे को बनाये रखते हुए आत्म निर्भरता के उद्देश्य पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया गया । उसमें ऐसे चुने हुए अप्राप्ताप्त उद्योगों के लिए, विशेषकर ऐसे उद्योगों के लिये, जिनमें निर्यात की पर्याप्त क्षमता है या जो आयातों पर होने वाले व्यय को कम करने में योगदान कर सकते हैं, आयातित मूल वस्तुओं का अधिक वितरण किये जाने की व्यवस्था है ।

89. वाणिज्यिक माल के व्यापार में जो अपेक्षाकृत कमी हुई वह अंशतः उनके सापेक्ष उच्चतर मूल्य और देश में हुई अधिक खरीद जैसे आंतरिक कारणों से हुई । दूसरी तरफ़ विदेशों में हुई कछ गतिविधियों के कारण भी हमारे निर्यातों में बाधा पड़ी । संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन III ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि विकसित देश अल्प विकसित देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं । प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली अब यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश, जापान, नार्वे, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों द्वारा उत्पादित और अर्ध उत्पादित वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनायी जा चुकी है ; उक्त प्रणाली कोटा और उच्चतम सीमाओं के कारण उलझ गयी है ।

90. पौंड स्टर्लिंग के चालू किये जाने के कारण, इस वर्ष के अंत में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी अनिश्चिततायें कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ती हुई दिखाई पड़ीं । 1970 और 1971 के बीच में विश्व व्यापार का विकास धीमा पड़ गया था । जहां एक ओर विकासोन्मुख देशों के निर्यातों की वृद्धि में कमी आयी वहां दूसरी ओर उनके निर्यात आयात मूल्यांक (Terms of Trade) में भी गिरावट आयी । यद्यपि इस बात की काफ़ी आशा है कि पश्चिम जर्मनी और अमेरिका की गतिविधियों को पुनः प्रवर्तित किया जाएगा, फिर भी 1972-73 में विश्व व्यापार

सारणी 16 :—भारत के मुख्य निर्यात

(राशि करोड़ रुपयों में)

पण्य	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	अप्रैल-दिसम्बर		(5) की अपेक्षा (6) में वृद्धि (+)/कमी(—)	
					1970	1971	वास्तविक	वास्तविक
	1	2	3	4	5	6	7	8
(अ) मुख्य परम्परेतर वस्तुएं								
इंजीनियरी सामान . .	35	69	91	1,26	90	86	—4	—4
लोहा और इस्पात . .	55	79	87	91	71	34	—37	—52
खनिज लोहा . . .	75	88	95	1,17	86	72	—14	—16
रासायनिक पदार्थ . .	16	24	30	36	27	25	—2	—7
(आ) अन्य वस्तुएं								
जूट का तागा और उससे बनी वस्तुएं .	2,34	2,18	2,07	1,90	1,36	2,16	+80	+59
सूत का तागा और उससे बनी वस्तुएं .	88	1,01	1,16	1,18	88	81	—7	—8
चाय	1,80	1,57	1,25	1,48	1,20	1,22	+2	+2
खाल, छाल, चमड़ा और चमड़े की चीजें,								
जूतों को मिलाकर . .	70	87	99	87	64	74	+10	+16
काजू की गिरी . . .	43	61	57	52	42	51	+9	+21
तेल की खली . . .	45	49	41	55	41	29	—12	—29
मोती, बहुमूल्य और अर्धमूल्य पत्थर,								
न तराशे गए/तराशे गए .	30	45	42	42	31	38	+7	+23
गरम मसाले . . .	27	25	34	39	24	23	—1	—4
मछली और मछली से बनी वस्तुएं .	18	23	31	31	24	29	+5	+21
चीनी	16	10	9	28	18	27	+9	+50
काफी . . .	18	18	20	25	22	19	—3	—14
खनिज मैंगनीज . . .	11	13	11	14	11	8	—3	—27
तमाखू (अनुत्पादित) . .	25	33	33	31	26	35	+9	+35
(इ) जोड़ (अन्यों को मिलाकर) .	11,99	13,58	14,13	15,35	11,50	11,94	+44	+4

नोट : 1 नवंबर 1970 से निर्यातों के रिकार्ड के लिए वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा अपनायी गई क्रियाविधि में (अंतिम रूप से पारित पोतलदान बिल के स्थान पर पोतलदान बिल की मूल प्रति के आधार पर रिकार्ड करने की विधि स्वीकार की गयी) परिवर्तन किये जाने के कारण 1970-71 और 1971-72 के आंकड़ों की पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती।

स्रोत : वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय

सारणी 17—भारत के मुख्य आयात

(राशि करोड़ रुपयों में)

पण्य	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	अप्रैल-दिसम्बर		(5) की अपेक्षा (6) में वृद्धि (+)/कमी (—)	
					1970	1971	वास्तविक	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. अनाज (काजू को छोड़कर)	554	372	293	242	187	131	— 56	—30
अनाज और उनसे बनी वस्तुयें	518	336	261	213	170	105	— 65	—38
2. कच्ची रुई	83	90	83	99	74	87	+ 13	+18
3. पटसन और मेस्ता	5	16	5	नगण्य	नगण्य	—	—	—
4. काजू	25	31	28	29	22	20	—2	—10
5. खनिज तेल :	75	133	138	136	96	143	+47	+49
उनमें से]								
(क) कच्चा और अंशतः परिशोधित पैट्रोलियम	60	96	96	106	76	110	+34	+45
(ख) अन्य	15	37	42	30	20	33	+13	+65
6. रासायनिक पदार्थ :	273	283	195	192	135	161	+26	+19
उनमें से :								
(क) उर्वरक	139	139	77	61	38	52	+14	+37
(ख) अन्य	134	144	118	131	97	109	+12	+12
7. लोहा और इस्पात	106	86	82	147	102	179	+77	+75
8. अलौह धातु	89	89	75	120	86	83	—3	—3
9. कच्चा रबड़ (कृत्रिम और सुधारे गये रबड़ को मिला कर)	4	5	10	4	3	3	—	—
10. ऊन और दूसरे पशुओं के रोम	12	11	17	16	13	11	—2	—15
11. पशुओं और वनस्पति के तेल और चर्बी	34	19	30	39	32	32	—	—
12. कागज, गत्ते और उनसे बनी चीजें	18	18	24	25	17	24	+7	+41
13. मोती, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर	12	28	28	25	17	19	+2	+12
14. मशीनें और परिवहन उपस्कर	503	514	396	384	274	349	+75	+27
(क) बिजली से इतर मशीनें	336	366	280	257	190	211	+21	+11
(ख) बिजली की मशीनें	86	82	64	69	49	72	+23	+47
(ग) परिवहन के उपस्कर	81	66	51	58	35	66	+31	+89
15. अन्य	215	214	178	176	125	123	—2	—2
जोड़	**2008**	**1909**	**1582**	**1634**	**1183**	**1365**	**+182**	**+15**

स्रोत :—वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

की वृद्धि की संभावना तब तक अनिश्चित ही रहेगी जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था के सुधार संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति न हो ।

91. इस संदर्भ में भारत और अन्य विकासोन्मुख देशों का यह प्रयत्न रहा है कि वे भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी सुधार कार्य में सक्रिय रूप से सबद्ध हों और विकासोन्मुख देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विशेष आहरण अधिकारों का वितरण कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहे । पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को अस्त व्यस्त कर देने वाली जो कठिनाइयां उपस्थित हुई उनका कारण यह था कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक देश अपने उत्पादन और मांग को संतुलित करने में विफल हो गये थे । इस विफलता के दुष्परिणाम विकासोन्मुख देशों में भी पाये जाते हैं । अतः एक ऐसी व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है जिसमें (क) अंतर्राष्ट्रीय चल मुद्रा के निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण किया जाय, (ख) अपेक्षाकृत कम विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक प्रगति के व्यवस्थित विकास के लिये चलमुद्रा स्थिति में पर्याप्त वृद्धि की जाय और (ग) विनिमय दरों में परिवर्तन करने के लिए स्वीकार्य वस्तुगत मानदंड निर्धारित किया जाय ताकि समायोजन प्रक्रिया सुगम हो । अतः ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और उसकी स्वीकृति के बाद उसका परिचालन करने में विकासोन्मुख देशों को भी पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए ।

मूल्यांकन और संभावनाएं

92. पिछले पैराग्राफों में वस्तुस्थिति का जो सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया है उससे यह विदित होता है कि एक ओर जहां भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष के अंत तक शरणार्थियों के आगमन और युद्ध के तनावों का सफलतापूर्वक सामना कर सकी वहां दूसरी ओर उसने

कतिपय चिन्ताजनक तथ्यों को भी प्रस्तुत किया है । कुल मांग में हुई वृद्धि के अनुपात में उत्पादन में अधिक वृद्धि होने के बजाय मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई यद्यपि कृषि उत्पादन में निश्चित ही वृद्धि हुई है फिर भी औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर अंशतः बिजली, परिवहन और कतिपय कच्ची सामग्री की कमी के कारण चौथी योजना में परिकल्पित दर की अपेक्षा में कम ही थी । अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण औद्योगिक संबंध बिगड़ गये और इसका प्रतिकूल प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ा । यद्यपि देश में हुई अधिक बचत और विदेशों से प्राप्त शुद्ध पूंजी के कारण देशी निवेश में वृद्धि हुई फिर भी निवेश माल उद्योगों की मांग पहले की तरह कम ही रही है । इसी प्रकार जहां एक ओर सरकारी क्षेत्र की कुल प्राप्तियों में वृद्धि हुई है वहां दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र की बचत की मात्रा कम हो गयी है; इसके परिणाम-स्वरूप भारी मात्रा में घाटे की अर्थव्यवस्था करनी पड़ी । इस कारण अर्थव्यवस्था के कुल मुद्रागत साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

93. इस पृष्ठभूमि में पांचवीं योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के कार्यों को निर्धारित करना होगा । इन उद्देश्यों की पूर्ति उत्पादन को तेजी से बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बनाने से ही हो सकती है । उत्पादन को बढ़ाने का मतलब यह होगा कि नये उद्योगों को बढ़ाया जाए, वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए और कृषि क्षेत्र की नयी प्रणालियों को अधिक व्यापक क्षेत्र में विस्तरित किया जाय । इसी प्रकार मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए मांग को व्यवस्थित करना भी अधिक महत्वपूर्ण होगा । इसके लिए ऐसी नीतियों को अपनाना होगा जिनका लक्ष्य इस प्रकार हो कि आमदनियों में होनेवाली वृद्धि अर्थव्यवस्था की उत्पादिता में होने वाली वृद्धि के अनुरूप हो; साथ ही बचत बढ़े और आय का पुनर्वितरण हो । इस नीति को कार्यान्वित करने में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की कठिनाइयां अवश्य रहती हैं । इसके साथ ही इस प्रकार की नीति की आवश्यकता स्पष्ट है, क्योंकि इसके बिना समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में अपने-अपने अंश को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला प्रयास न केवल निरर्थक होगा, बल्कि उत्पादन के योजना-बद्ध लक्ष्यों तक वास्तविक रूप में पहुंचना भी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होगा ।

94. वित्तीय नीति के दृष्टिकोण से इसके लिए दो प्रकार की मूल कार्रवाइयां करनी होंगी । एक तो मुद्रागत विस्तार को सीमाओं के भीतर रखना होगा और दूसरी समाज की बचत को गतिशील बनाने के लिए व्यापक रूप से संस्थागत सुविधाएं प्रदान करनी होंगी । मुद्रागत विस्तार को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्यतः सरकारी क्षेत्र द्वारा की जानेवाली घाटे की अर्थव्यवस्था की मात्रा को सीमित कर देना होगा जैसा कि रिपोर्ट में इसके पहले कहा जा चुका है, कोई राज्य सरकार अब एक सप्ताह की अस्थायी अवधि के सिवाय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट नहीं ले सकती । इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की भी नीति अपनानी होगी । किंतु रक्षा और विकास के संबंध में केन्द्रीय सरकार को जो विशेष जिम्मेदारियां वहन करनी हैं उनके कारण ऐसे ऋण की कोई सुनिर्दिष्ट सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है । फिर भी अत्यावश्यक पण्यों या उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति की वर्तमान लचीली स्थिति को ध्यान में रखते हुए घाटे की अर्थव्यवस्था के स्तर पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए । इससे यह स्पष्ट होता है कि कराधान के आधार को व्यापक बनाने के द्वारा कर की वसूलियों को बढ़ाने, बाजार से लिये जाने वाले ऋणों की मात्रा को अधिकतम बनाने और विशेष रूप से, सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की परिचालन क्षमता में वृद्धि कर उनकी आय को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिए ।

95. वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले प्रयत्न यह अपेक्षा करेंगे कि बैंकिंग सेवाओं को व्यापक और सघन बनाकर मौलिक आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाए । भारत के बैंक व्यवसाय क्षेत्र की गतिविधियों से मालूम होता है कि यदि आवश्यक श्रम शक्ति और अन्य साधनों की व्यवस्था की जाए तो कम विकसित क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में बैंक उपयोगी भूमिका अदा कर सकेंगे । जमाराशियों में प्रत्याशित वृद्धि होने पर बैंक अब तक की अपेक्षा अधिक मात्रा में मीयादी ऋण और निर्यात ऋण भी प्रदान कर सकेंगे । इसका यह आशय होगा कि औद्योगिक, कृषि संबंधी और अन्य क्षेत्रों की कार्यकारी पूंजी की अपेक्षाओं की पूर्ति बिना अधिक कठिनाई के हो जानी चाहिए । फिर भी मध्यावधि और दीर्घावधि पूंजी की समस्या वैसी ही बनी रहेगी । अतः यह आवश्यक होगा कि मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता को जारी रखा जाए और बढ़ाया जाय । साथ ही, यह भी अत्यावश्यक होगा कि औद्योगिक आधार को व्यापक बनाने और उसमें विविधता लाने के लिए नये निवेशों को बढ़ाया जाए । संस्थाओं द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधाओं के अलावा मूल्य-स्थायिता के उद्देश्य को देखते हुए रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह सामान्य ऋण नियंत्रण की नीति का पालन करे ।

II. वाणिज्य बैंक व्यवसाय की प्रगति

96. आलोच्य वर्ष में, बैंकिंग संघटन ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी व्यापकता को बढ़ाने और इस प्रकार बैंक व्यवसाय के विकास के संदर्भ में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे । 1972 और अगले दो वर्षों के लिए शाखा विस्तार की प्रस्तावित व्यापक योजना के अंतर्गत समग्र रूप से 5000 शाखाएं खोलने का कार्यक्रम बनाया गया है । उससे यह आशा की जाती है कि क्षेत्रीय असंतुलन और कम हो जाएगा और साथ ही बैंक भी अपने शाखा विस्तार कार्यक्रम को अग्रणी बैंक योजना के अधीन अग्रणी बैंक होने के कारण अपने ऊपर आयी जिम्मेदारियों के अनुकूल बना सकेंगे । शाखा विस्तार के कार्यक्रम पर निरंतर जोर दिये जाने से यह संभव है कि हाल ही के वर्षों में बैंकों की जमाराशियों में जिस तेजी से वृद्धि हुई है उसे आगे भी बनाये रखा जाएगा ।

97. इस वर्ष भी छोटे किसान, लघु उद्योग उत्पादक, फुटकर व्यापारी, सड़क परिवहन चालक, छोटे-मोटे कारोबार करनेवाले व्यक्ति, व्यवसायिक व्यक्ति और स्वनियोजित व्यक्ति जैसे कम साधनों वाले ऋणकर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता रहा है । इसके साथ ही इस बात पर भी अधिकाधिक जोर दिया जाता रहा कि गुणात्मक आधार पर ऋण दिया जाए । गुणात्मक आधार पर ऋण दिये जाने पर जो बल दिया जाता है उसे अग्रतावाले और उपेक्षित क्षेत्रों के कम साधनों वाले ऋणकर्ताओं को दी जानेवाली ऋण सुविधाओं के लिए भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा दी जानेवाली गारंटी रक्षा संबंधी शर्तों को उदार बनाकर पुष्ट किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार ने विशिष्ट उत्पादक और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न कतिपय निर्दिष्ट कम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए विभेदक ब्याज दरों की योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है और यह आशा की जाती है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक इस योजना के अधीन लगभग 20 करोड़ रुपयों के ऋण प्रदान करेंगे; इससे इन वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में उक्त बैंकों का योगदान और अधिक बढ़ेगा ।

98. अग्रणी बैंक योजना के अधीन, शीघ्र प्रभावकारी सर्वेक्षणों के आधार पर रिपोर्टें तैयार करने के कार्य में काफी प्रगति हुई है । कई

जिलों में बैंक व्यवसाय के विकास के लिए सलाहकार समितियों का निर्माण करने के अलावा ऋण संबंधी अंतरालों का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन कार्य करने की दिशा में भी कुछ प्रयास किये गये हैं ।

99. सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्रीय योजनाएं बना रहे हैं । उदाहरण के तौर पर उन योजनाओं को लिया जा सकता है जिनके अंतर्गत बैंक अभिस्वीकृत गांवों के किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयास करते हैं । इन योजनाओं से ऐसे अवसर कम होंगे कि एक ऋणकर्ता को एक से अधिक संस्थागत ऋण अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो । इसके अलावा बैंक भी प्रदत्त ऋणों के अंतिम उपयोग का अधिक अच्छा निरीक्षण कर सकेंगे । छोटे कृषक विकास एजेन्सी प्रायोजनाएं/सामान्य कृषक और कृषि श्रम प्रायोजनाएं अभी तक प्रारंभिक अवस्था में हैं और अधिकारी योग्य व्यक्तियों का पता लगा रहे हैं । यदि राज्य अधिनियमों पर विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर राज्य सरकारें तेजी से कार्रवाही करें तो वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण दिये जाने में और अधिक सुविधा होगी ।

100. इस संदर्भ में स्वनियोजित व्यक्तियों, कारीगरों, शिल्पकारों आदि को ऋण प्रदान करने की दिशा में अनुभव प्राप्त करने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा देश भर में किये गये 60 केन्द्रों के चयन का उल्लेख भी किया जा सकता है । सक्षम उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बैंक आफ बड़ौदा ने जो विविध सेवा एजेंसी शाखा खोली वह भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है । रोजगार की संभाव्यता को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार की योजनाएं बनाने के संबंध में रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से संपर्क बनाये हुए है ।

101. इस लेखा वर्ष के अंत में केन्द्रीय क्षेत्र अर्थात् मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए उस क्षेत्र की बैंकिंग गतिविधियों का पुनरीक्षण करने के निमित्त बनायी गयी क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक लखनऊ में बुलाई गयी । समिति ने अग्रतावाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने और राज्य सरकारों और बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करने से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया । बैठक में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों और साथ ही छोटे ऋणकर्ताओं, विशेषकर किसानों को दिये जानेवाले ऋणों को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन करने का निर्णय किया गया ।

102. बैंकों ने यह भी स्वीकार किया है कि अग्रतावाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए एक सशक्त कार्यक्रम बनाने की दिशा में संगठनात्मक बाधाएं रहती हैं और इस कारण उन्होंने अपने वर्तमान संगठन स्वरूप को या तो पुनर्गठित कर लिया है या वे पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहे हैं । इसके लिए उन्होंने प्रधान कार्यालय और साथ ही क्षेत्रीय और जिला स्तरीय कार्यालयों में भी परिचालन और विकास कार्य से संबंधित उपयुक्त मिश्रित कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता को स्वीकार किया है ।

103. निम्नलिखित अनुच्छेदों में वाणिज्य बैंकों के संगठन स्वरूप में किये गये परिवर्तनों और विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में हुई प्रगति के विवरण दिये गये हैं ।

शाखा विस्तार

104. वाणिज्य बैंकों ने 1969 में 1,369 कार्यालय, 1970 में 2,137 कार्यालय और 1971 में 1,805 कार्यालय खोले; इस प्रकार दिसंबर 1971 को समाप्त हुए तीन वर्षों में कुल मिलाकर 5,311 कार्यालय खोले गए। शाखा विस्तार की व्यापक योजना के अधीन 1974 में समाप्त होनेवाले तीन वर्षों की अवधि में भी इस गति को बनाये रखने का प्रस्ताव किया गया है । इसके अधीन, वाणिज्य बैंक 1972 और 1973 में प्रतिवर्ष कम से कम 1,500 शाखाएं और 1974 में संभवतः उससे भी थोड़ी अधिक शाखाएं खोल सकेंगे । इस प्रकार इस अवधि में कुल मिलाकर लगभग 5,000 शाखाएं खोली जाएंगी । बैंकों को शाखाओं का अधिक विस्तार करने के संदर्भ में क्षेत्रों का चयन करने के मामले में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की सलाह दी गयी है । साथ ही उनसे यह भी कहा गया है कि वे बैंक व्यवसाय की संभावनाओं से युक्त केन्द्रों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य, अपने लिए निर्धारित अग्रणी जिलों में अपने उत्तरदायित्व, अपने कार्यक्षेत्रों और अपेक्षाकृत कम विकसित/कम बैंकिंग सुविधाओंवाले राज्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी ध्यान दें । इसके अलावा बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपनी शाखाओं के वर्तमान कारोबार और भविष्य के उनके लक्ष्यों के संदर्भ में उनके कार्य की जानकारी निरंतर प्राप्त करते रहें ।

105. 1971-72 के लेखा वर्ष में, वाणिज्य बैंकों ने 1970-71 के 1,890 कार्यालयों के मुकाबले में 1,612 कार्यालय खोले । इस वर्ष के दौरान खोले गए कुल कार्यालयों में से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 821 कार्यालय और स्टेट बैंक आफ़ इंडिया और उसके सहायक बैंकों ने 439 कार्यालय खोले । बैंक सुविधारहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों की संख्या 936 थी (सारणी 18) ।

106. बैंकिंग संघटन के क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में की गयी प्रगति को इस वर्ष के दौरान बनाये रखा गया (सारणी 19) । राष्ट्रीयकरण के बाद अर्थात् जुलाई 1969 से जून 1972 के अंत तक खोले गये 5,375 कार्यालयों में से लगभग 3,416 कार्यालय बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये थे (63.5 प्रतिशत) । इन नये कार्यालयों में से 31.6 प्रतिशत कार्यालय अल्पविकसित राज्यों अर्थात् असम, बिहार जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में खोले गये थे । बैंक सुविधारहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों में से भी 34.1 प्रतिशत कार्यालय इन राज्यों में खोले गये थे । मणिपुर राज्य और अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली तथा मिज़ोराम के संघशासित क्षेत्रों में इस वर्ष के दौरान सभी कार्यालय बैंक सुविधारहित केन्द्रों में खोले गए थे ।

107. 1971-72 में खोली गयी 1,612 अतिरिक्त शाखाओं की वृद्धि से प्रति बैंक कार्यालय उसकी सेवा प्राप्त आबादी जहां जून 1971 में 46,000 थी, वहां जून 1972 में घटकर 40,000 हो गयी । नागालैंड और त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में और संघशासित क्षेत्रों में से लक्कदीव, मिनीकाय और अमीनी द्वीप को छोड़कर सभी क्षेत्रों में यह कमी पायी गयी । अब केवल दो ही ऐसे जिले हैं जहां बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; वहां भी शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं ।

108. इस वर्ष शाखाओं की विस्तार दर में थोड़ी सी कमी होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के खोले जाने की दिशा में बैंकों का झुकाव इस वर्ष के दौरान भी अनुकूल बना रहा (सारणी 20) । कुल बैंक-शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक शाखाओं का अनुपात जहां जून 1971 के अंत में 35.6 प्रतिशत था वहां जून 1972 के अंत में 38.7 प्रतिशत हो गया ।

109. आठ महानगरीय केन्द्रों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलूर, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर और मद्रास के बैंकों के कारोबार के संबंध में हाल ही में किये गये अध्ययन से यह पता लगा कि इन केन्द्रों में जमाराशियों की अधिक संभावनाएं हैं और महानगरीय केन्द्रों में अधिक बैंक कार्यालय खोलने की संभावनाएं रहती हैं । यह भी महसूस

सारणि 18—वाणिज्य बैंकों द्वारा 1970-71 और 1971-72 में खोले गये नये कार्यालय

	वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय						बैंक कार्यालय	
	1970-71			1971-72			30 जून 1971 को	30 जून 1972 को
	जुलाई-दिसम्बर 1970	जनवरी-जून 1971	जुलाई 1970-जून 1971	जुलाई-दिसम्बर 1971	जनवरी-जून 1972	जुलाई 1971-जून 1972		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. स्टेट बैंक आफ इंडिया	234	178	412	187	102	289	2286	2575
	(164)	(123)	(287)	(106)	(58)	(164)		
2. स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक बैंक	86	87	173	66	84	150	1233	1383
	(64)	(55)	(119)	(39)	(46)	(85)		
3. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक	608	444	1052	540	281	821	6368	7189
	(413)	(245)	(658)	(321)	(149)	(470)		
4. अन्य अनुसूचित बैंक	124	115	239	175	165	340	1875	2238
	(57)	(65)	(122)	(108)	(99)	(207)		
5. विदेशी बैंक	—	—	—	—	—	—	130	130
	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)		
6. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1052	824	1876	968	632	1600	11892	13515
	(698)	(488)	(1186)	(574)	(352)	(926)		
7. गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5	9	14	4	8	12	121	105
	(—)	(8)	(8)	(3)	(7)	(10)		
8. सभी वाणिज्य बैंक	1057	833	1890	972	640	1612	12013	13620
	(698)	(496)	(1194)	(577)	(359)	(936)		

नोट :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों की संख्या के द्योतक हैं ।

किया गया कि बड़े शहरों में विशेषकर व्यापार क्षेत्रों में कार्यालयों की संख्या में वृद्धि करने से पहले से ही वहां रहने वाले ऐसे कार्यालयों को, जो कारोबार में तेजी से होने वाली वृद्धि को संभालने में कठिनाई महसूस करते हैं, राहत मिलेगी और साथ ही, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हुए कारोबार को व्यवस्थित करने में उन्हें सहायता मिलेगी । इसके परिणाम-स्वरूप ग्राहकों की सेवा में भी सुधार होगा । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, महानगरीय क्षेत्रों में और कुछ शहरी केन्द्रों में प्रति बैंक कार्यालय उसकी सेवा प्राप्त आबादी को 10,000 से घटाकर 5,000 कर दिया गया है । इसके अलावा, महानगरों और पत्तन शहरों सहित अन्य शहरों में कार्यालय खोलने का अधिकार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में निर्दिष्ट संख्या में कार्यालय खोलने की जो अनिवार्यता थी उसमें भी छूट दे दी गयी है जिससे कि महानगरों/पत्तन शहरों में और अधिक कार्यालय खोले जा सकें । परिवर्धित मानक के अनुसार, जिस बैंक के 60 प्रतिशत या उससे अधिक कार्यालय ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों में हों वह ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों में अपने द्वारा खोले गये प्रत्येक दो कार्यालयों के लिए शहरी केन्द्र और महानगर/पत्तन शहर में एक एक कार्यालय खोलने का पात्र है । अन्य मामलों में ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में खोले गये प्रत्येक तीन कार्यालयों के लिए यह मानक लागू होगा । महानगरीय केन्द्रों के लिए लाइसेंस जारी करने की दिशा में हुई प्रगति में तीव्रता लाने के लिए छः केन्द्रों अर्थात बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास और बंगलूर में बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठकें हुई और इन शहरों में 728 कार्यालय खोलने के लिए वितरण संबंधी व्यवस्थाएं की गयीं । बैंकों को शहरी क्षेत्रों में और 303 कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है । आशा कि जाती है कि इन उपायों से शहरी क्षेत्रों में विद्यमान जमाराशियों की संभावनाओं का उपयोग किया जा सकेगा और इससे वहां पहले से ही विद्यमान बैंक कार्यालयों पर पड़नेवाले दबाव दूर होंगे और साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के कार्यक्रम की गति भी बनी रहेगी ।

सारणी 19--जून 1970, जून 1971 और जून 1972 के अन्त में विद्यमान बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण

राज्य	कार्यालयों की संख्या		1970-71 के दौरान खोले गये		1971-72 के दौरान खोले गये		आबादी प्रति बैंक कार्यालय (हजार में)	
	जून 1970 के अन्त में	जून 1971 के अन्त में	जून 1972 के अन्त में	जोड़	उनमें से बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये	जोड़	उनमें से बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये	जून 1971 के अन्त में	जून 1972 के अन्त में
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	722	869	959	147	95	90	44	50	45
2. असम	96	122	149	26	23	27	22	120	98
3. बिहार	361	453	541	92	62	88	68	124	104
4. गुजरात	919	1105	1234	187	106	129	83	21	22
5. हरियाणा	219	258	299	39	19	41	29	39	34
6. हिमाचल प्रदेश	62	87	108	25	23	21	19	40	32
7. जम्मू और काश्मीर	71	101	116	27	13	15	8	46	40
8. केरल	713	845	978	132	100	136	92	25	22
9. मध्य प्रदेश	460	566	669	107	62	103	58	73	62
10. महाराष्ट्र	1301	1471	1679	167	86	208	77	34	30
11. मणिपुर	2	5	6	3	3	1	1	215	178
12. मेघालय	11	15	16	4	4	1	—	67	63
13. मैसूर	954	1124	1292	170	107	168	107	26	23
14. नागालैंड	4	5	5	1	1	—	—	103	103
15. उड़ीसा	133	173	192	40	30	19	12	126	114
16. पंजाब	465	556	651	91	55	95	59	24	21
17. राजस्थान	432	525	570	93	61	45	25	49	45
18. तमिलनाडु	1213	1371	1484	164	107	115	73	30	28
19. त्रिपुरा	6	12	12	6	6	—	—	130	130
20. उत्तर प्रदेश	932	1147	1324	215	142	177	107	77	67
21. पश्चिम बंगाल संघशासित क्षेत्र	588	684	760	96	67	76	40	65	58
22. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2	4	—	—	2	1	57	29
23. अरुणाचल प्रदेश	—	3	5	3	3	2	2	156	94
24. चंडीगढ़	26	28	33	2	—	5	—	9	8
25. दादरा और नागर हवेली	1	3	4	2	2	1	1	25	19
26. दिल्ली	318	350	385	32	2	35	1	12	10
27. गोवा, दमन और दीव	101	111	118	10	9	7	4	8	7
28. लक्का, दीव मिनीकॉय और अमीनी द्वीप	—	2	2	2	2	—	—	16	16
29. मिजोराम	—	—	1	—	—	1	1	—	332
30. पांडिचेरी	13	20	24	7	4	4	2	24	20
जोड़	**10131**	**12313**	**13620**	**1890**	**1194**	**1612**	**936**	**46**	**40**

सारणी 20--वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का केन्द्रवार वितरण

	निम्नलिखित अवधि के अन्त में कार्यालयों की संख्या									
	जून 1969		जून 1970		जून 1971		दिसम्बर 1971		जून 1972	
	संख्या	जोड़ में %	संख्या	जोड़ में %	संख्या	जोड़ में %	संख्या	जोड़ में %	संख्या	जोड़ में %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1) ग्रामीण	1832	22.4	3062	30.2	4279	35.6	4889	37.5	5267	38.7
(2) अर्ध शहरी	3322	40.1	3695	36.5	4016	33.4	4224	32.6	4351	31.9
(3) शहरी	1447	17.5	1583	15.6	1778	14.8	1850	14.3	1916	14.1
(4) महानगर/पत्तन शहर	1661	20.0	1791	17.7	1940	16.2	2022	15.6	2086	15.3
जोड़	8262	100.0	10131	100.0	12013	100.0	12985	100.0	13620	100.0

110. समामेलन, आस्तियों और देयताओं के अंतरण, रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंकों के जोड़े या उसमें से हटाये जाने के कारण कार्यालयों की संख्या में परिवर्तन होने के बावजूद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 1623 की वृद्धि हुई । परन्तु गैर अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 16 की कमी हुई (सारणी 21) । जून 1972 के अंत में अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या क्रमशः 13,515 और 105 थी जब कि उनकी संख्या जून 1971 के अंत में क्रमशः 11,892 और 121 थी ।

अग्रणी बैंक योजना :

111. पिछली रिपोर्ट में बैंकों द्वारा अग्रणी बैंक योजना के अधीन उनके लिए नियत किये गये जिलों का शीघ्र और प्रभावकारी ढंग

सारणी 21:—अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा भारत में खोले गये और बंद किये गये कार्यालयों की संख्या

	खोले गये नये कार्यालय	समामेलन, विलयन, आस्तियों और देयताओं के अंतरण तथा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़े या उसमें से हटाये जाने के कारण परिवर्तन	बंद किये गये वर्तमान कार्यालय	कार्यालयों की संख्या में समग्र घट-बढ़	अवधि के अंत में कार्यालयों की संख्या
	1	2	3	4	5
अनुसूचित वाणिज्य बैंक :					
1969 जनवरी-जून	565 (24)	+1	—3	+563	8045
जुलाई-दिसंबर	772 (65)	+53	—3	+822	8867
1970 जनवरी-जून	1068 (190)	+3	—	+1071	9938
जुलाई-दिसंबर	1052 (234)	+54	—4	+1102	11040
1971 जनवरी-जून	824 (178)	+32	—4	+852	11892
जुलाई-दिसंबर	968 (187)	+28	—	+996	12888
1972 जनवरी-जून	632 (102)	—	—5	+627	13515
गैर अनुसूचित बैंक					
1969 जनवरी-जून	11	—1	—	+10	217
जुलाई-दिसंबर	21	—53	—1	—33	184
1970 जनवरी-जून	12	—3	—	+9	193
जुलाई-दिसंबर	5	—54	—	—49	144
1971 जनवरी-जून	4	—32	—	—23	121
जुलाई-दिसंबर	9	—28	—	—24	97
1972 जनवरी-जून	8	—	—	+8	105
सभी वाणिज्य बैंक					
1969 जनवरी-जून	576	—	—3	+573	8262
जुलाई-दिसंबर	793	—	—5	+789	9051
1970 जनवरी-जून	1080	—	—	+1080	10131
जुलाई-दिसंबर	1057	—	—4	+1053	11184
1971 जनवरी-जून	833	—	—4	+829	12013
जुलाई-दिसंबर	972	—	—	+972	12985
1972 जनवरी-जून	640	—	—5	+635	13620

नोट : 1. कोष्टकों में दिये गये आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से संबंधित हैं।

2. इन आंकड़ों में प्रशासनिक, मौसमी, अस्थायी और गैर बैंकिंग कार्यालय और भारत के बाहर स्थित कार्यालय शामिल नहीं हैं।

से सर्वेक्षण करवाये जाने के उद्देश्य से उठाये गये कदमों का उल्लेख किया गया था। तब से बैंकों ने जिलों के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में अच्छी प्रगति की है। इस प्रकार बैंकों को वितरित किये गये कुल 337 जिलों में से 260 जिलों से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट अब तक पूरी हो चुकी हैं। रिपोर्टों को तैयार करते समय बैंकों ने इस बात का ध्यान रखा है कि अल्प विकसित राज्यों अर्थात् असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सर्वेक्षण विवरण उनमें आयें। वस्तुतः इन राज्यों के 80 प्रतिशत जिलों के विवरण उनमें दिये जा चुके हैं।

112. इस वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अग्रणी बैंक सर्वेक्षणों द्वारा पता लगाये गये केन्द्रों का वितरण करने के लिए जयपुर में एक बैठक का आयोजन किया। इसको मिलाकर, रिजर्व बैंक ने अब तक ऐसी सात बैठकों का आयोजन किया है और इन बैठकों में 833 बैंक-सुविधारहित केन्द्रों को विभिन्न वाणिज्य बैंकों में वितरित कर दिया गया है। अग्रणी बैंक सर्वेक्षणों द्वारा पता लगाये गये बैंक-सुविधारहित केन्द्रों को वितरित करने के लिए बैंक जिला स्तर पर भी ऐसी बैठकों का आयोजन करते रहे हैं।

113. अग्रणी बैंकों के नाम से अभिहित किये जाने वाले बैंकों से शाखा विस्तार की व्यापक योजना के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे केन्द्रों के नामों की सूचना जहां बैंकों के कार्यालय खोले जा सकते हों, अन्य सभी बैंकों और रिजर्व बैंक आफ इंडिया को दें ताकि अग्रणी और गैर अग्रणी जिलों में बैंकों द्वारा किये जाने वाले शाखा विस्तार कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जा सके। इससे अग्रणी बैंक होने के कारण बैंकों को जो उत्तरदायित्व वहन करने पड़ते हैं उनके अनुरूप उनके शाखा विस्तार कार्यक्रम को बनाने में भी सहायता मिलेगी।

114. इस योजना के अधीन अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में बैंकों ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में जिला स्तरीय परामर्श समितियों का गठन किया है। इन समितियों के उद्देश्य इस प्रकार हैं : ऋणकर्ताओं और अग्रता वाले क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान हो, जिलों में बैंक सुविधाओं की व्यवस्था करने वाली योजनाओं की संभावनाओं का पता लगाया जाए और समन्वित रूप से उन योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए आवश्यक प्रणालियां निर्धारित की जाएं। लगभग सौ जिलों में ऐसी समितियों का गठन किया जा चुका है। बैंकों को यह सलाह भी दी गयी है कि वे राज्य सरकारों के अधिकारियों से संपर्क बनाये रखें।

115. अग्रणी बैंक कार्यक्रम का एक प्रमुख कार्य इस प्रकार है : बैंक तेजी से किये गये सर्वेक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में क्षेत्रीय प्रायोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवश्यक योजनाएं बनाने के निमित्त गंभीर अध्ययन करेंगे। यद्यपि इस संबंध में थोड़ी सी प्रगति की गई है, फिर भी जितने सर्वेक्षण किये गये हैं, और जितने जिले ऐसे अध्ययनों के अंतर्गत आए हैं वे आवश्यकता के अनुपात में पर्याप्त नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि बैंकों के पास कृषि और लघु उद्योगों के क्षेत्रों में अपने अग्रणी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी दृष्टि से दक्ष कर्मचारी नहीं थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पुनर्गठन और पुनः कर्मचारियों को भर्ती करने की योजनाओं के द्वारा इस बाधा को दूर करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए वित्तीय सहायता

116. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के नाम कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जाने का उल्लेख किया गया था। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में वाणिज्य बैंक कृषि ऋण के संदर्भ में अपनी ऋण नीतियों और क्रियाविधियों को परस्पर अनुरूप बनाने का प्रयास करते रहते हैं। परन्तु इस वर्ष वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों की वृद्धि में कमी आयी; इस कमी का आंशिक कारण यह है कि गुणवत्ता के अनुसार ऋण प्रदान किये जाने और उनके अंतिम उपयोग का प्रभावशाली ढंग से पर्यवेक्षण किये जाने पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा। बैंक अब तक व्यापक क्षेत्रों में जो प्रयत्न करते थे उनसे उन क्षेत्रों के सभी भाग समान रूप से लाभान्वित होते थे। किन्तु अब बैंक इस प्रकार की कार्य पद्धति को धीरे-धीरे समाप्त कर रहे हैं और क्षेत्रीय योजनाओं, एकीकृत प्रणालियों, गांवों को अभिस्वीकृत करने की पद्धतियों, वर्गवार ऋण प्रदान करने के तरीकों आदि के सघन कार्यक्रमों को तैयार कर रहे हैं। इसका उदाहरण स्टेट बैंक आफ इंडिया का वह निर्णय है जिसके अनुसार देश भर में कृषि विकास शाखाएं खोलने के लिए 150 केन्द्रों का चुनाव किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक शाखा में तकनीकी और अन्य क्षेत्र कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी और यह आशा की जाती है कि अंत में प्रत्येक शाखा लगभग 100 गांवों को सेवा प्रदान करेगी। चूंकि पता लगाये गये अनेक केन्द्र छोटे किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए बनाये गये सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत आ जाते हैं इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि छोटे कृषक विकास एजेंसी/सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों की भूमिका में वृद्धि हो जाए। जैसे ही छोटे कृषक विकास एजेन्सी/सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं के प्राधिकारी बैंकों को योग्य व्यक्तियों की सूची एक बार उपलब्ध करा देंगे, वे फ़सल उगाने, डेरी उद्योग और सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने आदि के लिए ऋण संबंधी सहायता प्रदान कर सकेंगे। बैंकों को अपनी संगठन क्षमता के अनुसार इन क्षेत्रों में कुछ विस्तार कार्य करना पड़ सकता है। कृषि के सघन वित्तपोषण के लिए बैंकों ने स्वयं अपनी भी विशेष योजनाएं बनाई हैं।

117. अप्रैल, 1972 में रिजर्व बैंक के तत्वावधान में बड़े वाणिज्य बैंकों के कृषि वित्त विभागों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गयी जिसमें कृषि के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों में पायी गयी सामान्य कमी के कारणों और बैंकों द्वारा अपनाये गये क्षेत्रगत् दृष्टिकोण की पद्धति पर विचार-विमर्श किया गया। ऐसा सोचा गया कि केवल एक बैंक के लिए क्षेत्रों को निर्धारित करना वांछनीय नहीं है; क्योंकि इससे कृषि ऋण के संदर्भ में विविध सेवा एजेंसी दृष्टिकोण का सिद्धांत ही विफल हो जाएगा। दस मील की परिधि में किसी शाखा के अधिकार क्षेत्र का निर्धारित किया जाना कोई कठोर मानक नहीं है, बल्कि ऋणों की पर्यवेक्षण क्षमता के संदर्भ में जो महत्व दिया जाता है उसका परिचायक मात्र है। बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि वाणिज्य बैंकों को अपनी शाखाओं से ऋणों की मांग, वसूली और बकाया राशि की सूचना प्राप्त की जानी चाहिए।

118. इस बात को संभव बनाने के लिए कि कृषि के लिए वाणिज्य बैंक अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करें, कृषि के लिए

ऋण प्रदान करने वाले वाणिज्य बैंकों से संबंधित राज्य अधिनियमों, पर विशेषज्ञ दल द्वारा दी गयी सिफ़ारिशों पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सितम्बर 1971 में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह रिपोर्ट विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों/मुख्य सचिवों के पास भेजी थी। उन्होंने उनसे यह अनुरोध किया था कि राज्य विधान मंडल विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारिश किये गये आदर्श विधेयक को जल्दी अधिनियम का रूप दें जिससे कि वाणिज्य बैंकों से ऋण लेने वाले कृषकों को ये सारी सुविधायें प्राप्त करायी जा सकें जो सहकारी बैंकों से ऋण लेते समय उन्हें प्राप्त होती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारिश किये गये कतिपय प्रशासनिक उपायों को लागू करने की दिशा में कदम उठाये हैं। किन्तु अधिकांश राज्यों में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसार अधिनियम बनाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

119. निगम द्वारा 1 अप्रैल 1971 से शुरू की गयी भारतीय ऋण गारंटी निगम (छोटे ऋण) गारंटी योजना 1971 को इस वर्ष काफी अधिक उदार बना दिया गया है ताकि अधिक उपयुक्त ऋणकर्ताओं और और ऋणों को गारंटी की सुविधा दी जा सके। 1 जनवरी 1972 से लागू किये गये उदारीकरण के अधीन निगम की गारंटी के साथ किसानों और काश्तकारों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों की राशि पर सीमा संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं होता। उपर्युक्त उद्देश्यों में (चाय, काफ़ी या रबड़ से इतर) फ़सलों की खेती या भूमि का विकास या सुधार या मत्स्यपालन और रेशम उत्पादन जैसे संबंधित कृषि कार्य शामिल हैं। साथ ही ऐसे मौसमी ऋणों पर भी कुछ शर्तों के अधीन गारंटी प्रदान की जाती है जिन्हें प्राकृतिक या अन्य विपत्तियों के कारण अथवा किसानों के नियंत्रण के बाहर की विपरीत परिस्थितियों के कारण चुकाया नहीं गया हो और जिन्हें मीयादी या किस्त ऋणों में बदल दिया गया हो। फ़सल के उत्पादन के लिए दिये जाने वाले ऋणों को चुकाने की अधिकतम अवधि को 15 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दिया गया है और मौसमी कृषि संबंधी कार्यों को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों को चुकाने की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है।

120. 31 दिसम्बर 1971 तक निगम ने केवल ऋण संबंधी उन सुविधाओं के लिए गारंटी प्रदान की जो 1 अप्रैल 1971 के बाद वाणिज्य बैंकों ने प्रदान की थीं। परन्तु उदारीकृत उपबन्धों के अधीन 1 जनवरी 1972 को कारोबार शुरू करते समय बकाया रहने वाले सभी ऋणों के लिए गारंटी उपलब्ध है चाहे किसी भी तारीख को ऋण सुविधाएं मंजूर की गयी हों या उनका उपयोग किया गया हो। किन्तु शर्त यह है कि संबंधित ऋणकर्ता और प्रदान की गयी ऋण सुविधाएं उदारीकृत उपबंधों के अनुरूप हों। परन्तु 1 जनवरी 1972 को बकाया रहने वाली ऐसी ऋण सुविधाओं को इस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया है जिन्हें पहले ही वापस लिया जा चुका हो या अशोध्य या संदिग्ध समझा जा चुका हो या जिनका उपयोग पहले के अशोध्य या संदिग्ध ऋणों के समायोजन के लिए किया जा चुका हो या ऋणकर्ताओं ने अपने कार्यकलापों या कारोबार को बंद कर दिया हो। उदारीकृत उपबंधों के अधीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को गाड़ियां खरीदने के लिए परिवहन चालकों को दिये गये ऋणों के संदर्भ में एक लाख रुपये तक के लिए गारंटी सुविधा प्राप्त है; अब तक यह सुविधा 50,000 रुपयों तक के लिए दी जाती थी। उर्वरकों के उन व्यापारियों जिनकी वार्षिक बिक्री की राशि 5 लाख रुपयों तक (पहले यह सीमा 2 लाख रुपये थी) हो और ऐसे पैट्रोल स्टेशनों और खनिज तेलों के अन्य फुटकर व्यापार केन्द्रों के मालिकों जिनकी वार्षिक बिक्री की राशि 5 लाख रुपयों तक (पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी) हो, इस योजना के अधीन गारंटी सुविधा प्राप्त हो सकती है।

121. इस वर्ष निगम ने दो अन्य योजनाएं शुरू की। भारतीय ऋण गारंटी निगम छोटे ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना 1 जुलाई 1971 को शुरू की गयी। इस योजना के अधीन तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड सहित राज्य निगमों द्वारा प्रदान किये गये ऋण आते हैं। यह योजना पहले बतायी गयी छोटे ऋण गारंटी योजना के समान है। इस योजना के अधीन परिवहन चालकों, छोटे होटल मालिकों और ऐसे कारोबारी उद्यमों जो बिजली या किसी दूसरे प्रकार के पावर के उत्पादन में लगे हों या आसपास की भूमि को मिलाकर किसी क्षेत्र को औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित या प्रबन्धित करने में लगे हों अर्थात् ऐसे ऋणकर्ताओं जिन्हें वित्तीय निगम वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में हों और जो केन्द्रीय सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलायी गयी लघु उद्योग संबंधी ऋण गारंटी योजना के अधीन न आते हों, को दी जाने वाली ऋण सुविधाएं आती हैं। 1 जनवरी 1972 से वित्तीय निगम गारंटी योजना को भी उदार बना दिया गया ताकि 1 जनवरी, 1972 को बकाया रहने वाली सभी उपयुक्त ऋण सुविधाएं और प्रत्येक परिवहन चालक को दी गयी 1 लाख रुपये तक की परिवहन संबंधी वित्तीय सहायता उसके अंतर्गत आ सकें।

122. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना 1 अक्तूबर 1971 से अमल में लायी गयी। उक्त योजना के अधीन किसी भी तरह के औद्योगिक कार्य में संलग्न कारीगरों और कामगारों को सहायता प्रदान करने वाली सेवा सहकारी समितियों को प्रदान की गयी ऋण संबंधी सुविधाओं के लिए गारंटी दी जाती है। यह सुविधा देश के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध है। इस योजना से लाभान्वित होने वाली दूसरी ऋण संस्थाएं राज्य और संघशासित क्षेत्रों के ऐसे राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जिन पर जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 के उपबंध लागू हो चुके हैं।

123. दिसंबर 1971 के अंत तक निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं की राशि छोटे ऋण गारंटी योजना के संदर्भ में 71 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से 63 बैंकों के मामले में 109.72 करोड़ रुपये और वित्तीय निगम गारंटी योजना के संदर्भ में 18 वित्तीय निगमों में से 13 निगमों के मामले में 2.60 करोड़ रुपये थी। सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना के संदर्भ में एक बैंक को 1.89 लाख रुपयों की ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी थीं। निगम ने किसानों और काश्तकारों और अन्य ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले सहकारी ऋण को गारंटी रक्षा प्रदान करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

124. 31 दिसम्बर 1971 को समाप्त हुए वर्ष में लघु ऋणों और वित्तीय निगमों की गारंटी योजनाओं के संदर्भ में निगम को गारंटी शुल्कों के रूप में 4.05 लाख रुपये प्राप्त हुए। निगम को अब तक कोई दावे प्राप्त नहीं हुए हैं। निगम से किये जाने वाले दावों को निपटाने के उद्देश्य से यह विचार किया गया है कि असमाप्त गारंटी जोखिमों की एक प्रारक्षित निधि बनायी जाए जिसमें ऐसी राशि जमा

की जाए जो वर्ष के दौरान वसूल किये गये गारंटी शुल्कों में से उस वर्ष में अदा किये गये दावों की राशि घटाने पर शेष रहने वाली शुल्क राशि के 50 प्रतिशत से कम या 100 प्रतिशत से अधिक न हो। तदनुसार 1971 के दौरान प्राप्त किये गये 4.05 लाख रुपयों की पूरी राशि अवमाप्त गारंटी जोखिमों की प्रारक्षित निधि में जमा की गयी।

विभेदक ब्याज दरें

125. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 25 मार्च 1972 को संसद में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में विभेदक ब्याज दरों की योजना लागू करने के सरकार के निर्णय की घोषणा की। योजना के अधीन ली जाने वाली विभेदक ब्याज दर फिलहाल समान रूप से 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को सरकार के निर्णय की सूचना दी तथा उन्हें यह भी सूचित किया कि योजना के अधीन ऋणों के लिए पात्र व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कौन से मानदंड हैं और किन शर्तों के अधीन ऋण दिये जाने चाहिए।

126. जिस उद्यम में कुछ समय के बाद आत्मनिर्भर होने की क्षमता हो, वह उद्यम इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। जिन क्षेत्रों में से बैंकों को योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों का पता लगाना होगा, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं; अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों के लोग तथा अन्य लोग जो सामान्य स्तर पर कृषि और या/उससे संबद्ध कार्यों में लगे हों; वन उत्पादों के संग्रहण या प्रारंभिक संसाधन के कार्य में लगे हुए लोग, कठिन क्षेत्रों में चारा इकट्ठा कर उसे कृषकों या व्यापारियों को बेचने वाले लोग, सामान्य स्तर पर कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में तथा अन्य व्यवसायों में स्वयं परिश्रम करने वाले लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अच्छी योग्यता वाले गरीब विद्यार्थी, लाभप्रद व्यवसाय करने वाले विकलांग लोग ऐसे अनाथालय और महिला-गृह जहां विक्रेय वस्तुएं बनायी जाती हों और जिनके लिये पर्याप्त और निश्चित वित्तीय आधार न हो। इस योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जिसके परिवार की आय, यदि वह शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाला हो तो वार्षिक 2,000 रुपयों से अधिक न हो और यदि वह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हो तो वार्षिक 1,200 रुपयों से अधिक न हो। इसके अलावा, उसके पास एक एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो और यदि भूमि सिंचित न हो तो वह 2.5 एकड़ से अधिक न हो।

127. यद्यपि अलग-अलग व्यक्तियों को ऋण दिये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी बैंकों को चाहिए कि वे प्रारंभ में विशेष रूप से व्यक्ति समूहों को ऋण दें। योजना के अधीन कार्यकारी पूंजी और अचल आस्तियां प्राप्त करने के निमित्त पांच वर्षों से अनधिक अवधि के मीयादी साख के लिए ऋण प्रदान किये जायेंगे। यह आशा की जाती है कि सामान्यतः कार्यकारी पूंजी की राशि 500 रुपयों और मियादी ऋणों की राशि 2,500 रुपयों से अधिक नहीं होगी। मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं में छूट दी जा सकती है। फिर भी ऋणों की सहायता से खरीदी गयी आस्तियों को बैंक बंधक के रूप में रख ले सकते हैं। प्रत्येक ऋण को वर्तमान ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत रक्षा प्राप्त करनी होती है और उसके संबंध में गारंटी शुल्क का भार बैंकों को वहन करना होगा। ऋणकर्ता की निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक अदायगी के कार्यक्रम बनाये जायेंगे और मीयादी ऋणों के मामले में दो वर्षों से अनधिक अनुग्रह अवधि की भी व्यवस्था की गयी है।

128. उक्त योजना अभी प्रायोगिक स्थिति में है और उसे कतिपय चुने हुए पिछड़े जिलों में कार्यान्वित करना है। छोटे कृषक विकास एजेन्सी/सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं के अधीन आने वाले जिले इस योजना के अंतर्गत नहीं आयेंगे। प्रत्येक बैंक को चुने हुए जिलों की हर आठ या दस शाखाओं में से कम से कम एक शाखा को चुनना है और इस चयन कार्य में ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह आशा की जाती है कि इस योजना के अधीन प्रत्येक बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की मात्रा पिछले वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिये गये कुल ऋणों का लगभग आधा प्रतिशत होगी।

हुंडी पुनर्भाजन योजना

129. भारत में हुंडी बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने के निमित्त नवम्बर 1970 में शुरू की गयी हुंडी पुनर्भाजन योजना को इस वर्ष संशोधित किया गया ताकि उसका कार्य क्षेत्र व्यापक हो सके। सरकारी विभागों और अर्ध सरकारी निकायों तथा सांविधिक निगमों और सरकारी कंपनियों को माल बेचने से उत्पन्न होने वाली विनिमय हुंडियों के लिए भी 30 जुलाई 1971 को यह यह योजना लागू की गयी बशर्ते कि उक्त बिल योजना की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। रिजर्व बैंक को पुनर्भाजित बिलों की दाति करने और रिजर्व बैंक से उन्हें पुनः लौटाने में होने वाले विलंब को दूर करने तथा उसके कार्यभार को कम करने की दृष्टि से 25 अक्तूबर 1971 को यह निश्चय किया गया कि बैंक को 2 लाख रुपयों और उससे कम राशि के अंकित मूल्य की प्रत्येक हुंडी को रिजर्व बैंक के पास वास्तविक रूप से रखने की जो आवश्यकता है उसे समाप्त कर दिया जाए और ऐसी हुंडियों को रिजर्व बैंक के एजेंटों के रूप में अपने पास ही रखने के लिए बैंकों को प्राधिकृत किया जाए। रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्भाजन किये जाने योग्य हुंडी की न्यूनतम राशि को 5,000 रुपयों से कम कर 1,000 रुपये कर दिया गया। 6 अप्रैल 1972 से भारतीय औद्योगिक ऋण और विनिवेश निगम लिमिटेड के खरीदार घटकों की ओर से अकेले अथवा उनके साथ संयुक्त रूप से निगम पर आहरित किये गये और निगम द्वारा स्वीकार किये गये विनिमय बिलों को भी योजना के अधीन पुनर्भाजन योग्य बना दिया गया बशर्ते कि कोई योग्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक उन्हें पुनर्भाजन के लिए प्रस्तुत करे। इसके अलावा नयी हुंडी पुनर्भाजन योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाने की दृष्टि से उधार मामलों में बैंकों को रिजर्व बैंक ने यह सलाह दी है कि वही-ऋण सीमाओं को जहां तक संभव हो हुंडी सीमाओं में परिवर्तित कर दिया जाए। इसके साथ ही बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपने द्वारा भुनायी गयी हुंडियों के संबंध में अधिकाधिक मात्रा में हुंडी पुनर्भाजन सुविधाओं का लाभ उठायें।

130. उक्त योजना ने इस वर्ष के दौरान और प्रगति की और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 1971-72 के अधिक कामकाज के समय में योजना का अधिक उपयोग किया। पुनर्भाजन की गयी हुंडियों के बकाया स्तर में प्रारंभ में जुलाई और अगस्त 1971 में कमी हुई, परन्तु वह जहां जून 1971 के अंत में 10 करोड़ रुपये था वहां सितंबर 1971 के अंत में बढ़कर 25 करोड़ रुपये हो गया। 1971-72 के अधिक कामकाज के समय के प्रारंभ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पुनर्भाजन किये गये बिलों की राशि 14 करोड़ रुपये थी। जैसे जैसे अधिक कामकाज का समय बीतता गया, बैंकों ने अधिकाधिक मात्रा में पुनर्भाजन सुविधाओं का लाभ उठाया और मार्च 1972 के अंत में 42 करोड़ रुपयों की राशि बकाया थी; कम कामकाज का समय प्रारंभ होते ही यह राशि कम हो गयी और जून 1972 के अंत में 9.9 करोड़ रुपये रह गयी।

131. बैंक हुंडी पुनर्भांजन योजना का अधिकाधिक मात्रा में जो लाभ उठा रहे हैं उसका यह प्रमाण है कि संतोषजनक चलमुद्रा स्थिति के बावजूद रिजर्व बैंक में पुनर्भांजन की गयी हुंडियों की राशि 1971-72 के अधिक कामकाज के समय उच्चतम स्तर पर (17-3-72) 45 करोड़ रुपये थी जब कि वह 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में उच्चतम स्तर पर (30-4-71) 14.1 करोड़ रुपये थी।

ऋण प्राधिकरण योजना

132. ऋण प्राधिकरण योजना में 1970 के मध्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था और उसे इस तरह व्यापक बनाया गया था कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जानेवाला ऋण मूल्यांकन उसके अंतर्गत आ जाए ताकि बड़े ऋणकर्ताओं पर वित्तीय अनुशासन हो। यह नई विनियामक प्रणाली एक ऐसा प्रभावी तंत्र सिद्ध हुई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक ऋण का उचित उपयोग होता है; बैंकों ने भी ऋण मूल्यांकन संबंधी अपनी प्रणालियों को स्पष्ट रूप से नियमित कर लिया है और वे उन्हें और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकों के ऋण मूल्यांकन के स्तरों में सुधार होने के साथ साथ इस वर्ष के दौरान बैंक की पूर्व प्राधिकरण-शर्तों में कतिपय ऐसे परिवर्तन किये गये जो वास्तव में 'कार्यकलापों को नियमित करने वाले थे' जिससे कि बैंक बिना पूर्व प्राधिकरण के, अपने ऋणकर्ताओं द्वारा वास्तविक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली ऋण की मांग की पूर्ति कर सकें। इसके अलावा ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन आने वाले उधारकर्ताओं को बैंक जो ऋण सुविधाएं अपनी ओर से दे सकते हैं, वे मुख्यतः इस प्रकार हैं; तीन महीनों की अवधि के लिए 10 लाख रुपयों तक की अस्थायी/अंतरिम ऋण सीमाएं, अन्य पार्टी के बाहरी चेकों/बैंक ड्राफ्टों की खरीद, ऋण सीमा के 5 प्रतिशत या 10 लाख रुपयों (इनमें से जो भी कम हो) तक अस्थायी अतिरिक्त आहरण; भारग्रस्त चल संपत्ति पर अग्रिम, मूल स्तरों तक ऋण सीमाओं को फिर चालू करना और रिजर्व बैंक द्वारा पहले से ही प्राधिकृत सीमाओं का पुनर्वितरण।

133. योजना को अमल में लाते समय यह पाया गया कि बैंक वित्त की अधिकतम आवश्यकताओं को दिखाते समय कुछ बैंक बकाया स्टाकों को भी उधारकर्ताओं को ऋण सीमाओं को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए अनुमत बैंक वित्त का हिसाब लगाने के लिए उपलब्ध स्टाकों के रूप में दिखाते हैं। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप 'दुहरा वित्तपोषण' होने लगा। क्योंकि उधारकर्ता इस प्रकार एक ही वस्तु सूची के संबंध में विक्रेता से और साथ ही बैंकों से भी वित्तीय सहायता लेते थे; इस प्रकार उधारकर्ता अपनी निधियों के स्थान पर उधार ली गयी निधियों में से बैंकों को मार्जिन दे सकते थे। यद्यपि इस पहलू पर अध्ययन दल (यह दल प्रारूप विवरणियां बनाने के लिए नियुक्त किया गया था और इसका पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था) के सदस्यों द्वारा अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श किया गया, फिर भी बाद में यह अनुभव किया गया कि देश में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए (जहां बैंक वित्त पर भारी मात्रा में निर्भर रहने की प्रवृत्ति रहती है) रिजर्व बैंक कम से कम प्रारंभ में कुछ समय के लिए इस बात पर जोर नहीं देगा। कि अनुमत बैंक वित्त का निर्धारण करते समय ऐसे बकाया स्टाकों को उसमें शामिल न किया जाए। योजना में संशोधन किये जाने के बाद प्राप्त अनुभवों के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने स्थिति का पुनरीक्षण किया है और यह वांछनीय समझा गया है कि बकाया स्टाकों के शोधन के मामले में सभी बैंक एक समान प्रणाली अपनाएं। तदनुसार जनवरी 1972 में बैंक ने इस आशय के अनुदेश जारी किये कि वित्त की उच्चतम आवश्यकताओं को दिखाते समय बैंकों को चाहिए कि वे बकाया स्टाकों को हिसाब में लें और उनके लिए उपयुक्त समायोजन करें जिससे दुहरे वित्त पोषण को रोका जा सके। बैंकों को दिये गये ये अनुदेश 'दहेजिया समिति' के मतों के अनुरूप ही हैं: रिजर्व बैंक को यह मालूम है कि कई मामलों में उत्पादन कार्य में बाधा डाले बिना दुहरे वित्त पोषण के तत्व को तत्काल दूर नहीं किया जा सकता और ऐसी परिस्थितियों में बैंकों को चाहिए कि वे एक क्रमबद्ध प्रणाली से इस स्थिति में सुधार लायें। किसी भी हालत में, बैंकों को, विशेष रूप से अपने उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त ऋण सीमाओं निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दुहरे वित्त पोषण की वर्तमान मात्रा स्थायी न रहे या उसमें वृद्धि न हो; दुहरे वित्त की वर्तमान मात्रा का जहां तक संबंध है, उधारकर्ताओं को पर्याप्त समय देते हुए बैंक स्थिति को धीरे धीरे विनियमित कर सकते हैं।

134. दिसंबर 1971 के भारत-पाक युद्ध ने एक असामान्य स्थिति उत्पन्न कर दी और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की गति को बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करना भी आवश्यक हो गया। रक्षा प्रयत्नों और ऐसे उत्पादक कार्यकलापों को जिनके लिए बैंक ऋण की तत्काल आवश्यकता थी, सहायता पहुंचाने की दृष्टि से बैंक के पूर्व प्राधिकरण में छूट दी गयी। इस प्रकार वस्त्र उद्योग तथा वस्त्रों के व्यापारियों के मामले में बैंक पूर्व प्राधिकरण के बिना जुलाई 1972* तक वस्तु सूचियों पर वर्तमान प्राधिकृत सीमाओं के अधिकतम 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण सीमाएं प्रदान कर सकते थे। कतिपय बैंकों से तत्काल इस दिशा में कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया कि ऊन की रद्दी और ऊन की जो मिलें पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से प्राप्त रक्षा संबंधी आर्डरों की पूर्ति करती हैं उनको प्रदान किया जानेवाला ऋण पर्याप्त और सामयिक हो। बैंकों को यह सुझाव दिया गया है कि वे पूर्व प्राधिकरण के बिना रक्षा प्राधिकारियों के लिए वस्तुओं का निर्माण और सप्लाई करने के लिए वितरण-पूर्व और वितरणोत्तर स्थितियों में तथा सामान्य रूप से उत्पादन को बढ़ाने और विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों में वस्तुओं का निर्बाध वितरण होने देने के लिए 'रक्षा पैकिंग और सप्लाई' ऋण सीमाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों को इस बात की भी अनुमति दी गयी कि वे पूर्व प्राधिकरण के बिना निर्माता यूनिटों को उनकी कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनकी वर्तमान ऋण सीमाओं में 15 प्रतिशत तक की उचित वृद्धि करें। इसके अलावा बैंकों को कतिपय उद्योगों के लिए ऋण सीमाएं मंजूर करने की अनुमति भी दी गयी जिससे वे उनकी अस्थायी मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस प्रकार जूट उद्योग के मामले में जो 1971-72 के जूट मौसम में काफ़ी अधिक मात्रा में पटसन उपलब्ध होने के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा था, कतिपय बैंकों को पूर्व प्राधिकरण के बिना अतिरिक्त पूंजीगत सीमाएं प्रदान करने की सलाह दी गयी। इसी प्रकार 1971-72 के पेराई मौसम के लिए बैंक चीनी मिलों को 1969-70 के मौसम के दौरान चीनी पर प्रदान की गयी ऋण सीमाओं के 80 प्रतिशत तक ऋण सीमाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा कोयला उद्योग के मामले में परिवहन संबंधी अवरोधों से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों को दूर करने में उसकी सहायता करने की दृष्टि से बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे इस उद्योग को दिसंबर 1972 तक अधिकतम 15 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ऋण सीमाएं प्रदान करें। पूर्वी क्षेत्र और कम विकसित/पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक यूनिटों से प्राप्त अनुरोधों पर भी सहानुभूतिपूर्वक तत्काल विचार किया गया।

*इस अवधि को दिसंबर 1972 तक बढ़ा दिया गया है।

135. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बराबर इस बात की शिकायतें मिलती रहीं कि चीनी मिलों को गन्ने के उत्पादकों ने गन्ने की जो सप्लाई की थी उसके संबंध में मिलों से प्राप्य राशियों की अदायगी में विलम्ब हुआ करता है/अदायगी नहीं होती हालांकि चीनी के स्टाकों पर बैंकों द्वारा मिलों को उदारतापूर्वक ऋण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती थीं और उनका उपयोग सामान्यतः गन्ने के उत्पादकों को अदायगी करने के लिए होना चाहिए था ; अतः बैंकों को यह सलाह दी गयी कि चीनी के स्टाकों पर ऋण सीमाएं प्रदान करते समय वे ऐसी उपयुक्त विनियात्मक क्रियाविधियां लागू करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मिलें गन्ने के उत्पादकों को अविलंब अदायगी करती है।

136. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि चाहे किसी पार्टी को समग्र बैंकिंग संघटन से उपलब्ध कुल ऋण सीमाएं कितनी भी क्यों न हों, फिर भी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे (स्वयं या अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर) किसी एक पार्टी के लिए तीन वर्षों से अधिक अवधि में प्रतिदेय 25 लाख रुपयों से अधिक राशि के व्यक्तिगत मध्यावधि या दीर्घावधि ऋण मंजूर करते समय योजना के अधीन पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर लें। इस उपाय के परिणामस्वरूप बैंकों और मियादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं के कार्यकलापों में अधिक समन्वयन पाया गया है। 24 सितंबर 1971 को समाप्त हुई तिमाही से बैंकों से प्राप्त तिमाही विवरणों (गैर सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाओं के लिए उनके द्वारा मंजूर किये गये और तीन वर्षों के बाद प्रतिदेय 10 लाख रुपयों से अधिक राशि के मियादी ऋणों के विवरण दर्शाने वाले) से भी यह देखा गया है कि बड़ी राशियों के मियादी ऋण अब मियादी ऋण देनेवाली संस्थाओं के साथ सहभागिता के आधार पर या भारत औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अधीन प्रदान किये जा रहे हैं।

137. जुलाई 1971-जून 1972 की अवधि में योजना के अधीन ऋण सीमाओं के प्राधिकरण के लिए बैंकों से 127 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जबकि जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष में 338 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। आवेदन पत्र अधिकांशतः कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए प्राप्त हुए और केवल तीन आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य सभी आवेदनपत्रों के संबंध में प्राधिकरण दिया गया। फिर भी कतिपय मामलों में, प्राधिकरण प्रदान करते समय, रिजर्व बैंक ने आवेदन की गयी पूरी सीमा तक अतिरिक्त/परिवर्धित ऋण सीमाओं के लिए स्वीकृति नहीं दी ; क्योंकि बैंक के विचार में ऋण के लिए आवेदन करनेवाली संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए उनके द्वारा उल्लिखित उद्देश्यों के लिए कम ऋण सीमाएं पर्याप्त थीं। इसके अलावा, ऋण सीमाएं प्राधिकृत करते समय, अनेक मामलों में उचित शर्तें लगायी गयीं और वित्तीय विन्यास/स्थिति सुधारने के लिए कतिपय सुझाव भी दिये गये। उक्त सुझाव सामान्यतः गारंटी कमीशन की अदायगी न होना, बैंक अग्रिमों की तुलना में प्रवर्तकों की निधियों का कम होना, अंतर कंपनी ऋण/निवेश, लाभांशों की घोषणा के लिए बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता आदि से संबंधित थे और उन सुझावों का उद्देश्य अधिक अच्छा वित्तीय अनुशासन लाना था।

ऋण नियंत्रण

138. 1971-72 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर ने यह संकेत दिया था कि पहले की ऋण नीति के स्थूल तत्व जारी रहेंगे और अनाज की उगाही के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों के पुनर्वित्त के सम्बन्ध में किये जाने वाले कतिपय संशोधनों (संलग्न चार्ट में दर्शाये गये) को छोड़कर पुनर्वित्त सुविधाओं का स्वरूप भी लगभग वही रहेगा।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

139. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के क्षेत्र में रूई और कपास, अनाजों, तिलहनों और वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित) पर दिये जाने वाले अग्रिमों के नियंत्रण में जहां इस वर्ष छूट दी गयी वहां चीनी, गुड़ और खांडसारी पर दिये जाने वाले अग्रिमों के नियंत्रणों को पुनः लागू किया गया।

140. यह सुनिश्चित करने के लिए कि रूई खरीदने और उसका संग्रहण करने के लिए मिलों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध होता है, रिजर्व बैंक ने 3 अगस्त 1971 को रूई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों के मार्जिन सम्बन्धी नियंत्रणों के उपबन्धों में संशोधन किया जिससे निर्दिष्ट श्रेणियों की मिलें दो सप्ताहों की खपत के लिए आवश्यक रूई की अतिरिक्त मात्रा के बराबर के स्टाक बनाये रख सकें। रूई के नये मौसम के लिए 18 नवम्बर 1971 को घोषित की गयी ऋण नीति के कारण मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को रूई की नयी फ़सल पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए न्यूनतम मार्जिन पहले के 60-75 प्रतिशत से कम होकर 50-70 प्रतिशत हो गया ; यह परिवर्तन विभिन्न किस्मों की रूई के विपणन की अवधियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लम्बे रेशे की रूई की नयी किस्मों पर दिये जानेवाले अग्रिमों को उच्चतम सीमा सम्बन्धी नियंत्रण से छूट दी गयी ; फिर भी उन पर 40 प्रतिशत (जिसे बाद में घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया) के न्यूनतम मार्जिन और ब्याज की 12 प्रतिशत की न्यूनतम दर की शर्तें लगा दी गयीं। मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों के लिए ऋण सीमाएं निर्धारित करने के सम्बन्ध में बैंकों को अक्तूबर 1971—जनवरी 1972 से शुरु होने वाली चार महीनों की अवधि के दौरान 1970—71 के मौसम में तदनुरूपी चार महीनों की अवधि में प्रत्येक पार्टी द्वारा बनाये रखे गये ऋण के औसत कुल स्तर के 100 प्रतिशत के बराबर का ऋण स्तर बनाये रखने की अनुमति दी गयी। रूई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित नियंत्रण में 27 मार्च 1972 को रूई की नयी फ़सल के संदर्भ में न्यूनतम मार्जिन में 10 प्रतिशत की कमी कर और अग्रिमों को पिछले मौसम की तदनुरूपी चार महीनों की अवधि में विद्यमान ऋण के उच्चतम स्तर के बराबर की ऋण सीमाओं से सम्बद्ध कर अतिरिक्त छूट दी गयी। कपड़ों की मिलों की खपत की जिन निर्दिष्ट अवधियों के सम्बन्ध में मार्जिन निर्धारित किये गये थे उनमें सभी मामलों में चार सप्ताहों की वृद्धि की गयी।

141. अनाजों के मामले में मक्के और जौ पर दिये जाने वाले अग्रिमों को जहां 7 अगस्त 1971 से ऋण नियंत्रण से पूर्ण रूप से छूट दी गयी वहां गेहूं पर दिये जाने वाले अग्रिमों को उच्चतम सीमा सम्बन्धी नियंत्रण से छूट दी गयी। इसके अलावा सरकार द्वारा नियुक्त किये गये/लाइसेंसीकृत और सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सांविधिक राशन/उचित मूल्य वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कारोबार करने वाले थोक और फुटकर विक्रेताओं को राशनीकृत अनाजों पर दिये जाने वाले अग्रिमों को ऋण नियंत्रणों से पूर्ण रूप से छूट दी गयी। सुधरी हुई सप्लाई स्थिति को देखते हुए बैंक ने अनाजों के नियंत्रणों में 3 जनवरी 1972 से और छूट दी। आटा बेलन मिलों को गेहूं पर दिये जाने वाले अग्रिमों को मार्जिन नियंत्रण से छूट दी गयी। 1 लाख या उससे कम आबादी वाले किसी केन्द्र में 1 जनवरी 1970 को या उसके

बाद खोले गये नये कार्यालयों के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक कार्यालय के लिए 50,000 रुपयों की उच्चतर संयुक्त अतिरिक्त सीमा स्वीकार की गयी। व्यापारियों को अनाज पर दिये जाने वाले ऐसे अग्रिमों को जो भारतीय ऋण गारन्टी निगम लि० की गारन्टी के अन्तर्गत आते हैं, अधिकतम 20,000 रुपयों तक उच्चतम सीमा और मार्जिन सम्बन्धी नियंत्रण से छूट दी गयी बशर्ते कि व्यापारी यह वचन दे कि वह अनाजों पर केवल एक ही बैंक से उधार लेगा। 19 अप्रैल 1972 को बैंकों को अनाजों पर उनके द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की स्तर की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि (मार्च–अप्रैल 1972 से) करने की अनुमति दी गयी।

142. **तिलहनों और वनस्पति सहित वनस्पति तेलों** पर दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित नियंत्रण को 7 अगस्त 1971 से केवल मूंगफली, सरसों/तोरिया, एरंड और असली, उनके तेलों तथा वनस्पति के लिए लागू किया गया। तिलहन उत्पादक क्षेत्रों में (i) तिलहनों और (ii) वनस्पति सहित वनस्पति तेलों के सम्बन्ध में और/या असंगठित क्षेत्र की नयी पार्टियों, विशेष रूप से तेल मिलों का वित्तपोषण करने के निमित्त 1970 के तदनुरूपी दो महीनों की अवधि के अग्रिमों के स्तर के 15 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त सीमा प्रदान की गयी। वनस्पति निर्माताओं और पंजीकृत तेल मिलों को अलसी/सरसों के तेल तथा तिलहनों वनस्पति तेलों और वनस्पति पर दिये जाने वाले अग्रिमों को 3 जनवरी 1972 से उच्चतम सीमा सम्बन्धी नियंत्रण से छूट दी गयी। इसके अलावा व्यापारियों को तिलहनों, उनके तेलों और वनस्पति पर दिये जाने वाले अधिकतम 20,000 रुपयों की सीमा तक के उन अग्रिमों को, जो भारतीय ऋण गारन्टी संगठन लिमिटेड की गारन्टी योजना के अधीन आते हैं, मार्जिन और उच्चतम सीमा सम्बन्धी नियंत्रणों से छूट दी गयी बशर्ते कि व्यापारी ऐसे अग्रिम केवल एक ही बैंक से लेने का वचन दें। मूंगफली की वर्तमान मूल्यस्थिति को देखते हुए मूंगफली पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित न्यूनतम मार्जिन को 30 मई 1972 से 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा वनस्पति निर्माताओं को वनस्पति पर दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित न्यूनतम मार्जिन को भी घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया।

143. **चीनी, गुड़ और खांडसारी** के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा सट्टेबाजी के उद्देश्य से इन पण्यों के स्टाक बनाये रखने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिए बैंक ने इन पण्यों पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर 23 सितम्बर 1971 से पुनः नियंत्रण को लागू किया। चीनी के उत्पादकों को छोड़कर अन्य पार्टियों को इन पण्यों पर और चीनी मिलों को ऐसे स्टाकों के सम्बन्ध में जो कारखाने के परिसर से बाहर निकल चुके हों और जिन पर उत्पादन शुल्क अदा किया जा चुका हो, दिये जाने वाले अग्रिमों के संदर्भ में 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन (जिसे 27 दिसम्बर 1973 को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया) निर्धारित किया गया और 12 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित की गयी। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद निकाली जाने वाली चीनी पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर भी कतिपय शर्तों के अधीन 40 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन लेने के लिए बैंकों से कहा गया। निर्यात करने के उद्देश्य से बैंकों के पास बन्धक/दृष्टि-बंधक रखे गये चीनी के स्टाकों पर दिये जाने वाले अग्रिमों को नियंत्रण से छूट दी गयी।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त होने वाले पुनर्वित्त-सुविधाएं

अक्तूबर 1971 के अंत तक			
वास्तविक चलमुद्रा स्थिति	4½% की दर पर	बैंक दर पर (6%)	टिप्पणी
1	2	3	4
I निर्यात ऋण :			
चाहे वास्तविक चल मुद्रा अनुपात कुछ भी हो	1970 के वार्षिक औसत के 10% बराबर की राशि तक।	1970 के वार्षिक औसत के 10% की अतिरिक्त राशि।	1970 के निर्यात ऋण के वार्षिक औसत के 20% के बराबर के ऋणों से वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
II निम्नलिखित मामलों में निर्धारित आधार पर अवधि के दौरान अग्रिमों में हुई वृद्धि के बराबर की राशि :			
—वही—	(क) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मैसूर के चुने हुए जिलों में स्थित प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों को ऋण।	(क) ऋण गारंटी संगठन की गारंटी आधीन आनेवाले लघु उद्योगों को अल्पावधि ऋण। (ख) कृषकों को अल्पावधि प्रत्यक्ष ऋण।	**आधार अवधि** : पिछले वर्ष की तदनुरूपी कैलेंडर तिमाही में विद्यमान ऐसे ऋणों का औसत स्तर अर्थात् जनवरी-मार्च 1971 की तिमाही के लिए जनवरी-मार्च 1970 की तिमाही का औसत आधार होगा।
III हुंडी पुनर्भाजन योजना :			
—वही—	—	नयी योजना के अधीन हुंडियों का पुनर्भाजन।	नयी योजना के अधीन पुनर्भाजन की गयी हुंडियों के संबंध में बकाया रहने वाली देयता से वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
IV अनाजों के जखीरों के लिए अग्रिम :			
—वही—	—	जुलाई 1971 के अंत तक 30 अक्तूबर 1970 को विद्यमान ऐसे अग्रिमों के बकाया स्तर की अपेक्षा हुई वृद्धि के 75% तक, अगस्त में 60% तक और उसके पश्चात् 50% तक।	—

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त होने वाले पुनर्वित्त सुविधाएं

1 नवंबर 1971 से अमल में रहनेवाली

वास्तविक चलमुद्रा-स्थिति	$4\frac{1}{2}\%$ की दर पर	बैंक दर पर (6%)	टिप्पणी
1	2	3	4
I निर्यात ऋण :			
चाहे वास्तविक चलमुद्रा अनुपात कुछ भी हो	1971 के वार्षिक औसत के 10% के बराबर की राशि तक।	1971 के वार्षिक औसत के 10% की अतिरिक्त राशि।	1971 के निर्यात ऋण के वार्षिक औसत के 20% के बराबर के ऋणों से वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1971 का आधार 1 जनवरी 1972 से लागू होगा।
II निम्नलिखित मामलों में निर्धारित आधार अवधि के दौरान अग्रिमों में हुई वृद्धि के बराबर की राशि :			
—वही—	(क) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मैसूर के चुने हुए जिलों में स्थित प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों को ऋण।	(क) ऋण गारंटी संगठन की गारंटी के अधीन आने वाले लघु उद्योगों को अल्पावधि ऋण। (ख) कृषकों को अल्पावधि प्रत्यक्ष ऋण	**आधार अवधि** : पिछले वर्ष की तदनुरूपी कैलेंडर तिमाही में विद्यमान ऐसे ऋणों का औसत स्तर अर्थात् जनवरी-मार्च 1972 की तिमाही के लिए जनवरी-मार्च 1971 का औसत आधार होगा।
III हुंडी पुनर्भाजन योजना :			
—वही—	—	नयी योजना के अधीन हुंडियों का पुनर्भाजन।	नयी योजना के अधीन पुनर्भाजन की गयी हुंडियों के संबंध में बकाया रहनेवाली देयता से अक्तूबर 1972 के अंत तक वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
IV अनाजों की उगाही के लिए अग्रिम :			
—वही—	—	अक्तूबर 1971 के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान अनाजों की उगाही के लिए दिये गये अग्रिमों के बकाया स्तर का 10% और अक्तूबर 1971 के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान स्तर की अपेक्षा हुई वृद्धि का अतिरिक्त $\frac{1}{3}$।	
V 'रक्षा पैकिंग और सप्लाई' ऋण :			
—वही—	—	कुल बकाया स्तर तक	रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(ग) के अधीन पुरानी हुंडी बाजार योजना के अंतर्गत यह सुविधा उपलब्ध होगी (गवर्नर का परिपत्र डीबी-ओडी. सं. जीसीएस. बीसी. 142/सी 483-71 तारीख 11 दिसंबर 1971 देखें)।

नोट :—बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त के लिए न्यूनतम वास्तविक चलमुद्रा अनुपात 34% है। किसी बैंक के अतिरिक्त ऋणों पर परिवर्धित दर पर ब्याज लिया जाएगा। यह दर बैंक के वास्तविक चलमुद्रा अनुपात में होने वाली प्रत्येक अंक या उसके अंश की कमी पर (फ़िलहाल 34% से कम) बैंक दर के स्तर से वार्षिक 1% अधिक होगी। फिर भी, जब वास्तविक चलमुद्रा अनुपात 26% से कम हो जाएगा तब अधिकतम 15% की परिवर्धित दर से ब्याज लिया जाएगा।

144. पाकिस्तान द्वारा युद्ध की घोषणा किये जाने के बाद चीनी, गुड़ और खांडसरी, तिलहनों और वनस्पतियों तेलों (वनस्पति सहित), अनाजों तथा रूई और कपास पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों को 11 दिसम्बर 1971 को सीमाक्षेत्र और सीमाक्षेत्र के नज़दीक के जिलों में प्रारम्भ में फ़रवरी 1972 के अन्त तक तथा बाद में अक्तूबर 1972 के अन्त तक नियंत्रणों से छूट दी गयी ।

145. इस बात के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के गोदाम निगमों के गोदामों द्वारा की जाने वाली संग्रहण सुविधाओं का उपयोग किया जाए, अन्य नियंत्रित पण्यों के मामले में भी 19 अप्रैल 1972 को ऐसे निगमों द्वारा जारी की गयी गोदाम रसीदों पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में उन्हें जो न्यूनतम मार्जिन बनाये रखने की आवश्यकता है उसमें (जैसे अनाजों के संदर्भ में किया गया है) 10 प्रतिशत की कटौती करने की अनुमति दी गयी ।

146. ग्रामीण उद्योग प्रायोजनाओं के अधीन आनेवाले अभिसंस्करण निर्माण यूनिटों को उनके द्वारा बैंकों से वित्त प्राप्त करने में अनुभव की, जाने वाली कठिनाइयों को देखते हुए अनाजों, तिलहनों, तेलों, वनस्पति रूई और कपास तथा चीनी, गुड़ और खांडसरी पर दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के उपबन्धों से 30 मई 1972 को छूट दी गयी ।

जूट उद्योग संबंधी कार्यकारी दल

147. कार्यकारी दल ने जूट उद्योग को कुछ राहत देने की दृष्टि से जूट मिलों के उत्पादन के जिस अंश का निर्यात किया जाता है, उसके सम्बन्ध में दिये जाने वाले ऋणों के लिए ब्याज की रियायती दर लागू करने की एक विशेष योजना की जो सिफ़ारिश की थी, वह अभी सरकार के विचाराधीन है । उक्त सिफ़ारिश का उल्लेख पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया था (पैराग्राफ 291) ।

चाय उद्योग संबंधी कार्यकारी दल

148. चाय उद्योग की वित्तीय सहायता का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सितम्बर 1971 में नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने फ़रवरी 1972 में अपनी रिपोर्ट पेश की व उक्त दल ने इस उद्देश्य से कि इस उद्योग को संस्थागत ऋण (अल्पावधि और दीर्घावधि, दोनों) बराबर मिलता रहे, अनेक सिफ़ारिशें की हैं । चूंकि यह अनुभव किया गया कि चाय के बागानों को अल्पावधि ऋण की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है, रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नाम 8 मार्च 1972 को दल की सम्बन्धित सिफ़ारिशों की सूचना देते हुए एक परिपत्र जारी किया* । दल की अन्य सिफ़ारिशें विचाराधीन हैं ।

कोयला उद्योग संबंधी कार्यकारी दल

149. कोयला उद्योग की तात्कालिक वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र, अर्थात् बिहार और पश्चिम बंगाल में इस उद्योग के विस्तारपोषण के लिए उपलब्ध संस्थागत व्यवस्थाओं तथा बैंक ऋणों का पुनरीक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जनवरी 1972 में एक कार्यकारी दल का गठन किया ।

काजू उद्योग संबंधी अध्ययन दल

150. काजू उद्योग के निर्यात और उसकी नियोजन क्षमता के संदर्भ में उसे वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का पुनरीक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक ने मार्च 1972 में एक अध्ययन दल का गठन किया ।

बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट

151. भारत सरकार द्वारा फ़रवरी 1969 में श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये बैंकिंग आयोग ने 9 फ़रवरी 1972 को अपनी रिपोर्ट पेश की । आयोग द्वारा की गयी प्रमुख सिफ़ारिशें वाणिज्य और सहकारी बैंकों की पुनर्व्यवस्था, उनके कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने के लिए आवश्यक उपायों, उनकी परिचालनगत क्षमता में सुधार, वैधानिक सुधार तथा आगे के अनुसंधान और अध्ययन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों से सम्बन्धित थीं ।

152. इसके अलावा, आयोग ने ऋण आयोजना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, देशी बैंकरों, बैंकों के लिए आवश्यक प्रबन्ध विकास, प्रशिक्षण और भर्ती सम्बन्धी प्रणालियों तथा बैंक संगठन की संस्थागत रूपरेखा में सुधार लाने की आवश्यकता के संदर्भ में सूचना प्रणाली से सम्बन्धित सिफ़ारिशें भी की हैं ।†

153. आयोग की सिफ़ारिशें भारत सरकार और बैंक के विचाराधीन हैं ।

बैंकिंग सांख्यिकी समिति

154. एक समान तुलन बही और अन्य सम्बन्धित विवरणियों को सरल बनाने और उन्हें शीघ्र तैयार करने तथा आंकड़ों की वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में उनमें संशोधन सुझाने के निमित्त रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1972 में बैंकिंग सांख्यिकीय समिति का गठन किया । आशा है कि उक्त समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी ††

संगठन संबंधी अन्य बातें

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाएं

155. युगांडा में स्थित राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताओं को लगभग अन्तिम रूप दे दिया गया है ; अत: बैंक आफ इण्डिया (युगांडा) लिमिटेड को बैंक आफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड द्वारा अधिकार में लिये जाने का कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा । मलेशिया में स्थित तीन भारतीय बैंकों की ग्यारह शाखाओं को अधिकार में लेने के लिए एक नयी कम्पनी स्थापित करने के प्रस्ताव को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है । इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विवरण दिये गये हैं । इन शाखाओं के पुनर्गठन की योजना मलेशिया बैंकिंग अध्यादेश, 1958 की धारा 14 के अधीन मलेशिया सरकार के वित्त मंत्रालय के पास भेजी गयी है । उक्त योजना की एक प्रतिलिपि बैंक नेगरा मलेशिया के पास भेजी गयी है । आशा की जाती है कि नयी मलेशिया कम्पनी शीघ्र ही पंजीकृत की जाएगी ।

156. सिंगापुर में कार्यरत चार भारतीय बैंकों में से दो बैंक स्थानीय विधान के अन्तर्गत न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते । उन बैंकों को उन अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जनवरी 1973 तक समय दिया गया है । बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत बनायी गयी योजना में संशोधन करने की कार्रवाई की जा रही है जिससे सम्बन्धित बैंकों के पूंजीगत स्वरूप को परिवर्तित किया जा सके ।

*उक्त परिपत्र के लिए रिज़र्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन, अप्रैल 1972 के पृष्ठ 674-675 देखें ।

†आयोग की सिफ़ारिशों के सारांश के लिए रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन, मई 1972 के पृष्ठ 826-837 देखें ।

††समिति ने अपनी रिपोर्ट 7 अगस्त 1972 को पेश की और बैंक ने उसकी सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

157 यहां रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और एक बैंक के परिरक्षक के साथ गठित उस दल का भी उल्लेख किया जा सकता है जो सिंगापुर और हांगकांग गया । उक्त दल का उद्देश्य यह था कि इन केन्द्रों में स्थित राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों की शाखाओं के कामकाज का प्रधान कार्यालय और विदेशी शाखाओं के बीच शक्तियों के प्रत्यायोजन और विकेन्द्रीकरण की सीमा का परीक्षण करने के उद्देश्य से अध्ययन किया जाए और साथ ही, शाखाओं की लाभदायकता में सुधार लाने की संभावना, दक्षिण पूर्व एशिया को भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यातों और वहां किये जाने वाले निवेशों को बढ़ाने तथा उक्त क्षेत्र के भारतीय मूल के निवासियों द्वारा भारत में निवेश कराने में उन शाखाओं की भूमिका भी अध्ययन किया जाए व इसके अलावा उक्त दल को एक ही केन्द्र में स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों की अपनी-अपनी विशिष्टाओं को जारी रखने की वांछनीयताओं के बारे में भी परीक्षण करना था । दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परिचालन को लचीला बनाने की दृष्टि से इन केन्द्रों में स्थित बैंकों के प्रबन्धकों को विवेकाधीन शक्तियां और अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान किये जाने के लिए काफ़ी गुंजाइश है जिसकी पुष्टि बाद में प्रधान कार्यालय को करनी होगी । विदेशी शाखाओं में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने और विदेशी शाखाओं में अविलम्ब कारोबार चलाने के लिए प्रधान कार्यालय का उपयुक्त रूप से पुनर्गठन करने की भी सिफ़ारिशें की गयी हैं । भारतीय निर्यातों और संयुक्त उपक्रमों की सहायता करने के लिए प्रारम्भ में सिंगापुर में दो बैंकरों की एक वाणिज्यिक और आर्थिक जानकारी कक्ष की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है । बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि व भारत से आयात करने वाले आयातकों को ब्याज की दर में रियायत प्रदान करें । विदेशी व्यापार के लाभप्रद वित्तपोषण को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है । स्थानीय व्यवसाय से घनिष्ठतापूर्वक सम्बद्ध होने के लिए यह अनुभव किया गया कि पर्यवेक्षक संवर्गों में स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करने, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ऋणों की प्रलेखन-विधियां बनाने और स्थानीय उद्योगों, विशेष रूप से लघु उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है । एक ही केन्द्र में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं की अपनी-अपनी विशिष्टताओं को बनाये रखने की वांछनीयता के प्रश्न पर दल का यह मत था कि बैंकिंग आयोग की सिफ़ारिशों के संदर्भ में भारत में बैंकों का जो संगठन-स्वरूप बनेगा उस पर जहां यह बात निर्भर रहेगी वहां इन दो केन्द्रों में स्थित भारतीय बैंकों की अपनी-अपनी विशिष्टताओं को बनाये रखना फ़िलहाल लाभप्रद होगा ।

साख सूचना

158. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि मार्च 1971 में बैंकों और अन्य अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के ऋण कर्ताओं के सम्बन्ध में साख सम्बन्धी सूचनाओं को एकत्रित करने और उन पर कार्रवाई करने की पद्धति को व्यवस्थित रूप से परिशोधित किया गया ताकि ऐसी सूचनाएं इन संस्थाओं के लिए अधिक उपयोग हो सकें । 14 फ़रवरी 1972 से उपर्युक्त संस्थाओं के घटकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली साख-सुविधाओं के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक से जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के स्वरूप में संशोधन किया गया है । संशोधित क्रियाविधि के अधीन अब रिज़र्व बैंक अधिक व्यापक जानकारी प्रस्तुत करता है जिसमें घटकों का वित्तपोषण करने वाले बैंकों (बिना उनके नाम बतायें) की कुल संख्या भी सम्मिलित रहती है । प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी के क्षेत्र को व्यापक बनाने के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की विभिन्न शाखाओं को रिज़र्व बैंक से सीधे ही साख सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है । अब उन्हें आवेदनपत्रों को अपने प्रधान कार्यालयों के द्वारा भिजवाने की आवश्यकता नहीं रही है । आवेदक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को पिछले वर्ष के 1,458 आवेदनपत्रों के मुकाबले में आलोच्य वर्ष में 2,255 आवेदनपत्रों के संदर्भ में साख सूचना प्रदान की गयी ।

159. यह उल्लेखनीय है कि 1 नवम्बर 1969 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वयन समिति की जो पहली बैठक हुई उसमें यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि सभी बैंकों के बीच साख सूचना का और व्यापक रूप से विनिमय होना चाहिए ; उसके परिणामस्वरूप एक अध्ययन दल गठित किया गया । अध्ययन दल ने रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । दल के मतानुसार, वर्तमान वैधानिक उपबन्ध बैंकों को न केवल वर्तमान ऋणकर्ताओं के सम्बन्ध में, बल्कि ऐसे संभाव्य ऋणकर्ताओं के सम्बन्ध में भी, जिनके केवल जमा लेखे बैंकों में हों, उपयोगी साख सूचना का विनिमय करने में पर्याप्त संरक्षण प्रदान करते हैं । नये क्षेत्रों के बाज़ार स्रोतों से और छोटे ऋणकर्ताओं के सम्बन्ध में व्यवस्थित रूप से साख सूचना एकत्रित करने में विद्यमान संगठन सम्बन्धी अपर्याप्तता को देखते हुए दल ने सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग के हित के लिए दीर्घकालीन उपाय के रूप में साख सूचना न्यास नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करने की सिफ़ारिश की है । अपनी सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिए दल ने एक समयबद्ध कार्यक्रम भी बनाया है । इस रिपोर्ट की एक एक प्रति सभी वाणिज्य बैंकों के पास उनकी टिप्पणियां मांगते हुए भेजी गयी हैं ।

बैंकों का निरीक्षण

160. वाणिज्य बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनकी परिचालन पद्धतियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों का आवधिक निरीक्षण करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया है उसके अनुसार आलोच्य अवधि में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत 35 अनुसूचित बैंकों और दो गैर अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण किया गया अथवा उनका निरीक्षण शुरु किया गया । इसके अलावा, इस अवधि में फ़िजी द्वीपसमूहों, गयाना, जापान, हांगकांग और थाईलैंड में भारतीय बैंकों की जो विदेशी शाखाएं रहती हैं उनका भी निरीक्षण किया गया/निरीक्षण शुरु किया गया । इसके अतिरिक्त दो बैंकों के कार्यकलापों की जांच-पड़ताल की गयी ; उनमें से, एक के सम्बन्ध में यह निर्णय करना था कि क्या बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45ठ (4) के अधीन अपकरण सम्बन्धी कार्रवाई करने के लिए प्रत्यक्षतः कोई आधार है और दूसरे के सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44(1) के अधीन एक प्रमाणपत्र जारी करना था ।

161. वाणिज्य बैंकों के 364 कार्यालयों की सेवा प्राप्त 76 केन्द्रों में आलोच्य वर्ष में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का केन्द्रवार निरीक्षण किया गया, जिसका उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था ।

162. उपर्युक्त निरीक्षणों के अलावा, आलोच्य अवधि में बैंकों की प्रणालियों और क्रियाविधियों का अध्ययन शुरु किया गया ; उक्त अध्ययन का उद्देश्य यह था कि ऐसे क्षेत्रों का स्थूल रूप से पता लगाया जाए जहां उक्त प्रणालियों और क्रियाविधियों में कमियां विद्यमान हों और जहां जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय सुझाये जाएं जिससे सम्बन्धित बैंक ऐसे उद्देश्यों जिनके लिए उसकी स्थापना की गयी हो, तथा सामाजिक उद्देश्यों की यथासम्भव अच्छी तरह से पूर्ति कर सकें तथा जालसाजी की घटनाओं को यथासम्भव दूर किया जा सके । दो बैंकों के संदर्भ में ऐसे अध्ययन किये गये और उनकी रिपोर्ट सम्बन्धित बैंकों के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गयीं ।

बैंकों का विलयन

163. आलोच्य अवधि में ईस्टर्न बैंक लिमिटेड (जिसके भारत में चार कार्यालय थे) के भारतीय कार्यालयों का कारोबार 1 जुलाई 1971 से चार्टर्ड बैंक ने अपने अधिकार में ले लिया ।

164. एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी के रूप में 18 जनवरी 1972 को निगमित किये गये पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को भारत में बैंक व्यवसाय करने के निमित्त 14 जून 1972 को लाइसेंस प्रदान किया गया ; उक्त बैंक का पंजीकृत कार्यालय गौहाटी (असम) में है । उसने 3 जुलाई 1972 को अपना कारोबार शुरू किया और उसी तारीख को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में उसका नाम सम्मिलित भी किया गया । उक्त बैंक की चुकता पूंजी 23 मई 1972 को 8.06 लाख रुपये थी, जो प्रति शेयर रु० 100 के मूल्य के 13,430 ईक्विटी शेयरों के संदर्भ में प्रति शेयर रु० 60 की प्रदत्त राशि से बनी थी । उपर्युक्त राशि में से युनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गये अभिदान की राशि उसको दिये गये 4,500 शेयरों के संदर्भ में 2.70 लाख रुपये थी । बैंक द्वारा जारी की गयी विवरणिका के अनुसार प्रति शेयर रु० 100 के मूल्य के 25,000 ईक्विटी शेयरों से प्राप्त होने वाले 25,00,000 रुपयों की उसकी जारी की गयी पूंजी में से प्रति शेयर रु० 100 के मूल्य के 9,00,000 रुपयों के ईक्विटी शेयर युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों, मित्रों तथा सहयोगियों द्वारा अभिदान किये जाने के लिए आरक्षित किये गये हैं (यदि इनमें से कोई शेयर इस प्रकार नहीं लिए जाएं तो उनका उपयोग जनता से प्राप्त आवेदनपत्रों के संदर्भ में किया जाएगा) ।

बैंकों का लाइसेंसीकरण

165. इस वर्ष के दौरान ईस्टर्न बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया और पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को लाइसेंस प्रदान किया गया : इस कारण लाइसेंसीकृत बैंकों की संख्या जून 1972 के अन्त में अपरिवर्तित रही अर्थात् उक्त संख्या पहले की तरह 46 ही थी । जिन बैंकों के मामले में लाइसेंस रद्द किये गये उनकी संख्या बढ़कर जून 1972 के अन्त में 51 हो गयी । इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में ऐसे 22 बैंक थे जिनके लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

166. आलोच्य अवधि में, एक वर्तमान बैंक के नयी निधि सम्बन्धी कारोबार की देयताओं और आस्तियों को दूसरे बैंक में अन्तरित कर देने के कारण उसे भारत में बैंक व्यवसाय करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन लाइसेंस देने से इन्कार किया गया । जिन बैंकों को लाइसेंस देने से इन्कार किया गया उन बैंकों की संख्या जून 1972 के अन्त में 283 थी ।

परिसमापन की कार्रवाइयां

167. आलोच्य अवधि में उच्च न्यायालय द्वारा छः गैर अनुसूचित बैंकों का विघटन किया गया और एक बैंक ने स्वैच्छिक परिसमापन कर दिया । बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) (2) के अधीन बैंक आफ कारैकुडि लिमिटेड (मद्रास क्षेत्र) बैंकिंग कम्पनी नहीं रहा और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (5) के अधीन इंटर प्रोविन्शियल बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (कलकत्ता क्षेत्र) का नाम रजिस्टर में से हटा दिया गया ।

168. केन्द्रीय सरकार से आवश्यक निदेश प्राप्त करने के बाद बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45थ के अधीन तीन बैंकों का निरीक्षण शुरू किया गया । उनमें से एक बैंक का निरीक्षण पूरा किया गया और सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट 10 दिसम्बर 1971 को सरकार तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालय के पास भेजी गयी । शेष दो बैंकों का निरीक्षण कार्य सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण स्थगित रहा ।

समाशोधन गृह सुविधाएं

169. बैंकिंग सुविधाओं को व्यापक बनाने की रिजर्व बैंक की नीति के एक अंश के रूप में आलोच्य वर्ष में 22 समाशोधन गृह स्थापित किये गये ; इससे देश में विद्यमान समाशोधन गृहों की कुल संख्या बढ़कर 157 हो गयी ; इनमें से रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा क्रमशः 9, 119 और 29 समाशोधन गृहों का प्रबन्ध किया जाता है ।

170. राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान के तत्त्वावधान में दिसम्बर 1969 में हुए कार्य शिविर द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसरण में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने फ़रवरी 1970 में स्टेट बैंक आफ इंडिया से कहा कि वह 1961 की जनगणना के अनुसार 50,000 या उससे अधिक आबादी वाले ऐसे स्थानों पर जहां तीन या चार से अधिक बैंक कारोबार करते हैं, समाशोधन गृह खोलने की सम्भाव्यता की जांच पड़ताल करे । उपर्युक्त आधार पर समाशोधन गृह खोलने की दिशा में स्टेट बैंक आफ इंडिया कदम उठाता आ रहा है । आलोच्य अवधि में स्थापित 22 समाशोधन गृहों में से 16 समाशोधन गृह ऐसे केन्द्रों में खोले गये । 1971 की जनगणना के अनुसार समाशोधन गृह खोलने के लिए पात्र केन्द्रों की एक नयी सूची बनायी जा रही है और उन केन्द्रों में समाशोधन गृह स्थापित करने के लिए अपना भावी कार्यक्रम बनाने के निमित्त उसे स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास भेजा जाएगा । महानगरीय केन्द्रों में अतिरिक्त समाशोधन गृह खोलने का प्रश्न भी रिजर्व बैंक के विचाराधीन है ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य परिणाम

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

171. सरकारी क्षेत्र के 22 वाणिज्य बैंकों (अर्थात् स्टेट बैंक आफ इंडिया, उसके 7 सहायक बैंक और 14 राष्ट्रीयकृत बैंक) के कार्य-परिणामों का विश्लेषण करने से इस बात का पता चलता है कि 12.8 करोड़ रुपयों की उनकी लाभ राशि* 1970 की तुलना में 2.7 करोड़ रुपये (या 26.2 प्रतिशत) अधिक थी । इन बैंकों की कुल आय में जहां 1970 में 76.3 करोड़ रुपयों (22.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी वहां 1971 में 101.0 करोड़ रुपयों (24.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । 1971 में आय में हुई इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि ब्याज और बट्टे से प्राप्त होने वाली आमदनियों में 1971 में 91.6 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970 में उनमें 71.5 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । ब्याज से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह था कि 9 जनवरी 1971 से बैंक दर में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप अग्रिमों की ब्याज दरें भी बढ़ गयीं और उनके अग्रिमों की मात्रा में भी वृद्धि हो गयी । इन बैंकों के कुल व्यय में जहां 1970 में 75.2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी वहां 1971 में 98.3 करोड़ रुपयों (24.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । जमाराशियों और उधारों पर अदा किये गये ब्याज की राशि में 1970 में हुई 19.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 27.0 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई पड़ी,

*करों और कर्मचारियों को देय बोनस के लिए व्यवस्था करने के बाद शुद्ध लाभ । बोनस की व्यवस्था को स्थापना व्यय के अधीन सम्मिलित किया गया है ।

जिसका आंशिक कारण यह था कि जमाराशियों और उधारों की ब्याज दरों में वृद्धि हो गयी थी। फिर भी वेतन और भत्तों से सम्बन्धित व्यय में 1971 में हुई 35.9 करोड़ रुपयों (21.7) प्रतिशत की वृद्धि 1970 की 36.5 करोड़ रुपयों या 28.4 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा कम ही थी; इसका कारण यह था कि 1971 में बैंक कार्यालयों की संख्या में 1970 की अपेक्षा कम वृद्धि ही हुई।

स्टेट बैंक समूह

172. स्टेट बैंक आफ इंडिया की कुल आय 1970 के 112.7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1971 में 142.1 करोड़ रुपये हो गयी। कमीशन, विनिमय और दलाली से प्राप्त होने वाली आय में 1971 में 3.4 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970 में उसमें 0.6 करोड़ रुपयों की भिन्नात्मक वृद्धि हुई थी। स्टेट बैंक के व्यय में भी 1971 में 28.3 करोड़ रुपयों (25.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 1970 में कुल व्यय में 21.4 करोड़ रुपयों या 24.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1971 में स्टेट बैंक आफ इंडिया के लाभ की राशि 3.8 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें 1.1 करोड़ रुपयों (40.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1970 में उसमें 10 लाख रुपयों की थोड़ी-सी कमी हुई थी। इस लाभ-राशि में से बैंक ने 2.0 करोड़ रुपये प्रारक्षित निधि में अन्तरित किये और शेयरधारियों को लाभांश देने के निमित्त 1.3 करोड़ रुपये अलग रखे।

173. स्टेट बैंक के सात सहायक बैंकों ने अपनी आय को 1970 के 32.5 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 1971 में 40.2 करोड़ रुपये कर लिया; ऋणों और अग्रिमों के ब्याज से प्राप्त अधिक आमदनी इस वृद्धि का प्रमुख कारण थी। चूंकि उनके व्यय में भी लगभग आय के अनुपात में ही वृद्धि हुई अतः उनकी लाभ-राशि में 1971 में 2 लाख रुपयों की सीमान्त कमी पायी गयी जबकि 1970 में उसमें 10 लाख रुपयों की वृद्धि हुई थी। इस लाभ-राशि में से इन बैंकों ने 12 लाख रुपये प्रारक्षित निधियों में अन्तरित किये और लाभांशों की अदायगी के लिए 36 लाख रुपये अलग रखे।

राष्ट्रीयकृत बैंक

174. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने सारे व्यय की पूर्ति करने और नियमित व्यवस्थाओं के लिए राशि सुरक्षित रखने के बाद 1971 में 4.43 करोड़ रुपये भारत सरकार को अन्तरित किये जबकि 1970 में 4.17 करोड़ रुपये अन्तरित किये गये थे।

175. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के 1971 के कार्यपरिणामों से उनकी लाभ राशि में वृद्धि होने का पता चलता है। उक्त लाभ राशि* जहां 1970 में 6.9 करोड़ रुपये थी वहां 1971 में 8.5 करोड़ रुपये हो गयी। उनके व्यय में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद उनकी लाभ-राशि में यह वृद्धि पायी गयी।

176. इन बैंकों की कुल आय में 1971 में 63.8 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् उनकी आय बढ़कर 330.6 करोड़ रुपये हो गयी; 1970 में उसमें 49.4 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। जमाराशियों और उधारों पर अदा किये गये ब्याज की राशि में 1971 में 34.4 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उसमें 21.3 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। फिर भी स्थापना व्यय में 1971 में हुई वृद्धि 1970 में हुई 22.3 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले में केवल 20.1 करोड़ रुपये थी। इसलिए इन बैंकों की लाभ-राशि में 1971 में 1.6 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उसमें 1.1 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। 1971 की लाभ राशि में से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 3.94 करोड़ रुपये की प्रारक्षित निधियों में और 4.43 करोड़ रुपये भारत सरकार को अन्तरित किये।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कामकाज

गैर सरकारी क्षेत्र के 10 करोड़ रुपयों से अधिक जमाराशियों वाले सभी बैंक

177. गैर सरकारी क्षेत्र के 10 करोड़ रुपयों अधिक जमा राशियों वाले 25 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (विदेशी बैंकों को भी मिलाकर) के कार्य परिणामों में दिसम्बर 1971 के अन्त में प्रगति पायी गयी और उनकी लाभ-राशि** जहां 1970 में 3.9 करोड़ रुपये थी वहां 1971 में बढ़कर 4.6 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उनकी लाभ-राशि में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन बैंकों की कुल आय में 18.7 करोड़ रुपयों (26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बैंकों की आय में जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण यह था कि ब्याज और बट्टे से प्राप्त होने वाली आमदनियों में 1971 में 15.5 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त आमदनियां बढ़कर 74.4 करोड़ रुपये हो गयीं। उक्त वृद्धि प्रमुख रूप से 9 जनवरी 1971 से बैंक दर में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बैंकों द्वारा उच्चतर दरों पर अग्रिमों पर ब्याज लिये जाने और उनके अग्रिमों की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण हुई। जमाराशियों और उधारों पर अदा किये गये ब्याज 1971 में 8.5 करोड़ रुपयों (27.4 प्रतिशत) की वृद्धि पायी गयी। यह अंशतः जमाराशियों और उधारों की ब्याज दरों में हुई वृद्धि और अंशतः ब्याज-धारक जमाराशियों में हुई वृद्धि के कारण हुई। वेतन और भत्तों से सम्बन्धित व्यय में भी 4.50 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जो 1970 की अपेक्षा 22.8 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक थी। वेतन और भत्तों से सम्बन्धित व्यय में जो वृद्धि हुई उसका आंशिक कारण 1971 में कार्यालयों की संख्या में 249 की वृद्धि हो जाना भी था।

गैर सरकारी क्षेत्र के भारतीय अनुसूचित बैंक

178. 10 करोड़ रुपयों से अधिक जमाराशियों वाले गैर सरकारी भारतीय अनुसूचित बैंकों की कुल आय जहां 1970 में 27 करोड़ रुपये थी वहां 1971 में बढ़कर 35.6 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात इस एक वर्ष के दौरान उसमें 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय में हुई वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज और बट्टे में हुई। वृद्धि के कारण हुई ब्याज और बट्टे से प्राप्त राशि जहां पिछले वर्ष 23.2 करोड़ रुपये थी वहां 1971 में 30.8 करोड़ रुपये हो गयी। किन्तु आय में हुई भारी वृद्धि से वास्तविक लाभ राशि में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई। इस वर्ष लाभ राशि में केवल 0.4 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। कुल आय में हुई वृद्धि जमाराशियों और उधारों पर दिये गये ब्याज तथा वेतन और भत्तों आदि में हुई वृद्धि के कारण लगभग समायोजित हो गयी। किन्तु इस वर्ग के कुल बैंकों के कारोबार में अच्छी प्रगति पायी गयी; इसका मुख्य कारण यह था कि उनके द्वारा अधिक मात्रा में अग्रिम प्रदान किये गये थे और इस कारण ब्याज के रूप में उन्हें अधिक आमदनी प्राप्त हुई थी।

---

* यहां दिये गये आंकड़े बोनस की अदायगी के लिए किये गये समायोजन के बाद के हैं।

** करों और कर्मचारियों को देय बोनस के लिए व्यवस्था करने के बाद शुद्ध लाभ। बोनस की व्यवस्था को स्थापना व्यय के अधीन सम्मिलित किया गया है।

विदेशी बैंक

179. 1971 में छः विदेशी बैंकों की कुल आय में 10.3 करोड़ रुपयों (22.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका जो स्थापना व्यय हुआ वह उनकी कुल आय के संदर्भ में जहां 1969 में 27.1 प्रतिशत था वहां 1971 में कम होकर 25.2 प्रतिशत हो गया; 14 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में उक्त प्रतिशत 1969 और 1971 में क्रमशः 32.9 और 30.9 था। इन बैंकों की प्रकाशित वास्तविक लाभ राशि में वृद्धि पायी गयी अर्थात् उक्त राशि जहां 1970 में 2.8 करोड़ रुपये थी वहां 1971 में बढ़कर 3.1 करोड़ रुपये हो गयी जो इस वर्ष के दौरान हुई 10.7 प्रतिशत वृद्धि का परिचय देती है। इन बैंकों के समूह के वास्तविक लाभ का उनकी कार्यकारी निधि के संदर्भ में प्रतिशत भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में अधिक था। उसके निम्नलिखित कारण थे। (क) विदेशी बैंक प्रायः महानगरों में कारोबार करते हैं; (ख) वे प्रमुख रूप से विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार करते हैं; और (ग) वे सामान्य रूप से बड़े पैमाने पर लेन-देन का कार्य करते हैं। किन्तु भारतीय बैंक न केवल इस प्रकार के कारोबार करते हैं, बल्कि किसानों, लघु उद्योगों और शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के अन्य छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण प्रदान करने का कार्य भी करते हैं।

गैर बैंकिंग कम्पनियों पर नियंत्रण

180. इस संदर्भ में इस वर्ष के दौरान जो महत्वपूर्ण गतिविधि पायी गयी वह यह थी कि गैर बैंकिंग कम्पनियों के नाम जारी किये गये निदेशों में दिसंबर 1971 में संशोधन किया गया जिससे कि शेयरधारियों से प्राप्त गैर जमानती ऋणों और निदेशकों, भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा गारन्टीकृत ऋणों को भी उनके अंतर्गत लाया जा सके। जो ऋण अब तक जमाराशियों से संबंधित प्रतिबंधों से मुक्त थे उन पर अब 1 जनवरी 1972 से कंपनियों की वास्तविक स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत की एक अलग उच्चतम सीमा लागू की गयी है। यदि उपर्युक्त गैर जमानती ऋण निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक हों तो उस अतिरिक्त अंश का समायोजन करने के लिए तीन वर्ष और तीन महीने का समय दिया गया है। किन्तु कंपनियों की वास्तविक व्यावसायिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से कतिपय वर्गों के ऋणों, विशेषकर सरकार की गारंटी पर प्राप्त ऋणों और विदेशी स्रोतों से प्राप्त ऋण का उक्त निदेशों से विशिष्ट रूप से छूट दी गयी है।

181. पिछले वर्ष की रिपोर्ट के बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में जनता से जमाराशि स्वीकार करनेवाले और ब्याज की अत्यधिक ऊंची दरों पर ऋण देनेवाले कुछ 'वित्त निगमों' के कार्यकलाप भी प्रकाश में आये हैं। स्थानीय साहूकार अधिनियमों के उपबन्धों को इन निगमों पर लागू करने और कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन अधिनियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर संबंधित सरकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

182. आंध्र प्रदेश की सरकार 1 जुलाई 1971 को आंध्र प्रदेश चिट फंड अधिनियम, 1971 को अमल में लायी। केरल और तामिलनाडु में चिट कंपनियों के संबंध में विद्यमान विधि में संशोधन करने का प्रश्न उन राज्य सरकारों के विचाराधीन है। मैसूर राज्य और गोवा, दमन और दीव के संघशासित क्षेत्र की सरकारें चिट फंड विधानों को अधिनियमित करने का विचार कर रही हैं।

183. 31 मार्च 1969 तक की विवरणियों के आधार पर गैर बैंकिंग कंपनियों के पास रहनेवाली जमाराशियों का जो सर्वेक्षण किया गया उसके अनुसार कुल 27,961 कार्यरत मिश्रित पूंजी कंपनियों (वित्तीय और वित्तेतर) में से 2,241 कंपनियों ने रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को विवरणियां प्रस्तुत कीं। उनके द्वारा सूचित किये गये लेखों की कुल संख्या लगभग 6.25 लाख थी। मार्च 1969 के अंत में उन कंपनियों के पास (जमाराशियों के रूप में न माने जानेवाले 270.76 करोड़ रुपयों के छूट प्राप्त ऋण सहित) 593.65 करोड़ रुपये की कुल जमा राशियां थीं जबकि मार्च 1968 के अंत में (209.59 करोड़ रुपयों के छूट प्राप्त ऋण सहित) उनके पास 477.89 करोड़ रुपयों की कुल जमाराशियां थीं। 31 मार्च 1969 तक की इस जमा रकम में उन कंपनियों द्वारा विश्व बैंक, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी, अंतराष्ट्रीय विकास संघ, राष्ट्र मंडल विकास वित्त निगम और निर्यात-आयात बैंक जैसे विदेशी स्रोतों से लिये गये 121.64 करोड़ रुपयों तक के गैर जमानती ऋण शामिल हैं। मार्च 1968 के अंत में उक्त राशि 79.60 करोड़ रुपये थी।

जमा बीमा निगम

184. बीमाकृत वाणिज्य बैंकों की संख्या 82 से घटकर 81 हो गयी, क्योंकि एक बैंक का दूसरे बैंक में विलयन हो गया था। इस मामले में निगम पर कोई देयता नहीं आयी। आलोच्य अवधि में बीमाकृत जमाराशियों के संदर्भ में निगम पर कोई नई देयता नहीं आयी। निगम की स्थापना से लेकर 30 जून 1972 तक 14 बैंकों के जिन दावों के संबंध में अदायगी की गयी अथवा अदायगी के लिए व्यवस्था की गयी उनकी कुल राशि 113.04 लाख रुपये थी और स्थापना से लेकर अब तक कुल 113.04 लाख रुपयों के प्रतिस्थापित दावों के संदर्भ में 49.99 लाख रुपयों की कुल राशि निगम को वापस मिली।

185. बीमा रक्षा की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ; वह प्रति जमाकर्ता 10,000 रुपये थी। उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 1971 के अंत तक बीमाकृत बैंकों के 96.3 प्रतिशत जमा लेखों और 62.1 प्रतिशत जमाराशियों को बीमा योजना के अधीन रक्षित किया गया था। बीमाकृत बैंको द्वारा अपनी निर्धार्य जमाराशियों के संदर्भ में देय बीमा प्रीमियम की दर जहां जमाराशियों के प्रत्येक 100 रुपये पर वार्षिक पांच पैसे थी वहां उसे 1 अक्तूबर 1971 से कम कर प्रति 100 रुपये चार पैसे कर दिया गया।

सहकारी क्षेत्र में जमा बीमा योजना

186. 1 जुलाई 1971 से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तथा गोवा, दमन और दीव के संघशासित क्षेत्र में स्थित सहकारी बैंकों के लिए जमा बीमा योजना लागू कर दी गयी। निगम ने उस तारीख को 385 पात्र सहकारी बैंकों को बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत किया। परन्तु आलोच्य वर्ष अवधि में इन सहकारी बैंकों में से 5 बैंकों का पंजीकरण रद्द किया गया क्योंकि वे पात्र सहकारी बैंक नहीं रहे और रिज़र्व बैंक के कृषि ऋण विभाग ने भी 'प्राथमिक सहकारी बैंकों' की सूची में से उनका नाम हटा दिया। इसी अवधि में ग्यारह प्राथमिक सहकारी बैंकों ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) की धारा 5 (गगग) के साथ पढ़ी जानेवाली रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 2 (ग III) में निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति कर प्राथमिक सहकारी बैंकों का स्तर प्राप्त कर लिया था; अतः उन्हें बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत किया गया। इस प्रकार बीमाकृत सहकारी बैंकों की कुल संख्या जून 1972 के अंत में 391 थी।

187. रिज़र्व बैंक आफ इंडिया इस उद्देश्य से शेष राज्य सरकारों संघशासित क्षेत्रों के साथ सक्रिय प्रयत्न कर रहा है कि जमा बीमा निगम उन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों को भी योजना की सुविधा प्रदान कर सके।

III. सहकारी बैंक व्यवसाय की गतिविधियां

188. आलोच्य वर्ष में रिज़र्व बैंक ने देश की समग्र सहकारी ऋण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने की कोशिश की। इस क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थीं : (क) छोटे और कमजोर कृषकों के लिए निर्दिष्ट ऋण के अनुपात को बढ़ाया गया; (ख) ऋण संबंधी आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाने और तदनरूप निधियों की पूर्ति करने के के उद्देश्य से खरीफ और रबी की फसलों के लिए अलग अलग ऋण की व्यवस्था की गयी; (ग) खेती में काम आनेवाली मूल वस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया गया; (घ) कृषि उत्पादों के सुव्यवस्थित विपणन के लिए ऋण प्रदान किये जाने की अलग व्यवस्था कर उक्त विपणन कार्य को सुविधा प्रदान की गयी; (ङ) रूई के अनुचित स्टाक बनाये रखने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उस पर दिये जानेवाले अग्रिमों को विनियमित किया गया; (च) ऋण नीतियों में विशेषरूप से मियादी ऋण के क्षेत्र में और सुधार किया गया ताकि सीमित साधनों का प्रभावकारी उपयोग हो; (छ) वित्तीय साधनों के अच्छे प्रबंधनों के लिए वित्तीय अनुशासन लागू किया गया; और (ज) सहकारिता की दृष्टि से कमजोर राज्यों में ऋण के संदर्भ में विद्यमान खाइयों का पता लगाने के लिए विशेष अध्ययन प्रारंभ किये गये ताकि सहकारी गतिविधि में पाये जानेवाले असंतुलन को यथासंभव दूर किया जा सके।

कृषि ऋण मंडल और उसकी स्थायी समितियां

189. कृषि ऋण मंडल द्वारा आलोच्य वर्ष में विचार किये गये महत्वपूर्ण विषयों में निम्नलिखित सिफ़ारिशें भी शामिल थीं कृषि को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों से संबंधित राज्य अधिनियमों पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशें और विभेदक ब्याज दरों से संबंधित समिति की सिफारिशें जहां तक उक्त दरें कृषि ऋणों पर लिये जानेवाले ब्याज से संबंधित हों। उपर्युक्त विशेषज्ञ दल ने सहकारी बैंकों को प्राप्त रियायतों और विशेषाधिकारों को कृषि ऋण संबंधी कारोबार में लगे हुए वाणिज्य बैंकों के लिए भी लागू करने की जो सिफ़ारिशें की थीं उन्हें स्वीकार कर लिया गया; किन्तु यह अनुभव किया गया कि विभेदक दरों से संबंधित समिति द्वारा सिफ़ारिश की गयी विभेदक दरों की योजना प्रारंभ में छोटे कृषक एजेन्सी प्रायोजनाओं और सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं के अंतर्गत आनेवाले कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से सहकारी बैंकों द्वारा लागू की जानी चाहिए।

190. कृषि के वित्तपोषण के क्षेत्र में सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों के कार्यकलापों को समन्वित करने के प्रश्न पर भी उक्त मंडल ने विचार किया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि को दी जानेवाली ऋण सहायता से संबंधित सभी कार्यकलापों को राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया कि यदि मंडल अपनी स्थायी समिति के द्वारा यह कार्य करे तो उचित होगा। अतः एक स्थाई समिति गठित करने का निश्चय किया गया है। रिज़र्व बैंक के गवर्नर उक्त समिति के अध्यक्ष होंगे और सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों, भारत सरकार तथा कतिपय राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उसके सदस्य होंगे।

छोटे कृषकों का वित्तपोषण

191. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा जा चुका है देश, में 46 छोटे कृषक विकास एजेन्सी प्रायोजनाओं और 41 सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं की प्रायोगिक आधार पर स्थापना की गयी है। छोटे कृषक विकास एजेन्सी प्रायोजना कार्यक्रमों के जो विशेष अध्ययन योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछले वर्ष प्रारंभ किये गये थे उन्हें इस वर्ष भी जारी रखा गया। इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के एक दल ने छिदवाड़ा छोटे कृषक विकास एजेन्सी प्रायोजना के कार्यचालन का अध्ययन किया। उक्त दल ने इस बात पर काफी जोर दिया कि आय वर्ग के आधार पर कृषकों का पता लगाया जाए और यह सुझाव दिया कि उसके बाद 'विशिष्ट कार्यक्रम' का दृष्टिकोण अपनाया जाय। दल की टिप्पणियां योजना आयोग के पास भेजी जा चुकी हैं।

192. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर अन्य कृषकों को ऋण उपलब्ध किया जाता है, जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया चुका है, केन्द्रीय सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे शिखर बैंकों से लिये गये अल्पावधि कृषि ऋणों के अंतर्गत अपनी बकाया राशि के कम से कम 10 प्रतिशत को ऐसे कृषकों की वित्तीय सहायता करने के लिए रखी हुई राशि के रूप में दिखायें। उक्त प्रतिशत को इस वर्ष बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। सूचना देनेवाले 182 केन्द्रीय बैंकों में से 117 केन्द्रीय बैंकों ने 1971-72 में उक्त अपेक्षा की पूर्ति की।

193. ऋण सुविधा प्राप्त करने की पात्रता के लिए प्रारंभिक निवेश करने का जो भार रहता है उसे कम करने के उद्देश्य से छोटे कृषकों को ऋण राशि के जिस सुनिश्चित अनुपात के शेयर लेने पड़ते हैं उसे कम कर दिया गया है; इससे उन्हें अल्पावधि ऋणों के मामले में पहले वर्ष में केवल 5 प्रतिशत और उसके बाद के दो वर्षों में प्रतिवर्ष 2½ प्रतिशत और मध्यावधि ऋणों के मामले में एकमुश्त 5 प्रतिशत का अभिदान करने की आवश्यकता है। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के मामले में छोटे कृषकों को पहले वर्ष में 2 प्रतिशत और उसके बाद के 3 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत का अभिदान करने की आवश्यकता है; इस प्रकार कुल शेयरों की राशि को बढ़ाकर ऋण राशि का 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

194. निवेश ऋणों के संबंध में छोटे कृषकों को दो रियायतें दी गयीं; वे इस प्रकार थीं : उन्हें ऋणों की वापसी अदायगी के लिए लंबी अवधि प्रदान की गयी और यह सुविधा दी गयी कि वे कम मार्जिन-राशि रखें। मुर्गी पालन, डेरी उद्योग जैसे उद्देश्यों के लिए छोटे कृषकों को रिज़र्व बैंक से उधार ली गयी निधियों में से 2000 रुपयों तक के मियादी ऋण बंधक जमानत के स्थान पर व्यक्तिगत जमानत पर प्रदान किये जा सकते हैं।

वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण समितियों का वित्तपोषण

195. वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्तपोषण किये जाने के संदर्भ में 1970 में शुरू की गयी संक्रमणकालीन योजना इस वर्ष पांच राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर और उत्तर प्रदेश राज्यों के 49 जिलों में जारी रही। उक्त योजना को हाल ही में उड़ीसा के दो जिलों में लागू किया गया है और यह आशा की जाती है कि इन जिलों के वाणिज्य बैंक अपने लिए नियत की गयी समितियों का 1972 के खरीफ मौसम से वित्तपोषण करेंगे। उक्त योजना के दूसरे वर्ष में वाणिज्य बैंकों द्वारा समितियों को प्रदान किये गये फ़सली ऋणों में पहले वर्ष में वितरित किये गये फ़सली ऋणों की अपेक्षा 176 लाख रुपयों की वृद्धि हुई और प्रत्येक समिति को प्रदान किये गये ऋण की औसत राशि उक्त अवधि में 0.12 लाख रुपयों से बढ़कर 0.50 लाख रुपये हो गयी। उत्पादन ऋणों के अलावा वाणिज्य बैंकों ने विकासात्मक उद्देश्यों के लिए मार्च 1972 के अंत तक 39 लाख रुपयों तक के मीयादी ऋण भी मंजूर किये थे। इन क्षेत्रों में कार्य करनेवाली समितियों को पुनः सशक्त बनाने के उद्देश्य से ऐसी समितियों की शेयर पूंजीमें अभिदान करने के निमित्त रिज़र्व बैंक ने दीर्घकालीन क्रियाएँ निधि में से राज्य सरकारों के लिए उधार शर्तों पर ऋण मंजूर किये हैं।

196. रिजर्व बैंक की सिफारिश पर राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने मैसूर राज्य की योजना के कार्य-चालन का अध्ययन किया और यह पाया कि उक्त योजना के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति की गयी थी और इस प्रकार के कृषि वित्तपोषण को समेकित और विस्तारित करने के निमित्त उसने अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया है कि वैतनिक प्रबन्धकों की नियुक्ति की जाए और वैतनिक कर्मचारियों पर होनेवाले व्यय की पूर्ति के लिए राज्य सरकार अधिक अभिदान करे। इस योजना की प्रगति पर बैंक बारीकी से ध्यान देता आ रहा है।

सहकारी गतिविधि

197. चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से कृषि ऋण के वितरण में विद्यमान क्षेत्रीय असमानताएँ प्रकाश में आयीं और इस संतुलन को दूर करने की आवश्यकता पर रिजर्व बैंक और भारत सरकार ध्यान देती रही। सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श के साथ कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्गठन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रगत योजना बनायी ताकि पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों में कृषि ऋण की उपलभ्यता में सुधार लाया जा सके। उक्त योजना के अधीन केन्द्रीय बैंक और प्राथमिक बैंकों की प्रतिदेय राशियों की ब्योरेवार छान-बीन करने के लिए कहा गया है ताकि अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया जाए और इस प्रकार बट्टे खाते डाले जाने योग्य राशि को सहकारी ऋण ढांचे के तीन चरणों की संस्थाओं में से प्रत्येक चरण की संस्थाओं को लगभग 20 प्रतिशत की दर पर विभाजित कर लेना होगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के कार्य से रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से संबद्ध है। उक्त योजना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार रिजर्व बैंक ने 74 कमजोर बैंकों का पता लगाया और इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाई भी शुरू की गयी है।

198. सहकारिता की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में कृषि ऋण सुविधा को विस्तारित करने की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से ऋण स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक समझा गया और योजना आयोग द्वारा इस संबंध में की गयी सिफ़ारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की है। पश्चिम बंगाल के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जनवरी 1972 में कृषि ऋण विभाग के मुख्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक दल की नियुक्ति की; उक्त दल प्रत्येक जिले की कृषि ऋण संबंधी स्थिति का पुनरीक्षण करेगा और कृषि ऋण स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगा। दल ने अपनी रिपोर्ट जून 1972 में प्रस्तुत की।

सहकारी ऋण नीति, क्रिया विधियां और कार्यकलाप

199. कृषि के मौसमी कार्यकलापों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं का उपयोग करने के संदर्भ में अनुशासन लाने की दृष्टि से बैंक ने खरीफ और रबी फ़सलों के लिए अलग अलग सीमाएं प्रदान करने और उन न्यूनतम स्तरों को जहां तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऋणों को वर्ष के किसी भी महीने में लाना होगा, निर्धारित करने की अपनी नीति को जारी रखा। इस प्रकार ऋणों के स्तर को कम करने से इस बात का परिचय मिलेगा कि बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की चुकौती होती है। रूई और कपास का विपणन कार्य चयनात्मक ऋण नियंत्रण के क्षेत्र में आता है उक्त विपणन कार्य के लिए विशेष ऋण व्यवस्था को जारी रखा गया; और रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान रूई और कपास को छोड़कर अन्य फ़सलों के विपणन के लिए भी ऋण सीमाएँ मंजूर कीं। जनजातीय वर्गों के सामान्य वन उत्पादों के विक्रय से संबंधित विपणन समितियों को भी बैंक ने पहली बार वित्तीय सहायता प्रदान की।

200. सहकारी ऋण संस्थाओं अर्थात् राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा 1970-71 में समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान किये गये समग्र कार्यकलापों को सारणी 22 में दर्शाया गया है।

201. उपर्युक्त सारणी से यह मालूम होगा कि जहां राज्य सहकारी बैंकों के स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिये गये ऋणों की बकाया राशि 534 करोड़ रुपये थी वहां रिजर्व बैंक को देय राशि 245 करोड़ रुपये या लगभग 46 प्रतिशत थी। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सहकारी बैंकों में अपने वित्तीय स्रोतों पर अवलंबित रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इसके परिणामस्वरूप अल्पावधि कृषि ऋणों के लिए रिजर्व बैंक से लिये जानेवाले उधारों पर उनकी निर्भरता क्रमशः कम होती जा रही है।

सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

202. सहकारी क्षेत्र को विभिन्न शीर्षों के अधीन और विभिन्न उद्देश्य के लिए विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में हाल ही में हुए तकनीकी सुधारों के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता में लगातार जो वृद्धि होती रही है वह सारणी 23 में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होती है।

अल्पावधि वित्त

203. अल्पावधि वित्त के संबंध में इस वर्ष के दौरान शुरू किये गये महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं: (i) आंध्र प्रदेश के कतिपय जिलों के जनजातीय कृषकों को कृषि ऋण प्रदान किये जाने के निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत गिरिजन सहकारी विकास निगम के लिए इस वर्ष के दौरान 40 लाख रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की गयी। (ii) रिजर्व बैंक ने पहली बार 1971-72 में उड़ीसा के एक केन्द्रीय बैंक की ओर से सामान्य वन उत्पादों के विपणन के लिए 1.50 लाख रुपयों की ऋण सीमा मंजूर की (iii) उर्वरकों की खरीद, संचयन, वितरण आदि के लिए वित्तपोषण करने के संबंध में राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ने केवल ऐसे ही मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान की जहां शिखर विपणन समितियों वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित निधियां प्राप्त करने में असमर्थ थीं। इस नीति के अनुरूप ब्याज दरों को लगभग वाणिज्य बैंकों की दरों के स्तर पर लाने के उद्देश्य से अब तक बैंक दर पर लिये जानेवाले ब्याज की दर को 1972 से बढ़ाकर बैंक दर 2 प्रतिशत अधिक कर दिया गया। (iv) रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (ख) के अंतर्गत रिजर्व बैंक हथकरघा/बिजली चालित करघा बुनकर समितियों के उत्पादन तथा विपणन संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के लिए बैंक दर से 1½ प्रतिशत कम दर पर वित्तीय सहायता देता रहा। 22 अनुमोदित वर्गों के अंतर्गत आनेवाले अन्य कुटीर और लघु उद्योग यूनिटों का वित्तपोषण करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

मध्यावधि वित्त

204. मध्यावधि वित्त के क्षेत्र में बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किये कि भूमि विकास बैंकों द्वारा मीयादी ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में लागू किये गये अनुशासन का केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थूल रूप से पालन करते हैं। केन्द्रीय बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि नये कुएं खोदने और पंप सेट लगाने आदि के लिए ऋण मंजूर करने से पहले वे भूमिगत पानी की उपलभ्यता के संबंध में सुनिश्चित कर लें।

सारणी 22 :—सहकारी ऋण संबंधी गतिविधि में प्रगति

(राशि करोड़ रुपयों में)

संस्था का प्रकार	1968–69	1969–70	1970–71 (अनंतिम)
1	2	3	4
(क) राज्य सहकारी बैंक			
(i) संख्या	25	25	25
(ii) स्वाधिकृत निधियां	75	83	92
(iii) जमाराशियां	216	234	279
(iv) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार	227	249	245
(क) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण	184	216	190
(v) कार्यकारी पूंजी	567	619	685
(vi) जारी किये गये ऋण	667	707	723
(vii) बकाया ऋण	459	510	534
(क) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण	227	276	287
(viii) (iv क) का (क) में प्रतिशत	81	78	66
(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंक			
(i) संख्या	341	340	340
(ii) स्वाधिकृत निधियां	155	174	193
(iii) जमाराशियां	351	382	419
(iv) रिजर्व बैंक/शिखर बैंक से लिये गये उधार	291	331	अनु:
(v) कार्यकारी पूंजी	830	928	1030
(vi) जारी किये गये ऋण	860	873	969
(vii) बकाया ऋण	641	740	801
(ग) राज्य भूमि विकास बैंक			
(i) संख्या	19	19	19
(ii) स्वाधिकृत निधियां	36	46	58
(iii) बकाया डिबेंचर	426	571	725
(iv) कार्यकारी पूंजी	488	638	807
(v) जारी किये गये ऋण	144	153	168
(vi) बकाया ऋण	395	510	638
(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां			
(i) संख्या (हजारों में)	168	163	161
(ii) सदस्यता (,,)	29173	29766	30961
(iii) स्वाधिकृत निधियां	215	242	265
(iv) जमाराशियां	57	63	70
(v) उधार	540	618	675
(vi) जारी किये गये ऋण	504	540	578
(vii) बकाया ऋण	619	711	784

अनु.—अनुपलब्ध

205. इसके अलावा छोटे और आर्थिक दृष्टि से कमजोर कृषकों को दुधारू पशु खरीदने और मुर्गीपालन उद्योग के लिए प्रदान किये जानेवाले ऋणों के संबंध में भी रिजर्व बैंक ने इस बात की स्वीकृति दी थी कि "अनुमोदित उद्देश्यों" के लिए 40 प्रतिशत ऋण प्रदान करने की शर्त के भीतर उन्हें भी हिसाब में लिया जा सके जिससे कि उनके संदर्भ में भी रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके। मध्यावधि कृषि ऋण प्रदान किये जाने के लिए 'अनुमोदित' उद्देश्यों की सूची को व्यापक बना दिया गया है और इस प्रकार उसमें कृषि के साथ-साथ किये जानेवाले सुअर पालन, भेड़-बकरी पालन, कृषकों द्वारा

सारणी 23—सहकारी संस्थाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा 1970-71 और 1971-72 में दिए गए ऋण

(राशि करोड़ रुपयों में)

वित्तीय सहायता का उद्देश्य	1970-71 (जुलाई-जून)				1971-72 (जुलाई-जून)			
	मंजूरी की गयी सीमाएं	आहरण	वापसी अदायगियां	बकाया राशि	मंजूरी की गयी सीमाएं	आहरण	वापसी अदायगियां	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I अल्पावधि								
(i) कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलाप (बैंक दर से 2% कम दर पर)	390.11	124.76	149.76	188.84	394.04	168.51	505.27	152.08
(ii) रूई और कपास को छोड़कर अन्य फ़सलों का विपणन					3.18	3.59	2.96	0.66
(iii) रूई और कपास का विपणन	10.65	8.56	9.52	1.03	11.70	10.25	10.10	1.19
(iv) उर्वरकों की खरीद और वितरण (बैंक दर से 2% अधिक दर पर) (1)	16.80	11.27	21.11	4.22	24.75	23.04	18.49	8.76
(v) हथकरघे पर वस्तुओं का उत्पादन और उनका विपणन (बैंक दर से $1\frac{1}{2}$% कम दर पर (5)	10.12	12.36	10.95	7.83	12.76	14.92	13.24	9.51
(vi) अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का विकासपोषण	0.47	0.02	—	0.02	0.86	0.59	0.20	0.33
(vii) तागे की खरीद और बिक्री (बैंक दर पर)	0.80	0.04	0.06	0.03	0.97	0.14	0.17	कुछ नहीं
(viii) कृषिनि को ऋण (बैंक दर पर)	8.00	11.80	1.28	7.52	8.00	1.36	8.88	कुछ नहीं
II मध्यावधि								
(i) कृषि उद्देश्यों के लिये (बैंक दर से $1\frac{1}{2}$% कम दर पर)	18.76	14.20	10.31	24.31(2)	20.62	6.15	9.76	20.70(3)
(ii) प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन (बैंक दर से $1\frac{1}{2}$% कम दर पर)	21.80	13.64	4.33	13.66(2)	31.39	24.08	12.04(2)	25.70(2)
III दीर्घावधि								
(i) सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिये राज्य सरकारों को दिये गये ऋण	11.88(5)	12.49(4)	4.40	41.93	16.38	14.14	4.72	51.34
(ii) कृषिनि को दिये गये दीर्घावधि ऋण (वार्षिक 4.25% की दर पर)	—	—	—	—	5.00	5.00	—	5.00

(1) 1972 के पहले उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए रिज़र्व बैंक दर पर विकासपोषण किया जाता था। परन्तु उक्त दर को वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों के समान बनाने के उद्देश्य से जनवरी 1972 से बढ़ाकर बैंक दर से 2% अधिक बना दिया गया । उक्त आंकड़े 1970 और 1971 के कैलेण्डर वर्षों से संबंधित हैं।

(2) पुनर्व्यवस्था को मिलाकर।

(3) बैंक दर पर मंजूर की गयी सीमाओं के आधार पर दिये गये ऋणों की बकाया राशि को मिलाकर।

(4) 1969-70 के दौरान मंजूर किये गये 75.96 लाख रुपयों के ऋणों को मिलाकर।

(5) वित्तीय वर्ष के आंकड़े।

संग्रह धानी की खरीद और कृषि संबंधी मशीनों के अंतर्गत रबड़-रोलरों की खरीद जैसे कार्यकलापों को शामिल कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वित्तीय सहायता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, यह भी निश्चित किया गया है कि अब तक सहकारी वर्ष के लिए मंजूर की जानेवाली मध्यावधि ऋण सीमाएँ 1973 से कैलेण्डर वर्ष के लिए मंजूर की जाएंगी।

206. रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से मध्यावधि ऋण प्रदान करता रहा ताकि वे प्राकृतिक विपत्तियों से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर सकें। एक राज्य सहकारी बैंक के संदर्भ में उसके क्षेत्र में फ़सल के लगातार खराब हो जाने के कारण परिवर्तन ऋणों की मियाद को पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति दी गयी। इसके अलावा चार राज्य सहकारी बैंकों के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण परिवर्तन संबंधी सुविधाएँ प्रदान करने के निमित्त सरकारी/न्यासी प्रतिभूतियों के बंधक पर बैंक दर पर 9.65 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं। उक्त प्रतिभूतियां उन राज्य सहकारी बैंकों की स्थिरीकरण निधियों में से किये गये निवेश की द्योतक हैं। इन ऋण सीमाओं में से जून 1972 तक 7.1 करोड़ रुपये लिये गये थे और 30 जून 1972 को 5.4 करोड़ रुपये बकाया थे।

शेयर पूंजीगत ऋण

207. राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से राज्य सरकारों के लिए मंजूर किये जानेवाले ऋणों के संबंध में उदार नीति जारी रही। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य सरकारें (क) विशेष पुनः स्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत आनेवाले कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों (ख) छोटे कृषक विकास एजेन्सी प्रायोजना और सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजना जैसे विशेष कार्यक्रमवाले क्षेत्रों की सक्षम समितियों (ग) समितियों आदि का वित्तपोषण करनेवाले वाणिज्य बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान कर सकें। अपर्याप्त चलमुद्रागत साधनों की समस्या का सामना करनेवाले केन्द्रीय बैंकों के संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने विशिष्ट मामलों में विशेष शर्तों पर शेयर सहभागिता के लिए भी ऋण मंजूर किये थे; ऐसे ऋणों पर 4 प्रतिशत की ब्याज दर लागू है और वे तीन समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय हैं।

208. मार्च 1972 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 14 राज्य सरकारों को पांच शिखर बैंकों, 108 केन्द्रीय बैंकों, 8,999 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 10 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 85 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों, 31 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और एक राज्य औद्योगिक सहकारी बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिए दीर्घकालीन क्रियाएँ निधि में से कुल 15.81 करोड़ रुपयों (0.57 करोड़ रुपये के नवीकृत ऋणों को छोड़कर) के ऋण प्रदान किये गये।

दीर्घावधि वित्त

209. रिजर्व बैंक पहले की तरह यह सुनिश्चित करता रहा है कि भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर कार्यक्रमों को पर्याप्त संस्थागत सहायता उपलब्ध होती है। 1971-72 के लिए पहले 140 करोड़ रुपयों के डिबेंचर कार्यक्रम की जो परिकल्पना की गयी थी, उसके मुकाबले में भूमि विकास बैंकों ने वास्तव में 125.39 करोड़ रुपयों के डिबेंचर जारी किये। इस राशि के अधिकांश भाग (107 करोड़ रुपये) का अभिदान राज्य और केन्द्रीय सरकारों के अलावा भारतीय बीमा निगम, स्टेट बैंक आफ इंडिया, अन्य वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक आफ इंडिया जैसी संस्थाओं द्वारा किया गया। शेष 25 करोड़ रुपयों की राशि पारस्परिक सहायता से प्राप्त हुई।

210. रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख निवेशकों और केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक फ़रवरी 1972 में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में 1972–73 के लिए जहां 155 करोड़ रुपयों का ऋण कार्यक्रम स्वीकार किया गया वहां 122 करोड़ रुपयों का डिबेंचर कार्यक्रम स्वीकार किया गया। डिबेंचर कार्यक्रम को इस प्रकार परिशोधित किया गया कि भूमि विकास बैंकों के अपने वित्तीय साधनों का उसमें विनियोजन हो और वे अपने स्वायत्त साधनों का लाभकारी ढंग से उपयोग करें। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपयों की सहायता राशि निर्धारित की गयी और यह आशा की गयी कि शेष 22 करोड़ रुपयों की राशि निजी सहायता से प्राप्त होगी।

211. इस वर्ष के दौरान नीति में किया गया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि केन्द्रीय भूमि विकास बैंक के स्तर पर रहनेवाली अतिदेय राशियों की सीमा तक सहायता कार्यक्रम में परिशोधन किया गया ताकि किसी राज्य के कतिपय क्षेत्रों में रहनेवाली भारी अतिदेय राशियों के कारण विकास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए संस्थागत सहायता प्राप्त करने की समूचे राज्य की पात्रता पर प्रभाव न पड़े। फिर भी यदि प्राथमिक बैंकों/उनकी शाखाओं की अतिदेय राशि उनकी मांग के 50 प्रतिशत से अधिक हो तो शिखर बैंकों को उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु विशेष संदर्भ में उन प्राथमिक बैंकों/उनकी शाखाओं को जिनकी अतिदेय राशि 50 प्रतिशत से अधिक हो, सामान्य सिंचाई के उद्देश्यों के लिए शिखर बैंकों से ऋण प्राप्त करने योग्य बना दिया गया बशर्ते कि ऐसे ऋणों की राशि, 1969–70 या 1970–71 में जारी किये गये कुल ऋणों की राशि में से जो भी अधिक हो उसके 25 प्रतिशत से अनधिक हो। इसके अलावा कमजोर राज्यों अर्थात् पूर्वी क्षेत्र के चार राज्यों और राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर के प्राथमिक बैंक/उनकी शाखाएं भी छोटे कृषकों का वित्तपोषण करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकती थीं। चाहे उनकी अतिदेय राशि की मात्रा कुछ भी क्यों न हो।

212. भूमि विकास बैंकों द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान किये जा सकते हैं उनको रिजर्व बैंक पिछले वर्षों की तरह बराबर महत्व देता रहा। पहले की तरह इस वर्ष भी यह शर्त जारी रखी गयी कि प्रदान किये गये ऋणों का कम से कम 90 प्रतिशत उत्पादक उद्देश्यों के लिए हो जिसमें से 70 प्रतिशत ऋण ऐसे उद्देश्यों के लिए हो जिनका आसानी से अभिज्ञान हो सके।

213. कृषि पुनर्वित्त निगम और रिजर्व बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के संदर्भ में भूमि विकास बैंकों की ऋण नीतियों में समन्वयन लाने के उद्देश्य से भूमि विकास बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे (क) सामान्य सिंचाई के उद्देश्यों के लिए ऋण मंजूर करने के पहले भूमिगत जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लें; (ख) विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदान किये जानेवाले ऋणों के संदर्भ में न्यूनतम जोत सीमा निर्धारित करें जिससे कि निवेश कार्य में अधिक पूंजी लगाये जाने या साधनों का कम उपयोग किये जाने की प्रवृत्ति को रोका जा सके; (ग) ऋणकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता तथा निवेश द्वारा निर्मित आस्तियों की उपयोगी जीव्यता के आधार पर ऋणों की अवधि निर्धारित करें और (घ) इस बात पर जोर दें कि निवेश की लागत में ऋणकर्ता का उचित अभिदान हो।

214. 31 मार्च 1972 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान भूमि विकास बैंकों ने कुल कुल 4.09 करोड़ रुपयों के ग्रामीण डिबेंचर जारी किये जिनमें रिजर्व बैंक के अभिदान की राशि 1.33 करोड़ रुपये थी। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में बचत करने की सीमित क्षमता तथा युद्ध से प्रभावित

पंजाब के क्षेत्रों में हुई फ़सल की हानि को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों के भूमि विकास बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे 5 प्रतिशत की दर पर सामान्य डिबेंचर जारी करने के कार्यक्रमों के स्थान पर 2½ प्रतिशत की दर पर ग्रामीण डिबेंचर जारी करने का सीमित कार्यक्रम बनायें।

कृषि पुनर्वित्त निगम को ऋण

215. आलोच्य वर्ष में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम 1934 और कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम 1963 में संशोधन किये गये जिससे कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिश के अनुसरण में दीर्घकालीन क्रियाएं निधि में से रिज़र्व बैंक कृषि पुनर्वित्त निगम को दीर्घावधि ऋण प्रदान कर सके। निगम ने इस वर्ष के दौरा मंजूर किये गये 5 करोड़ रुपयों के ऋण लिये। उनके अलावा रिज़र्व बैंक निगम को अल्पावधि ऋण भी देता रहा (सारणी 23)।

सहकारी बैंकिंग विनियमन

216. इस वर्ष के दौरान प्राथमिक सहकारी बैंकों की सूची में कतिपय कृष्येतर ऋण समितियों को शामिल करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत आनेवाले सहकारी बैंकों की संख्या मार्च 1971 के अंत में विद्यमान 1,315 से बढ़कर जून 1972 के अन्त में 1,337 हो गयी है (29 राज्य सहकारी बैंक, 366 केन्द्रीय सहकारी बैंक और 942 प्राथमिक सहकारी बैंक)।

217. 1971-72 के दौरान दो राज्य सहकारी बैंकों और तीन प्राथमिक सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, की 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 22 के अधीन भारत में बैंक व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस दिये गये; इससे लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गयी। सहकारी बैंकों के कार्यालयों की जो संख्या 30 जून 1971 को 4,931 थी वह 31 दिसम्बर 1971 को बढ़कर 5,164 हो गयी। राज्य और प्राथमिक सहकारी बैंकों को 74 नये कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस दिये गये जब कि 1970-71 में 76 नये कार्यालय खोलने के लिए उन्हें लाइसेंस दिये गये थे।

218. इस वर्ष के दौरान आठ राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के उपबन्धों का पालन नहीं किया। इन बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनके कार्यकलापों पर बारीकी से निगरानी रखी गयी। उक्त उपबन्धों का पालन न करनेवाले 21 प्राथमिक सहकारी बैंकों में से 11 बैंकों के आवेदन-पत्रों के संदर्भ में भारत सरकार से 1 मार्च 1972 से एक वर्ष की अवधि तक छूट देने की सिफ़ारिश की गयी थी; उनमें से चार बैंकों ने बाद में उपबन्धों का पालन किया और अन्य बैंकों के आवेदन पत्र विचाराधीन थे।

219. इस वर्ष के दौरान निरीक्षण किये गये 744 सहकारी बैंकों में से 99 बैंकों का निरीक्षण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35(1) के अधीन रिज़र्व बैंक की तरफ़ से राज्य सहकारी बैंकों के अधिकारियों ने किया। 1 जुलाई 1971 से 30 जून 1972 तक की अवधि में 15 राज्य सहकारी बैंकों, 219 केन्द्रीय सहकारी बैंकों 11 राज्य और जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों, 9 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों 5 राज्य हथकरघा बुनकर समितियों, 3 शिखर विपणन समितियों और 459 प्राथमिक सहकारी बैंकों के संदर्भ में 721 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गयी।

220. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा जा चुका है, जमा बीमा योजना 1 जुलाई 1971 से तीन राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गोवा दमन और दीव के संघशासित क्षेत्र के सहकारी बैंकों के लिए लागू की गयी। शेष राज्य सरकारों को ऐसे उचित विधान बनाने की सलाह दी गयी है जिससे उनके राज्यों में स्थित सहकारी बैंकों के लिए भी उक्त योजना लागू हो सके।

221. सहकारी बैंकों द्वारा रुई पर प्रदान किये जानेवाले अग्रिमों को विनियमित करने के लिए शुरु किये गये चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों को इस वर्ष भी जारी रखा गया जिससे कि मूल्यों के बढ़ने की प्रत्याशा में स्टाकों को रोक रखने की प्रवृत्ति को दूर किया जा सके। जिन सहकारी बैंकों के संबंध में यह पाया गया कि वे अपनी निधियों का उपयोग उगाही तथा समीकरण भंडार से संबंधित कार्यकलापों के लिए कर रहे हैं, उनसे कहा गया कि वे ऐसा न करें और उन्हें यह सलाह दी गयी कि वे ऐसे कार्यकलाप केवल एजेंसी के आधार पर करें।

प्रशिक्षण सुविधाएं

222. इस वर्ष के दौरान तमिलनाडु, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा गोवा, दमन और दीव की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को कृषि ऋण विभाग द्वारा मार्गदर्शक अध्ययन की सुविधाएं प्रदान की गयीं। इनके अलावा, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका ईरान, त्रिनिदाद और बंगला देश के सात विदेशी उच्च अधिकारी उक्त विभाग में आये और उसकी कार्यपद्धतियों का अध्ययन किया। रिज़र्व बैंक, सहकारी बैंकों और छोटे कृषक विकास एजेंसी प्रायोजना और सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजना के कर्मचारियों को बैंक द्वारा संचालित संस्थाओं में दिये गये प्रशिक्षण के विवरणों पर शिक्षा और प्रशिक्षण के खण्ड में चर्चा की गयी है।

223. इसके अलावा कृषि ऋण विभाग ने सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज, पूना में जुलाई 1971 में प्राथमिक शहरी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की पहली विचार-गोष्ठी और फ़रवरी 1972 में राज्य सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की चौथी विचार-गोष्ठी का आयोजन किया। इन विचार-गोष्ठियों का उद्देश्य इनमें भाग लेनेवाले अधिकारियों के लिए एक ऐसे मंच की व्यवस्था करना था जहां वे अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकें और अपने विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें जिससे विशेष रूप से अनुमोदित नीतियों का पालन करने में आनेवाली कठिनाइयों को समझा जा सके और परिणामस्वरूप उनके प्रभावकारी क्रियान्वयन की प्रणालियां बनायी जा सकें/उनमें सुधार लाया जा सके।

कृषि पुनर्वित्त निगम

224. 1971-72 के दौरान निगम ने कृषि विकास से संबंधित 269 योजनाओं का अनुमोदन किया और 154.24 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता मंजूर की जबकि पिछले वर्ष अनुमोदित 100 योजनाओं के संदर्भ में 62.15 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता मंजूर की थी। 269 योजनाओं में से केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा क्रमशः 176,11 और 82 योजनाओं का वित्तपोषण किया जाना है और उनके संदर्भ में प्रदान किये जानेवाले पुनर्वित्त की राशियां क्रमशः 115.12 करोड़ रुपये, 11.03 करोड़ रुपये और 8.98 करोड़ रुपये हैं।

225. इस वर्ष के दौरान अनुमोदित की गयी योजनाओं में से 198 योजनाएं लघु सिंचाई से, 40 योजनाएं बागान/बागवानी से, 13 योजनाएं भूमि सुधार से, 3 योजनाएं मत्स्य पालन से, 5 योजनाएं गोदामों के निर्माण-कार्य से, 4 योजनाएं मुर्गी पालन से, 2 योजनाएं डेरी उद्योग के विकास से और एक-एक योजना भूमि के संरक्षण और बकरी पालन से और 2 योजनाएं खेती के मशीनीकरण से संबंधित थीं। उपर्युक्त योजनाओं के अलावा 30 जून 1972 को 342 योजनाएं निगम के पास संवीक्षण के विभिन्न चरणों में थीं।

226. आलोच्य वर्ष में निगम ने पहले मंजूर की गयी 103 योजनाओं के वित्तीय परिव्यय में कटौती करने और 30 अन्य योजनाओं के वित्तीय परिव्यय में वृद्धि करने का अनुमोदन किया। परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुरोध किये जाने पर 13 योजनाओं के संदर्भ में अवधि बढ़ा दी गयी। यदि पहले मंजूर की गयी कतिपय योजनाओं के वित्तीय परिव्यय में पुनर्व्यवस्था, योजनाओं के विनिवर्तन आदि के परिणामस्वरूप किये गये परिशोधन को हिसाब में लिया जाए तो निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की कुल संख्या 30 जून 1972 को 711 थी। उनके अधीन निगम द्वारा दी गयी कुल वित्तीय सहायता और उसके वायदे की राशि क्रमशः 404.75 रुपये करोड़ और 350.79 करोड़ रुपये थी।

227. 1971–72 के दौरान निगम द्वारा किये गये कुल वितरणों की राशि 34.8 करोड़ रुपये थी जिसमें से भूमि बंधक/विकास बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में अभिदान के रूप में प्रदान किये गये पुनर्वित्त की राशि 28.40 करोड़ रुपये थी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को वितरित की गयी राशि क्रमशः 3.26 करोड़ रुपये और 3.32 करोड़ रुपये थी। निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर 30 जून 1972 तक वितरित राशि 124.69 करोड़ रुपये थी।

कृ. पु. निगम के वित्तीय साधनों में वृद्धि

228. निगम ने आलोच्य वर्ष में तीन स्रोतों अर्थात् भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया और खुले बाजार के माध्यम से अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि कर ली। कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 20(i) (ख) और (ग) के अधीन भारत सरकार से ऋणों के रूप में 10.4 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त की। इन ऋणों में गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा कृषि ऋण प्रायोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण के रूप में प्राप्त 3.3 करोड़ रुपये और तराई क्षेत्र प्रायोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त 0.05 करोड़ रुपये तथा सामान्य योजनाओं के लिए प्राप्त 7 करोड़ रुपये शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से रिजर्व बैंक द्वारा 5 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की गयी है। निगम ने 5 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त की है जो दस समान वार्षिक किस्तों में वापस अदा की जानी चाहिये। 5½—कृपुनि बाण्डों की तीसरी श्रेणियों के अन्तर्गत निगम ने 8.25 करोड़ रुपये प्राप्त किये। इस राशि के साथ खुले बाजार से लिये गये कुल ऋणों की राशि 27.71 करोड़ रुपये हो गयी। इस वर्ष के दौरान सात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और छः राज्य सहकारी बैंकों ने क्रमशः 0.12 करोड़ रुपये और 0.38 करोड़ रुपये के मूलधन की चुकौती कर दी। निगम ने 5 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त शेयर की पूंजी भी जारी की जिससे कि उपयुक्त संस्थाओं की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करने के निमित्त वह अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था कर सके। इस प्रकार दूसरी बार जो शेयर जारी किये गये उनके संबंध में मूलधन तथा 4.5 प्रतिशत के न्यूनतम लाभांश की अदायगी के लिए भारत सरकार ने गारंटी दी। इस प्रकार 30 जून 1972 को निगम की प्रदत्त शेयर-पूंजी की राशि 10 करोड़ रुपये थी।

229. आलोच्य वर्ष के दौरान बनायी गयी निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीतियां और क्रिया विधियां उल्लेखनीय हैं :—

(क) लघु सिंचाई योजनाओं की वित्तीय सहायता करने के निमित्त केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये विशेष विकास डिबेंचरों में राज्य सरकारों द्वारा सामान्यतया किये जानेवाले 25 प्रतिशत के अभिदान की मात्रा को घटाकर 1967–68 के सहकारी वर्ष से 10 प्रतिशत बना दिया गया। उसके बाद इस सुविधा की अवधि को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाता रहा है और उक्त सुविधा 30 जून 1972 तक चालू थी। उसकी अवधि को अब 30 जून 1974 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से छोटे कृषक विकास एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित सक्षम योजनाओं के संदर्भ में दिये जानेवाले 100 प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा की अवधि को 30 जून 1972 तक बढ़ाया गया था। इस सुविधा को अब 30 जून 1973 तक बढ़ा दिया गया है। 30 जून 1972 तक लघु सिंचाई के विकास की ऐसी 15 छोटे कृषक विकास एजेंसी योजनाएं—पांच उत्तर प्रदेश में, चार मध्य प्रदेश में, तीन आंध्र प्रदेश में और हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में एक-एक योजना—निगम द्वारा मंजूर की गयी। इन योजनाओं के सन्दर्भ में कृपुनि द्वारा मन्जूर की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि 14.37 करोड़ रुपये थी।

(ग) सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम एजेन्सियों द्वारा बनायी गयी और केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के माध्यम से पेश की गयी योजनाओं के संदर्भ में श्री निगम ने 100 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करना स्वीकार किया है, बशर्ते कि वे योजनाएं आर्थिक दृष्टि से उपादेय और तकनीकी दृष्टि से सक्षम हों। यह सुविधा इस वर्ष प्रारम्भ की गयी और इसकी अवधि को अब 30 जून 1973 तक बढ़ा दिया गया है। आलोच्य वर्ष में पांडिचेरी के संघशासित क्षेत्र में लघु सिंचाई के विकास की एक योजना को निगम ने मंजूरी दी। इस योजना के संदर्भ में कुल वित्तीय सहायता और कृपुनि के वायदे की कुल राशि 0.16 करोड़ रुपये थी।

परामर्श सेवा

230. निगम ने 9 अगस्त 1971 को लखनऊ में एक परामर्श सेवा स्थापित की। जिन मुख्य उद्देश्यों के लिए परामर्श सेवा की स्थापना की गयी है वे निम्न प्रकार हैं :—

(i) वित्तपोषण करनेवाली एजेंसियों को प्रायोजनाओं का स्थान-निर्धारण, उनकी छान-बीन और उनका मूल्यांकन करने की क्रियाविधियों का पालन करने तथा कृषकों का समर्थन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।

(ii) छान-बीन तथा मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में वित्तपोषण करनेवाले बैंकों को राज्य सरकारों की तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना।

(iii) जहां राज्य सरकारों के पास भूमि जल का अन्वेषण करने आदि की अपनी व्यवस्थाएं नहीं हों, वहां तकनीकी अन्वेषण की सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(iv) भूमि विकास बैंकों को उनके संगठन को सुव्यवस्थित करने, कार्यपद्धतियों को सरल बनाने, स्वत्वाधिकार का पता लगाने में होनेवाले विलंब को दूर करने और कर्मचारियों के लिए पर्यवेक्षण संबंधी मानदण्डों का निर्धारण करने तथा ऋण संबंधी कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्यों के लिए कार्य संबंधी मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना।

संक्षेप में परामर्श सेवा प्रायोजनाओं की रूपरेखा बनाने पर ध्यान देगी और पूर्वी राज्यों में अविलंब कृषि विकास की सक्षम योजनाएं बनाने में सहायता देगी।

चाय उद्योग का वित्तपोषण

231. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, चाय के बागानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विद्यमान संस्थानगत व्यवस्थाओं

सारणी 24 :—कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा 1970-71 और 1971-72 (जुलाई जून) के दौरान मंजूर की गयी योजनाओं का उद्देश्यवार विभाजन

(राशि करोड़ रुपयों में)

	जुलाई 1970—जून 1971				जुलाई 1971—जून 1972			
	मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या @	मंजूर की गयी योजनाओं के लिए कुल वित्तीय सहायता	कुल वित्तीय सहायता में कृपुनि के वायदे	वर्ष के दौरान किये गये वितरण	मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या @	मंजूर की गयी योजनाओं के लिए कुल वित्तीय सहायता	कुल वित्तीय सहायता में कृपुनि के वायदे	वर्ष के दौरान किये गये वितरण
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. लघु सिंचाई कार्यों का विकास	55	49.41	44.52	23.06	198	116.30	104.30	26.77
2. भूमि का विकास	9	6.21	4.53	4.37*	13	10.44	7.90	2.34
3. बागान और बागबानी	26	3.16	2.32	1.99	40	11.00	8.36	2.06
4. कृषि का मशीनीकरण	1	0.76	0.57	0.11	2	4.76	3.63	0.36
5. मुर्गी पालन का विकास	2	0.04	0.03	—	4	0.08	0.06	—
6. मछली उद्योग का विकास	2	0.25	0.15	0.37	3	0.81	0.59	0.58
7. डेरी विकास	3	1.42	1.07	—	2	0.66	0.55	0.40
8. गोदामों का निर्माण कार्य	2	0.90	0.73	0.72	5	9.43	9.17	2.47
9. भूमि संरक्षण					1	0.25	0.19	—
10. भेड़ पालन					1	0.51	0.38	—
जोड़	100	62.15	53.92	30.62	269	154.24	135.13	34.98

@इसमें मंजूर की गयी, परन्तु उसी वर्ष वापस ली गयी योजनाएं शामिल नहीं हैं ।

*इसमें भूमि संरक्षण योजनाओं के लिए किये गये वितरण शामिल हैं ।

का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ने सितम्बर 1971 में चाय उद्योग के वित्तपोषण संबंधी एक कार्यकारी दल का गठन किया था जिसके सदस्य चाय उद्योग, रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। कृपुनि के एक वरिष्ठ अधिकारी को इस दल में सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

देशी मत्स्य उद्योग

232. निगम ने वित्तपोषण करनेवाले बैंकों के नाम देशी मत्स्य उद्योग के विकास की योजनाएं बनाने के संबंध में पहले मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये थे। निगम ने पहली बार एक वाणिज्य बैंक के माध्यम से पश्चिम बंगाल में देशी मत्स्य-उद्योग के विकास की योजना को मंजूरी दी।

लघु सिंचाई योजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन

233. यद्यपि वाणिज्य बैंक लघु सिंचाई के लिए कई क्षेत्र विकास योजनाओं का प्रवर्तन करते आ रहे हैं फिर भी यह पाया कि निगम के पास आयी अधिकांश लघु सिंचाई योजनाओं में तकनीकी पहलुओं, विशेष रूप से भूमिगत जल की उपलब्धता के संबंध में अत्यावश्यक विवरणों की कमी थी। ऐसी योजनाओं का शीघ्रता से मूल्यांकन करने की दृष्टि से कृ० पु० नि० ने अप्रैल 1972 में वाणिज्य बैंकों को यह सलाह दी है कि वे प्रस्तावों की तकनीकी संभाव्यता के अध्ययन की व्यवस्थाएं करें और प्रत्येक योजना के संबंध में कृ० पु० नि० की नाम सूची में रहनेवाले किसी एक विशेषज्ञ से प्राप्त तकनीकी संभाव्यता संबंधी रिपोर्ट के साथ योजनाओं को कृ० पु० नि० के पास भेजें । बैंकों को तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विचारणीय विषयों की भी सूचना दी जा चुकी है।

234. आलोच्य वर्ष में कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम में इस दृष्टि से संशोधन किया गया कि (i) 'मत्स्य पालन' की परिभाषा को व्यापक बनाया जा सके जिससे कि उसमें देशी और समुद्री दोनों प्रकार के मछली उद्योगों का विकास कार्य, मछली पकड़ना तथा उससे संबंधित या प्रासंगिक कार्यकलाप सम्मिलित हो सकें; और (ii) कृषि पुनर्वित्त निगम रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया से उसकी राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण ले सकें।

235. जैसा कि पिछली रिपोर्ट में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने सात कृषि ऋण प्रायोजनाओं को मंजूरी दी थी । आलोच्य वर्ष में तीन और प्रायोजनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा अनुमोदित की गयीं । उनसे संबंधित विवरण नीचे दिये गये हैं।

प्रायोजना का नाम	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के माध्यम से दी जानेवाली राशि	
	दस लाख डालर	करोड़ रुपये	दस लाख डालर	करोड़ रुपये
1. मैसूर कृषि ऋण प्रायोजना	40.000	29.11	36.700	26.71
2. महाराष्ट्र कृषि ऋण प्रायोजना	30.000	21.83	25.401	18.49
3. बिहार में बाजारों का विकास	14.000	11.61	12.850	9.35

IV. औद्योगिक वित्त की गतिविधियां

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भाऔवि बैंक के विकास परक कार्य के नये कार्यकलाप

236. विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक-विकास के लिए भाऔवि बैंक प्रायोजना संबंधी परिकल्पनाओं का अन्वेषण करने और उन्हें साकार बनाने से संबंधित कई विकासपरक कार्यों में संलग्न रहा है। इस उद्देश्य के साथ 1970 में भाऔवी बैंक ने, जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, मीयादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाओं तथा रिजर्व बैंक की सहायता से पिछड़े राज्यों में औद्योगिक संभावनाओं का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया था। जून 1971 के अन्त तक 10 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में ऐसे सर्वेक्षण पूरे किये गये; एक राज्य और तीन संघशासित क्षेत्रों के मामले में 1971–72 में सर्वेक्षण पूरे किये गये। शेष एकमात्र पिछड़े राज्य का सर्वेक्षण जहां आरम्भ किया जा रहा है वहां शेष दो संघ शासित क्षेत्रों में शीघ्र ही सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का विचार है। अन्य वित्तीय संस्थाओं और परामर्श सेवाओं की सहायता से भाऔवि बैंक त्रिवेन्द्रम और मैसूर के जिलों और आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र में कुछ जिला सर्वेक्षण भी किये है। भाऔवि बैंक पश्चिम बंगाल के एक विश्वविद्यालय के साथ उस राज्य के सबसे अधिक पिछड़े पुरुलिया जिले के सर्वेक्षण के संबंध में व्यवस्थाएं कर रहा है। कतिपय राज्यों में परिकल्पित कुछ प्रायोजनाओं के संबंध में प्रारम्भिक संभाव्यता संबंधी अध्ययन की व्यवस्था की गयी है और अन्य मामलों में ऐसे अध्ययन प्रारम्भ किये जानेवाले हैं।

237. सक्षम उद्यमकर्ताओं की खोज का कार्य भी व्यापक रूप से किया जा रहा है । भाऔवि बैंक ने कतिपय राज्यों के राज्य औद्योगिक विकास निगमों और कतिपय व्यवसाय केन्द्रों के साथ इस उद्देश्य से संपर्क स्थापित किया है कि संयुक्त क्षेत्रों में परिकल्पित प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रबन्धन का कार्य किया जा सके और ऐसे सक्षम प्रबन्धकों को जो स्वीकृत अवधि के बाद प्रबंध संबंधी कार्यभार ले सकते हैं, कार्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके। औद्योगिक प्रायोजनाओं से संबंधित मामलों पर समन्वित कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य में विभिन्न संस्थाओं के एक दल का गठन करने के निमित्त अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं, अग्रणी बैंकों और राज्य सरकारों के उद्योग विभागों को अपने नेतत्व के अधीन एक मंच पर लाने की दिशा में भाऔवि बैंक एक प्रेरणाप्रद प्रतिनिधि संस्था की भूमिका अदा कर रहा है। सात राज्यों में विभिन्न संस्थाओं के ऐसे दल गठित किये जा चुके हैं।

तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्र

238. केरल में विभिन्न संस्थाओं के उक्त दल ने एक तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्र का प्रवर्तन किया है, उक्त केन्द्र का नाम केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन है और वह प्रायोजना कार्य संबंधी विभिन्न पहलुओं पर उपर्युक्त दल की सहायता करेगा। यह परिकल्पना की गयी है कि कतिपय अन्य पिछड़े राज्यों में भी ऐसे तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्रों का गठन किया जाए। देश में उपलब्ध तकनीकी परामर्श सेवाओं की एक सूची बनायी गयी है। 1971–72 के दौरान भाऔवि बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी निकट संपर्क स्थापित किया।

239. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि देश के कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास लाने की दृष्टि से भाऔवि बैंक ने मई/जुलाई 1970 में रियायती वित्त प्रदान करने की दो योजनाएं प्रारम्भ की—एक योजना विशिष्ट क्षेत्रों में छोटी और मझौली प्रायोजनाओं को राज्य वित्तीय निगमों/बैंकों द्वारा दिये गये 20 लाख रुपयों तक के सभी योग्य ऋणों के संबंध में उन्हें दिये जानेवाले रियायती पुनर्वित्त से संबंधित थी और दूसरी योजना पिछड़े क्षेत्रों में प्रायोजनाय स्थापित करने के लिए रियायती शर्तों पर दी जानेवाली प्रत्यक्ष सहायता से संबंधित थी। 13 दिसम्बर, 1971 से उपर्युक्त रियायतें निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पर्याप्त विस्तार कार्य करनेवाले वर्तमान यूनिटों के लिए भी लागू की गयीं।

240. इस वर्ष की अन्य उल्लेखनीय गतिविधियां इस प्रकार थीं; (i) सहायता संबंधी पुनर्वित्त और पुनर्भाजन योजनाओं को और उदारीकृत किया गया और (ii) हैदराबाद, कानपुर और भूवनेश्वर*, में तीन और शाखा कार्यालय खोले गये; ये कार्यालय राज्य स्तरीय संस्थाओं, सरकारी एजेन्सियों तथा सक्षम उद्यमकर्ताओं के लिए सूचना केन्द्रों और संपर्क माध्यमों के रूप में कार्य करेंगे।

भाऔवि बैंक के कार्यकलाप

241. आलोच्य वर्ष में वित्तीय सहायता की तीनों योजनाओं अर्थात् प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों के लिए दी गयी सहायता को छोड़कर), औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त और मशीनों से संबंधित बिलों के पुनर्भाजन की योजनाओं के अधीन स्वीकृत और वितरित की गयी वित्तीय सहायता की मात्रा 1970–71 से काफ़ी अधिक थी। इन योजनाओं के संदर्भ में स्वीकृत की गयी कुल सहायता की राशि 1970–71 के 97.7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1971-1972 में 141.8 करोड़ रुपये हो गयी और वितरित की गयी राशि 54.2 करोड़ रुपयों से बढ़कर 73.7 करोड़ रुपये हो गयी।

242. ऋणों, हामीदारी और गारंटियों के रूप में (निर्यातों के लिए दी गयी सहायता को छोड़कर) औद्योगिक संस्थाओं के लिए मंजूर की गयी प्रत्यक्ष सहायता की राशि 1970–71 के 47.2 करोड़ रुपयों (31 प्रयोजनाओं के सम्बन्ध में) से बढ़कर 1971–72 में 65.9 करोड़ रुपये (37 प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में) हो गयी । 1971–72 के दौरान वितरित की गयी प्रत्यक्ष सहायता की राशि 1970–71 के 8.6 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 11.4 करोड़ रुपये थी । भारत सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति की जांच पड़ताल सम्बन्धी समिति की सिफ़ारिशों के स्वीकार किये जाने के कारण तथा अखिल भारतीय मीयादी वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं द्वारा दी गयी ऋण सहायता के एक भाग को शेयरों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में भाऔवि बैंक उपयुक्त मामलों में परिवर्तन सम्बन्धी धारा निर्धारित करने लगा है ।

243. औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त की प्रभावी मंजूरियों की राशि जहां 1970–71 में 1406 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 24.5 करोड़ रुपये थी वहां 1971–72 में बढ़कर 2003 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 30.6 करोड़ रुपये हो गयी । पुनर्वित्त की मात्रा में अधिकांश वृद्धि छोटे सड़क परिवहन चालकों-सहित छोटे उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए प्रदान की गयी सहायता के कारण हुई ।

244. आस्थगित अदायगी के आधार पर संभाव्य खरीदार-उपयोगकर्ताओं को देशी मशीनों की बिक्री में सुविधा पहुंचाने के लिए भाऔवि बैंक द्वारा बनायी गयी मशीनों से सम्बन्धित बिलों के पुनर्भाजन की योजना के अधीन पुनर्भाजित बिलों की राशि 1970–71 के 28.5 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1971–72 में 45.3 करोड़ रुपये हो गयी ।

*1जुलाई 1972 को खोला गया।

निर्यात सहायता

245. निर्यात सहायता के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष सहभागिता ऋणों के अधीन दी गयी मंजूरियों की राशि 1970-71 के 11.3 करोड़ रुपयों के स्तर से बढ़कर इस वर्ष 19.3 करोड़ रुपये हो गयी और इसके विपरीत मध्यावधि निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त के अधीन मंजूर की गयी राशि 1970-71 के 13.7 करोड़ रुपयों से कम होकर 3.3 करोड़ रुपये हो गयी । यह कमी निम्नलिखित कारणों से हुई: (क) निधियों के सम्बन्ध में बैंकों की स्थिति संतोषजनक थी, (ख) निर्यातक भाग्रौवि बैंक से बैंकों की सहभागिता के साथ प्रत्यक्ष निर्यात ऋण प्राप्त करते रहे और (ग) भारत-पाकिस्तान युद्ध छिड़ जाने के कारण जहाजों में स्थान पाने में कठिनाई उत्पन्न हुई ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम

246. आर्थिक रूप से कमजोर और बन्द किये गये यूनिटों को पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भाग्रौवि बैंक के प्रयास से अप्रैल 1971 में स्थापित किये गये भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने उल्लेखनीय रूप से अपना कार्य प्रारम्भ किया है । उक्त निगम केवल ऋण देने वाली संस्था के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि वह सहायता प्राप्त यूनिटों की वर्तमान कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के उद्देश्य से पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है । उसके कार्यकलापों में प्रबन्ध-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना तथा अपने कर्मचारियों द्वारा या बाहर से उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध कराकर तकनीकी तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी मार्गदर्शन की व्यवस्था करना शामिल है । अपनी तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान करने के पहले निगम श्रमिक वर्ग तथा प्रबन्ध-तन्त्र के बीच हुए करार के सम्बन्ध में भी अपने आपको आश्वस्त कर लेता है । अपनी स्थापना से लेकर जून 1972 के अन्त तक भाग्रौपु निगम ने 48 यूनिटों को सरल शर्तों पर जो ऋण सहायता तथा गारन्टी सुविधाएं प्रदान की हैं उनकी राशि 7.4 करोड़ रुपये थीं इन 48 यूनिटों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 38,326 थी । उपयोग की गयी सहायता की राशि 30 यूनिटों के संदर्भ में 2.7 करोड़ रुपये थी ।

अन्य वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान

247. आलोच्य वर्ष में भाग्रौवि बैंक ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के सार्वजनिक और विशेष डिबेंचरों में 3.2 करोड़ रुपयों का अभिदान किया; इससे उक्त संस्था को उसकी स्थापना से लेकर जून 1972 के अन्त तक दी गयी कुल सहायता की राशि 18.9 करोड़ रुपये हो गयी । इस वर्ष के दौरान भाग्रौवि बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शेयर पूंजी में भी 41.3 लाख रुपयों का अभिदान किया और अब उक्त संस्था में बैंक की शेयर पूंजी की राशि 4.59 करोड़ रुपये अर्थात् उसकी चुकता शेयर पूंजी का 50 प्रतिशत है । इसके अलावा भाग्रौवि बैंक ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की चुकता पूंजी में 1.37 करोड़ रुपयों का और अभिदान भी किया; इससे भाग्रौवि बैंक के कुल अभिदान की राशि 2.75 करोड़ रुपये हो गयी (इसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किये जाने के पहले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की ओर से भाग्रौवि बैंक द्वारा अभिदान किये गये 25 लाख रुपये भी शामिल हैं; अब संशोधित अधिनियम ऐसे अभिदान करने की अनुमति नहीं देता) । इसके अतिरिक्त भाग्रौवि बैंक ने तीन राज्य वित्तीय निगमों की शेयर पूंजी में 80 लाख रुपयों का अभिदान किया; इससे उसके द्वारा राज्य वित्तीय निगमों के शेयरों और बांडों में किये गये अभिदान की कुल राशि 7.7 करोड़ रुपये हो गयी । भाग्रौवि बैंक ने केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन की 2 लाख रुपयों की चुकता पूंजी में भी 51 प्रतिशत का अभिदान किया है ।

मीयादी ऋण देने वाली अन्य संस्थाएं

भाग्रौऋनिनि और भाग्रौवित्तनि

248. इसके विपरीत मीयादी ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता की मात्रा में आलोच्य वर्ष में कुछ कमी हुई है । प्रत्यक्ष ऋणों (रुपया और विदेशी मुद्रा), हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदानों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (भाग्रौऋनिनि) की कुल मंजूरियों की राशि 1970-71 (अप्रैल-मार्च) के 43.9 करोड़ रुपयों से घटकर 1971-72 में 39.7 करोड़ रुपये हो गयी परन्तु उसके द्वारा वितरित की गयी राशि 28.9 करोड़ रुपयों से बढ़कर 30.3 करोड़ रुपये हो गयी । मंजूरियों में उक्त कमी मुख्यत: विदेशी मुद्रा ऋणों के कारण हुई जिनकी राशि 1970-71 में 29.0 करोड़ रुपये थी और 1971-72 में घटकर 22.5 करोड़ रुपये हो गयी । हामीदारी में भी सीमान्त कमी हुई । विदेशी मुद्रा ऋणों में कमी होने के परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भाग्रौवित्तनि) द्वारा दी गयी मंजूरियों (गारंटियों को छोड़कर) की राशि भी 32.3 करोड़ रुपयों से सीमान्त रूप से कम होकर 32.1 करोड़ रुपये हो गयी परन्तु उसके द्वारा वितरित की गयी राशि 17.4 करोड़ रुपयों से बढ़कर 20.3 करोड़ रुपये हो गयी ।

राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप

249. तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम को मिलाकर 18 राज्य वित्तीय निगमों (रावि निगमों) के कार्यकलापों में पहले की परह वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी । उनके द्वारा मंजूर किये गये कुल ऋण 1970-71 (अप्रैल-मार्च) के 49.0 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1971-72 में 63.4 करोड़ रुपये हो गये (अर्थात् उनमें 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनके द्वारा वितरित की गयी राशि 32.9 करोड़ रुपयों से बढ़कर 38.8 करोड़ रुपये हो गयी (अर्थात् उनमें 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई) । 31 मार्च 1972 को बकाया रहने वाले ऋणों की कुल राशि 154.6 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की राशि से 21 प्रतिशत अधिक थी । वित्तीय सहायता का बहुत बड़ा भाग लघु उद्योगों को प्रदान किया जाता रहा और कुल मंजूरियों और वितरणों में ऐसी सहायता की अंश-राशि क्रमश: 51.2 करोड़ रुपये और 27.1 करोड़ रुपये अर्थात् 80 प्रतिशत और 69.8 प्रतिशत थी ।

250. इस उद्देश्य से कि राज्यों के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने में रावि निगम अधिक महत्वपूर्ण अदा कर सके और राज्यों के सामने रहने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा सके, वित्त मंत्री ने 3 नवम्बर 1971 को नई दिल्ली में निगमों के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों की एक बैठक आयोजित की । उक्त बैठक में की गयी एक सिफ़ारिश के अनुसरण में छोटे और मझौले क्षेत्रों के उद्योगों की सहायता करने में रावि निगमों और वाणिज्य बैंकों की सम्भावनाओं का परीक्षण करने और उनके बीच समन्वयन लाने के लिए आवश्यक क्रियाविधियों का निर्धारण करने के लिए श्री आर० के० तलवार (अध्यक्ष, स्टेट बैंक आफ इंडिया) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया ।

251. रावि निगमों द्वारा वित्तीय साधन जुटाये जाने, उनकी लाभ-दायकता आदि के सम्बन्ध में कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफ़ारिशों के अनुसार राशि निगमों के अधिनियम में कतिपय संशोधन भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तावित किये गये हैं ।

लघु उद्योगों का वित्तपोषण

ऋण गारंटी योजना

252. संशोधित ऋण गारन्टी योजना ने इस वर्ष के दौरान काफी प्रगति की है। सभी प्रमुख वाणिज्य बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और सहकारी बैंकों को मिलाकर अब तक 173 ऋण संस्थाएं संशोधित योजना में शामिल हुई हैं। आलोच्य वर्ष में अनुमोदित ऋण संस्थाओं की सूची में 72 गैर लाइसेंसीकृत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सम्मिलित किया गया जिनमें से 22 बैंक आवश्यक करार निष्पादित करके योजना में शामिल हुए हैं। योजना के क्षेत्र को विस्तारित कर उसे 'कृषि-सेवा यूनिटों' के लिए भी लागू किया गया; 'कृषि-सेवा यूनिटों' से ऐसे यूनिट अभिप्रेत हैं जो खेती के लिए उपयोगी उपकरण किराये पर देते, उनकी सफ़ाई और मरम्मत आदि का काम करते हों, खेती के ऐसे उपकरणों, फालतू पुर्जों तथा मूलभूत वस्तुओं की बिक्री करते हों तथा मिट्टी की परीक्षा जैसी तकनीकी सेवाएं प्रदान करते हों।

253. बकाया गारंटियों की राशि जहां जून 1971 के अन्त में 791.0 करोड़ रुपये थी वहां जून 1972 के अन्त में 913.3 करोड़ रुपये थी। यह योजना जुलाई 1960 में शुरू हुई; तब से लेकर जून 1972 के अन्त तक कुल 43.3 लाख रुपयों की राशि के लिए 281 दावे प्राप्त हुए और उनके संदर्भ में ऋण संस्थाओं को अदायगी कर दी गयी। किन्तु जिस राशि के सम्बन्ध में यह सूचना प्राप्त हुई है कि उनकी अदायगी नहीं हुई है (जिसके फलस्वरूप अन्ततः दावों का निपटान करना पड़ सकता है) वह मई 1972 के अन्त में 4,425 खातों के संदर्भ में 1431.1 लाख रुपये थी जबकि मई 1971 के अन्त में उक्त राशि 2,129 खातों के संदर्भ में 800.8 लाख रुपये थी।

254. गारन्टी संगठन की हैसियत से रिजर्व बैंक योजना उपबन्धों को, जब कभी उचित समझा गया, उदारीकृत करता आ रहा है। तदनुसार हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से प्रभावित पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों को अधिक उदारता के साथ ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऋण संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक की सलाह पर भारत सरकार ने योजना के कतिपय मुख्य उपबन्धों को अस्थायी रूप से उदार बना दिया है। 16 दिसम्बर 1971 से लागू किये गये उक्त उदारीकरण में यह परिकल्पित किया गया कि गारंटी रक्षा को अदत्त राशि या गारंटीकृत राशि में से जो भी कम हो, उसके 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए। इसके साथ ही, गारंटी संगठन से दावों के द्वारा वसूली योग्य राशि की उच्चतम सीमाओं को भी कार्यकारी पूंजीगत अग्रिमों और मीयादी ऋणों के संदर्भ में क्रमशः 7.5 लाख रुपयों और 2.5 लाख रुपयों से बढ़ाकर 10 लाख रुपये और 4 लाख रुपये कर दिया गया। प्रारम्भ में 31 मार्च 1972 तक प्रभावी रहने वाले अस्थायी रूप से उदारीकृत उपबंधों की अवधि को 30 जून 1972 तक बढ़ा दिया गया; फिर भी उदारीकृत उपबंधों के अन्तर्गत आनेवाले तथा रियायतों के अमल में रहते समय या उसके बाद के छः महीनों की अवधि में वापस बुलाये जाने वाले अग्रिम सम्बन्धित उच्चतर गारंटी रक्षा के पात्र होंगे। रिजर्व बैंक की सिफ़ारिश पर भारत सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में उदारीकृत उपबन्धों की अवधि को और छः महीनों अर्थात् 31 दिसम्बर 1972 तक बढ़ा दिया है और पूर्वी क्षेत्र में फ़िलहाल विद्यमान सामान्य स्थितियों को देखते हुए उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया है।

255. यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग संस्थाओं के लिए अग्रिमों की मंजूरी और उनका पर्यवेक्षण किये जाने तथा उनके द्वारा देय राशि की वसूली किये जाने के संदर्भ में ऋण संस्थाएं उचित सावधानी बरतती है, गारंटी संगठन ऋण संस्थाओं की शाखाओं के पास रहने वाले लघु उद्योग यूनिटों के लेखों का नमूना परीक्षण करता है। संशोधित योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान सूचना देने वाली शाखाओं में से 5 प्रतिशत अर्थात् 425 शाखाओं का जहां नमूना परीक्षण किया गया वहां दूसरे वर्ष के दौरान उक्त प्रतिशत को बढ़ाकर 10 प्रतिशत अर्थात् 906 शाखाओं का नमूना परीक्षण करने का निर्धारण किया गया। तीसरे वर्ष के लिए भी 10 प्रतिशत ही बनाये रखने का निश्चय किया गया है। इस प्रकार तीसरे वर्ष (1972-73) के अन्त तक गारन्टी संगठन नमूना परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना देने वाली शाखाओं के एक चौथाई अंश का कार्य पूरा करेगा। ऐसे निरीक्षणों के द्वारा पायी गयी त्रुटियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित ऋण संस्थाओं को सूचित किया जाता है। इसके अलावा, जिन लेखों के मामले में अग्रिमों की वसूली नहीं हो पायी है, गारन्टी संगठन एक कार्य प्रणाली के रूप में उन लेखों की जांच करता है ताकि ऋण संस्थाओं द्वारा उनको अपनी सहायता जारी रखने में अनुभव की जाने वाली समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो सके। जहां यूनिटों में अपनी स्थिति में सुधार लाने की संभावना परिलक्षित होती है, वहां गारन्टी संगठन ऋण देनेवाले बैंकों को इन लेखों की सहायता करने का सुझाव देता है; इन प्रयत्नों से कतिपय मामलों में संतोषजनक परिणाम पाये गये हैं।

लघु उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम

256. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये गये ऋणों में और वृद्धि हुई परन्तु उसकी गति आलोच्य वर्ष में धीमी ही रही। 1971–72 (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्रदान किये गये ऋण (कारीगरों और अन्य योग्यता प्राप्त उद्यमियों को दिये गये मीयादी ऋणों और अग्रिमों को मिलाकर) की कुल राशि में 84 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि बढ़कर 578 करोड़* रुपये हो गयी जबकि इसके मुकाबले में 1970–71 और 1969–70 में उक्त वृद्धि की राशि क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 132 करोड़ रुपये थी। आलोच्य अवधि में वित्त पोषित यूनिटों की संख्या (18,811) में हुई वृद्धि भी पिछले वर्ष की संख्या (21,810) में हुई वृद्धि से कम थी। फिर भी, कुल बैंक ऋण में लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की मात्रा जहां मार्च 1971 के अन्त में 10.6 प्रतिशत थी वहां मार्च 1972 में बढ़कर 11.1 प्रतिशत हो गयी।

257. लघु उद्योगों को हाल ही के वर्षों में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में दो बातें उल्लेखनीय हैं: पहली बात यह है कि मंजूर की गयी ऋण सीमा की औसत राशि जहां मार्च 1970 में प्रति यूनिट 91,700 रुपये थी वहां वह क्रमशः घटकर मार्च 1971 में 83,100 रुपये हो गयी और मार्च 1972 में और घटकर 75,700 रुपये हो गयी जिससे यह संकेत मिलता है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लघुतर यूनिटों के वित्तपोषण की दिशा में धीरे-धीरे अनुकूल प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि असम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में लघु उद्योगों का वित्तपोषण करने के संदर्भ में बैंक अधिकाधिक योगदान करते आ रहे हैं और यह बात इन राज्यों के लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अग्रिमों की बढ़ती हुई मात्रा से स्पष्ट होती है।

258. वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये जाने वाले मीयादी ऋणों के सम्बन्ध में बराबर आंकड़े प्राप्त करने के लिए जून 1971 से व्यवस्थाएं की गयी हैं। उपलब्ध आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र के सावधि निवेशों का वित्तपोषण करने की दिशा में बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मार्च 1972 के अन्त में बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के लिए मंजूर किये गये मीयादी ऋणों की राशि 27,739 यूनिटों के संदर्भ में 132 करोड़ रुपये थी। मार्च 1972

*अनंतिम

के अन्त में बकाया रहने वाली 89 करोड़ रुपयों की राशि इस क्षेत्र के कुल बकाया बैंक ऋण का लगभग 15 प्रतिशत थी ।

259. कारीगरों और योग्यता प्राप्त उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए बहुत पहले 1967 में ही स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों ने विशेष योजनाएं बनायी थीं । इनके अलावा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य 18 बैंक भी अब तक उसी प्रकार की योजनाएं बना चुके हैं । मार्च 1972 के अन्त तक इन वर्गों के ऋणकर्ताओं के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की राशि 8,076 यूनिटों के संबंध में 24 करोड़ रुपये थी और बकाया राशि 15 करोड़ रुपये थी ।

260. स्टेट बैंक आफ इंडिया समुदाय द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये गये ऋणों की राशि मार्च 1972 के अन्त में 231 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें मार्च 1971 के स्तर की अपेक्षा 34 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 45 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । स्टेट बैंक आफ इंडिया समुदाय द्वारा मार्च 1971 और मार्च 1972 के बीच वित्तपोषित यूनिटों की संख्या में 5,788 की वृद्धि हुई जबकि 1971 की तदनुरूपी अवधि में 11,796 की वृद्धि हुई थी । 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में बकाया ऋणों में जहां 1970–71 में 45 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी वहां 1971–72 में 40 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई; किन्तु उक्त अवधि में वित्तपोषित यूनिटों की संख्या (12,719) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में वित्तपोषित यूनिटों की संख्या (9,151) के मुकाबले में अधिक थी ।

261. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा छोटे सड़क और जल परिवहन चालकों को दिये जाने वाले ऋण में हुई वृद्धि की गति भी 1970–71 की अपेक्षा 1971–72 में धीमी थी । इस क्षेत्र को दिये गये ऋण में 1971–72 में 12 करोड़ रुपयों की जो वास्तविक वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष हुई वृद्धि (23 करोड़ रुपये) की लगभग आधी ही थी । मार्च 1972 के अन्त में 33,052 यूनिटों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की राशि 82 करोड़ रुपये थी और 60 करोड़ रुपये बकाया थे ।

262. मार्च 1972 के अन्तिम शुक्रवार को 14 बैंकों ने लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक आस्थान निर्मित करने के निमित्त 5.4 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएं मंजूर की थीं । इस क्षेत्र के बकाया ऋण में अप्रैल 1971–मार्च 1972 के दौरान जो वास्तविक वृद्धि हुई (1.6 करोड़ रुपये) वह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में हुई 2.8 करोड़ रुपयों की वृद्धि के आधे से थोड़ी-सी अधिक थी ।

263. यहां यह बात उल्लेखनीय है कि औद्योगिक आस्थानों के वित्तपोषण के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा 1970 में गठित किये गये कार्यकारी दल की रिपोर्ट के शीघ्र ही प्रकाशित होने की आशा की जाती है ।

बिलों के निपटान से संबंधित समिति

264. वाणिज्य बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं का पुनरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अक्तूबर 1970 में श्री बी० डी० ठक्कर की अध्यक्षता में गठित की गयी समिति ने इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की थी कि बड़े उद्योग लघु उद्यमियों के बिलों का निपटान करने में काफी विलम्ब करते हैं । तदनुसार रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अप्रैल 1971 में बड़े और मझोले उद्योगों को लघु उद्यमों और उद्यमियों द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की पूर्ति से सम्बन्धित बिलों की अदायगी के संदर्भ में उक्त उद्योग जो विलम्ब करते हैं उसके कारण उत्पन्न समस्या का अध्ययन करने और दावों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं करने के निमित्त एक समिति का गठन किया । सरकारी विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लघु उद्यमियों के बिलों की अदायगी में जो विलम्ब करते हैं उससे सम्बन्धित समस्या को भी समिति ने जांच-पड़ताल के अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया । लघु उद्योग के बिलों की अदायगी में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए समिति ने अनेक उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव दिये हैं और सम्बन्धित संस्थाओं और एजेंसियों के पास उन्हें भेजा गया है ताकि वे उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अविलम्ब कदम उठायें जिससे हमारे देश में लघु उद्योग-उद्यमों के विकास की दिशा में रहने वाली कठिनाई को दूर किया जा सके ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

यूनिट योजना 1964

265. 1971–72 (जुलाई–जून) के दौरान बेचे गये यूनिटों का मूल्य 15.1 करोड़ रुपये था जो 1970–71 के 18.0 करोड़ रुपयों के मुकाबले में कम था ।

266. पुनः खरीदे गये यूनिटों के अंकित मूल्य की राशि जहां 1970–71 में 3.2 करोड़ रुपये थी वहां 1971-72 में 2.6 करोड़ रुपये थी । बेचे गये और ट्रस्ट के पास बकाया रहने वाले यूनिटों की कुल राशि 30 जून 1972 को 104.7 करोड़ रुपये थी और ट्रस्ट में पंजीकृत यूनिटधारियों की कुल संख्या 4,34,000 से भी अधिक थी । यूनिटों से प्राप्त होने वाली आय पर यूनिटधारियों को 1970 के वित्त अधिनियम के अधीन कर सम्बन्धी जो विशेष छूट मिल रही थी (जिसका पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था) उसे हटा देने के कारण यूनिटों की बिक्री पर 1970–71 की तरह 1971–72 में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इसके साथ-साथ राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की ब्याज दरों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सावधि जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों को बढ़ा देने के कारण भी निवेश के माध्यम के रूप में यूनिटों की सापेक्ष आकर्षकता में बाधा पड़ी ।

267. ट्रस्ट के निवेशों की कुल राशि 30 जून 1972 को 119.3 करोड़ रुपये थी । इनमें से सामान्य शेयरों, अधिमान्य शेयर और डिबेंचरों की राशियां क्रमशः 44.6 करोड़ रुपये (37.4 प्रतिशत), 13.9 करोड़ रुपये (11.7 प्रतिशत) और 41.9 करोड़ रुपये (35.1 प्रतिशत) थीं । शेष 18.8 करोड़ रुपयों (15.8 प्रतिशत) की राशि सरकारी प्रतिभूतियों और निगम बांडों में किये गये निवेशों, डिबेंचरों और अधिमान्य शेयरों के लिए जमा की गयी अग्रिम राशियों, जिनके लिए हामीदारी की स्वीकृति ट्रस्ट ने दी थी, अग्रिम बोली जमा राशियों और शेयर खरीदने के लिए दिये गये आवेदन शुल्क तथा बोली और अल्पसूचना पर प्रतिदेय जमाराशियों से सम्बन्धित थी ।

यूनिट योजना, 1971

268. यह योजना मुख्यतः यूनिट से सम्बद्ध बीमा योजना की सहायक योजना के रूप में 1 अक्तूबर 1971 को शुरू की गयी । भविष्य में किसी समय ट्रस्ट इस योजना को सभी निवेशकों के लिए लागू कर सकता है परन्तु फ़िलहाल इस योजना के अधीन यूनिटों की बिक्री को यूनिट से सम्बद्ध बीमा योजना में भाग लेने वालों के लिए सीमित रखा गया है । इस योजना का उद्देश्य यह है कि निवेशकों, विशेष रूप से समाज के छोटे और मझोले आय वर्गों के निवेशकों को नियमित रूप से बचत करने और उस बचत का ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश करने की सुविधा प्रदान की जाए और इसके साथ ही उक्त योजना की अवधि के दौरान बीमा-रक्षा की सुविधा भी उन्हें प्राप्त हो । अब तक इस योजना की प्रगति धीमी ही रही है और इस संदर्भ में 30 जून 1972 तक 464 आवेदनपत्रों के संदर्भ में कुल 3.1 लाख रुपयों के यूनिटों की बिक्री हुई है । फिर भी वित्त अधिनियम, 1972 के अधीन यह अतिरिक्त

कर सुविधा दी गयी है कि योजना के अधीन किये जाने वाले अभिदानों की तरह माना जाएगा इससे यह सम्भव है कि योजना की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ जाए ।

V. विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां

269. जैसा कि भाग I में उल्लेख किया जाचुका है आलोच्य वर्ष में आधिकारिक रूप से रखे गये डालरों को परिवर्तित न करने के अगस्त 1971 में अमेरिका द्वारा किये गये निर्णय और जून 1972 में पौंड चालू करने के संबंध में ब्रिटेन द्वारा की गयी घोषणा के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय चल मुद्रा बाजार में अनिश्चितताएं पायी गयीं। रुपये की विनिमय दर में इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा।

विनिमय दरें –

रिजर्व बैंक द्वारा स्टर्लिंग का विक्रय और क्रय

270. अमेरिका सरकार ने 15 अगस्त 1971 को घोषणा की कि आधिकारिक रूप से रखे गये डालरों को सोने या अन्य प्रारक्षित आस्तियों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और उसके बाद ब्रिटेन के प्राधिकारियों ने घोषणा की कि 23 अगस्त 1971 से डालर-स्टर्लिंग दर में बाजार की परिस्थितियों के अनुसार घट-बढ़ होने दी जाएगी हालांकि पौंड स्टर्लिंग की सममूल्यता बिना किसी परिवर्तन के अमेरिकी डालर 2.40=पौंड 1 की दर पर ही रहेगी। किन्तु डालर स्टर्लिंग दर को डालर 2.38=पौंड 1 की दर से कम होने नहीं दिया जाएगा; किन्तु जब उक्त दर बढ़ने लगे तो उसे बिना किसी उच्चतम सीमा के प्रति पौंड डालर 2.42 की दर पर चालू होने दिया जायेगा । इन गतिविधियों के बाद भारत सरकार ने यह घोषणा की कि भारतीय रुपये की स्वर्ण मूल्यता (और इस कारण अमेरिकी डालर-सममूल्यता) में कोई परिवर्तन नहीं होगा और रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया तत्काल दाति के लिए ऐसी दरों पर पौंड स्टर्लिंग का क्रय और विक्रय करेगा जो जून 1966 में निर्धारित भारतीय रुपये के सममूल्य (जो अमेरिकी डालर 13.3333=रु० 100 था) और लंदन बाजार में पिछले काम के दिन में स्टर्लिंग के संदर्भ में विद्यमान डालरों की (चल) विनिमय दरों के आधार पर तैयार क्रय दर और हाजिर विक्रय दर के मामले में क्रमशः 0.0175 पौंड का मार्जिन जोड़कर और घट कर निर्धारित की जाएँगी दर निर्धारित करने का यह आधार 24 अगस्त 1971 से अमल में आया। बाद में उपर्युक्त मार्जिन को 8 सितंबर 1971 से घटाकर 0.0125 पौंड कर दिया गया ।

271. रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ने 23 अगस्त 1971 से अस्थायी रूप से स्टर्लिंग के वायदा क्रय को रोक दिया था; किन्तु उसे 28 अगस्त 1971 से रु० 100 के लिए पौंड 5.5556 की दर पर छः महीनों तक दाति करने के लिए पुनः चालू किया गया ।

272. 18 और 19 दिसंबर 1971 को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चलमुद्राओं की सममूल्यता को समायोजित किया गया और सब अमेरिकी डालर के संदर्भ में स्टर्लिंग की नयी दर में पहले की अपेक्षा 8.57 प्रतिशत वृद्धि की गयी (सोने का मूल्य प्रति शुद्ध औंस डालर 35.00 से बढ़कर डालर 38.00 हो जाने से अमेरिकी डालर का अवमूल्यन हो गया था और पौंड स्टर्लिंग की स्वर्ण सममूल्यता अपरिवर्तित ही रही); अतः भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि रुपये को डालर से अलग कर दिया जाए और स्टर्लिंग के संदर्भ में समायोजन के तत्काल पूर्व अर्थात् 17 दिसंबर 1971 को विद्यमान डालरों के अंतिम लंदन भाव पर आधारित स्टर्लिंग की क्रय और विक्रय दरों के औसत के बराबर की एक केन्द्रीय दर स्वीकार की जाए । यह केन्द्रीय दर रु० 100=पौंड 5.2721 अथवा पौंड 1=रु. 18.9677 थी । तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह सूचना दी गयी कि भारत स्टर्लिंग की क्रय-विक्रय दरों की घटबढ़ के लिए केन्द्रीय दर के उक्त दोनों पक्षों में 2.25 प्रतिशत की व्यापक सीमा का लाभ उठायगा । यह प्रणाली 20 दिसंबर 1971 से अमल में लायी गयी । रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचना दी कि रु० 100=पौंड 5.2721 की केन्द्रीय दर पर आधारित उसकी हाजिर क्रय-विक्रय दर निम्न प्रकार होंगी :

क्रय — पौंड 5.2851=रु० 100
विक्रय —पौंड 5.2592 =रु० 100

273. रिजर्व बैंक द्वारा 20 दिसंबर 1971 से स्टर्लिंग का जो वायदा क्रय रोक दिया था उसे पुनः 28 दिसंबर 1971 से चालू कर दिया गया । बैंक ने 9 महीनों तक के लिए वायदा रक्षा सुविधाएँ प्रदान की और उसकी दरें निम्नलिखित आधार पर निर्धारित की जाएँगी ।

दाति की अवधि	विनिमय दर
3 महीनों तक	रिजर्व आफ़ इंडिया की वर्तमान हाजिर क्रय दर और प्रति रु० 100 पौंड 0.0125 का मार्जिन
9 महीनों तक	रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया की वर्तमान हाजिर क्रय दर और प्रति रु० 100 पौंड 0.0252 का मार्जिन

तीन महीनों की प्रारंभिक दाति अवधि के ठेकों को और तीन या छः महीनों तक प्रत्येक तिमाही के लिए प्रति रु० 100 पौंड 0.0125 की प्रभार दर पर बढ़ाने की अनुमति दी गयी। इसी आधार पर उक्त दोनों मामलों में 15 मार्च 1972 से प्रभारों की अदायगी किये जाने पर मूल ठेके की तारीख से 12 महीनों की कुल अवधि तक और बढ़ाने की अनुमति दी गयी । इस प्रकार वायदा रक्षा की सुविधा 12 महीनों तक उपलब्ध करायी गयी।

274. 23 जून 1972 को ब्रिटेन के प्राधिकारियों द्वारा स्टर्लिंग के चालू किये जाने का निर्णय करने के बाद और अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों में पायी गयी अनिश्चित स्थितियों को देखते हुए स्टर्लिंग के हाजिर क्रय और विक्रय की रिजर्व एक की दरें 26 जून 1972 से क्रमशः प्रति रु० 100 पौंड 5.2910 और प्रति रु० 100 पौंड 5.2632 निर्धारित की गयी। रिजर्व बैंक ने स्टर्लिंग के वायदा क्रय को रोक दिया ।

275. स्थिति का पुनिरक्षण करने के बाद इन दरों को 4 जुलाई 1972 से निम्न प्रकार परिशोधित किया गया।

क्रय—प्रति	रु० 100	पौंड 5.3333
विक्रय—प्रति	रु० 100	पौंड 5.3050

बैंक ने 5 जुलाई 1972 को 6 महीनों तक निम्नलिखित दरों पर स्टर्लिंग के वायदा क्रय को पुनः चालू किया :

अवधि	विनिमय दर
3 महीनों तक	प्रति रु० 100 पौंड 5.3458
6 महीनों तक	प्रति रु० 100 पौंड 5.3583

तीन महीनों की प्रारंभिक दाति अवधि के लिए किये गये वायदा ठेकों को और तीन महीनों की अवधि के लिए प्रति रु० 100 पौं 0.0125 की प्रभार दर पर बढ़ाने की अनुमति दी गयी ;

276. विदेशी मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में 1971-72 के दौरान मुख्यतः विनिमय दर और मूल्य परिवर्तनों के अनुसार यात्रा, अध्ययन आदि से संबंधित नियमों में परिशोधन किया गया।

व्यवसाय आदि के उद्देश्यों के लिए विदेशों में यात्रा

277. व्यवसाय के उद्देश्य से विदेशों में यात्रा करने के लिए उच्चतर मान पर विदेशी मुद्रा प्रदान करने के निमित्त कतिपय व्यवसायियों को सर्वोच्च श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की प्रणाली को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। आगे से व्यवसायी दो श्रेणियों के अंतर्गत अर्थात् (i) वरिष्ट व्यवसायी और (ii) चल विक्रेता के रूप में वर्गीकृत किये जायेंगे ।

उच्चतर अध्ययन के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा

278. ब्रिटेन में निर्वाह-व्यय के बढ़ जाने और यूरोपीय चल मुद्राओं की विनियम दरों में परिवर्तन हो जाने के कारण भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि विद्यार्थियों/प्रयणत्क्षार्थियो को उनके अपने निर्वाह के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा के मान को सामान्य रूप से अमेरिका और कनाडा को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए वार्षिक 600 पौंड से बढ़ाकर 700 पौंड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के मामलों में वार्षिक 750 पौंड कर दिया जाए। इस मान में शिक्षण शुल्क शामिल नहीं है। शिक्षण शुल्क के संबंध में विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा प्रमाणित वास्तविक राशि अब तक की तरह आगे भी प्रदान की जाएगी।

हज तीर्थ यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा का कोटा

279. 18–19 दिसंबर 1971 को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चलमुद्राओं की सममूल्यताओं का समयोजन किये जाने के संदर्भ में सउदी अरब के रियाल का पुनर्मूल्यन हो जाने के परिणामस्वरूप (रियाल की स्वर्ण सममूल्यता अमेरिकी डालरों के संदर्भ में 8.57 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से अपरिवर्तित रही) हज तीर्थयात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों को दिये जाने वाले विदेशी मुद्रा कोटा को प्रत्येक वयस्क व्यक्ति (16 वर्ष की आयु से ऊपर के) मामले में 1,575 रुपयों से बढ़ाकर 1,670 रुपये और 14 और 16 वर्ष की आयु के बीच के प्रत्येक बच्चे के मामले में 790 रुपयों से बढ़ाकर 835 रुपये कर दिया गया है ताकि तीर्थयात्रीयों को पहले की तरह विदेशी मुद्रा की वही राशि मिल सके।

बकाया विदेशी मुद्राओं का प्रत्यार्पण :

विशेष रियायत

280. बकाया विदेशी मुद्राओं के प्रत्यर्पण से संबंधित विनियमों में इस उद्देश्य से कुछ रियायतें की गयीं कि विदेशों में रहने वाले योग्यता प्राप्त भारतीय नागरिकों को उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने अथवा लघु उद्योग यूनिटों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से भारत में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ऐसे व्यक्तियों को आवेदन किये जाने पर भारत में आने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी बकाया विदेशी मुद्राओं को प्रत्यर्पित करने के बजाय भारत में लौटाने की तारीख से तीन साल की अवधि तक अपने पास ही रखने की अनुमति दी जाएगी। इस सुविधा के अधीन जिन व्यक्तियों के पास ऐसी बकाया विदेशी मुद्राएं हों, उन्हें मणीनों, कच्ची सामग्री और फालतू पुर्जों के आयातों के लिए राशि अदा करने के निमित्त उन मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। उक्त आयातों के लिए उदारतापूर्वक आयात लाइसेंस दिये जाएंगें । उन बकाया विदेशी मुद्राओं को प्रत्यर्पित भी किया जा सकता है किन्तु तीन साल पहले या रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के भीतर उन्हें विदेशों को पुनः अंतरित करने का अधिकार भी रहेगा।

बंगला देश के संदर्भ में विदेशी मुद्रा नियंत्रण

यात्रा

281. जहाजरानी/हवाई कंपनियों और यात्रा एजेंटों को 15 मई 1972 से यह अनुमति दी गयी है कि वे भारत के निवासियों के लिए भारतीय रुपये में किराये की अदायगी किये जाने पर बंगला देश की यात्रा के लिए टिकट बुक करें ; इसके लिए केवल यही शर्त है कि 'पी' फ़ार्म भरा जाए । रिजर्व बैंक से 'पी' फार्म पर कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और किसी यात्री द्वारा बंगला देश को की जानेवाली यात्राओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बंगला देश की यात्राओं को विदेश यात्रा योजना, 1970 के उद्देश्यों के लिए विदेशी यात्राओं के रूप में भी नहीं माना जाएगा।

सारणी 25 :—जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिटों और अनुमोदित 'पी' फ़ार्मों से संबंधित आंकड़े

अ. जुलाई 1971—जून 1972 की अवधि के दौरान विदेशों में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिट

देश	तकनीकी पाठ्यक्रम		गैर तकनीकी पाठ्यक्रम	
	जारी किये गये परमिटों की संख्या	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)	जारी किये गये परमिटों की संख्या	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)
ब्रिटेन और यूरोप	508	37,88	551	16,96
अमेरिका और कनाडा	1132	2,60,02	603	1,03,81
अन्य देश	201	13,54	78	2,19

आ. जुलाई 1971—जून 1972 की अवधि के दौरान अध्ययन/प्रशिक्षण को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए की जानेवाली विदेश यात्राओं के लिए जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिट

	जारी किये गये परमिटों की संख्या	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)
1. कारोबार	10716	6,62,86
2. डाक्टरी चिकित्सा	576	57,95
3. अध्ययन दौरे	1082	46,04
4. सम्मेलन में भाग लेना	1413	28,34
5. विविध	5678	1,33,33

ई. जुलाई 1971—जून 1972 की अवधि के दौरान अनुमोदित 'पी' फ़ार्म-आवेदन पत्रों की संख्या

उद्देश्य	अनुमोदित 'पी' फ़ार्मों की संख्या
1. परिवार के प्रमुख से मिलना	11778
2. रिश्तेदारों से मिलना	9288
3. निर्यात वृद्धि	256
4. विदेशों में नौकरी	4253
5. स्थायी निवास के लिए उत्प्रवास	6083
6. विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी	3130
7. विविध	23190

282. भारतीय नागरिकों और भारत में स्थायी रूप से निवास करने वाले भारतेतर नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को व्यवसाय (सम्मेलनों में भाग लेना भी इसमें शामिल है) अध्ययन, प्रशिक्षण, डाक्टरी चिकित्सा, आदि के लिए की जाने वाली बंगला देश की यात्रा से संबंधित खर्चों के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान की जाएगी। विदेशी मुद्रा केवल भारतीय रुपया यात्री चैकों के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। उन पर स्पष्ट रूप से 'केवल बंगला देश में बंगला देश टके में भुनाया जा सकता है' अंकित रहेगा। बंगला देश बैंक ने बंगला देश के निवासियों को उनके द्वारा की जाने वाली भारत-यात्राओं के लिए इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना स्वीकार किया है।

283. निजी तौर पर बंगलादेश की यात्रा करने वाले भारत के निवासियों को अपने साथ प्रत्येक यात्रा के लिए भारतीय मुद्रा नोटों में (रु० 100 या अधिक मूल्य वर्ग के नोटों को छोड़कर) रु० 500 प्रति व्यक्ति ले जाने की अनुमति दी गयी है। बंगला देश के प्राधिकारियों ने भी बंगलादेश के निवासियों के लिए उनके द्वारा की जाने वाली भारत यात्राओं के संदर्भ में उपर्युक्त सीमाओं तक टका नोट ले जाने की अनुमति दी है।

दूसरे लेन-देन

284. प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि सीमित रुपया अदायगी व्यापार व्यवस्थाओं के अधीन आनेवाले लेन-देनों को छोड़कर बंगलादेश और भारत के बीच होनेवाले सभी लेन-देनों को स्टर्लिंग या स्टर्लिंग क्षेत्र की किसी मुद्रा (पाकिस्तानी रुपयों को छोड़कर) या भारतीय रुपयों या बंगला देश टके में निपटाने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे लेन-देनों पर सामान्य रूप से भारत के बाहर अन्य देशों के साथ किये जाने वाले लेन-देनों पर लागू होने वाले विनिमय लागू होंगे। बंगला देश ने भी भारत के साथ किये जानेवाले अनुमोदित लेन-देनों के निपटान के लिए इसी प्रकार स्टर्लिंग प्रदान करना स्वीकार किया है।

VI. रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित सर्वेक्षण और विचार गोष्ठियां

सर्वेक्षण

285. भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और राज्य सरकारों के सांख्यिकीय विभागों के सहयोग से रिजर्व बैंक दशवर्षीय अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, 1971-72 का जो कार्य कर रहा था उसमें आलोच्य वर्ष में प्रगति हुई। सर्वेक्षण के निमित्त मांग पक्ष की छान-बीन का क्षेत्रगत कार्य राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा केन्द्रीय नमूने के संदर्भ में किया जा रहा है तथा राज्य और रिजर्व बैंक के तदनुरूपी नमूनों के संदर्भ में यह कार्य राज्य सरकारों के सांख्यिकीय विभागों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय, राज्यों और रिजर्व बैंक के नमूनों के अंतर्गत आने वाले 1,44,000 ग्रामीण परिवारों और 53,000 शहरी परिवारों के बीच सर्वेक्षण के संदर्भ में मांग-पक्ष की छान-बीन का कार्य तीन अनुसूचियों और एक अनुपूरक अनुसूची के प्रचार द्वारा किया जाता है। मांग पक्ष की छानबीन के लिए चुने गये 12,000 गांवों में, एक अतिरिक्त ग्राम अनुसूची का भी प्रचार किया जायेगा। विभिन्न राज्यों के प्रमुख केन्द्रों में रिजर्व बैंक ने सांख्यिकीय कक्षों की स्थापना की है ताकि क्षेत्र विशेष से भरी गयी अनुसूचियां बराबर मिलती रहें और अनुसूचियों का संवीक्षण और संकलन किया जा सके।

286. बैंक के कृषि ऋण विभाग के अनुरोध पर आर्थिक विभाग के ग्रामीण सर्वेक्षण प्रभाग ने केवल राज्य में फ़सलवार वित्तीय मानदंडों का क्षेत्रगत अध्ययन कार्य प्रारंभ किया; इस अध्ययन का उद्देश्य ऐसी आवश्यक सामग्री जुटाना था जो धान और अन्य प्रमुख अनाजों के लिए वित्त प्रदान करने के संबंध में यथार्थपरक मानदंड निर्धारित करने में केरल के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम आये। उक्त प्रभाग ने महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड तालुके में सम्मिलित रूप से स्वाधिकृते निजी कुओं और सरकार द्वारा बनाये गये सामुदायिक कुओं के संचालन के संबंध में भी क्षेत्रगत अध्ययन किया। लघु कृषक विकास एजेंसीयों, भूमि विकास बैंकों और अन्य उपयुक्त ऋण संस्थाओं के लिए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के उद्देश्य से यह अध्ययन कार्य किया गया ताकि वे कृषकों विशेषकर लघु कृषकों की सुविधा के लिए देश में लघु सिंचाई योजनाओं को विस्तारित करने के प्रयास में दूसरे क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के संयुक्त कार्यों का वित्तपोषण कर सकें। सहकारी बैंकों के अग्रिमों और जमाराशियों के संबंध में इस प्रभाग द्वारा नियमित रूप से किये जाने वाले सर्वेक्षण में भी आलोच्य वर्ष में प्रगति हुई।

287. आलोच्य अवधि के दौरान आर्थिक विभाग के ग्रामीण अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा निम्नलिखित तीन अध्ययन कार्य किये गये, (i) एक चल बैंक के परिचालन का क्षेत्रगत अध्ययन, (ii) बैंक के कृषि ऋण विभाग के सहयोग से केरल में नारियल उत्पादन के वित्तपोषण के लिए नकदी ऋण व्यवस्था का अध्ययन और (iii) विदर्भ प्रदेश के सूती बाजारों का स्थानिक अध्ययन। इस प्रभाग के अधिकारियों ने हरियाणा, मैसूर और मध्य प्रदेश के वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए किये जाने वाले वित्तपोषण की योजनाओं के परिचालन से संबंधित अंतर्विभागीय अध्ययन में भाग लिया।

288. आर्थिक विभाग के अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग ने इस वर्ष जुलाई-सितम्बर 1970 की तिमाही की अवर्गीकृत प्राप्तियों के सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दे दिया (जैसे 10,000 रुपयों से कम या उसके बराबर की राशि की ऐसी प्राप्तियां जिनके उद्देश्यवार विवरणों की सूचना प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग को

दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है) । उक्त सर्वेक्षण का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था। इन परिणामों का विश्लेषण करने वाली एक विस्तृत टिप्पणी रिजर्व बैंक बुलेटिन के नवंबर 1971 के अंक में प्रकाशित की गयी। इस सर्वेक्षण द्वारा जिस उद्देश्यवार प्रणाली का पता लगा वह पिछले सर्वेक्षण द्वारा पता लगायी गयी प्रणाली के लगभग समान ही थी। इसलिए भुगतान शेष के आंकड़ों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए वितरित की जाने वाली अवगीकृत प्राप्तियों के आधार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गयी। अप्रैल-जून की तिमाही के 1971 के सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1972 का सर्वेक्षण फ़रवरी—अप्रैल की तिमाही से सम्बन्धित है और उक्त सर्वेक्षण कार्य जारी है। यह प्रभाग वार्षिक आधार पर भारतीय और विदेशी जहाजरानी और हवाई कंपनियों से संबंधित भाड़े और यात्रा शुल्क की अदायगियों और प्राप्तियों का सर्वेक्षण कार्य करता रहा।

289. अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग विदेशी कंपनियों और भारतीय मिश्रित पूंजी कंपनियों की शाखाओं से विदेशी निवेश संबंधी तिमाही सर्वेक्षण रिपोर्टें मंगाता रहा। 1968-69 की भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का प्रमुख रूप से इन रिपोर्टों पर आधारित मूल्यांकन अभी जारी है।

290. इस वर्ष के दौरान आर्थिक विभाग के व्यापार प्रभाग ने दो सर्वेक्षण कार्य शुरू किये; एक भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग का सर्वेक्षण और दूसरा विदेशों में स्थित भारतीय संयुक्त उपक्रमों का सर्वेक्षण था। उक्त दूसरा सर्वेक्षण बैंक द्वारा पहली बार किया जा रहा है और भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग का सर्वेक्षण 1965 में शुरू किये गये इसी प्रकार के सर्वेक्षण का अनुवर्ती कार्य है; 1965 के सर्वेक्षण के परिणाम 1968 में प्रकाशित किये गये थे। जो सर्वेक्षण अभी जारी हैं वे 1964-65 से 1969-70 तक की अवधि के हैं।

विचार गोष्ठियां

291. अप्रैल 1972 में सही आंकड़ों का संकलन करने, अग्रतावाले क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाने के लिए आवश्यक ऋण आयोजनाएं और नीति के क्रियान्वयन में भाग लेने, जमा राशि जुटाने और अग्रणी बैंक क्षेत्रों की योजनाओं का निवेश पूर्व और निवेशोत्तर मूल्यांकन करने के संदर्भ में बैंकों में काम करने वाले अर्थशास्त्रियों की भूमिका पर विचार-विमर्श करने के लिए रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अर्थशास्त्रियों की एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। उसी महीने में, कृषि क्षेत्र को दिये जानेवाले वित्त की मात्रा को बढ़ाने और कृषि विकास के लिए दिये गये ऋणों को वसूल करने के संदर्भ में बैंकों के सामने आनेवाली समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए बैंक ने बड़े वाणिज्य बैंकों के कृषि वित्त विभागों के अध्यक्षों की एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया।

vii. शिक्षा और प्रशिक्षण

292. रिजर्व बैंक ने न केवल अपने, बल्कि वाणिज्य बैंकों, सहकारी संस्थाओं और संस्थागत ऋण की विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी विभागों के भी सभी स्तरों के अर्थात् अवर, पर्यवेक्षी और वरिष्ठ कार्यपालक स्तरों के कर्मचारियों को सामान्य और गहन प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता का अनुभव करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है। ये संस्थाएं कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया करती हैं। आलोच्य वर्ष में इस संबंध में किये जाने वाले कार्यों का काफी विस्तार हुआ।

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान

293. राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने अपने दीर्घकालीन उद्देश्यों के अनुसार जुलाई 1971-जून 1972 के दौरान अपनी क्षमता को और बढ़ाया जिससे कि बैंकिंग उद्योग को अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उनको सक्षम बनाने में सहायता दी जा सके, कई प्रकार की परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकें और व्यावसायिक ज्ञान और जानकारी का प्रचार किया जा सके। इस अवधि के दौरान कुल उन्नीस कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें भारत के बैंकों और विदेशों के चार सौ उन्नीस अधिकारियों ने भाग लिया। इन पाठ्यक्रमों में उच्च प्रबन्ध प्रशिक्षण, वरिष्ठ कार्यपालक पाठ्यक्रम, विकास कार्यक्रम का निष्पादन, शाखा प्रबन्ध कार्यक्रम, ऋण प्रबन्ध, प्रशिक्षकों का कार्य शिविर, श्रम शक्ति विकास पर प्रथम विचार गोष्ठी, कार्य आयोजना शिविर और निर्यात वित्त प्रशिक्षण सम्मिलित थे।

294. संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में संस्थान ने विकास बैंक व्यवसाय और प्रादेशिक आर्थिक क्षमता, कृषि ऋण प्रदान किये जाने के लिए साख संबंधी जोखिम के विश्लेषण, ग्रामीण बैंक व्यवसाय के लिए कारोबार के आयोजन और कार्यान्वयन, कृषि के वित्तपोषण, नियोजन को अधिकतम बनाने के लिए निवेश और ऋण के आयोजन से संबंधित विभिन्न अध्ययन कार्यों का प्रवर्तन किया और उक्त कार्य या तो समाप्त हो गये या संपूर्ण गति के साथ चल रहे थे। स्थूल रूप से अनुसंधान कार्यक्रम या तो नीति निर्धारण या संस्थान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और बैंकिंग उद्योग द्वारा आपेक्षित परामर्श सेवा पर केन्द्र भूत था।

295. 1971 के दौरान शुरू की गयी परामर्श प्रायोजनाएं निम्नलिखित विषयों से संबंधित थीं: (क) संगठन आयोजन, (ख) निर्णायक तंत्र, (ग) प्रबन्ध विकास और (घ) भर्ती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के त्वरित विस्तार के लिए एक पुनर्गठन प्रायोजना का कार्य शुरू किया गया और उसकी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। संस्थान ने बैंक आफ़ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय बैंक संगठन को अपने यहां विकसित की गयी नयी परीक्षण प्रतिक्रियाओं का प्रयोग कर क्लर्कों और अधिकारों का चयन करने के संदर्भ में परामर्श सहायता प्रदान की। क्लर्क के पदों के लिए कुल 8,947 उम्मीदवारों और अधिकारी वर्ग के लिए कुल 5,755 उम्मीदवारो का परीक्षण किया गया।

296. राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने 'प्रज्ञान' शीर्षक की अपनी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उसका पहला अंक जनवरी 1972 में प्रकाशित किया गया। संस्थान द्वारा तीन अन्य प्रकाशन अर्थात् पाठ्यक्रमों की निदेशिका —1971-72 संस्करण, अंतर्देशीय प्रेषणों की योजनाबद्ध पाठ्यक्रपुस्तक और राष्ट्रिय बैंक प्रबन्ध संस्थान की विवरणिका— प्रस्तुत किये गये।

बैंकर प्रशिक्षण कालेज, बम्बई

297. आलोच्य अवधि के दौरान, इस कालेज ने ऋण मूल्यांकन पर पांच पाठ्यक्रम और मियादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं और बैंकों के विधि अधिकारियों और वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षी निरीक्षण कर्मचारी वर्ग के लिए दो-दो पाठ्यक्रम चलाये। कालेज ने पहली बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के लिए ऋण मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट बैंक पाठ्यक्रम चलाया। कालेज में अवर बैंकिंग और विदेशी मुद्रा पर दो दो पाठ्यक्रमों, मध्यवर्ती बैंकिंग कर्मचारी वर्ग और संगठन तथा संगठन और प्रणाली पर एक एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, इस अवधि में कालेज

में दो नये पाठ्यक्रम अर्थात् मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं के अधिकारियों और वाणिज्य बैंकों के ऐसे अधिकारियों के लिए जो मीयादी ऋण प्रदान करने से संबंधित कार्य करते हैं, प्रायोजना मूल्यांकन (वित्तीय) और बाजार विश्लेषण पर एक एक पाठ्यक्रम चलाया गया। प्रायोजना मूल्यांकन (वित्तीय) पाठ्यक्रम को अब साख मूल्यांकन पाठ्यक्रम में समाविष्ट कर दिया गया है।

298. यह कालेज अपने अधिकारियों के लिए भी पाठ्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। इस अवधि में ग्रेड I स्टाफ आफिसरों के लिए दो केन्द्रीय बैंक संघटन पाठ्यक्रम और बैंक के बैंक परिचालन तथा विकास विभाग और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारियों के लिए एक साख मूल्यांकन पाठ्यक्रम चलाये गये। इनके अलावा दो नये पाठ्यक्रम अर्थात् एक पाठ्यक्रम बैंक की अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्यों के लिए और ग्रेड III वरिष्ठ स्टाफआफ़िसरों के लिए केन्द्रीय बैंक संघ टन संबंधी एक उच्च पाठ्यक्रम भी चलाये गये। वाणिज्य बैंकों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्द्रीय बैंक संकटन संबंधी उच्च पाठ्यक्रम में भी भाग लिया।

299 इस अवधि में इस कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों और बैंक के अपने अधिकारियों की कुल संख्या 685 थी। 1954 में जब इस कालेज की स्थापना की गयी तब से लेकर अब तक कुल 4525 अधिकारियों ने कालेज द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्क्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

300. कालेज शीघ्र ही वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 'प्रशासन' और परिचालन अधिकारियों की सुविधा के लिए बैंक संघटन में औद्योगिक संबन्ध पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने और बैंक सांख्यिकी तथा निर्यात वित्त पर अल्पाकालीन पाठ्यक्रम और लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन करने का विचार कर रहा है। कालेज वाणिज्य बैंकों के शाखा प्रबन्धकों और लेखापालों के लिए भारतीय प्रबन्ध, संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से शाखा प्रबन्ध संबन्धी एक द्विस्तरीय पाठ्यक्रम का आयोजन करने का भी विचार कर रहा है। कालेज वाणिज्य बैंकों के मध्यस्तरीय कार्यपालक अधिकारियों के लिए भी एक समेकित पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहा है :

301. अब कालेज आर्थिक विकास संस्थान वाशिंगटन के सहयोग से एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों के विकास बैंकों के कार्यपालक और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विकास बैंक संघटन पर एक द्विस्तरीय अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रीय पाठ्क्रम की योजना तैयार कर रहा है। 1973 के आरम्भ में उक्त पाठ्यक्रम के शुरू होने की संभावना है।

सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज, पूना

302. आलोच्य अवधि में राज्य। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारी वर्ग के लिए दो पाठ्क्रम और औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले शहरी बैंकों और केन्द्रीय बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारी वर्ग के लिए एक एक पाठ्यक्रम चलाये गये। राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखा एजेन्टों के लिए तीन पाठ्यक्रम, भूमि विकास बैंकों के लिए पांच पाठ्क्रम (तीन सामान्य पाठ्यक्रम और प्रायोजना आयोजन और मूल्यांकन पर दो पाठ्क्रम) और तीन कृषि वित्त पाठ्यक्रम अर्थात् वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ और मध्य स्तरीय कर्मचारियों और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए एक एक पाठ्यक्रम भी इस अवधि में चलाये गये। इनके अतिरिक्त कालेज में राज्य। केन्द्रीय और शहरी सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारी वर्ग के लिए एक एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और तमिलनाडु और मैसूर राज्यों के भूमि विकास बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारी वर्ग के लिए एक एक विशेष पाठ्क्रम भी चलाये गये। इस वर्ष कालेज में छोटे कृषक विकास एजेन्सियों। सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं के प्रयोजना अधिकारियों और सहायक प्रायोजन अधिकारियों के लिए एक विशेष पाठ्क्रम शुरू किया गया और ऐसे तीन पाठ्यक्रम चलाये गये। कालेज ने अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी शुरू किये। इस अवधि में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पर दो ऐसे पाठ्यक्रम और बुनकर समितियों के वित्तपोषण पर एक पाठ्यक्रम राज्य। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारी वर्ग के लिए आयोजित किये गये।

303. इस अवधि में कालेज में सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों और वाणिज्य बैंकों के जिन अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनकी संख्या 723 थी। सितम्बर 1969 में जब इस कालेज की स्थापना की गयी तब से लेकर अब तक कुल 1443 अधिकारियों ने कालेज द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्क्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

304. इन पाठ्यक्रमों के अलावा दो विचार गोष्ठियों अर्थात् राज्य सहकारी बैंकों केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए एक एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, मद्रास

305. उक्त कालेज ग्रेड II स्टाफ आफिसरों (सीधे भर्ती और पदोन्नत किये गये) और सहायक कर्मचारी वर्ग के लिए केन्द्रीय बैंक संघटन पर सामान्य पाठ्क्रम तथा बैंक के बैंक परिचालन और विकास विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग और कृषि ऋण विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन नियमित रूप से करता रहा। ग्रेड I ग्रेड II (सीधे भर्ती किये गये) स्टाफ़ आफ़िसरों के लिए भी कालेज ने दो प्रवेश पाठ्क्रम चलाये हैं। इस कालेज में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या 3386 है।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

306. रिजर्व बैंक के अवर और प्रवर क्लर्कों के लिए बंबई, मद्रास और नयी दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पाठ्यक्रमों का आयोजन करते रहे। कतिपय अनिवार्य प्रशासनिक कारणों से कलकत्ता का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र इस अवधि में नहीं खोला जा सका। विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त क्लर्क कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या 6961 है।

शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी अन्य बातें

कर्मचारी वर्ग की प्रतिनियुक्ति

307. भारतीय प्रशासी कर्मचारी कालेज, हैदराबाद के साथ की गयी स्थायी व्यवस्थाओं के अधीन रिजर्व बैंक के अधिकारी उक्त कालेज के द्वारा आयोजित प्रबन्ध विकास पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किये गये। वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के लिए बैंकर प्रशिक्षण कालेज द्वारा चलाये जानेवाले कुछ पाठ्यक्रमों में और साथ ही, अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं और इसी प्रकार के कुछ अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रबन्ध विकास संबन्धी अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी अधिकारियों को भेजा गया। बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और बैंकाक स्थित एशियाई आर्थिक विकास और योजना संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। रिजर्व बैंक ने दक्षिण पूर्व एशिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया केन्द्रीय बैंक संघटन कार्यक्रम तथा कुछ विदेशी संस्थाओं द्वारा आयोजित अपने हित के अन्य पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। इनके अतिरिक्त ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और इटली की बैंक

व्यवसाय संबन्धी और वित्तीय संस्थाओं में अध्ययन दौरे/प्रशिक्षण के लिए भी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया में हिन्दी की प्रगति

308. आलोच्य वर्ष में रिजर्व बैंक ने 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कामकाज एवं भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य और कार्य पद्धति के परिशोधित संस्करण के हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित किये। परिशोधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियम पुस्तक (छटा संस्करण) का हिन्दी अनुवाद भारत के राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशित करने के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया। रिजर्व बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जमा बीमा निगम और भारतीय ऋण गारन्टी निगम लिमिटेड जैसी अपनी सहयोगी संस्थाओं को भी उनकी वार्षिक रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियों, विज्ञापनों, अधिसूचनाओं, नोटिसों आदि के हिन्दी अनुवादों के लिए बराबर सहायता प्रदान करता रहा।

309. राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का पालन करते हुए रिजर्व बैंक प्रेस विज्ञप्तियों/नोटों/प्रकाशनियों/सारांशों, नोटिसों, विज्ञापनों और अधिसूचनाओं को अंग्रेजी और हिन्दी में एक साथ जारी करता रहा। जनता, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त पत्र आदि स्वीकार किये गये और उनका हिन्दी में उत्तर दिया गया।

310. वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपनी एक बैठक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में बैंक द्वारा की गयी उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उक्त समिति के अनुरोध पर बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की गति में तीव्रता लाने के उद्देश्य से मुख्य प्रबन्धक की अध्यक्षता में सात सदस्यों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गयी। 24 मार्च 1972 को उक्त समिति की पहली बैठक हुई और उसमें अब तक बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और बैंक की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम में हुई प्रगति का पुनरीक्षण किया गया।

311. रिजर्व बैंक विभिन्न केन्द्रों में अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए अपनी शिक्षण योजना के अधीन स्वैच्छिक आधार पर हिन्दी कक्षाएं चलाता रहा। हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए जो प्रोत्साहन दिये जाते थे वे इस वर्ष के दौरान भी जारी रहे। रिजर्व बैंक के टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपराइटिंग (टंकण कला) परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मानदेय प्रदान करने की जो व्यवस्था की गयी थी वह इस वर्ष भी जारी रही। बैंक की हिन्दी शिक्षण योजना की गति में तीव्रता लाने के लिए हमारे कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रश्न भी विचाराधीन था।

	वर्ष	
	1971-72	1970-71
	रु.	रु.
(i) राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	15.32 करोड़	10.21 करोड़
(ii) राज्य सरकारों (उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखित अर्थोपाय अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज को छोड़कर) और वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	20.56 करोड़	21.74 करोड़
(iii) रुपया प्रतिभूतियों पर ब्याज और रुपया खजाना बिलों पर बट्टा	156.25 करोड़	133.51 करोड़
(iv) विदेशी प्रतिभूतियों, निवेशों और खजाना बिलों पर ब्याज और बट्टा	22.58 करोड़	29.29 करोड़
(v) विदेशी मुद्रा विनियम से प्राप्त कमीशन और लाभ या लब्धि	6.40 करोड़	1.39 करोड़
(vi) अन्य आय	1.06 करोड़	0.32 करोड़
जोड़	222.17 करोड़	196.46 करोड़
घटाइए : पैराग्राफ 313 के उल्लेखानुसार निधियों में किये गये अंतरण	65.00 करोड़	60.00 करोड़
	157.17 करोड़	136.46 करोड़

VIII लेखे और अन्य विषय

312. 30 जून, 1972 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में नियमित और आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद बैंक की आय 222.17 करोड़ रुपये थी जब कि पिछले वर्ष की आय 196.46 करोड़ रुपये थी।

313. राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में जो अंशदान किये गये उनकी राशि क्रमशः 19 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपये और 40 करोड़ थी जब कि 1970-71 में उनकी राशि क्रमशः 18 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये थी।

314. इस वर्ष के दौरान 37.17 करोड़ रुपयों का कुल व्यय हुआ जब कि पिछले वर्ष 36.46 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ था। 157.17 करोड़ रुपयों की जो आय राशि शेष थी उसमें से उक्त व्यय राशि को घटाने के बाद केन्द्रीय सरकार को अदा करने के लिए अलग रखी गयी लाभ राशि 120 करोड़ रुपये थी; पिछले वर्ष यह राशि 100 करोड़ रुपये थी।

315. इस वर्ष आय में 25.71 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई उससे कुल आय 196.46 करोड़ रुपयों से बढ़कर 222.17 करोड़ रुपये हो गयी। उक्त वृद्धि प्रमुख रूप से रुपया प्रतिभूतियों और खजाना बिलों पर प्राप्त होने वाले ब्याज में वृद्धि होने के कारण हुई। यह स्थिति (i) 9 जनवरी 1971 से बैंक दर में एक प्रतिशत की वृद्धि किये जाने से पूरे वर्ष के दौरान पड़े प्रभाव (ii) केन्द्रीय सरकार के घाटे की पूर्ति करने के निमित्त केन्द्रीय सरकार के लिए उदय खजाना बिलों के निर्माण और (iii) इस वर्ष राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्टों के उच्च

स्तर के कारण हुई । व्यय में 0.71 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह प्रमुख रूप से व्यय की विभिन्न मदों में हुई सामान्य वृद्धि के कारण हुई ।

लेखा परीक्षक

316. बैंक के लेखों की परीक्षा मेसर्स राय एण्ड राय, कलकत्ता, मेसर्स ए० एफ० फर्गुसन एण्ड कंपनी, बम्बई, मेसर्स सूरि एण्ड कंपनी, मद्रास और मेसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा की गयी जिन्हें भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी तारीख 5 अक्तूबर 1971 की अधिसूचना सं० एफ० 3 (24)—बीसी 71 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। इस वर्ष बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के कार्यालयों के अलावा बंगलूर और पटना के कार्यालयों के लेखों की भी परीक्षा की गयी है। लेखा परीक्षकों के लिए प्रति कार्यालय 15,000 रुपयों का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है ।

केन्द्रीय बोर्ड

317. केन्द्रीय सरकार ने उप गवर्नर श्री पी० एन० डमरी की कार्यावधि को 13 फरवरी 1972 से दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

318. श्री पी० एल० टंडन और डॉ० वी० षण्मुगसुन्दरम् 14 जनवरी 1972 को अपनी पदावधि समाप्त होने पर केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से निवृत्त हुए । सेवानिवृत्त निदेशकों की सेवाओं के प्रति बोर्ड अपना आभार प्रदर्शित करता है ।

319. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त हो जाने के कारण श्री ए० बक्शी 26 मार्च 1972 से निदेशक न रहे।

320. रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (ग) के अधीन श्री एस० एम० जोशी और डॉ० भवतोष दत्त 7 फरवरी 1972 से रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नियुक्त किये गये। श्री सी० पी० श्रीवास्तव भी उसी धारा के अधीन 17 फरवरी 1972 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये ।

321. इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुईं जिनमें से एक एक बैठक लखनऊ, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, भुवनेश्वर, नई दिल्ली और शिलांग में हुई। केन्द्रीय बोर्ड की समिति की 51 बैठकें हुईं जिनमें से 6 बैठकें नई दिल्ली, में 2 बैठकें कलकत्ता में, एक बैठक मद्रास में और शेष बैठकें बम्बई में हुईं ।

322. श्री वी० जी० पेंढारकर, कार्यपालक निदेशक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन बैंक ऑफ़ तंजानिया के वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए और वे उक्त पद भार ग्रहण के लिए 14 अप्रैल 1972 को भारत से रवाना हुए।

स्थानीय बोर्ड

323. श्री दयालजी जी० पटेल ने 26 अप्रैल 1972 को बम्बई स्थित पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। आलोच्य वर्ष में स्थानीय बोर्डों के स्वरूप और सदस्यता में कोई दूसरा परिवर्तन नहीं हुआ ।

कार्यालय खोलना और बंद करना तथा संगठन और प्रबन्ध में परिवर्तन

324. अहमदाबाद में 1 दिसम्बर 1971 से इशु विभाग का एक उप कार्यालय खोला गया और उस केन्द्र के नोट निरसन अनुभाग को उक्त उप कार्यालय में सम्मलित कर दिया गया। उक्त केन्द्र में 1 दिसम्बर 1971 को जमा लेखा विभाग भी खोला गया।

बैंक के भवन

नये कार्यालय भवन

325. बंबई स्थित टकसाल के अहाते में प्रस्तावित बहु-मंजिलों वाले भवन के लिए विभाजक दीवार का निर्माण करने का ठेका दे दिया गया है और उसका कार्य प्रगति कर रहा है ।

कार्यालय के उपयोग के लिए पट्टे पर लिये गये भवन

326. भुवनेश्वर में इशु विभाग का उप कार्यालय राज्य शासकीय आलेखागार भवन में स्थापित करना था और उक्त भवन अधिकार में ले लिया गया है । भुवनेश्वर में बैंक परिचालन और विभाग विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए आवश्यक भवन पट्टे पर लेने की व्यवस्थाएं की गयी हैं। जयपुर के वर्तमान विभागों को एक स्थान पर स्थापित करने और एक उप कार्यालय खोलने के लिए जयपुर में निर्माणाधीन एक भवन में कार्यालय स्थान पट्टे पर लेने की व्यवस्थाएं भी की गयी हैं ।

आवास भवन

327. बैंक सभी प्रमुख केन्द्रों में आवास भवनों की व्यवस्था करने की बराबर कोशिश कर रहा है। इन आवास भवनों के लिए बैंक भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करता है । आलोच्य वर्ष के दौरान मद्रास में क्लर्कों के लिए 16 आवासों का निर्माण कार्य समाप्त हो गया और क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिए 1038 आवासों—नई दिल्ली में 272, कलकत्ता में 444, कानपुर में 218 और नागपुर में 104—का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है। ग्रेड I और II के स्टाफ आफिसरों के लिए बंगलूर में 54 आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र ही समाप्त होगा और बम्बई में 152 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है। नई दिल्ली, मद्रास, बंगलूर, हैदराबाद और भुवनेश्वर में क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिए और 850 फ्लैटों का निर्माण करने की प्रायोजनाएं तैयार की जा रही हैं अथवा उनके लिए टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। नई दिल्ली और कानपुर में ग्रेड I और II के स्टाफ ऑफिसरों के लिए 258 फ्लैटों का निर्माण करने की प्रायोजना तैयार की जा रही है ।

328. ऐसे केन्द्रों में जहां कोई भूमि प्राप्त नहीं की गयी है या जहां आवासों की संख्या अपर्याप्त है, आवास भवनों का निर्माण करने के निमित्त उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मालिक-कर्मचारी सम्बंध

329. बैंक और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के बीच पहले के समझौते के अन्तर्गत जो-जो बातें नहीं आयी थीं उनपर बातचीत हुई । सभी विभागों के क्लर्कों की संयुक्त वरीयता और क्लर्क संवर्ग में उससे भिन्न संवर्गों के योग्य कर्मचारियों के स्वयमेव अन्तरण से सम्बन्धित समझौते पर 7 मई 1972 को हस्ताक्षर किये गये। इसके साथ ही बैंक ने ग्रेड II स्टाफ आफिसरों के रूप में साक्षात्कार पर आधारित वर्तमान चयन प्रणाली के बजाय लिखित परीक्षा के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने की योजना से सम्बन्धित अपने निर्णय की सूचना कर्मचारी संघ को दी है। बैंक ने संघ को यह सूचना भी दी है कि स्टाफ आफिसर, ग्रेड II के संवर्ग के जितने पद सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिए निर्धारित किये गये हैं और उनके द्वारा भरे जाएंगे वे स्टाफ ऑफिसर ग्रेड II के पदों की कुल संख्या (समय-समय पर परिवर्तनीय) का 17½ प्रतिशत होंगे और सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिए निर्धारित पदों के अवधांश को भर्ती परीक्षा में योग्य पाये जाने वाले कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया जाएगा और उनके द्वारा उन पदों को भरा जाएगा ।

330. बैंक ने "रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिकारी संवर्ग पुनरीक्षण समिति" नामक एक समिति का भी गठन किया है। समिति का स्वरूप निम्न प्रकार है :

श्री न्यायमूर्ति जे० एल० नैन, बंबई उच्च न्यायालय, बम्बई	अध्यक्ष
श्री बी० ईश्वरन, आई० सी० एस० (सेवानिवृत्त)	सदस्य
प्रो० एन० एस० रामस्वामी, निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई	सदस्य

उक्त समिति का उद्देश्य बैंक के अधिकारियों की वर्तमान परिलब्धियों अके विन्यास, पदोन्नति संबन्धी नीति और क्रियाविधि, सेवाकालीन प्रशिक्षण की प्रणालियों आदि का पुनरीक्षण करना है। आलोच्य वर्ष में अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी कर्मचारी संघ, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिकारी संघ और बैंक के विचारों से अवगत होने के लिए कई बार समिति की बैठकें हुईं। आशा है कि समिति की रिपोर्ट कुछ महीनों में प्राप्त होगी।

कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण योजना

331. आलोच्य वर्ष में गृह निर्माण के लिए जो ऋण मंजूर किये गये उनका विवरण नीचे दिया जाता है :

	समितियों की संख्या	राशि रु०
(अ) नयी सहकारी गृह निर्माण समितियां	11	39,13,679
पहले ही गठित सहकारी गृह निर्माण समितियों को दिये गये अतिरिक्त ऋण	4	4,19,772
		43,33,451

	कर्मचारियों की संख्या	राशि रु०
(आ) अलग-अलग कर्मचारी		
नये ऋण	168	30,72,004
जिन कर्मचारियों ने पहले ही ऋण लिये थे उनको दिये गये अतिरिक्त ऋण	36	4,54,527
		35,26,531

1961 में इस योजना के अमल में आने से लेकर अब तक मंजूर किये गये 'समिति' ऋणों और 'वैयक्तिक' ऋणों की कुल राशि क्रमशः रु० 3,27,27,611.00 और रु० 1,13,71,634.00 है। कुल मिलाकर 2,069 कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया

30 जून 1972 तक का तुलन-पत्र

इशू विभाग

देयताएं	रु०	पै०	रु०	पै०	आस्तियां	रु०	पै०	रु०	पै०
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	28,79,48,120.00				सोने का सिक्का और बुलियन:				
संचलन में नोट	4877,73,13,265.50				(क) भारत में रखा हुआ	182,53,10,862.72			
जारी किये गये कुल नोट			4906,52,61,385.50		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	—			
					विदेशी प्रतिभूतियां	221,65,38,085.47			
					जोड़			404,18,48,948.19	
					रुपये का सिक्का			28,05,41,745.87	
					भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां			4474,28,70,691.44	
					देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र			—	
कुल देयताएं			4906,52,61,385.50		कुल आस्तियां			4906,52,61,385.50	

बैंकिंग विभाग

देयताएं	रु०	पै०	आस्तियां	रु०	पै०
चुकता पूंजी	5,00,00,000.00		नोट	28,79,48,120.00	
आरक्षित निधि	150,00,00,000.00		रुपये का सिक्का	2,77,688.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	209,00,00,000.00		छोटा सिक्का	2,08,240.65	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	45,00,00,000.00		खरीदे और भुनाये गये बिल		
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	175,00,00,000.00		(क) देशी	9,85,75,721.88	
जमा राशियां :—			(ख) विदेशी	—	
(क) सरकारी			(ग) सरकारी खजाना बिल	311,17,49,668.84	
(i) केन्द्रीय सरकार	47,03,13,413.14		विदेशों में रखा हुआ बकाया*	195,27,24,607.67	
(ii) राज्य सरकारें	7,91,08,468.66		निवेश**	448,18,03,896.33	
(ख) बैंक			ऋण और अग्रिम		
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	296,76,30,028.10		(i) केन्द्रीय सरकार को	—	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	18,42,05,095.16		(ii) राज्य सरकारों को‡	38,01,00,000.00	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	99,77,914.40		ऋण और अग्रिम:—		
(iv) अन्य बैंक	76,52,821.40		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	27,10,79,000.00	
(ग) अन्य	214,39,88,634.13		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	169,11,51,249.00	
देय बिल	75,52,14,714.43		(iii) दूसरों को	10,88,91,800.00	
अन्य देयताएं	285,28,09,886.83		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश		
			(क) ऋण और अग्रिम		
			(i) राज्य सरकारों को	53,05,82,256.54	
			(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,70,01,632.00	
			(iii) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों को	—	
			(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	5,00,00,000.00	
			(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,77,030.00	
			राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम		
			राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	25,70,39,464.00	
			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश		
			(क) विकास बैंकों को ऋण और अग्रिम	92,82,33,544.00	
			(ख) विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	—	
			अन्य आस्तियां	84,74,57,057.34	
कुल देयताएं	1531,09,00,976.25		कुल आस्तियां	1531,09,00,976.25	

अंशतः चुकता शेयरों पर फुटकर देयता रु० 9,48,388.69 (पौण्ड 50,000 के स्टर्लिंग निवेशों को रु० 100 = 5.2721 पौण्ड की दर पर बदला गया)।

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**(i) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

(ii) विदेशों में रखे हुए रु० 5,17,76,414.16 (50,000 पौण्ड और 6,982,500 अमेरिकी डालर के समान राशि) शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

†रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 45,00,000 रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

के० एन० आर० रामानुजम, मुख्य लेखापाल

तारीख 8 अगस्त, 1972

आर० के० हजारी, उप गवर्नर
एस० एस० शिरालकर, उप गवर्नर
पी० एन० डमरी, उप गवर्नर
वी० बी० चारी, उप गवर्नर

30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

आय	रु०	पै०
ब्याज, भांजन, विनिमय, कमीशन आदि*	157,16,50,995.	40
व्यय		
स्थापना	20,93,25,621.	86
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फ़ीस और व्यय	65,527.	68
लेखा परीक्षकों की फ़ीस	90,000.	00
किराया, कर, बीमा, बिजली, आदि	1,02,10,648.	99
विधि प्रभार	2,16,523.	57
डाक और तार खर्च	11,87,907.	87
कोष-प्रेषण	67,29,577.	01
लेखन सामग्री, आदि	27,98,163.	31
प्रतिभूति-छपाई (चेक, नोट फ़ार्म आदि)	4,80,22,762.	31
बैंक संपत्ति का मूल्य ह्रास और मरम्मतें	1,06,19,459.	89
एजेंसी प्रभार	7,28,37,842.	14
कर्मचारी निधि और अधिवार्षिकी निधि में अंशदान	—	
विविध व्यय	95,46,783.	63
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि	120,00,00,177.	14
जोड़	157,16,50,995.	40
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष	120,00,00,177.	14

प्रारक्षित निधि लेखा

30 जून 1972 को शेष	150,00,00,000.	00
लाभ-हानि लेखा से अंतरित किया गया	कुछ नहीं	
जोड़	150,00,00,000.	00

*रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद।

एस० जगन्नाथन, गवर्नर
पी० एन० डुमरी, उप गवर्नर
आर० के० हज़ारी, उप गवर्नर
वी०वी० भारी, उप गवर्नर
एस०एस० शिरालकर उप गवर्नर

के० एन० आर० रामानुजम,
मुख्य लेखापाल

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में,

हम रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के अधोहस्ताक्षरित लेखापरीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1972 तक के रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र तथा लेखों पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने केन्द्रीय कार्यालय और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली, पटना और बंगलूर के कार्यालयों के लेखों और उनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के मैनेजरों द्वारा पेश की गयी प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उक्त तुलन-पत्र में समाविष्ट किया गया है, उपर्युक्त तुलनपत्र की जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो-जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह सारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और वह संतोषजनक है। हमारी राय में यह तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलनपत्र है; इसमें रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिये गये हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य निर्धारण किया गया है। जहां तक हमारी जानकारी है, यह तुलनपत्र हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

राय एण्ड राय,
ए. एफ. फर्गुसन एण्ड कंपनी,
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी,
सूरि एण्ड कंपनी,
} लेखा परीक्षक

तारीख 8 अगस्त 1972

[सं० एफ० 10(13)बी० ओ० I/72]

(Department of Banking)
New Delhi, the 25th January, 1973

ANNUAL REPORT OF THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA AND TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA FOR THE YEAR JULY 1, 1971-JUNE 30, 1972

S.O. 877.—In accordance with Section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following report on the working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1972.

I. TRENDS IN THE ECONOMY

The dominant feature of the Indian economy during the period July 1971-June 1972 was the resilience it demonstrated under conditions of unexpected and large increases in domestic expenditure. These increases arose primarily from the influx of refugees from across the border in the East and subsequently the conflict with Pakistan in December 1971; they also derived in part from the continuation of Government policies, both at the Centre and in the States, seeking the multiple plan objectives of growth in output, greater social justice and increased self-reliance. Since not all of the addition to domestic spending was matched by increases in industrial and agricultural outputs, the excess demand manifested itself both in higher prices and a bigger trade deficit. The latter was financed through larger utilisation of foreign assistance already available rather than any net draft on foreign exchange reserves. The effects on domestic prices, however, could not be avoided but only moderated and postponed. This was based partly on larger issues from Government's food stocks in the pre-harvest period. But the main efforts undertaken were in the fiscal and monetary fields, to restrain private spending when Government expenditurers were rising steeply. Price increases between September 1971 and March 1972 were fairly small reflecting the usual seasonal pattern, but since then, the rise has been larger than anticipated and rather disconcerting.

2. Within this overall picture, changes in the different sectors of the economy took different forms depending on the particular forces operating on them. Not all of these changes or their causes can be precisely identified at this stage; available information makes it possible to assess only some of them and that too in approximate terms. For example, while there are no data pertaining to private consumption expenditure as such, the trends in aggregate monetary resources indicate an increase in household savings, particularly financial savings, in absolute magnitude as well as in comparison with the Net Domestic Product (NDP) at market prices. Likewise, enough information is available to show that in the Government sector the relative share of consumption expenditure increased at the expense of public savings. In the aggregate, it would appear that domestic saving at current prices constituted a somewhat higher proportion of Net Domestic Product in 1971-72 than in the previous year; and since aid utilisation also was higher, the inflow of foreign resources available for financing investment increased relatively to 1970-71. It thus emerges that despite the unusual circumstances of the year under review, total domestic investment formed a higher proportion of NDP than in the previous years, as may be observed from the table given below. It is important to note that along with this increase, there was also a sizeable increase in prices; hence the achievement in real terms was probably less impressive.

Table 1 :—Provisional Estimates of Savings and Investment as Per Cent of NDP at Market Prices

Financial Year	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1973-74 (Mid-term Appraisal Estimate)
1. Domestic saving	8.2	8.6	9.4	10.0	10.2(11.9)
2. Inflow of foreign resources	1.3	0.7	1.1	1.5	0.9(1.2)
3. Investment (1+2)	9.5	9.3	10.5	11.5	11.1(13.1)

(Figures within brackets show ratios implied in the Fourth Plan Document).

3. It will be observed from the data given in subsequent paragraphs that much the larger part of the increase in domestic saving during 1971-72 is reflected in the large increase of aggregate monetary resources with the public. Indeed, while both currency with the public and the deposits of scheduled commercial banks grew during the year under review, the increase in the latter was at a much faster rate than at any time previously. Again reckoned in current prices, this growth was of the order of 21 per cent compared to 17.9 per cent in the previous year; and within the area of bank deposits, savings and time deposits have risen much faster than demand deposits. Since on the credit side, the general policy was one of restraint and industrial borrowing was slack; deposit accretion outpaced the growth in bank advances, leaving the banks in a highly liquid position.

4. The position at the end of June 1972 was, therefore, one in which the public commanded, both in terms of currency and in the form of bank deposits, a large stock of potential demand while output trends in the commodity sectors were anything but comfortable. The cushion against further price increases consisted of food stocks amounting to 8.9 million tonnes and to some extent those of raw cotton and jute. For the rest, larger supplies to meet any increase in demand clearly require an upturn in industrial production and a good monsoon; they also depend on the maintenance of, if not an increase in, imported raw materials and capital goods.

5. Concurrently with these events within the country, there occurred, in the international monetary sphere, changes of a far reaching nature, with implications for India's trade and external payments. Commencing with the U.S. decision in August 1971 to end dollar convertibility as also official support to parity and culminating with the U.K.'s decision in June 1972 to float the pound sterling, the year witnessed a complete change from the Bretton Woods arrangement of fixed parities and defined obligations in the matter of exchange relations. These fluctuations and uncertainties in the international monetary arrangements have inevitably had repercussions on the trade and aid benefits available to developing countries, including India. Having continued the old parity with the dollar until December 1971, the Indian rupee participated in the general realignment of currencies resulting from the monetary agreements of December 1971 and established its central rate for exchange with sterling, subject to the accepted margin of 2-1/4 per cent for fluctuations in either direction. The floating of the pound sterling last June has not resulted in any change in India's policy in this regard.

6. These changes in the exchange system have been a factor additional to tariff and non-tariff barriers abroad affecting India's exports. Export earnings during the fiscal year 1971-72 (April-March) were larger than the previous year's total by only Rs. 32 crores or about 2 per cent.* This was despite the fact that considerable benefit accrued to Indian jute exports because of the closure of mills in Bangladesh for a substantial part of the year. While some of the deceleration in the growth rate of exports was attributable to the external factors mentioned above, there were equally weighty elements within the economy, such as lower levels of output and cost and price increases which contributed to reduced exports of certain commodities.

7. Clearly, a much higher growth in exports than in 1971-72 will be required if the import requirements of the economy are to be met adequately in the future, without undue reliance on aid or an undue draft on foreign exchange reserves. Both for checking a further rise in domestic prices

*These figures are based on D.G.C.I.S. data. As will be explained in paragraph 80, if adjustment is made for the change in the recording of exports in 1970-71, the percentage increase in exports in 1971-72 over the previous year would be larger than 2 per cent.

and achieving higher exports, policy has therefore to be directed towards establishing a more viable relationship between rise in domestic expenditure and increase in aggregate output. Since in the coming years an increasingly large part of domestic expenditure will arise from plan and non-plan outlays in the Government sector, the present situation warrants the pursuit of a policy based on minimal resort to deficit financing. Simultaneously, it will be essential to direct the additional deposits mobilised within the banking system to the attainment of larger production and more employment in the economy. It is hoped that these conclusions emerging from developments in the last year will be taken into consideration in the formulation of the Fifth Plan.

Output, Prices and Policy Measures

National Income

8. We turn now to the details of developments in the period July 1971-June 1972. Production trends in the economy indicate that the increase in real national income (at 1960-61 prices) was somewhat less than 4 per cent in the fiscal year 1971-72, compared to increases of 5.3 per cent and 4.7 per cent recorded in 1969-70 and 1970-71, respectively. With this record for the first three years of the Fourth Plan, national income would have to grow at a rate of about 7 per cent in the remaining two years if the target (5.5 per cent per annum) postulated in the Fourth Five-Year Plan is to be achieved.

Agricultural Output and Supply

9. The deceleration in national income growth was caused by a decline in the growth rates of both commodity sectors. Agricultural production which had increased at an average rate of 7 per cent during the preceding two years is likely to show a much smaller rise in 1971-72. Largely because of a decline of about 2.7 million tonnes in bajra, the output of coarse grains has failed to keep pace with the trends in major cereals. Coupled with the shortfalls in pulses, indications are that the foodgrains output may not equal last year's level of 108 million tonnes. This is somewhat of a setback particularly in view of the fact that the area under high-yielding varieties programme was expanded during the year.

10. In spite of stagnation in current output, the foodgrains supply situation was comfortable during 1971-72 because of stocks with the Government. The fall in imports of foodgrains was offset by a sufficiently larger rise in the quantity domestically procured, thereby increasing the level of end-year stocks. Foodgrains stocks at the end of June 1972 were 8.9 million tonnes as compared to 8.4 million tonnes last year. Of the total stocks, rice constituted 2.5 million tonnes and wheat 6.1 million tonnes. While this position constitutes a vantage starting point for food management in the coming year, it also indicates that there was not a sufficient drawal on stocks to mitigate the increase in foodgrains prices during the last few months.

11. Among the commercial crops, again, the situation is a mixed one. While cotton and jute have recorded increases in output, the production of oilseeds and sugarcane has declined. Cotton output in 1971-72 estimated by trade at more than 7 million bales sets a new record; the increase over the year, however, has to be viewed against a relatively low level of output of 5.7 million bales estimated by trade for 1970-71. Jute and mesta also showed an increase of 0.6 million bales to reach a level of 6.8 million bales. Output of five major oilseeds, on the other hand, which had risen substantially in 1970-71 to reach a level of 9.2 million tonnes, is expected to be lower by about a million tonnes in the year under review; groundnut output is placed lower at 5.7 million tonnes, as against 6.1 million tonnes last year. Sugarcane production which had declined from the 1969-70 peak level of 13.8 million tonnes to 13.2 million tonnes in 1970-71, is expected to decline further to 12.8 million tonnes in 1971-72.

12. Despite these annual variations, agricultural output generally and that of foodgrains in particular has been showing a rising trend following the adoption of the new agricultural strategy in 1966-67. The coverage of high-yielding varieties programme is expected to reach the target of 18 million hectares fixed for the year as against 14.6 million hectares achieved in 1970-71. Unlike in the previous two years, consumption of chemical fertilizers recorded a substantial rate of increase during 1971-72. The situation, however, does not admit of complacency; while progress is faster than scheduled in the case of wheat, in others—particularly in jowar, Maize, and pulses—it has been slower than envisaged. In the case of rice—the most important cereal crop in the country—the initial problems that inhibited the success of high-yielding varieties programmes are being gradually overcome with the release of suitable high-yielding strains with superior grain quality and resistance to pests and diseases. Thus a very considerable part of the potential benefits of the new strategy still remains to be garnered.

13. A problem associated with the proper management of foodgrains is that of storage and transport. The total storage capacity with the Food Corporation of India (FCI) increased from 7.2 million tonnes in 1970-71 to 8.3 million tonnes in 1971-72 (inclusive of 4.2 million tonnes capacity hired from other Government and private sources). Even so the existing capacity is inadequate in relation to rising storage requirements and the FCI's efforts to construct additional *silos*, particularly in heavy procurement areas of Punjab, Rajasthan and U.P., have suffered on account of steel scarcity. As for transport, inadequate wagon availability on both the broad and meter-gauge systems during the last few years has come in the way of smooth and timely movement of grains from producing centres to the large consuming markets. A large procurement and buffer stocks programme for foodgrains can succeed in the object of evening out fluctuations in different parts of the country only if these impediments are removal and efficient systems of storage and transportation of foodgrains to urban markets assured.

Industrial Output

14. The growth of industrial output has been decelerating for the last three years; it has declined from 7.1 per cent in 1969 to 4.8 per cent in 1970 and was only 2.9 per cent in 1971, or less than half of the target rate of 8 to 10 per cent envisaged in the Fourth Five-Year Plan.

15. A classification of industrial groups by size of their annual growth rates shows that industries recording absolute declines in output have steadily increased from 24 per cent (by weightage) in 1968 to 38 per cent in 1971. Correspondingly, the weightage of industries showing increases in output has gone down from 74 per cent to 60 per cent in the same period.

16. Industries showing marked declines of 5 per cent and above in 1971 accounted for about 18 per cent of the total weightage. Included in this group were cotton spinning, industrial machinery, railroad equipment and sugar. Industries showing declines of less than 5 per cent were iron and steel, weaving of cotton textiles and motor cycles and bicycles. Among the industries which showed increases in output in 1971, the weightage of those with increases of 5 per cent and above, came down from 38 to 32 per cent and those which showed increass of 10 per cent and above accounted for 16 per cent as against 22 per cent in 1970. Industries showing marked increases included basic chemicals, cement, all non-ferrous metals, electricity generation and vanaspati.

17. Supply bottlenecks as well as demand constraints were responsible for the persistent declining trend in the overall growth rate of industrial output. Among the former set of factors were shortages of raw materials like raw cotton and oilseeds and basic industrial materials like steel and non-ferrous metals. These shortages contributed to lower production in other industries also. The decline in the output of finished steel, for instance, from 4.8 million tonnes in 1970-71 to 4.6 million tonnes in 1971-72, though marginal, created serious problems for steel-using industries whose increasing demand could be eased only to a limited extent through imports. Accumulation of coal and cement stocks was caused by bottlenecks in rail transport, though slackness in demand for cement from construction activities and for coal from metallurgical consumers also affected their output. Organizational and labour relations problems in some critical sectors such as steel, automobiles and allied industries further contributed to this slack in industrial output. In addition, power shortages also seriously affected the output of some industries.

18. There were some industries which did not work at all capacity because of continued sluggishness in demand.

Table 2 :—Classification of Industries by their Growth Rates

Range of Growth Rates@	In terms of Weights in the General Index (1960=100)				
	1967	1968	1969	1970	1971
Absolute Decline					
Moderate : Less than 5 per cent	35.68	4.43	16.61	16.10	19.98
Marked : 5 per cent and above	25.48	19.04	12.15	13.24	17.59
Of which,					
(i) 10 per cent and above	13.93	9.18	9.79	6.13	5.30
	61.16	**23.47**	**28.76**	**31.34**	**37.57**
Increase					
Moderate : Less than 5 per cent	15.34	23.81	26.69	27.78	27.99
Marked : 5 per cent and above	21.02	50.24	42.07	38.40	31.96
Of which,					
(i) 10 per cent and above	13.20	25.68	28.10	22.42	15.72
	36.36	**74.05**	**68.76**	**66.18**	**59.95**
Total Weight	**97.52***	**97.52***	**97.52***	**97.52***	**97.52***

@Growth Rates represent percentage increases over the respective preceding years.

*C.S.O. does not regularly publish the index of industries with the balance of 2.48 percentage points of weightage.

Among these were investment goods industries like steel pipes and tubes, railway wagons building and almost all important machinery manufacturing industries (such as of cement, tea, printing and leather). They have not only been experiencing considerable under-utilisation of capacity but the rate of utilisation has also come down during the past two years. Some of the industries such as steel castings and machine tools, have doubtless shown improvement in the rate of capacity utilisation in 1971; even so, they still have substantial capacity unutilised. As mentioned earlier, in a few cases shortages of raw materials, power, etc., contributed to this situation; however, in all these cases, the major factor responsible for the decline in the growth of output was the persistent sluggishness in demand. There were, on the other hand, certain industries, the demand for which was not a restraining factor, but their output suffered because of lack of capacity. These included paper and paper products, caustic soda, soda ash, automobiles, and agricultural tractors. Both these factors, viz., sluggishness in demand for investment goods and insufficient capacity can be traced to relatively slow increase in aggregate investment during the last few years.

19. The outlook for industrial output in 1972 is somewhat better than in the previous year. There has been an easing of raw material shortages in some cases. For instance, supply of raw cotton for the textile industry has improved but the future outlook has again become uncertain. An increase in investment activity is expected to have a favourable impact on the demand for industrial products. The Government has also taken some measures to encourage industrial output. Blanket permission has been given in January, 1972 to 54 critical industries to expand output and diversify to the extent of about 100 per cent above their licensed capacity. The impact of this policy on output has yet to be seen although it may be observed that regulatory constraints on the installation of capital equipment and machinery even in the case of these 54 industries may dampen the effect of the new policy. Special measures have also been adopted to correct organizational deficiencies in the implementation of new public sector projects as well as the working of existing plants. As against these favourable elements, shortages continue in certain fields, such as vanaspati manufacturing industry which is suffering from an inadequate supply of oilseeds. Similarly raw jute output during 1972-73 is now placed at a low level which may affect the output of jute textiles in the second half of 1972.

Price Situation

20. With these trends in output, increased internal demand naturally worsened the price situation. Between June, 1971 and June, 1972, there was a sharp rise in the wolesale price index of 6.8 per cent which was more than double that in the previous year. With the single exception of industrial raw materials, all the major groups included in the price index shared in the rise. Foodgrains prices, which had declined by 2.4 per cent in 1970-71 (July-June), increased by more than 14 per cent and the prices of manufactured articles showed a rise of more than 5 per cent, on top of an increase of 8.6 per cent in the previous year. In the foodgrains group, prices increased not only in the case of coarse grains and pulses whose output had declined but in respect of wheat as well, despite increase in its output. Rice and wheat prices went up by 10.1% and 3.8% in the year under review in contrast to declines of 2.1 per cent and 2.9 per cent, respectively, in the preceding year. Among other essential commodities the price of sugar shot up by 27.5 per cent over the year. It was only in raw cotton prices, which had increased by more than 20 per cent in the previous year, that there was a sharp fall of over 31 per cent in the year under review, owing to an estimated rise of more than 26 per cent in overall output. The prices of all the other industrial raw materials, e.g., raw jute, oilseeds and sugarcane recorded varying degrees of increases. Similarly in the manufactured articles group, prices of all the important products like cotton manufactures, jute manufactures, chemical products, iron and steel manufacures and paper products showed increases.

21. In consonance with the uptrend in the general price level especially in prices of foodgrains and sugar, consumer price index numbers (Base: 1960 = 100), represented by the all-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers and Consumer Price Index Numbers for Urban Non-Manual Employees, have also moved up. The average Index for Industrial Workers increased from 186 in 1970-71 (July-June) to 195 during 1971-72 (July-June), recording a larger rise of 4.8 per cent as compared to 3.9 per cent in 1970-71 over 1969-70. The average Index for Urban Non-Manual Employees too rose by 4.6 per cent in 1971-72 (July-June) over 1970-71 as against a rise of 3.6 per cent in 1970-71 over 1969-70. Continuation of this upward pressure on the cost of living has serious cost implications because many establishments in the public and private sectors have clauses linking the wage bill to cost of living variations.

22. While outputs in many cases either declined or rose only by a small percentage, trends on the monetary side were quite the other way. Aggregate monetary spending grew at a faster rate than last year; this is what emerges, whether we take money supply with the public or aggregate monetary resources as an index of total monetary expenditure in the economy. In conjunction with supply limitations, such an increase in monetary spending could only be consistent with higher prices.

23. Continuation of procurement prices at the previous year's level had the effect of preventing price declines when

the new rabi crop arrived in the market. Thus, when the supply position in the market was one of surplus, procurement operations of the Food Corporation of India virtually provided a floor to the farmer's selling price. Urban consumers, therefore, could not benefit from lower prices when adequate supplies were available in the market and the situation for them has worsened recently. In recent weeks owing largely to a short supply in coarse grains as well as to some drought demand to the current year's khariff crop prospects, market prices of wheat along with those of other foodgrains have rise to levels somewhat higher than procurement prices. It is to be noted that small farmers, those who had little or no surplus to sell, or who, having sold part of the output earlier were obliged to buy when prices had gone up, were unable to benefit in this situation. Against this background and in view of the recent price increases, it is all the more important that larger releases through regulated channels are made to prevent further rise in consumer prices. Furthermore, the maintenance of current levels of procurement prices has created the problem of inter-crop imbalances resulting in a shift recently of acreage away from pulses and certain cash crops such as cotton which also are important.

24. The basic point here is that a situation has been created where a decline in production gets immediately reflected in a rise in prices whereas increase in production does not result in a commensurate benefit to the consumer. It may be added that sharp fluctuations in the output and prices of cash crops like raw cotton and raw jute also adversely affect industrial output and balance of payments. Hence the thrust of policy in administering the prices of different commodities should clearly be in the direction of maintaining them at stable levels; but in deciding what these levels should be, it is necessary to keep in mind the income requirements of farmers as well as the interests of the consumer.

BUDGETARY OPERATIONS*

Combined Position of Central and State Governments

25. We turn now to trends in the components of aggregate national expenditure, increases in which contributed to the price situation described above. Starting with the operations of the Central and State Governments, their overall budget deficit@ amounted to Rs. 631 crores** in 1971-72, thus showing a considerable deterioration from the position in 1970-71 (accounts) when the overall deficit amounted to Rs. 431 crores. Compared to the budget estimates for the year, the 1971-72 deficit was higher by Rs. 244 crores. This divergence from the anticipated magnitude arose not because receipts were less but because total disbursements were much greater than originally budgeted. For 1972-73, after taking into account the yield from additional measures for resource mobilization, the combined overall deficit is estimated at Rs. 242 crores (Table 3).

Trends in Disbursements†

26. Total disbursements (including loans and advances) of the Central and State Governments which had increased by 11.4 per cent in 1969-70 and 9.5 per cent in 1970-71 shot

*Figures in this Section relate to fiscal years; figures for 1971-72 refer to revised estimates, unless mentioned otherwise.

@ The above figures of the deficit of the Centre are as given in the budget papers; for the concept of the States' deficit, see footnote to paragraph 28.

**On the basis of final accounts the deficit was larger.

†Figures in this paragraph have been adjusted for conversion of loans into equity and transfer to Contingency Fund of India. (See footnote 2 to Table 3 on page 8).

Table 3:—Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments

(Amounts in Rupees Crores)

	1970-71 (Accounts)		1971-72 (Budget Estimates)*		1971-72 (Revised Estimates)			1972-73 (Budget Estimates)*		
	Amount	Per cent increase (+)/decrease (—) over the previous year	Amount	Per cent increase (+)/decrease (—) over the previous year	Amount		Per cent increase(+)/decrease(—) over the previous year	Amount		Per cent increase(+)/decrease (—) over the previous year
I. Total Receipts (A+B)	**85,64**	**+4.1**	**94,32**	**+10.1**	**1,01,32**	**(98,50)**	**+18.3 (+15.0)**	**10581,**	**(10,651)**	**+4.4 (+8.1)**
A. Revenue Receipts of which:	59,58	+10.5	66,65	+11.9	70,43		+18.2	78,42		+11.3
Tax Recepits	47,35	+13.2	52,61	+11.1	55,16		+16.5	63,22		+14.6
B. Capital Receipts	26,06	+8.1	27,67	+6.2	30,89	(28,07	+18.5 (—7.7)	27,39	(28,09)	—11.3 (+0.1)
II. Total Disbursements of which :	**89,95**	**+9.5**	**98,19**	**+9.2**	**1,07,63**	**1,04,81)**	**+19.7 (—16.5)**	**1,08,23**	**(10,893)**	**+0.6 (+3.9)**
Developmental outlay (a+b)	35,90	+14.3	41,48	+15.5	44,27	(42,15)	+23.3 (+17.4)	46,38		+4.8(+10.0)
(a) Revenue	24,00	+14.0	27,54	+14.8	28,25		17.7	31,23		+10.5
(b) Capital	11,90	+15.0	13,94	+17.1	16,02	(13,90)	+34.6 (+16.8)	15,15		—5.4 (+9.0)
Non-Developmental Outlay (a+b)	36,75	+12.1	37,39	+1.7	44,72	(44,02)	21.7 (+19.8)	42,92	(43,62)	—4.0) (—0.9)
(a) Revenue	33,66	+6.6	35,93	+6.7	42,64		+26.7	42,16		—1.1
(b) Capital	3.09	+153.3	1,46	+52.8	2,08	(1,38)	—32.7 (—55.3)	76	(1,46)	—63.5 (+5.8)
III. Overall Surplus (+) Or Deficit(—)(I—II).	**—4,31**		**—3,87**		**—6,31**			**—2.42**		

Notes:— 1. Figures are adjusted for inter-Governmental transfers. The combined overall position, however, remains unchanged.

2. Figures in brackets exclude national capital receipts/disbursements on account of conversion of loan of Rs. 212 crores to public sector undertakings into equity caiptal (during 1971-72) and of Rs. 70 crores under the Contingency Fund of India (during 1971-72 and 1972-73).

3. The figures of total receipts, capital receipts and overall surplus/deficit as given in this Table and Table 4 would not be comparable with those given in previous Annual Reports since beginning from this year net ways and means advances and overdrafts from RBI (as per State budgets) are treated as financing items and not as capital receipts as was done earlier.

* Includes effects of budget proposals.

up by 16.5 per cent to Rs. 10,481 crores in 1971-72. Developmental outlay which was anticipated in the budgets of 1971-72 to rise by 15.5 per cent actually rose by 17.4 per cent. But the increase in non-developmental outlay was much sharper; instead of rising by 1.7 per cent it went up by 19.8 per cent. This rise in non-developmental expenditure was mainly on account of additional expenditures on defence, refugee relief and famine relief, which together accounted for Rs. 560 crores of the increase over the original provision. Budget estimates for 1972-73 have provided for a step-up in developmental outlay of 10 per cent and a decline in non-developmental outlay of about 1 per cent. The lower percentage increase in developmental outlay budgeted for 1972-73 is mainly due to the smaller rise in the provisions made by State Governments for education, agriculture, medical and public health and civil works.

Trends in Receipts

27. On the receipts side there was a large rise under both tax and capital receipts. Aggregate tax receipts which had increased by 12.2 per cent in 1969-70 and 13.2 per cent in 1970-71 rose further by 16.5 per cent in 1971-72; Central taxes (inclusive of States' share) increased by larger percentage (20 per cent) in 1971-72 than the States' own tax revenue which rose by 10.2 per cent.

Budgetary Operations of the State Governments—1971-72

28. The combined budgetary deficit* of all the States was Rs. 246 crores in 1971-72—Rs. 92 crores higher than anticipated (Table 4). This was in spite of the fact that the aggregate receipts of the States increased by 21 per cent to Rs. 6313 crores, compared to an increase of a little more than 7 per cent anticipated in the budget. Whereas their own revenue receipts were only slightly higher than anticipated in the budget, resources transferred from the Centre (including gross loans) were very much larger. One reason for this was the special assistance provided by the Central Government to some of the States. In spite of this, the deficit increased because aggregate disbursements which were anticipated to be Rs. 5745 crores in the budget were actually higher by Rs. 814 crores. An important factor contributing to this rise was a sharp increase of Rs. 335 crores in non-developmental outlay because of additional expenditure (Rs. 126 crores) on famine relief by some States. Six States viz., Maharashtra,

*The withdrawal from cash balances, net sales of securities held by States in their cash balances investment account, net transfer from Revenue Reserve Funds of States and budget figures of net increase in ways and means advances and overdraft from the Reserve Bank of India.

Table 4:—Overall Budgetary Position of States

(Amounts in Rupees Crores)

	1970-71 (Accounts)	1971-72 (Budget (Estimates)†	Percentage increase of (2) over 1	1971-72 (Revised Estimates)	Percentage increase of (3) over 1	1972-73 (Budget Estimates)*	Percentage increase of (4) over 3
	(1)	(2)		(3)		(4)	
I. Aggregate Receipts (A+B)	**52,14**	**55,91**	**+7.2**	**63,13**	**+21.1**	**65,26** (66,43)	**+3.4**
A. Revenue Receipts (i+ii)	35,19	40,26	+14.4	42,25	+20.1	44,62 (45,79)	+5.6
(i) States' Own Revenue Receipts	21,97	24,17	+10.0	24,24	+10.3	26,46 (27,15)	+9.2
Of which : Tax receipts	15,28	16,42	+7.5	16,84	+10.2	18,53 (19,17)	+10.0
(ii) Resources transferred from the Centre (a+b)	13,22	16,09	+21.7	18,01	+36.2	18,16 (18,64)	+0.8
(a) Shared Taxes	7,56	9,01	+19.2	9,31	+23.1	10,10 (10,58)	+8.5
(b) Grants from the Centre	5,66	7,08	25.1	8,70	+53.7	8,06	—7.4
B. Capital Receipts (i+ii)	16,95	15,65	—7.7	20,88	+23.2	20,64	—1.1
(i) States' Own Capital Receipts of which : Market borrowings (Gross)	6,90 1,65	7,54 1,52	+9.3 —7.9	7,71 1,75	+11.7 +6.1	8,62 1,88	+11.8 +7.4
(ii) Loans from the Centres (Gross)	10,05	8,11	— 19.3	13,17	+31.0	12,02	—8.7
II Aggregate Disbursements	**53,60**	**57,45**	**+7.2**	**65,59**	**+22.4**	**66,33**	**+1.1**
Of which:							
(a) Developmental outlay	25,75	29,70	+15.3	30,65	+19.0	33,41	+9.0
(b) Non-developmental outlay.	15,19	16,50	+8.6	19,85	+30.7	19,20	—3.3
(c) Repayment of loans to the Centre	6,34	5,64	—11.0	8,13	+28.2	7,85	—3.4
(d) Loans and advances to third parties	4,91	4,37	—11.0	5,81	+18.3	4,53	—22.0
(e) Repayments of market loans	59	75	+27.1	77	+30.5	84	+9.0
III. Overall Surplus (+) or Deficit (—) (I—II)	**—1,46**	**—1,54**		**—2,46**		**—1,07** (+10)	

Notes : (1) Figures given here do not tally with those given in the budget papers as certain adjustments have been made. (2) See footnote 3 of Table 3.

† Include the effect of budget proposals. *Figures in brackets are after taking into account estimated yield from budget proposals by States and their share in additional taxation proposed by the Centre during 1972-73.

Orissa, Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh spent as much as Rs. 110 crores more for this purpose. Developmental outlay, on the other hand, was stepped up by Rs. 95 crores. Other disbursements showed a rise of Rs. 384 crores over the budget estimates mainly under the repayment of loans to the Centre (Rs. 249 crores) and loans and advances to third parties (Rs. 144 crores).

Overdrafts by States

29. Mention was made in the last year's Report about the persistent overdrafts of certain State Governments with the Reserve Bank of India. During 1971-72 (July-June), the position worsened in this respect. Outstanding overdrafts of 11 States which aggregated Rs. 371 crores as on June 28, 1971 (as against Rs. 82.7 crores on June 27, 1970 for 6 States) reached a level of Rs. 642 crores at the end of April, 1972 with as many as 12 States having overdrawn on their accounts. Although this figure reflected to some extent the results of the repayment of the ways and means advances obtained from the Central Government for clearing the overdrafts in the earlier years, the further additions to the total amount caused serious concern in view of the wider repercussions on financial balance in the economy of the unauthorised and unregulated borrowings by the State Governments from the Reserve Bank. At the same time, provision had to be made for meeting, the genuine needs of State Goverments, particularly in view of the rather limited flexibility in their potential in raising financial resources. The Central Board took an opportunity to raise with the Union Finance Minister the problem of the heavy overdrafts of the States and the need to put an end to them. The question was discussed by the Union Finance Minister with the Chief Ministers/Governors of the State Governments concerned. Following these discussions and consultations between the Reserve Bank of India, the Ministry of Finance and the Planning Commission, a new policy on overdrafts was subsequently formulated.

30. The new scheme which came into force with effect from May 1, 1972 required that overdrafts be discontinued from end-April, 1972. In view of the increased volume of budgetary transactions of State Governments, the limits for clean or unsecured ways and means advances from the Reserve Bank were enchanced with effect from that date to four times the previous levels. This is in addition to what they can get from secured advances. Overdrafts of all the 12 States on the books of the Reserve Bank were cleared as at the close of business on April 30, 1972. As many as 10 States were granted special ways and means advances totalling Rs. 416 crores by the Centre to clear their overdrafts, while the balance was adjusted against plan assistance (Rs. 32 crores) and payment on account of States' share of income tax (Rs. 195 crores) released as on April 30, 1972.

31. Under the new policy no overdrafts are allowed by the Reserve Bank except for purely temporary periods of not more than seven days. In the event of any State Government's overdraft continuing to exceed seven days, suspension of payment on behalf of the concerned State has been made automatic. These steps which represent a tightening of treasury control over States are expected to contain the expenditure, plan and non-plan, of the State Governments within available resources.

32. Since May 1, 1972, no State Government has overdrawn its account with the Reserve Bank of India continuously for a period of more than seven days and even within this period, the amounts actually overdrawn from time to time were mariginal. These occasional overdrafts were due to the fact that disbursements by the State Governments concerned could not be exactly anticipated. They were, however, invariably cleared within the time limit of seven days. While the new policy has thus been successful and effective, a permanent improvement in the financial position of the States will also be necessary. Some of the States have recently announced measures for the mobilisation of additional resources.

33. The problems relating to State finances have to be viewed in the context of resources needed for both plan and non-plan outlays. The Sixth Finance Commission appointed at the end of June, 1972 will be examining a whole range of questions in this regard. The terms of reference of the Commission are much wider than in the past. The Commission is expected, for example, to assess the non-plan capital resources of the States, the burden of the revision of salaries of State Government servants as well as the employees of local bodies and the cost of servicing the loans obtained from the Central Government upto the end of the financial year 1973-74. It is also expected to review the policy and arrangements regarding relief expenditure in the States, which are affected by natural calamities. It is expected that the Commission's report will be available by the end of October, 1973.

Budgetary Operations of Central Government—1971-72

34. Turning to the Central Government's budgetary operations in 1971-72, there was a sharp rise in total expenditure which increased over the year by Rs. 1146 crores to Rs. 6722 crores* (Table 5). To meet this higher level of expenditure, a large effort to mobilise additional resources was made through imposition of fresh taxation in October and December, 1971. In the event total revenue receipts of Government administration at Rs. 3819 crores were about 11 per cent higher than estimated in the budget of which tax revenue at Rs. 2881 crores showed an improvement of Rs. 181 crores (or 6.7 per cent) over the budget anticipation. External assistance for refugee relief exceeded budget anticipation by about Rs. 100 crores.

35. The improvement in receipts was more than offset by a rise in non-developmental expenditure which showed a rise of 23 per cent over the previous year in contrast to an anticipated decline of 6 per cent. This was caused by the expenditure on refugees, defence and additional assistance to some State Governments especially for famine relief. Developmental expenditure, on the other hand, declined slightly as compared to budget estimate. This was in contrast to the position of State Governments whose developmental expenditure was higher than budgeted. In terms of capital formation, actual outlays by the Centre fell short of the budgeted amount by Rs. 42 crores. Savings of Government administration *i.e.*, the difference between revenue receipts and current expenditure, turned out to be only Rs. 95 crores as against the budget anticipation of Rs. 242 crores (Table 6). All of these adjustments were reflected in a deterioration in the Centre's budgetary position, with the overall deficit increasing very substantially as compared with Rs. 233 crores estimated in the budget.

Budget for 1972-73—Centre

36. The budget for 1972-73 aims at enlarging the amount of capital formation and the contribution of Government to the total savings pool, thus reversing to 1971-72 position. The public sector Plan outlay is to rise by 22 per cent or Rs. 710 crores, raising it to Rs. 3973 crores. The Plan provision in the central budget at Rs. 2569 crores† anticipates a rise of 14.7 per cent over 1971-72 budget estimate. Savings of the Government administration are also expected to rise over four-fold; non-developmental expenditure is to decline by 7.6 per cent and developmental expenditure show an increase of 13.4 per cent. In other words, developmental expenditure which constituted about 47 per cent of total expenditure in 1971-72 is expected to reach 52 per cent in 1972-73. In accordance with the priorities of the Plan, expenditure on social services (*e.g.*, social welfare schemes such as those relating to rural unemployment, rural water supply, rural housing, etc.) as a proportion of total expenditure would go up from 7.4 per cent to 9.7 per cent. Gross capital formation including financial assistance for capital formation at Rs. 2441 crores is expected to be 12 per cent higher and constitute 36 per cent of total expenditure as against 32 per cent in 1971-72. Despite the anticipated increase in

*The figures relating to expenditure (other than plan provision) and receipts of the Central Government referred to here are based on an Economic and Functional Classification of Central Government Budget, Ministry of Finance, Government of India.

†Inclusive of internal resources of departmental undertakings and other resources, Plan provision will be Rs. 2,844 crores.

Table 5 :—Developmental and Non-Developmental Expenditure of the Central Government

(Amounts in Rupees Crores)

	1970-71 (Accounts)		1971-72 (Budget Estimates)		1971-72 (Revised Estimates)		1972-73 (Budget Estimates)	
	Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year	Amount	Per cent variation over the previous year
Total expenditure (A+B)	5576*	+13.2	5874	+5.3	6722	+20.6	6869	+2.2
A. Developmental Expenditure (i+ ii)	2659 (47.7)	+13.0	3136 (53.4)	+17.9	3124 (46.5)	+17.5	3544 (51.6)	+13.4
(i) Social Services	364 (6.5)	+19.7	578 (9.8)	+58.8	495 (7.4)	+36.0	663 (9.7)	+33.9
(ii) Economic Services	2295 (41.2)	+12.0	2558 (43.6)	+11.5	2629 (39.1)	+14.6	2881 (41.9)	+9.6
B. Non-Developmental expenditure (i+ii)	2917 (52.3)	+13.4	2738 (46.6)	—6.1	3598 (53.5)	+23.5	3325 (48.4)	—7.6
(i) General Services	1777 (31.9)	+19.2	1627 (27.7)	—8.4	1898 (28.2)	+6.7	1909 (27.8)	+0.6
(ii) Unallocable	1140 (20.4)	+5.5	1111 (18.9)	—2.6	1700 (25.3)	+49.2	1416 (20.6)	—16.7

Notes : Figures in brackets are percentages to total expenditure.

*Include compensation paid to nationalised bank estimated at Rs. 84 crores and additional subscription to I.M.F. and I.B.R.D. paid in the form of non-negotiable non-interest bearing rupee securities estimated at Rs. 114 crores.

@Include block grants and loans.

Table 6 :—Savings of the Central Government

(Amounts in Rupees Crores)

	1970-71 (Accounts)	1971-72 (Budget Estimates)	1971-72 (Revised Estimates)	1972-73 (Budget Estimates)	Per cent variation of Col. 4 over Col. 3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Revenue Receipts of Governmen			3819	4210	10.2
(i) Tax Revenue			2881	3320	15.2
(ii) Non-tax Revenue			938	890	+5.1
2. Current Expenciture	2909	3209	3724	3724	—
3. Savings of the Government Administrasion (1—2)	224	242	95	486	+411.6
4. Depreciation Provision and Retained Profits of Departmental Commercial Undertaking (i+ ii)	179	193	211	255	+20.9
(i) Depreciation Provision	123	131	129	137	+6.2
(ii) Retained Profits	56	62	82	118	+43.9
5. Gross Savings of the Central Government (3+4)	403	435	306	741	+142.2
6. Expenditure on Renewals and Replacements	91	100	95	120	+26.3
7. Net Savings (5—6)	312	335	211	621	+194.3
8. Net investment	428	542	516	604	+17.1
9. Excess (+) or shortfall (—) of Net Savings over Net investment (7—8)	—116	—207	—305	+17	
10. Item 3 as per cent of Item 1	7.1	7.0	2.5	11.5	

expenditure in 1972-73, additional net financial liabilities are expected to be lower than in 1971-72. Additional expenditure in 1972-73 is expected to be financed by an increase in revenue receipts of the order of Rs. 391 crores (10.2 per cent over 1971-72); tax revenue at Rs. 3320 crores is projected to show an increase of 15 per cent and non-tax revenue a decline of 5 per cent.

37. The additional resource mobilisation during 1972-73 may be viewed along with the expected revenue from tax measures implemented in 1971-72. Total yield from the 1971-72 measures (including States' share and resources raised by Railways and Posts and Telegraphs) is estimated at Rs 500 crores in a full year, an unprecedented rise in a single year; combined with measures taken during 1972-73 the total may be expected to exceed Rs. 650 crores in the current year. Consequently, savings of the Government administration are placed at Rs. 486 crores in 1972-73, a rise of Rs. 391 crores over 1971-72. In other words, savings of Government administration are to constitute 11.5 per cent of revenue receipts, as against 2.5 per cent in 1971-72. Besides, retained profits and depreciation provision of departmental undertakings are anticipated to be of the order of Rs. 255 crores in 1972-73; thus total gross savings of the Central Government would rise to Rs. 741 crores from Rs. 306 crores in 1971-72. Net savings of the Central Government (gross savings minus expenditure on renewals and replacements) estimated at Rs. 621 crores in 1972-73 would exceed direct net investment by Rs. 17 crores.

States

38. The major features of the State budgets for 1972-73 are: (*a*) Aggregate receipts (at 1971-72 rate of taxation) which had increased by about 21 per cent in 1971-72 are expected to show a rise of 3.4 per cent in 1972-73. States' own tax receipts show a rise of 10 per cent, the same as in 1971-72. Capital receipts, however, show a marginal fall of 1.1 per cent due to a decline of Rs. 115 crores in loans from the Central Government, as against a rise of Rs. 312 crores in 1971-72. This decline was partly offset by increases in market borrowings, recovery of loans from third parties and loans from autonomous bodies. (*b*) Aggregate disbursements which had increased by more than 22 per cent in 1971-72 are budgeted to rise marginally by 1.1 per cent in 1972-73. Developmental outlay is to rise by 9 per cent while non-developmental outlay would decline by about 3 per cent. The overall deficit of State Governments is expected to amount to Rs. 107 crores. If allowance is made for Rs. 69 crores expected from the additional measures proposed by some States and their share of Rs. 48 crores in the Centre's fresh tax efforts, this overall deficit would be converted into a surplus of Rs. 10 crores.*

Market Borrowings

39. It will be seen from the above discussion that a fairly large part of the sharp increase in expenditure in 1971-72 was met by additional tax mobilisation. In this context mention should be made also of the borrowings by the Central and State Governments. The combined net receipts of the Central and State Governments from such borrowings amounted in 1971-72 to Rs. 396 crores—*i.e.*, Rs. 161 crores more than in 1970-71. The entire increase was in the net borrowings of the Centre, the States' borrowings increasing only by Rs. 1 crore. In fact, net market borrowing of the Centre during 1971-72 at Rs. 295 crores was Rs. 127 crores more than what had been budgeted. A special feature of the Centre's borrowing programme in 1971-72 was the issue of three National Defence Loans following the declaration of emergency in December, 1971, subscriptions to which were received only in cash and aggregated Rs. 111 crores. For 1972-73, the Centre's borrowing programme originally envisaged gross receipts of Rs. 515 crores or Rs. 215 crores net. In the first phase of market floatation in July, 1972 the Centre raised Rs. 132 crores (net) from market borrowings. In view of the recent trends in deposits and advances of the banking system, the Centre decided to increase the gross market borrowings for 1972-73 to Rs. 565 crores notified (with the right to retain upto Rs. 623 crores of subscripstion) or a net amount of Rs. 323 crores—which would mean an increase of about Rs. 100 crores over the budget estimates. The State Governments' borrowings in 1972-73 are also expected to be higher at Rs. 133 crores as compared to Rs. 101 crores in 1971-72. Under small savings the net collections in 1972-73 are expected to be Rs. 230 crores as against Rs. 210 crores in 1971-72.

Savings and Investment

40. Together with other receipts on capital account these funds made it possible for the Centre to finance—both directly and through assistance to States, Union Territories, and non-departmental undertakings—net capital formation of Rs. 2081 crores in 1971-72. This represents an increase of Rs. 368 crores over the comparable amount for 1970-71 (Table 7).

*This overall surplus in 1972-73 would be higher if receipts from market loans to be floated by Maharashtra are taken into account. No credit has been taken by this State in its budget on this account.

Table 7 :—Expenditure on Capital Formation by Government of India

(Amounts in Rupees Crores)

	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72 (R.E.)	1972-73 (B.E.)
1. Gross Capital Formation	**276**	**393**	**519**	**611**	**724**
(a) Fixed Capital Formation	449	430	485	592	757
(b) Inventaries	—173	—37	34	19	—33
2. Net Capital Formation (i.e., excluding expenditure on renewals and replacements)	**193**	**318**	**428**	**516**	**604**
3. Financial Assistance for Capital Formation	**1,384**	**1,219**	**1,285***	**1,565**	**1,717**
(a) to States, Union Territories, etc.	761	775	837	1,007	1,043
(b) to non-departmental commercial undertakings	**623**	**444**	**448**	**558**	**674**
(i) Financial	..	42	70	71	103
(ii) Others	..	402	378	487	571
Total (2+3)	**1,577**	**1,537**	**1,713**	**2,081**	**2,321**

*Excluding compensation paid to nationalised banks.

41. Similar expenditure on net capital formation by the Government of India for 1972-73 is estimated at Rs. 2321 crores, or Rs. 240 crores more than in the last fiscal year.

42. Comparable data on savings and expenditure on capital formation in the States are not at present available and hence it is not possible to give any estimates for the public sector as a whole. It will, however, be seen from Table 4 that *total* developmental outlay (on both revenue and capital accounts) of State Governments in 1971-72 was only Rs. 490 crores higher than in the previous year. Since the major element in States' developmental expenditure is current outlay on education public health, civil works, etc. only a small portion of this increase consists of outlay on capital formation. And most of such capital formation was financed by capital transfers from the Centre; on their own account, the States probably contributed little by way of an addition to public sector savings.

43. Coupled with the heavy losses suffered by the large public undertakings, such as Hindustan Steel, Heavy Engineering Corporation and Heavy Electricals, it seems very likely that public savings declined both absolutely and relatively. However, based on larger loans and grants from the

Centre, as well as overdrafts, the States and non-departmental undertakings apparently maintained, and perhaps increased somewhat, their investment outlays.

44. In the private sector also, it would appear from available indicators that the magnitude of investment was probably higher in 1971-72 than in the previous year. There was a rise in the consents sanctioned to non-banking public limited companies for new capital issues. The market for such issues also showed some recovery from the sluggishness observed in the previous year; public response was encouraging and some of these issues were over-subscribed. Loans sanctioned and disbursed by term-lending institutions showed a further increase during the year. In the agricultural sphere, the aggregate of finance for investment available from Agricultural Refinance Corporation, Agricultural Finance Corporation, Rural Electrification Corporation and drawals from Reserve Bank's medium-term loans and debentures floated by central land mortgage banks during the year (July 1971-June 1972) shows that the rising trend in the tempo of investment in agriculture has been maintained (Table 8).

45. The main point which emerges from the preceding paragraphs is this. While public saving was smaller in 1971-72 than previously, public investment expenditure increased somewhat. From available indicators, it would also appear that private sector investment probably rose particularly in agriculture and small industries. Apart from any small increase in corporate savings which may have occurred, the bulk of the increase in investments was financed partly by an inflow of foreign savings, but mostly by a rise in the savings of household sector, particularly in the form of financial assets.

46. The increase in household savings in the form of financial assets was evident in the growth of deposits, currency holdings, contributions to provident funds and life insurance, small savings and subscriptions to capital issues of companies. This development is particularly noteworthy because it implies a greater flexibility in the deployment of savings in the economy. For a better appreciation of this feature, it is necessary to look at the details of the variations on the monetary side.

Monetary and Banking Developments

Trends in Money Supply and Monetary Resources

47. Monetary trends in 1971-72 (July-June) show an acceleration in the rate of expansion both of money supply with the public and aggregate monetary resources. Money supply with the public expanded by 13.6 per cent in 1971-72 as against 12.5 per cent in the previous year; corresponding rates of expansion of aggregate monetary resources were 16.2 per cent and 14.3 per cent, respectively. A notable feature of the expansion in money supply during the year was that, unlike in the previous year, the increase in deposit money (Rs. 592 crores) was considerably larger than that in the currency component (Rs. 423 crores).

48. The dominant factor behind this monetary expansion was the striking increase of Rs. 1176 crores in net bank credit to Government (as against Rs. 931 crores in 1970-71) reflecting the widening budgetary gap referred to in earlier paragraphs.* External transactions of the banking system resulting in a net rise of Rs. 29 crores in foreign exchange assets (which had declined by Rs. 95 crores last year) also contributed to a small increase in money supply. Increase in total bank credit to the commercial sector at Rs. 788 crores was larger than in the previous year by Rs. 67 crores. However, since credit extended to the commercial sector was higher than the amount of time deposits (Rs. 786 crores) mobilised by banks by only Rs. 3 crores, the expansionary impact of net bank credit to commercial sector on money supply was quite nominal (Table 9).

Seasonal Trends

49. These features of the monetary situation were also reflected in seasonal trends. During the traditional slack season of 1971 (May to October) money supply with the public registered for the second successive year an expansion, which at Rs. 162 crores was somewhat larger than in the previous slack season. The entire increase was in deposit money, with currency component showing a decline. As will be seen from Table 10, this expansion resulted mostly from additional bank credit to Government and to a small extent from increase in foreign exchange assets. Net bank credit to commercial sector exerted a contractionary effect on money supply.

50. The expansion in money supply during the busy season of 1971-72 (November 1971-April 1972) at Rs. 779 crores (10.5 per cent) was substantially larger than Rs. 581 crores (8.7 per cent) in the previous busy season. While the increase in currency component was higher than that in the previous year busy season, the growth in deposit money was nearly twice as much. Again, the increase in net bank credit to Government at Rs. 820 crores was larger than in the previous busy season. The rise in net bank credit to the commercial sector was, however, much smaller than that in the previous busy season, attributable mainly to a decline of Rs. 71 crores in food procurement credit (Table 10).

51. Money supply with the public registered an expansion in the first two months of the 1972 slack season as in the corresponding period of the previous slack season. A substantial expansion in net bank credit to Government was the principal factor accounting for this increase. A small increase in net bank credit to commercial sector as against a decline during the corresponding period of last year also contributed to the rise in money supply.

Trends in components of money supply and aggregate monetary resources

52. A noteworthy feature during the last three years has been the declining proportion of currency in the increase in money supply. Thus, of the increase in money supply, currency formed 71 per cent in 1968-69*; the proportion has steadily declined since then to 47 per cent in 1971-72 (Table 11). The same trend emerges if the rate of expansion of currency is compared with that of aggregate monetary resources (Table 12). Another aspect which deserves notice is that of the two components (i.e. current deposits and demand portion of saving deposits) of bank money, the rate of increase in savings deposits has been higher than that of current deposits over a period of years. In 1971-72 total bank money formed 53 per cent of the increase in money supply; of this increase, saving deposits constituted 35 per cent and current deposits only 17 per cent. A slower increase in the rate of currency expansion can be explained by two factors. In line with growing economic activity especially in the agricultural sector, the transactions demand for currency has increased in the aggregate. Simultaneously, and again in the rural areas particularly, a section of the population which was accustomed to keep its savings in the form of currency has apparently developed the banking habit. This is evidenced by the growing proportion of saving deposits relative to bank money. In other words, along with the rapid expansion of banking services in the country, there is a change in the asset preferences of the public from currency to deposits. Whether this is attributable more to the feeling of security engendered by the nationalization of banks than to the attraction of interest yields, it is difficult to say. Perhaps both have contributed to this change of habit and require to be borne in mind in the formulation of banking policies.

Banking Trends and Credit Policy

Annual Variations: July 1971-June 1972

53. Another significant development during 1971-72 was the highly liquid position attained by the banking system due to the accretion of deposits at a rate faster than that of expansion of bank credit. Aggregate deposits of scheduled commercial banks (at current prices) increased by Rs. 1307 crores or at an unprecedented rate of 21 per cent as against Rs. 942 crores or 17.9 per cent in 1970-71. The higher rate of growth in deposits was influenced among other factors

*Net of some accounting adjustment effected during the year, the increase in net bank credit to Government works out to Rs. 1,101 crores as compared with Rs. 831 crores during 1970-71, while the rise in net foreign exchange assets during 1971-72 was only Rs. 6 crores. These accounting adjustments have not affected figures of 'money supply.'

*Data in this paragraph refer to financial years.

Table 8 :—Institutional Finance for Investment in Agriculture
(July-June)

(Amounts in Rupees Crores)

	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
1. Debentures floated by Central Co-operative Land Mortgage/Development Banks[1]												
(a) Ordinary debentures	9.97	10.50	19.25	23.34	34.81	43.10	52.05	64.51	103.42	114.82	119.49	127.81
(b) Rural debentures	1.55	2.24	1.57	1.84	3.23	4.33	2.93	1.57	5.00	1.10	4.78	5.72
2. Agricultural Refinance Corporation (ARC)[2]												
(a) Number of schemes sanctioned				3	10	24	15	89	108	142	100	269
(b) Total financial assistance				2.72	20.60	17.96	10.53	68.16	79.21	92.78	62.15	154.24
(c) ARC's commitments				2.45	16.88	14.18	8.53	58.64	69.32	70.92	53.92	135.13
(d) Disbursements during the year				—	0.45	4.45	2.08	5.67	17.84	28.60	30.62	34.98
3. Agricultural Finance Corporation (AFC)[3]												
(a) Number of schemes sanctioned									6	21	10	6
(b) Total outlay									61.50	45.70	23.33	25.12
(c) Disbursements during the year									0.96	15.77	13.24	11.22
4. Rural Electrifcation Corporation (REC)												
(a) Number of schemes sanctioned[4]										47+	73†	127
(b) Total outlay										39.91+	49.15†	83.63
(c) REC's commitments										28.95+	48.82†	73.25
(d) Disbursements during the year											26.09†	36.81
5. Reserve Bank of India—Medium-term Loans												
(a) Amount sanctioned	4.68	9.56	9.31	14.01	14.39	14.11	15.49	16.57	19.00	18.30	18.76	20.62
(b) Drawals during the year	5.69	7.39	4.18	7.45	7.91	7.45	8.37	9.12	8.98	11.48	14.20	6.15@

Note : In this table figures of investment finance extended by the following institutions are not included because these are not available.

(a) Term finance to agriculture extended by commercial banks other than by way of contribution to the debentures floated by central co-operative land mortgage/development banks and participation with the Agricultural Finance Corporation.

(b) Investment finance provided by co-operative credit agencies out of their owned funds.

1. Co-operative land mortgage/development banks also floated special development debentures to the extent of Rs. 18.00 lakhs in 1961-62, Rs. 5.41 lakhs in 1963-64, Rs. 1.45 lakhs in 1965-66, Rs. 1.23 lakhs in 1966-67, Rs. 0.32 lakh in 1967-68 and Rs. 0.18 lakh in 1968-69. While the first series of special development debentures were floated prior to the inception of ARC, the remaining series were those not falling under ARC schemes.

2. The operations reflect schemes sanctioned during the year after excluding schemes withdrawn during the same year.

3. The data presented relate to schemes sanctioned during the year after taking into account withdrawals of schemes/changes in outlays, if any, during the same year but without taking into account cancellation of schemes and changes in outlays, if any, subsequently. After taking into account these factors, since its inception, i.e. from April 10, 1968 to June, 30, 1972, the Corporation sanctioned 39 schemes involving a total outlay of Rs. 153.20 crores and disbursed an amount of Rs. 41.19 crores.

4. Of these, three schemes in 1969-70 and two in 1970-71 related to Rural Electric Co-operatives.

†Revised.

@The amount drawn against the Reserve Bank's medium-term credit limits during 1971-72 is lower as compared with the preceding year mainly because according to the revised arrangement, the limits for 1971-72 are allowed to be drawn upon till December 1972.

Table 9 :—Trends in Money Supply and Monetary Resources (Annual)

(Amounts in Rupees Crores)

	Outstandings at End-June			Variations during July-June	
	1970	1971	1972	1969-70	1970-71	1971-72
1. Currency with the Public	41,70	45,91	50,14	+3,81	+4,21	+4,23
2. Demand Deposits	24,65	28,71	34,63	+2,11	+4,06	+5,92
3. Money Supply (1+2)	66,34	74,62	84,78	+5,91	+8,28	+10,16
4. Time Deposits	30,98	36,60	44,46	+4,19	+5,62	+7,86
5. Aggregate Monetary Resources (3+4)	97,33	1,11,22	1,29,24	+10,11	+13,89	+18,02
6. Net Bank Credit to Government	48,24	57,55	69,31	+2	+9,31	+11,76
7. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	6,64	5,69	5,98	+2,64	—95	+29
8. Government's Net Currency Liabilities to the Public	3,74	3,95	4,05	+20	+21	+11
9. Total (6+7+8)	58,62	67,19	79,34	+2,86	+8,57	+12,15
10. Bank Credit to Commercial Sector*	50,27	57,48	65,36	+7,55	+7,21	+7,88
(a) Net Bank Credit to Commercial Sector*	19,29	20,87	20,90	+3,36	+1 58	+3
11. Net Non-Monetary Liabilities of Reserve Bank of India (Increase—)	6,40	8,17	10,66	—50	—1,77	—2,49
12. Net Non-Monetary Liabilities of other Banks (Increase—)	5,17	5,27	4,82	+29	—10	+45
13. Total (9+10)	1,08,89	1,24,67	1,44,70	+10,41	+15,78	+20,03

*Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes.

Note : Net of some accounting adjustments effected during the year, the increase in 'net bank credit to Government' works out to Rs. 1101 crores as compared with Rs. 831 crores during 1970-71. These accounting adjustments have not affected figures of 'money supply', since adjustments have been so made as to neutralise the expansionary influence of one by the contractionary influence of another. However, they have, in effect, overstated net bank credit to Government sector by Rs. 75 crores during 1972-72 and Rs. 100 crores during 1970-71 (July-June) and resulted in appreciation of net foreign exchange assets by Rs. 23 crores during 1971-72. The non-monetary liabilities of the Reserve Bank of India acted as a contractionary factor to the tune of Rs. 98 crores during 1971-72 and Rs. 100 crores during 1970-71.

Table 10 : Trends in Money Supply and Monetary Resources (Seasonal)

(Amounts in Rupees Crores)

	Variations during			
	Slack Season		Busy Season	
	1970	1971	1970-71	1971-72
1. Currency with the Public	—35	—33	+4,05	+4,42
2. Demand Deposits	+1,78	+1,93	+1,78	+3 39
3. Money Supply (1+2)	+1,44	+1,62	+5,81	+7,79
4. Time Deposits	+2,77	+4,35	+2,61	+3,08
5. Monetary Resources (3+4)	+4,21	+5,97	+8,42	+10,87
6. Net Bank Credit to Government	+1,11	+3,88	+6,07	+8,20
7. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	+36	+26	—84	+14
8. Government's Net Currency Liabilities to the Public	+6	+6	+16	+7
9. Total (6+7+8)	+1,53	+4,20	+5,39	+8,41
10. Bank Credit to Commercial Sector*	+3,46	+2,49	+4,78	+4,33
(a) Net Bank Credit to Commercial Sector*	+70	—1,87	+2,16	+1,26
11. Net Non-Monetary Liabilities of Reserve Bank of India (Increase—)	+27	—1,01	—1,13	—2,23
12. Net Non-Monetary Liabilities of other Banks (Increase—)	—1,06	+30	—61	+34
13. Total (9+10)	+4,99	+6,69	+10,17	+12,74

*Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes.

Table 11 :—Marginal relationship between Money Supply and its Components

Financial Year	Money Supply	Currency	Bank Money Total	Bank Money Current	Bank Money Savings	Rates of Growth Money Supply	Rates of Growth Currency	Rates of Growth Current deposits of commercial banks	Rates of Growth Demand portion of savings deposits
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Rs. Crores)								
1961–62	+177(100)	58.2	41.8	18.6	19.2	6.2	4.9	6.0	18.6
1962–63	+264(100)	67.4	32.6	15.9	14.0	8.7	8.1	7.2	17.1
1963–64	+442(100)	51.4	48.6	9.5	36.4	13.4	9.5	6.7	63.4
1964–65	+328(100)	49.7	50.3	20.7	30.2	8.7	6.3	10.2	23.9
1965–66	+449(100)	59.0	41.0	12.0	29.6	11.0	9.6	7.4	25.9
1966–67	+421(100)	38.7	61.3	22.6	30.6	9.3	5.4	12.1	19.9
1967–68	+400(100)	44.8	55.2	18.5	30.5	8.1	5.6	8.4	15.7
1968–69	+429(100)	71.3	28.7	12.4	8.6	8.0	9.1	5.5	4.1
1969–70	+608(100)	53.9	45.9	24.8	24.7	10.5	8.9	15.0	16.0
1970–71	+749(100)	49.3	50.7	25.0	27.0	11.7	9.2	16.1	18.6
1971–72	+906(100)	47.0	53.0	17.0	34.7	12.7	9.7	11.4	24.4

Note : 1 Figures in Col (1) are absolute changes over the year ; figures in columns (2) to (5) are % of Col. (1).

2. Current and savings bank money do not add up to total bank money because 'other deposits' with the Reserve Bank and net demand liabilities of state co-operative banks are included in the total.

Table 12 :—Monetary Resources and Currency

(Amounts in Rupees Crores)

Financial Year	Monetary Resources* (excluding P.L. 480)	Currency	Increase in Monetary Resources	Increase in Currency	Currency Monetary Resources (Marginal Ratio) [Col.(4) as % of col. (3)]
	1	2	3	4	5
1961–62	41,02	22,01	3,15	1,03	32.6
1962–63	44,61	23.79	3,59	1,79	55.2
1963–64	49,76	26,05	5,14	2,26	44.0
1964–65	54,77	27,69	5,10	1,63	32.6
1965–66	61,34	30,34	6,57	2,65	40.4
1966–67	68,16	31,96	6,82	1,62	23.8
1967–68	74,60	33,76	6,43	1,79	27.8
1968–69	83,06	36,81	8,45	3,05	36.2
1969–70	93,36	40,10	10,30	3,28	31.9
1970–71	1,05,71	43,79	12,34	3,69	29.9
1971–72	1,22,33	48,06	16,61	4,26	25.6

*Money supply plus time deposits with banks.

by a substantially larger Government deficit in 1971-72 than in 1970-71 and as mentioned above, by the shift in preferences.

54. Total credit extended by scheduled commercial banks during the year expanded by Rs. 614 crores (12.9 per cent) as against Rs. 550 crores (13.1 per cent) in the previous year. Advances for food procurement operations increased by Rs. 164 crores compared to Rs. 172 crores in 1970-71; consequently, excluding food procurement advances, the rise in bank credit during the year under review was of a larger order, viz., Rs. 451 crores (10.3 per cent) as compared to Rs. 378 crores (9.4 per cent) last year (Table 13).

55. Not only was the credit-deposit ratio of commercial banks low in the year under review but their cash ratio was low as well. The improved resources position of banks enabled them to step up their investment in Government and other approved securities as also to reduce their indebtedness to the Reserve Bank. Thus, during the year, banks utilised Rs. 433 crores for increasing their investment portfolio raising their investment deposit ratio to 29.8 per cent at the end of June 1972. Additionally, they repaid Rs. 165 crores to the Reserve Bank of India and brought down the level of their borrowings at the end of June 1972 to as low a level as Rs. 42 crores, as against Rs. 207 crores a year ago. The comfortable liquidity position of commercial banks was also reflected in the reduced call money rates. In Bombay, at the peak level, they were over 3 per cent lower than in the last year. At the end of June 1972, the rate was in the range of 3½—4 per cent as compared to 4½ per cent a year ago.

Table 13 :—Annual Variations in Important Banking Data

(Amounts in Rupees Crores)

	End-June 1969	Variations during the year ended June 1969	End-June 1970	Variations during the year ended June 1970	Percentage increase (+)/decrease (—) over the previous year	End-June 1971	Variations during the year ended June 1971	Percentage increase (+)/decrease (—) over the previous year	End-June 1972	Variations during the year ended June 1972	Percentage increase (+)/decrease (—) over the previous year
1. Total Bank Credit	3598.8	+495.9	4212.7	+613.9	+17.1	4762.9	+550.2	+13.1	5377.1	+614.2	+12.9
of which :											
(a) Food Procurement Advances	233.2	+41.1	206.7	—26.5	—11.4	378.8	+172.1	+83.3	542.3	+163.5	+43.2
(b) Other Advances	3365.6	+454.8	4006.0	+640.4	+19.0	4384.1	+378.1	+9.4	4834.8	+450.7	+10.3
2. Total Investments	1358.9	+198.2	1504.2	+145.3	+10.7	1806.9	+302.7	+20.1	2240.1	+433.2	+24.4
(a) In Government securities	1126.3	+150.7	1186.1	+59.8	+5.3	1375.1	+189.0	+15.9	1664.1	+289.0	+21.0
(b) In other approved securities	232.6	+47.5	318.1	+85.5	+36.8	431.8	+113.7	+35.7	576.0	+144.2	+33.4
3. Cash and Balances with R.B.I.	380.3	+110.8	357.6	—22.7	—6.0	402.9	+45.3	+12.7	447.4	+44.5	+11.0
4. Money at call and short notice	88.1	+37.5	47.9	—40.2	—45.6	82.7	+34.8	+72.7	106.6	+23.9	+28.9
5. Aggregate Deposits	4645.8	+676.8	5274.5	+628.7	+13.5	6216.2	+941.7	+17.9	7523.5	+107.3	+21.0
(a) Demand	2103.5	+228.7	2328.8	+225.3	+10.7	2742.8	+414.0	+17.8	3288.6	+545.8	+19.9
(b) Time	2542.3	+448.1	2945.7	+403.4	+15.9	3473.4	+527.7	+17.9	4234.9	+761.5	+21.9
6. Borrowings from R.B.I.	172.2	+68.7	291.5	+119.3	+69.3	207.2	—84.3	—28.9	42.1	+165.1	—79.1
7. Credit-Deposit Ratio	77.5		79.9			76.6			71.5		
8. Investment-Deposit Ratio	29.3		28.5			29.1			29.8		

Credit Policy for 1971-72 Busy Season

56. The increase in deposits of scheduled commercial banks by a record figure of Rs. 624 crores in the 1971 slack season period enabled the banking system in spite of an expansion in credit of the order of Rs. 163 crores (Rs. 156 crores for food procurement), to conserve funds for deployment in the succeeding busy season (November 1971-April 1972). The banks increased their investments in Government and other approved securities by Rs. 249 crores and reduced their indebtedness to the Reserve Bank by Rs. 172 crores. At the end of the season the level of borrowings from the Reserve Bank was only Rs. 19 crores, as against Rs. 151 crores a year ago and the credit-deposit ratio was much lower (73.1 per cent) than in the previous year (77.0 per cent). With this relatively easy liquidity position at the commencement of the 1971-72 busy season, the banks were well-equipped to meet the demand for advances that was expected to develop However, the large increase in Government indebtedness to the banking system warranted a cautious approach to credit deployment so as not to aggravate the pressure on prices. At the same time, increased defence needs of the economy had to be met and all possible assistance rendered to increase production and maintain distribution. Further, there was also the need to encourage the flow of credit to priority and hitherto neglected sectors as also to expand banking facilities. Credit policy announced at the commencement of the 1971-72 busy season was attuned to these tasks.

57. In the context of the need for credit restraint, the main plank of policy adopted was to minimise the dependence of commercial banks on Reserve Bank finance. Banks were advised that while the refinance entitlements were designed to take care of the peak requirements of borrowings from the Reserve Bank they should resort to such borrowings only for short periods. The Bank also suggested to commercial banks that the level of their borrowings from the Reserve Bank at the end of April, 1972 should not exceed that at the end of April, 1971, *i.e.*, Rs. 191 crores. They were informed that the Bank intended to raise, with effect from the first Friday of August, 1972, the banks' liquidity requirement by 1 percentage point from 28 per cent to 29 per cent, excluding the statutory 3 per cent balances with the Reserve Bank.*

*Banks have accordingly been advised to raise their holdings of liquid assets by 1 percentage point from first Friday of August 1972.

58. While the emphasis in Reserve Bank policy was on *general* credit restraint, measures were also taken to encourage the flow of resources to certain sectors which were in urgent need of credit. In order to support the efforts of authorities to help industrial units in the Eastern region, some of which were in need of special assistance, commercial banks were asked to help the Industrial Reconstruction Corporation of India by providing working capital assistance to the Corporation's client units. Scheduled commercial banks were instructed to liberalise their lending procedures in respect of the coal industry, to enable it tide over the difficulties experienced by it and to grant medium-term credit both for modernisation of existing rice mills or for installation of new ones.

59. The structure of selective credit controls on bank advances against certain sensitive commodities like foodgrains, oils and oilseeds, sugar and gur and cotton and kapas was broadly maintained. Watch was kept on the supply and price situation of sensitive commodities and adjustments were made in the margin and ceiling requirements in respect of advances against such commodities in accordance with the demand, supply and price situation (Details in this regard are given in Part II of this Report).

60. The outbreak of Indo-Pakistan hostilities on December 3, 1971 necessitated some relaxation in this policy in order to enable commercial banks to meet additional credit requirements of industry for the manufacture and supply of goods for defence purposes and ensure a smooth distribution of goods, particularly in the border area. Banks were asked to grant expeditiously and adequately defence packing-cum-supply credit to manufacturing units and sub-contractors fulfilling defence orders. Banks were assured full refinance facilities at Bank rate irrespective of their net liquidity ratio in respect of their advances for the above purposes. With a view to meeting the increased working capital needs arising from accumulation of stocks and increased production, banks were permitted to enhance credit limits on merits upto 15 per cent to parties covered by the Credit Authorisation Scheme without prior approval of the Reserve Bank.

61. Subject to these policies the expansion in credit during the 1971-72 busy season amounted to Rs. 351 crores compared with that of Rs. 394 crores in the 1970-71 busy season. This smaller expansion was the result of lower credit utilization for food procurement operations, which declined during the season by Rs. 76 crores as against an

increase of Rs. 70 crores in the preceding busy season. Bank credit excluding food procurement credit, showed an increase of Rs. 427 crores compared with an increase of Rs. 324 crores during the previous busy season (Table 14). As deposit growth at Rs. 590 crores substantially outstripped the expansion in credit in 1971-72 busy season, dependence on the Reserve Bank was much less than in the previous busy season. At the peak level, increase in borrowing from the Reserve Bank during the 1971-72 busy season was Rs. 233 crores against Rs. 292 crores reached in the preceding busy season. Banks' investments in Government and other approved securities registered a sharp rise of Rs. 245 crores, compared to an increase of Rs. 115 crores in the 1970-71 busy season. The credit-deposit ratio at the end of the busy season in April 1972 stood at 72 per cent or 6 percentage points lower than that a year ago.

Sectoral Distribution of Credit—Food Procurement and Exports

62. Estimates of data on sectoral flow of bank credit are available only upto end-December, 1971 (*i.e.*, for the half year under review). These data show that between end-June and end-December 1971, while total credit extended by scheduled commercial banks increased by Rs. 294 crores to Rs. 5,052 crores, advances for food procurement operations declined by Rs. 14 crores and stood at Rs. 365 crores at the end of December, 1971. Total advances granted by these banks for exports which had shown a rise of Rs. 19 crores in the first half of 1971 rose further by Rs. 77 crores to Rs. 459 crores by the end of December, 1971. Of the total increase in scheduled commercial bank credit during this period, 26 per cent went to the export sector as compared to 18 per cent in the corresponding period of 1970. With the priority accorded to the promotion of exports, Reserve Bank continues to provide refinance facilities to banks in respect of credit granted by them for exports. The share of such refinance provided by the Reserve Bank to scheduled commercial banks in its total lending to them rose sharply during the year from 35 per cent at the end of June, 1971 to 64 per cent at the end of December, 1971. Banks were informed that in granting packing-credit facilities to export units they could relax margin requirements with a measure of discretion. The interest subsidy scheme was also continued and during the period July, 1971 to end-June 1972 37 eligible commercial banks availed of this subsidy to the extent of Rs. 4 crores against export credit provided by them.

Other Priority Sectors

63. During the period end-June 1971 to end-December 1971 credit to other priority sectors (comprising agriculture, small industries, road transport operators, professionals, self-employed, education, retail trade and small business) increased by Rs. 77 crores or by 7.5 per cent as against Rs. 143 crores or by 16.4 per cent in the corresponding period last year (Table 15). In the event the share of these priority sectors in total credit of all scheduled commercial banks declined from 22.8 per cent in December, 1970 to 21.8 per cent in December, 1971.

64. Sector-wise, direct finance to agriculture increased by Rs. 27 crores while indirect finance fell by Rs. 14 crores. In the result, total, advances to agriculture increased by only Rs. 13 crores during the half year ended December, 1971 as against by Rs. 58 crores in the corresponding period of 1970. Trends in credit to small-scale industries and other priority sectors like professionals and self-employed, retail trade and small business etc., were not dissimilar to those in the agricultural sector. The expansion in credit to small industry during June-December, 1971 was Rs. 45 crores as against Rs. 55 crores in the corresponding period of 1970, while in respect of other priority sectors the order of expansion was Rs. 19 crores as against Rs. 30 crores. The credit to small-scale industry (including term loans and advances granted to craftsmen and other qualified entrepreneurs) extended during 1971-72 (April—March) rose by Rs. 84 crores to Rs. 578 crores* as against an increase of Rs. 100 crores in 1970-71.

65. Slackness in the growth of credit to agriculture was partly due to emphasis given by banks on quality and recovery of their advances and partly due to banks focussing on the strength of their organisational structure for handling credit to this sector and streamlining their policies and procedures in accordance with the guidelines issued to them by the Bank. The slower pace of expansion in bank credit to the small industries sector is attributable partly to the general slack in the industrial sector, affecting the small industries output levels. Greater attention to maintaining a minimum standard of quality was also a contributory factor. It may also be added that the rate of growth in credit recorded in the period immediately following the nationalisation of 14 major banks could not be sustained as the base of advances to these sectors which was narrow in the initial period, has since considerably widened and, therefore, the rate of growth would be necessarily lower. The decline in the share of these sectors in total scheduled bank credit has to be viewed in the light of the above background and thus does not reflect a shift in policy.

Credit to other sectors

66. As Table 15 shows the share of other sectors, particularly large and medium industries and wholesale trade, including Government and other public sector undertakings, increased by Rs. 231 crores and amounted to 70.9 per cent of total advances as against 70.5 per cent at the end of June, 1971. Apart from the fact that large and medium industries and wholesale trade have always been the major borrowers from banks, this increase should be viewed against the special defence and distributional orders that had to be

*Provisional.

Table 14:—Seasonal Variations in Scheduled Commercial Banks Data

Busy Season

(Amount in Rupees Crores)

	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	April 1971	1971-72	April 1972
1. Total Bank Credit	+509.5	+426.8	+562.9	+394.2	4675	+351.1	5189
Of which :							
(a) Food Procurement Advances	+101.0	+8.3	—27.3	+70.3	203	—76.0	283
(b) Other Advances	+408.5	+418.5	+590.2	+323.9	4472	+427.1	4906
2. Total Investments	—152.7	—2.4	—51.3	+115.4	1774	+244.6	2268
(a) In Government securities	—182.3	—43.0	—100.9	+39.1	1360	+143.7	1712
(b) In other approved securities	+29.6	+40.6	+49.6	+76.3	414	+100.9	556
3. Cash and Balances with R.B.I.	—4.2	+20.2	+7.8	+12.4	359	+1.9	419
4. Money at Call and Short Notice	—20.5	+6.7	—14.8	—10.7		—6.8	
5. Aggregate Deposits	+221.7	+324.9	+320.9	+435.5	5993	+590.3	7207
(a) Demand	+122.1	+145.1	+171.9	+190.2	2631	+295.7	3128
(b) Time	+99.6	+179.8	+149.0	+245.3	3362	+294.6	4079
6. Borrowings from R.B.I.	+105.3	+70.8	+203.0	+40.2	191	+4.3	23
7. Credit-Deposit Ratio (as at the end of the Season)	79.4	78.0	79.4	78.0	78.0	72.0	72.0
8. Investment-Deposit Ratio (as at the end of the Season)	29.6	28.9	28.8	29.6		31.5	

Table 15 :—Sectoral Distribution of Scheduled Commercial Banks' Credit

(Amounts in Rupees Crores)

	Outstandings as on			Variation (3) over (2)	Outstandings as on		Variation (6) over (5)
	June 1969	June 1970	December 1970		June 1971	December 1971	
	1	2	3	4	5	6	7
1. Total Bank Credit	3399	4213	4452	+239	4758	5052	+294
(of which exports)	(263)	(320)	(363)	(+43)	(382)	(459)	(+77)
2. Food Procurement Operations	233	207	217	+10	379	365	—14
3. Agriculture :	188	342	400	+58	382	395	+13
of which :							
(a) Direct Finance	54	184	240	+56	236	263	+27
(b) Indirect Finance	134	158	160	+2	146	132	—14
4. Small-scale Industries	286	414	469	+55	500	545	+45
5. Other priority sectors including retail trade	31	114	144	+30	144	163	+19
6. Bank credit to large and medium industry, wholesale trade and others@	2661	3136	3222	+86	3353	3584	+231
[1—(2+3+4+5)]	(78.3)	(74.4)	(72.4)		(70.5)	(70.9)	
7. Available Aggregate Deposits (excluding cash in hand and balances with RBI, balances with other banks in current account and investments in Government and other approved securities)	2833	3350	3530	+180	3932	4251	+319
8. Item 6 as percentage of Item 7	93.9	93.6	91.3	+7.8	85.3	84.3	+72.4
9. Borrowings from R.B.I.	172	292	302	+10	207	171	—36

Note : (i) Figures for other priority sectors including retail trade are available for public sectors banks only and hence have been blown up on the basis of proportion (86%) of credit of public sectors banks to total credit.

(ii) Figures in brackets against Item 6 indicate proportion to total bank credit.

@ Estimated.

fulfilled in this period by industry and trade. Also, the bulk of export trade is included in the figures of advances extended to these sectors. Thus, for meeting fully the genuine credit requirements of the productive sectors of the economy, the general policy of credit restraint was not an obstacle. This is shown by the fact that during the year under review, out of 726 applications received from banks under the Credit Authorisation Scheme of the Reserve Bank, only 3 involving a small amount of Rs. 1.45 crores were rejected as not being need-based.

Differential Rates

67. In the context of credit to weaker sections of the community, mention may be made of the announcement by the Finance Minister on March, 25, 1972 of the Government decision to implement the scheme of concessional interest rates on advances made by public sector banks to selected low income groups, who deserved financial assistance. Following the statement a set of guidelines laying down criteria for identification of persons eligible for loans under the scheme and the conditions under which loans are to be given has been issued to banks. The two basic criteria for the selection of borrowers would be their weak economic status and the productive character of the activity. The differential interest rate is fixed uniformly at 4 per cent *i.e.*, 2 per cent below the Bank rate. The scheme is at the pilot stage now, and it is expected that lending under the scheme will amount to about half of one per cent of the aggregate lending of banks at the end of the previous year. Although the total quantum of credit—estimated at Rs. 20 crores—under the scheme would not be large, the major advantage would be the initiation of bankers to the policy of using interest rates as an instrument for reducing inequalities of income and wealth.

Bills Rediscounting Scheme

68. The scope of the Bills Rediscounting Scheme introduced in November, 1970 with a view to encouraging the growth of bill market was widened during the year with a few modifications (discussed in Part II). Refinancing under the old Bill Market Scheme was discontinued except for the specific purposes of defence packing credit-cum-supply credit and providing funds for food procurement operations and to banks, especially smaller banks, unable to provide eligible paper for other types of borrowings from the Reserve Bank.

69. After an initial phase of decline during July, and August 1971 the outstanding level of bills rediscounted increased to Rs. 25 crores at the end of September, 1971 as compared to Rs. 10 crores at the end of June, 1971. At the commencement of 1971-72 busy season bills rediscounted with the Reserve Bank stood at Rs. 14 crores. As the busy season progressed banks availed of rediscounting facilities on an increasing scale and by end of March 1972, the outstandings were of the order of Rs. 42 crores. With the commencement of the slack season recourse to this facility declined and at the end of June, 1972 bills rediscounted amounted to Rs. 10 crores. Maximum amount of outstanding bills rediscounted under the Scheme during the period from July 1, 1971 to June 30, 1972 amounted to Rs. 45.3 crores.

Credit Planning

70. The rationale and content of credit planning and its significance in the context of overall economic planning and the measures initiated in this direction were referred to in the last year's Report. As a further step for preparing a credit plan for the economy as a whole, a broad exercise of the increase in resources of the banking system and their deployment was undertaken in respect of financial year 1971-72, slack season 1971 and the 1971-72 busy season. For arriving at these estimates, 31 major banks which accounted for 95 per cent of deposits and 96 per cent of advances of the banking system, were asked to supply data in a special proforma designed for the purpose. The proforma included details of accretion of

total deposit resources and advances of the banks, deployments of funds State-wise and sector-wise as also the banks programme of branch expansion in the country. The individual banks' projections were discussed with the Chief Executive and high officials of the bank concerned and wherever necessary the estimates were revised, taking into account the past performance and its expected role in the context of social objectives regarding deposit mobilization and disbursal of loans sector-wise and region-wise. Utilizing the consolidated data from these banks and such information on production trends, prices, etc. as was available, a broad credit plan for the year 1971-72 for the banking system was prepared.

71. In order to have an idea of the credit requirements of the jute, tea and engineering industries, discussions with Jute Manufacturers' Association, Engineering Association and tea interests were held during the year. Similar dialogues with the representatives of other sectors (private and public) in the country are being initiated to help make proper estir[illegible] requirements.

72. The [illegible] ... rehensive credit plan for 1971-72 and the pro[illegible] lan were discussed at the meetin[illegible] comercial banks convened by the Reserve Bank in April, 1972. Besides explaining the objectives of the plan, the Economists were requested to send to the Reserve Bank their methods of estimating deposits and sectoral deployment of credit; these are to be discussed with individual bankers.

Regional Credit Planning

73. Although in the credit plan for 1971-72, State-wise classification of deposits and deployment of funds (including investments) was done and inter-State comparisons were made, a complete picture of regional distribution of bank funds was not possible, since the banks were not able to classify State-wise credit on utilisation basis. The banks are not as yet fully aware of the credit requirements of agriculture and small industry in many parts of the country. Nonetheless, a beginning has been made through quick impressionistic surveys carried out by them in respect of districts allotted under the lead bank scheme. Reports for 260 out of 335 districts have been prepared; further, the first phase of identification of unbanked/underbanked centres has been completed. In regard to follow-up action under the lead bank scheme, formation of the district level consultative committee for some districts has been completed. These committees are expected to maintain liaison with State Governments, besides co-ordinating the activities of financial institutions in meeting the credit gaps. While banks have familiarised themselves with the district economy, the scheme has not as yet brought about any substantial increase in banks' involvement in the local economy. In particular, lending to priority sectors has not yet made much headway under this scheme. This is due to the fact that banks have not so far conducted depth studies to assess the credit needs of different small-scale industries and agriculture in most areas. The effort made in this direction has been inadequate upto now. This is due, to a certain extent, to the narrow operational base with which some lead banks have started in their districts. In drawing up the perspective branch expansion programme for 1972—74, this aspect has been taken into account.

74. For evolving a meaningful lending programme, almost all public sector banks have set up offices at regional/divisional level and, in certain cases at the district level, with a mixture of developmental staff and subject matter specialists. With the conduct of area studies and identification of credit gaps with the active co-operation of other institutional agencies in the area and adequate support from State Government in regard to bankable schemes in districts, regional credit planning will become more effective in the coming years.

75. An important aspect of credit planning continues to be the expansion of banking facilities in the less developed regions of the country. Out of 1,612 branches opened during the year as many as 936 (53 per cent) were opened at hitherto unbanked centres and 507 were opened in the 9 relatively underbanked States of Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Orissa, U.P. and West Bengal. These 9 States and Tripura and Nagaland which have also been identified as underbanked States, account for more than half of the population of the country. They had only about onefourth of the total number of branches at the end of June 1969, but because of the branch expansion policy pursued during the last three years, this proportion has increased to more than 29 per cent at the end of June 1972. Details of the branch expansion programme of the commercial banks are given in Part II of the Report.

Balance of Payments

76. We turn now to the position regarding the external payments balance of the country in 1971-72 (July-June). During this period, the value of foreign exchange reserves increased from Rs. 787 crores to Rs. 846 crores. However, this rise includes Rs. 16 crores by way of the appreciation in the rupee value of the reserve assets held in currencies whose exchange rates went up over the year. In 1970-71, on the other hand, there was a decline of reserves from Rs. 837 crores to Rs. 787 crores, owing largely to an outflow of Rs. 124 crores for repurchases from and additional gold subscription to the IMF. There were no transactions of this nature in 1971-72. If we excluded these special transactions and the value change, the reserves would show an increase of Rs. 43 crores in 1971-72 and of Rs. 72 crores in 1970-71. In other words, the improvement in the payments situation was somewhat less marked than in the previous year.

77. Details of the total external transactions of which the changes in foreign exchange reserves are the final upshot are not yet available. However, whatever information is available shows that import payments have risen. Larger imports of steel, non-ferrous metals and other maintenance items have more than offset the reduction in food imports made possible by the comfortable domestic stocks. Debt servicing payments were larger than in the preceding year, partly on account of the rise in the exchange value of the currencies of some of our creditors. At the same time, export earnings probably went up moderately, in the face of the international currency uncertainties, and despite particularly good performance of jute exports.

78. At the end of the year, the external assistance available in the pipeline will thus have been significantly lower than at the end of the last year. Since December 1971, there have been no fresh aid authorisations from the U.S. With U.S. inaction on the third replenishment of funds for the International Development Association, flow of assistance from that source too has been affected. The breakdown of the international monetary system also led to uncertainty regarding assistance from other sources.

Trade Deficit

79. So far as imports and exports are concerned the D.G.C.I.S. data show that India's trade deficit which had narrowed down considerably since 1968-69 once again widened during 1971-72. The trade deficit in 1971-72 (April-March) amounted to Rs. 286 crores and was substantially higher than the deficit of Rs. 99 crores in 1970-71. This sharp increase was due to a substantial rise of Rs. 219 crores in imports, exports showing a rise of only Rs. 32 crores.

Exports

80. The growth rate of exports during the financial year 1971-72 was 2.1 per cent compared to 8.6 per cent in the preceding year. As pointed out in the last year's Report, a part of the increase in exports in 1970-71 was statistical arising out of the change in procedure for recording exports. If adjustment in the official export figures for 1970-71 is made on this ground, the effect would be to reduce the growth rate in exports in 1970-71, and correspondingly, to raise the growth rate in 1971-72. In the absence of concrete data, these adjusted growth rates cannot be easily determined but it is apparent that the growth rates based on the unadjusted figures are an overestimate for 1970-71 and an underestimate for 1971-72.

81. The trend of exports in 1971-72 can be divided fairly clearly into two periods, *viz.*, April 1971 to July 1971 when

they showed a smart rise of 25 per cent over the corresponding period of 1970 and the subsequent period from August 1971 to March 1972 when exports were 7 per cent lower than in the corresponding period of 1970-71. The better performance in the former period was due mainly to the buoyant demand for jute goods consequent on the virtual cessation of shipments from Bangladesh. In the period, after July 1971 exports were adversely affected, *inter alia*, by the dislocation of trade caused by the floating of world's major currencies and the Indo-Pak conflict.

Exports : Commodity-wise

82. Commodity-wise details of exports which are available upto December 1971 show that the modest growth rate of exports (4 per cent during the period April-December 1971 over the corresponding period of 1970) was almost entirely due to the increase in exports of jute manufactures. Among other items, tea recorded a modest rise of 2 per cent due to realizatton of higher unit values. On the other hand, exports of cotton textiles and yarns, oil cakes and spices recorded some decline (Table 16).

Table 16:—India's Principal Exports

(Amounts in Rupees Crores)

Commodities	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	April-December		Increase(+)/ Decrease(—) of (6) over (5)	
					1970	1971	Actual	Percentage
	1	2	3	4	5	6	7	8
A. Major non-traditional items								
Engineering goods	35	69	91	126	90	84	—4	—4
Iron and steel	55	79	87	91	71	34	—37	—52
Iron ore	75	88	95	117	86	72	—14	—16
Chemicals	16	24	30	36	27	25	—2	—7
B. Other Items								
Jute yarns and manufactures	234	218	207	190	136	216	+80	+59
Cotton yarns and manufactures	86	101	116	118	88	81	—7	—8
Tea	180	157	125	148	120	122	+2	—2
Hides, skins, leather and leather goods including footwear	70	87	99	87	64	74	+10	+16
Cashew kernels	43	61	57	52	42	51	+9	+21
Oil cakes	45	49	41	55	41	29	—12	—29
Pearls, precious and semi-precious, stones, unworked/worked	30	45	42	42	31	38	+7	+23
Spices	27	25	34	39	24	23	—1	—4
Fish and fish preparations	18	23	31	31	24	29	+5	+21
Sugar	16	10	9	28	18	27	+9	+50
Coffee	18	18	20	25	22	19	—3	—14
Manganese ore	11	13	11	14	11	8	—3	—27
Tobacco (unmanufactured)	25	33	33	31	29	35	+9	+35
C. Total (including others)	**1199**	**1358**	**1413**	**1535**	**1150**	**1194**	**+44**	**+4**

Note : Data for 1970-71 and 1971-72 are not cmparable with those of the previous years owning to the change in procedure (from the finally passed shipping bill to the original copy of the shipping bill) for recording exports adopted by the DGCIS, with effect from November 1, 1970.

Source : DGCIS.

83. If the increase in jute exports is excluded, total exports in the period April-December, 1971 would show a decline of Rs. 36 crores. The share of non-traditional exports in the total came down from 24 per cent in April-December, 1970 to 18 per cent in the same period in 1971. Increasing domestic demand for steel in the face of lower output reduced the export surplus considerably, while export of iron ore fell mainly due to decline in foreign demand. Shortage of steel and the pull of domestic demand also held down the exports of engineering goods and chemicals which had shown a rising trend in the previous years.

Export Policy

84. Reference was made in the last year's Report to the Export Policy Resolution presented to the Parliament on July 30, 1970 which emphasised the need for expanding India's export earnings at a high rate. In keeping with this objective the industrial licensing policy and the import policy were further geared to the expansion of export-oriented production. As observed earlier, export credit facilities were also extended in a larger measure.

85. A significant development in regard to external trade was the signing of the Trade Agreement in March 1972, between India and Bangladesh. In terms of this agreement India's exports to Bangladesh would comprise, among others, unmanufactured tobacco, cement, coal and cotton yarn, while India's imports from Bangladesh would include, inter alia, fish, raw jute and newsprint. The Agreement also provided for special facilities in regard to border trade.

Trends in Imports

86. Imports which had risen somewhat in 1970-71 for the first time after the devaluation of the rupee in June 1966, rose sharply in 1971-72. According to DGCIS data they increased by Rs. 219 crores (13 per cent) to Rs. 1853 crores during 1971-72 as compared to Rs. 52 crores (3 per cent) registered in 1970-71. The increase in imports during the year was partly due to shortfalls in domestic production of certain essential raw materials and steel products; the liberalised import policy followed in respect of maintenance imports was also a contributory factor.

Imports : Commodity-wise

87. Commodity-wise details of imports are available upto December 1971. These show that the increase in imports during April-December 1971 over the corresponding period

of the previous year was accounted for entirely by non-food imports. Imports of foodgrains were lower by Rs. 65 crores (or 38 per cent) than in April-December 1970, while non-foodgrains imports were higher by Rs. 247 crores (or 24 per cent). Almost all the major items under non-food imports recorded increases, but the rises were substantial in the case of iron and steel (Rs. 77 crores), machinery and transport equipment (Rs. 75 crores) and mineral oils (Rs. 47 crores) (Table 17). During 1971-72 (April-March) the value of import licences increased by 13 per cent on top of increasese of 36 per cent recorded during the year 1970-71; this should increaee further non-food imports in 1972-73.

Table 17:—India's Principal Imports

(Amounts in Rupees Crores)

Commodities	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	April-December		Increase (+) Decrease(—) of (6) over (5)	
					1970	1971	Actual	Percentage
	1	2	3	4	5	6	—7	—8
1. Food (excluding cashewnuts)	554	372	293	242	187	131	—56	—30
Cereals and cereal preparation	518	336	261	213	170	105	—65	—38
2. Raw cotton	83	90	83	99	74	87	+13	+18
3. Raw jute and mesta	5	16	5	Negl.	Negl.	—	—	—
4. Cashewnuts	25	31	28	29	22	20	—2	—10
5. Mineral Oil :	75	133	138	136	96	143	+47	+49
of which :								
(a) Petroleum crude and partly refined	60	96	96	106	76	110	+34	+45
(b) Others	15	37	42	30	20	33	+13	+65
6. Chemicals :	273	283	195	192	135	161	+26	+19
of which :								
(a) Fertilisers	139	139	77	61	38	52	+14	+37
(b) Others	134	144	118	131	97	109	+12	+12
7. Iron and steel	106	86	82	147	102	179	+77	+75
8. Non-ferrous metals	89	89	75	120	86	83	—3	—3
9. Crude rubber (including synthetic and reclaimed)	4	5	10	4	3	3	—	—
10. Wood and other animal hair	12	11	17	16	13	11	—2	—15
11. Animal and vegetable oils and fats	34	19	30	39	32	32	—	—
12. Paper, paper boards and manufactures thereof	18	18	24	25	17	24	+7	+41
13. Pearls, precious and semiprecious stones	12	28	28	25	17	19	+2	+12
14. Machinery and transport equipment	503	514	396	284	274	349	+75	+27
(a) Machinery other than electric	336	366	280	257	190	211	+21	+11
(b) Electrical Machinery	86	82	64	69	49	72	+23	+47
(c) Transport equipment	81	66	51	58	35	66	+31	+89
15. Others	215	214	178	176	125	123	—2	—2
Total	**2008**	**1909**	**1582**	**1634**	**1183**	**1365**	**+182**	**+15**

Source : DGCIS.

Import Policy

88. The import policy for 1972-73, while maintaing the basic framework of previous year's policy laid greater stress on the goal of self-reliance. It provided for greater allocation of imported inputs to selected priority industries, particularly those having substantial exports potential or contributing to net savings on imports.

89. The relative deterioration in merchandise trade was partly due to internal factors, such as relatively high prices and larger domestic offtake. On the other hand, there were certain developments abroad which also impeded our exports. UNCTAD III underlined the fact that developed countries are doing little to foster their trade with underdeveloped countries. The Generalized System of Preferences which has now been adopted by the developed countries such as EEC countries, Japan, Norway, Sweden and U.K. to provide opportunities for expanding exports of manufactured and semi-manufactured goods is riddled with quotas and ceilings.

90. With the floating of the pound sterling, at the end of the year, the international currency uncertainties seemed to grow rather than abate. World trade growth decelerated sizeably between 1970 and 1971. Developing countries' terms of trade deteriorated even as their export growth declined. Though rivival of activity is now strongly forecast for West Germany and the U.S. the prospects for the growth of world trade in 1972-73 would remain uncertain if credible progress is not achieved in the matter of the reform of the international monetary system.

91. It is in this context that India and the other developing nations have been seeking to be actively associated with the process of the international monetary reform and the continuation without any disruption of the SDR distribution in quantities adequate to meet the developing countries' needs. The difficulties that have ravaged the international payments system in the last few years are entirely due to the failure of the leading industrial countries of the world to manage their output and demand. The ill-

effects of this failure are, however, visited upon the developing countries also. A system in which (a) creation of international liquidity is internationally controlled, (b) adequate additions to liquidity are provided for the orderly growth of international trade and economic development of less developed countries, and (c) acceptable objective criteria are laid down for exchange rate changes to facilitate the adjustment process, is thus a matter of immediate necessity. Obviously, the developing countries need to have adequate voice in formulating such a system and in operating it after its adoption.

Assessment and Prospects

92. The synoptic view given in the preceding paragraphs shows that while the economy was able to withstand successfully the strains of refugee influx and war till the end of last year, it has also exhibited certain disquieting features. The response to an increase in aggregate demand has been more in terms of price increases than of output increases. While there has doubtless been a rise in agricultural output, industrial growth continues to be much slower than envisaged in the Fourth Plan—due partly to shortages in power, transport and certain raw materials. The rise in consumer goods prices has, among other things, worsened industrial relations and this also has had an adverse effect on industrial production. Although larger domestic savings and net capital inflow from abroad have contributed to an increase in domestic investment, the demand for investment goods indutries continues to be less than adequate. Likewise, while aggregate receipts of the public sector have gone up, public savings have diminished; in consequence, deficit spending has been larger. This has in turn affected aggregate monetary resources in the economy.

93. It is against this background that the tasks ahead have to be defined keeping in view the objectives of the Fifth Plan. The fulfilment of these objectives is predicated on a rapid rise in production and strengthening of competitive efficiency. Maximising production would imply promotion of new industries, fuller utilisation of existing capacity and wider spread of new agricultural technology. Equally, the management of demand will be crucial to restraining price increases. Ideally, this will require the adoption of policies relating the increase in money earnings to increases in productivity in the economy, concurrently with increasing savings and redistribution of income. There are, no doubt, both conceptual and practical difficulties in implementing this policy. At the same time, the need for such a policy is evident because the attempt of different sections of the community to increase their shares in the national output will not only be self-defeating but will also make it difficult, if not impossible, to achieve in real terms the planned targets of output.

94. From the point of view of financial policy, this would require two basic lines of action; first, monetary expansion will have to be kept within limits and, second, institutional facilities will have to be provided on an extensive scale to mobilise the savings of the community. An essential element in controlling monetary expansion would be to limit the extent of deficit financing resorted to by the public sector. As pointed out earlier in the Report, no State Government can now have overdrafts from the Reserve Bank except for a temporary period of one week; to supplement this a policy of keeping the Reserve Bank credit to the Central Government under restraint would have to be pursued. It is clearly not possible to prescribe any precise limit to such credit, because of the special responsibilities in regard to defence and development that the Central Government has to shoulder. However, a continuous watch should be kept on the level of deficit financing, taking into account the prevailing elasticity of supply of essential commodities or wage-goods. This implies that maximum efforts should be made to enlarge tax collections through a widening of the tax base, to maximise market borrowings and, in particular, to generate surpluses in the public sector commercial undertakings through increased operational efficiency.

95. The institutional measures in the financial field will require the provision of infrastructure, in the form of extending and deepening banking services. Banking developments in India show that given the requisite man-power and other resources, banks can play a useful role in the development of the less developed regions. With the anticipated increase in the deposits, banks can also extend term-lending and export credit to a larger extent than they have done so far. This would mean that the working capital requirements of industrial, agricultural and other sectors should be capable of being financed without undue difficulties. However, the problem of medium and long-term capital would still remain. It will, therefore, be necessary to continue — and augment — the assistance given through the term-lending institutions; it will also be essential to promote fresh investment for the further widening and diversifying of the industrial base. Apart from encouraging institutional facilities, the Reserve Bank's policy will have to be one of general credit constant in view of the objective of price stability.

II. PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING

96. The banking system continued its efforts, during the year under review, in widening its geographical coverage and in reducing thus the regional imbalances in banking development. The perspective plan of branch expansion proposed for 1972 and the succeeding two years, during which an overall expansion of 5,000 branches is contemplated, is expected to further reduce regional imbalances and also enable banks to integrate their branch expansion programme with their lead responsibilities under the lead bank scheme. The momentum in the growth of deposits of banks witnessed in the recent years in likely to be maintained, in view of the continued emphasis on widening the network of branches.

97. Emphasis on meeting credit requirements of borrowers of small means, such as small farmers, small-scale manufacturers, retial traders, road transport operators, small businessmen, professionals and self-employed persons also continued during the year with increased accent on qualitative lending. The accent on qualitative lending will be fortified by the liberalisations in respect of guarantee cover provided by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., for credit facilities extended to borrowers of small means in the priority and neglected sectors. The Union Government's decision to implement the differential interest rates scheme, in favour of specified low income categories of persons engaged in specified productive, economic activities and the expectation that public sector banks will lend about Rs. 20 crores under the scheme will increase their involvement in catering to the credit needs of these sectors.

98. Under the Lead Bank Scheme, considerable progress has been made in the preparation of reports based on quick impressionistic surveys. Besides convening Consultative Committees for Banking Development in a number of districts, some efforts have also been made in conducting intensive studies to identify credit gaps.

99. In the field of agriculture, public sector banks are evolving specific area schemes, as for example, schemes in terms of which they endeavour to meet the financial needs of farmers in adopted villages. Apart from reducing the chances of more than one institutional credit agency financing the same borrowers, such schemes also enable banks to have better supervision over the end-use of credit provided. The SFDA/MFAL projects are still in the initial stages and the authorities are identifying eligible persons. Commercial bank lending to agriculture will be facilitated further, if action on the report of the Expert Group on State Enactments is taken expeditiously by State Governments.

100. Mention may also be made of the selection by the State Bank of India of 60 centres throughout the country to gain experience in lending to self-employed persons, artisans, craftsmen, etc. To the same category belonged the opening of a multi-service agency branch by the Bank of Baroda for giving technical assistance to potential entrepreneurs. The Reserve Bank is in touch with other banks in regard to evolving similar schemes to augment employment potential.

101. Towards the close of the accounting year, the Regional Consultative Committee for nationalised banks for the central region, comprising Madhya Pradesh and Uttar Pradesh

to review banking developments within the region, was convened at Lucknow. The Committee discussed matters relating to the provision of loans to priority sectors and also co-ordination between State Governments and banks. At the meeting, a decision to set up a working group to make substantial efforts to increase lending in rural and semi-urban areas as well as to small borrowers, specially agriculturists was taken.

102. Banks have also recognised the organisational constraints for a dynamic programme of lending to the priority sectors, and, therefore, have either reorganised or are in the process of reorganising their existing set-up. In this they have taken note of the need to have an appropriate mix of operational and developmental staff at the head office, as well as regional and district level offices.

103. The following paragraphs bring out details of organisational changes and the progress in the implementation of various schemes affecting commercial banks.

Branch Expansion

104. Commercial banks opened 1,805 offices in 1971 as against 2,137 offices in 1970 and 1,369 in 1969 making a total of 5,311 for the three years ending December, 1971. It is proposed to maintain this momentum in the three-year period ending 1974 under the perspective plan of branch expansion. Under it commercial banks would be able to open at least about 1,500 branches each in 1972 and 1973 and perhaps somewhat more in 1974, adding up to a total of about 5,000 branches. Banks have been advised to be more selective in the matter of further branch expansion, and take into account the objective of providing banking facilities in centres with potential, their responsibility in their lead districts, their areas of operation and the need for giving priority to the relatively under-developed/under-banked States. In addition, banks have been advised to constantly appraise the performance of their branches in relation to their present business and future goals.

105. In the accounting year 1971-72, commercial banks opened 1,612 offices as against 1,890 offices in 1970-71. Of the offices opened during the year, the nationalised banks opened 821 offices and the State Bank of India and its subsidiaries 439 offices. The number of offices opened at unbanked centres was 936 (Table 18).

Table 18:—New offices opened by commercial banks during 1970—71 and 1971—72

	New offices opened by commercial banks						Bank Offices as on	
	1970-71			1971-72				
	July-December 1970	January-June 1971	July-1970 June 1971	July-December 1971	January-June 1972	July-1971-June 1972	30th June 1971	30th June 1972
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. State Bank of India	234 (164)	178 (123)	412 (287)	187 (106)	102 (58)	289 (164)	2286	2575
2. Subsidiaries of State Bank of India	86 (64)	87 (55)	173 (119)	66 (39)	84 (46)	150 (85)	1233	1383
3. Fourteen nationalised banks	608 (413)	444 (245)	1052 (658)	540 (321)	281 (149)	821 (470)	6368	7189
4. Other scheduled banks	124 (57)	115 (65)	239 (122)	175 (108)	165 (99)	340 (207)	1875	2238
5. Foreign banks	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	130	130
6. All scheduled commercial banks	1052 (698)	824 (488)	1876 (1186)	968 (574)	632 (352)	1600 (926)	11892	13515
7. Non-scheduled commercial banks	5 (—)	9 (8)	14 (8)	4 (3)	8 (7)	12 (10)	121	105
8. All commercial banks	1057 (698)	833 (496)	1890 (1194)	972 (577)	640 (359)	1612 (936)	12013	13620

Note :—Figures in brackets relate to the number of offices opened at unbanked centres.

106. Progress in regard to extending the territorial spread of banking was maintained during the year (Table 19). Of 5,375 offices opened since nationalisation, i.e., from July, 1969 to end-June, 1972, as many as 3,416 branches were in unbanked centres (63.5 per cent). The under-developed States of Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal accounted for 31.6 per cent of these new offices. Even out of the offices opened at unbanked centres, these States accounted for 34.1 per cent. In Manipur and the Union Territories of Arunachal Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Mizoram, all the offices opened during the year were at unbanked centres.

107. With the addition of 1,612 branches in 1971-72, population covered per bank office declined from 46,000 at the end of June, 1971 to 40,000 in June, 1972. Such decline was noticed in all the States except Nagaland and Tripura, and among the Union Territories, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands. There are only two districts which are still unbanked; licences for opening of branches therein have already been issued to banks.

108. In spite of a slight decline in the rate of growth of branches in the year, the shift in favour of opening branches in rural areas continued during the year (Table 20). The proportion of bank branches in rural areas increased from 35.6 per cent of the total a, the end of June, 1971 to 38.7 per cent at the end of June, 1972.

109. A recent study of the performance of banks in eight metropolitan centres, viz. Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Delhi, Hyderabad, Kanpur and Madras, revealed that good deposit potential existed in these centres and that metropolitan centres offered scope for opening more bank offices. It was also felt that increase in the number of offices

Table 19 :—State-wise distribution of bank offices as at the end of June 1970, June 1971 and June 1972

States	No. of offices as at the end of			Opened during 1970-71		Opened during 1971-72		Population per bank office (in thousands) as at the end of	
	June 1970	June 1971	June 1972	Total	Of which unbanked centres	Total	Of which unbanked centres	June 1971	June 1972
1. Andhra Pradesh	722	869	959	147	95	90	44	50	45
2. Assam	96	122	149	26	23	27	22	120	—98
3. Bihar	361	453	541	92	62	88	68	124	104
4. Gujarat	919	1105	1234	187	106	129	83	24	22
5. Haryana	219	258	299	39	19	41	29	39	34
6. Himachal Pradesh	62	87	108	25	23	21	19	40	32
7. Jammu & Kashmir	74	101	116	27	13	15	8	46	40
8. Kerala	713	845	978	132	100	136	92	25	22
9. Madhya Pradesh	460	566	669	107	62	103	58	73	62
10. Maharashtra	1304	1471	1679	167	86	208	77	34	30
11. Manipur	2	5	6	3	3	1	1	215	178
12. Meghalaya	11	15	16	4	4	1	—	67	63
13. Mysore	954	1124	1292	170	107	168	107	26	23
14. Nagaland	4	5	5	1	1	—	—	103	103
15. Orissa	133	173	192	40	30	19	12	126	114
16. Punjab	465	556	651	91	55	95	59	24	21
17. Rajasthan	432	525	570	93	61	45	25	49	45
18. Tamil Nadu	1213	1371	1484	164	107	115	73	30	28
19. Tripura	6	12	12	6	6	—	—	130	130
20. Uttar Pradesh	932	1147	1324	215	142	177	107	77	67
21. West Bengal	588	684	760	96	67	76	40	65	58
Union Territories :									
22. Andaman & Nicobar Islands	2	2	4	—	—	2	1	57	29
23. Arunachal Pradesh	—	3	5	3	3	2	2	156	94
24. Chandigarh	26	28	33	2	—	5	—	9	8
25. Dadra & Nagar Haveli	1	3	4	2	2	1	1	25	19
26. Delhi	318	350	385	32	2	35	1	12	10
27. Goa Daman & Diu	101	111	118	10	9	7	4	8	7
28. Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	—	2	2	2	2	—	—	16	16
29. Mizoram	—	—	1	—	—	1	1	—	332
30. Pondicherry	13	20	24	7	4	4	2	24	20
Total :	**10131**	**12013**	**13620**	**1890**	**1194**	**1612**	**936**	**46**	**40**

Table 20 :—Centre-wise distribution of commercial bank offices

Centre	No. of offices as at the end of									
	June 1969		June 1970		June 1971		December 1971		June 1972	
	No.	*% to total*	No.	*% to total*	No.	*% to total*	No.	*% to total*	No.	*% to total*
(*i*) Rural	18,32	*22.4*	30,62	*30.2*	42,79	*35.6*	48,89	*37.5*	52,67	*38.7*
(*ii*) Semi-urban	33,22	*40.1*	36,95	*36.5*	40,16	*33.4*	42,24	*32.6*	43,51	*31.9*
(*iii*) Urban	14,47	*17.5*	15,83	*15.6*	17,78	*14.8*	18,50	*14.3*	19,16	*14.1*
(*iv*) Metropolitan/Port towns	16,61	*20.0*	17,91	*17.7*	19,40	*16.2*	20,22	*15.6*	20,86	*15.3*
Total :	82,62	*100.0*	1,01,31	*100.0*	1,20,13	*100.0*	1,29,85	*100.0*	1,36,20	*100.0*

in the large cities will offer relief to the existing offices, particularly in business localities, which find it difficult to cope with the rapid increase in business and help them in siphoning off the overflowing business and thereby bring about improvement in customer service too. In view of these considerations, the population norm per bank office was reduced from 10,000 to 5,000 for metropolitan areas and certain urban centres. Further, the requirement of banks to open the requisite number of offices in rural/semi-urban areas to get entitlement for opening urban offices including those at metropolitan and port towns, was relaxed so that more offices in metropolitan cities/port towns may be opened. According to the revised norm, a bank which has 60 per cent or more of its offices in rural/semi-urban areas is eligible for opening one office each in an urban and a metropolitan/port town for every two offices opened in rural/semi-urban areas; and in other cases it will be for every three offices opened in rural/semi-urban centres. In order to accelerate the pace of issue of licences relating to metropolitan centres, meetings of representatives of banks were held at six centres, viz., Bombay, Calcutta, Delhi, Hyderabad, Madras and Bangalore and allocations were made for opening 728 offices in these cities. Banks have also been allowed to open 303 more offices in urban centres. These steps are expected to tap the deposit potential in urban areas and relieve the pressure on existing bank offices there, and at the same time, maintain the momentum of the programme of expanding banking facilities in rural areas.

110. Allowing for changes in the number of offices due to amalgamations, transfer of assets and liabilities and inclusion in and exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, the number of offices of scheduled commercial banks increased by 1623. Offices of non-scheduled commercial banks, however, declined by 16 (Table 21). At the end of June, 1972, the number of offices of scheduled and non-scheduled commercial banks stood at 13,515 and 105, respectively; at the end of June, 1971 the corresponding numbers were 11,892 and 121.

Table 21 :—Number of offices opened and closed by scheduled and non-scheduled commercial banks in India

	New offices opened	Changes due to amalgamations, mergers, transfers of assets and liabilities and inclusion in and exclusion from the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934	Existing offices closed	Overall variation in the number of offices	Number of offices at the end of the period
	1	2	3	4	5
Scheduled Commercial Banks :					
1969					
January-June	5,65 (24)	+ 1	—3	+5,63	80,45
July-December	7,72 (65)	+53	—3	+8,22	88,67
1970					
January-June	10,68 (190)	+3	—	+10,71	99,38
July-December	10,52 (234)	+54	—4	+11,02	1,10,40
1971					
January-June	8,24 (178)	+32	—4	+8,52	1,18,92
July-December	9,68 (187)	+28	—	+9,96	1,28,88
1972					
January-June	6,32 (102)		—5	+6,27	1,35,15
Non-Scheduled Banks :					
1969					
January-June	11	— 1	—	—10	2,17
July-December	21	—53	—1	—33	1,84
1970					
January-June	12	— 3	—	+ 9	1,93
July-December	5	—54	—	—49	1,44
1971					
January-June	9	—32	—	—23	1,21
July-December	4	—28	—	—24	97
1972					
January-June	8	—	—	+ 8	1,05
All Commercial Banks :					
1969					
January-June	5,76	—	—3	+5,73	82,62
July-December	7,93	—	—5	+7,89	90,51
1970					
January-June	10,80	—	—	+10,80	1,01,31
July-December	10,57	—	—4	+10,53	1,11,84
1971					
January-June	8,33	—	—4	+8,29	1,20,13
July-December	9,72	—	—	+9,72	1,29,85
1972					
January-June	6,40	—	—5	+6,35	1,36,20

Notes : 1. Figures within brackets relate to the State Bank of India.

2. Data exclude administrative, seasonal, temporary, non-banking offices and offices outside India.

Lead Bank Scheme

111. In the last year's Report, mention was made about the steps taken for the purpose of enabling banks to conduct quick, impersssionistic surveys of districts allotted to them under the Lead Bank Scheme. Since then there has been good progress in the completion of lead surveys by banks. Thus far, survey reports in respect of 260 out of 337 districts allotted to banks have been completed. In the preparation of reports, banks have ensured that a number of districts in the under-developed States of Assam, Bihar, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are covered; in fact, about 80 per cent of districts in these States have already been covered.

112. During the year, the Reserve Bank of India convened a meeting at Jaipur for allocation of centres identified in the lead bank surveys. With this, the Reserve Bank has convened seven such meetings, and 833 unbanked centres have been allotted to various commercial banks at these conferences. Banks have also been convening similar meetings at district level for allocation of unbanked centres identified in the lead surveys.

113. Under the perspective programme of branch expansion, banks which have been designated as lead banks have been required to indicate to all other banks and the Reserve Bank of India the names of centres where bank offices could be opened, so that the branch expansion programmes of banks in their lead and non-lead districts can be co-ordinated. This will also help align branch expansion programme of banks with their lead responsibilities.

114. As a follow-up action under the scheme, banks have constituted district level consultative committees to serve as a forum for discussion among banks and other financial institutions for exchanging information about borrowers and lending to priority sectors, identifying bankable schemes in the districts and evolving methods of financing them in a co-ordinated manner. Such committees have been set up in about a hundred districts. Banks have also been advised to maintain liaison with officers of State Governments.

115. An important plank of the Lead Bank programme is that banks would conduct studies in depth as a follow-up of the quick surveys to evolve schemes for financing local projects. Although some progress has been made in this regard, the number of surveys conducted and districts covered by such studies is not adequate in relation to the requirements. This is mainly due to the fact that banks did not have an adequate complement of technically competent personnel in the fields of agriculture and small industries to discharge their lead responsibilities. As mentioned earlier, steps are being taken to overcome this obstacle through reorganisation and re-staffing schemes.

Financing of Agriculture by commercial banks

116. Mention was made in the last year's Report about the issue by the Bank of guidelings on agricultural financing to commercial banks. In line with these guidelines, commercial banks have been streamlining their loan policies and procedures for agricultural lending. However, the growth of advances to agriculture by commercial banks slowed down during the year; this is due partly to increased attention given to the qualitative aspects of loans and effective supervision of end-use. Banks are also getting away from thinly dispersing their efforts over wide areas and are now evolving concentrated programmes of area schemes, cluster approach, village adoption approach, group loans, etc. Illustrative of this is the decision of the State Bank of India to select 150 centres throughout the country to open agricultural development branches. Each of these will be provided with technical and other field staff, and is expected ultimately to cover anything upto 100 villages. Since many of the centres identified are in areas covered by Government programmes for small farmers and other weaker sections of the community, the involvement of commercial banks in SFDA/MFAL areas is likely to increase substantially. Once the list of eligible persons is made available to banks by SFDA/MFAL project authorities, they will be able to provide loan assistance to them for raising of crops, dairy farming, augmentation of irrigation facilities, etc. In these areas, banks may have to do some extension work depending upon their organisational strength. Special schemes have also been formulated by banks themselves for intensive financing of agriculture.

117. At a meeting of heads of agricultural finance departments of major commercial banks convened by the Reserve Bank of India in April, 1972, the reasons for the general slow-down of agricultural advances and the strategy of area approach adopted by banks were discussed. Demarcation of areas to one bank exclusively was considered not desirable as it would negate the concept of multi-agency approach to agricultural lending. The command area of a branch stipulated at ten miles is not a rigid norm but illustrative of the emphasis on ability to supervise loans. The meeting also decided that commercial banks should obtain from their branches information on demand, collection and outstanding of loans on a quarterly basis.

118. To facilitate larger financing of agriculture by commercial banks, there is need for expeditious action on the recommendations of the 'Expert Group on State Enactments having a bearing on commercial banks lending to agriculture.' The report was forwarded to the Chief Ministers/Chief Secretaries of the various State Governments by the Governor of the Reserve Bank in September, 1971 requesting early enactment by the State Legislatures of the model bill recommended by the Group and thereby extending to agriculturists borrowing from commercial banks, facilities similar to those available to them when they borrow from co-operatives. Some of the States Governments have taken steps in respect of some of the administrative measures recommended by the Expert Group. But action in regard to enacting legislation on the lines indicated by the Expert Group, has not taken concrete shape in most of the States.

Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

119. The Cerdit Guarantee Corporation of India (Small Loans) Guarantee Scheme, 1971 introduced by the Corporation with effect from April 1, 1971, was substantially liberalised during the year, in order to extend the benefit of the guarantee to a larger number of eligible borrowers and loans. Under the liberalisation, effective January 1, 1972, there are no limits on the amount to be lent direct to farmers and agriculturists for various purposes with the Corporation's guarantee. The purposes covered include cultivation of crops (other than tea, coffee or rubber) or development or improvement of land or allied agricultural activities like pisciculture and sericulture. In addition, guarantee is provided under certain conditions against seasonal loans which are not repaid owing to crop failure as a result of natural or other calamities or adverse circumstances beyond the farmer's control and are converted into term or instalment credits. The maximum period for the repayment of credit facilities for sugarcane cultivation has been extended from 15 to 24 months and in respect of repayment of credit for purposes other than seasonal agricultural operations, the period has been extended from five to ten years.

120. Till December, 31, 1971 the Corporation guaranteed only those credit facilities which were extended by commercial banks after April 1, 1971. Under the liberalised provisions, however, guarantee is available in respect of all credit facilities outstanding at the commencement of business as on January 1, 1972, irrespective of the date on which the credit facilities were sanctioned or availed of, provided the borrowers concerned and the credit facilities extended satisfied the liberalised provisions. However, outstanding credit facilities as on January 1, 1972, which were already recalled or treated as bad or doubtful or utilised for adjustment of earlier bad or doubtful debts or where the borrowers have suspended their activities or business are excluded. Guarantee facility is available, under the liberalised provisions, to credit institutions to the extent of Rs. 1 lakh as against Rs. 50,000 hitherto in respect of loans to transport operators for purchase of vehicles. Dealers in fertilisers with a larger annual turnover upto Rs. 5 lakhs (previously Rs. 2 lakhs) and owners of petrol stations and other retail outlets for mineral oils with annual turnover upto Rs. 5 lakhs (previously Rs. 1 lakh) have been made eligible under the scheme.

121. The Corporation introduced two other schemes during the year. The Credit Guarantee Corporation of India Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme introduced

on July 1, 1971, covering loans granted by the State Financial Corporations including the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd., is similar to the Small Loans Guarantee Scheme referred to earlier. It covers credit facilities to transport operators, small hoteliers, business enterprises engaged in generation or distribution of electricity or any other form of power or in the development or management of any contiguous area of land as an industrial estate, i.e., to borrowers to whom the financial corporations are in a position to grant financial assistance and who are not already covered under the credit guarantee scheme for small-scale industries administered by the Reserve Bank of India on behalf of the Central Government. The Financial Corporations Guarantee Scheme was also liberalised effective January 1, 1972 so as to cover all eligible credit facilities outstanding as on January 1, 1972 and transport finance upto Rs. 1 lakh per operator.

122. The Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, which came into force from October 1, 1971, guarantees credit facilities sanctioned to service co-operative societies assisting artisans and workers engaged in any form of industrial activity. This facility is available to all the scheduled commercial banks in the country; other credit institutions eligible to participate in this scheme, are the State and Central Co-operative banks in the States and Union Territories to which the provisions of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 have been extended.

123. The credit facilities covered under the various schemes of the Corporation as at end-December, 1971, amounted to Rs. 109.72 crores under the Small Loans Guarantee Scheme in respect of 63 out of 71 scheduled commercial banks; and under the Financial Corporation Guarantee Scheme to Rs. 2.6 crores in respect of 13 out of 18 financial corporations. As regards the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, credit facilities covered amounted to Rs. 1.89 lakhs in respect of one bank. The Corporation has set up wrong group to examine the question of extension of guarantee cover for co-operative credit granted to farmers and agriculturists and other borrowers.

124. During the year ended December 31, 1971, the Corporation received by way of guarantee fees a sum of Rs. 4.05 lakhs in respect of the Small Loans and Financial Corporations Guarantee Schemes. No claims have been received by the Corporation so far. For meeting the claims on the Corporation, it is proposed to build up a Reserve for Unexpired Guarantee Risks by crediting to it an amount which will not be less than 50 per cent or more than 100 per cent of the guarantee fees collected during the year, less the claims paid in that year. Accordingly, the entire guarantee fee of Rs. 4.05 lakhs received during 1971 has been credited to the Reserve for Unexpired Guarantee Risks.

Differential Interest Rates

125. The Union Finance Minister announced in the Parliament on March 25, 1972 Government's decision to implement the scheme of differential interest rates on advances by public sector banks. The differential interest rate under the scheme is for the present to be uniformly fixed at 4 per cent. The Reserve Bank conveyed to banks the Government decision and the criteria laid down for identifying persons who will be eligible for loans under the scheme and the conditions under which loans should be given.

126. An endeavour which should have the capability of standing on its own after some period will be eligible for assistance under the scheme. The sectors from among which banks are to locate parties eligible for loans under the scheme include scheduled tribes/scheduled castes and other engaged, on a modest scale, in agriculture and/or allied activities; people occupied in the collection or elementary porcessing of forest products; people collecting fodder in difficult areas and selling them to farmers or traders; people physically engaged on a modest scale in cottage and rural industries and vocations; indigent students of merit going in for higher education, physically handicapped persons pursuing a gainful occupation and orphanages and Women's Homes where saleable goods are made and for which there is no adequate and dependable source of finance. A person to be eligible for a loan under the scheme should not have family income of more than Rs. 2,000 per annum if resident in an urban or semi-urban area, or Rs. 1,200 per annum if resident in a rural area. In addition, he should not have land exceeding one acre if irrigated and 2.5 acres if unirrigated.

127. While loans to individuals are not barred, banks are, in the beginning, to look for groups in particular. Loans under the scheme will be provided both for working capital and for term credit for a period not exceeding five years for acquisition of fixed assets. It is expected that ordinarily the former will not exceed Rs. 500 and the latter Rs. 2,500. Margin requirements may be waived. Banks may, however, take hypothecation of assets purchased with loans. Each loan is to be covered under the existing credit guarantee schemes and the guarantee fee will be borne by the banks. Repayment schedules will be worked out taking into account sustenance requirements of the borrower; and there is provision for a grace period, not exceeding two years, in the case of term loans.

128. The scheme is only at the pilot stage and is to be implemented in certain selected backward districts. District covered by SFDA/MFAL projects are not covered by the scheme. Each bank is to select at least one in every eight or ten branches in the selected districts, with suitable representation to rural, semi-urban and urban areas. It is expected that the quantum of lending under the scheme by each bank will correspond to about half a per cent of its aggregate lending at the end of the previous year.

Bills Rediscounting Scheme

129. The Bills Rediscounting Scheme introduced in November 1970, with a view to encouraging the growth of a bill market in India, was modified during the year so as to expand its coverage. On July 30, 1971 the scheme was extended to cover bills of exchange arising out of sale of goods to Government departments and quasi-Government bodies as well as to Statutory Corporations and Government companies provided such bills conformed to the requirements of the Scheme. On October 25, 1971 in order to avoid delays and reduce the work involved in delivering and redelivering the rediscounted bills, to and from the Reserve Bank, it was decided to dispense with the actual lodgement of bills each of the face value of Rs. 2 lakhs and below by the banker with the Reserve Bank and to authorise the banks to hold such bills with themselves as agents of the Reserve Bank. The minimum amount of a bill eligible for rediscount with the Reserve Bank was reduced from Rs. 5,000 to Rs. 1,000. Effective April 6, 1972, bills of exchange drawn on and accepted by the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., on behalf of its purchaser constituents singly or jointly with them, were also made eligible for rediscount under the Scheme, provided an eligible scheduled commercial bank offered them for rediscount. Further, with a view to widening the scope of the new bills rediscounting scheme, the Bank has taken the opportunity to suggest to banks in appropriate cases that book debt limits might be converted into bill limits to the extent feasible. In addition the banks are also asked to avail of bills rediscounting facilities on an increasing scale in respect of bills discounted by them.

130. The Scheme gained further momentum during the year and the scheduled commercial banks made larger use of the Scheme during the 1971-72 busy season. After an initial decline during July and August 1971, the outstanding level of bills rediscounted increased to Rs. 25 crores at the end of September 1971 as compared with Rs. 10 crores at the end of June 1971. At the beginning of 1971-72 busy season bills rediscounted with Reserve Bank of India amounted to Rs. 14 crores. With the progress of the busy season, banks availed of rediscounting facilities on an increasing scale and at the end of March 1972 the outstandings were of the order of Rs. 42 crores; with the commencement of the slack season, this amount came down and at the end of June 1972, stood at Rs. 9.9 crores.

131. A measure of the increasing extent to which the Bills Rediscounting Scheme is being availed of by banks is evident from the fact that despite the comfortable liquidity position, bills rediscounted with the Bank in the 1971-72 busy season amounted to Rs. 45 crores, at the peak

level (17-3-1972) as against Rs. 14.1 crores (30-4-1971) at the peak level in the 1970-71 busy season.

Credit Authorisation Scheme

level (17-3-1972) as against Rs. 14.1 crores (30-4-1971) at major transformation in the middle of 1970 and been widened to cover credit appraisal by scheduled commercial banks to impose financial discipline on large borrowers. This new regulatory system has, over the past two years, evolved itself into an effective mechanism for ensuring the proper use of bank credit; banks have also perceptibly toned up their credit appraisal procedures and are making efforts to further rationalise them. With the standards of credit appraisal in banks showing improvement, certain changes which were really in the nature of a 'tidying up operation' in the requirement of prior authorisation of the Bank, were effected during the year with a view to enabling banks to meet urgent demands of their borrowers for genuine purposes without prior authorisation. Further credit facilities which banks could, on their own, grant to the borrowers covered by the Credit Authorisation Scheme are, mainly, temporary/interim credit limits up to Rs. 10 lakhs for three months; purchase of third party outstation cheques/bank drafts; temporary excess drawing up to 5 per cent of the limit or Rs. 10 lakhs (whichever is lower); advances against uncleared effects, restoration of limits to the original levels, and reallocation of limits already authorised by the Bank.

133. During the administration of the Scheme, it was observed that while projecting the peak requirements of bank finance, some banks were showing unpaid stocks also as being available for computing the permissible bank finance for purposes of fixing the borrowers' credit limits. This practice resulted in 'double financing' which enabled the borrowers to get finance from sellers as also from the banks in respect of identical inventories: the borrowers could, thus, provide margins to the banks out of the borrowed funds instead of from their own funds. Although this aspect was informally discussed by the members of the Study Group (which was appointed for the purpose of drawing up the proforma statements referred to in last year's Report), it was then felt that considering the conditions obtaining in the country (where there is a heavy reliance on bank finance), the Bank may not, at least for sometime in the beginning, insist upon exclusion of such unpaid stocks while arriving at the permissible bank finance. The position has been reviewed by the Bank in the light of the experience gained after the revision of the Scheme and it is considered desirable that all banks should follow a uniform practice in regard to the treatment of the unpaid stocks. Accordingly in January 1972, the Bank issued instructions that while projecting the peak requirements of finance, banks should take into account the unpaid stocks and make suitable adjustment therefor, so as to curb double financing. These instructions to banks are also in line with the views of the 'Dehejia Committee.' The Bank is aware that in several cases the element of double financing cannot be eliminated forthwith without impairing the productive activity, and in such circumstances, banks are required to rectify the position in a phased manner. In any case, they should ensure that the existing quantum of double finance is not perpetuated or enlarged, particularly while fixing the **additional** credit limits for their borrowers; in so far as the existing quantum of double finance is concerned, the banks may progressively regularise the position, allowing the borrowers sufficient time for the purpose.

134. The Indo-Pak hostilities in December 1971 created an abnormal situation and it was also necessary to make sustained efforts to keep up the tempo of production in the various spheres. To help the defence effort and to facilitate the productive activities which needed immediate bank credit relaxations in the Bank's prior authorisation were made. Thus in the case of the textile industry and dealers in textiles, banks could, without prior authorisation, grant increased credit limits up to a maximum of 15 per cent of the existing authorised limits against inventories till July 1972@. Certain banks were requested to take immediate steps to see that the supply of credit to the shoddy and woollen mills which were executing defence orders from D.G.S. & D., was adequate and timely. It was suggested to banks that they could grant without prior authorisation, 'defence packing-cum-supply' credit limits both at the pre-delivery and post-delivery stages for manufacture and supply of goods to the defence authorities, as also for augmenting production in general and ensuring smooth distribution of goods, particularly in the border areas. Banks were further allowed to grant, without prior authorisation, suitable enhancements up to 15 per cent in the existing credit limits to the manufacturing units for their working capital requirements. Besides, banks were allowed to sanction credit limits to certain industries, so as to enable them to meet their temporary/seasonal needs. Thus, in the case of jute industry which was facing financial problems on account of considerable increase in the availability of raw jute supplies in the 1971-72 jute season, certain banks were advised to grant additional working capital limits without prior authorisation. Similarly, banks could grant to the sugar mills for the 1971-72 crushing season credit limits up to 80 per cent of those allowed against sugar during the 1969-70 season. Again, in the case of the coal industry, in order to help it in overcoming the difficulties arising out of the transport bottlenecks, banks were advised to grant to that industry additional credit limits up to a maximum of 15 per cent till December 1972. Sympathetic and prompt consideration was also given to the requests from the industrial units in the Eastern region as also in the under-developed/backward areas.

135. It may also be mentioned that as there were persistent complaints of delays/defaults by the sugar mills in paying the dues to the cane growers on account of cane supplied to them despite liberal credit facilities made available by banks against stocks of sugar, which should have normally been utilised for payment to the cane growers, banks were advised that while granting credit limits against stocks of sugar, they should introduce suitable regulatory procedures for ensuring prompt payment by the mills to the cane growers.

136. A reference was made in the last year's Report regarding the requirement of prior authorisation under the Scheme for sanctioning by banks (singly or jointly with other institutions) individual medium or longterm loan exceeding Rs. 25 lakhs repayable over a period of more than 3 years to any single party, irrespective of the totality of credit limits available to it from the banking system as a whole. As a result of this measure, there has been greater co-ordination in the activities of banks and term-lending institutions. It is also observed from the quarterly statements received from banks since the quarter ended September 24, 1971 (showing particulars of term loans exceeding Rs. 10 lakhs and repayable after 3 years sanctioned by them to the industrial concerns in the private sector), that term loans for larger amounts are now being sanctioned mainly on participation basis with the term-lending institutions or under the Refinancing Scheme of IDBI.

137. During the year July 1971-June 1972, 727 applications were received from banks for authorisation of credit limits under the Scheme, as against 338 during the year ended June 1971. The applications were mostly for working capital requirements and with the exception of only three applications, all these were authorised. However, in certain cases, while according authorisation, the Bank did not allow the additional/enhanced credit limits to the full extent applied for because, in its view, lower limits were adequate for the purposes stated taking into account the financial requirements of the concern's applying for the credit limits. Further, while authorising the credit limits, suitable stipulations were laid down in several cases, and some suggestions for improving the financial structure/position were also made. These were usually on matters such as non-payment of guarantee commission, subordination of promoters' funds to bank advances, inter-corporate lending/investments, requirement of bank's approval for declaraion of divdents, etc., and were designed to bring about better financial discipline.

Credit Controls

138. Announcing the credit policy for the 1971-72 busy season, the Governor indicated that the broad features of the earlier credit policy would be continued and the structure of refinance facilities would remain broadly the same except for some modifications in regard to refinance for food procurement advances (described in the chart appended).

@Since extended upto December 1972

REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE BANK OF INDIA

UPTO END OCTOBER 1971

Net Liquidity Position	At 4½%	At Bank Rate (6%)	Remarks
1	2	3	4
	I. Export Credit :		
Irrespective of net liquidity ratio.	Upto an amount equal to 10% of the annual average in 1970.	An additional amount of 10% of the annual average in 1970.	Borrowings equal to 20% of the annual average of export credit in 1970 will not impair the net liquidity ratio.
	II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed base period in respect of :		
-do-	(a) lending to primary cooperative credit scieties in selected districts of A.P., Haryana, M.P., U.P. and Mysore.	(a) short-term lending to small-scale industries covered by guarantee of C.G.O. (b) short-term direct lending to agriculturists.	**Base Period :** Average level of such credit in the corresponding calendar quarter of the previous year, *i.e.* for the quarter January-March 1971, base will be the average for the quarter January-March 1970.
—	**III. Bills rediscounting Scheme :—**		
-do-		Rediscounting of bills under the new Scheme.	Outstanding liability in respect of bills rediscounted under the new Scheme will not impair the net liquidity ratio.
	IV. Food Procurement Advances :		
-do-	—	Upto 75% of the increase over the outstanding level of such advances as on October 30, 1970, till end July 1971, upto 60% in August and upto 50% thereafter.	..

EFFECTIVE NOVEMBER 1, 1971

	I. Export Credit :		
Irrespective of net liquidity ratio.	Upto an amount equal to 10% the annual average in 1971.	An additional amount of 10% of the annual average in 1971.	Borrowings equal to 20% of the annual average of export credit in 1971 will not impair the net liquidity ratio. 1971 base to be effective from January 1, 1972.
	II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed base period in respect of :		
-do-	(a) lending to primary co-operative credit societies in selected districts of A.P., Haryana, M.P., U.P., and Mysore.	(a) short-term lending to small-scale industries covered by guarantee of C.G.O. (b) short-term direct lending to agriculturists.	**Base Period :** Average level of such credit the corresponding calendar quarter of the previous year, *i.e*, for the quarter January-March 1972, base will be the average for the quarter January-March 1971.
	III. Bills Rediscounting Scheme :		
-do-	—	Rediscounting of bills under the new Scheme.	Outstanding liability in respect of bills rediscounted under the new Scheme will not impair the net liquidity ratio till the end of October 1972.
	IV. Food Procurement Advances :		
-do-	—	10% of the outstanding level of food procurement advacnces as on the last Friday of October 1971 and an additional ⅓ of the increase over the level as on the last Friday of October 1971.	
	V. 'Defence Packing-cum-Supply' Credit :		
-do-	—	Upto the total outstanding level.	The facility will be available under the old Bill Market Scheme under section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (vide Governor's circular DBOD. No. GCS. B C. 142/C. 483-71 dated December 11, 1971).

Note : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 34%. An enhanced rate of interest is chargeable on the excess borrowings of a bank. It would be the rate raised by 1% per annum above the level of Bank rate for a shortfall of every one point or a fraction thereof in the bank's net liquidity ratio (below 34% at present). However, when the net liquidity ratio falls below 26% a maximum enhanced rate of 15% will be charged.

Selective Credit Controls

139. In the field of selective credit controls while those in regard to advances against raw cotton and kapas, foodgrains, oilseeds, vegetable oils (including vanaspati) were relaxed during the year, controls on advances against sugar, gur and khandsari were re-imposed.

140. To ensure adequate supply of credit to mills for buying and stocking **raw cotton,** the Bank modified on August 3, 1971 the provisions of margin control on advances against raw cotton and kapas, enabling specified categories of mills to carry stocks equivalent to an additional two weeks' consumption of cotton. Credit policy for the new cotton season announced on November 18, 1971 revised downward the minimum margin for advances granted to parties other than mills against the new cotton crop to 50-70 per cent from 60-75 per cent earlier, depending on the marketing periods of the different varieties of cotton. Further, with a view to encouraging local production, advances against new long staple varieties of cotton were exempted from ceiling control; however, they were subjected to a minimum margin of 40 per cent (later reduced to 25 per cent) and minimum rate of interest at 12 per cent. In regard to fixing of credit limits for parties other than mills, banks were permitted to maintain a level of credit during each four-month period commencing from October 1971-January 1972, equivalent to 100 per cent of the average aggregate level of credit maintained by each party in the corresponding four-month period in the 1970-71 season. Further relaxations of the control on advances against cotton and kapas were made on March 27, 1972 by way of reducing minimum margin in respect of new cotton crop by 10 percentage points, and by relating credit limits equivalent to the peak level of credit in the corresponding four-month period in the previous season. The specified periods of consumption by textile mills in respect of which the margins were fixed were increased by four weeks in all cases.

141. In the case of **foodgrains,** while advances against maize and barley were completely exempted from credit control with effect from August 7, 1971, advances against wheat were exempted from the ceiling control. Further, advances against rationed foodgrains granted to wholesale and retail dealers appointed/licensed by Government and operating under statutory rationing/fair price distribution system in all the States and Union Territories were completely exempted from the credit controls. In view of the improved supply position, controls on foodgrains were further relaxed by the Bank on January 3, 1972. Advances against wheat to roller flour mills were exempted from margin control. For the new offices opened on or after January 1, 1970 at a centre with a population of 1 lakh or below, a higher combined additional limit of Rs. 50,000 for each such office was allowed. Advances against foodgrains to traders covered by the guarantee of the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., were exempted from ceiling and margin control upto a maximum of Rs. 20,000, provided the trader under-took to borrow against foodgrains from only one bank. On April 19, 1972, banks were permitted to increase their advances against foodgrains by 10 per cent (beginning from March-April 1972) compared to the level in the corresponding period of previous year.

142. On August 7, 1971, the control on advances against **oilseeds and vegetable oils** including vanaspati was made applicable only to advances against groundnut, mustardseed/rapeseed, castorseed and linseed, oils thereof and vanaspati. An additional limit equivalent to 15 per cent of the level of advances in the corresponding two-month period in 1970 was allowed in respect of (i) oilseeds and (ii) vegetable oils including vanaspati in oilseeds producing areas and/or for accommodating new parties particularly oil mills in the unorganised sector. On January 3, 1972 advances against rapeseed/mustarseed oil and those against oilseeds vegetable oils and vanaspati to vanaspati manufacturers and registered oil mills were freed from ceiling control. Further, advances upto a maximum limit of Rs. 20,000 to traders against oilseeds, oils thereof and vanaspati covered by the guarantee scheme of the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., were exempted from margin and ceiling controls, provided the trader undertook to borrow against them from only one bank. In view of the prevailing price situation of groundnut, the minimum margin on bank advances against groundnut was reduced from 75 per cent to 60 per cent on May 30, 1972. Further, the minimum margin on advances to vanaspati manufacturers against vanaspati was also reduced to 60 per cent.

143. In view of the rising trend in prices of **sugar, gur and khandsari** and with a view to discouraging speculative holding of stocks of these commodities, the Bank reimposed control on advances against these commodities on September 23, 1971. A minimum margin of 50 per cent was fixed (which was subsequently raised to 65 per cent on December 27, 1971) and a minimum rate of interest of 12 per cent was prescribed on advances against these commodities granted to parties other than sugar manufacturers and to sugar mills in respect of such stocks which had left the factory premises and on which excise duty had been paid. Banks were also required to charge a minimum margin of 40 per cent on advances against lapsed releases of sugar subject to certain conditions. Advances against stocks of sugar pledged/hypothecated with banks which were intended for export were exempted from the purview of the control.

144. Following the declaration of war by Pakistan, bank advances against sugar, gur and Khandsari, oilseeds and vegetable oils (including vanaspati) foodgrains and cotton and kapas were exempted from controls on December 11, 1971 in border and near-border districts initially upto end-February, 1972 and subsequently till the end of October,1972.

145. With a view to encouraging the use of storage facilities provided by warehouses of Central and State Warehousing Corporations a reduction of 10 per cent was allowed (as in the case of foodgrains) in respect of other controlled commodities also on April 19, 1972, in the minimum margin to be maintained by banks in respect of their advances against warehouse receipts issued by such Corporations.

146. On May 30, 1972, the processing/manufacturing units covered under the Rural Industries Projects were exempted from the provisions of selective credit controls relating to advances against foodgrains, oilseeds, oils, vanaspati, cotton and kapas and sugar, gur and Khandsari in view of the difficulties experienced by these units in procuring finance from banks.

Working Group on Jute Industry

147. The special scheme recommended by the Working Group for providing some relief to jute industry by way of charging a concessional rate of interest on borrowings representing that portion of the mill's production which is exported, a mention of which was made in last year's Annual Report (para 291), is still under the consideration of Government.

Working Group on Tea Industry

148. The Working Group on Finance for Tea Industry, appointed by the Reserve Bank in September 1971, submitted its report in February 1972. The Group has made several recommendations for ensuring the flow of (both short-term and long-term) institutional credit to this industry. As it was felt that the short-term credit needs of tea gardens were more acute, a circular letter endorsing the relevant recommendations of the Group, was issued by the Reserve Bank of India to all the scheduled commercial banks on March 8, 1972.* The other recommendations of the Group are under consideration.

Working Group on Coal Industry

149. The Reserve Bank constituted, in January, 1972, a Working Group to study the immediate financial problems of coal industry and to review the existing institutional arrangements including bank credit for financing the industry, especially in the Eastern region, viz., Bihar and West Bengal.

*For text, see R.B.I. Bulletin, April 1972 pp. 674-675.

Study Group on Cashew Industry

150. A Study Group was set up by the Reserve Bank in March 1972 to review commercial bank lending to cashew industry with reference to its export and employment potential.

Report of the Banking Commission

151. The Banking Commission, appointed by the Government of India in February 1969 under the Chairmanship of Shri R. G. Saraiya, submitted its report on February 9, 1972. The major recommendations of the Commission relate to restructuring of commercial and co-operative banks, measures for widening their functional coverage, improving their operational efficiency, legislative reforms and areas for further research and study.

152. Besides these, the Commission has also made recommendations regarding credit planning, non-banking financial institutions, indigenous bankers, management development, training and recruitment for banks, and an information system in the context of the need for improving the institutional framework of the banking system.*

153. The recommendations of the Commission are under consideration of the Government of India and the Bank.

Committee on Banking Statistics

154. With a view to simplifying and speeding up the Uniform Balance Book and other associated returns and suggesting modifications therein in the light of the current requirements of data, the Reserve Bank constituted a Committee on Banking Statistics in April 1972. The Committee is expected to submit its report early.**

Other Organisational Matters

Foreign Branches of Nationalised Banks

155. As regards the branches of nationalised banks in Uganda, the necessary formalities having been practically finalised, the taking over of Bank of India (Uganda) Ltd., by Bank of Baroda (Uganda) Ltd., is expected to be completed shortly. The proposal to form a new company to take over the business of the eleven branches of three Indian banks in Malaysia, details of which were given in the last year's Report, has since been finalised and the scheme of reconstruction of these branches filed with the Ministry of Finance, Government of Malaysia under Section 14 of the Malaysian Banking Ordinance, 1958. A copy of the scheme has also been submitted to the Bank Negara Malaysia. It is expected that the new Malaysian Company will be registered very shortly.

156. Two of the four Indian banks operating in Singapore do not satisfy the statutory minimum capital requirements of the local legislation. Banks have been given time till January, 1973 to comply with the requirements. Action is being taken to amend the scheme prepared under Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act so as to change the capital structure of the banks concerned.

157. Mention may also be made here of a team, comprising an officer each from the Reserve Bank and the Union Ministry of Finance and Custodian of a bank that visited Singapore and Hong Kong to study the working of branches of nationalised Indian banks at these centres from the point of view of examining the extent of delegation and decentralisation of powers between the Head Office and foreign branches, scope for improving profitability of branches, the role of these branches in the promotion of Indian exports to and investments in South East Asia and attracting investments in India from people of Indian origin resident in the area. Besides, the team was also to examine the desirability of continuing the separate identity of the different Indian banks at the same centre. The team came to the conclusion that to facilitate flexibility of operation, considerable scope for grant of discretionary powers and extra-discretionary powers, subject to ratification by Head Officer later, to Managers of banks at these centres existed. Posting of senior officers in foreign branches and suitable reorganisation of Head Office set-up to expeditiously handle business of foreign branches have also been recommended. The building up of a commercial and economic intelligence cell composed of a couple of bankers, initially in Singapore, to assist Indian exports and joint ventures has been suggested. Banks are advised to offer a concession in the rate of interest to importers importing from India. The importance of building up foreign trade financing, which is lucrative has been emphasised. To get involved intimately in local business, the need to employ local persons in supervisory cadres, evolving documentation procedures for loans suited to local conditions and paying more attention to domestic industry, particularly small-scale ones, are felt to be important. On the question of the desirability of continuing the separate identity of branches of Indian banks at the same centre, the team believed that while it would depend upon the shape that the organisational structure banks will take in India, in the wake of the recommendations of the Banking Commission, it would be of advantage to retain, for the time being, the separate identity of the Indian banks at these two centres.

Credit Information

158. Mention was made in the last year's Report of the systematic revision in March 1971 of the system of collection and processing of credit information on the borrowers of banks and other notified financial institutions with a view to enhancing its utility to these institutions. Effective from February 14, 1972, the form of application seeking information from the Bnak relating to credit facilities enjoyed by their constituent has been revised. Under the revised procedure, the Reserve Bank now furnishes more comprehensive information including the total number of banks (without disclosing their names) that finance the constituents. Along with the enlargement of the scope of the information furnished, the facility of obtaining credit information directly from the Reserve Bank, instead of routing the applications through the Head Offices, has been extended to the various branches of banks and financial institutions. During the year under review credit information in respect of 2,255 applications was furnished to applicant banks/financial institutions as against 1,458 applications during the previous year.

159. It may be mentioned that pursuant to the view taken at the first meeting of the co-ordination committee of public sector banks held on November 1, 1969, that there should be greater exchange of credit information among all banks, a Study Group was constituted. The Study Group has submitted its report to the Reserve Bank. According to the Group, existing legal provisions provide adequate protection to banks for exchange of meaningful credit information not only in respect of borrowers but also in respect of prospective borrowers who have only deposit accounts with banks. In view of the organisational inadequacy inhibiting systematic collection of credit information from market sources in new areas and on small borrowers, the Group has recommended the setting-up of an autonomous body called Credit Information Trust, as a long-term measure, for the benefit of the entire banking industry. A time bound programme for implementing its recommendations has also been outlined by the Group. A copy of this report has been forwarded to all commercial banks for their comments.

Inspection of Banks

160. In pursuance of the Reserve Bank's programme of periodical inspection of commercial banks with a view to assessing their financial position as well as methods of operation, 35 scheduled banks and 2 non-scheduled banks were inspected, or taken up for inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 during the period. Besides, the inspection of foreign branches of Indian banks in Fiji Islands, Guyana, Japan, Hong Kong and Thailand was carried out/taken up during the period. In addition, scrutiny of the affairs of two banks one for judging whether there is a *prima facie* case for misfeasance proceedings under Section

*For a summary of the recommendations of the Commission, see Reserve Bank of India Bulletin, May 1972—pp. 826-837.

**The Committee submitted its report on August 7, 1972 and its recommendations have been accepted by the Bank.

45 I.(4) of the Banking Regulation Act and the other for issue of a certificate under Section 44(1) of the Banking Regulation Act, 1949 was carried out.

161. During the year under review, centrewise inspection of branches of commercial banks, to which a reference was made in the last year's Report, was conducted at 76 centres served by 364 offices of commercial banks.

162. Apart from the above inspection, a study of the systems and procedures obtaining in banks was initiated, during the period under review, to broadly identify the areas of deficiencies therein and to suggest improvements, wherever necessary, to enable the bank concerned to accomplish, in the best possible way, the objectives for which it exists, including the social objectives, and to eliminate, to the extent possible, the incidence of frauds. Studies in respect of two banks were made and the reports sent to the banks concerned for necessary action.

Bank Mergers

163. During the period under review, the business of the Indian Offices of Eastern Bank Ltd. (which had four offices in India) was taken over by the Chartered Bank with effect from July 1, 1971.

164. The Purbanchal Bank Ltd., a public limited company incorporated on January 18, 1972, with its registered office at Gauhati (Assam), was granted a licence to carry on the business of banking in India on June 14, 1972. It commenced business on July 3, 1972 on which date its name was also included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934. The bank's paid-up capital as on May 23, 1972 amounted to Rs. 8.06 lakhs divided into 13,430 equity shares of Rs. 100 each, Rs. 60 per share paid-up. Out of the above amount, the contribution made by the United Bank of India amounted to Rs. 2.70 lakhs in respect of 4,500 shares allotted to it. According to the Prospectus issued by the bank, out of its issued capital of Rs. 25,00,000 consisting of 25,000 equity shares of Rs. 100 each, an amount of Rs. 9,00,000 consisting of equity shares of Rs. 100 each has been reserved for subscription by United Bank of India, Directors and their relatives, friends and associates. (If any of the shares are not so taken up they will be utilised in meeting applications from the public).

Licensing of Banks

165. With the cancellation of licence to the Eastern Bank Ltd. and the grant of licence to the Purbanchal Bank Ltd. during the year, the number of licensed banks stood unchanged at 46 at end-June 1972. The number of banks in whose cases licences have been cancelled increased to 51 as at the end of June 1972. Besides, there were 22 banks in the public sector which are not required to hold a licence.

166. During the period under review, a licence under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on banking business in India was refused to one existing bank consequent upon the transfer of its liabilities and assets in its New Fund business to another bank. The total number of banks to which licences were refused stood at 283 as at the end of June 1972.

Liquidation Proceedings

167. During the period under review, six non-scheduled banks were dissolved by the High Court and one bank went into voluntary liquidation. The Bank of Karaikudi Ltd. (Madras Area) ceased to function as a banking company under Section 36(A)(2) of the Banking Regulation Act, 1949, while the name of the Inter-Provincial Banking Corporation Ltd. (Calcutta Area) was struck off the register under Section 560(5) of the Companies Act, 1956.

168. After obtaining the necessary directives from Central Government, the inspection of three banks under Section 45Q of the Banking Regulation Act, 1949 was taken up. Of these, the inspection of one bank was completed and the relative Inspection Report forwarded to Government and the respective High Court, on December 10, 1971. The inspection of the other two banks remained suspended as the relative records were not available.

Clearing House Facilities

169. As part of the Bank's policy of extension of banking facilities, 22 clearing houses were established during the year bringing the total number of clearing houses in the country to 137; of these, nine are managed by the Reserve Bank of India, 119 by the State Bank of India and 29 by the subsidiaries of the State Bank of India.

170. Following the recommendations of the Workshop held under the auspices of the National Institute of Bank Management in December 1969, the Bank took up with the State Bank of India, in February 1970, the question of examining the feasibilty of opening clearing houses at places with a population of 50,000 or more, as per the 1961 Census, which are being served by more than three or four banks. The State Bank of India has been taking steps to open clearing houses on the above basis. Of the 22 clearing houses established during the period under review, 16 were opened at such centres. A fresh list of centres eligible for opening clearing houses as per the 1971 Census is being prepared and will be furnished to the State Bank of India for drawing up its future programme for setting up clearing houses at the centres. The question of opening additional clearing houses at metropolitan centres is also engaging the Bank's attention.

Working Results of Public Sector Banks

All Public Sector Banks

171. An analysis of working results of 22 public sector commercial (*i.e.* State Bank of India, its seven subsidiaries and 14 nationalised Indian banks) reveals that their profits* at Rs. 12.8 crores, for the year 1971 showed an improvement of Rs. 2.7 crores (26.2 per cent) over that for 1970. The total income of these banks increased by Rs. 101.0 crores (24.5 per cent) during 1971 as compared to a rise of Rs. 76.3 crores (22.7 per cent) during 1970. The increase in the income during 1971 was mainly due to the rise in earnings from interest and discount, which rose by Rs. 91.6 crores in 1971 as compared to a rise of Rs. 71.5 crores in 1970. The rise in interest income was mainly due to the stepping-up of the rates of interest on advances following the rise in Bank rate from January 9, 1971 and the increase in the level of their advances. The total expenses of these banks increased by Rs. 98.3 crores (24.5 per cent) in 1971 as compared to an increase of Rs. 75.2 crores in 1970. Interest paid on deposits and borrowings showed an increase of 27.0 per cent as compared to a rise of 19.9 per cent in 1970, partly owing to the rise in interest rates on deposits and borrowings. The rise in the expenditure on salaries and allowances amounting to Rs. 35.9 crores (21.7 per cent) in 1971 was, however, lower than that in 1970, when it had increased by Rs. 36.5 crores or 28.4 per cent, reflecting smaller increase in the number of banking offices in 1971 than in 1970.

State Bank Group

172. Total income of the State Bank of India improved from Rs. 112.7 crores in 1970 to Rs. 142.1 crores in 1971. Income from commission, exchange and brokerage increased by Rs. 3.4 crores in 1971 as compared with a fractional increase of only Rs. 0.6 crore in 1970. The Bank's expenditure also increased by Rs. 28.3 crores (25.7 per cent) in 1971. In 1970, the rise in total expenses was of the order of Rs. 21.4 crores or 24.1 per cent. The profits of the State Bank of India, at Rs. 3.8 crores in 1971, recorded an increase of Rs. 1.1 crores (40.0 per cent) as against a small decline of Rs. 10 lakhs in 1970. Out of these profits, the Bank transferred Rs. 2.0 crores to Reserve Fund and provided Rs. 1.3 crores for dividend to shareholders.

173. The seven subsidiary banks of the State Bank increased their income from Rs. 32.5 crores in 1970 to Rs. 40.2 crores in 1971 mainly on account of larger interest earnings from loans and advances. Since their exepnditure also increased by almost the same extent as the income, their profits showed a marginal decline of Rs. 2 lakhs in 1971 as,

* Net of provision for taxes and for bonus to staff. The bonus provision has been included under establishment expenses.

against a rise of Rs. 10 lakhs in 1970. Out of the profits, these banks transferred Rs. 12 lakhs to reserves and provided Rs. 36 lakhs for payment of dividend.

Nationalised Banks

174. The fourteen nationalised banks, after meeting all their expenses and providing for usual provisions, transferred to the Government of India Rs. 4.43 crores in 1971 as compared to Rs. 4.17 crores in 1970.

175. The working results of the fourteen nationalised banks for 1971 reveal an improvement in their profits @ from Rs. 6.9 crores in 1970 to Rs. 8.5 crores in 1971. This improvement in profits occurred despite a sharp rise in their expenditure.

176. The total income of these banks increased by Rs. 63.8 crores to Rs. 330.6 crores in 1971; in 1970, it had increased by Rs. 49.4 crores. Interest payment on deposits and borrowings increased by Rs. 34.4 crores in 1971 as compared to a rise of Rs. 21.3 crores in the preceding year. However, the increase of establishment expenditure was only Rs. 20.1 crores during 1971 as compared to Rs. 22.3 crores in 1970. The profits of these banks, therefore, rose by Rs. 1.6 crores in 1971, as compared to a rise of Rs. 1.1 crores during the preceding year. Out of the profits during 1971, the nationalised banks transferred Rs. 3.94 crores to reserves and Rs. 4.43 crores to Government of India.

Working of Scheduled Commercial Banks other than Public Sector Banks

All Private Sector Banks with Deposits of over Rs. 10 crores

177. The working results of 25 private sector scheduled commercial banks (including foreign banks) with deposits of over Rs. 10 crores as at the end of December, 1971 showed an improvement in thenir profits* from Rs. 3.9 crores in 1970 to Rs. 4.6 crores in 1971, *i.e.* an increase of 16.3 per cent. The total income of these banks went up by Rs. 18.7 croes (26 per cent). The increase in income was mainly due to an improvement in earnings from interest and discount, which rose by Rs. 15.5 crores to Rs. 74.4 crores in 1971. The rise was mainly due to higher rates of interest charged by them on advances following the rise in Bank rate from January 9, 1971 and an increase in the level of their advances. The interest paid on deposits and borrowings showed an increase of Rs. 8.5 crores (27.4 per cent) in 1971 partly due to the rise in interest rates on deposits and borrowings and partly due to increase in interest-bearing deposits. There was also a rise in the expenditure on salaries and allowances by Rs. 4.50 crores, an increase of 22.8 per cent over 1970. A part of the rise in the expenditure on salaries and allowances was accounted for by an increase of 249 in the number of offices in 1971.

Private Sector Indian Scheduled Banks

178. The total income of private Indian scheduled banks with deposits exceeding Rs. 10 crores improved from Rs. 27 crores in 1970 to Rs. 35.6 crores in 1971, an increase of 31 per cent over the year. The increase in income was mainly due to interest and discount earned at Rs. 30.8 crores in 1971 as against Rs. 23.2 crores in the previous year. The substantial increase in the income was not, however, reflected in a corresponding increase in net profits, which increased only by Rs. 0.4 crore during the year. The increase in gross income was more of less offset by increase in interest on deposits and borrowings and salaries and allowances, etc. Some of the banks in this group, however, showed a better performance mainly due to a higher level of advances and consequently improved earnings from interest.

Foreign Banks

179. There was an increase of Rs. 10.3 crores (22.9 per cent) in the gross income of six foreign banks in 1971. Their establishment expenses during the last three years expressed as a percentage to gross income have declined from 27.1 per cent in 1969 to 25.2 per cent in 1971, the comparable ratios of 14 major nationalised banks being 32.9 per cent and 30.9 per cent, respectively. The published net profits of these banks showed an improvement from 2.8 crores in 1970 to Rs. 3.1 crores in 1971, a rise of 10.7 per cent over the year. The percentage of net profits of these banks as a group to working funds was higher as compared with the Indian scheduled commercial banks due to the following factors: (a) the foreign banks operate mostly in metropolitan cities, (b) they deal mainly in foreign exchange business, and (c) they generally have large-scale transactions. The Indian banks, on the other hand, deal not only with these types of business but also make advances to farmers, small industries and other small borrowers both in urban and rural areas.

Control over Non-Banking Companies

180. An important development during the year was the amendment, in December 1971, of the directions issued to non-banking companies so as to bring within their purview, unsecured loans from shareholders as also loans guaranteed by directors, ex-managing agents or secretaries and treasurers. Such loans, which were hitherto exempt from the restrictions relating to deposits, have now been subjected to a separate ceiling of 25 per cent of the net owned funds of companies with effect from January 1, 1972. A period of three years and three months has been provided for the adjustment of excess, if any, over the ceiling prescribed, of the unsecured loans mentioned above. To provide for the genuine business requirements of companies, however, certain categories of loans, particularly loans obtained on guarantees furnished by Government and any loan obtained from foreign sources have been specifically exempted from the purview of the directions.

181. Since the last year's Report, activities of some 'Finance Corporations' accepting deposits from the public and lending money at usurious rates of interest have also been noticed in the Punjab, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Gujarat. The question of enforcing the provisions of the local Money-Lenders Acts in relation to these corporations, and of amending these enactments so as to provide for certain additional safeguards has been taken up with the respective Governments.

182. The Government of Andhra Pradesh brought into force the Andhra Pradesh Chit Funds Act, 1971 on July 1, 1971. The question of amending the existing law relating to 'chitties' in Kerala and Tamil Nadu is under consideration of the State Governments. The Government of Mysore and the Union Territory of Goa, Daman and Diu are contemplating enactment of chit fund legislations.

183. According to the survey of deposits with non-banking companies based on the returns as on March 31, 1969, 2,241 companies out of a total number of 27,961 joint stock companies (financial and non-financial) at work submitted returns to the Reserve Bank of India. The total number of accounts reported was about 6.25 lakhs. The total amount of deposits (including exempted loans not counting as deposits at Rs. 270.76 crores) held by them as at the end of March 1969 was Rs. 593.65 crores. The corresponding figure as at the end of March 1968 was Rs. 477.89 crores (including exempted loans amounting to Rs. 209.59 crores). Unsecured borrowings to the extent of Rs. 121.64 crores by companies from foreign sources such as World Bank, U. S. A. I. D., I. D. A., C. D. F. C., and the Ex-im Bank are included in the figure of deposits as at March 31, 1969. The corresponding figure at the end of March 1968 was Rs. 79.60 crores.

Deposit Insurance Corporation

184. The number of insured commercial banks was reduced from 82 to 81 due to merger of one bank with another. No liability arose to the Corporation in this case. During the period under report no fresh liability of the Corporation arose in respect of insured deposits. The total claims paid or provided for by the Corporation since its inception upto June 30, 1972 amounted to Rs. 113.04 lakhs in respect of 14 banks, while the total repayments received, so far, in respect of the subrogated claims aggregating Rs. 113.04 lakhs since the inception, amounted to Rs. 49.99 lakhs.

@ The figures given are after adjustment for payment of bonus.

* Net of provision for taxes and bonus to staff. The bonus provision has been included under establishment expenses.

185. There was no change in the limit of insurance cover which stood at Rs. 10,000 per depositor. According to the latest available data, 96.3 per cent of deposit accounts and 62.1 per cent of the deposits in insured banks were protected by the insurance scheme as at the end of September 1971. The rate of insurance premium which was five paise per annum per Rs. 100 of deposits, payable by insured banks on their assessable deposits, was reduced to four paise per Rs. 100 from October 1, 1971.

Deposit Insurance Scheme in the Co-operative Field

186. The deposit insurance scheme was extended to the co-operative banks in the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union Territory of Goa, Daman and Diu with effect from July 1, 1971. The Corporation on that date registered as insured banks 385 eligible co-operative banks. During the period under report, however, the registration of five of these co-operative banks was cancelled as they ceased to be eligible co-operative banks and their names were also excluded from the list of "Primary Co-operative Banks" by the Agricultural Credit Department of the Bank. During the same period, eleven primary co-operative banks were registered as insured banks as they attained the status of primary co-operative banks by fulfilling all the conditions laid down in Section 2 (*cill*) of the Reserve Bank of India Act, 1934 read with Section 5(*ccc*) of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative societies). Thus, the total number of insured co-operative banks stood at 391 as at the end of June 1972.

187. The Reserve Bank of India is actively pursuing the matter with the remaining State Governments/Union Territories in order to enable the Deposit Insurance Corporation extend the benefit of the scheme to the co-operative banks operating in these areas.

III. DEVELOPMENTS IN CO-OPERATIVE BANKING

188. The Bank has endeavoured during the year under review to bring about a qualitative improvement in the overall co-operative credit administration in the country. Important developments in this sphere were (a) the raising of the proportion of credit earmarked for small and weak farmers; (b) provision of credit separately for kharif and rabi crops with a view to rationalising credit needs and the corresponding flow of funds; (c) encouraging increased use of farm inputs; (d) facilitating orderly marketing of agricultural produce by providing a separate line of credit for the purpose; (e) regulating the advances against cotton to discourage undue holding back of stocks; (f) introduction of further refinements in the lending policies, especially in the sphere of term-lending with a view to ensuring effective use of the limited resources; (g) enforcing financial discipline to ensure better management of the resources; and (h) undertaking special studies to identify the credit gaps in the co-operatively weak States with a view to rectifying, to the extent possible, the imbalance in co-operative development.

Agricultural Credit Board and its Standing Committees

189. Among the important subjects considered by the Agricultural Credit Board during the year were the recommendations of the Expert Group on State Enactments. Having a Bearing on Commercial Banks Lending to Agriculture and of the Committee on Differential Interest Rates, in so far as those related to agricultural loans. While the recommendations made by the former Committee for extending the concessions and privileges enjoyed by the co-operative banks to commercial banks engaged in the business of agricultural credit were endorsed, it was felt that the scheme of differential rates recommended by the latter should be initially implemented by the co-operative banks on a pilot basis in a few selected areas covered by SFDA and MFAL projects.

190. The Board also considered the question of co-ordinating the activities of the co-operative and commercial banks in the financing of agriculture. In view of the importance of co-ordination at the national level of all activities pertaining to the institutional credit support to agriculture, it was felt that it would be appropriate for the Board to perform this function through a Standing Committee of its own. It has, therefore, been decided to constitute a Standing Committee with the Governor of the Bank as its Chairman and the representatives of the co-operative and commercial banks and the Government of India and some of the State Governments, as members.

Financing of Small Farmers

191. Forty-six SFDA and 41 MFAL projects have been set up in the country on a pilot basis as referred to in the last year's Report. Special studies of SFDA programmes initiated last year at the instance of the Planning Commission, were also carried out this year. The working of Chhindwara SFDA project was studied by a team of officers from the Bank during the year. The team laid considerable emphasis on identification of farmers with reference to the income concept and suggested that it should be followed up by a 'specific programme' approach. The observations of the team have been communicated to the Planning Commission.

192. With a view to ensuring the availability of credit to the small and other economically weak farmers, the central co-operative banks were required to show, as mentioned in the last year's Report, not less than 10 per cent of their outstandings under the short-term agricultural borrowings from the apex bank for financing such farmers. The percentage was increased to 20 during the year. Of the 182 reporting central banks, 117 had complied with the requirements in 1971-72.

193. To minimise the burden of the initial investment for credit eligibility, the ratio of shareholdings to borrowing has been relaxed in the case of small farmers whereby a contribution of only 5 per cent need be made in the first year and 2-1/2 per cent in each of the subsequent two years in respect of short-term loans and 5 per cent in a lumpsum for medium-term loans. In the case of primary land development banks, the small farmers need contribute only 2 per cent in the first year and 1 per cent in each of the subsequent three years, thus raising the total shareholdings to 5 per cent of the borrowings.

194. As for investment credit, the concessions relate to the granting of a longer period of repayment and providing of lower margin money by the small farmers. Term loans upto Rs. 2,000 could be granted to the small farmers out of funds borrowed from the Bank against personal security instead of mortage security for purposes, such as poultry keeping and dairy farming.

Commercial Banks Financing Credit Societies

195. The transitional scheme of financing primary agricultural credit societies by commercial banks introduced in 1970 continued to operate during the year in 49 districts of five States, viz., Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Mysore and Uttar Pradesh. Recently the scheme has been extended to two districts of Orissa and the commercial banks in these districts are expected to finance the societies allotted to them from the kharif 1972 season. During the second year of the scheme, the crop loans advanced by the commercial banks to societies recorded an increase of Rs. 176 lakhs over the loans disbursed in the first year and the average amount of loan per society during the same period increased by Rs. 0.12 lakh to Rs. 0.50 lakh. Besides production credit, the commercial banks had also sanctioned term credit for development purposes to the extent of Rs. 39 lakhs upto the end of March 1972. With a view to revitalising the societies functioning in these areas, the Bank has sanctioned loans to State Governments out of the Long-term Operations Fund on liberal terms for share capital contribution to such societies.

196. A Study Team appointed by the National Institute of Bank Management at the instance of the Bank studied the working of the scheme in Mysore State and observed that a remarkable achievement had been made under the scheme, and in the interest of consolidation and extension of this type of financing of agriculture, it has suggested, among others, the appointment of paid managers and greater contribution from the State Government for meeting the cost of the paid staff. The Bank has been keeping a close watch over the progress of the scheme.

Co-operative Development

197. The Fourth Plan Mid-Term Appraisal brought to light regional disparities in the distributoin of agricultural credit and the need for rectifying this imbalance was engaging the at-

tention of the Bank and the Government of India. A central sector scheme for rehabilitation of the week central co-operative banks so as to improve the availability of agricultural credit in backward areas/States was formulated by the Government in consultation with the Bank. Under the scheme, a detailed investigation of the overdues of the central bank and the primaries is called for with a view to writing off irrecoverable loans and the amount eligible for such write-off is to be shared at the rate of about 20 per cent by each of the three tiers in the co-operative credit structure. The Bank is actively associated with the implementation of the scheme. As many as 74 banks were identified as weak by the Bank in accordance with the norms laid down in the scheme and follow-up action has also been initiated.

198. With a view to exploring the possibilities of expansion of agricultural credit in the co-operatively backward States, a micro-study of the credit situation was considered necessary and in pursuance of a recommendation made by the Planning Commission in this behalf, the Government of India have appointed an Expert Team to undertake the study in Assam, Bihar, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh. For West Bengal, the Bank's Governor appointed in January 1972 a team with the Chief Officer, Agricultural Credit Department as the Chairman to review the position of agricultural credit, district by district, and make appropriate recommendations to improve the agricultural credit situation. The latter team submitted its report in June 1972.

Co-operative Credit Policy, Procedures and Operations

199. With a view to enforcing discipline in the operations of credit limits sanctioned for seasonal agricultural operations, the Bank continued the policy of granting limits separately for kharif and rabi crops and also fixing minimum levels to which the borrowings of central co-operative banks should be brought down during any month of the year reflecting a return flow of bank credit. The special line of credit for marketing of cotton and *kapas* falling within the sphere of selective credit control was continued; and the Bank sanctioned, during the year, limits for the marketing of crops other than cotton and *kapas* as well. The Bank also provided, for the first time, financial accommodation to the marketing societies connected with sale of minor forest produce of tribals.

200. The overall performance of the co-operative credit institutions, *viz.*, the State and central co-operative banks, the State land development banks and the primary agricultural credit societies during the three years ended 1970-71 is presented in Table 22.

Table 22:—Progress of Co-operative Credit Movement

(Amounts in Rupees Crores)

Type of institution	1968-69	1969-70	1970-71 (Provisional)
(*a*) *State co-operative banks :*			
(*i*) Number	25	25	25
(*ii*) Owned funds	75	83	92
(*iii*) Deposits	216	234	279
(*iv*) Borrowings from the Reserve Bank of India	227	249	245
(*a*) of which, short-term agricultural	184	216	190
(*v*) Working capital	567	619	685
(*vi*) Loans issued	667	707	723
(*vii*) Loans outstanding	459	510	534
(*a*) of which, short-term agricultural	227	276	287
(*viii*) Percentage of (*iv a*) *to* (*vii a*)	81	78	66
(*b*) *Central co-operative banks :*			
(*i*) Number	341	340	340
(*ii*) Owned funds	155	174	193
(*iii*) Deposits	351	382	419
(*iv*) Borrowings from the Reserve Bank/apex bank	291	331	N.A.
(*v*) Working capital	830	928	1030
(*vi*) Loans issued	860	873	969
(*vii*) Loans outstanding	641	740	801
(*c*) *State land development banks :*			
(*i*) Number	19	19	19
(*ii*) Owned funds	36	46	58
(*iii*) Debentures outstanding	426	571	725
(*iv*) Working capital	488	638	807
(*v*) Loans issued	144	153	168
(*vi*) Loans outstanding	395	510	638
(*d*) *Primary agricultural credit societies :*			
(*i*) Number (in thousands)	168	163	161
(*ii*) Membership (,,)	29173	29766	30961
(*iii*) Owned funds	215	242	265
(*iv*) Deposits	57	63	70
(*v*) Borrowings	540	618	675
(*vi*) Loans issued	504	540	578
(*vii*) Loans outstanding	619	711	784

201. From the above, it may be observed that as against the loans of Rs. 534 crores outstanding at the level of State co-operative banks for various purposes, the amount owed to the Reserve Bank was of the order of Rs. 245 crores or about 46 per cent. It should, however, be noted that State co-operative banks have been increasingly relying on their own resources and consequently their dependence on the Reserve Bank borrowings for short-term agricultural loans has been progressively showing a declining trend.

Reserve Bank's Financial Assistance to Cooperatives

202. The data presented in Table 23 bring out the sustained increase in the financial accommodation provided by the Bank to the co-operative sector under the various heads and for various purposes, particularly in the context of the recent technological developments in agriculture.

Short-term Finance

203. Important measures effected during the year in respect of short-term finance are as follows: (i) The Girijan Co-operative Development Corporation which was recognised by the Bank for channelling agricultural credit to the tribal cultivators in some of the districts of Andhra Pradesh was sanctioned a short-term credit limit of Rs. 40 lakhs during the year. (*ii*) The Bank, for the first time, granted a limit of Rs. 1.50 lakhs during 1971-72 on behalf of one central bank in Orissa for the marketing of minor forest produce. (*iii*) With regard to the finance for the purchase, stocking, distribution, etc., of fertilizers, Bank accommodation to State co-operative banks was provided only in case the apex marketing societies were unable to obtain the necessary funds from commercial banks. As part of this policy the rate of interest hitherto charged at the Bank rate was raised to 2 per cent above the Bank rate from 1972, with a view to bringing the lending rates more or less on par-with those of commercial banks. (*iv*) The Bank continued to provide financial accommodation under Section 17(2)(*bb*) of the Reserve Bank of India Act for financing the production and marketing activities of the handloom/powerloom weavers' societies at a concessional rate of interest at 1-1/2 per cent below the Bank rate. Accommodation was also provided to the State co-operative banks for financing other cottage and small-scale industrial units coming under the 22 approved groups.

Table 23:—Reserve Bank Credit to Co-operatives, 1970-71 and 1971-72

(Amounts in Rupees Crores)

Purpose of Finance	1970-71 (July-June)				1971-72 (July-June)			
	Limits sanctioned	Drawals	Repay-ments	Out-standings	Limits sanctioned	Drawals	Repay-ments	Out-standings
I. Short-term :								
(i) Seasonal agricultural operations (at 2% below Bank rate)	390.11	424.49	449.76	188.84	394.04	468.51	505.27	152.08
(ii) Marketing of crops other than cotton and kapas					3.18	3.59	2.96	0.66
(iii) Marketing of cotton and kapas	10.65	8.56	9.52	1.03	11.70	10.25	10.10	1.19
(iv) Purchase and distribution of fertilisers (at 2% above Bank rate)(1)	16.80	11.27	21.11	4.22	24.75	23.04	18.49	8.76
(v) Production and marketing of handloom products (at 1½% below Bank rate)(5)	10.12	12.36	10.95	7.83	12.76	14.92	13.24	9.51
(vi) Financing other cottage and small-scale industries	0.47	0.02	—	0.02	0.86	0.59	0.20	0.33
(vii) Purchase and sale of yarn (at Bank rate)	0.80	0.04	0.06	0.03	0.97	0.14	0.17	Nil
(viii) Loans to ARC (at Bank rate)	8.00	11.80	4.28	7.52	8.00	1.36	8.88	Nil
II. Medium-term:								
(i) Agricultural purposes (at 1½% below Bank rate)	18.76	14.20	10.34	24.31(3)	20.62	6.15	9.76	20.70(3)
(ii) Conversion of short-term loans into medium-term loans in scarcity affected areas (at 1½% below Bank rate)	21.80	13.64	4.33	13.66(2)	31.39	24.08	12.04(2)	25.70(2)
III. Long-term:								
(i) Loans to State Governments for contribution to share capital of co-operative credit institutions	11.88(5)	12.49(4)	4.40	41.93	16.38	14.14	4.72	51.34
(ii) Long-term loans to ARC (at 4.25% Per annum)	..	..	..	..	5.00	5.00	..	5.00

(1) Prior to 1972, purchase and distribution of fertilisers was financed at the Bank arate by the Bank. However, from January 1972, the interest rate was raised 2% above the Bank rate with a view to aligning it to the lending rates of the commercial banks. Data relate to calendar years 1970 and 1971.

(2) Including rephasement.

(3) Including those against limits sanctioned at the Bank rate.

(4) Including extended loans of the order of Rs. 75.96 lakhs sanctioned during 1969-70.

(5) Data for financial year.

Medium-term Finance

204. In the sphere of medium-term finance, the Bank took special measures to ensure that the central co-operative banks conformed broadly to the discipline enforced by land development banks in regard to term lending. Central banks have been advised to make sure of the ground-water potential before sanctioning loans for sinking of new wells, installation of pump-sets, etc.

205. The Bank had further recognised the advances for purchase of milch cattle and poultry keeping made to the

small and economically week farmers for being reckoned within the stipulation of 40 per cent lendings to 'approved purposes' with a view to availing of accommodation from the Reserve Bank. The list of 'approved' purposes for medium-term agricultural loans has been widened by including such activities undertaken alongside agriculture as pig breeding, sheep and goat rearing, purchase of storage bins by agriculturists and purchase of rubber rollers under farm machinery. It has also been decided that to ensure the accommodation being utilised fully, medium-term credit limits now sanctioned for the co-operative year will henceforth be sanctioned for the calendar year from 1973.

206. The Bank continued the grant of medium-term credit to state co-operative banks from out of the National Agricultural Credit (Stabilization) Fund to enable them to convert the short-term loans into medium-term loans to tide over the difficulties arising out of natural calamities. Rephasing of conversion loans was allowed to one State co-operative bank due to persistent crop failure in its region. Besides, four State co-operative banks were sanctioned short-term credit limits of Rs. 9.65 crores at the Bank rate against the pledge of government/trustee securities representing investment of their stabilization funds for granting conversion facilities to the central co-operative banks. The drawal against these limits till June 1972 amounted to Rs. 7.1 crores and the amount outstanding as on June 30, 1972 was Rs. 5.4 crores.

Share Capital Loans

207. The liberal policy in respect of sanction of loans out of the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund to the State Governments was continued. This has the purpose of benefiting State Government contributions to the share capital of (a) weak central co-operative banks under a specific programme of rehabilitation, (b) viable societies in the special programme areas such as the SFDA/MFAL projects, (c) commercial banks financing societies, etc. In respect of the central banks facing the problem of inadequate liquid resources the Bank had in specific cases also sanctioned loans for share participation on special terms; such loans carried interest at 4 per cent and are repayable in three equal annual instalments.

208. During the financial year ended March 1972, loans aggregating Rs. 15.81 crores (excluding renewals to the extent of Rs. 0.57 crore) were granted to 14 State Governments from out of the Long-term Operations Fund for contribution to the share capital of five apex banks, 108 central banks, 6,999 primary agricultural credit societies, 10 central land development banks, 85 primary land development banks, 31 primary urban co-operative banks and one state industrial co-operative bank.

Long-term Finance

209. The Bank had, as in the past, ensured adequate institutional support to the debenture programmes of land development banks. As against the debenture programme of Rs. 140 crores for 1971-72 earlier envisaged, the land development banks actually issued debentures for Rs. 125.39 crores. Much of this (Rs. 107 crores) was subscribed by institutions such as Life Insurance Corporation of India, State Bank of India, other commercial banks, and the Reserve Bank of India, besides the State and Central Governments. The balance of Rs. 25 crores came from mutual support.

210. At a meeting of the representatives of the principal investors and central land development banks convened by the Bank in February 1972, the debenture programme for 1972-73 was approved at Rs. 122 crores as against the lending programme of Rs. 155 crores. The debenture programme was modified to ensure involvement of land development banks' own resources and to make them utilise the disposable resources profitably. The supported programme was placed at Rs. 100 crores and the balance of Rs. 22 crores was expected to be raised by way of self-help.

211. An important policy change during the year was the modification of the extent of supported programme in relation to overdues at the central land development bank level so that heavy over-dues in certain pockets of a State did not affect the eligibility for institutional support for the State as a whole to carry on the developmental programmes. The apex banks were, however, required not to finance the primary banks/branches if the overdues exceeded 50 per cent of the demand. As a special case primaries/branches with overdues exceeding 50 per cent were made eligible for loans from the apex bank for minor irrigation purposes provided such loans did not exceed 25 per cent of the total loans issued in 1969-70 or 1970-71 whichever was higher. Again, primaries/branches in the weaker States, *i.e.*, four Eastern States and Rajasthan and Jammu and Kashmir were also eligible for loans for financing the small farmers, irrespective of their overdues.

212. The Bank continued to lay emphasis as in the previous years on the purpose for which loans should be advanced by the land development banks. The condition that at least 90 per cent of the loans advanced should be for productive purposes, of which 70 per cent constituted easily identifiable purposes as in the past, was maintained during the year also.

213. With a view to bringing about co-ordination between the lending policies of land development banks in respect of schemes financed by the Agricultural Refinance Corporation and the Reserve Bank, the land development banks were advised (a) to ensure ground-water potential before granting loans for minor irrigation purposes; (b) to fix minimum land holding in respect of loans for different purposes to prevent over-capitalisation of investment or under-utilisation of sources; (c) to fix the period of loans on the basis of repaying capacity of borrowers and the useful life of the assets created from the investment and (d) to insist on reasonable contribution by the borrower towards the cost of investment.

214. During the financial year ended March 31, 1972, land development banks issued rural debentures for an aggregate amount of Rs. 4.09 crores, the Bank's contribution being Rs. 1.33 crores. Considering the limited saving potential in the rural areas of the Eastern States, and Rajasthan and Jammu & Kashmir and the loss of crop in the war affected areas of Punjab, the land development banks in these States were allowed a reduce programme of rural debentures at 2-1/2 per cent instead of 5 per cent of the ordinary debenture programmes.

Loans to the Agricultural Refinance Corporation

215. During the year, the Reserve Bank of India Act, 1934, and the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 were amended for enabling the Bank to grant long-term loans to the Corporation from the Long-term Operations Fund, as recommended by the All-India Rural Credit Review Committee. The Corporation availed of Rs. 5 crores sanctioned during the year. In addition, the Reserve Bank continued to give short-term loans to the Corporation (Table 23).

Co-operative Banking Regulation

216. With the inclusion of certain non-agricultural credit societies in the list of primary co-operative banks during the year, the number of co-operative banks coming under the purview of the Banking Regulations Act, 1949, has increased from 1,315 at the end of March 1971 to 1,337 at the end of June 1972 (29 State, 366 central and 942 primary banks).

217. During the year 1971-72, two State co-operative banks and three primary co-operative banks were issued licences to commence banking business in India under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to Co-operative Societies), raising the total number of licenced co-operative banks to 38. The number of offices of the co-operative banks which stood at 4,931 as on June 30, 1971 increased to 5,164 as on December 31, 1971. Licences were granted to the State and primary co-operative banks for opening 74 new offices as against 76 granted during 1970-71.

218. There were eight State and central co-operative banks which did not comply with the provisions of Section 11(1)

of the Banking Regulation Act, 1949. The financial position and working of these banks was closely watched. Out of 21 primary co-operative banks which did not comply with these provisions, applications of 11 banks had been recommended for exemption to the Government of India for a period of one year from March 1, 1972; four banks had subsequently complied with the provisions. The remaining were under cosideration.

219. Of 744 co-operative banks inspected during the year, 99 were inspected by the officers of State co-operative banks on behalf of the Reserve Bank under Section 35(1) of the Banking Regulation Act, 1949. During the period from July 1, 1971 to June 30, 1972, 721 inspection reports—15 State co-operative banks, 219 cental co-operative banks, 11 State and district industrial co-operative banks, 9 central land development banks, 5 State handloom weavers' societies, 3 apex marketing societies and 459 primary co-operative banks —were issued.

220. As mentioned in the last year's Report, the scheme of deposit insurance was extended to the co-operative banks in the three States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union Territory of Goa, Daman and Diu with effect from July 1, 1971. The remaining State Governments have been advised to enact suitable legislation for enabling the extension of the scheme to co-operative banks in their States.

221. The selective credit control measures for regulating the advances by co-operative banks against cotton were continued during the year with a view to arresting the tendency to hold back the stocks in anticipation of rise in prices. Co-operative banks which were found to be utilising their funds for procurement and buffer stocking operations were asked to desist from doing so and have been advised to conduct such operations only on agents basis.

Training Facilities

222. During the year, orientation study facilities were provided by the Agricultural Credit Department to the senior officers of the Government of Tamil Nadu, Assam, Gujarat, Madhya Pradesh and Goa, Daman and Diu. In addition, seven foreign dignitaries from Malaysia, Thailand, Ceylon, Iran, Trinidad and Bangladesh visited the Department and studied its working. The details of the training imparted to the Staff of the Reserve Bank, co-operative banks and of SFDA/MFAL project personnel by the institutions managed by the Bank are discussed under the section of Education and Training.

223. Besides, the Department organised at the Co-operative Bankers Training College, Poona, the first seminar of the Chief Executive Officers of primary urban banks in July, 1971 and the fourth Seminar of the Chief Executive Officers of the State co-operative banks and central land development banks in February, 1972. The main purpose of these seminars was to provide a forum for the paticipants to discuss their problems and exchange their views and experiences, particularly to bring about a measure of understanding of the difficulties in the execution of the approved policies so as to improve/take measures for the effective implementation.

Agricultural Refinance Corporation

224. During 1971-72, the Corporation approved 269 schemes of agricultural development and sanctioned financial assistance for an amount of Rs. 154.24 crores as against 100 schemes involving financial assistance to the extent of Rs. 62.15 crores sanctioned in the previous year. Of the 269 schemes, 176 are to be financed by the central land development banks, 11 by State co-operative banks and 82 by scheduled commercial banks involving refinance to the extent of Rs. 115.12 crores, Rs. 11.03 crores and Rs. 8.98 crores, respectively.

225. Of the schemes approved during the year, 198 were for minor irrigation, 40 for plantation/horticulture, 13 for land reclamation, 3 for fisheries and 5 for construction of godowns, 4 for poultry and 2 for development of dairy farming, and 1 each for soil conservation and sheep breeding and 2 for farm mechanization. Besides the above schemes, 342 schemes were under various stages of scrutiny in the Corporation as on June 30, 1972.

226. During the year, the Corporation approved reduction in the financial outlays in respect of 103 schemes sanctioned earlier and an upward revision in the financial outlay of 30 others. Extension of period was given in respect of 13 schemes on requests from the financing institutions due to operational difficulties. Taking into account the revision in the financial outlay in respect of certain schemes sanctioned earlier as a result of rephasing, withdrawal of schemes, etc., the total number of schemes sanctioned by the Corporation as on June 30, 1972 was 711; the total financial assistance and Corporation's commitment thereunder were Rs. 404.75 crores and Rs. 350.79 crores, respectively.

227. The disbursements made by the Corporation during 1971-72 aggregated Rs. 34.8 crores of which refinance by way of subscription to special development debentures of the land mortgage/development banks amounted to Rs. 28.40 crores. Disbursements made to the scheduled commercial banks and State co-operative banks, amounted to Rs. 3.26 crores and Rs. 3.32 crores, respectively. The disbursements made by the Corporation since its inception upto June 30, 1972 amounted to Rs. 124.69 crores.

Increase in ARC's Resources

228. The Corporation augmented its resources during the year under review from three sources, Government of India, Reserve Bank of India and open market. An amount of Rs. 10.4 crores was raised by way of borrowings from the Government of India, under Section 20(i)(b) and (c) of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963. These consist of a sum of Rs. 3.3 crores received as IDA credits under Gujarat, Andhra Pradesh and Haryana Agricultural Credit Projects and Rs. 0.05 crore as IBRD credit under Tarai Seeds Project and Rs. 7 crores under normal schemes. An amount of Rs. 5 crores has been sanctioned by the Reserve Bank from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund. The Corporation has availed of Rs. 5 crores which is to be repaid in ten equal annual instalments. The Corporation raised an amount of Rs. 8.25 crores under III series of 5-3/4 per cent ARC Bonds. With this, the total borrowings from the open market amounted to Rs. 27.71 crores. During the year seven scheduled commercial banks and six State co-operative banks repaid principal amounting to Rs. 0.12 crore and Rs. 0.38 crore, respectively. The Corporation also issued an additional share capital of Rs. 5 crores to enable it to borrow additional funds required to meet the growing demands from eligible institutions. The Government of India stood guarantee in regard to the repayment of principal and payment of a minimum dividend of 4.5 per cent in respect of this second issue of shares. The paid-up share capital of the Corporation thus stood at Rs. 10 crores as on June 30, 1972.

229. The following important items of policy and procedures during the year under review deserve mention.

(a) The contribution of State Governments to special development debentures floated by the central land development banks to finance minor irrigation schemes had been reduced to 10 per cent, instead of the normal 25 per cent with effect from the co-operative year 1967-68. This relaxation, which has been extended threafter from year to year, which was current upto June 30, 1972 has now been extended upto June 30, 1974.

(b) A reference was made in the last year's Annual Report regarding the extension of the concession of 100 per cent refinance in respect of viable schemes sponsored by the Small Farmers Development Agencies (SFDA) through eligible institutions upto June 30, 1972. This facility has now been extended upto June 30, 1973. As on June 30, 1972 fifteen such SFDA schemes for development of minor irrigation—five in Uttar Pradesh, four in Madhya Pradesh, there in Andhra Pradesh and one each in Haryana, West Bengal and Rajasthan—were sanctioned by the Corporation. The total financial assistance sanctioned by ARC in respect of these schemes came to Rs. 14.37 crores.

(c) The Corporation has also agreed to give 100 per cent refinance in respect of schemes formulated by the Marginal

Farmers and Agricultural Labour (MFAL) agencies and submitted through the central land development banks, State co-operative banks and scheduled commercial banks provided they are economically feasible and technically sound. This facility which was introduced this year has now been extended upto June 30, 1973. During the year under review, one scheme for development of minor irrigation in the Union Territory of Pondicherry was sanctioned by the Corporation. The total financial assistance and ARC's commitment in respect of this scheme was Rs. 0.16 crore.

Consultancy Service

230. The Corporation set up a Consultancy Service located in Lucknow on August 9, 1971. The main objects for which the Consultancy service has been set are referred to below:

(i) To help the financing agencies in getting through the procedures of locating, investigating, appraising projects and canvassing cultivators' support.

(ii) To make the State Governments technical service available to the financing banks in the process of investigation and appraisal.

(iii) To provide technical investigation in cases where the State Governments have no arrangements of their own for ground water investigation etc.

(iv) To assist the Land Development Banks in job evaluation processes for purposes of streamlining their organization, simplification of procedures, avoidance of delay in searching title and determination of norms of staff for supervision and control over lending operations.

Briefly, the Consultancy Service will concentrate on formulation of projects and will help accelerate the formulation of viable schemes of agricultural development in the Eastern States.

Financing of Tea Industry

231. As mentioned earlier, the RBI had constituted in September 1971 a Working Group on finance for tea industry consisting of representatives of the tea industry RBI and important financial institutions to review the existing institutional arrangements for meeting the credit needs of the tea plantations. A senior officer of ARC was associated with this group as a member.

Inland Fisheries

232. The Corporation had earlier circulated to financing banks guidelines for preparation of schemes for development of inland fisheries. For the first time the Corporation sanctioned, through a commercial bank, a scheme for development of inland fisheries in West Bengal.

Technical evaluation of minor irrigation schemes

233. Although commercial banks have been sponsoring a number of area development schemes for minor irrigation, it was observed that a majority of the minor irrigation schemes received in the Corporation lacked essential details on technical aspects, particularly on the ground-water availability. In order to expedite the evaluation of such schemes, the commercial banks have been advised by ARC in April 1972, to make arrangements to study the technical feasibility of the proposals and send the schemes to ARC alongwith a technical feasibility report from one of the experts on the panel of ARC in respect of each scheme. The terms of reference for the technical experts have also been advised to the banks.

234. The Agricultural Refinance Corporation Act, was amended during the year (i) to make the term 'pisciculture' broad-based to include development of fisheries, both inland and marine, catching of fish and all activities connected therewith or incidental; and (ii) to enable ARC to borrow from the RBI out of its National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund.

235. As reported in the last year's Report, IBRD/IDA had sanctioned seven agricultural credit projects. During the year, 3 more projects were approved by IDA. The details of which are given below:

Name of the Project	Assistance from IDA		Amount to be route through ARC	
	$ million	Rs) Crores	$ million	Rs. crores
1. Mysore Agricultural Credit Project . . .	40.000	29.11	36.700	26.71
2. Maharashtra A.C.P. .	30.000	21.83	25.401	18.49
3. Development of markets in Bihar	14.000	11.61	12.850	9.35

Table 24—Purpose-wise distribution of schemes sanctioned by the ARC during 1970-71 and 1971-72 (July-June)

(Amounts in Rupees Crores)

	July 1970—June1971				July 1971—June 1972			
	No. of schemes sanctioned@	Total financial assistance on schemes sanctioned	ARC's commitments to total financial assistance	Disbursements made during the year	No. of schemes sanctioned@	Total financial assistance on schemes sanctioned	ARC's commitments to total financial assistance	Disbursements made during the year
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Development of minor irrigation works .	55	49.41	44.52	23.06	198	116.30	104.30	26.77
2. Development of land	9	6.21	4.53	4.37*	13	10.44	7.90	2.34
3. Plantation and horticulture . . .	26	3.16	2.32	1.99	40	11.00	8.36	2.06
4. Farm mechanization	1	0.76	0.57	0.11	2	4.76	3.63	0.36
5. Development of poultry farming . .	2	0.04	0.03	—	4	0.08	0.06	—
6. Development of fisheries . . .	2	0.25	0.15	0.37	3	0.81	0.59	0.58
7. Dairy development	3	1.42	1.07	—	2	0.66	0.55	0.40
8. Construction of godowns . . .	2	0.90	0.73	0.72	5	9.43	9.17	2.47
9. Soil conservation					1	0.25	0.19	—
10. Sheep breeding					1	0.51	0.38	—
TOTAL	100	62.15	53.92	30.62	269	154.24	135.13	34.98

@ Excludes schemes sanctioned and withdrawn during the same year.

* Includes disbursements on account of soil conservation schemes.

VI. DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE

Industrial Development Bank of India

IDBI's Promotional Functions—New Initiatives

236. In order to promote industrial development particularly in backward areas, the IDBI has been engaged in a series of promotional functions regarding identification of project ideas and bringing them into fruition. With this end in view, as reported in the last year's Report, the IDBI with the assistance of other term-lending institutions as also the Reserve Bank had initiated in 1970 surveys of industrial possibilities in backward States. Upto the end of June 1971, such surveys were completed in respect of 10 States and one Union Territory; in respect of one State and three Union Territories, the surveys were completed during 1971-72. Survey of the only remaining backward State is being undertaken, while in the remaining two Union Territories, it is proposed to be taken up shortly. The IDBI has also carried out, with the assistance of other financial institutions as well as consultancy services, some district surveys as in the districts of Trivandrum and Mysore and the Rayalaseema belt of Andhra Pradesh. The IDBI is making arrangements with a University in West Bengal in respect of the survey of Purulia district, the most backward in the State. In respect of some project ideas identified in some States, preliminary feasibility studies have already been arranged and in respect of others, such studies are being undertaken.

237. The search for potential entrepreneurs is being intensified. The IDBI is in touch with SIDCs in some States as well as with some business houses for undertaking the implementation and management of some identified projects in the joint sector and providing on-the-job training to potential managers who could take over the management functions after an agreed period. The IDBI is playing the role of a catalytic agent in bringing together, under its leadership, all-India and State level institutions, as also the lead banks and the Industries Departments of State Governments, to form an Inter-Institutional Group in each State to take co-ordinated action on issues connected with industrial projects. Such Inter-Institutional Groups have already been formed in seven States.

Technical Consultancy Service Centre

238. In Kerala, the Inter-Institutional Group has sponsored a technical consultancy service centre, called the Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation (KITCO), for assisting it with regard to the various aspects of project work. It is envisaged that such technical consultancy service centres would be formed in some other backward States. A list of technical consultancy services available in the country has been prepared. The IDBI also established during 1971-72 close liaison with international organisations such as International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Asian Development Bank (ADB), and the United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO).

239. It was mentioned in the last year's Report that with a view to fostering industrial development in the less developed areas of the country, the IDBI introduced two schemes of concessional finance in May/July, 1970—one of concessional refinance to SFCs/banks in respect of all of their eligible loans upto Rs. 20 lakhs to small and medium-sized projects in the specified areas and another of direct assistance on concessional terms for setting up of projects in backward areas. The above concessions were extended from December 13, 1971 to existing units undertaking substantial expansion in the specified backward areas.

240. The other significant developments during the year were: (i) further liberalisation of the refinancing and rediscounting schemes of assistance and (ii) opening of 3 more branch offices by IDBI at Hyderabad, Kanpur and Bhubaneswar* which would function as information centres and contact points for State level institutions, Government agencies as well as potential entrepreneurs.

*Opened on July 1, 1972.

IDBI's Operations

241. During the year under review, the quantum of financial assistance sanctioned and disbursed under all the three schemes of finance, viz., direct assistance (other than for exports), refinance of industrial loans, and machinery bills rediscounting, was sizeably larger than in 1970-71. Total sanctions in respect of these categories of finance together rose from Rs. 97.7 crores in 1970-71 to Rs. 141.8 crores in 1971-72 and disbursements from Rs. 54.2 crores to Rs. 73.7 crores.

242. Sanctions of direct assistance to industrial concerns (other than for exports in the forms of loans, underwriting and guarantees rose from Rs. 47.2 crores (in respect of 31 projects) in 1970-71 to Rs. 65.9 crores (in respect of 37 projects) in 1971-72. Disbursements of direct assistance during 1971-72 aggregated Rs. 11.4 crores as against Rs. 8.6 crores in 1970-71. With the acceptance by the Government of India of the recommendations of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee and in terms of the guidelines formulated by the Government in regard to conversion into equity of a part of loan assistance given by all-India term-financing institutions, the IDBI has started stipulating the conversion clause in appropriate cases.

243. Effective sanctions of refinance of industrial loans also increased from Rs. 24.5 crores covering 1406 applications in 1970-71 to Rs. 30.6 crores covering 2003 applications in 1971-72. Bulk of the increase in refinance was accounted for by assistance in respect of loans to small-scale industries including small road transport operators.

244. Under the IDBI scheme for rediscounting of machinery bills to facilitate sale of indigenous machinery to prospective purchaser-users on deferred payment basis the amount of bills rediscounted has gone up from Rs. 28.5 crores in 1970-71 to Rs. 45.3 crores in 1971-72.

Export Assistance

245. In regard to export assistance, while sanctions under direct participation loans have increased over the 1970-71 level from Rs. 11.3 crores to Rs. 19.3 crores, the sanction under refinance of medium-term export credit was lower at Rs. 3.3 crores compared to Rs. 13.7 crores during 1970-71. The decline in the latter may be attributable to (a) the comfortable funds position of banks, (b) the exporter availing himself of direct export-credit from the IDBI in participation with banks, and (c) difficulty relating to shipping space in the wake of the Indo-Pakistan hostility.

IRCI

246. The Industrial Reconstruction Corporation of India (IRCI) which was set up at the initiative of the IDBI in April, 1971, for the provision of reconstruction and rehabilitation assistance to sick and closed units has made a significant beginning. It functions not as a mere lending institution, but as a reconstruction agency interested in finding out the causes for the present predicament of the assisted units and attempting to remove them. Its activities include restructuring of the management, providing technical and managerial guidance either through its staff or by procuring suitable personnel from outside. It also assures itself of an agreement between the labour and the management before its financial assistance is given. Since its inception upto the end of June, 1972, the IRCI sanctioned loan assistance on softer terms and guarantee facilities to 48 units for Rs. 7.4 crores. The employment involved in these 48 units was 38,326. Utilisation of assistance amounted to Rs. 2.7 crores in respect of 30 units.

Subscriptions to Shares and Bonds of other Financial Institutions....

247. During the year, the IDBI contributed Rs. 3.2 crores to the public and special debentures of ICICI, bringing the total assistance to that institution since inception upto the end of June 1972 to Rs. 18.9 crores. The IDBI also contributed during the year Rs. 41.3 lakhs to the share capital of IFCI and now holds Rs. 4.59 crores, i.e. 50 per cent of the paid-up share capital of that institution. The IDBI further contributed Rs. 1.37 crores to the paid-up capital of the

Industrial Reconstruction Corporation of India (IRCI) bringing the total contribution to Rs. 2.75 crores (including Rs. 25 lakhs subscribed by IDBI on behalf of the IFCI, pending an amendment of the IFC Act, which does not at present permit such subscriptions). Besides, the IDBI subscribed Rs. 80 lakhs to the share capital of three SFCs, bringing the total subscription to shares and bond issues of SFCs to Rs. 7.7 crores. IDBI has also subscribed to 51 per cent of KITCO's Rs. 2 lakhs paid-up capital.

Other Term-lending Institutions

ICICI and IFCI

248. On the other hand, the quantum of assistance provided by the other term-lending institutions has declined somewhat during the year under review. The ICICI's sanctions of direct loans (rupee and foreign currency). underwriting and direct subscriptions together declined from Rs. 43.9 crores in 1970-71 (April-March) to Rs. 39.7 crores in 1971-72, but disbursements increased from Rs. 28.9 crores to Rs. 30.3 crores. The decline in sanctions was mainly brought about by foreign currency loans which were Rs. 22.5 crores in 1971-72 as compared with Rs. 29.0 crores in 1970-71. There was also a marginal decline in underwrting. IFCI's sanctions (excluding guarantees) declined marginally from Rs. 32.3 crores to Rs. 32.1 crores as a result of decline in foreign currency loans and underwriting, but disbursements increased from Rs. 17.4 crores to Rs. 20.3 crores.

Operations of State Financial Corporations

249. The operations of 18 State Financial Corporation, inclding the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation, have continued to show a rising trend. The total loans sanctioned by them increased from Rs. 49.0 crores during 1970-71 (April-March) to Rs. 63.4 crores during 1971-72 (or by 30 per cent) and disbursements from Rs. 32.9 crores to Rs. 38.8 crores (by 17.9 per cent). Loans outstanding as on March 31, 1972 totalled Rs. 154.6 crores and were over 21 per cent higher than a year ago. The bulk of the financial assistance continued to be granted to the small-scale industries, and share of such assistance in the total sanctions and disbursements was Rs. 51.2 crores and Rs. 27.1 crores, i.e., 80 per cent and 69.8 per cent, respectively.

250. In order that the SFCs may play an effective role in stepping up the tempo of industrial development of the States as well as to discuss important problems the States were confronted with, a conference of Chairmen and Managing Directors of the Corporations was convened by the Finance Minister on November 3, 1971 at New Delhi. In pursuance of one of the recommendations, a Working Group under the Chairmanship of Shri R. K. Talwar (Chairman, State Bank of India) was set up to examine the scope for, and formulate the mechanics of co-ordination between SFCs and commercial banks in assisting industries in the small and medium sectors.

251. In the light of the recommendations of the Working Group on Resource Mobilisation, Profitability, etc., of SFCs, certain amendments to the SFCs Act have been proposed to the Government of India for their consideration.

Financing of Small-scale Industries

Credit Guarantee Scheme

252. The modified Credit Guarantee Scheme has made considerable progress during the year. So far, 173 credit institutions including all major commercial banks, State Financial Corporations and co-operative banks have joined the modified scheme. During the year under review, 72 unlicensed primary urban co-operative banks were included in the list of approved credit institutions, of which 22 have joined the scheme by executing the necessary agreement. The scope of the scheme was also extended to 'agro-service units', *i.e.*, units engaged in hiring out, servicing and repairing of agricultural implements, etc., sale of such agricultural implements, spare parts and inputs and offering of technical services such as soil testing.

253. The amount of guarantees outstanding as at the end of June, 1972 amounted to Rs. 913.3 crores as against Rs. 791.0 crores as at the end of June 1971. Since the introduction of the Scheme in July, 1960 upto the end of June, 1972, there have been 281 claims for an aggregate sum of Rs. 43.3 lakhs which were paid to the credit institutions. However, as at the end of May, 1972, amounts reported in default (which may eventually lead to settlement of claims) covered 4,425 accounts for Rs. 1431.1 lakhs as against 2,129 accounts for Rs. 800.8 lakhs as at the end of May, 1971.

254. The Reserve Bank as the Guarantee Organisation has been liberalising the Scheme's provisions whenever considered appropriate to do so. Accordingly, in order to encourage the credit institutions to grant credit facilities, on a more liberal basis to small-scale units located in the Eastern and Western border areas affected by the recent conflict with Pakistan, some of the major provisions of the Scheme have been temporarily liberalised by the Government of India on the advice of the Bank. The liberalisation, which took effect from December 16, 1971, envisaged the enhancement of the extent of guarantee cover to 90 per cent of the amount in default of the amount guaranted whichever is less. Simultaneously, the ceilings on the amount recoverable from the Guarantee Organisation by way of claims were also raised from Rs. 7.5 lakhs and Rs. 2.5 lakhs to Rs. 10 lakhs and Rs. 4 lakhs in respect of working capital advances and term loans, respectively. The temporarily liberalised provisions, initially effective upto March 31, 1972, were further extended upto June 30, 1972; advances covered under the liberalised provisions and recalled during the period when the relaxations are in force or during the next six months would, however, be eligible for the relative higher cover. On the recommendation of the Reserve Bank the Government have since extended the liberalised provisions for a further period of six months, i.e., upto December 31, 1972 in the Western region and discontinued the facility in the Eastern region having regard to the normal conditions now prevailing in that area.

255. With a view to ensuring that the credit institutions exercise due diligence and care both in the sanctioning and supervising of the advances to small-scale industrial concerns as well as in recovering the dues from them, the Guarantee Organisation conducts a test check of the accounts of small-scale units with the branches of the credit institutions. The coverage under test check was raised from 5 per cent of the reporting branches involving 425 branches during the first year of the operation of the modified scheme to 10 per cent involving 906 branches during the second year. It has been decided to maintain the coverage at 10 per cent for the third year also. Thus, by the end of the third year (1972-73), the Guarantee Organisation would have covered one-fourth of the reporting branches under the test check programme. The deficiencies observed through such inspections are taken up with the concerned credit institutions for rectification. Further, in respect of the accounts under default, the Guarantee Organisation, as a matter of procedure, inspects those accounts in order to have a first hand knowledge of the problems faced by the credit institutions in continuing their assistance to them. Where the units show promise of retrieving their position, the Guarantee Organisation suggests that the lending banks nurse these accounts; these efforts have yielded satisfactory results in certain cases.

Scheduled Commercial Banks' Advances to Small-scale Industries

256. The credit extended by scheduled commercial banks to small-scale industries recorded a further rise, but at a slower pace, during the period under review. The total credit (including term-loans and advances granted to craftsmen and other qualified entrepreneurs) extended during 1971-72 (April—March) rose by Rs. 84 crores to Rs. 578 crores*, which compares with an increase of Rs. 100 crores in 1970-71 and Rs. 132 crores in 1969-70. The increase in the number of units financed during the period under review (18,811) was also smaller than in the previous year (21,810). However, the share of advances granted to the small-scale sector in the total bank credit went up from 10.6 per cent as at the end of March 1971 to 11.1 per cent in March 1972.

* Provisional.

257. Two features in the flow of bank credit to small industries in recent years are noteworthy: the first is the steady decline in the average amount of credit limit sanctioned per unit from Rs. 91,700 in March 1970 to Rs. 83,100 in March 1971 and further to Rs. 75,700 in March 1972 indicating a gradual shift towards financing of smaller units in the small-scale sector. The second is the greater involvement of banks in financing small industries in industrially backward States, such as Assam, Bihar, Orissa and Uttar Pradesh, as reflected in the rising share of advances to small-scale industries in these States

258. Beginning with June 1971, arrangements have been made to obtain data on a continuing basis regarding term-loans granted by commercial banks to small-scale industries. The data indicate that banks have played a significant role in the financing of fixed investments in this sector. As at the end of March 1972, the term loans sanctioned by banks to small industries amounted to Rs. 132 crores covering 27,739 units. The amount outstanding at Rs. 89 crores as at the end of March 1972 formed about 15 per cent of the total outstanding bank credit to this sector.

259. Besides the State Bank of India and its subsidiaries, which had formulated special schemes for financing craftsmen and qualified entrepreneurs as early as 1967, all the nationalised banks and 18 other banks have also by now formulated similar schemes. The total credit limit sanctioned to these classes of borrowers as at the end of March 1972 amounted to Rs. 24 crores covering 8,076 units and the amount outstanding was Rs. 15 crores.

260. Credit extended by the SBI Group to small-scale industries as at the end of March 1972 amounted to Rs. 231 crores showing an increase of Rs. 34 crores over the March 1971 level which compares with the increase of Rs. 45 crores showing an increase of Rs. 34 crores over the March the number of units financed by the SBI Group between March 1971 and March, 1972 was 5,788 as against 11,796 in the corresponding period of 1971. In the case of the 14 nationalised banks, while the increase in outstanding credit during 1971-72 was Rs. 40 crores as against Rs. 45 crores in 1970-71, the number of units financed during this period (12,719) was higher than in the corresponding period last year (9,151).

261. The pace of expansion of credit granted by scheduled commercial banks to the small road and water transport operators was also lower during 1971-72 than in 1970-71. The net increase in the credit extended to this sector during 1971-72 was Rs. 12 crores or about half the increase in the previous year (Rs. 23 crores). As at the end of March 1972, the limits sanctioned amounted to Rs. 82 crores spread over 33,052 units, the balance outstanding being Rs. 60 crores.

262. As on the last Friday of March 1972, 14 banks had sanctioned credit limits for setting up of industrial estates for small-scale industries; the amount involved was Rs. 5.4 crores. The net rise in outstanding credit to this sector during April 1971-March 1972 (Rs. 1.6 crores) was a little more than half the rise of Rs. 2.8 crores in the corresponding period of the preceding year.

263. Mention may be made here that the Report of the Working Group on Financing of Industrial Estates set up by the Reserve Bank in 1970 is expected to be released shortly.

Committee on Settlement of Bills

264. The Committee set up by the Reserve Bank of India in October 1970 under the Chairmanship of Shri V. D. Thakkar to review the special credit schemes of the commercial banks had expressed its concern at the delay in the settlement of bills of small entrepreneurs by large industries. The Reserve Bank of India, accordingly constituted in April 1971 a Committee to study the problem of payment of bills by large and medium industries to small enterprises and entrepreneurs in respect of supplies made to them and to work out suitable arrangements so as to ensure speedy settlement of claims. The Committee extended the scope of the enquiry to cover the delay in payment of bills to small entrepreneurs by Government Departments/public sector undertakings. The Committee has made a number of useful and practical suggestions for minimising the delay in the payment of bills of small industries and these have been commended to the institutions and agencies concerned to take early steps to implement them, thereby removing one of the bottlenecks in the growth of small industrial enterprises in our country.

Unit Trust of India

Unit Scheme, 1964

265. Sales of units during 1971-72 (July-June) at Rs. 15.1 crores were lower as compared to Rs. 18.0 crores during 1970-71.

266. Units of the face value of Rs. 2.6 crores were repurchased during 1971-72 as against Rs. 3.2 crores during 1970-71. The total amount of units sold and outstanding with the Trust as on June 30, 1972 amounted to Rs. 104.7 crores, the total number of unit holders registered with the Trust being over 4,34,000. Unit sales during 1971-72, as in 1970-71, were adversely affected by the removal, under the 1970 Finance Act, of the special tax advantage which unit holders were enjoying on their income from units (referred to in the last year's Report). This factor together with the increase in interest rates on National Savings Certificates and those offered by nationalised banks on fixed deposits reacted adversely on the relative attractiveness of units as a medium of investment.

267. The total investments of the Trust aggregated Rs. 119.3 crores as on June 30, 1972. Of these, ordinary shares accounted for Rs. 44.6 crores (37.4 per cent), preference shares for Rs. 13.9 crores (11.7 per cent), and debentures for Rs. 41.9 crores (35.1 per cent). The balance of Rs. 18.8 crores (15.8 per cent) represented investments in Government Securities and Corporation Bonds, advance deposits for debentures and preference shares which the Trust had agreed to underwrite, advance call deposits, application money for purchase of shares and call and short notice deposits.

Unit Scheme, 1971

268. This Scheme was introduced on October 1, 1971 primarily as an adjunct of the Unit-linked Insurance Plan. At a later stage, the Trust may want to throw the Scheme open for all investors but for the time being at least the sale of units under the Scheme is made for the limited purpose of participation in the Unit-linked Insurance Plan. The object of this Plan is to provide investors, especially from the relatively small and medium-income groups of the community, a facility for regular savings and investment of their savings in the units of the Trust, combined with the advantage of insurance cover during the period of the Plan. The Plan has so far made slow progress with total sales amounting to Rs. 3.1 lakhs under 464 applications upto June 30, 1972. However, with the additional tax advantage granted in the Finance Act 1972, viz., the treatment of the contributions made under the Plan for income-tax purposes on the same basis as insurance premia and contributions to provident fund, the popularity of the Plan is likely to increase considerably.

V. DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL

269. As pointed out in Part I, the year under review was characterised by uncertainties in the international currency markets following the U.S. decision in August 1971 not to convert officially-held dollars and the U.K. announcement in June 1972 to float the pound. These events had their effect on the exchange rate of the rupee also.

Exchange rates—Sales and Purchases of Sterling by Reserve Bank

270. The U.S. Government announced on August 15, 1971 that they would cease to convert officially-held dollars into gold or other reserve assets, following which the U.K.

authorities announced that with effect from August 23, 1971, the dollar-sterling rate would be allowed to move in response to market forces although the parity of the pound sterling would remain unchanged at U.S. $2.40 is equal to £1. The dollar-sterling rate would not, however, be allowed to fall below $2.38 is equal to £1 but that when it tended to rise it would be allowed to float upwards without a ceiling at $2.42 per pound. Following these developments the Government of India announced that there would be no change in the gold (and, therefore, the U.S. dollar) parity of the Indian rupee and that the Reserve Bank of India would buy and sell pound sterling, for ready delivery, at rates to be determined every day having regard to the par value of the Indian rupee as fixed in June 1966 (which was U.S. $13.3333 is equal to Rs. 100) and the (floating) exchange rates for dollars in terms of sterling in the London market on the preceding working day by adding in the case of buying spot rate and deducting in the case of selling spot rate, a margin of £0.0175. This basis of fixing rates came into force from August 24, 1971. The margin was later reduced to £0.0125 with effect from September 8, 1971.

271. Forward purchases of sterling by the Reserve Bank of India which were suspended temporarily from August 23, 1971, were resumed with effect from August 28, 1971, for delivery upto six months at £5.5556 for Rs. 100.

272. Following the relignment of the parities of major international currencies on December 18 and 19, 1971, when a new rate for sterling in terms of the U.S. dollar was fixed 8.57 per cent higher than before (with the U.S. dollar devalued through an increase in the price of gold from $35.00 to $38.00 per fine ounce and the gold parity of the pound sterling remaining unchanged), the Government of India decided to de-link the rupee from the dollar and to adopt a central rate in terms of sterling, equivalent to the average of buying and selling rates of sterling based on the closing London quotations for dollars on December 17, 1971, i.e., immediately before the realignment. This rate was Rs. 100 is equal to £5.2721 or £1 is equal to Rs. 18.9677. The IMF was accordingly informed that India would take advantage of the wider band of 2.25 per cent on either side of the central rate for fluctuation of the buying and selling rates for sterling. The system was enforced from December 20, 1971. The authorised dealers were advised by the Reserve Bank, that its spot buying and selling rates based on the central rates of Rs. 100 is equal to £5.2721 would be as follows:

Buying ----£5. 2851 = Rs. 100

Selling ---- £5.2592 = Rs. 100

273. Forward purchases of sterling suspended from December 20, 1971 were resumed by the Bank with effect from December 28, 1971. The Bank offered forward cover facilities upto 9 months, at rates to be determined on the following basis:

Period of delivery	Rate of Exchange
Upto 3 months	RBI's prevailing spot buying rate *plus* a margin of £0.0125 per Rs. 100
Upto 9 months	RBI's prevailing spot buying rate *plus* a margin of £0.0250 per Rs. 100.

Contracts with an initial delivery period of three months were allowed to be extended for further three or six months at a charge of £.0.0125 per Rs. 100 per quarter. Further extension upto a total period of 12 months from the date of the original contract on payment of charges on the same basis was allowed in both the cases with effect from March 15, 1972. Thus, in effect, forward cover was available upto 12 months.

274. After the decision of the U.K. authorities on June 23, 1972 to allow sterling to float and the uncertain conditions in the international foreign exchange markets, the Bank's rates for buying and selling spot sterling were fixed with effect from June 26, 1972 at £5.2910 per Rs. 100 buying and £5.2632 per Rs. 100 selling. Forward purchases of sterling by the Reserve Bank were suspended.

275. After reviewing the position, these rates were revised, effective July 4, 1972, as follows:

Buying—£5.3333 per Rs. 100

Selling—£5.3050 per Rs. 100

The Bank resumed purchase of sterling on a forward basis upto 6 months on July 5, 1972 at the following rates:

Period	Rate of Exchange
Upto 3 months	£5. 3458 per Rs. 100
Upto 6 months	£5.3583 per Rs. 100

Forward contracts booked for an initial delivery period of 3 months were allowed to be extended for a further period of 3 months at a charge of £0.0125 per Rs. 100.

276. In the sphere of Exchange Control the Rules relating to travel, studies, etc., were revised during the year 1971-72 largely to take into account the exchange rate and price changes.

Travel abroad for business etc. purposes

277. The practice of classifying some businessmen as top-ranking for the purpose of release of exchange at higher scales for travel abroad on business grounds has been abolished by the Government of India. Hereafter businessmen will be classified into two categories, viz., (i) senior businessmen and (ii) travelling salesmen.

Release of exchange for higher studies

278. In view of the increase in the cost of living in U.K. and changes in exchange rates of Continental currencies, the Government of India decided to enhance the scale for release of exchange to students/trainees for their maintenance from £600 to £700 per annum generally for all countries other than U.S.A. and Canada and to £750 per annum in the case of students at Oxford and Cambridge Universities. This scale is exclusive of tution fees for which actual amounts as certified by the foreign university/institution will continue to be released as hitherto.

Exchange Quota for Haj Pilgrimage

279. Consequent on the revaluation of the Saudi Arabian ryals in the wake of realignment of the parities of major international currencies on December 18-19, 1971 (the gold parity of the ryals remained unchanged so that its par value has gone up by 8.57 per cent in terms of U.S. dollars), the exchange quota for persons performing Haj Pilgrimage has been revised upward from Rs. 1,575 to Rs. 1,670 per adult (above the age of 16 years and from Rs. 790 to Rs. 835 for each child between the ages of 14 and 16 years to enable the pilgrims to receive the same amount of foreign currency as before.

Surrender of Foreign Balances: Special Exemption

280. With a view to encouraging qualified Indians residing abroad to return to India for securing suitable employment, or for exploring the possibilities of setting up small-scale industrial units in this country, certain exemptions were granted in respect of regulations covering surrender of foreign currency balances. They would be permitted on application to retain their foreign currency balances for a period of three years from the date of their return to India, instead of having to surrender them within 30 days of the date of arrival. Under this facility, the balances will be allowed to be used by the holders to pay for imports of machinery, raw materials and components for which import licences will be issued on a liberal basis. The balances can also be surrendered with the right to re-transfer them abroad within a period of three years

or such further extended period which the Reserve Bank may allow.

Exchange Control with Bangladesh

Travel

281. Steamship/airline companies and travel agents have been permitted with effect from May 15, 1972 to book passages to Bangladesh for residents of India against payment of fairs in Indian rupees subject only to the completion of form 'P'. No prior approval on form 'P' from the Reserve Bank need be obtained and no restriction has been imposed on the number of trips to Bangladesh undertaken by any passenger. Visits to Bangladesh will also not be counted as visits abroad for purposes of Foreign Travel Scheme, 1970.

282. Indian national or persons of non-Indian nationality, who are permanently residing in India will be released exchange for meeting expenses for travel to Bangladesh for business (including attending conferences), studies, training, medical treatment, etc. The exchange will be made available only in Indian rupee travellers' cheques marked clearly as 'encashable only in Bangladesh in Bangladesh Taka'. The Bangladesh Bank has agreed to grant similar facilities to residents of Bangladesh for their visits to India.

283. Residents of India proceeding to Bangladesh for private visits are permitted to take out with them Indian currency notes upto Rs. 500 (other than notes of the denomination of Rs. 100 or higher) per person per trip. Similar limits have also been fixed by the Bangladesh authorities for residents of Bangladesh to take out Taka notes with them on visits to India.

Other transactions

284. Authorised dealers have been advisd that all transactions between Bangladesh and India other than those falling under the limited payments rupee trade arrangements will be allowed to be settled in sterling or any sterling area currency (except Pakistan rupees) or Indian rupees or Bangladesh Taka and will generally be subject to the same regulations as applicable to transactions with other countries outside India. The Bangladesh Bank has also similarly agreed to release sterling for settlement of approved transactions with India.

TABLE 25

Data Relating to Exchange Permits Issued and 'P' Forms Approved

A. Foreign Exchange Permits Issued for Study/Training Abroad during the period July 1971—June 1972

Country	Technical Courses		Non-Technical Courses	
	Number of Permits Issued	Amount of Exchange Released (Rs. 000s)	Number of Permits Issued	Amount of Exchange Released (Rs.000s)
U.L. and Europe :	508	37,88	551	16,96
U.S.A. and Canada	1,132	2,60,02	603	1,03,81
Othe. Countries :	201	13,54	78	2,19

B. Foreign Exchange Permits Issued for Travel Abroad for Purposes Other than Study/Training during the period july 1971-June 1972

	Number of Permits Issued	Amount of Exchange Released (Rs.000s)
Business	10,716	6,62,86
Medical treatment	576	57,95
Study tours	1,082	46,04
Attendance at conferences	1,413	28,34
Miscellaneous	5,678	1,33,33

C. Number of 'P' Form Applications Approved during the period July 1971—June 1972

Purpose	No. of 'P' Form Approved
Joining head of family	11,778
Visits to relatives	9,288
Export promotion	256
Employment abroad	4,253
Emigration for permanent settlement	6,083
Students/Trainees	3,130
Miscellaneous	23,190

VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE RESERVE BANK

Surveys

285. The decennial All-India Debt and Investment Survey 1971-72, being conducted by the Bank in collaboration with the National Sample Survey (NSS) Organisation of the Government of India and the Statistical Bureaux of the State Governments, was in progress during the year under review. The field work on the demand side investigations for the Survey is being carried out by the National Sample Survey Organisation for the Central Sample and that on the State matching sample and the Reserve Bank matching sample by the Statistical Bureaux of the State Governments. The demand side investigations for the Survey are conducted through canvassing of three schedules and a supplementary schedule, among 1,44,000 rural and 53,000 urban households covered by the Central, State and Reserve Bank samples. An additional village schedule will also be canvassed among the 12,000 villages selected for the demand side investigation. The Bank has set up Statistical Cells in the various State Headquarters to ensure smooth flow of filled-in schedules from the field and to carry out scrutiny and editing of the schedules.

286. At the instance of the Bank's Agricultural Credit Department, the Division of Rural Surveys of the Economic Department undertook the Fill Study on Crop-wise Scales of Finance in Kerala State. The object of the study was to collect the requisite material to serve as guidelines to District Central Co-operative Banks in arriving at realistic scales of finance for paddy and other important crops in Kerala. The Division also conducted a field study on the working of jointly-owned private wells and Government-sponsored community wells in Karad Taluk, Satara District, Maharashtra. This was undertaken with a view to evolving some guidelines to Small Farmers Development Agencies, land development banks and other appropriate credit institutions for taking up the financing of similar joint ventures in other areas as a measure of promoting minor irrigation schemes in the country for the benefit of cultivators, especially the small farmers. The Division's regular Survey of Co-operative Bank Advances and Deposits was also in progress during the year.

287. The Division of Rural Economics of the Economic Department also conducted during the period under review three studies, viz., (i) a field study on the operations of a mobile bank, (ii) study in collaboration with the Bank's Agricultural Credit Department on cash credit system for financing coconut cultivation in Kerala and (iii) an on-the-spot study of cotton markets in the Vidarbha region. Officers of this Division participated in an inter-departmental study on the working of the scheme of financing primary agricultural credit societies by commercial banks in Haryana, Mysore and Madhya Pradesh.

288. The Division of International Finance of the Economic Department finalised during the year the results of the survey of unclassified receipts during the quarter July-September 1970 (i.e., receipts in amounts below Rs. 10,000 or its equivalent for which no purpose-wise details are required to be reported to the Exchange Control Department

by the authorised dealers) referred to in the last year's Report, and a detailed note analysing the results was published in the November, 1971 issue of the Bank's Bulletin. The purpose-wise pattern revealed by this survey was more or less the same as that obtained in the earlier survey. No change was, therefore, called for in the basis on which the unclassified receipts are allocated to different purposes in the balance of payments statistics. The results of the survey for 1971 which covered the quarter April-June are being finalised. The survey for 1972, which covers the three-month period, February-April, is in progress. The Division continued to undertake on an annual basis the survey of freight and passage fare payments and receipts relating to Indian and foreign shipping and airline companies.

289. The Division of International Finance also continued to call for quarterly foreign investment survey reports from branches of foreign companies and Indian joint stock companies. The assessment of India's international investment position in 1968-69, based primarily on these reports, is under preparation.

290. During the year, the Division of Trade of the Economic Department launched two surveys, a Survey of Foreign Collaboration in Indian Industry and a Survey of Indian Joint Ventures Abroad. While the latter is a fresh Survey being conducted for the first time by the Bank, the Survey of Foreign Collaboration in Indian Industry is a followup of a similar Survey initiated in 1965, the results of which were published in 1968. The Surveys, already in progress, cover the period 1964-65 to 1969-70.

Seminars

291. A seminar of the economists of the public sector banks was held by the Reserve Bank in April 1972 to discuss the role of the economists working in banks in collecting appropriate statistics, involvement in policy and credit planning in evolving special schemes for priority sectors and deposit mobilisation and in pre-investment and post-investment appraisal of schemes in lead bank areas. In the same month the Bank also held a seminar of the heads of agricultural finance departments of the major commercial banks to discuss the problems faced by the banks in increasing finance to the agricultural sector and recovering loans advanced for agricultural development.

VII. EDUCATION AND TRAINING

292. Realising the importance of general as well as intensive training for the personnel at all levels—junior, supervisory and senior executive—not only in respect of its own but also in respect of the commercial banks, of co-operative institutions and even of Government Departments concerned with the execution of special schemes linked with institutional credit, the Reserve Bank has established various training institutions. These institutions have been carrying out a series of training courses. The year under review saw considerable expansion of activities in this regard.

National Institute of Bank Management

293. In terms of its long-term objectives, the National Institute of Bank Management (NIBM) expanded further during the period July 1971-June 1972 its capabilities to help the banking industry in training and developing its senior personnel, to provide a series of consultancy services, and to disseminate professional knowledge and information. During this period, in all nineteen programmes were offered in which four hundred and nineteen officers from banks in India and from abroad participated. These included advanced management training, senior executive course, executing development programme, branch management programme, credit management, workshop for trainers, first man-power development seminar, workshop for performance planning, and training for expert finance.

294. On the research side, which is the core of the Institute's activities, various studies in the areas of development banking and regional economic potential, credit risk analysis for agricultural lending, business planning and implementation for rural banking, financing of agriculture, investment and credit planning for maximisation of employment were launched and either completed or were in full swing Broadly, the research programme concentrated on contribution either to policy formulation or to the Institute's training programmes and consultancy for the banking industry.

295. The consultancy projects undertake during 1971 pertained to: (a) organisational planning, (b) decision making systems, (c) management development and (d) recruitment. A reorganisation project for meeting the rapid expansion of the Bank of Maharashtra has been undertaken and the report has been submitted. The Institute provided consultancy help to Bank of India, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank and Indian Banks' Association for the selection of clerical and officer staff using the battery of tests developed at the Institute. A total of 8,947 candidates was tested for clerical position and 5,755 candidates for officers' cadre.

296. NIBM started the publication of a quarterly journal titled Prajnan; its first issue was published in January, 1972. Three other publications, viz., Directory of Courses—1971-72 Edition, Programmed Text on Inland Remittances and NIBM Brochure were also issued.

Bankers Training College, Bombay

297. During the period under review, the College conducted five courses on Credit Appraisal and two courses each for legal officers of term-lending institutions and banks and for supervisory inspection staff of commercial banks. The College also conducted, for the first time, an in-company course on Credit Appraisal for the officers of Central Bank of India. Two courses each in Senior Banking and Foreign Exchange and one course each on Intermediate Banking, on Personnel and Organisation, and on Organisation and Methods were also conducted at the College. As mentioned in the last year's Report, two new courses, viz., a course on Project Appraisal (Financial) and another on Market Analysis for the officers of term-lending institutions as also for such officers of commercial banks as are handling term loans were introduced at the College during the period. The former course has since been merged with the Credit Appraisal Course.

298. The College is also conducting courses for the Bank's own officers. Two Central Banking courses for Staff Officers Grade I and a Credit Appraisal course for the officers of the Bank's Department of Banking Operations and Development and the IDBI were conducted at the College during the period. Further, two new courses, a course for the faculty attached to the Bank's own training institutions and a Central Banking-Advanced Course for the Senior Staff Officers Grade III were instituted. A few senior officers of commercial banks also attended the Central Banking-Advanced Course.

299. The total number of officers from banks and financial institutions including Bank's own officers who received training in the College during the period was 685. Since the inception of the College in 1954, 4,525 officers have received training in the different courses conducted by the College.

300. The College proposes to introduce very soon a course on Industrial Relations in Banking for the benefit of both the 'staff' and the 'line' executives of commercial banks and financial institutions and conduct short courses on Bank Statistics and Export Finance and a Seminar on Financing of Small-Scale Industries. The College also proposes to offer a two-tier course in Branch Management, in collaboration with the Indian Institute of Management, Ahmedabad for branch managers and accountants of commercial banks. The College is also working on an integrated course for middle level executives of commercial banks.

301. Further, the College is now designing a two-tier Afro-Asian Regional Course on Development Banking in collaboration with the Economic Development Institute, Washington, for executives and senior officers of development banks from various countries in Asia and Africa. The course is likely to be offered in early 1973.

Co-operative Bankers Training College, Poona

302. During the period under review, two courses for the managerial staff of State/central co-operative banks and one course each for the managerial staff of urban banks and central banks financing industrial co-operatives were held. Three courses for the branch agents of State/central co-operative banks, five courses for the land development banks (three general courses and two courses on project planning and appraisal) and three agricultural finance courses, one each for the senior and the middle level personnel of commercial banks and the officers of the Reserve Bank, were also held during this period. In addition, one refresher course each, for the managerial staff of State/central and urban co-operative banks and one special course each, for the managerial staff of land development banks in Tamil Nadu and Mysore States, were also held at the College. A special course for project officers and assistant project officers of Small Farmers Development Agencies/Marginal Farmers and Agricultural Labourers projects was introduced at the College and three such courses were held. The College also instituted short-term courses and two such courses on Banking Regulation Act and one course for the managerial staff of State/central co-operative banks on financing of weavers' societies were conducted during this period.

303. The number of officers from co-operative, land development and commercial banks who received training in the College during the period was 723. Since the inception of the College in September 1969, as many as 1,443 officers have received training in the different courses conducted by the College.

304. Besides these courses, two seminars, one each for the chief executive officers of State co-operative banks/central land development banks and urban co-operative banks were organised.

Staff Training College, Madras

305. The College continued to conduct the General Course on Central Banking for Staff Officers Grade II (Direct Recruits and Promotees) and Assistants and the Inspection Course for officers of the Bank's Department of Banking Operations & Development, the Industrial Finance Department and the Agricultural Credit Department on a regular basis. The College has also conducted two Induction Courses for Staff Officers Grade I/Grade II (Direct Recruits). The total number of employees who have so far received training in the college is 3,386.

Zonal Training Centres

306. The Zonal Training Centres at Bombay, Madras and New Delhi continued to conduct courses for junior and senior clerks of the Bank. The Zonal Training Centre at Calcutta could not be reopened during the period due to certain administrative exigencies. The total number of clerical staff who have so far received training in the various Zonal Training Centres is 6,961.

Other Matters of Education and Training

307. *Deputation of staff.*—Under the standing arrangements with the Administrative Staff College of India, Hyderabad, Bank's Officers were deputed to attend management development courses conducted by the College, Officers were also sent to participate in some of the courses conducted by the Bankers Training College for the officers of commercial banks and financial institutions, as also to short-term courses on management development organised by the All-India Management and State Level Associations, Management Institutes and a few other similar institutes. The Bank also deputed its officers to participate in the courses conducted by the I.M.F., the I.B.R.D. and the Asian Institute of Economic Development & Planning, Bangkok. The Bank deputed its officers to participate in the SEANZA Central Banking Course and other courses of interest to it organised by some other foreign institutions. Besides officers were also deputed for study visits/training to banking and financial institutions in the U.K., West Germany, Sweden, France and Italy.

Promotion of Hindi in R.B.I.

308. During the year under review, the Bank brought out the Hindi version of the Annual Report on the Working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1971, as also the Hindi version of the revised edition of the Functions and Working of the Reserve Bank of India. Besides, the Hindi translation of the revised exchange Control Manual (sixth edition) was sent to Government for publication in a special issue of the Gazette of India. The Bank also continued to offer assistance to its associate institutions, viz., the Industrial Development Bank of India, Agricultural Refinance Corporation, Unit Trust of India, Deposit Insurance Corporation and Credit Guarantee Corporation of India Ltd., for Hindi translation of their annual reports as well as their press communiques, advertisements, notifications, notices, etc.

309. In compliance with the provisions of the Official Languages Act, 1963, the Bank continues to issue press communiques/notes/releases/summaries, notices, advertisements and notifications simultaneously in English and Hindi. The letters and communications received in Hindi from the members of the public, the Central Government and the State Governments were entertained and replied to in Hindi.

310. At one of its meetings, the Official Languages Implementation Committee set up in the Department of Banking, Ministry of Finance appreciated the significant progress made by the Bank in the field of progressive use of Hindi. At its instance, a seven-member Official Languages Implementation Committee was set up in the Bank under the Chairmanship of the Chief Manager with the object of accelerating the progressive use of Hindi in the Bank. The Committee held its first meeting on March 24, 1972 and reviewed the progress made so far in the progressive use of Hindi in the Bank and in the Hindi teaching programme under the Bank's Hindi Teaching Scheme.

311. The Hindi classes continued to be conducted by the Bank under its own teaching scheme at different centres on voluntary basis for the benefit of the Bank's employees. The incentive provided for passing Hindi examinations were also continued during the year. The incentive of honorarium to the typists of the Bank for passing the Hindi Typewriting Examination continued to be offered. With a view to accelerating the pace of Bank's Hindi Teaching Scheme, the question of providing additional incentives to out employees was also taken up for consideration.

VIII. ACCOUNTS AND OTHER MATTERS

312. During the accounting year ended June 30, 1972, the Bank's income after making the usual and necessary provisions amounted to Rs. 222.17 crores as compared with the last year's income of Rs. 196.46 crores.

(Rs. in crores)

	Year	
	1971-72	1970-71
(i) Interest on Ways and Means Advances to State Governments. . .	15.32	10.21
(ii) Interest on Loans and Advances to the State Governments [other than on Ways and Means Advances referred to at item (i) above] and Commercial and Co-operative Banks .	20.56	21.74
(iii) Interest on Rupee Securities and Discount on Rupee Treasury Bills .	156.25	133.51
(iv) Interest and Discount on Foreign Securities, Investments and Treasury Bills	22.58	29.29
(v) Commission and profit or gain by Exchange	6.40	1.39
vi) Other income	1.06	0.32
TOTAL . .	222.17	196.46
Less Transfers to Funds as stated in Para 313	65.00	60.00
	157.17	136.46

313. The contributions to the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund were Rs. 19 crores, Rs. 6 crores and Rs. 40 crores, respectively, as against Rs. 18 crores, Rs. 2 crores and Rs. 40 crores, respectively, during the year 1970-71.

314. Out of the balance of income amounting to Rs. 157.17 crores after allowing for the total expenditure amounting to Rs. 37.17 crores during the year as against Rs. 36.46 crores in the previous year, the surplus of profit set aside for payment to Central Government was Rs. 120 crores as against Rs. 100 crores paid last year.

315. The rise of Rs. 25.71 crores in the total income from Rs. 196.46 crores to Rs. 222.17 crores was mainly due to increase in interest on rupee securities and treasury bills reflecting (i) the effect during a full year of the increase in the Bank rate by one per cent with effect from the January 9, 1971 (*ii*) the creation of *ad hoc* treasury bills for the Central Government for meeting the Centre's deficit and (iii) the high level of the State Governments' overdrafts during the year. The increase of Rs. 0.71 crore in the expenditure was mainly due to nominal increases in the various items of expenditure.

Auditors

316. The Accounts of the Bank have been audited by M/s. Ray and Ray, Calcutta, M/s. A. F. Ferguson & Co., Bombay, M/s. Suri & Co., Madras and M/s. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co., New Delhi who were appointed by Government of India as auditors of the Reserve Bank of India by the Notification No. F. 3(24)-BC/71, dated October 5, 1971 issued in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India Act. In addition to the Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi Offices, accounts at Bangalore and Patna Offices have been audited by the Bank's statutory auditors this year. The remuneration of the auditors has been fixed at Rs. 15,000 per office.

The Central Board

317. The term of office of Shri P. N. Damry, Deputy Governor, was extended by the Central Government for a period of two years with effect from February 13, 1972.

318. Shri P. L. Tandon and Dr. V. Shanmugasundaram retired as Directors of Central Board on the expiry of their terms of appointment on January 14, 1972. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by the retired Directors.

319. Consequent on his appointment as Comptroller and Auditor General of India, Shri A. Baksi ceased to be a Didector, with effect from March 26, 1972.

320. Shri S. N. Joshi and Dr. Bhabatosh Datta were appointed as Directors of the Central Board of the Reserve Bank of India with effect from February 7, 1972 under Section 8(1)(*c*) of the Reserve Bank of India Act, 1934. Shri C. P. Srivastava was also appointed as Director of the Central Board under the same Section with effect from February 17, 1972.

321. Seven meetings of the Central Board were held during the year, one each at Lucknow, Bombay, Madras, Calcutta, Bhubaneshwar, New Delhi and Shillong. The Committee of the Central Board held 51 meetings of which 6 were held in New Delhi, 2 in Calcutta, 1 in Madras and the rest in Bombay.

322. Shri V. G. Pendharkar, Executive Director, left India on April 14, 1972 to take up the appointment of Economic Adviser to the Bank of Tanzania under the Technical Assistance Programme of I.M.F.

Local Board

323. Shri Dayalji G. Patel resigned his office as a member of the Western Area, Local Board, Bombay, with effect from April 26, 1972. There was no other change in the composition or in the membership of the Local Boards during the year under report.

Opening and Closing of Offices and Changes in Organisation and Management

324. A sub-office of the Issue Department was set up at Ahmedabad with effect from December 1, 1971 and the Note Cancellation Section functioning at that centre was merged with the sub-office. Deposit Accounts Department was also opened on December 1, 1971, at that centre.

Bank's Premises

New Office Premises

325. A contract has been placed for the construction of the diaphragm wall for the proposed multi-storeyed building in the Mint Compound at Bombay and the work is in progress.

Leased Premises for Office Use

326. The State Archives Building where the sub-office of the Issue Department at Bhubaneshwar is to be located has been taken possession of. Arrangements have been made to take on lease necessary premises for opening a Regional Office of the Department of Banking Operations & Development at Bhubaneswar. Arrangements have also been made to take on lease office accommodation in a building under construction at Jaipur for housing the existing departments at that centre and for opening a sub-office.

Residential Quarters

327. The Bank is continuing its efforts to provide residential quarters which are heavily subsidised at all important centres. During the year under review, the construction of 16 quarters for clerical staff at Madras was completed, while construction of 1,038 quarters for clerical and sub-ordinate staff—272 at New Delhi, 444 at Calcutta, 218 at Kanpur and 104 at Nagpur—is in progress. As regards Staff Officers Gr. I and II the construction of 54 quarters at Bangalore is nearing completion, while construction of 152 quarters at Bombay is in progress. Further residential projects which will provide another 850 flats for clerical and sub-ordinate staff at New Delhi, Madras, Bangalore, Hyderabad and Bhubaneswar are in the planning/tender stage, while 258 flats for Staff Officers Gr. I and II at New Delhi and Kanpur are in the planning stage.

328. Efforts are being made to secure land for construction of quarters at centres where no plot has been secured or where the number of quarters provided is inadequate.

Employer-Employee Relations

329. Negotiations were held between the Bank and the All-India Reserve Bank Employees' Association on remaining items which were not covered by the earlier settlement. A settlement was signed on May 7, 1972 on combined seniority for the clerical staff of all departments and automatic switchover of eligible non-clerical staff to clerical cadre. Simultaneously the Bank has communicated its decision to the Association on a scheme for making promotions to the Staff Officers Gr. II in the Bank on the basis of a written test as against the present method of screening through a system of interviews. The Bank has also advised the Association that the number of posts earmarked for and to be filled by direct recruits to the cadre of Staff Officer Gr. II will be 17½ per cent of the sanctioned strength of Staff Officers Gr. II (as it will be from time to time) and that half of the posts for direct recruits will be reserved for and filled by members of the staff who qualify at the recruitment test.

330. The Bank has also set up a Committee known as "Reserve Bank of India Officer-Cadres Review Committee." The composition of the Committee is as follows:

Chairman

Mr. Justice J. L. Nain,
Bombay High Court, Bombay

Members

Shri V. Isvaran, I.C.S. (Retd.)
Prof. N. S. Ramaswamy,
Director, National Institute
For Training in Industrial
Engineering, Bombay.

The Committee is to review the existing emoluments-structure, promotion policy and procedure, methods of 'in-service' training, etc., of the officers of the Bank. The Committee met on several occasions during the year under review to hear the views of the All-India Reserve Bank Supervisory Staff Association, Reserve Bank of India Officers' Association and the Bank. The report of the Committee's is expected in a few months.

Employees' Housing Loan Scheme

331. During the year under report Housing Loans were sanctioned as under:

	No. of Societies	Amount Rs.
A. New Co-operative Housing Societies.	11	39,13,679
Additional loans to Co-operative Housing Societies already formed .	4	4,19,772
		43,33,451
	No. of Employees	**Amount Rs.**
B. Individual members of staff		
New loans	168	30,72,004
Additional loans to employees who had already availed of loans earlier	36	4,54,527
		35,26,531

The total amount of 'society' and 'individual' loans Sanctioned since the introduction of the scheme in 1961 amounts to Rs. 3,27,27,611.00 and Rs. 1,13,71,634.00, respectively. In all 2,069 employees have availed themselves of this facility.

RESERVE BANK OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT JUNE 30, 1972

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs. P.	Rs. P.	ASSETS	Rs. P.	Rs. P.
Notes held in the Banking Department .	28,79,48,120.00		Gold Coin and Bullion :—		
			(a) Held in India . .	182,53,10,862.72	
			(b) Held outside India		
Notes in circulation .	4877,73,13,265.50		Foreign Securities . .	221,65,38,085.47	
			Total		404,18,48,948.19
Total Notes issued . .		4906,52,61,385.50	Rupee Coin . . .		28,05,41,745.87
			Government of India Rupee Securities . .		4474,28,70,691.44
			Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper . .		. . . .
Total Liabilities .		**4906,52,61,385.50**	**Total Assets . .**		**4906,52,61,385.50**

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs. P.	ASSETS	Rs. P.
Capital Paid-up	5,00,00 000.00	Notes	28,79,48,120.00
Reserve Fund	150,00,00,000.00	Rupee Coin	2,77,688.00
National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	209,00,00,000.00	Small Coin	2,08,240.65
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	45,00,00,000.00	(a) Internal	9,85,75,721.88
		(b) External	
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	175,00,00,000.00	(c) Government Treasury Bills	311,17,49,668.84
		Balances held abroad*	195,27,24,607.67
		Investments**	448,18,03,896.33
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
		(i) Central Government	
(a) Government		(ii) State Governments‡	38,01,00,000.00
(i) Central Government	47,03,13,413.14	Loans and Advances to :—	
(ii) State Governments	7,91,08,468.66	(i) Scheduled Commercial Banks†	27,10,79,000.00
		(ii) State Co-operative Banks††	169,11,51,249.00
(b) Banks		(iii) Others	10,88,91,800.00
(i) Scheduled Commercial Banks	296,76,30,028.10		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	18,42,05,095.16	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	99,77,914.40	(a) Loans and Advances to :—	
(iv) Other Banks	76,52,821.40	(i) State Governments	53,05,82,256.54
		(ii) State Co-operative Banks	20,70,01,632.00
(c) Other	214,39,88,634.13	(iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	5,00,00,000.00
Bills Payable	75,52,14,714.43	(b) Investment in Central Land Mortagage Bank Debentures	10,60,77,030.00
Other Liabilities	285,28,09,886.83	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	25,70,39,464.00
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	92,82,33,544.00
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	84,74,57,057.34
Total Liabilities	**1531,09,00,976.25**	**Total Assets**	**1531,09,00,976.25**

Contingent liability on partly paid shares Rs. 9,48,388.69 (Sterling Investments of £ 50,000 converted @ Rs. 100=£5.2721)

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Seucrities.

** (i) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.

(ii) Includes Rs. 5,17,76,414.16 (equivalent of £ 50,000 and U.S. $ 6,982,500) held abroad.

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund.

† Includes Rs. 45,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

†† Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

S. JAGANNATHAN, Governor.
P.N. DAMRY, Deputy Governor.
R.K. HAZARI, Deputy Governor.
V.V. CHARI, Deputy Governor,
S.S. SHIRALKAR, Deputy Governor.

K.N.R. RAMANUJAM,
Chief Accountant.
Dated the 8th August, 1972.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED JUNE 30,1972

	Rs. P.
INCOME	
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc. £	157,16,50,995.40
EXPENDITURE	
Establishment	20,93,25,621.86
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses	65,527.68
Auditors' Fees	90,000.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.	1,02,10,648.99
Law Charges	2,16,523.57
Postage and Telegraph Charges	11,87,907.87
Remittance of Treasure	67,29,577.01
Stationery, etc.	27,98,163.31
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	4,80,22,762.31
Depreciation and Repairs to Bank Property	1,06,19,459.89
Agency Charges	7,28,37,842.14
Contributions to Staff and Superannuation Funds	
Miscellaneous Expenses	95,45,783.63
Net available balance	120,00,00,177.14
Total	**157,16,50,995.40**
Surplus Payable to Central Government	120,00,00,177.14

RESERVE FUND ACCOUNT

By Balance on 30th June 1972	150,00,00,000.00
By transfer from Profit and Loss Account	Nil
Total	**150,00,00,000.00**

£ After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

S. JAGANNATHAN, Governor.
P.N. DAMRY, Deputy Governor.
R.K. HAZARI, Deputy Governor.
V.V. CHARI, Deputy Governor.
S.S. SHIRALKAR, Deputy Governor.

K.N.R. RAMANUJAM,
Chief Accountant.

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA,

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30th June, 1972.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and of the Offices at Calcutta, Bombay, Madras, New Delhi, Patna and Bangalore and with the returns submitted and certified by the Managers of the other Offices and Branches, which Returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information from the Central Board such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act. 1934 and Regulations from thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank.

RAY & RAY,
A.F. FERGUSON & CO.,
THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.
SURI & CO.
} Auditors

Dated the 8th August 1972

[No. F. 10 (13)—BOI/72]
D.M. Sukthankar, Director

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1973

का. आ. 878.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, तेल-रहित चावल की भूसी का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम तेल-रहित चावल की भूसी का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है ।

2. तेल-रहित चावल की भूसी का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1966 में, —

(1) नियम 4 के उप-नियम (3) में, खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्, :—

"(2) गैस-बंद आवरणों के भीतर 120 घंटों की प्रभावन अवधि सहित एल्यूमिनियम फोसफाइड की 9 ग्राम/टन की मात्रा का प्रयोग करके ।"

(2) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. फीस-इन नियमों के अधीन—

(1) चार रुपये प्रति टन, यदि धूमक के रूप में मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग किया गया है ;

(2) तीन रुपये प्रति टन, यदि धूमक के रूप में एल्यूमिनियम फोसफाइड प्रयोग किया गया है,

की दर से फीस मान्यताप्राप्त प्रधूमन अभिकरण द्वारा धूम देने के लिये ली जाएगी ।"

[सं. 6(3)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

एम. के. बी. भटनागर, उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 24th March, 1973

S.O. 878.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of De-oiled Rice Bran (Quality Control and Inspection) Rules, 1966, namely:—

1. These rules may be called the Export of De-oiled Rice Bran (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1973.

2. In the Export of De-oiled Rice Bran (Quality Control and Inspection) Rules, 1966,—

(i) in sub-rule (3) of rule 4, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) Aluminium Phosphide by using a dose of 9 grams/tonne with an exposure period of 120 hours under gastight covers.";

(ii) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. **Fees.**—A fee at the rate of—

(i) four rupees per tonne if Methyl Bromide is used as a fumigant;

(ii) three rupees per tonne if Aluminium Phosphide is used as a fumigant,

shall be charged by the recognised fumigation Agency for carrying out fumigation under these rules.".

[No. 6(3)/72-EI&EP]

M. K. B. BHATNAGAR, Deputy Dirctor, (Export Promotion)

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1973

का. आ. 879.—श्रीमती रीमन्दर कौर धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रंजीत सिंह मान को 1964 मर्सीडीज बेन्ज 190 सैलून कार के आयात के लिए 15000 रु. का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं पी/जे/3039500/एन/एम पी/42/एच/33-34 दिनांक 16-3-72 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया है । आगे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका उपयोग नहीं किया गया था ।

इस तर्क के समर्थन में श्रीमती रीमन्दर कौर ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । उन्होंने यह वचन दिया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट के मिल जाने पर वह उसे कार्यालय रिकार्ड के लिए वापिस लौटा देंगी । मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3039500/एन/एम पी/42/एच/33-34 दिनांक 16-3-72 खो गया है और निदेश देता हूं कि उन्हें अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी किया जाना चाहिए । मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट को रद्द किया गया समझा जाए ।

[सं. 2(आर-221)/71-72/बी एल एस/5153]

एम. जी. गोम्बर, उप-मुख्य नियंत्रक

पदेन मुख्य-नियंत्रक

(Office of the Chief Controller of Import and Exports)

ORDER

New Delhi, the 13th March, 1973

S.O. 879.—Mrs. S. Raminder Kaur W/o late Shri Ajit Singh Mann was granted custom Clearance Permit No. P/J/3039500/N/MP/42/H/33-34, dated 16-3-1972 for Rs. 15,000 for import of a 1964 Mercedes Benz 190 Saloon Car has applied for a duplicate copy of the custom clearance permit as the original Customs Clearance Permit has been lost. It is further stated that the original Customs Clearance Permit was not registered with any Custom House and not utilised.

In support of this contention Mrs. Raminder Kaur has filed an affidavit. She has undertaken to return the Custom Clearance Permit if traced later to this office for record. I am satisfied that the original custom clearance Permit No. P/J/3039500/N/MP/42/H/33-34, dated 16-3-1972 has been lost and direct that a duplicate Custom Clearance permit should be issued to her. The original custom Clearance Permit may be treated as cancelled.

[F. No. 2(R-221)/71-72/BLS/5153]

Sd/-

M. G. GOMBER, Dy. Chief Controller.

for Chief Controller

(उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

बंगलौर, 1 फरवरी, 1973

विषय :—5100 रु. के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं. पी/एस/1676183/सी/एक्स.एक्स/40/एक्स/33-34 दिनांक 17-9-71 की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति को रद्द करना ।

का. आ. 880.—सर्वश्री आनन्द ट्रान्सपोर्ट एंड प्रिंटर्स, 12/1, विनोबा रोड, मैसूर-5 को आफसेट प्रिन्टिंग के लिए रबड़ ब्लैंकेट्स तथा लिथोग्राफिक जिंक प्लेट्स के आयात के लिए 5100 रु. का एक आयात लाइसेंस सं. पी/एस/1676183/सी/एक्स.एक्स/40/एक्स/33-34 दिनांक 17-9-1971 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई के पास पंजीकृत करवाने के बाद और आंशिक रूप से 3476 रु. का उपयोग कर लेने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और अब उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति शेष बचे मूल्य यानी 1624 रु. के लिए चाहिए ।

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई और निदेश देता हूं कि आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए । लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है ।

[संख्या आई.टी.जी/एल.एस.आई/483/सी.69/ए.एम.72/एन.पी]

के. जयरामन, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Bangalore, the 1st February, 1973

Subject:—Cancellation of Customs Purpose Copy of Licence No. P|S|1676183|C|XX|40|X|33-34, dated 17-9-71 for Rs. 5,100.

S.O. 880.—M/s. Anand Transport and Printers, 12/1 Vinoba Road, Mysore-5, were granted Import Licence No. P|S|1676183|C|XX|40|X|33-34, dated 17-9-1971 for Rs. 5,100 for the import of Rubber Blankets and Lithographic Zinc Plates for offset Printing. They have now applied for duplicate copy of Customs Purposes Copy of the above licence on the ground that the original of the above Customs Purposes Copy of licence has been lost/misplaced after having been registered with Collector of Customs, Bombay and utilised partly for Rs. 3,476 and that the duplicate copy of Customs Purposes Copy of above licence now required is for the balance value of Rs. 1,624.

In support of the above contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs Purposes copy of the above licence has been lost/misplaced and direct that a duplicate copy of Customs Purposes copy of above licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes copy of the licence is hereby Cancelled.

[No. ITC/SSI/483/C. 69/A.M. 72/NP]

K. JAYARAMAN, Deputy Chief Controller.

परमाणु ऊर्जा मंत्रालय

आदेश

बम्बई, 26 फरवरी, 1973

का० आ० 881.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, के नियम 9 के उपनियम (2) नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि दिनांक 27 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र के भाग दो खण्ड तीन उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी भारत सरकार के आदेश संख्या का० आ० 3187 दिनांक 3 दिसम्बर, 1970 में निम्नलिखित संशोधन किए जायें, नामत :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(1) "भाग II-साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III में"—

(क) 'विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में पद" के मद (VII) के उप-मद (ख) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, तथा

(ख) "मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में पद" के मद (VIII) के उप-मद (ख) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-मद तथा प्रविष्टियां शामिल की जायें, नामतः

"(ख) प्रशासनिक पद	मुख्य प्रशासन अधिकारी	मुख्य प्रशासन अधिकारी	सभी	निदेशक"
"(ख) प्रशासनिक पद	मुख्य प्रशासन अधिकारी	मुख्य प्रशासन अधिकारी	सभी	निदेशक, परियोजना इंजीनियरी प्रभाग"

2. "भाग III-साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग IV" में:—

(क) "विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में पद" के मद (vii) के उप-मद (ख) तथा उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, तथा

(ख) "मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में पद" के मद (viii) के उप-मद (ख) तथा उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उप-मद तथा प्रविष्टियां शामिल की जायें, नामतः—

(ख) प्रशासनिक पद	प्रशासन अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	सभी	मुख्य प्रशासन अधिकारी"
"(ख) प्रशासनिक पद	प्रशासन अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	सभी	मुख्य प्रशासन अधिकारी"

[सं० 22 (1)/68-प्रशासन]

डी० सी० भोपड़ा, उप सचिव,

MINISTRY OF ATOMIC ENERGY

ORDER

Bombay, the 26th February, 1973

S. O. 881.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President thereby directs

that the following amendments shall be made in the Order of the Government of India in the Department of Atomic Energy No. S.O. 5187; dated the 3rd December, 1970, Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th November, 1971, namely:—

In the Schedule to the said notification

(1) in "Part II-General Central Service, Class III",—

(a) for sub-item (b) of item (vii) relating to "Posts in Power Projects Engineering Division" and the entries relating thereto, and

(b) for sub-item (b) of item (viii) relating to "Posts in Madras Atomic Power Project" and the entries relating thereto,

the following sub-items and entries shall respectively be substituted, namely:—

"(b) Administrative Posts	Chief Administrative Officer	Chief Administrative Officer	All	Director".
"(b) Administrative posts	Chief Administrative Officer	Chief Administrative Officer	All	Director, Power Projects Engineering Division".

2. In 'part III-General Central Service, Class IV",—

"(a) for sub-item (b) of item (vii) relating to posts in Power Projects Engineering Division" and the entries relating thereto, and

(b) for sub-item (b) of item (viii) relating to "posts in Madras Atomic Power Project" and the entries relating thereto,

the following sub-items and entries shall respectively be substituted, namely:—

"(a) Administrative posts	Administrative Officer	Administrative Officer	All	Chief Administrative Officer".
"(b) Administrative posts	Administrative Officer	Administrative Officer	All	Chief Administrative Officer".

[No. 22 (1) 68-Adm]

D. C. CHOPRA Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(लोहा और इस्पात नियंत्रण)

आदेश

कलकत्ता, 3 मार्च, 1973

का० आ० 882 [सं० ई एस एस-कौम०/ई पी ओ ई/80].—आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनों के लिये उत्पादन और वितरण का विनियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत अधिसूचना सं० एस० ओ० 1436 दिनांक 18-4-67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद् द्वारा नीचे दिये गये तालिका के स्तम्भ 1 के फर्म को स्तम्भ 2 में उल्लेखित वस्तुओं को, स्तम्भ 3 में नामांकित फर्म को इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात हेतु स्तम्भ 4 में दिये गये मूल्य पर, स्तम्भ 5 में दिये हुए शर्त पर विक्रय करने का आदेश देता हूं।

फर्म का नाम	वस्तुओं का विस्तृत विवरण	निर्यातक का नाम	मूल्य	शर्त
1	2	3	4	5
मेसर्स इंडियन स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इन्द्रनगर, टाटानगर, सिंगभूम।	एच० बी० वायर्स 205.737 एम० टि० (दो शत पांच दशमलव सात तीन सात सिर्फ)	हिरो साइकिल्स प्रा० लि० जी० टी० रोड, हिरो नगर, लुधियाना-3	सामान्य मूल्य जो माल के भुगतान के समय हो।	माल का भुगतान निर्यात प्राथमिकता के आधार पर (अर्थात् ऐसी प्राथमिकता जो प्रतिरक्षा के माल के भुगतान के बाद हो) देनी होगी।

[पी आर-वी/5(170)/70]

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Iron & Steel Control)

ORDER

Calcutta, the 3rd March, 1973

S. O. 882 [NO.ESS-COMM/EPDE/80].—In exercise of the powers conferred on me by Notification No.S.O.1436 Dated 18-4-67 under the Essential Commodities (Regulation of Production & Distribution for purposes of export) Order, 1966, I hereby direct that the firm specified in Column 1 of the Table below shall sell the goods as specified in Column 2 there-against to the firm specified in the corsponding entry in Column 3 of the said table for purposes of manufacture of Engineering goods for export at the price indicated there-against in Column 4 subject to the conditions enumerated in Column 5 of the said table.

Name of the firm	Specification of goods	Name of the exporter	Price	Condition
1	2	3	4	5
M/s. Indian Steel & Wire Products Ltd., Indranagar, Singhbhum.	H.B.Wire-205.737M/Tons (Two hundred and five point seven three seven)	M/s. Hero Cycles (P) Ltd., G.T. Road, Hero Nagar, Ludhiana-1.	At current market rate.	Supply should be made on export promotion basis (*i.e.* a priority next to defence)

[No. PR-V/5(170)/70]

आदेश

का० आ० 883 [सं० ई एस.एस-कौम/ईपीडीई/81].—आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनों के लिये उत्पादन और वितरण का विनियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत अधिसूचना सं० एस०ओ० 1436 दिनांक 18-4-1967 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद् द्वारा नीचे दिये गये तालिका के स्तम्भ 1 के फर्म को स्तम्भ 2 में उल्लेखित वस्तुओं को, स्तम्भ 3 में नमांकित फर्म को इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात हेतु स्तम्भ 4 में दिये गये मूल्य पर, स्तम्भ 5 में दिये हुए शर्त पर विक्रय करने का आदेश देता हूं।

फर्म का नाम	वस्तुओं का विस्तृत विवरण	निर्यातक का नाम	मूल्य	शर्त
1	2	3	4	5
मैसर्स इंडियन स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इन्द्रनगर, टाटानगर, सिंगभूम।	एच०बी० वायर—140.612 एम०टी० वायर—57.370,, मोट 197.982 (एक सौ सातानवे दशमलव नौ आठ दो एम. टन सिर्फ)	दि रोड मास्टर इन्डस्ट्रीज आफ इन्डिया प्रा० लि०, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राजपुरा (पंजाब)	सामान्य मूल्य जो माल के भुगतान के समय हो।	माल का भुगतान निर्यात प्राथमिकता के आधार पर (अर्थात् ऐसी प्राथमिकता जो प्रतिरक्षा के माल के भुगतान के बाद हो) देनी होगी।

[सं० पी आर-वी/5/112/68]

टी. घोष, निर्यात उत्पादन निदेशक और लोहा तथा इस्पात नियंत्रक

ORDER

S.O.883[NO.ESS-COMM/EPDE/81].—In exercise of the powers conferred on me by Notification No.S.O.1436 dated 18-4-67 under the Essential Commodities (Regulation of Production & Distribution for purposes of export) Order, 1966, I hereby direct that the firm specified in Column 1 of the Table below shall sell the goods as specified in Column 2 there-against to the firm specified in the corresponding entry in Column 3 of the said table for purposes of manufacture of Engineering Goods for export at the price indicated there-against in Column 4 subject to the conditions enumerated in Column 5 of the said table.

Name of the firm	Specification	Name of the exporter	Price	Condition
1	2	3	4	5
M/s. Indian Steel & Wire Products Ltd., Indranagar, Singhbhum.	H.B.Wire-140.612 m/t M.S.Wire 57.370 ,, Total 197.982,, (One hundred ninety-seven point nine eight two m/t)	The Roadmaster Industries of India (P) Ltd., Rajpura, Punjab.	At current market rate.	Supply should be made on export priority basis (*i.e.* a priority next only to Defence).

[No. PR-V/5/112/68]

T. GHOSH, Director of Export Production and Iron & Steel Controller

औद्योगिक विकास मंत्रालय
(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 12 मार्च 1973

का० आ० 884.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम 1955 के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि मानक चिह्न जिनके डिजाइन और शाब्दिक विवरण तत्संबंधी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं :—

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने निमित ये मानक चिह्न 16 जनवरी, 1973 से लागू हो जायेंगे

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद और उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	भारतीय मानक चिह्न की डिजाइन का शीर्षक का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,	ISI IS:844	पेंचकस	IS : 844-1962 पेंचकस की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के बाहर दायीं ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी हुई है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	IS:3195	कुंडलीनुमा और चक्राकार कमानियां बनाने का इस्पात (मालगाड़ी के डिब्बों के लिए)	IS :3195-1965 कुंडलीनुमा और चक्राकार कमानियां बनाने के इस्पात की विशिष्टि (मालगाड़ी के डिब्बों के लिए)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें "ISI" शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी हुई है ।
3.	IS:3885	परतदार कमानियां बनाने का इस्पात (मालगाड़ी के डिब्बों के लिए) भाग 1 चपटे भाग 2 पत्ती और नाका सेक्शन	IS : 3885 (भाग 1)-1966 परतदार कमानियां बनाने के लिए इस्पात की विशिष्टि (मालगाड़ी के डिब्बों के लिए) भाग 1 चपटे सेक्शन IS: 3885 (भाग 2)-1966 परतदार कमानियां बनाने के इस्पात की विशिष्टि (मालगाड़ी के डिब्बों के लिए) भाग 2 पत्ती और नाका सेक्शन	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी हुई है ।
4.	IS:3930	सौ तथा प्रेरण द्वारा कठोरकारी इस्पात	IS : 3930-1966 सौ तथा प्रेरण द्वारा कठोरकारी इस्पात की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी हुई है ।
5.	IS:5517	कठोरीकरण तथा टेम्पर देने का इस्पात	IS : 5517-1969 कठोरीकरण तथा टेम्पर देने के इस्पात की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक पद संख्या दी हुई है ।

[सं० सी एम डी/13:9]

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 12th March, 1973

S.O. 884 .—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design (s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 16th January 1973 :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS:844	Screw drivers	IS:844-1962 Specification for screw drivers	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the outer righthand side of monogram as indicated in the design.
2.	IS:3195	Steel for the manufacture of volute and helical springs (for railway rolling stock.)	IS:3195-1965 Specification for steel for the manufacture of volute and helical spring (for railway rolling stock)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col.(2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.
3.	IS:3885	Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part I Flat sections Part II Rib and groove sections	(*i*) IS:3885 (Part I)-1966 Specification for steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part I Flat section (*ii*) IS:3885 (Part II)-1969 Specification for steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part II Rib and groove sections.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col.(2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	IS:3930	Flame and induction hardening steels	IS:3930—1966 Specification for flame and induction hardening steels.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.
5.	IS:5517	Steels for hardening and tempering	IS:5517-1969 Specification for steels for hardening and tempering	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9]

का० आ० 885 .—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के उपविनियम 7 के उपनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहरांकन फीस जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए जा रहे हैं, निर्धारित की गई है और ये फीसें 16 जनवरी 1973 से लागू हो जाएंगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद का नाम	सम्बद्ध भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पेचकस	आई एस :844-1962 पेचकस की विशिष्टि	100 पेचकस	50 पैसे
2.	कुंडलीनुमा और चक्राकार कमानियां बनाने का इस्पात (माल गाड़ी के डिब्बों के लिए)	आई एस: 3195-1965 कुंडलीनुमा और चक्राकार कमानियां बनाने के इस्पात की विशिष्टि (माल गाड़ी के डिब्बों के लिए)	एक मीटरी टन	50 पैसे
3.	(1) परतदार कमानियां बनाने का इस्पात (मालगाड़ी के डिब्बों के लिए) भाग 1—चपटे सेक्शन भाग 2—पत्ती और नाका सेक्शन	आई एस:3885(भाग 1)-1966 परतदार कमानियां बनाने के इस्पात की विशिष्टि (मालगाड़ी के डिब्बों के लिए) भाग 1 चपटे सेक्शन आई एस :3885(भाग 2)—1966 परतदार कमानियां बनाने के इस्पात की विशिष्टि (मालगाड़ी के डिब्बों के लिए) भाग 2 पत्ती और नाका सेक्शन	एक मीटरी टन	50 पैसे
4.	लौ तथा प्रेरण द्वारा कठोरीकारी इस्पात	आई एस :3930-1966 लौ तथा प्रेरण द्वारा कठोरकारी इस्पात की विशिष्टि	एक मीटरी टन	50 पैसे
5.	सुकट्य और कार्बन मैगनीज इस्पात	आई एस : 4431-1967 सुकट्य और कार्बन मैगनीज इस्पात की विशिष्टि	एक मीटरी टन	50 पैसे
6.	सतह कठोरकारी इस्पात	आई एस :4432-1967 सतह कठोरकारी इस्पात की विशिष्टि	एक मीटरी टन	50 पैसे
7.	कठोरीकरण और टेम्पर देने के लिए इस्पात	आई एस :5517-1969 कठोरीकरण और टेम्पर देने के लिए इस्पात की विशिष्टि	एक मीटरी टन	50 पैसे

[सं० सी एम डी/13 :10]

S.O. 885.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee(s) per unit for various products, details of which are given in the Schedule hereto annexed have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from 16 January, 1973 :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Screw drivers . .	IS:844-1962 Specification for screw drivers	100 pieces	50 Paise
2.	Steel for the manufacture of volute and helical springs (for railway rolling stock)	IS:3195-1965 Specification for steel for the manufacture of volute and helical springs (for railway rolling stock)	One Tonne	50 Paise
3.	Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock)	(*i*) IS:3885 (Part I) 1966 Specification for steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock)	One Tonne	50 Paise
	Part I Flat sections	Part I Flat section and		
	Part II Rib and groove sections	(*ii*) IS:3885 (Part II)-1969 Specification for steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock)		
		Part II Rib and groove sections		
4.	Flame and induction hardening steels	IS:3930-1966 Specification for flame and induction hardening steels	One Tonne	50 Paise
5.	Carbon and carbon-manganese free-cutting steel	IS:4431-1967 Specification for carbon and carbon-manganese free-cutting steels	One Tonne	50 Paise
6.	Case hardening steels	IS:4432-1967 Specification for case hardening steels	One Tonne	50 Paise
7.	Steels for hardening and tempering	IS:5517-1969 Specification for steels for hardening and tempering	One Tonne	50 Paise

[No. CMD/13:10]

का०आ० 886.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे दिए गए हैं वे 1 से 31 दिसम्बर 1971 तक की अवधि में निर्धारित किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं	निर्धारित भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा रद्द हुए भारतीय मानक यदि हों, की पदसंख्या और शीर्षक	संक्षिप्त विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
	आई एस:245-1970 ट्राइक्लोरोइथाइलीन तकनीकी की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस:245-1962 ट्राइक्लोरोइथाइलीन तकनीकी की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	इस मानक में ट्राइक्लोरोइथाइलीन तकनीकी के विषय में अपेक्षाएं और नमूने लेने तथा परीक्षण की पद्धतियां निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 5.50)
2.	आई एस : 708-1970 पोटैशियम क्लोरेट तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस:708-1956 पोटैशियम क्लोरेट तकनीकी की विशिष्टि	इस मानक में पोटेशियम क्लोरेट तकनीकी के विषय में अपेक्षाएं और नमूने लेने तथा परीक्षण की पद्धतियां निर्धारित की गई हैं (मूल्य रु० 6.00)
3.	आई एस:1448 (भाग 21)-1970 पेंस्की मार्टिन्स उपकरण द्वारा दीप्ति अंक (बंद) (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 1448 (भाग 21)-1960 पेंस्की मार्टिन्स उपकरण द्वारा दीप्ति अंक (बंद)	इस मानक पद्धति में ईंधन के तेलों, स्नेहक तेलों, चिरकोसी सामग्री और ठोस पदार्थों के मिलम्बन का दीप्ति-अंक पेंस्की मार्टिन्स उपकरण द्वारा निकालने की पद्धतियां दी गई हैं । (मूल्य रु० 2.50)

(1)	(2)	(3)	(4)
4.*	आई एस : 1475-1971 पीने के पानी के स्वतः पूर्ण जल कूलर (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 1475-1959 स्वतः पूर्ण जल-कूलर की विशिष्टि	इस मानक में स्वतः पूर्ण पीने के पानी के भंडारण तथा कूलरों के निर्माण संबंधी सामान्य अपेक्षाएं, मानक साइज, परीक्षण तथा रेट निर्धारण पद्धतियां दी गई हैं। जल कूलर बिजली के भाप संपीड़ण प्रकार की प्रशीतक मशीन द्वारा चलते हैं, जिनमें वायु शीतलित संघनक लगे होते हैं। (मूल्य रु० 5.50)
5.	आई एस: 1477 (भाग 2)-1971 इमारतों में लौह धातुओं पर रंगरोगन करने की रीति संहिता भाग 2 रंग रोगन करना।	आई एस: 1477 (भाग 2)-1963 इमारतों में लोहे और इस्पात/लौह धातुओं पर फिनिश देने की रीति संहिता: रंगरोगन और संबद्ध फिनिश, भाग 2 अनुसूची और साज सामान	इस मानक में इमारतों में लोहे की वस्तुओं पर रंग रोगन करने तथा रंग रोगन अनुसूची के ब्यौरे निर्धारित किए गए हैं। इसमें इस कार्य में प्रयुक्त औजारों और साज सामान को भी लिया गया है। इस मानक में दिए प्रावधान इमारतों के अतिरिक्त अन्य स्थानों जैसे टंकियों और चिमनियों में भी लागू हो सकते हैं। (मूल्य रु० 6.50)
6.	आई एस: 1878 (भाग 2)-1971 सामान्य कार्यों वाली समांतर खरादों के परीक्षण चार्ट भाग 2 800 मिमी से ऊपर से 1600 मिमी तक के स्विंग ओवर बेड वाली खराद (पहला पुनरीक्षण)	आई एस: 1878-1961 खरादों के परीक्षण चार्ट (800 मिमी तक के स्विंग बोर्ड वाली)	इस मानक में 800 मिमि से 1600 मिमि तक स्विंग बोर्ड वाली सामान्य कार्यों वाली समांतर खरादों के बारे में ज्यामितीय तथा व्यावहारिक परीक्षण निर्धारित किए गए हैं। इसमें आई एस: 2063-1962 मशीनी औजारों की परीक्षण संहिता के अनुरूप अनुमत घट बढ़ भी दी गई है। (मूल्य रु० 6.50)
7.	आई एस: 1893-1970 आगारों की भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन संबंधी कसौटियां (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस: 1893-1966 आगारों की भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन संबंधी कसौटियां (पहला पुनरीक्षण)	इस मानक में आगारों की भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन को लिया गया है और इमारतों के ऊंचे आगारों, पुलों, कंक्रीट चिनाई और मिट्टी के बांधों, पुश्तों और धारण दीवारों पर लागू होता है। (मूल्य रु० 13.50)
8.	आई एस: 2571-1970 मौके पर कंक्रीट का फर्श देने की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	आई एस: 2571-1963 मौके पर कंक्रीट का फर्श देने की रीति संहिता।	इस संहिता में अनौद्योगिक तथा हलकी औद्योगिक इमारतों के लिए मौके पर कंक्रीट का फर्श देने तथा उसकी फिनिश संबंधी रीति दी गई है। (मूल्य रु० 8.00)
9.	आई एस: 2983-1971 पीतल की वस्तुओं पर गर्म कलई करने की सिफारिशी रीति (पहला पुनरीक्षण)	आई एस: 2983-1964 पीतल की वस्तुओं पर गर्म कलई करने की रीति संहिता	इस मानक में पीतल की वस्तुओं पर कलई करने संबंधी आवश्यक मार्गदर्शक बातें निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 2.50)
10.	आई एस: 3625-1971 एल्युमिनियम के प्लगनुमा तकुओं पर उपयोग के लिये ताने की नलियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस: 3625-1966 एल्युमिनियम के प्लगनुमा तकुओं पर उपयोग के लिए ताने की नलियों की विशिष्टि	इस मानक में कताई और मरोड़ देने के फ्रेमों में काम आने वाले खुले मुंह (कटे) और वेल्लित सिरे (गुम्बदनुमा) वाली ताने की नलियों के बारे में अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। ये नलियां स्प्रिंगदार ग्रिपों वाले प्लगनुमा तकुओं में काम आने के योग्य होती हैं (मूल्य रु० 2.50)
11.	आई एस: 3949-1971 कंठदर्शी में प्रयुक्त बल्बों के माप और चूड़ियां	—	इस मानक में कंठदर्शी में काम आने वाले बल्बों के अनिवार्य बाहरी माप और चूड़ियों के रूप तथा साइज निर्धारित किए गए हैं। (मूल्य रु० 3.00)
12.	आई एस: 4049-1971 टंकियों और दाब पात्रों के बने ढक्कनों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस: 4049-1968 टंकियों और दाब पात्रों के बने ढक्कनों की विशिष्ट	इस मानक में दाब पात्रों, ग्राही पात्रों टंकियों और ऐसे ही अन्य साज सामान के लिए ढक्कनों के रूप में आम तौर से प्रयुक्त रकाबीनुमा और गोटदार, दबा कर और काट कर बने किनारों (ढक्कनों) के सीमांत माप और पूर्ति की तकनीकी शर्तें निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 5.00)
13.	आई एस : 4816-1971 स्थायी चुम्बकीय चकों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 4816-1968 स्थायी चुम्बकीय चकों की विशिष्टि।	इस मानक में स्थायी चुम्बकीय चकों के विषय में अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 3.00)
14.	आई एस : 4880 (भाग 4)-1971 जलवाही सुरंगों की डिजाइन की रीति संहिता, भाग 4 चट्टान में कंक्रीट का अस्तर देने की संरचना डिजाइन।	—	इस मानक में मुख्य रूप से नयी घाटी योजनाओं के लिए चट्टान में सुरंगों और शाफटों में सादी और प्रबलित कंक्रीट का अस्तर देने की संरचना डिजाइन की कसौटियां दी गई हैं। (मूल्य रु० 8.00)

*भा मा संस्था प्रमाणन योजना के लिए आई एस : 1475-1970 1 जनवरी 1972 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	आई एस : 5477 (भाग 4)–1971 जलाशयों की समाई नियत करने की पद्धतियां: भाग 4 वाढ़ के पानी का भंडारण।	—	इस मानक में जलाशयों में बाढ़ के पानी के भंडारण की समाई नियत करने की पद्धतियां निर्धारित की गई हैं। ये पद्धतियां आगार का बचाव और उसकी जिन्दगी और गुणधर्मों के अनुरूप हैं। (मूल्य रु० 7.50)
16.	आई एस : 5785 (भाग 1)–1970 सतह सक्रियकारी पदार्थों की कार्यप्रवता परीक्षण पद्धति भाग 1 सापेक्षिक विसरण शक्ति।	—	इस मानक में वस्त्रादि उद्योग में प्रयुक्त सतह सक्रियकारी पदार्थों की सापेक्षिक विसरण शक्ति की परख के लिए परीक्षण पद्धतियां निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 2.00)
17.	आई एस : 5878 (भाग 2/अनुभाग 2)–1971 सुरंगों की निर्माण संहिता भाग 2 चट्टान में भूमिगत खुदाई अनुभाग 2 संवातन, प्रकाश, शिलाखंड हटाना और पानी निकालना।	—	इस मानक में सुरंगों की खुदाई के लिए संवातन, प्रकाशन व्यवस्था, टूटे शिलाखंड हटाना और पानी निकालने के विषय को लिया गया है। (मूल्य रु० 3.50)
18.	आई एस : 5887-1970 खाद्य पदार्थ विषाक्त करने तथा खाद्य वाहित रोगों के बैक्टीरिया पता करने की पद्धति।	—	इस मानक में खाद्य पदार्थ विषाक्त करने तथा खाद्य द्वारा रोग पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का पता करने की पद्धतियों की सिफारिश की गई हैं। (मूल्य रु० 7.00)
19.	आई एस : 5889-1970 कम्पनशील पट्टी संघनक (कम्पैक्टर) की विशिष्टि।	—	इस मानक में स्वतः नोदित कम्पनशील पट्टी संघनक की सामग्री, साइज, पदनाम, निर्माण और कार्यप्रवता के बारे में अपेक्षाएं दी गई हैं। (मूल्य रु० 4.00)
20.	आई एस : 5892-1970 कंक्रीट के पारेषण मिश्रकों और विलोड़क यंत्रों की विशिष्टि।	—	इस मानक में झुकी धुरी वाले, घूमने वाले ड्रमनुमा मिश्रक तथा विलोड़क यंत्रों को लिया गया है। ये यंत्र किसी चल वाहन इंजिन या पारेषण के समय कंक्रीट मिश्रण और विलोड़न के लिए प्रयुक्त इंजिन से चलते हैं। (मूल्य रु० 4.00)
21.	आई एस : 5979-1970 साइन केन्द्रों की विशिष्टि	—	इस मानक में 200 से 300 मिमी की केन्द्र दूरी के रोलरों वाले साइन केन्द्रों के विषय में अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। ये साइन केन्द्र 60° की नीति पर काम आते हैं (मूल्य रु० 3.00)
22.	आई एस : 5989-1971 छिद्र मिलों की विशिष्टि	—	इस मानक में अनियंत्रित छिद्र मिल टाइप-ए और नियंत्रित छिद्र मिल टाइप-बी के माप और अन्य अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 5.00)
23.	आई एस : 6042-1969 हल्के वजन वाली कंक्रीट ब्लाकों की चिनाई कार्य के निर्माण की रीति संहिता।	—	इस मानक में आई एस : 3590-1966 के अनुरूप पूर्व ढले वजन वाले कंक्रीट के टोस ब्लाकों और आई एस: 3115-1965 के अनुरूप चूना सीमेन्ट राखी के ब्लाकों से बनी दीवारों और विभाजन दीवारों के निर्माण को लिया गया है। (मूल्य रु० 7.00)
24.	आई एस : 6046-1971 कृषि उपयोग के लिए जिप्सम की विशिष्टि	—	इस मानक में खेती में उपयोग के लिए जिप्सम संबंधी अपेक्षाएं, जानगी लेने तथा परीक्षण की पद्धतियां निर्धारित की गई हैं। इसमें खनिज जिप्सम, नमक के कारखानों से प्राप्त कैल्शियम सल्फेट तथा फास्फोरिक अम्ल निर्माण की गीली पद्धति में उप-उत्पादन के के रूप में प्राप्त कैल्शियम सल्फेट को भी लिया गया है। (मूल्य रु० 4.00)
25.	आई एस : 6049-1971 अस्थायी संक्षारण संरोधों के उपयोग की रीति संहिता।	—	इस मानक में परिवहन और भंडारण की अवधि में धातु की वस्तुओं पर संक्षारण से बचाने के लिए अस्थायी संक्षारण संरोध लगाने के बारे में रीति संहिता निर्धारित की गई है। (मूल्य रु० 7.00)
26.	आई एस : 6052-1970 काँच के संघनकों की विशिष्ट	—	इस मानक में प्रयोगशालाओं में सामान्य कार्यों के लिए प्रयुक्त हवा से अथवा जल द्वारा ठंडे होने वाले संघनकों के बारे में अपेक्षाएं दी गई हैं। (मूल्य रु० 8.00)
27.	आई एस: 6080-1971 दोहरे सिरे वाले क्लैम्पों की विशिष्टि	—	इस मानक में मशीन करते समय कार्यखण्ड को यथास्थान पकड़े रखने के लिए प्रयुक्त दोहरे सिरे वाले क्लैम्पों के माप और अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 3.00)

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	आई एस : 6081-1971 सादे क्लैम्पों की विशिष्टि	—	इस मानक में मशीन करते समय कार्यखण्ड को यथास्थान पकड़े रखने के लिए प्रयुक्त सादे क्लैम्पों के माप और अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 3.00)
29.	आई एस : 6082-1971 खांचेदार क्लैम्पों की विशिष्टि	—	इस मानक में मशीन करते समय कार्यखण्ड को यथास्थान पकड़े रखने के लिए प्रयुक्त खांचेदार क्लैम्पों के माप और अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 3.00)
30.	आई एस:6086-1971 समांतर क्रिया वाले चपटे नोकदार प्लास	—	इस मानक में समांतर क्रिया वाले चपटे नोकदार प्लास के विषय में माप और अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 3.00)
31.	आई एस : 6098-1971 घूमने वाली बिजली की मशीनादि से निकला वायुवाहित शोर मापने की पद्धति।	—	शोर नापने संबंधी यह मानक घूमने वाली बिजली की मशीनों जैसे सभी प्रकार के मोटर और जनित्रों पर लागू होता है। उनके सामान्य सहायक अंग लगे होने पर विद्युत उत्पादन या वोल्टता की कोई सीमा नहीं होती। (मूल्य रु० 7.00)
32.	आई एस : 6100-1971 अजल तकनीकी सोडियम ट्राइ पॉलीफास्फेट की विशिष्टि	—	इस मानक में अपमार्जक निर्यात और अनुर्णक के रूप में उपयोग के लिए सोडियम अजल तकनीकी ट्राइ पालीफास्फेट के विषय में अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा परीक्षण की पद्धतियाँ दी गई हैं। (मूल्य रु० 8.00)
33.	आई एस : 6102(भाग 1)-1971 इलेक्ट्रानिक और दूर संचार साज सामान में प्रयुक्त अंगुलि घुंडी की विशिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं और परिक्षण	—	इस मानक में इलेक्ट्रानिक और दूर संचार साज-सामान में प्रयुक्त घुंडियों की मशीनी और परिवातीय गुणधर्मों की जांच के लिए सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियां दी गई हैं और अंतर्विनिमेयता तथा अनुरूपता के लिए माप भी दिए गए हैं। (मूल्य रु० 1.00)
34.	आई एस : 6115-1971 गर्भाशय टिनाक्यूलम फोर्सेप्स की विशिष्टि	—	इस मानक में गर्भाशय टिनाक्यूलम फोर्सेप्स के विषय में माप संबंधी तथा अन्य अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 5.00)
35.	आई एस : 6118-1971 सरक–जोड़ वाले प्लास की विशिष्टि	—	इस मानक में सरक जोड़ प्लास के विषय में माप और अन्य अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं (मूल्य रु० 3.00)
36.	आई एस : 6134(भाग 1/अनुभाग 1)-1971 सूक्ष्मतरंग ट्यूबों पर मापन पद्धति भाग 1 सामान्य मापन अनुभाग 1 मापन की सामान्य शर्तें और पूर्वोपाय	—	इस मानक में सूक्ष्मतरंग ट्यूबों पर मापन के लिए आवश्यक सामान्य शर्तें तथा पूर्वोपायों को लिया गया है। (मूल्य रु० 2.00)
37.	आई एस : 6146-1971 जलयान के ब्लाकों के साथ प्रयुक्त बेकेट।	—	इस मानक में सांकेतिक साइज 1 से 12 तक के जलयान के ब्लाकों के साथ प्रयुक्त बेकेट के माप तथा लगने वाली सामग्री निर्धारित की गई है। (मूल्य रु० 2 00)
38.	आई एस : 6151 (भाग 1)–1970 भंडारण व्यवस्था संहिता भाग 1 शब्दावली।	—	इस मानक में भंडारण व्यवस्था से संबंधित तकनीकी शब्द और परिभाषाएं दी गई हैं। (मूल्य रु० 3.50)
39.	आई एस : 6159-1971 जस्त लेपन के पहले सामग्री की डिजाइन तथा तैयारी की सिफारिश पद्धति	—	इस मानक में इस्पात की जड़ी वस्तुओं पर गर्म डुबाऊ रीति से अच्छे किस्म के जस्त लेपन विषयक पूर्वोपाय दिए गए गए हैं। (मूल्य रु० 2.00)
40.	आई एस : 6162 (भाग 2)- 1971 कागज चढ़े एल्यूमिनियम चालकों की विशिष्टि भाग 2 आयताकार चालक।	—	इस मानक में दो या तीन परत कागज चढ़े मुख्य रूप से ट्रांसफर्मरों की वाइण्डिंग के लिए प्रयुक्त आयताकार सेक्शन वाले चालकों के बारे में अपेक्षाएं और परीक्षण दिए गए हैं। (मूल्य रु० 6.00)
41.	आई एस : 6166-1971 पतली गावदुम की और की-मार्ग।	—	इस मानक में पतली गावदुम की और की-मार्ग के माप और छूटें दी गई हैं। (मूल्य रु० 5.00)
42.	आई एस:6180-1971 जलयानों के पार्श्व झरोखों के लिए दृढ़ीकृत बचाव कांचों की विशिष्टि	—	इस मानक में जलयानों के पार्श्व झरोखों तथा जड़ी रोशनियों के लिए दृढ़ीकृत बचाव कांच (कांच की पट्टी और चद्दर के रूप में) के माप तथा परीक्षण विधियां दी गई हैं। (मूल्य रु० 4.00)

(1) (2)	(3)	(4)
43. आई एस : 6194-1971 हस्तचालित थैलेनुमा आंतरालिक घनात्मक श्वसन यंत्र की विशिष्टि।	--	इस मानक में बनावटी सांस देने के लिए प्रयुक्त हस्तचालित थैलेनुमा आंतरालिक घनात्मक श्वसन यंत्र के विषय में अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। (मूल्य रु० 1.50)
44. आई एस : 6213(भाग 5)- 1971 गूदे की परीक्षण पद्धति भाग 5 एक प्रतिशत कास्टिक सोडा के घोल में गूदे की घुलनशीलता।	--	इस मानक में एक प्रतिशत कास्टिक सोडा के घोल में गूदे की घुलनशीलता निकालने की विधि निर्धारित की गई है। (मूल्य रु० 1.50)

इन भारतीय मानकों की प्रतियां, भारतीय मानक संस्था, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-1, और उसके शाखा कार्यालयों (1) साधना नूरमुहमद शेख मार्ग, खानपुर अहमदाबाद-1 (2) सिंडीकेट बैंक बिल्डिंग, गांधीनगर, बंगलौर-9(3), 535, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड, बम्बई-7 (4) चौरंगी एप्रोच रोड, कलकत्ता-13 (5) 5-201/21 चिरागअली लेन, हैदराबाद-1 (6) 1171/418-बी, सर्वोदयनगर, कानपुर-5 और (7) 54, जनरल पैटर्स रोड, मद्रास-2 से प्राप्त की जा सकती हैं।

[सं सी एम डी/13:2]

S. O. 886.—In pursuance of sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard (s), particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been established during the period 1 December to 31 December, 1971 :

THE SCHEDULE

S. No. No. and Title of the Indian Standard Established	No. and Title of the Indian Standard if any, superseded by the new Indian Standard.	Brief Particular
(1) (2)	(3)	(4)
1. IS.245-1970 Specification for trichloroethylene, technical **(second revision)**	IS : 245-1962 Specification for trichloroethylene, technical (revised)	This standard prescribes the requirements and the methods of sampling and test for trichlorethylene, technical. (Price Rs. 5.50)
2. IS:708-1970 Specification for potassium chlorate, technical (first revision)	IS:708-1956 Specification for potassium chlorate, technical	This standard prescribes the requirements and the methods of sampling and test for potassium chlorate, technical (Price Rs. 6.00)
3. IS:1448 (P:21)-1970 Flash point (closed) by Pensky-Martens apparatus (P:21) (first revision)	IS:1448 (P:21)-1960 Flash point (closed) by Pensky-Martens apparatus	This method covers the determination of the flash point by Pensky-Martens closed tester of fuel oils, lubricating oils, viscous materials, and suspension of solids. (Price Rs. 2.50)
4. *IS:1475-1971 Specification for self-contained drinking water coolers (first revision)	IS:1475-1959 Specification for self-contained water coolers.	This standard prescribes the general constructional requirements, standard sizes, methods of testing and rating, and installation of self-contained drinking water coolers of storage and instantaneous types operated by electrically driven vapour compressior type refrigerating machine with air cooler condenser. (Price 5.50)
5. IS:1477 (Part II)-1971 Code of practice for paintings of ferrous metals in buildings (first revision) Part II Painting.	IS:1477(Part II)-1963 Code of practice for finishing of iron and steel/ferrous metal in buildings : painting and allied finishes Part II Schedules and equipment.	This standard lays down the details of painting operations and paint schedules applicable to ferrous metals in buildings. It also covers the use of tools and equipment in the work. The provsions of the standard may also generally be applied to painting work in situations other than buildings, such as tanks and chimneys. (Price 8.50)
6. IS:1878 (Part II)-1971 Test chart for general purpose parallel lathes Part II lathes with swing over bed over 800 mm and up to 1600 mm(first revision)	IS:1878-1961 Test charts for lathes) Upto 800 mm swing overbed)	This standard describes both geometrical and practical tests on general purpose parallel lathes with swing over bed over 800 mm and up to 1600 mm and the corresponding permiscible deviations, with reference to IS:2063-1962 'Code for testing machine tools' (price 6.50)
7. IS:1893-1970 Criteria for earthquake resistant design of structures (second revision)	IS:1893-1966 Criteria for earthquake resistant design of structures (first revision)	This standard deals with earthquake resistant design of structures and is applicable to buildings : elevated structures ; bridges ; concrete, masonry and earth dams ; embankments and retainoing walls (Price 13.50)

*For purposes of ISI Certification marks Scheme, IS:1475-1971 shall come into force with effect from 1 January 1972.

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	IS:2571-1970 Code of practice for laying *in-situ* cement concrete flooring (first revision)	IS:2571-1963 Code of practice for laying *in-situ* cement concrete flooring.	This standard covers laying and finishing of *in-situ* cement concrete flooring for non-industiral and light industriel buildings (Price Rs. 8.00)
9.	IS:2983-1971 Recommended practice for hot tinning of brassware (first revision)	IS:2983-1964 Code of practice for hot tinning of brassware.	This standard recommends importent guidelines for hot tinning of brassware. (Price Rs. 2.50)
10.	IS:3625-1971 Specification for warp tubes for use on aluminium plug type spindles (first revision)	IS:3625-1966 Specification for warp tubes for use on aluminium plug type spindles.	This standard prescribes the requirements of warp tubes of open-top (cut type) and rolled-in-top (dome type) types used in spinning and doubling frames. These tubes are suitable for use on aluminium plug type spindles with spring grips. (Price Rs. 2.50)
11.	IS:3949-1971 Dimensions and screw thread for lamp used in laryngoscopes	—	This standard specifies the essential external dimensions, and form and size of screw thread for lamp used in laryngoscopes. (Price Rs. 3.00)
12.	IS:4049-1971 Specification for formed ends for tanks and pressure vessels (first revision)	IS:4049-1968 Specification for formed ends for tanks and pressure vessels.	This standard specifies the boundary dimensions and technical delivery conditions of dished and flanged, pressed or spun ends commonly used as end closures of pressure vessels, receivers, tanks and similar equipment (Price Rs. 5.00)
13.	IS:4816-1971 Specification for permanent magnetic chucks (first revision)	IS:4816-1968 Specification for permanent magnetic chucks.	This standard specifies the requirements for permanent magnetic chucks. (Price Rs. 3.00)
14.	IS:4880 (Part IV)-1971 Code of practice for design of tunnels conveying water Part IV structural design of concrete lining in rock.	—	This standard covers criteria for structural design of plain and reinforced concrete lining for tunnels and circular shafts in rock mainly for river valley projects. (Price Rs. 8.00)
15.	IS:5477 (Part IV)-1971 Methods for fixing the capacities or reservoirs Part IV flood storage	—	This standard covers the criteria and procedure to be followed in fixing the flood storage capacity of a reservior consistent with the safety of the structure itself and the life and properties downstream of the reservior (Price Rs. 7.50)
16.	IS:5785 (Part I)-1970 Methods for performance tests for surface active agents Part I relative dispersing power	—	This Standard prescribes the method of test for evaluating the reletive dispersing power of surface active agents used in the textile industry. (Price Rs. 2.00)
17.	IS:5878 (Part II/Sec 2)-1971 Code of practice for construction of tunnels Part II uderground excavation in rock Section 2 ventilation, lighting, mucking and dewatering.	—	This standard deals with ventilation, lighting, mucking and dewatering for excavation of tunnels. (Price Rs. 3.50)
18.	IS:5887-1970 Methods for detection of bacteria responsible for food poisoning and food-borne diseases.	—	This standard recommends the methods for detection of bacteria responsible for food poisoning and foodbrone diseases. (Rs. 7.00)
19.	IS:5889-1970 Specification for vibratory plate compactor	—	This standard lays down the requirements for materials, size, designation, construction and performance of self-propelled vibratory plate compactors. (Price Rs. 4.00)
20.	IS:5892-1970 Specification for concrete transit mixers and agitators.	—	This standard covers concrete transit mixers and agitators of the inclined axis rotary drum type, driven by power take off from the mobile vehicles, engine itself or through a separate engine for mixing and agitating concrete during transit. (Price Rs. (4.00)
21.	IS:5979-1970 Specification for sine centres	—	This standard covers the requirements of sine centres with centre distances of rollers 200 and 300 mm and for use up to an inclination of 60° (Price Rs. 3.00)
22.	IS:5989-1971 Specification for hole mills	—	This standard specifies the dimensions and requirements for unguided hole mills. Type A ; and guided hole mills, Type B, (Price Rs. 5.00)
23.	IS:6042-1969 Code of practice for construction of light-weight concrete block masonry	—	This standard covers the construction of walls and partitions with precast light-weight concrete solid blocks conforming to IS:3590-1966 and lime cement cinder blocks conforming to IS:3115-1965. (Price Rs. 7.00)

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	IS:6046-1971 Specification for gypsum for agricultural use.	—	This standard prescribes the requirements and methods of sampling and test for gypsum for agricultural use. It covers mineral gypsum, calcium sulphate obtained in salt works and by-product calcium sulphate obtained in the wet-process manufacture of phosphoric acid. (Price Rs. 4.00)
25.	IS:6049-1971 Code of practice for application of temporary corrosion preventives.	—	This standard lays down a code of practice for application of temporary corrosion preventives to metal articles for prevention of corrosion during transport and storage. (Price Rs. 7.00)
26.	IS:6052-1970 Specification for glass condensers	—	This standard specifies air and water-cooled glass condensers commonly used for general laboratory purposes (Price Rs. 8.00)
27.	IS:6080-1971 Specification for double ended clamps	—	This standard specifies the dimensions and requirements for double ended clamps used in holding work pieces in place when they are being machined. (Price Rs. 3.00)
28.	IS:6081-1971 Specification for plain clamps	—	This standard specifies the dimensions and requirements for plain clamps used in holding work pieces in place when they are being machined. (Price Rs. 3.00)
29.	IS:6082-1971 Specification for slotted clamps	—	This standard specifies the dimensions and requirements for slotted clamps used in holding work piece in places when they are being machined. (Price Rs. 3.00)
30.	IS:6086-1971 Specification for parallel action flat nose pliers	—	This standard specifies the dimensions and requirements for parallel action flat nose pliers. (Price Rs. 3.00)
31.	IS:6098-1971 Method of measurement of the airborne noise emitted by rotating electrical machinery.	—	This standard for the measurement of noise applies to rotating electrical machines, such as motors and generators of all sizes without limitation of output or voltage when fitted with their normal auxiliaries. (Price Rs. 7.00)
32.	IS:6100-1971 Specification for sodium tripolyphosphate, anhydrous, technical	—	This standard prescribes the requirements and the methods of sampling and test for sodium tripolyphospate, anhydrous, technical for use as a detergent builder, and as a deflocculant. (Price Rs. 8.00)
33.	IS:6102 (Part I)-1971 Specification for finger knobs used in electronic and telecommunication equipment Part I general requirements and tests	—	This standard describes the general requirements and methods of tests for judging the mechanical and climatic properties of knobs intended for use in electronic and telecommunication equipments, and specifies dimension for the purpose of interchangeability and compatibility. (Price Rs. 4.00)
34.	IS:6115-1971 Specification for forceps, uterine tenaculum	—	This standard covers dinensional and other requirements of uterine forceps tenaculum (Price Rs. 5.00)
35.	IS:6118-1971 Specification for slip-joint pliers	—	This standard prescribes the dimensions and other requirements for slip-joint pliers. (Price Rs. 3.00)
36.	IS:6134-(Part I/Sec I)-1971 Methods of measurement on microwave tubes Part I general measurements Section I general conditions and precautions for measurements.	—	This standard lays down the general conditions, precautions to be taken, etc. for making measurements on microwave tubes. (Price Rs. 2.00)
37.	IS:6146-1971 Specification for beckets used with ship's blocks	—	This standard specifies the material and dimensions for beckets used with ship's blocks of nominal size 1 to 12. (Price Rs. 2.00)
38.	IS:6151 (Part I)-1971 Storage management code Part 1 terminology.	—	This code prescribes the definitions for various terms most frequently used in storage management. (Price Rs. 3.50)
39.	IS:6159-1971 Recommended practice for design and preparation of material prior to galvanizing.	—	This standard describes the precautions that should be taken to obtain good quality of hot-dip galvanized coatings on assembled steel products. (Price Rs. 2.00)
40.	IS:6162 (Part II)-1971 Specification for paper covered aluminium conductors Part II rectangular conductors.	—	This standard gives requirments and tests for solid aluminium condcutors of rectangular section, covered with two or more layers of paper, primarily intended for transformer windings. (Price Rs. 6.00)

(1)	(2)	(3)	(4)
41.	IS:6166-1971 Specification for thin taper keys and keyways.	—	This standard gives dimensions and tolerances for think taper keys and keyways. (Price Rs. 5.00)
42.	IS:6180-1971 Specification for toughened safety glasses for Ships' side scuttles	—	This standard specifies the dimensions and testing of toughened safety glasses (plate glass ands heet glass) for ships' side scuttles and fixed lights. (Price Rs. 4.00)
43.	IS:6194-1971 Specification for intermittent positive pressure respirator bag type, manually operated.	—	This standard prescribes the requirements for manually operated bag type intermittent positive respirator used for artificial respiration and resuscitation (Price Rs. 1.50)
44.	IS:6213 (Part V)-1971 Methods of test for pulp Part V solubility of pulp in one per cent caustic soda solution.	—	This standard describes the procedure for determination of solubility of pulp in one per cent caustic soda solution. (Price Rs. 1.50)

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1 and also its branch offices at (i) 534 Sardar Vallabhbhai Patel Road, Bombay-7 (ii) 5 Chowringhee Approach Road, Calcutta-13; (iii) 54 General Patters Road; Madras-2; (iv) 117/418 B, Sarvodaya Nagar, Kanpur-5; (v) 5-9-201/2A Chirag Ali Lane, Hyderabad-1; (vi) 'Sadhna', Nurmohamed Shaikh Marg. Khanpur, Ahmedabad-1; and (vii) F Block, Unity Bldg. Narasimharaja Square, Bangalore-2.

[No. CMD/13:3]

नई दिल्ली, 13 मार्च 1973

का० आ० 887.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन 87 लाइसेंसों के ब्यौरे दिए गए हैं, लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी मुहर लगाने के अधिकार देते हुए मार्च 1972 से स्वीकृत किए गए हैं:

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या (सी एम/एल—)	वैधता की अवधि से	वैधता की अवधि तक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी आई०एस०: पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सी एम/एल-2954	9-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	तिनसुखिया आयल एण्ड सा मिल्स, माकम रोड, तिनसुखिया (असम)	चाय की पेटियों के लिए पट्टियां— आई०एस०: 10—1970
2.	सी एम/एल-2955	9-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	जयन्ती टिम्बर इंडस्ट्रीज, सहारनपुर रोड, यमुनानगर, जिला अम्बाला (हरियाणा)	चाय की पेटियों के लिए प्लाइवुड की पट्टियां— आई० एस०: 10-1970
3.	सी एम/एल-2956	9-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	प्रताप इंजीनियरी वर्क्स, रेलवे स्टेशन के सामने मलेरकोटला (पंजाब)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— आई० एस०: 226-1969
4.	सी एम/एल-2957	9-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	,, ,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)— आई० एस०: 1977-1969
5.	सी एम/एल-2958	9-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	राजेश इंडस्ट्रीज, श्री लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, शेड सं० 2-3 स्टेशन रोड भयंडर जिला थाना (महाराष्ट्र राज्य)	पिटवां एल्युमिनियम के बर्तन ग्रेड एस आई सी, एम आई बी और एन एस 3— आई एस: 21-1959
6.	सी एम/एल-2959	9-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	उषा सीविंग मशीन वर्क्स, (जय इंजीनियरी वर्क्स लि० की इकाई) 183-ए, प्रिंस अनवरशाह रोड, कलकत्ता-31	साफ, ठंडे पानी के लिए क्षैतिज अपकेन्द्रीय पम्प केवल साइज 100 मिमी × 100 मिमी (यू एस 600) और 80 मिमी × 65 मिमी (यू एस 500)— आई० एस०: 1520-1960

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	सी एम/एल-2960 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	मंजु इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, पोलाची रोड, मालूमीचम्पटी डाकघर, वरास्ता इंडस्ट्रियल इस्टेट, कोयम्बटूर-21 (तमिल नाडु)	तीन फेजी प्रेरण मोटर 3.7 कि वा (5 हा पा) तक ए श्रेणी के रोधन वाले— आई० एस० : 325–1961
8.	सी एम/एल 2961 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	एम्को जनरल इंडस्ट्रीज, 6/1, नवाब दिलावर जंग रोड, कासीपुर, कलकत्ता-2 (कार्यालय: 44 ए, रफी अहमद किदवई रोड, कलकत्ता-16)	100 मिमी तक बाहरी व्यास की साइज वाले पीने के पानी के उच्च घनत्व वाले पोलीइथाईलीन के पाइप 40 कि ग्रा ब/से मी² दाब रेटिंग के लिए— आई एस : 4984–1968
9.	सी एम/एल-2962 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	किशन इंडस्ट्रीज, माकम जंक्शन डाकघर, (असम)	चाय की पेटियों के लिए पट्टियां— आई एस : 10-1970
10.	सी एम/एल-2963 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	हिन्दुस्तान स्टील लि०, रूरकेला इस्पात संयंत्र, रूरकेला-1 (उड़ीसा)	बायलरों के लिए इस्पात की प्लेटें— आई० एस : 2002–1962
11.	सी एम/एल-2964 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	दि इंडस्ट्रियल गैसेस लि०, 146-अबूल रोड, हावड़ा-3 (पं० बंगाल) (कार्यालय : 15 गणेश-चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-1)	एक चालक वाले रेक्टीफायर लगे डी सी आर्क वेल्डर, रेटिंग : 250 अम्पी— आई एस : 4559–1968
12.	सी एम/एल-2965 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेन्ट मैन्यू० (इंडिया), प्रा०लि०, 35, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली (कार्यालय : सनलाइट बिल्डिंग, 26-27 आसफअली रोड, नई दिल्ली)	विकाट उपकरण— IS:5513-1969
13.	सी एम/एल-2966 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	पुलिंग एण्ड लिफ्टिंग मशीन (प्रा०) लि०, बी-10, इंडस्ट्रियल एरिया सं० 3, मेरठ रोड, गाजियाबाद	निम्नलिखित रेटिंग वाली यूनिवर्सल गियर रहित हस्त चालित खींचने तथा उठाने की मशीनें: (1) 1.6 मीटरी टन उठाई क्षमता और 2.6 मीटरी टन खिंचाई उठाई क्षमता वाली, (2) 3.2 मीटरी उठाई क्षमता और 5.2 मीटरी टन खिंचाई क्षमता वाली IS:5604-1970
14.	सी एम/एल-2967 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	नेट स्टील इक्विपमेण्ट (प्रा०) लि०, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सामने जी टी अम्बेकर मार्ग (नाई गाम रोड) दादर, बम्बई-14 डी डी	क्षैतिज बेलनाकार और क्षैतिज आयताकार दाब नुमा भाप स्टेरीलाइजर—: 3829-1966 क्षतिज शंकुनुमा उच्च गति दाबनुमा भाप स्टेरीलाइजर, IS:4510-1968
15.	सी एम/एल-2968 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	” ” ”	पायरोजन रहित आसुत पानी के लिए भभके IS:3830-1970
16.	सी एम/एल-2969 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	कनकार्ड आराय प्रा०लि०, उक्कियम तोरायपक्कम गांव, मद्रास-20 (कार्यालय: 13 जी एस टी रोड, गिंडी मद्रास-32)	नागरिक सुरक्षा के लिए धात्विक टोप-IS:2300-1968
17	सी एम/एल-2970 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	ज्यूपिटरग्लास वर्क्स, 23/4, ईस्ट पटेल नगर मार्किट, दिल्ली-8	ब्यूटायरोमीटर 10 प्रतिशत-IS:1223 (भाग 1)-1970

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	सी०एम०/एल-2971 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	लुधियाना स्टील रोलिंग मिल्स, मिलर गंज, जी टी रोड, लुधियाना	संरचना इस्पात (मानक किस्म)—IS : 226-1969
19	सी०एम०/एल-2972 10-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	,, ,, ,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)—IS:1977-1969
20	सी०एम०/एल-2973 14-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज, मरोल-मरोशी रोड, मरोल, बम्बई-59 (कार्यालय: कसरा स्ट्रीट, दारू-खाना, बम्बई-10 डी डी)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)—IS: 226-1969
21	सी०एम०/एल-2974 14-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज, मरोल-मरोशी रोड, मरोल, बम्बई-59 (कार्यालय: कसरा स्ट्रीट, दारू-खाना, बम्बई-10 डी डी)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)—IS:1977-1969
22	सी०एम०/एल-2975 14-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	सिल्वेक्स केबल कम्पनी प्रा०लि०, साकी-बिहार रोड, पवई, बम्बई-72 ए एस	निम्न प्रकार के पी वी सी रोधित केबल:— (1) इकहरी कोर, बिना खोल वाले 650/1100 वी ग्रेड के तांबा के चालकों वाले, (2) इकहरी कोर, बिना खोल वाले 250/440 वी ग्रेड के एल्युमिनियम चालकों वाले, और (3) चार कोर, पी वी सी खोल वाले 650/1100 वी ग्रेड के तांबा के चालकों वाले—IS:694 (भाग 1 और 2)-1964
23	सी०एम०/एल-2976 15-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	बजरगंबली स्टील कं० प्रा० लि०, हीजीगुरी, ए टी रोड, तिनसुखिया जिला डिबरूगढ़, (असम) [कार्यालय: मनकोटा रोड, डिबरूगढ़ (असम)]	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)—IS:1977-1969
24	सी०एम०/एल-2977 15-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	असम उद्योग कं०, मनकोटा रोड, डिबरूगढ़ (असम)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)—IS:1977-1969
25.	सी०एम०/एल-2978 15-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	वेंकटेश्वर एग्रो केमिकल्स एण्ड मिनरल्स, प्लाट सं० 3 बी, इंडस्ट्रियल इस्टेट, अम्बात्तूर, मद्रास-53	बी एच सी जल विसर्जनीय तेज चूर्ण—IS:562-1962
26.	सी०एम०/एल-2979 16-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	स्टील सल्स (इंडिया) प्रा० लि०, 131, इंडिस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़	संरचना इस्पात (मानक किस्म)—IS : 226-1969
27	सी०एम०/एल-2980 16-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	,, ,, ,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)—IS:1977-1969
28.	सी०एम०/एल-2981 16-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	पोलीआरोफिल्स इंडस्ट्रीज लि०, 5वां मील पत्थर, थाना बेलापुर, थाना (महाराष्ट्र)	1100 मिमी तक बाहरी व्यास की साइज वाले पीने के पानी के उच्च घनत्व वाले पालीइथाइलीन के पाइप 6.0 किग्रा / सें मी^{2} दाबरेटिंग के लिए—IS:4984-1968
29.	सी० एम०/एल–2982 16–3–1972	1-4-1972	31 3-1973	जयहिन्द ट्रैडिंग कारपोरेशन आक्सीजन हाउस, ज्ञानी वार्डर, जी० टी० रोड, डाकघर पसौंदा, गाजियाबाद (कार्यालय :1805, बिस्सोमल कालोनी, भागीरथ पैलस, दिल्ली)	टम्बलर स्विच-पोसलेन आधार वाले 15 अम्पी 250 वोल्ट—आई०एस० 3854-1966

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30. सी०एम०/एल-2983 16-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	कोंकाई ग्रराय प्रा०लि०, उविकयम तरी-पक्कम गांव मद्रास 20 (कार्यालय : 13, जी० एस० टी० रोड गिंडी, मद्रास-32	स्कूटर तथा मोटर चालकों के बचाव टोप--ग्राई०एम० : 4151-1967
31. सी०एम०/एल०-2984 16-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	फरनोन फाउंड्री, 3130, मंधारी रोड, भ्रागारा	केवल 50 मिमी साइज वाले बालू ढले लोहे के मल पाइप--ग्राई० एस० : 1729-1964
32. सी०एम०/एल०-2985 17-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	दि विदर्भ कोग्रापरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, फैक्टरी डिवीजन ग्रदनेरा रोड, पो० बाक्स० सं० 46, ग्रमरावती	एन्जिन का पायसनीय तेज द्रव ग्राई० एस० 1310-1958
33. सी०एम/एल०-2986 17-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	ग्रोमेगा केबल्स लि०, प्लाट सं० 16 ग्रौर 17 इंडस्ट्रियल इस्टेट, ग्रम्बात्तूर मद्रास-58 (कार्यालय : बुखारिया बिल्डिंग (चौथी मंजिल) सं० 1 मूर रोड़ रोड़, मद्रास-6)	एल्यूमिनियम या तांबे के चालकों वाले पी०वी०सी० रोधित (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल 1100 कार्यकारी वोल्टता के लिए--ग्राई०एस० 1554 (भाग 1)--1964
34. सी०एम०/एल०-2987 22-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	ग्राई० एम० सी० वोगन इंडस्ट्रीज प्रा०लि०, बजबज रोड, चन्द्रनगर निकट बाटानगर, 24 परगना (कार्यालय : 10/1, प्रिंस स्ट्रीट, कलकत्ता-13)	ठंडे ग्रौर ताजे पानी के लिए क्षैतिज ग्रपकेन्द्रीय पम्प केवल 80 × 85 मिमी साइज--ग्राई० एस० : 1520-1960
35. सी०एम०/एल०-2988 22-3 1972	1-4-1972	3-3-1973	पी०एस०जी० इंडस्ट्रियल इंस्टीच्यूट ग्रवनाशी रोड, पीलामेडू, डाकघर कोयम्बटूर-4 (तमिलनाडु)	ताजे ग्रौर ठंडे पानी के लिए क्षैतिज ग्रपकेन्द्रीय पम्प साइज 65×50 मिमी (एस०बी० ग्रौर एम० ए० 22 टाइप) ग्रौर 80×65 मिमी एम० ए० 22×टाइप)--ग्राई० एस०: 1520-1960
36. सी० एम०/एल-2989 22-3-1972	1-4-1972	31-3-1972	दि इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स लि०, महदेवपुरा, हिन्दुस्तान स्टील लि०, स्टाकयार्ड के निकट महदेवपुरा, बंगलौर-38 (कार्यालय : 108 ग्रारमेनियन स्ट्रीट, मद्रास-1	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी इस्पात की विकृत छड़ें--ग्राई०एस० 1786-1966
37. सी०एम०/एल०-2990 24-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	सिलवेनिया केबल कं० प्रा० लि०, साकी-बिहार रोड, 4 पवई बम्बई-72 एएस	पी०वी०सी० रोधित (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल 1100 तक कार्यकारी वोल्टता के लिए--ग्राई० 1554 (भाग 1)--1964
38. सी०एम/एल०-2991 24-3-1972	1-10-1972	30-9-1973	ग्रलका रबड़ कं० लि०, नागरगांव लोनावल्ला, जिला पूना (महाराष्ट्र) (कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालय हाउस, 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1)	पी०वी०सी० रोधित (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल 1100 तक कार्यकारी वोल्टता के लिए--ग्राई०एस : 1554 (भाग 1)--1959
39. सी०एम०/एल०-2992 24-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	नेशनल मशीन टूल इंडस्ट्रीज, ग्रो०/एम० इंडस्ट्रियल टावर जलंधर शहर	3-जा वाले खराद के स्वकेन्द्रीय चक, फेस्ल टाइप ए० 200 मिमी साइज--ग्राई०एस० : 2876-1964
40. सी०एम०/एल०-2993 28 3-1972	1-4-1972	31-3-1973	विक्टरी मेटल वर्क्स, 17/803 पवमणि रोड, पुतियारा कालीकट (केरल राज्य)	चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग--ग्राई०एस०: 10-1970

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.	सी०एम०/एल०-2994 28-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	कार्स (इंडिया) लि०, 1-पोखरन, थाना (पश्चिम) (महाराष्ट्र)	रंजकों से बनी फाउंटेन पेन की स्याही (रायल नीली, और लाल)—आई० एस० : 1221-1957
42.	सी०एम०/एल०-2995 28-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	एक्सट्रूजन, 5 नवाबपट्टी स्ट्रीट, कासीपुर, कलकत्ता-2 (कार्यालय 243, चितरंजन एवेन्यू कलकत्ता-6 (प० बंगाल)	अल्प घनत्व पोलीइथाइलीन फिल्म-आई०एस० : 2508-1963
43.	सी० एम०/एल०-2996 28-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	एक्सट्रूजन, 208, बी टी रोड़, सोदपुर, 24 परगना (प० बंगाल) (कार्यालय: 243 चितरंजन एवेन्यू कलकत्ता 6 (पं बंगाल)	अल्प घाव पोलीइथाइलीन फिल्म—आई० एस० : 2508-1963
44.	सी० एम०/एल-2997 28-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	गेथरवेयर प्लास्टिक्स प्रा० लि० वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विले पार्ले (पूर्व), बम्बई-57 (कार्यालय : चौपटी चैम्बर्स, मैडहर्स्ट ब्रिज, बम्बई-7	इमारतों में बिजली लगाने के लिए अधात्विक अनम्य तार नालियां, साइज 19 मिमी और 38 मिमी—आई० एस० : 2509-1963
45.	सी० एम०/एल०-2998 28-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	एफ० सी० सोधी एण्ड कं० (इंडिया) प्रा० लि० 1, बस्सी नौ, जलंधर शहर	फुटबाल (फीता रहित)—आई० एस० : 417-1969
46.	सी० एम०/एल०-2999 28-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	एसोसियेटेड प्रिसीजन मेटल वर्क्स, 4149, शाहतारा, अजमेरीगेट, दिल्ली	भीगे डायल वाले पानी के मीटर 15 मिमी अनुमानित प्रकार ए०—आई० एस० 779-1968
47.	सी० एम०/एल०-2000 29-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	रमिण इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, सी०/5, कोयम्बटूर प्रा० इंडस्ट्रियल इस्टेट, पोलाची रोड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (कार्यालय : 44 राजाजी रोड, रामनगर, कोयम्बटूर-9	ठंडे और साफ पानी के लिए केवल 65 मिमी × 50 मिमी साइज वाले क्षैतिज अपकेन्द्रीय पम्प—आई० एस०: 1520-1960
48.	सी० एम०/एल०-3001 29-3-1973	1-4-1972	31-3-1972	दि० सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०, 84/54 जी० टी० रोड कानपुर (उ० प्र०)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)—आई०एस० : 226-1969
49.	सी० एम०/एल०-3002 29-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	,, ,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)—आई०एस० : 1977-1967
50.	सी० एम०/एल०-3003 29-3-1972	1-4-1972	31-3-1972	एसोसियेटेड इस्ट्रूमैन्ट मैन्यु० (इंडिया) प्रा० लि० 35, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली (कार्यालय: मनलाइट बिल्डिंग 26/27, आसफअली रोड, नई दिल्ली)	(1) खण्ड 5.2 (बी०) के अनुसार लम्बाई मापक (2) खण्ड 4.2 (बी०) के अनुसार मोटाई मापक (3) खण्ड 3.2 (बी०) के अनुसार 3 लीटर, 15 लीटर तथा 30 लीटर वाले वेलनाकार धातु के नपने— आई०एस०: 2386 (भाग 1)—1963 आई०एस०: 2386 (भाग 3)—1963

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51. सी० एम०/एल०-3004	29-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	दि० टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड, तुगलकाबाद (कार्यालय : तीसरी मंजिल, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1)	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी इस्पात की विकृत छड़ें—आई०एस० : 17865-1966
52. सी० एम०/एल०-3005	30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	गंगा प्रीसीजन इंडस्ट्रीज, अवनाशी रोड, पम्पानाय चन पलयम् कोयम्बटूर-18 (तमिलनाडु) (कार्यालय : रामनगर, कोयम्बटूर-9)	निम्नलिखित रेटिंग के खड़ी प्रकार के डीजल इंजन :— किवा० आर०पी०एस० टाइप 3.7 1500 जी० पी० आई० 2 आई०एस० : 1601-1960
53. सी० एम०/एल०-3006	30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	दि इंगलिश इलैक्ट्रिक क० आफ इंडिया लिमिटेड, 19/1 जी० एस० टी० रोड, पल्लवरम, मद्रास-43 (तमिलनाडु)	गैस चालित रिले—आई०एस० : 3637-1966
54. सी० एम०/एल०-3007	30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	दि पंजाब स्टील रोलिंग मिल्स, अम्लोह रोड, मंडी गोबिन्द गढ़, जिला पटियाला	संरचना इस्पात (मानक किस्म)—आई०एस० : 226-1969
55. सी० एम०/एल०-3008	30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	,, ,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)—आई०एस० : 1977-1969
56. सी० एम०/एल०-3009	30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	पंजाब गैज एण्ड माइट ग्लास कं०, प्लाट सं० 25, सैक्टर 25 सैक्टर 25 बल्लभगढ़ (हरियाणा)	दृढ़ीकृत कांच—आई०एस०: 2553-1964
57. सी० एम०/एल० -3010	30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	गंगप्पा केबल्स लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलेमेंट एरिया, उप्पल, हैदराबाद-39 (आन्ध्र प्रदेश)	(1) वाइरिंग इनैमलकृत गोल ताम्बे के तार : उच्च यांत्रिक गुणो वाले— (2) वाइरिंग के इनैमलकृत गोल तांबे के तार: ऊंचे तापों के लिए—आई०एस० 4800(भाग 4)-1968 आई० एस० : 4800 (भाग 5)-1968
58. सी० एम०/एल०-3011	30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	केजरीवाल आटो-इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, 29 बाबुल बोना रोड, डाकघर बरहामपुर, मुर्शिदाबाद (पं० बंगाल)	मोटर गाड़ियों के लिए सीसा अम्ल वाला संग्राही बैटरियां (भारी ड्यूटी वाले)—आई० एस० : 985-1962
59. सी० एम०/एल०-3012	30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	एवरशाईन इलैक्ट्रिकल वर्क्स (इंडिया) 10/16, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्तिनगर, नई दिल्ली	पोलीइथाइलीन रोधित ऋतुसह केबल टेपलगे ब्रेडेड और सहमिलित इकहरी कोर वाले एल्युमिनियम चालकों वाले 250/440 और 650/1100 वोल्ट—आई० एस० : 3035(भाग 2)—1965
60. सी० एम०/एल०-3013	30-3-1972	1-4-172	31-3-1973	महेन्द्र मेटल वर्क्स, 111/सी०, गवर्नमेन्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट, कान्डीवली (पश्चिम) बम्बई-67 (कार्यालय : जी० - 73 सर्वोदयनगर, पंजरापोल रोड, बम्बई-4)	पिटवां एल्युमिनियम के बर्तन, ग्रेड एस० आई सी० एस० आई बी० और एन० एस० 3— : 21-1959

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61.	सी० एम०/एल०-3014 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	एलायन्स जूटमिल्स : (एलायन्स मिल्स) (पट्टाधारी) प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर जगतदल, 24-परगना (पं० बंगाल) (कार्यालय: 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	बी०-ट्विल पटसन के बोरे--आई०एस० : 2566-1965
62.	सी० एम०/एल०-3015 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	हिन्दुस्तान इंसुलेटेड केबल्स कं०, पटेल मार्ग, गाजियाबाद	पी० वी० सी० रोधित बिना खोल वाले केबल, 250/440 वो० के एल्युमिनियम चालकों वाले और पी० वी० सी० रोधित खोल वाले केबल, 250/1100 वो० के एल्युमिनियम चालकों वाले--आई०एस० 694 (भाग 2)--1964
63.	सी० एम०/एल०-3016 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	छाबड़ा इंडस्ट्रीज, सी-121, माडर्न इंडस्ट्रियल इस्टेट, बहादुरगढ़ (कार्यालय : 511, कटरा ईश्वरभवन, दिल्ली)	घूमने वाले दंडों की तेल सील केवल ए टाइप की--आई० एस० : 5129-1969
64.	सी० एम०/एल०-3017 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	दि इंगलिश इलैक्ट्रिक क० आफ इंडिया लिमिटेड, 19/1 जी० एस० टी० रोड, पल्लावरम, मद्रास-43 (तमिलनाडु)	(1) विद्युत चुम्बकीय रिलेज और (2) प्रेरण रिलेज-- आई०एस० : 3231-1965
65.	सी० एम०/एल०-3018 30-3-1972	1-1-1972	31-3-1973	केबल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, दत्तापाड़ा बोरीवली-पूर्व बम्बई-66 एम० बी०, (कार्यालय : लक्ष्मी बिल्डिंग, 6 शूरजी बल्लभदास मार्ग, बम्बई-1 बी० आर०)	पी. वी० सी० रोधित केबल बिना खोल वाले 650/1100 वो० तांबा के चालकों के वाले --आई०एस० : 694 (भाग 1)--1964
66.	सी० एम०/एल०-3019 30-3-1972	1-1-72	31-3-1973	इंडियन केबल इंडस्ट्रीज, बम्बई-पूना रोड, पिम्परी पूना-18 (मद्रास)	तापनम्य रोधित कठोर केबल, पी० वी० सी० रोधित और पी० वी० सी० खोलवाले इकहरी कोर, 250/440 वो० वाले एल्युमिनियम चालकों वाले--आई०एस० : 3035 (भाग 1)-1965
67.	सी० एम०/एल०-3020 30-3-1973	1-4-1972	31-3-1973	फ्रेंकली इंडिया, 4/ए, घोर बागान, कलकत्ता-7	इलेक्ट्रोड होल्डर--आई०एस० : 2641-1964
68.	सी० एम०/एल०-3021 30 3-1972	1-4-1972	31-3-1973	रामतीर्थ आयरन एण्ड स्टील रि-रोलिंग मिल्स, मंडी. गोबिन्द गढ़, जिला पटियाला (पंजाब)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)--आई० एस० : 226-1969
69.	सी० एम०/एल०-3022 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	,, ,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)--आई० एस० : 1977-1969
70.	सी० एम०/एल०-3023 30-3-1973	1-4-1972	31-3-1973	कमरहट्टी कम्पनी लि०, ग्राहम रोड, कमरहट्टी, कलकत्ता-58 कार्यालय : 9 ब्रैबोर्न रोड, कलकत्ता	बी०-ट्विल पटसन के बोरे--आई०एस० 2566-1965
71.	सी० एम०/एल-3024 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लि०, मौलाअली. हैदराबाद-40 (आ० प्र०)	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी इस्पात की विकृत छड़ें-- (1) 14 मि मी तक सांकेतिक व्यास की साइज वाली, (2) 15 मि मी से ऊपर के सांकेतिक व्यास की साइज वाली--आई०एस० : 1786-1966

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72. सी० एम०/एल०-3025 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	मर्दन स्टील लि०, मौलाअली, हैदराबाद-40	टंडी बेल्लित इस्पात की पत्तियां (बक्से बांधने के लिए)—आई० एस० : 5872-1070
73. सी० एम०/एल०-3026 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	प्रोगेसिव इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इस्टेट, धेनकनाल (कटक) (कार्यालय : मनीमाइ उाब, कटक-1 उड़ीसा)	सामान्य जलसह तिरपाल—आई० एस० : 2089-1962
74. सी० एम०/एल०-3027 30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	किलैब इंडस्ट्रीज, 49, बी० टी० रोड, पानीहट्टी 24-परगना (प० बंगाल) (कार्यालय : 25 आर्मिनियन स्ट्रीट, कलकत्ता-16)	चाय की पेटियों के लिए प्लाइवुड के तख्ते—आई० एस० : 10-1970
75. सी० एम०/एल०-3028 30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	विजय इंडस्ट्रीज, 70 धर्मतल्ला रोड, डाकघर धुसुरी, सल्किया, हावड़ा (कार्यालय : 28, स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता-1)	बाड़ के लिए जस्ता चढ़े इस्पात के कांटेदार तार—आई० एस० : 278-1969
76. सी० एम०/एल०-3029 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	मुलेखराम एण्ड संस स्टील रोलिंग मिल्स, बल्लभ नगर, ऊधव रोड, अहमदाबाद-21	संरचना इस्पात (मानक किस्म)—आई० एस० : 225-1969
77. सी० एम०/एल०-3030 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	,, ,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)—आई० एस० : 1977-1969
78. सी० एम०/एल०-3031 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	रीजनल पिग ब्रीडिंग स्टेशन कम बेकन फैक्टरी, हरिनघाटा, हरिनघाटाफार्म, डाकघर मोहनपुर, जिला नादिया, (प० बंगाल)	सुअर की जांघ का मांस—आई० एस० : 2476-1963
79. सी० एम०/एल०-3032 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	,, ,,	सुअर का धुआंया मांस—आई० एस० : 2475-1963
80. सी० एम०/एल०-3033 30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	केमिकल्स एण्ड इंसेक्टीसाइड्स, रामनगर, करंजहा, डाकघर मेहमहा रेलवे स्टेशन कुसमी (उ पू रे) गोरखपुर (कार्यालय : सराफ चैम्बर्स, हिन्दी बाजार, गोरखपुर (उ० प्र०)	दृढ़ीकृत मिथाइसी इथाइल पारा क्लोराइड के तेज चूर्ण से बने यौगिक—आई० एस० : 2358-1963
81. सी० एम०/एल०-3034 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	नाथक इंडस्ट्रीज, 11/12, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजपुरा	डोर क्लोजर (द्रव नियंत्रित) केवल 2 साइज—आई० एस० : 3564-1970
82. सी० एम०/एल०-3035 30-3-1973	16-4-1972	15-4-1973	इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स (इंडिया), पी० 47, हाइड रोड, एक्सटेंशन, कलकत्ता-27 (कार्यालय : 15, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16)	औद्योगिक बचाव टोप—आई० एस० : 2925-1964
83. सी०एम०/एल०-3036 30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	सरोज इंजीनियरिंग कारपोरेशन, इछापुर रोड, दासनगर, हावड़ा-5	जल कल कार्यों के लिए स्लूस वाल्व, श्रेणी 1, 300 मि० मी० तक की साइज वाले—आई० एस० : 780 1969
84. सी० एम०/एल०-3037 30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	रस्टन एण्ड आम्स्टन मशीन सप्लाई कं० 30, सुखराम कनोडिया रोड, हावड़ा-1 (कार्यालय : 21-ए, विप्लवी रासबिहारी बोस रोड, (दूसरी मंजिल) (कलकत्ता-1)	ठंडे और साफ पानी के क्षैतिज अपकेन्द्रीय पम्प केवल 80 मि० मी०, 65 मि०मी० साइज वाले (5 हा० पा०, सप्लाई वाले)—आई० एस० 1520-1960

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
85.	सी० एम/एल०-3038 30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	दि भारत कार्बन एण्ड रिबन मैन्यु० कं० लि०, 66-ए, इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद (हरयाणा) (कार्यालय : एन-75, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-1)	मध्य स्याही (काली) लगे टाइपराइटर के रिबन—आई० एस० : 4174-1967
86.	सी० एम०/एल०-3039 30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	पारस प्रा० लि०, 16, इंडस्ट्रियल एरिया, बांस वाड़ा (राजस्थान)	शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए सख्त खिंचे लड़दार इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चालक—आई० एस० : 398-1961
87.	सी० एम०/एल०-3040 30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	नेशनल पेस्टीसाइड्स, 5-इंडस्ट्रियल इस्टेट, विदिशा (म० प्र०)	डी० डी० टी० जल विसर्जनीय तेज चूर्ण—आई० एस० : 565-1961

[सं० सी एम डी/13 : 11]

New Delhi, the 13th March, 1973

S. O. 887.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that eightyseven licences, particulars of which are given in the following schedule, have been granted during the month of March 1972 authorizing the licensees to use the Standard Marks :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L)	Period of From	Validity To	Name and Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licence and the Relevant IS: Designation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CM/L-2954 9-3-1972	16-3-72	15-3-73	Tinsukia Oil & Saw Mills, Makum Road, Tinsukia (Assam)	Tea-chest battens—IS:10-1970
2.	CM/L-2955 9-3-1972	16-3-72	15-3-73	Jayanti Timber Industries, Saharanpur Road, Yamuna Nagar, Distt. Ambala (Haryana)	Plywood Tea-chest Battens—IS : 10-1970
3.	CM/L-2956 9-3-1972	16-3-72	15-3-73	Partap Engineering Works, Opposite Railway Station, Malerkotla (Punjab)	Structual Steel (Standard Quality)—IS : 226-1969
4.	CM/L-2957 9-3-1972	16-3-72	15-3-73	Partap Engineering Works, Opposite Railway Station, Malerkotla (Punjab)	Structural Steel (Ordinary Quality) IS: 1977-1969
5.	CM/L-2958 9-3-1972	16-3-72	15-3-73	Rajesh Industries, Shree Laxmi Industrial State, Shed No. 2-3 Station Road, Bhayandar, Distt. Thana (Maharashtra State)	Wrought Aluminium Utensils, Grade : SIC, SIB and NS3—IS : 21-1959
6.	CM/L-2959 9-3-1972	16-3-72	15-3-73	Usha Sewing Machine Works, (A Unit of the Jay Engg. Works Ltd.) 183-A, Prince Anwar Shah Road, Calcutta-31	Horizontal Centrifugal Pumps, for clear, cold fresh water, Sizes 100 mm × 100 mm (US-600) and 80 mm × 65 mm (US-500) only IS: 1520-1960
7.	CM/L-2960 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Manju Electrical Industries Pvt. Ltd., Pollachi Road, Malumichampatti Post, Via Industrial Estate, Coimbatore-21 (Tamil Nadu)	Three-phase Induction Motors upto 3.7 Kw (5 HP) with class 'A' insulation—IS : 325-1961
8.	CM/L-2961 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Emco General Industries. 6/1, Nawab Dilawar Jung Road, Cossipore, Calcutta-2 (Office : 44A Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16)	High density polyethlene pipes for potable water supplies for sizes upto and including 110 mm outside diameter for pressure rating upto and including 4.0 Kgf/cm^2—IS : 4984-1968
9.	CM/L-2962 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Keshan Industries, Makum Junction, P.O. Assam	Tea-chest Battens — IS: 10-1970
10.	CM/L-2963 10 3-1972	16-3-72	15-3-73	Hindustan Steel Ltd. Rourkela Steel Plant, Rourkela-1 (Orissa)	Steel Plates for Boilers—IS : 2002 1962

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	CM/L-2964 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	The Industrial Gases Limited, 146, Andul Road, Howarah-3 (West Bengal). (Office : 15 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-1.)	Single Operator rectifier type dc arc welder, rating : 250 amps—IS : 4559-1968
12.	CM/L-2965 10-3-1972	16-3 72	15-3-73	Associated Instrument Mfrs. (India) Pvt. Ltd., 35, Najafgarh Road, New Delhi, (Office: Sunlinght Buildings, 26-27, Asaf Ali Road, New Delhi.)	Vicat apparatus—IS : 5513-1969 5513-1969
13.	CM/L-2966 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Pulling and Lifting Machines (P) Ltd., B-10, Industrial Area No. 3, Meerut Road, Ghaziabad.	Universal gearless hand-operated pulling and Lifting machines of following ratings: (i) 1.6 tonnes lifting capacity and 2.6 tonnes pulling capacity (ii) 3.2 tonnes lifting capacity and 5.2 tonnes pulling capacity—IS : 5604-1970
14.	CM/L-2967 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Nat Steel Equipment (P) Ltd., Opposite Police Training School, G.D. Ambekar Marg (Naigaum Road), Dadar, Bombay-14 DD.	Horizontal Cylinderical and Horizontal Rectangular Steam Sterilizer, Pressure Type—IS : 3829-1966 Horizontal Cylinderical High Speed Steam Sterilizers, Pressure Type—IS : 4510-1968
15.	CM/L-2968 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Nat Steel Equipment (P) Ltd., Opposite Police Training School, G.D. Ambekar Marg (Naigaum Road), Dadar, Bombay-14 DD.	Water stills for Pyrogen-Free Distilled water—IS : 3830-1970
16.	CM/L-2969 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Concord Arai Pvt. Ltd., Ukkiam, Thoraippakkam Village, Madras-20. (Office: 13, G.S.T. Road, Guindy, Madras-32.	Non-metal helmets for civil defence—IS : 2300-1968
17.	CM/L-2970 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Jupitor Glass Works, 23/4, East Patel Nagar, Market, Delhi-8.	Butyrometers 10%—IS : 1223 (Part I)-1970
18.	CM/L-2971 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Ludhiana Steel Rolling Mills, Miller Ganj, G.T. Road, Ludhiana.	Structural Steel (Standard Quality)—IS : 226-1969
19.	CM/L-1972 10-3-1972	16-3-72	15-3-73	Do.	Structural Steel (Ordinary Quality)—IS : 1977-1969
20.	CM/L-2973 14-3-1972	16-3-72	15-3-73	Agarwal Steel Industries, Marol-Maroshi Road, Marol, Bombay-59. (Office : Kasara, Street Darukhana, Bombay-10 DD.	Structrural Steel (Standard Quality)—IS : 226-1969
21.	CM/L-2974 14-3-1972	16-3-72	15-3-73	Do.	Structural Steel (Ordinary Quality)—IS : 1977-1969
22.	CM/L-2975 14-3-1972	16-3-72	15-3-73	Sylvex Cable Company Pvt. Ltd., Saki-Vihar Road, Powai, Bombay 72 AS.	PVC insulated cables of the following types : (i) Single core, unsheathed 650/1100 Volts grade with copper conductor; (ii) Single core, unsheathed, 250/440 volts grade with aluminium conductor; and (iii) Four core, PVC sheathed, 650/1100 volts grade with Copper Conductor—IS : 694 (Part I and II)-1964
23.	CM/L-2976 15-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	Bajrangbali Steel Co. Pvt. Ltd., Hijiguri, A.T. Road, Tinsukia, Distt. Dibrugarh, (Assam) [Office: Mancotta Road, Dibrugarh, (Assam)].	Structural Steel (Ordinary Quality)—IS : 1977-1969
24.	CM/L-2977 15-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	Assam Udyog Co,, Mancotta Road, Dibrugarh, (Assam).	Structural Steel (Ordinary Quality)—IS : 1977-1969
25.	CM/L-2978 15-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	Venkateswara Agro Chemicals and Minerals. Plot No. 3B, Industrial Estate, Ambattur, Madras-53.	BHC Water Dispersible Powder Concentrates IS : 562—1962
26.	CM/L-2979 16-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	Steel Sales (India) Pvt. Ltd., 131, Industrial Area, Chandigarh.	Structural Steel (Standard Quality)—IS : 226-1969
27.	CM/L-2980 16-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	-do-	Structural Steel (Ordinary Quality)—IS : 1977-1969

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. CM/L-2981 16-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	Polyolefins Industries Ltd., Mile Stone No. 5, Thana Belapur Road, Thana (Maharashtra)	High density polyethylene pipes for portable water supplies for sizes up to and including 110 mm outside diameter for pressure ratings 6.0 kg/cm²—IS : 4984—1968
29. CM/L-2982 16-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Jai Hind Trading Corporation, Oxygen Houses Giani, Border, G.T. Road, P.O. Pasonda, Ghaziabad (Office: 1805, Bissomal Colony, Bhagirath Palace, Delhi).	Tumbler Switches porcelain base, 15 amp 250 volts—IS : 3854—1966
30. CM/L-2983 16-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Concord Arai Pvt. Ltd, Ukkiam, Thoraippakkam, Village, Madras-20 [Office: 13, G.S.T. Road, Guindy, Madras-32].	Protective halmets for scooter and motor-cycle riders—IS : 4151—1967
31. CM/L-2984 16-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	Fernon Foundary, 3/30 Khandhari Road, Agra,	Sand Cast Iron soil pipes, 50 mm size only—IS : 1729—1964
32. CM/L-2985 17-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	The Vidarbha Co-operative Marketing Society Ltd., Factory Division, Badnera Road, Post Box No. 46, Amravati.	Endrin EC—IS : 1310—1958
33. CM/L-2986 17-3-1972	16-3-1972	15-3-1973	Omega Cables Limited, Plot No.16 & 17 Industrial Estate, Ambattur, Madras-58. [Office: Bukharia Building (3rd Floor), No.1 Moores Road, Madras-6.]	PVC insulated (heavy duty) Electric cables for working voltages up to and including 1100 volts with aluminium or copper conductors—IS : 1554 (Part I)—1964
34. CM/L-2987 22-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	IMC–Vogel Industries Pvt. Ltd., Budge Budge Road, Chandannagar, Near Batanagar, 24 Parganas [Office: 10/1, Princep Street, Calcutta-13].	Horizontal Centrifugal Pumps for clear cold, fresh water size 80×65 mm only—IS : 1520—1960
35. CM/L-2988 22-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	P.S.G. Industrial Institute, Avanashi Road, Peelamedu P.O. Coimbatore-4 (Tamil Nadu).	Horizontal Centrifugal pumps for clear cold water for sizes 65×50 mm (SB 26 and SA 22 types) and 80×65 mm (SA22 type)—IS : 1520—1960
36. CM/L-2989 22-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	The Indian Steel Rolling Mills Ltd., Bayyappanahalli, Adjacent to Hindustan Steel Ltd.,Stockyard, Bayyappanahalli, Bangalore-38 [Office: 108 Armenian Street, Madras-1].	Cold Twisted Deformed Steel Bars for concrete Reinforcement—IS : —1786—1966
37. CM/L-2990 24-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Sylvex Cable Co. Pvt. Ltd., Saki-Vihar Road, Powai, Bombay-72 AS.	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages up to and including 1100 volts—IS : 1554 (Part I)—1964
38. CM/L-2991 24-3-1972	1-10-1972	30-9-1973	Alfa Rubber Co Ltd, Nagargaon, Lonavla, Distt. Poona (Maharashtra) [Office: 2nd Floor, Himalaya House, 23 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-1].	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages up to and including 1100 volts—IS: 1554 (Part I)—1964
39. CM/L-2992 24-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	National Machine Tool Industries, O/S Industrial Tower, Jullundur City.	3-Jaw Self-centring lethe Chucks, Type A, 200 mm size only—IS : 2876—1964
40. CM/L-2993 28-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Victory Metal Works, 17/803, Pavammani Road, Puthiyara, Calicut (Kerala State).	Tea-chest metal fittings—IS : 10—1970
41. CM/L-2994 28-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Kores (India) Ltd, 1st Pokharan, Thana (West), Maharashtra.	Dye Based Fountain Pen Ink (Royal Blue & Red)—IS : 1221—1957
42. CM/L-2995 28-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	Extrusions, 5, Nawavputty Street, Cossipore, Calcutta-2 [Office : 243, Chittaranjan Avenues Calcutta-6 (West Bengal)].	Low Density Polyethylene Films—IS : 2508—1963
43. CM/L-2996 28-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	Extrusions, 208, B.T. Road, Sodepur, 24 Parganas (West Bengal) [Office: 243, Chittaranjan Avenue, Calcutta-6, (West Bengal)].	Low Density Polyethylene Films-IS 2508—1963
44. CM/L-2997 28-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Garevare Plastics Pvt. Ltd., Western Express Highway, Vile Parle (East), Bombay-57 [Office: Chowpatty Chambers, Sandhurst Bridge, Bombay-7].	Rigid non-metallic conduits for electrical installations 19 mm and 38 mm sizes.—IS : 2509—1963

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	CM/L-2998 28-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	F. C. Sondhi & Co, (India) Pvt. Ltd., 1, Basti Nau, Jullundur City.	Football (Laceless)–IS:417-1969
46.	CM/L-2999 28-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Associated Precision Metal Works, 4149, Shahtara, Ajmerigate, Delhi.	Water meters, wet dial, 15 mm inferential Type 'A'–IS : 779-1968
47.	CM/L-3000 29-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Rashmi Engineering Industries, C-5, Coimbatore Private Industrial Estate, Pollachi Road, Coimabatore (Tamil Nadu) [Office: 44, Rajaji Road, Ramnagar, Coimbatore-9].	Horizontal centrifugal pumps for clear cold, fresh water size 65 mm 50 mm only—IS : 1520-1960
48.	CM/L-3001 29-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	The Singh Engineering Works Pvt. Ltd, 84/54 G.T. Road, Kanpur (U.P.).	Structural Steel (Standard Quality)— IS : 226-1969
49.	CM/L-3002 29-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	-do-	Structural Steel (Ordinary Quality)— IS : 1977-1969
50.	CM/L-3003 29-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Associated Instrument Mfrs (India) Private Limited, 35, Najafgarh Road, New Delhi [Office: Sunlight Buildings, 26-27 Asaf Ali Road, New Delhi].	(i) Length Gauge as per clause 5.2 (b) (ii) Thickness gauge as per clause 4.2 (b) (iii) Cyclindrical metal measures, 3 litres, 15 litres and 30 litres as per clause 3.2 (b)– IS : 2386(Part I)-1963 IS : 2386 (Part III)-1963
51.	CM/L-3004 29-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	The Tata Iron & Steel Co. Ltd., Tughlakabad [Office: 3rd Floor Bank of Baroda Building, 16 Parliament Street, New Delhi].	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement–IS:1786-1966
52.	CM/L-3005 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Ganga Precision Industries, Avanashi Road, Pappanaickan Palayam, Coimbatore-18 (Tamil Nadu) [Office: Ramnagar Coimbatore-9].	Vertical Diesel Engines of the following ratings: KW R.P.M. Type– 3.7 1500 GPI-2 5 HP IS : 1601-1960
53.	CM/L-3006 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	The English Electric Co of India Ltd., 19/1 G.S.T. Road, Pallavaram, Madras-43 (Tamil Nadu).	Gas operated relays–IS:3637-1966
54	CM/L-3007 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	The Punjab Steel Rolling Mills, Amloh Road, Mandi, Govind Garh, Distt. Patiala.	Structural Steel (Standard Quality)— IS : 226-1969
55.	CM/L-3008 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	-do-	Structural Steel (Ordinary Quality)— IS : 1977-1969
56.	CM/L-3009 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Punjab Gauge and Sight Glass Co, Plot No.25, Secton 25, Ballabh Garh (Haryana).	Toughened Glass—IS : 2553-1964
57.	CM/L-3010 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Gangappa Cables Ltd, Industrial Development Area, Uppal, Hyderabad-39 (Andhra Pradesh).	(1) Enamelled Rounding copper wires with high mechanical properties and (2) Enamelled round winding copper wires for elevated temperatures IS : 4800(Part IV)-1968 IS : 4800(Part V)-1968
58.	CM/L-3011 30-3-1972	16-4-1972	15-4-1973	Kejriwal Auto-Electric & Engineering Works, 29, Babul Bona Road, P.O. Berhampore, Murshidabad (West Bengal).	Lead-acid storage batteries (heavy duty) motor vehicles—IS : 985-1962
59.	CM/L-3012 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Evershine Electrical Works (I), 10/61, Industrial Area, Kirti Nagar, New Delhi.	Polyethylene insulated weather proof cables taped braided and compounded single core, aluminium conductors, 250/440 and 650/1100 volts—IS : 3035(Part II)-1965
60.	CM/L-3013 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Mahendra Metal Works, 111-C, Government Industrial Estate, Kandivali (West) Bombay-67 [Office: G-73, Sarvodayanagar, Panjrapole Road, Bombay-4].	Wrought Aluminium Utensils, Grades–STC. SIB & NS3—IS : 21-1959
61.	CM/L-3014 30-3-1972	1-4-1972	31-3-1973	Alliance Jute Mills, [Alliance Mills (Lessees) Pvt. Ltd.] P. O. Jagatdal, 24, Parganas (West Bengal) [Office : 18 Nataji Subash Road, Calcutta].	B-Twill Jute Bags—IS : 2566-1965

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62. CM/L-3015 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Hindustan Insulated Cables Co., Patel Marg, Ghazianad.	PVC insulated unsheathed cables, 250/440 volts with aluminium conductors and PVC insulated sheathed cables, 250/440 and 650/1100 volts with aluminium conductors—IS : 694 (Part II)-1964
63. CM/L-3016 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Chhabra Industries, C-21, Modern Industrial Estate, Bahadurgarh [Office : 511 Katra Ishwar Bhawan, Delhi]	Rotary Shaft Oil Seal, Type 'A only—IS : 5129-1969
64. CM/L-3017 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	The English Electric Co. of India Ltd, 19/1, G.S.T. Road, Pallavarn, Madras-43.(Tamil Nadu)	(1) Electro megnetic relays; and (2) Induction relays—IS : 3231-1965
65. CM/L-3018 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Cable Corporation of India Ltd, Duttapada, Borivli-East, Bombay-66 NB [Office : Laxmi Building, 6 Shoorji Vallabhdas Marg, Bombay-1 BR]	PVC insulated cables unsheathed 650/1100 volts with copper Conductors—IS : 694 (Part I)-1964
66. CM/L-3019 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	India Cable Industries, Bombay Poona Road, Pimpri, Poona-18 (Maharashtra).	Thermolpastic insulated weather-proof cables, PVC insulated and PVC sheathed single core, 250/440 volts with aluminium conductor—IS:3035 (Part I)-1965
67. CM/L-3020 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Frankly India, 4/A, Chore Bagan, Calcutta-7.	Electrode holders—IS : 2641-1964
68. CM/L : 3021 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Ram Tirth Irons & Steel Rerolling Mills, Mandi, Gobindgarh, Distt. (Patiala Punjab)	Structural Steel (Standard Quality)—IS : 226-1969
69. CM/L-3022 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	-do-	Structural Steel (Ordinary Quality)—IS : 1977-1969
70. CM/L-3023 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Kamarhatty Company Limited, Graham Road, Kamarhatty, Calcutta-58 [Office : 9 Brabourne Road, Calcutta-1]	B-Twill Jute Bage—IS : 2566-1965
71. CM/L-3024 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Andhra Steel Corporation Limited, Moula Ali, Hydcrabad-40(A.P.)	Cold twisted deformed steel bars for concretre reinforcement. (1) Sizes upto and including 14 mm nominal dia (2) Sizes above 14 mm nominal dia IS : 1786-1966
72. CM/L-3025 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Southern Steel Limited, Moula Ali, Hyderabad-40	Cold Rolled Steel Stripes (Box Strappings)—IS : 5872-1970
73. CM/L-3026 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Orilin Industries, Industrial Estate, Dhenkanal, Cuttack [Office : Manisahu Chhak, Cuttack-1 (Orissa)]	Common Proofed paulins (Tarpaulins)—IS : 2089-1962
74. CM/-L-3027 30-3-1972	16-4-72	15-4-73	Kinlab Industries, 49, B. T. Road, Panihati, 24 Parganas (W. Bengal) [Office : 25 Morquis Street, Calcutta-16]	Tea-chest plywood panels—IS : 10-1970
75. CM/L-3028 30-3-1972	16-4-72	15-4-73	Vijay Industries, 70, Dharamtolla Rd, P. O. Ghusuri, Salkia, Howarh [Office : 28 Strand Road, Calcutta-1]	Galvanized steel barbed wire for fencing—IS : 278-1969
76. CM/L-3029 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Sulekh Ram & Sons Steel Rolling Mills, Vallabh Nagar, Odhav Road, Ahmedabad-21.	Structural Steel (Standard Quality)—IS : 226-1969
77. CM/L-3030 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	-do-	Structural Steel (Ordinary Quality)—IS : 1977-1969
78. CM/L-3031 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	Regional Pig Breeding Station-cum Bacon Factory, Haringhata, Haringhata Farm P. O. Mohanpur, District, Nadia, West Bengal.	Ham—IS : 2476-1963
79. CM/L-3032 30-3-1972	1-4-72	31-3-73	-do-	Smoked Bacon—IS : 2475-1963
80. CM/L-3033 30-3-1972	16-4-72	15-4-73	Chemicals & Insecticides, Ram Nagar, Karanjaha, P. O. Bhaisaha, Rly. Station Kushmi (NER), Gorakhpur [Office : Saraf Chambers, Hindi Bazar, Gorakpur (U.P.)	Formulations based on stabilized methoxy ethyl marcury chloride concentrates, 3% and 6%—IS : 2358-1963

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81. CM/L-3034 30-3-72	1-4-72	31-3-73	Tarak Industries, 11 & 12 Industrial Estate, Rajpura	Door closer hydraulically regulated size 2 only—IS : 3564-1970
82. CM/L-3035 30-3-1972	16-4-72	15-4-73	Industrial Plastics (India), P-47, Hide Road, Extension, Calcutta-27 [Office : 15, Park Street, Calcutta-16]	Industrial Safety helmets IS : 2925 1964
83. CM/L-3036 30-3-1972	16-4-72	15-4-73	Saroj Engineering Concern, Ichapur Road, Dasnagar, Howrah-5.	Sluice valves for water works purposes, class I upto 300 mm size—IS : 780:1969
84. CM/L-3037 30-3-1972	16-4-72	15-4-73	Ruston & Crompton Machines Supply Company, 30, Mukhram Kanoria, Road, Howrah-1. [Office: 21-A, Biplabi Rashpbchari Bose, Road, (First Floor), Calcutta-1.]	Horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water, size 80mm x 65mm only (5HP, Capacity) IS : 1520-1960
85. CM/L-3038 30-3-1972	16-4-72	15-4-73	The Bharat Carbon & Ribbon Manufacturing Company Limited, 66-A, Industrial Area, Faridabad (Haryana) [Office : N-75, Connaught Circus, New Delhi-1]	Typewriter ribbons with medium inking (Black)—IS : 4174-1967
86. CM/L-3039 30-3-1972	16-4-72	15-4-73	Paras Pvt. Ltd., 16 Industrial Area, Banswara (Rajasthan)	Hard-drawn stranded aluminium and steel cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes—IS : 398-1961
87. CM/L-3040 30-3-72	16-4-72	15-4-73	National Pesticides, 5 Industrial Estate, Vidisha(M.P.)	DDT Water Dispersible Powder Concentrates—IS : 565—1961

[No. CMD/13:11]

का० आ० 888.—नीचे जिन प्रमाणन मुहर लाइसेंसों के ब्यौरे अनुसूची में दिये गये हैं या तो वे रद्द हो गये हैं अथवा उनका नवीकरण स्थगित कर दिया गया है:

अनुसूची

क्रम संख्या लाइसेंस संख्या तथा जारी करने की तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	वस्तु/प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी IS: पद नाम	एस० ओ० संख्या तथा लाइसेंस स्वीकृति छपने वाले गजट की तिथि	विवरण
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सी० एम०/एल-1297 13-7-1966	अग्रवाल हार्डवेयर वर्क्स, प्रा०लि०, 2 ईश्वर चटर्जी रोड, सोदेपुर (24 परगना)	गर्म वैल्लित इस्पात की पत्तियां– IS : 1029-1956	एस० ओ० 2600 दिनांक 27-8-1966	इस लाइसेंस का नवीकरण 31-7-1968 के बाद स्थगित कर दिया गया था अब यह उसी तिथि से रद्द हो गया है
2. सी एम०/एल-2496 28-12-1970	मलानी आयरन मेटल वर्क्स, 13-6 मील, दिल्ली मेरठ रोड, गाजियाबाद	डब्लयूसी और मूत्रालयों के लिये फ्लश की टंकियां–IS:774-1964	एस० ओ० 2014 दिनांक 22-5-1971	31-12-1972 के बाद रद्द
3. सी० एम०/एल-2613 29-3-1971	स्टैण्डर्ड फर्नीचर कं०, (सुवर्शन ट्रेडिंग कं० की इकाई) कालीकट (केरल)	चाय की पेटियों के लिये प्लाइवुड की पट्टियां–IS:10-1970	एस० ओ० 2405 दिनांक 29-6-1971	3-3-1972 के बाद रद्द
4. सी० एम०/एल-2846 18-12-1971	केम्फा इंडस्ट्रीज, 61–इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कालोनी, महरौली रोड, गुड़गांव (हरयाणा)	रबड़ उद्योग के लिये जस्ता आक्साइड–IS:3399-1965	एस० ओ० 2769 दिनांक 7-10-1972	31-12-1972 के बाद रद्द
5. सी० एम०/एल-2868 14-1-1972	न्यू सेंट्रल जूट मिल्स क० लि०, ऐल्बियन मिल्स) बज बज, 24 परगना (प० बंगाल)	कालीन के पीछे लगाने का पटसन कपड़ा IS:4900-1969	एस० ओ० 2777 दिनांक 7-10-1972	15-1-1973 के बाद रद्द

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सी० एम०/एल-47	20-1-1958	हूंसर प्लाइवुड वर्क्स, डाकघर हूंसर (मैसूर राज्य)	चाय की पेटियों के लिये प्लाइवुड के तख्ते-IS:10-1970	एस० ओ० 13 दिनांक 15-2-1958	31-1-1973 के बाद स्थगित
7. सी० एम०/एल०-80	24-4-1958	दास एण्ड कम्पनी, 32-चौलपट्टी रोड, कलकत्ता-10	चाय की पेटियों के लिए प्लाइवुड के तख्ते-IS:10-1970	एस० ओ० 758 दिनांक 10-5-1958	31-1-1973 के बाद स्थगित
8. सी० एम०/एल-365	12-12-1961	डिट्ज इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०, 29 मल्कागंज, सब्जीमंडी दिल्ली-7	घरेलू उपयोग के लिये बिजली के इमर्सन हीटर (4000 वाट समाई वाले)-IS:368-1963	एस० ओ० 199 दिनांक 20-1-1962	31-12-1972 के बाद स्थगित
9. सी० एम०/एल-406	25-4-1962	दि गंगा प्लाइवुड कं०, प्रा०लि०, 35-सेण्ट मिशन रोड, कलकत्ता-23	चाय की पेटियों के लिये प्लाइवुड के तख्ते IS:10-1970	एस० ओ० 1509 दिनांक 19-5-1962	31-1-1973 के बाद स्थगित
10. सी० एम०/एल-424	30-6-1962	अनाम इलैक्ट्रिकल मैन्यू० कं० कादियाम, पूर्व गोदावरी जिला, (आन्ध्रप्रदेश)	शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिये सख्त खिंचे लड़दार एल्युमिनियम और इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चालक, IS:398-1961	एस० ओ० 2146 दिनांक 14-7-1962	31-12-1972 के बाद स्थगित
11. सी० एम०/एल-477	29-11-1962	शालीमार टार प्राडक्टस् (1935) लि०, पी-46, हाइड रोड, एक्सटेंशन, खिदिरपुर, कलकत्ता-27	जलरोक कार्यों के लिए बिटूमेन (नम्य)-IS : 1580-1969	..	31-12-1972 के बाद स्थगित
12. सी०एम०/एल-470	29-11-1962	,, ,,	कंक्रीट में प्रसार जोड़ों के लिए पूर्वनिर्मित फिलेट, लचकीले प्रकार के और दबकर बाहर न निकलने वाले बिटयूमेनी सीसे फाइबर- IS : 1838-1961	..	31-12-1972 के बाद स्थगित
13. सी०एम०/एल-487	26-12-1962	सूलेखा वर्क्स लि०, सूलेखा पार्क, जादवपुर कलकत्ता-32	ड्राइंग के लिए जलसह काली स्याही-IS: 789-1955	एस०ओ०241 दिनांक 26-1-1963	15-1-1973 के बाद स्थगित
14. सी० एम०/एल-979	21-12-1964	पेरियार मेटल प्राडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इस्टेट, इट्टीमनूर, कोट्टायाम (केरल)	बर्तनों के लिए एल्युमिनियम ग्रेड एस आई सी- IS: 21-1959	एस०ओ०274 दिनांक 23-1-1965	31-12-1972 के बाद स्थगित
15. सी० एम०/एल-1323	31-8-1966	शालीमार टार प्राडक्टस (1935) लि०, लोदना, (बिहार)	गर्म लगाने वाले सील बंद करने के लिए मसाले-IS : 1834-1961	एस०ओ० 2925 दिनांक 1-10-1966	31-12-1972 के बाद स्थगित
16. सी० एम०/एल-1444	16-5-1967	पेस्टीसाइड्स इंडिया, उदयसागर रोड, उदयपुर	मिथाक्सी इथाइल पारा क्लोराइड के तेज चूर्ण से बने यौगिक - IS: 2358-1963	एस०ओ०2080 दिनांक 24-6-1967	15-12-1972 के बाद स्थगित
17. सी० एम०/एल-1624	16-1-1968	एम एन चटर्जी एण्ड कम्पनी, पी०-48 बनारस रोड, हावड़ा-5	बी०-खांच वाली गिरियां-बी 200, IS : 3142-1965	एस०ओ०684 दिनांक 24-2-1968	15-1-1973 के बाद स्थगित
18. सी० एम०/एल-1860	12-12-1968	कार्बन केमिकल्स कम्पनी, (यूनियन कार्बाइड आफ इंडिया लि०, का प्रभाग) अनिक चैम्बर, बम्बई-74 (एस)	ठंडे पानी की सप्लाई के लिए अल्प घनत्व वाले पोलीइथाइलीन पाइप-IS : 3076-1968	एस०ओ०370 दिनांक 25-1-1969	31-12-1972 के बाद स्थगित

(1) (2)	(3) (4)	(5)		(6)
19. सी एम/एल-2211 13-1-1970	वेस्ट बंगाल आयरन एण्ड स्टील मैन्यु वर्क्स, 27 इंडन अस्पताल रोड, कलकत्ता-12	चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग-IS : 10-1970	एस ओ 771 दिनांक 28-2-1970	15-1-1973 के बाद स्थगित
20. सी एम/एल-2357 1-7-1970	नेशनल पेस्टीसाइड्स, 5-इंडस्ट्रियल इस्टेट, विदिशा (म०प्र०)	एल्ड्रिन पायसनीय तेज प्रभाव IS : 1310-1958	एस ओ 2109 दिनांक 29-5-1971	31-12-1972 के बाद स्थगित
21. सी एम/एल-2396 31-8-1970	एक्सेल इंडस्ट्रीज लि०, 184/87 स्वामी विवेकानंद रोड, जोगेश्वरी, बम्बई-60	मालाथियान, तकनीकी, IS : 1832-1961	एस ओ 57 दिनांक 2-1-1971	15-12-1972 के बाद स्थगित
22. सी एम/एल-2858 31-12-1971	न्यू कंमी मिनरल मिल्स प्रा० लि०, क्रास रोड, सं० 1 कांडीवली (पूर्व) बम्बई-67	मालाथियान धूलन पाउडर-IS : 2568-1963	एस ओ 2769 दिनांक 7-10-1972	31-12-1972 के बाद स्थगित
23. सी एम/एल-2859 31-12-1971	उदयपुर डिस्टिलरी कं० प्रा लि० उदयसागर रोड उदयपुर (राजस्थान)	हिवस्कियां-IS : 4449-1967	एस ओ 2769 दिनांक 7-10-1972	31-12-1972 के बाद स्थगित
24. सी एम/एल-2863 5-1-1972	जयश्री टेक्सटाइल एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, रिषरा, जिला हुगली	आग बुझाने के लिए बिना अस्तर लगे सन कैनवस के होज-63 मिमी और 70 मिमी-IS : 4927 1968	एस ओ 2777 दिनांक 7-10-1972	15-1-1973 के बाद स्थगित

[सं० सी एम डी/13 : 14]

ए० वी० राव, निदेशक (सेंट्रल मार्क्स)

S.O. 888.—Certification Marks Licences, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have lapsed or their renewals deferred :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and date of Issue	Name and Address of the Licensee	Article/Process and the Relevant IS : Designation	S.O.Number and Date of the Gazette Notifying Grant of Licence	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CM/L-1297 13-7-1966	Agarwal Hardware Works, P. Limited, 2 Ishwar Chatterji Rd., Sodepur (24 Parganas)	Hot rolled steel strips—IS : 1029-1956	S.O. 2600 dated 27-8-1966	Renewal was deferred after 31-7-1968; the licence now stands lapsed after that date.
2.	CM/L-2496 28-12-1970	Jhalani Iron Metal Works, 13-6, Mile Delhi Meerut Road, Ghaziabad	Flushing cisterns for water closets and urinals—IS : 774-1964	S.O. 2014 dated 22-5-1971	Lapsed after 31-12-1972
3.	CM/L-2613 29-3-1971	Standard Furniture Company, (Unit of Sudersan Trading Company, Calicut (Kerala)	Tea-chest plywood battens—IS : 10-1970	S.O.2405 dated 29-6-71	Lapsed after 31-3.1972
4.	CM/L-2846 18-12-1972	Chempha Industries, 61, Industrial Development Colony, Mehrauli Road, Gurgaon (Haryana)	Zince oxide for rubber industries—IS : 3399-1965	S.O. 2769 dated 7-10-1972	Lapsed after 31-12-1972
5.	CM/L-2868 14-1-1972	New Central Jute Mills Co. Limited, (Albion Mills) Budge Budge 24 Parganas (W. Bengal)	Jute carpet backing fabric—IS : 4900-1969	S.O. 2777 dated 7-10-1972	Lapsed after 15-1-1973
6.	CM/L-47 20-1-1958	Hunsur Plywood Works, P. O. Hunsur (Mysore) State)	Tea-chest plywood panels—IS : 10-1970	S.O.13 dated 15-2-1958	Deferred after 31-1-1973
7.	CM/L-80 24-4-1958	Das & Company, 32, Chualpatty Road, Calcutta-10.	Tea-chest plywood panels—IS : 10-1970	S.O.758 dated 10-5-1958	Deferred after 31-1-1973

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	CM/L-365 12-12-1961	Ditz Electricals (India) Ltd., 29 Malka Ganj, Sabzimandi, Delhi-7	Electric immersion water heaters for domestic use (up to 4000 Watts capacity)— IS : 368-1963	S.O. 199 dated 20-1-62	Deferred after 31-12-72
9.	CM/L-406 25-4-1962	The Ganges Plywood Mfg. Co. Private Limited, 35, Dent Mision Road, Calcutta-23	Tea-chest plywood panels— IS : 10-1970	S.O. 1509 dated 19-5-62	Deferred after 31-1-73
10.	CM/L-424 30-6-1962	Anam Electrical Mfg. Co., Kadiam, East Godawari Distt (A.P.)	Hard-drawn stranded aluminium and steel-cored aluminium conductors for overhead powers transmission purposes— IS : 398-1961	S.O.2146 dated 14-7-62	Deferrred after 31-12-72
11.	CM/L-477 29-11-1962	Shalimar Tar Products (1935) Limited, P-46, Hide Road Extension, Kidderpore, Calcutta-27	Bitumen (Plastic) for waterproofing purposes— IS : 1580-1969	—	Deferred after 31-12-72
12.	CM/L-479 29-11-1962	-do-	Preformed fillers for expansion joint in concrete, non-extruding and resilient type (Bitumen—Impregnated Fibre)— IS:1838-1961	—	Deferred after 31-12-72
13.	CM/L-487 26-12-1962	Sulekha Works Ltd., Sulekha Park, Jadavpur, Calcutta-32	Ink, drawing, waterproof, black— IS : 789-1955	S. O. 241 dated 26-1-63	Deferred after 15-1-73
14.	CM/L-979 21-12-1964	Periyar Metal Products, Industrial Estate, Ettumanoor, Kottayam (Kerala)	Wrought aluminium utensils, Grade SIC— IS : 21-1959	S.O.274 dated 23-1-1965	Deferred after 31-12-72
15.	CM/L-1323 31-8-1966	Shalimar Tar Products (1935) Ltd., Lodna (Bihar)	Hot applied sealing compounds— IS : 1834-1961	S.O. 2925 dated 1-10-1966	Deferred after 31-12-72
16.	CM/L-1444 16-5-1967	Pesticides India, Udaisagar Road, Udaipur	Formulations based on stabilized methoxy ethyl mercury chloride concentrate— IS : 2358-1963	S.O. 2080 dated 24-6-67	Deferred after 15-12-72
17.	CM/L-1624 16-1-1968	M. N. Chatterjee & Company, P-48 Banaras Road, Howrah-5	V-Grooved pulleys, B 200— IS : 3142-1965	S.O.684 dated 24-2-68	Deferred after 15-1-73
18.	CM/L-1860 12-12-1968	Carbon Chemicals Company, Division of Union Carbide of India Limited, Anik Chembur, Bombay-74 (AS)	Low density polyethylene pipes for cold water services— IS : 3076-1968	S.O. 370 dated 25-1-69	Deferred after 31-12-72
19.	CM/L-2211 13-1-1970	West Bengal Iron & Steel Mfg. Works, 27, Eden Hospital Road, Calcutta-12	Tea-chest metal fittings —IS : 10-1970	S.O.771 dated 28-2-70	Deferred after 15-1-73
20.	CM/L-2357 1-7-1970	National Pesticides, 5, Industrial Estate, Vidisha (M.P.)	Endrin emulsifiable concentrates— IS : 1310-1958	S.O. 2109 dated 29-5-71	Deferred after 31-12-72
21.	CM/L-2396 31-8-1970	Excel Industries Ltd., 184-87, Swami Vivekanand Road, Jogeshwari, Bombay-60	Malathion, technical— IS : 1832-1961	S.O. 57 dated 2-1-71	Deferred after 15-12-72
22.	CM/L-2858 31-12-1971	New Chemi Mineral Mills Pvt. Ltd., Cross Road, No.1, Kandivli (East) Bombay-67	Malathion dusting powders— IS : 2568-1963	S.O. 2769 dated 7-10-72	Deferred after 31-12-72
23.	CM/L-2859 31-12-1971	Udaipur Distillery Co. Pvt. Ltd., Udaisagar Road, Udaipur (Rajasthan)	Whiskies— IS : 4449-1967	S.O. 2769 dated 7-10-72	Deferred after 31-12-72
24.	CM/L-2863 5-1-1972	Jaya Shree Textiles & Industries Ltd, Rishra, Distt. Hooghly	Unlined Flax Canvas hose for fire fighting, 63 mm. and 70mm. — IS : 4927-1968	S.O.2777 dated 7-10-72	Deferred after 15-1-73

[No. CMD/13 : 14]

A. B. Rao, Director (Central Marks)

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1973

का. आ. 889.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय के 14 अगस्त, 1962 की अधिसूचना सं. 16/8/61-चि.-1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए डाक्टर ऑफ मेडिसिन, हम्बर्ग, जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ।

यतः धार्मिक कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल 310 अब्दुल साहिब-अल-दिवानें राम कृष्ण मिशन सेवाश्रम, कन्खल, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के साथ सम्बद्ध हैं ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(1) 3 अक्तूबर, 1972 से दो वर्ष की अवधि

अथवा

(2) उस अवधि की जब तक डा. अब्दुल साहिब अल-दिवानें कृष्ण मिशन सेवाश्रम, कन्खल, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा. मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे ।

[फ. सं. बी. 11016/35/72-एम. पी. टी.]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING
(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1973

S.O. 889.—WHEREAS by a notification of the Govt. of India in the late Ministry of Health No. 16-8/61 MI, dated the 14th August, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualification, "Doctor of Medicine" granted by the University of Hamburg, Germany shall be recognised Medical qualification for the purposes of the India, Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

AND WHEREAS, Dr. Abdul Sahib Al-Diwamy who possesses the said qualification is for the time being attached to the Ramakrishna Mission, Sevashrama, Kankhal, Hardwar, Uttar Pradesh for the purposes of charitable work;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a period of two years with effect from the 3rd October, 1972, or

(ii) the period during which Dr. Abdul Sahib Al-Diwamy is attached to the said Ramakrishna Mission Sevashrama, Kankhal, Hardwar, Uttar Pradesh, whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V-11016/35/72-MPT]

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

का. आ. 890.—यतः दन्त चिकित्सा 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (क) के अधीन डा. जगदीश चन्द्र मनचन्दा, एल. डी. एस., आर. सी. एस, सी-2/9 वसन्त विहार कालोनी नई दिल्ली-22 को 21 दिसम्बर, 1972 से दन्त चिकित्सों के पंजाब रजिस्टर के भाग 'क' में पंजीकृत चिकित्सकों में से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है ।

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (घ) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डा. सुशान्त कुमार सरकार, एम. बी., डी. सी. पी., पी. एच. डी., एम. आर. सी. पी., पी-34, बांगुर एवेन्यू, ब्लाक 'क' कलकत्ता-55 को 26 अगस्त, 1972 से उक्त परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय, 17 अक्तूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या 3-2/62-चि.-11 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में (1) "धारा 3 के खण्ड (क) के निर्वाचित शीर्ष के अधीन क्रम सं. 8 में उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय :

डा. जगदीश चन्द्र मनचन्दा, एल. डी. एस., आर. सी. एस., सी. 2/9, वसन्त विहार कालोनी, नई दिल्ली-22."

(11) धारा 3 के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित शीर्ष अन्तर्गत क्रम संख्या 3 में उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय :—

"डा. सुशान्त कुमार सरकार, एम.बी.डी.सी.पी., पी.एच.डी., एम. आर.सी.पी., पी-34, बांगुर एवेन्यू, 'ए', कलकत्ता-55."

[संख्या. बी. 12013/1/72-एम. पी. टी.]

के. सत्यनारायण, उप सचिव

New Delhi, the 12th March, 1973

S.O. 890.—Whereas Dr. Jagdish Chander Manchanda, LDS RCS, C-2/9, Vasant Vihar Colony, New Delhi-22, has been elected with effect from the 21st December, 1972 from among the dentists registered in Part A of the Punjab register of dentists, as a member of the Dental Council of India under clause (a) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948);

And whereas in pursuance of the provisions of clause (d) of section 3 of the said Act, Dr. Sushanta Kumar Sarkar, MB., DCP., Ph.D., MRCP., P-34, Bangur Avenue, Block A, Calcutta-55, has been elected by the Calcutta University to be a member of the said Council with effect from the 26th August, 1972;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 3-2/62-MII, dated the 17th October, 1962, namely:—

In the said notification,

(i) under the heading "Elected under clause (a) of section 3", for the entry against serial No. 8, the following entry shall be inserted, namely:—

"Dr. Jagdish Chander Manchanda, LDS RCS, C-2/9, Vasant Vihar Colony, New Delhi-22".

(ii) under the heading "Elected under clause (d) of section 3" for the entry against serial No. 3, the following entry shall be inserted, namely:—

"Dr. Sushanta Kumar Sarkar, MB., DCP., Ph.D., MRCP., P-34, Bangur Avenue, Block A, Calcutta-55".

[No. V. 12013/1/72-MPT]

K. SATYANARAYANA, Dy. Secy.

पर्यटन और सागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

का. आ. 891.—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एयर-इंडिया के प्रबंधनिदेशक, श्री के. के. उन्नी को 14-2-1973 से तथा अगले आदेशों तक इंडियन एयरलाइन्स के बोर्ड के एक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एवी. 18013/3/71-ए सी]

टी. आरूमुगम्, उप-सचिव

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 12th March, 1973

S.O. 891.—In exercise of the powers conferred by the Section 4 of the Air Corporation Act, 1953 (27 of 1953), the Central Government hereby appoints Shri K. K. Unni, Managing Director, Air-India, as a Director on the Board of Indian Airlines with effect from 14-2-1973 and until further orders

[No. AV. 18013/3/71-AC]

T. ARUMUGHAM, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1973

का. आ. 892.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने लखीमपुर खेरी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-4-73 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-2/73-पीएचबी (19)]

ए. एस. वोहरा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 24th March, 1973

S.O. 892.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627, dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-4-1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in LAKHIMPUR KHERI Telephone Exchange, U.P. Circle.

[No. 5-2/73-PHB(19)]

A. S. VOHRA, Asstt. Director General (PHB).

निर्माण और आवास मंत्रालय

(संपदा-निदेशालय)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1973

का. आ. 893.—लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सहायक आवास अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) की अधिसूचना सं. का. आ. 846, तारीख 24 फरवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 1 में, विद्यमान प्रविष्टि को सं. 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और सं. 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"2 सहायक आवास अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकारी"

[सं. 21012(3)/73-नीति 3]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 13th March, 1973

S.O. 893.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Asstant Housing Officer, Delhi Development Authority, to be estate officer for the purposes of the said Act, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing (Directorate of Estates) No. S.O. 846, dated the 24th February 1972, namely:—

In the said notification, in the Table, in column 1, the existing entry shall be numbered as number 1 and after number 1 the following entry shall be inserted, namely:—

"2. Assistant Housing Officer, Delhi Development Authority."

[No. 21012(3)/73-Pol. III]

का० आ० 894.—लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के बारे में अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर अधिनियम द्वारा या के अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पद नाम	लोक परिसरों के प्रवर्ग और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
श्री शिवनन्दन सहाय, सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन लिमिटेड ।	औद्योगिक संपदा, नयनी, डाकघर उद्योग नगर, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) की वह भूमि और इमारतें जो कारपोरेशन के स्वामित्व में हैं, उसके द्वारा अर्जित की गई या भाड़े पर ली गई हैं ।

[फा० सं० 21012(10)/72-नीति 3]

S.O. 894.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of Gazetted officer of the Government to be estate officer for the purpose of the said Act and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers, by or under the said Act within the limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of the public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Shri Sheo Nandan Sahai, Assistant Manager, The National Small Industries Corporation Limited.	Land and buildings of the Industrial Estate, Naini, Post Office Udyog Nagar Allahabad (U.P.) owned, acquired or hired by the Corporation.

[F. No. 21012(10)/72-Pol. III]

का० आ० 895.—लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारियों को, सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के बारे में अपने अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का पद नाम	लोक परिसरों के प्रवर्ग और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
1. अभ्रक खान कल्याण आयुक्त, नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)	आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थित अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर ।
2. अभ्रक खान कल्याण आयुक्त धनबाद (बिहार)	बिहार राज्य में स्थित अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर ।
3. अभ्रक खान कल्याण आयुक्त भिलवाड़ा (राजस्थान)	राजस्थान राज्य में स्थित अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर ।

[फा० सं० 21012(18)/72-नीति III]

आर० बी० सक्सेना, उप संपदा निदेशक और पदेन अवर सचिव

S.O. 895.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officers of Government to be estate officers for the purposes of the said Act, and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by our under the said Act, within the limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer.	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
1. Mica Mines Welfare Commissioner, Nellore (Andhra Pradesh)	Premises under the administrative control of the Mica Mines Labour Welfare Organisation, situated in the state of Andhra Pradesh.
2. Mica Mines Welfare Commissioner, Dhanbad (Bihar)	Premises under the administrative control of the Mica Mines Labour Welfare Organisation, situated in the state of Bihar.
3. Mica Mines Welfare Commissioner, Bhilwara (Rajasthan).	Premises under the administrative control of the Mica Mines Labour Welfare Organisation, situated in the state of Rajasthan.

[F. No. 21012(18)/72-Pol. III]

R. B. SAXENA, Deputy Director of Estates and ex-officio Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

का. आ. 896.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना में फिल्म सम्पादन के प्रोफेसर श्री आर. के रामचन्द्रन को 1 मार्च, 1973 (पूर्वान्ह) से अगले आदेश तक, श्री जी. वेंकटारमन के स्थान पर प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड, मद्रास नियुक्त किया है।

2. श्री जी. वेंकटारमन ने 1 मार्च, 1973 (पूर्वान्ह) को प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड, मद्रास के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

राष्ट्रपति के नाम में तथा उनके आदेशानुसार

[फा. सं. 2/11/73-एफ. सी.]

हरजीत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 12th March, 1973

S.O. 896.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952, the Central Government has been pleased to appoint Shri R. K. Ramachandran, Prof. of Film Editing, Film and TV Institute of India, Poona, as Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras vice Shri G. Venkataraman with effect from 1st March, 1973 (forenoon) until further orders.

2. Shri G. Venkataraman relinquished charge of the post of Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras with effect from 1st March, 1973 (forenoon).

By order and in the name of the President.

[No. 2/11/73-FC]

HARJIT SINGH,
Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1973.

का. आ. 897.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय सेंट्रल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी. पी. आर. साहनी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या भारतीय सेन्ट्रल बैंक के प्रबन्धतंत्र की, निजाम रोड शाखा, लुधियाना के लिपिक श्री के. एल. सहगल को 3 फरवरी, 1972 से 11 अगस्त, 1972 तक टेल्लर (गणक) के रूप में स्थानापन्न के रूप में कार्य न करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं. एल. 12012/86/72-एल आर 3]

करनैल सिंह, अवर सचिव।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 12th February, 1973

S.O. 897.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri P. P. R. Sawhney shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Bank of India in not allowing Shri K. L. Sehgal, Clerk of Nizam Road Branch, Ludhiana, to officiate as Teller with effect from the 3rd February, 1972 to 11th August, 1972 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

[No. L. 12012/86/72/LRIII]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 9 March, 1973

S.O. 898.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Chandigarh in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Shri Mohinder Singh, Chargeman special Token No. I-N which was received by the Central Government on 28th February, 1973.

BEFORE SHRI P. P. R. SAWHNY, B. A. (Hons.) CANTAB BAR-AT-LAW, PRESIDING OFFICER, CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Complaint No. 2/17 of 1972

Under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947, Shri Mohinder Singh, Chargeman Special, Token No. I-N, Excavation Division, Pandoh ..... **Complainant.**

Vs.

(1) Chief Engineer, B. S. L. Project, Sundernagar, Distt. Mandi (H. P.).

(2) *Superintending Engineer,* B.S.L. *Construction Circle* No. J, Sundernagar, Distt. Mandi (H. P.).

Respondents.

Appearances :
Shri Mohinder Singh, complainant—in person,
Shri Rattan Lal—for the respondents.

AWARD

Shri Mohinder Singh, Chargeman special, President of the B. S. L. Workers Union, Sundernagar, body which is registered and recognised and who is a protected workman, has filed this complaint under section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947.

According to Shri Mohinder Singh, Reference No. 2/C of 1971 was pending before this Tribunal on 4-3-71, in which he along with other co-workers was an interested party and that without taking prior permission from this Tribunal, he had been dismissed from service on 10-3-71 by the Superintending Engineer, respondent No. 2.

that in view of contravention of provisions of section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 he filed a complaint under section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 before the Tribunal,

that during the pendency of that complaint, No. 2/1 of 1971, a plea was taen by the respondent that as he (Shri Mohinder Singh) had filed an appeal before the Chief Engineer, B.S.L. Sundernagar, he should have awaited the decision of the appellate authority,

that thereupon this Tribunal gave an award that the complaint was not competent at that stage, an award that the complaint was not competent at that stage, and that the Chief Engineer should take appropriate steps to dispose of the appeal at the earliest, and that there would be no bar to his (Shri Mohinder Singh) filing fresh complaint in case the appeal was decided against him,

that on the publication of the award, he reminded the Chief Engineer for hearing of the appeal who did not give his decision, though according to circular issued by the Chief Engineer, B. S. L. a notice for hearing appeal ought to have been issued within one month of the receipt of the appeal and after hearing of the argument, decision ought to have been conveyed within 15 days,

that he (Shri Mohinder Singh) again sent reminders on 14-3-72 and 28-3-72, but no decision was conveyed to him and that he was put to great deal of hardship without a job for the reason that his appeal had not been disposed of for more than a year.

2. In the reply that was filed to the complaint by the respondents, it has been *inter alia* stated that they were not aware whether Shri Mohinder Singh could be treated as a protected workman under the Industrial Disputes Act, 1947 and they denied that dismissal orders were served upon Shri Mohinder Singh during the pendency of an Industrial dispute, and added that as such there was no necessity for securing and prior permission from this Tribunal,

that since the complainant had filed a appeal, which was pending before the Chief Engineer, B. S. L. Sundernagar and he had not exhausted the remedy available to him under the certified standing orders, he could not file a complaint before this Tribunal,

that orders after hearing arguments of the parties had been reserved by the Chief Engineer,

that effort had been made to dispose of appeal as early as possible, and that decision had been taken by the Chief Engineer, after taking into consideration the evidence on record and he had been conveyed his decision to the Tribunal vide his letter No. 12410-12/B. S. L./1143/69, dated 25-4-72, along with a prayer that permission to revert Shri Mohinder Singh from the post of Chargeman Special to Euclid operator be given, and the complaint having in that way had become infructuous.

3. The complainant, in his rejoinder, has more or less reiterated the position taken by him in his complaint, and generally controverted the pleas that have been raised by the respondents in their reply to the complaint, and added that the punishing authority being prejudiced declared him guilty of all the charges mentioned in his letter No. 819-21 34-M, dated 5-9-68 without initiating any enquiry and providing opportunity to explain his position, which exhibited prejudice on his part, that the enquiry that had been held was by way of covering his *mala fide* intentions and that the enquiry had been entrusted to a convenient person and was not fair and just and consistent with principles of natural justice.

4. The following issues were framed:—

(i) Whether the respondent Project was justified in terminating the services of Shri Mohinder Singh, complainant, without securing approval of the Tribunal, during the pendency of reference No. 2/C of 1971 before this Tribunal, and whether as a result thereof there has been contravention of section 33(2) (b) of the Industrial Disputes Act, 1947?

(ii) Whether Shri Mohinder Singh is a 'protected workman' being the President of the B. S. L. Workers Union, and whether on that score the respondent was debarred from taking the impuged action?

(iii) Whether the complaint is pre-mature for the resons as stated by the respondent Project that appeal filed by Shri Mohinder Singh was pending at the time when he filed the complaint and whether the instant complaint had become infructuous for the reason given by the respondent management in their reply to the complaint that the appeal has since been disposed of, and Shri Mohinder Singh's order of termination of services had been sent aside he had been reduced from Chargeman Special to Euclid Operator?

Thereafter an application was put in by the complainant on 29-6-72 requesting that since circumstances had changed, he may be allowed to amend his complaint, inasmuch as during the pendency of the complaint the appeal filed by him had been partially decided in his favour it having been held that he had been demoted from the post of Chargeman Special to the post of Euclid Operator.

After hearing the parties, he was allowed to put in an amended complaint.

An application was also received from the B.S.L. Project, Sundernagar under section 33(2) (b) of the Industrial Disputes Act for approval being given to the action taken against the complainant on the basis of a departmental enquiry.

5. Since the point at issue in the complaint No. 2/17 as well as in the aforesaid application of the respondent Project was the same, as desired by the parties, the proceedings were consolidated and it was ordered on 30-6-72 that the evidence that may be recorded in the complaint of Shri Mohinder Singh be also read as evidence in the application of the B.S.L. Project, Sundernagar.

6. After the parties had put in reply to the complaint/application for approval as also rejoinders, the following issues were framed, and the parties were provided with opportunity to produce their evidence:—

ISSUES

"1. Whether the punishing authority was justified in holding that Shri Mohinder Singh, complainant was guilty of the charge levelled against him and

awarding punishment of dismissal from service during the pendency of Reference No. 2/c of 1971, without obtaining prior permission from the Industrial Tribunal, Central?

2. Whether respondent Chief Engineer was justified in reducing rank of Shri Mohinder Singh, complainant in appeal filed by him against the orders of dismissal passed by the punishing authority during the pendency of reference No. 2/C of 1971 without taking prior approval of the Industrial Tribunal, Central?

3. Whether approval be given to the action taken by the Chief Engineer, B.S.L. Project in reducing Shri Mohinder Singh in rank in an appeal having been filed by him before the applicant Chief Engineer, against the orders of dismissal passed by the punishing authority?

7. The B.S.L. Project have examined only one witness, Shri Rattan Lal, their Personnel Officer and authorised representative and the complainant has examined himself and Shri Narinder Pal Sharma, General Secretary of the B.S.L. Workers Union as witnesses.

8. According to Shri Rattan Lal, Shri Ujagar Singh, Executive Engineer had been appointed as enquiry officer, who submitted his report, Ext. R/4, and on its receipt a show cause notice was served upon Shri Mohinder Singh by the Superintending Engineer vide Ext. R/5, to which Shri Mohinder Singh subimitted reply, Ext. R/6 when orders Ext. R/7 dated 6-3-71 were passed dismissing Shri Mohinder Singh from service with effect from 6-3-71, that on appeal filed by Shri Mohinder Singh, the Chief Engineer passed orders, Ext. R/9, setting aside the orders of dismissal of Shri Mohinder Singh and on the basis of the decision taken in appeal by the Chief Engineer, application Ext. R/10 had been filed under section 33(2) of the Industrial Disputes Act, 1947, for permission being given to inflict punishment of reduction in rank upon Shri Mohinder Singh.

Shri Narinder Pal Sharma has stated that Shri Mohinder Singh was President of the Union since 1964, and in 1968 the respondent tried to victimise all the trade union leaders, including Shri Mohinder Singh by mass transfers when Shri Mohinder Singh went on hunger strike in 1969 for 16 days in order to have the demands of the workmen met by the respondent Project and it was at his instance that the workmen also went on strike for two days,

that in 1970 again the workmen went on strike on the asking of Shri Mohinder Singh,

that he as the General Secretary of the B.S.L. Workers Union served a demand notice on the respondent Project on behalf of Shri Mohinder Singh, who had been dismissed,

that a writ petition was filed with the Punjab and Haryana High Court, which was accepted but the respondent Project did not pay wages to him that were due to him for a long time, and transferred him from Pandob Excavation Division to Ghamrolla while under suspension it being the solitary case when an employee while under suspension had been transferred, and that this had been done when Shri Mohinder Singh was the President of the union.

Shri Mohinder Singh has stated that he had joined the respondent Project on 23-10-62, and was working as shift Incharge in November, 1965 when the respondent ordered his dismissal from services as he had declined to work as an operator a lower post than that of Shift Incharge and his service conditions had been changed without serving a notice as required under section 29 of the Industrial Disputes Act, 1947, and that Sarvshri Sohan Singh and Kanshi Ram, who had been appointed after him had allowed to continue in service, thereby discriminating against him because he was the President of the Union and been espousing the cause of the workmen which was not relisted by the respondent Project authorities.

According to him he had challenged this order of dismissal by way of filing a writ petition in the Punjab and Haryana High Court, which was accepted with costs vide judgement Ext. C/1, and the respondent Project thereafter filed a Latters Patent Appeal which was also dismissed and that he was ordered to be reinstated as Chargeman Special vide Ext. C/2 and posted at Pandoh though earlier to his dismissal he was working at Sundernagar, and that he had put in representation Ext. C/3 since on reinstatement he was not appointed Shift Incharge, but as Euclid operator vide orders Ext. C/4 and he subsequently protested vide C/5 and all this had been done in order to victimise him inasmuch as the respondent Project authorities had also with-held his dues amounting to Rs. 9000/- as arrears for the period he had been kept out of employment by the respondents. necessitating his filing an application before the Labour Court, Jullundur and that ultimately the amongst involved was paid to him on 10-6-71.

He has also stated that on 13-5-69 he was assaulted by the S.D.O., Excavation Division, and he made a complaint to the Superintending Engineer but instead of taking action against the S.D.O. he (Shri Mohinder Singh) was placed under suspension and ordered to be transferred from Pandoh to Ghamrolla, which was about 65 miles from Pandoh contrary to the provisions of Model Standing orders that were applicable to the employees of the Project, according to which no workman can be transferred while under suspension, and that no other employee had been transferred under such circumstances,

that he submitted an application to the Executive Engineer, Excavation Division, Pandoh which was rejected vide C/6,

that since he did not report for duty at Ghamrolla the respondent Project authorities did not pay to him subsistance allowance, and he served the demand notice, Ext. C/7 on the respondent Project, and that the respondents subsequently finding that the orders of transferring him from Pandoh to Gamrolla were not in order, withdrew the same vide Ext. C/8, and he was also allowed payment of the entire amount due for the suspension period vide order Ext. C/9.

He has further stated that the charges on the basis of which he had been dismissed from service were taken to have been proved by the Superintending Engineer without applying his mind and without securing any reply from him,

that he had been served with R/3 and he filed a complaint under section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 which was disposed of by this Tribunal on 18th December, 1971 holding that it was pre-mature while giving directions to the Chief Engineer to hear early the appeal and that it would be open to him (Shri Mohinder Singh) to file a fresh complaint if need be in order to have is grievances redressed.

He has also stated that he had given application Ext. C/10 to the enquiry officer pointing out irregularities requiring his attention, and also Engineer as well as application Ext. C/11 in tis bealf to the Superintending Engineer as well as application Ext. C/13, requesting him to give details of the damage caused to the euclid but that this information was not imparted to him.

According to him the Superintanding Engineer ordered his dismissal from service after te enquiry had been concluded when he filed appeal C/1 and subsequently put in another application Ext. C/15 and that since his appeal was not being disposed of, he had submitted application, Ext. C/16 to the Chief Engineer, and that as is evident from the minutes of the meeting, Ext. A/17, held on 10-9-69 it had been decided that the appeals should be decided within a month and decision communicated within 15 days thereafter,

that after the decision in appeal had been made known to him he filed the instant complaint as orders had been passed against him by the Superintending Engineer with a view only to victimise him, and that his dismissal during the pendency of Reference No. 2/C of 1971 without securing prior permission from this tribunal was not proper or in order, inasmuch as the *tatus quo* was not allowed to be maintained by passing orders in the appeal and he had not been allowed payment of wages for the period he remained out of service and was subsequently ordered to be reinstated.

He has also maintained that the enquiry conducted against him was not held consistent since principles of natural justice—he having not been allowed to put relevant and important questions in cross-examination to the witnesses that were produced by the respondent management and also not having been allowed to address arguments though the Enquiry Officer had premised to afford this facility inasmuch as the Enquiry Officer did not give him any intimation of the last date fixed *i.e.* 25-2-69, when the enquiry officer closed the enquiry without allowing him to address arguments.

He has also maintained tat the Chief Engineer was not competent to promote any one from the post of operator to Chargeman Special and it was the General Manager who could do so.

He has denied that he had any connection with the accident to euclid which had fallen into the Beas river but has admitted that he was sitting on the adjoining seat along with the driver (that had been provided there) as directed by the Shift Incharge, and conveyed to him by the Euclid operator who wanted him to bring another Euclid from the workshop. He has denied that he had pushed the driver from his seat or that he contributed to the euclid falling into the river, and has added that Shri Kishan Singh, Foreman had shouted that they should jump out of the Euclid and he (Shri Mohinder Singh) had also coutioned the driver about the Euclid falling into the river.

It has been urged by the complainant that the word "quilty" finds mention in the charge sheet which shows a baised mind of pre-judging the issue and apart from this the dismissal order shows baised mind inasmuch as it has been stated therein that even if Shri Mohinder Singh was allowed to argue personally, no difference would have been made to the case.

It has also been maintained by him that no opportunity had been given to him to submit reply to the charge-sheet before enquiry officer was appointed and that R/2 was not sent in reply to the charge-sheet, and that all this goes to show that the respondent authorities had already made up their mind and the holding of enquiry and appointment of an enquiry officer was a mere farce.

In this connection it may be mentioned that the charge-sheet is dated 5-9-68 and the dismissal order was passed on 6-3-71, Shri Mohinder Singh filed an appeal on 5-4-71 which was heard on 22nd January, 1972 and in that way Shri Mohinder Singh claims rightly that he has been unnecessarily kept out of service for a long time and harassed.

The complainant has relied upon 1967-II-L.L.J.-46 S.C.

Shri Mohinder Singh who is the President of the Union is a *persona non grata* with the B.S.L. Project having engineered a mass strike on a couple of occasions, and having espoused the demands of the workmen and he had also been successful in the writ petition with costs filed by him earlier on against his orders of dismissal, which would obviously not be to the liking of the B.S.L. Project authorities. He claims that he had been discriminated against as mentioned in details in his statement reproduced above had been unjustifiably transferred during the suspension period from Pandoh to Ghamrolla, which was borne out from the fact that this order was subsequently withdrawn by the respondent Project authorities and he had also not been paid wages for the period when he had been kept out of service till such time as he filed an application before the Labour Court, Jullundur.

All this goes to show that the B.S.L. authorities were far from happy with the activities of Shri Mohinder Singh as President of the union and he appears to have been harassed.

Though pendency of reference No: 2/C of 1971 has been alleged in the complaint filed by Shri Mohinder Singh when the impugned action was taken but not a word has been said about it by Shri Rattan Lal, the solitary witness of B.S.L. Project authorities.

In the reply to the complaint pendency of reference has no doubt been denied but the witness of the respondent Project, Shri Rattan Lal, who had appeared as such and made a statement, did not care to deny the pendency of the reference at the time of dismissal of Shri Mohinder Singh was ordered, against which he had filed an appeal to the Chief Engineer who had ordered setting aside of the orders of dismissal and instead ordered reduction in his rank from Chargeman Special to Euclid operator.

9. After the passing of the aforesaid order in the appeal the B.S.L. Project authorities have now sought approval of this Tribunal to the action proposed to be taken on the basis of the decision taken in appeal, but this prayer is belated as the orders placed in appeal are the ones which have been complained of in the complaint and these had been passed by the Superintending Engineer without securing prior permission of this Tribunal, whehn reference No. 2/C of 1971 was pending, in which Shri Mohinder Singh not as President of the union but as a workman was an interested party. In that way there has been contravention of the provisions of section 33-A of the Industrial Dispute Act, 1947 and the complainant is justified in claiming that *status quo* should be restored, and orders passed by the Superintending Engineer be held not sustainable.

It is also the case of the complainant, that if he were to be reduced in rank, he should have been served with a notice, which has not been done, and that even otherwise the concerned authorities had no right to reduce his rank as he had been directly appointed as Chargeman Special and he could not be made Euclid operator which category is a different category and lower in rank.

It has been urged on behalf of the respondent Project authorities that the reference should not be considered to be pending as the reference is dated 4-3-71 and since its copy was received by the respondent on 13-7-71, whereas the dismissal order was dated 6-3-71.

However for the purpose of considering pendency of the reference, it may be stated that it is the date wen the reference is made, and not the date when its copy is received by a party.

Having found that the impugned action had been taken during the pendency of reference N: 2/C of 1971 without securing prior permission, it is unecessary to go in detail into the findings of the enquiry officer.

It may all the same however be mentioned that Shri Mohinder Singh had required for an independent person to be appointed as enquiry officer, but this request was not acceded to and Shri Mohinder Singh was also not provided with the list of witnesses who were desired to be produced by the B.S.L. Project authorities, that important questions were not allowed to be put by them to the witnesses as is evident from the enquiry proceedings and his other obejections were also over ruled without and ostensible reasons which find mention in C/11, addressed to the Suprintending Engineer and the findings of enquiry officer were based on the statements of the Executive Engineer and S.D.O. Sri A. S. Sondhu, who had not witnessed the actual occurance and the enquiry officer had allowed Shri Sandhu to depose by reading from a written statement despite protest by Shri Mohinder Singh.

The enquiry officer's findings and the manner in whilch the enquiry had been held, has been assailed by the complainant on the above mentioned grounds and also for the reasons that he had imparted personal knowledge in this regard and it has also been maintained that is findings were perverse and he had not dealt with the pleas raised by him (the complainant) and had unjustifiably rejected the statements of his witnesses and had not provided him with facility to address arguments; and that the enquiry can not be said to be fair or just or held by any impartial person and was in contravention of principles of natural justice.

It is hardly necessary to deal with these points in detail but taken together they do go to show that conduct of the enquiry officer was not of a nature that could inspire confidence and he had also taken certain steps which were far from consistant wit principles of natural justice and fair play.

It may also be pointed out that the enquiry officer's proceedings have not been exhibited on the record.

This apart the conclusion that has been arrived at by the enquiry officer which formed the basis of dismissal of Shri Mohinder Singh on 6-3-71 is not legally warranted as statements of witnesses who are said to be eye witnesses have been brushed aside by enquiry officer without giving any cogent reasons.

Not only this the fault attributed to Shri Mohinder Singh is that he was sitting with a Euclid operator who was working on it there being no second seat in the Euclid and that he did not caution the Euclid driver. Even if it be conceded that Shri Mohinder Singh was sitting unauthorisedly, the fault is that of the euclid operator who should not have permitted him sitting with him and it cannot be attributed to Shri Mohinder Singh as the euclid was being driven by another person, and not Shri Mohinder Singh. Even it all this were to be conceded it was not incumbant upon Shri Mohinder Singh to have cautioned the operator though Shri Mohinder Singh claims that he had cautioned the operator and Shri Kishan Singh, Foreman, who was close by had also shouted and asked him (Shri Mohinder Singh) and the euclid operator to jump out. All this has been mentioned only to show that there was hardly any lapse or misconduct on the part of Shri Mohinder Singh, which could justify his dismissal or reduction in rank subsequently on a decision taken in the appeal filed by him.

With this background it is held that Shri Mohinder Singh is entitled to be placed in the status quo position and posted as Chargeman Special from the date he had been dismissed and to all also entitled the benefits that be open to him subsequent to the passing of orders in appeal when his rank was reduced to that of Euclid operator.

No order as costs.

P. R. R. SAWHNY, Presiding Officer.

[No. L 42012/1/73/LR III]

Dated 19-1-73.

S.O. 899.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1973.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/10 of 1971

Employees in Relation to the Central Bank of India

AND

Their Workmen

PRESENT:

Shri N. K. Vani, Presiding Officer.

Appearances :

For the Employers:—(i) Shri G. R. Sheikh, Asstt. Law Officer.
(ii) Shri S. K. Shikari, Agent, Special Duty, Nagpur.

For the Workmen:—(i) Shri A. M. Puranik, Vice President.
(ii) Shri S. P. Chaudhuri, President, Vidharbba Bank Employees Federation, Nagpur.

Industry : Banking **State :** Maharashtra

Bombay, dated the 2nd February, 1973

AWARD

By Order No. L. 12012/51/71/LRIII, dated 9-11-1971 the Central Government in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-clause (1) of Section 10 of the I.D. Act, 1947 (14 of 1947), referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule as mentioned below:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of Shri Nilam Kumar B. Vaidya, Clerk-cum-Cashier of their Tumsar Branch with effect from 9th December, 1970 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

2. The facts giving rise to this reference are as follows:—

(i) Shri Nilam Kumar B. Vaidya was appointed at Tumsar branch on 1-1-1970 as a Clerk-cum-Cashier. His services were extended from time to time. As per last appointment order dated 6-11-1970 the period was to expire on 5-1-1971, but the Bank terminated his services with effect from 9-12-1970 by giving him 15 days notice dated 25-11-1970 without showing any reason. On account of this he called upon the Bank to reinstate him in service but the Bank did not take any steps. He therefore raised an industrial dispute by making application before the Assistant Labour Commissioner (C), Nagpur. He tried to bring about conciliation between the parties but in vain. He, therefore submitted his failure of conciliation report to the Government. Thereafter the Government of India referred this dispute to this Tribunal for adjudication.

3. After the receipt of the reference notices were issued to the parties for filing their written statements.

4. In pursuance of the notice, the Central Bank of India staff Union (hereinafter referred as 'the Union') representing the employee Shri Nilam Kumar B. Vaidya filed written statement at Ex. 1/W.

5. According to the Union :—

(i) Shri Nilam Kumar B. Vaidya was appointed at Tumsar Branch on 1-1-1970 in a permanent vcancy at the time of opening the Branch, as a Clerk-cum-Cashier. Even though the post was permanent and in a clear vacancy, the Bank in order to circumvent provisions of the Bank Awards (Desai and Sastri Awards) and Bipartite settlement, issued an order of appointment for 3 months from 1-1-1970 to 3-1-1970 treating him as temporary on the pay and emoluments as per provisions of the Bipartite Settlement. Thereafter the management extended the period every time by different orders and pursued its unfair labour practice. This period of appointment extended from time to time is as mentioned below:—

Order No.	Date	Period	
1) Deptt. Staff	1-1-1970	1-1-1970 to 31-3-70	3 months
2) —	31-3-1970	1-4-1970 to 31-5-70	2 months
3) —	4-5-1970	5-5-1970	1 month
4) —	5-6-1970	5-7-70	1 month
5) —	4-7-1970	—	1 month
6) —	4-8-1970	6-8-1970 to 5-9-70	1 month
7) —	5-9-1970	6-9-1970 to 6-10-70	1 month
8) —	5-10-1970	6-10-1970 to 5-11-70	1 month
9) —	4-11-1970	6-11-1970 to 5-1-71	2 months

(ii) As per the last appointment order dated 6-11-1970 the period was to expire on 5-1-1971, but the bank illegally terminated his services with effect from 9-12-1970 by giving him 15 days notice without showing any reasons or cause for such illegal termination.

(iii) Shri Vaidya worked in the bank from 1-1-1970 to 9-12-1970 for a period of 11 months and 9 days

continuously. With a mala-fide intention the Bank showed a break in the service from 1-6-1970 to 4-6-1970 though Shri Vaidya actually attended the office and performed the duties of filing all pending letters, Circulars etc. and writing agency Ledger No. 1 during this period also. He signed the Muster-roll and marked the timings in the Gumasta Register on all days as usual.

(iv) The Tumsar branch was opened on 1-1-1970. Hence the vacancy was clear and permanent. Shri Vaidya was appointed from 1-1-1970. He was required to furnish a cash Security of Rs. 2,500, which was deposited by him in the post Bank at the time of appointment on 1-1-1970 as the post was permanent. As he was the only Clerk in the branch for a long time, he worked very hard and canvassed for deposits also. He brought a deposit of Rs. 3,00,000 after a strenuous efforts.

(v) The Bank in order to pursue the unfair labour practice employed several persons as temporary hands to fill up posts which are of a permanent nature and continued on temporary basis for unduly long periods without any justification. Shri Vaidya was also a victim of unfair labour practice.

(vi) It is prayed that :—

(a) Shri Vaidya be reinstated in Bank's service with effect from 9-12-1970.

(b) Shri Vaidya be declared as confirmed employee with effect from 1-7-1970. The Bank be directed to pay and implement all benefits provided for confirmed employees as per provisions of Bank Awards and Bipartite Settlement.

(c) Shri Vaidya be granted back wages with effect from 9-12-1970 onwards till the date of reinstatement in the Bank's services at the rate of Rs. 291.30 per month towards his monthly salary.

(d) The termination order dated 25-11-1970 be declared as illegal and in contravention of the provisions of the Bank Awards and Settlement and null and void.

(e) The Bank be directed to pay compensation for illegal termination of services, the cost and other relief.

6. The management of the Central Bank of India has filed written statement at Ex. 4/E.

7. According to the management :—

(i) Shri Nilam Kumar B. Vaidya was appointed as clerk-cum-Cashier at Tumsar Branch on 1-1-1970 at the time of opening of the branch for a temporary period of three months. Thereafter his services were extended from time to time and his services were terminated and he was re-appointed on 5-6-1970 for one month till 4-7-1970. Again his services were extended on month to month basis till 5-11-1970. His services were further extended for a period of two months from 6-11-1970. His last lease of extension of service was to have expired on 5-1-1971, but in the meanwhile, 15 days' notice of termination of service was served on him on 25-11-1970. As per the notice, his services were finally and conclusively terminated on 9-12-1970.

(ii) Shri Vaidya deposited a cash security of Rs. 2,500 with the Bank on 2-2-1970. It is not true that the vacancy in which Shri Vaidya was appointed was a permanent one.

(iii) Shri Vaidya brought a deposit of Rs. 3 lacs during his tenure of service from one party only but he could not persuade any second man to deposit any sum with the Bank. The work, conduct and behaviour of Shri Vaidya was not upto the mark. Shri Vaidya was never taken up to fill the permanent vacancy. Hence his claim for permanent job in the bank is unfounded.

(iv) It is not true that temporary appointment order given to Shri Vaidya was for the purpose of circumventing provisions of the Bank Awards and Bipartite settlement and the month to month extension of service orders given to Shri Vaidya after his first appointment were for the purpose of pursuing unfair labour practice.

(v) The allegation made against the Bank by the Union in its written statement are not correct.

8. The Union has filed rejoinder at Ex. 5/W.

9. According to the union :—

PORTS AND EXPORTS

(i) The Bank's statement that the vacancy in which Shri Vaidya was appointed was not a permanent vacancy is not true. The bank ought to have appointed him as probationer initially on 1-1-1970 and should have confirmed him immediately after completion of six month's service. As per provisions of the Sastry Award, Shri Vaidya is deemed to have been confirmed in the services of the Bank on 1-7-1970. Hence the Bank's action in issuing the orders of extension from time to time are illegal and in contravention of the provisions of Bipartite Settlement and Bank Awards. The Bank's contention that the services of Shri Vaidya were terminated on 1-6-1970 and was re-appointed on 5-6-1970 are baseless. In fact Shri Vaidya worked continuously in the bank even during this period. The Bank had malicious intentions to show breaks in the confirmed services of the employees.

(ii) The order of termination dated 9-12-1970 is illegal as Shri Vaidya was a confirmed employee on that date. The notice served by the Bank on 25-11-1970 is not in confirmity with the provisions of the Sastry and Desai Awards. It is therefore illegal.

(iii) The Bank's statement that Shri Vaidya was not promoted to the post of Head Cashier since August, 1970 is not true because he has drawn special allowance for the period from August, 1970 onwards. The most responsible duties performed by Shri Vaidya during the period of his services proves that his work, conduct and behavious were good and satisfactory. The Bank's statement that Shri Vaidya was not upto the mark is baseless and imaginary and afterthought.

10. The Union has produced documents as mentioned below:—

(i) Bank's order dated 31-3-1970 issued to Shri Vaidya at Ex. 6/W.

(ii) Bank's order dated 4-5-1970 issued to Shri Vaidya at Ex. 7/W.

(iii) Bank's order dated 5-6-1970 issued to Shri Vaidya at Ex. 8/W.

Shri Vaidya examined himself at Ex. 16/W.

11. The Bank has produced documents as mentioned below:—

(i) Letter dated 15-6-1970 from the Officer-in-charge to Nagpur branch.

(ii) Telegram confirmation copy dated 8-4-1972.

(iii) Circular No. 4 of 1968 dated 6-5-1968 at Ex. 9/E.

(iv) True copy of circulation No. B.I.D./STAFF/69/6, dated 10-1-1969 at Ex. 13/E.

(v) Copy of circular No. PRS/72/C.O./2, dated 7-1-72 at Ex. 14/E alongwith memorandum of settlement.

(vi) List of temporary clerical staff appointed from July, 1969 to April, 1972 at Ex. 15/E.

(vii) Register of Salaries at Ex. 10/E.

(viii) Daily Cash Balance Book at Ex. 11/E.

(ix) Agency Ledger from 1-1-1970 to 9/11-10-1970 at Ext. 12/E(i).

(x) Agency Ledger from 12-10-1970 to 17-4-1971 at Ext. 12/E(ii).

(xi) Daily Attendance Register at Ext. 18/E.

12. From the pleadings and documents on record, the points for consideration are as follows:—

(i) Whether the action of the management of the Central Bank of India in terminating the services of Shri Nilam Kumar B. Vaidya, Clerk-cum-Cashier of their Tumsar Branch with effect from the 9th December, 1970 is justified?

(ii) If not to what relief is he entitled?

13. My findings are as follows:—

(i) No

(ii) Entitled to reinstatement with continuity of service and back wages.

REASONS

Point No. i and ii :

14. It is common ground that the Central Bank of India opened a branch office at Tumsar on 1-1-1970 and that it appointed Shri Nilam Kumar B. Vaidya as temporary clerk-cum-cashier at Tumsar Branch office on 1-1-1970 for a period of three months (copy of appointment letter dated 1-1-1970 at Annexure 1 to the written statement Ext. 1/W). His services were extended for a further period of 2 months i.e. upto 31-5-1970 on the same terms and conditions as mentioned in the previous appointment letter (copy of letter Annexure 2 to the written statement Ext. 1/W). It means that Shri Vaidya was in continuous service of the Bank for five months.

15. It appears that the Bank has shown a break in the service of Shri Vaidya for the period from 1-6-1970 to 4-6-1970 but Shri Vaidya contends that in fact he was actually working in the Bank during this period also.

16. The Bank vide its letter dated 5-6-1970 Ext. 8/W informed Shri Vaidya that his services were extended by one month more i.e. upto 5-7-1970 on the same terms and conditions as mentioned in the Bank's letter dated 1-1-1970. The Bank by its letter dated 4-7-1970 annexure 5 to the written statement Ext. 1/W, extended the services of Shri Vaidya by one month on the same terms and conditions. The Bank by its Memo dated 4-8-1970 informed Shri Vaidya that his services were further extended for one month on the terms and conditions mentioned in the appointment letter dated 1-1-1970 from 6-8-1970 to 5-9-1970 (copy of Memo at Annexure 6 to the written statement Ext. 1/W). The bank by its letter dated 5-9-1970, annexure 7 to the written statement Ext. 1/W, further informed Shri Vaidya that his services were extended by one month on the terms and conditions mentioned in the appointment letter dated 1-1-1970 from 6-9-70 to 6-10-70. The Bank by its letter dated 5-10-70, annexure 8 to the written statement Ext. 1/W, informed Shri Vaidya that his services were extended by one month on the same terms and conditions as mentioned in the appointment letter dated 1-1-1970. On 4-11-1970 the Bank informed Shri Vaidya that he was appointed as temporary Clerk-cum-Asstt. Cashier for a specific period of 2 months i.e. from 6-11-1970 to 5-1-1971 and the Bank would have the right to terminate his services at any time with 14 days' notice or payment in lieu of notice, copy of letter at annexure 9 of the written statement Ext. 1/W.

17. It appears that on 25-11-1970 the Bank has been given notice to Shri Vaidya informing him that his services will stand terminated at the close of business on 9-12-1970, copy of notice at Annexure 10 to the written statement Ext. 1/W.

18. As regards the break in the services of Shri Vaidya for a period from 1-6-1970 to 4-6-1970 shown by the Bank Shri Vaidya says in his evidence Ext. 16/W as follows:—

"During the period in the month of June, 1970 I was on duty. In the daily attendance for the month of June, 1970 I have made entries in respect of each date showing hours of work, interval for rest or meals, hours worked with the employers overtime. I have also shown the holidyas. All the entries now shown to me relating to me for the month of June, 1970 are in my hand-writing.

On 1st, 2nd, 3rd and 4th June, 1970 I was working in Agency and filing department. Original statements for the Agency department for 1st to 4th June, 1970 both days inclusive were in my handwriting. These original statements have been sent to the Central Office of the Bank to Bombay. Carbon copies of these statements are on page Nos. 56, 57 and 58 in Agency Ledger Ext. 12/E(i).

It is not true that my services were discontinued even during the period from 1st June to 4th June, 1970. The endorsement of discontinuance made in red ink on page in the daily attendance for the month of June, 1970 was not made in my presence."

19. The Bank has produced Daily Attendance register at Ext. 18/E. In this book on the page pertaining to June, 1970, Shri Vaidya is shown to have worked even on 1st, 2nd, 3rd and 4th mentioning hours of works, interval for rest or meals, hours worked with the employer. In respect of dates 1st and 2nd overtime work is also shown. This page contains the attendance of Shri Vaidya from 1-6-1970 till 30th June, 1970.

20. It however appears that there is remark in red ink in the column of remarks as 'discontinued'. In the column of leave there is endorsement in red ink as 'Mr. Vaidya why (illegible)'. There is also a line in red ink suggesting cancellation of entries from 1st June to 4th June, 1970.

21. The Officer who cancelled these entries in red ink and shown Shri Vaidya as 'discontinued' for the period from 1st to 4th June, 1970 has not come in the witness box to give evidence. If he would have come in the witness box, the circumstances under which the entries were cancelled and as to why they were cancelled would have been available. In the absence of his evidence no weight can be attached to the cancellation of entries especially when Shri Vaidya states on oath that he actually worked in the Bank on the dates from 1st June to 4th June, 1970 also and that he was not absent.

22. Shri Sheikh representative for the Bank contends that Shri Vaidya was not given remuneration for these days and that it can be inferred from this that Shri Vaidya was discontinued and that there was break in the service during the period from 1st to 4th June, 1970.

23. Shri Vaidya has put in 5 months continuous service from 1-1-1970 till the end of May, 1970. He has also put in continuous service till 9-12-1970. As Shri Vaidya had put in continuous service for five months prior to 5-6-1970, it is not probable that he would leave the job of the Bank on his own accord. If he had some work on account of which he could not attend the office he would have taken leave to which he would have been entitled on account of five months continuous service with the Bank. Hence suspicion about this break and discontinuance of his service shown by the Bank in attendance register arises.

24. The Bank has produced Agency Ledger for the period from 1-1-1970 to 9/11-10-1970 at Ext. 12/E(i). Shri Vaidya says in his evidence Ext. 16/W that the original statements for the Agency department for 1st to 4th June, 1970 both days inclusive were in his handwriting, that the original statements have been sent to the Central Office of the Bank at Bombay, that carbon copies of these statements are on page Nos. 56, 57 and 58 in Agency Ledger Ext. 12/E(i).

25. According to Shri Sheikh, Agency statement means "It is compilation of entries both incoming and outgoing respecting branches and head office, since the branch accounts are now centralised, the statements are sent to Head Office, when entries are reconciled. The branch has a marking

system at their end as well as the Head Office, where unmarked entries are picked up branch-wise. The statement does not have to play a vital role as compared to cash book, daily book, cash memo book or the general ledger balance book. The statements are invariably delayed in posting and it is immaterial whether it is posted and despatched daily, weekly or fortnightly". What Shri Shaikh wants to suggest is that the entries regarding 1st to 4th June 1970 in the Agency Ledger must have been made by Shri Vaidya later on after 5-6-1970 at some time and that it cannot be inferred from these entries that he was on duty on these days. In support of this say the Bank has not adduced any evidence on record. The Manager has not come in the witness box to explain as to when the Agency statement was sent and as to when it was written. In the absence of any evidence to the contrary, the evidence of Shri Vaidya has to be accepted when he says that he made entries in these Agency statements during the period from 1st to 4th June 1970 as he was on duty on these days. This is another circumstance which shows that Shri Vaidya was in fact working in the Bank during the period from 1st to 4th June 1970 both days inclusive.

26. If the Bank has not given him pay for the 4 days to show a break in his service Shri Vaidya cannot be blamed for this and it cannot be inferred from this that Shri Vaidya had not actually done work in the Bank from 1st to 4th June, 1970.

27. In short I find from the sworn testimoney of Shri Vaidya referred to above and the entries in the agency Register Ext. 12/E(i) on pages 56 to 58 and the Daily Attendance Register for the month of June, 1970 in which the attendance of Shri Vaidya for the period from 1-6-1970 to 4-6-1970 was cancelled with red ink, that Shri Vaidya had in fact worked in the Bank from 1-6-1970 to 4-6-1970 both days inclusive though the Bank has shown break in his service during these 4 days.

28. If Shri Vaidya had in fact worked in the Bank from 1-6-1970 to 4-6-1970 both days inclusive though the Bank has shown a break in his service, it will mean that Shri Vaidya had a continuous service with the Bank from 1-1-1970 till 9-12-1970 for a period of 11 months and some days.

29. Admittedly the Tumsar branch of the Central Bank of India is working continuously since 1-1-1970. This branch is a permanent feature. Shri Vaidya was appointed in the vacancy of Clerk-cum-Cashier on the opening day i.e. 1-1-1970. There could not be any doubt that the vacany of the clerk in this branch was a permanent vacancy. It means that Shri Vaidya was employed temporarily in a permanent vacancy.

30. It appears that the Bank has violated the provisions of para. 20.8 of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966. Para. 20.8 is as follows:—

> "A temporary workman may also be appointed to fill a permanent vacancy provided that such temporary appointment shall not exceed a period of three months during which the bank shall make arrangements for filling up the vacancy permanently. If such a temporary workman is eventually selected for filling up the vacancy, the period of such temporary employment will be taken into account as part of his probationary period."

31. In the present case the Bank continued the appointment of Shri Vaidya on temporary basis even beyond the period of 3 months though the vacancy was a permanent one. It means that it had contravened the provisions of para. 20.8 of the Bipartite settlement referred to above.

32. Shri Puranik, Vice-President of the Union contends that the Bank in order to pursue its unfair labour policy employed several temporary hands in permanent vacancies and terminated their services during the last three four years. Shri Vaidya was also a victim of the Bank's unfair labour practice.

32-A. Certain temporary workmen who were appointed by the Bank in permanent vacancies as temporary workmen and continued from time to time, were later on discontinued. On account of this there was settlement between the Union and the Banks on 19-10-1966.

33. Cases of employees who were the victims of unfair labour policy followed by various banks were considered and their grievances were redressed as mentioned in paras 20.9 to 20.11 of the Bipartite settlement dated 19-10-1966. The intention in effecting the settlement and giving redress to the employees concerned was that various banks should not repeat the same practice, but in spite of this, the same practice has been followed by some branch offices. On account of this the Manager (Personnel) of the Central Bank of India issued a circular No. PRS/72/C.O./2, dated 7-1-1972 to all Controlling Branches. Copy of that circular is produced at Ext. 14/E. That circular is as follows:—

> "Re: Date of confirmation of the members of the Clerical and Subordinate Staff who were initially taken up on temporary basis and whose temporary services were continued from time to time with breaks of two to three days and subsequently taken up on probation.
>
> We send herewith a copy of the settlement arrived at between the Management and the All India Central Bank Employees' Federation for the information of Branches.
>
> The management and the A.I.C.B.E.F. had to arrive at this settlement for reasons mentioned in the short recital of the case in the settlement. Appointments of temporary hands for clerical and subordinate cadre were being made to fill up permanent vacancies by Controlling Branches indiscriminately and without following any principle or bearing in mind the provisions of para. 20.8 of the Bipartite Settlement and their temporary services were being renewed again and again after giving a break of 2 to 3 days. These temporary hands who were being kept on temporary basis for months together in the same vacancy has claimed that they should be treated as taken up on probation from the date of their initial appointment, and the present settlement has been arrived at to resolve this issue. To avoid such situations arising in future Controlling Branches are advised that temporary appointments should not normally be made except when the vacancy is of a temporary nature or in very emergent cases for which also prior approval of the Personnel Department should be obtained. The services of these temporary hands should be terminated on the expiry of the stipulated period. Anyway no member should be allowed to continue as temporary hand for more than 3 months. The Chief Agents of Controlling Branches will please bear this in mind for the future.
>
> According to the terms of this agreement, the following two categories of members who were initially taken up on probation from the original date of their appointment on temporary basis and confirmed effective from the date of expiry of six months from the original date of appointment on temporary basis.
>
> 1. Employees taken up on temporary basis on and after 1-7-1966 and their temporary services were continued giving breaks not exceeding three days.
>
> 2. Employees who were taken up prior to 1-7-1966 but not earlier than 1-1-1959 and whose temporary services were continued without any break.

It will be observed from the Settlement that the All India Central Bank Employees' Federation has agreed not claim arrears of increment and other benefits in regard to those members who will now be treated as confirmed in the Bank's service on the expiry of six months from the date of their initial appointment as temporary hands. The All India Central Bank Employees' Federation will also not take up supersession of their cases for promotion to higher cadres. However their names will be included in future Seniority List which will be drawn by the Groups as on 1st March and 1st September of every year.

Please let us have a list of the members of the Clerical and Subordinate staff at Offices in your Group who fall

under each of the two categories mentioned above giving full particulars of their names, designation, Branches where now working, details of temporary appointment, duration of breaks and the date on which they were taken up on probation. These particulars may be forwarded to Personnel Department to reach as before 31st January, 1972".

34. Alongwith the above circular a copy of the Memorandum of Settlement dated 23-12-1971 was also sent. That Memorandum of Settlement is as follows:—

"CENTRAL BANK OF INDIA

Memorandum of Settlement

Parties :

(1) Management of Central Bank of India represented by Mr. D. K. Contractor, Manager (Personnel).

(2) Representing the employees Shri T. Chakravorty, General Secretary, All India Central Bank Employees Federation and Shri H. R. Jhaveri, Joint Secretary, All India Central Bank Employees Federation.

A Short recital of the case

It has been pointed out by All India Central Bank Employees Federation and its affiliated units in different parts of India that in the past a number of employees in Clerical and Subordinate Cadre were kept temporary for indefinite periods and that they were taken on probation and confirmed in Bank's service, sometimes one year or two years after their initial appointments. There were also cases where employees were given temporary breaks for 2-3 days and after such periodical appointments they were subsequently taken into the Bank's permanent service. On behalf of the employees it was stressed that such employees were actually working against permanent vacancies and continuance of them in Banks temporary roll for months or years together has affected adversely their seniority, date of annual increment, leave, provident fund, gratuity and other consequential benefits.

After discussions between the parties it has been agreed as under :

Terms of Agreement

(1) The employees who have been appointed in the Bank's service originally on or after 1-7-1966 and were given breaks in the service not exceeding three days excluding Sundays and Bank Holidays, will be considered as having been confirmed on the permanent staff after six months from the date of their original appointments. Such members of Clerical and Subordinate staff will also be entitled to contribute towards provident fund from the date of their confirmation as per this agreement, and the due dates of their graded increments will be adjusted accordingly.

(2) In the case of such members of the clerical and subordinate staff who were continued to be temporary beyond the period of six months prior to 1-7-1966 and not earlier than 1-1-1959 without any break will also be allowed to contribute towards provident fund, six months after the date of their original appointment and they would be treated as confirmed from the said date.

(3) It is also agreed that the cases of the employees who were taken on temporary basis prior to 1-1-1966 and not earlier than 1-1-1959 but continued to work against permanent vacancies for more than six months will also be confirmed in service six months after the date of their original appointment and will be allowed to contribute towards provident fund as per para (2) above.

As regards the arrears of increment or other benefits, the All India Central Bank Employees Federation agreed not to claim the same. However, for the purpose of promotion, the All India Central Bank Employees Federation further agrees that while their cases for supersession will not be taken up, their names would be had included in future seniority lists, as and when drawn up, in terms of Promotion Policy Agreement. Now onwards their grade increment will fall due on the anniversary date of their original appointment."

35. It will be clear from Ex. 14/E referred to above that appointments of temporary hands in clerical and Subordinate Cadre were made to fill up permanent vacancies by Controlling Branches indiscriminately and without following any principle or bearing in mind the provisions of para. 20.8 of the Bipartite Settlement and their temporary services were renewed again and again after giving a break of 2 to 3 days. This supports the contention of Shri Puranik referred to above. In the present case Shri Vaidya was appointed as temporary clerk-cum-cashier in a permanent post and continued in the service by giving him extension from time to time in violation of para. 20.8 of the Bipartite Settlement. The Bank has taken a further step in respect of Shri Vaidya and discontinued him from service with effect from 9-12-1970 though he had put in more than 11 months and some days service. If he would have been in service he would have been treated as confirmed employee on account of the settlement.

36. Para. 20.7 of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966 is as follows:—

"In supersession of paragraph 21.20 and sub-clause (c) of paragraph 23.15 of the Desai Award, 'Temporary Employee' will mean a workman who has been appointed for a limited period for work which is of an essentially temporary nature or who is employed temporarily as an additional workman in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman."

37. It is clear from the above definition of temporary employee that Shri Vaidya could not be a temporary employee within the meaning of para. 20.7 of the Bipartite settlement dated 19-10-1966 as he was not appointed for doing a work which of an essentially temporary nature and as he was not appointed as an additional hand for clearing the increase in work of a permanent nature or in the vacancy caused by the absence of a permanent workman. As he was appointed as a temporary hand in permanent vacancy and continued for a period of more than 3 months, the Bank has violated the provisions of Bipartite Settlement para. 20.7 and 20.8.

38. In the written statement Ex. 4/E para. 7 it is contended by the Bank that the work, conduct and behaviour of Shri Vaidya were not up to the mark. In support of that contention the Bank has not adduced any evidence either oral or documentary. In the absence of any evidence the allegation that work, conduct and behaviour of Shri Vaidya during the tenure of his service with the Bank were not up to the mark cannot be accepted and this could not be a reason for termination of his service by the Bank.

39. Shri Shaikh for the Bank contends that Shri Vaidya could not be continued in service because he had not scored necessary percentage of marks in Mathematics in S.S.C. examination. In support of this contention he relies on Recruitment Rules in relation to Educational Qualification for clerk and confirmation copy of telegram dated 8-4-1972.

40. In circular No. 4 of 1968 regarding Recruitment of Staff dated 6-5-1968, produced at Ex. 9/E, it is mentioned as follows in para 7(A)(II).

"Educational qualification : For recruitment to clerical cadre in Accounts, Typing, Cash Godowns Sections etc. minimum qualification will be Degree from a Recognized University. However, the Bank may also permit candidates not exceeding 25 per cent from amongst non-graduates to sit for written test. Such non-graduates should have passed matriculation examination or its equivalent with English and Mathematics and should have obtained of 50 per cent marks."

41. In the advertisement calling applications from the candidates concerned it is mentioned as follows : —

"Applications from Matriculates or persons who have passed equivalent examinations with first class or high second class marks or in I or II Division with over 50 per cent marks in English and Mathematics,

will also be considered to a limited extent. Candidates for the posts of Cashiers and Godown-keepers will have to furnish minimum cash security of Rs. 2,500 on appointment."

42. It is clear from Ex. 9/E and the advertisement calling application for the post of clerks etc. that the candidates who has passed S.S.C. with 50 per cent marks in English and Mathematics will be eligible for appointment.

43. Copy of telegram confirmation dated 8-4-1972 produced on record shows that Shri Vaidya had secured 59 per cent marks in S.S.C. and that he obtained 58 per cent in English and 45 per cent marks in Mathematics.

44. There can be no doubt from the above mentioned confirmation copy of telegram produced by the Bank that Shri Vaidya had 58 per cent marks in English and 45 per cent in Mathematics in S.S.C. It means that Shri Vaidya had secured 51.5 per cent marks on average in English and Mathematics. The Recruitment Rules and the advertisement required that candidates concerned should have secured not less than 50 per cent marks in English and Mathematics. It is nowhere specifically mentioned that the candidates should have 50 per cent marks in Mathematics and 50 per cent marks in English. In view of this the contention raised by Shri Shaikh that Shri Vaidya was not eligible for continuing as clerks as he had less than 50 per cent marks in Mathematics in S.S.C. fails. Hence the ground of education qualification for not continuing or absorbing Shri Vaidya in the post of clerk-cum-cashier in Tumsar Branch of the Central Bank of India cannot be accepted.

45. Shri Shaikh for the Bank contends that Shri Vaidya's appointment was temporary and contractual that as Shri Vaidya accepted the terms and conditions of service by signing the contract, he is bound by the terms of contract and that he cannot claim anything more beyond the terms of contract. What Shri Shaikh wants to say is that the termination of services of Shri Vaidya by giving him 14 days notice as per terms of service contract is quite just and proper.

46. Appointment letter dated 1-1-1970, Annexure 1 to the written statement Ex. 1/W given to Shri Vaidya is as follows :—

"CENTRAL BANK OF INDIA

(Registered Office: Mahatma Gandhi Road, Bombay-1)

Dated 1-1-1970

Dept. Staff No. 1

With reference to the application dated 30-12-1969 of Shri N. B. Vaidya for the post of Clerk or Cashier he is hereby appointed as a temporary clerk-cum-cashier for a specific period of Three months only from 1-1-1970 to 31-3-1970. During the period of his employment Shri N. B. Vaidya will be paid emoluments as per provisions of the Bipartite Settlement viz. salary Rs. 132 plus dearness allowance Rs. 114.84 Total Rs. 241.84 per month. The dearness allowance will vary according to rise or fall in the cost of living index figure. Shri N. B. Vaidya's services will cease on the expiry of the said period on 31st March, 1970 after office hours.

The Management, however, reserves the right to terminate his services at any time with 14 days notice or payment in lieu of notice.

If Shri N. B. Vaidya is agreeable to the above terms and conditions, he should sign the duplicate here of the token of his acceptance and return the same to our office and report on duty at our office on 1-1-1970."

47. It appears from the above mentioned letter that the management had reserved the right to terminate Shri Vaidya's service at any time with 14 days notice or payment in lieu of notice, and that Shri Vaidya had accepted the terms and conditions of service.

48. It appears that on 4-11-1970, the Bank issued another order giving him appointment as temporary clerk-cum-Asstt. Cashier, for a specific period of two months from 6-11-1970 to 5-1-1971. In this order also the Bank incorporated the clause regarding its right to terminate his services at any time with 14 days notice or payment in lieu of notice.

49. In pursuance of the Bank's right to terminate the service of Shri Vaidya at any time with 14 days notice, the Bank terminated the services of Shri Vaidya by giving him notice on 25-11-1970 terminating his service at the close of business on 9-12-1970.

50. It is interesting to note that after the first appointment of Shri Vaidya with effect from 1-1-1970 his services were extended from time to time by passing orders. Even after the artificial break in his service shown by the Bank from 1-6-1970 to 4-6-1970 his services were extended from time to time. It is only on 4-11-1970 that the Bank changed the wording of the appointment letter stating that he was given temporary clerk-cum-Assistant cashier for a specific period of two months only i.e. 6-11-1970 to 5-1-1971. This specific change in the appointment order is a circumstance with indicates as to what the intention of the Bank in connection with Shri Vaidya was. If there would not have been something in mind, his services would have been extended as usual. After making this particular change in the order, the bank did not allow Shri Vaidya to continue in service till 5-1-1971 also, but it gave him notice on 25-11-1970 terminating his services with effect from 9-12-1970. This circumstance also speaks about the conduct of the Bank in connection with Shri Vaidya. It can be inferred from the above mentioned circumstances that the Bank was not exercising its power in connection with the appointment of Shri Vaidya fairly.

51. The next point for consideration is whether the Bank's action in terminating the services of Shri Vaidya by giving 14 days notice on the basis of the terms of contract of service is justified. In my opinion it is not justified.

52. In support of my view I am referring to 'The law of Industrial Disputes' by Shri Malhotra regarding Employer's right to discharge a workman, page 895 and 896.

"The question of the employer's freedom of contract in the context of industrial adjudication was considered by the Supreme Court in Rai Bhadur Dewan Badri Das Vs. Industrial Tribunal reported in 1962, II, LLJ, 366. His Lordship Justice Gajendragadkar speaking for the majority said 'The doctrine of absolute freedom of contract has thus to yield to the higher claims for social justice.....the right to dismiss an employee is also controlled subject to well-recognised limits in order to guarantee security of tenure to industrial employees'. Hence in industrial law, the claim of the employer to terminate the service of his workmen under the contract of employment or in the Standing Orders by giving him a notice or by paying him wages in lieu of such notice amounts to a claim to 'hire and fire' an employee. Such claim would negative security of service which has been secured to industrial employees through industrial adjudication and the process of collective bargaining evolved from long-drawn strike.

Hence, before the action of discharge or dismissal by way of punishment for a misconduct can be taken against a workman, the employer is bound under the Standing Orders as well as on the principles of natural justice to draw up a regular proceedings against him. Furthermore even in cases of discharge of a workman under the contract of service or standing orders, the requirement of bona-fide is sine quo non as mala fide or colourable exercise of a contractual or statutory power is not legal exercise of such power.

"If under the garb of termination simpliciter, the employer acts mala fide or with the intention to penalise the concerned workman, it would be colourable exercise of the power, victimisation or unfair labour practice and the industrial tribunal would have the jurisdiction to intervene and set aside such termination (1966, I, LLJ, Page 398)".

53. In the present case the termination of services of Shri Vaidya on the basis of contract of service is not just and proper because the Bank's exercise of contractual power in terminating the services of Shri Vaidya was colourable and not proper as the Bank has violated the provisions of Bipartite Settelement dated 19-10-1966. Hence the termination of the services of Shri Vaidya by the Bank is not justified.

54. As the termination of services of Shri Vaidya was not justified, he is entitled to reinstatement in service.

55. Shri Shaikh for the Bank contends that Shri Vaidya should not be given back wages from the date of termination of his services till the date of reinstatement as he is managing the family business and as he is not jobless.

56. It appears from the evidence of Shri Vaidya Ex. 16/W that his father is suffering from T. B. and confined to bad, that his uncle is supporting his family and that his mother is doing Manganese Ore business. He denies the suggestion that his mother is doing Manganese Ore business in partnership with him. In view of his sworn testimony it cannot be said that Shri Vaidya is carrying on Manganese Ore business in partnership with his mother.

57. I am satisfied from the evidence of Shri Vaidya in the absence of any evidence to the contrary on behalf of the Bank, that Shri Vaidya is jobless since the date of termination of his services and that he is entitled to get back wages with continuity of service. For the reasons given above, I record my findings on point Nos. i and ii as above and pass the following order :—

ORDER

(i) It is hereby declared that the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of Shri Nilamkumar B. Vaidya, Clerk-cum-Cashier of their Tumsar Branch with effect from 9th December, 1970 is not justified and that he is entitled to reinstatement with continuity of service and back wages with all allowances and other benefits from the date of termination of his services till the date of reinstatement.

(ii) Award is made accordingly

(iii) No order as to costs.

Dated 2-2-1973

N. K. VANI, Presiding Officer
[No. 12012/51/71/LR III]

New Delhi, the 12th March, 1973

S.O. 900.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Superintendent Personnel, Messrs. Bengal Coal Company Limited, Post Office Dishergarh, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th March, 1973.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

Reference No. 58 of 1972

Parties :

Employers in relation to the Superintendent Personnel, Messrs. Bengal Coal Company Limited, Post Office Dishergarh District Burdwan.

AND

Thier workmen

Present :

Sri S. N. Bagchi, Presiding officer,

On behalf of : Employers
Sri D. Narsingh, Advocate, with Sri B. N. Lala. Personnel Officer.

On behalf of : Workmen
Sri Provat Goswami, Joint Secretary of the Union.

State: West Bengal **Industry:** Coal Mine.

AWARD

By Order No. L-19012/48/72-LR.II., dated 9th October, 1972, the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, referred the following dispute existing between the employers in relation to the Superintendent Personnel, Messrs. Bengal Coal Company Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the demand of the Colliery Mazdoor Union, Asansol that the leaders of No. 5 Pit of the Seetalpur Colliery of Messrs. Bengal Coal Company Limited, Post Office Dishergarh, District Burdwan for payment of increased rates of wages for doing the jobs of drilling, dressing and earth-cutting is justified? If so, to what relief are the workmen entitled to and from what date?"

2. To-day is the date fixed for peremptory hearing of the reference case. The employers company had raised certain preliminary objections in their statement of case about the maintainability of the reference and jurisdiction of this tribunal.

3. When the matter was called on for hearing to-day, Sri D. Narsingh, learned Advocate for the employer company and Sri P. Goswami, Joint General Secretary of the Union submit that parties have arrived at a compromise, produce the memorandum of compromise and pray that an award be made in terms thereof. Since this tribunal has no jurisdiction to entertain the reference, the tribunal cannot accept the compromise petition. They however, jointly made a petition stating therein that there no longer existed any dispute over the subject matter of the reference. Hence, a 'no-dispute' award is rendered on their submissions.

This is my award.

Dated 2-3-73.

S. N. BAGCHI, Presiding Officer
[No. L-19012/48/72-LRII]

New Delhi, the 15th March 1973

S.O. 901.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamari Division, Post Office Kalyankhani (Andhra Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1973.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, (CENTRAL)

AT HYDERABAD

Present :

Sri P. S. Ananth, B. Sc., B. L., Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad.

Industrial Dispute No. 44 of 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapur and Mandamari Divisions.

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapur and Mandamari Divisions.

Appearances :

Sri B. Gangaram, Vice President, S. C. Workers Union, Bellampalli, for Workmen.

Sri S. Nagaiah Reddy, President, Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli, absent and he did not file his authorisation.

Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer, S. C. Co. Ltd., Bellampalli, for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by its Order No. 7/34/70-I.R. II dated 15-5-1971 referred the following dispute under Section 10-(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for adjudication to this Tribunal, namely,

"Whether the management of Ramakrishnapur and Mandamari Divisions of Singareni Collieries Company Limited is justified in not granting one service increment to Sarvashri Kasipeta Posham, Kalagura Lingaiah, Jaida Rajam, Shot firers of Ramakrishnapur 3 mine and Shri C. Muralidhar Rao, Sirdar of Kalyanikhani 1 and 4 as per Wage Board Recommendations with effect from the 15th August, 1967, if not to what relief are they entitled ?"

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 44 of 1971 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience the workmen of Ramakrishnapur and Mandamari Divisions of Singareni Collieries Company Limited are referred to as the petitioners and the Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapur and Mandamari Division is referred to as the respondent. There are two sets of claimants. One set of claimants are Kasipeta Posham, Kalagura Lingaiah, and Jaida Rajam who are Shot firers and they are referred to as claimants 1 to 3 respectively and the other claimant is C. Muralidhar Rao, Sirdar and he is referred to as the 4th claimant in the course of this Award.

2. Claimants 1 to 3 are represented by the Singareni Collieries Workers Union, Bellampalli (hereinafter referred to as the first Union) and the Vice President of the said Union filed the claims statement contending as follows : Kasipeta Posham, Kalagura Lingaiah and Jaida Rajam were officiating as Shot firers continuously in Ramakrishnapur No. 3 Incline from 24-5-64, 5-5-64 and 3-5-64 respectively. They were also officiating as Short firers in Shanti Khani since January, 1963 before they were transferred to Ramakrishnapur No. 3 Incline. They were permanently confirmed as Short firers with effect from 1-9-1964. They had put in more than five years of service as Shot firers upto 15-8-1967 and this means that they are eligible to get one service increment under Wage Board recommendations with effect from 15-8-67 and also arrears from 15-8-1967 but the Management is refusing to give them one service increment. To get one service increment three years service is sufficient. As per Sub-Rule (2) of Rule 2 of the Gratuity Rules of the Company if the temporary service is followed without a break by permanent service the temporary employees shall be deemed to draw pay in a permanent establishment and such service shall count for gratuity. It is clear from the above that even the temporary service is also being computed for purpose of gratuity and in the instant dispute the said three Shot firers have put in above five years of service without break as Shot firers but the Management did not confirm them for two years but they were paid the wages of Shot firers only. Due to delay by Management in confirming the workmen in the job, the workmen should not be deprived of the benefits. So the demand of the workmen is that their officiating period as Shot Firers should be counted for the purpose of service increment and they should be paid one service increment with effect from 15-8-1967.

3. The respondent filed a counter contending as follows :— The reference of the individual workmen who are working as Shot Firers in Ramakrishnapur Division for grant of service increment is a matter that comes under the purview of Section 33(c)(2) of the said Act and so the present reference is bad and incompetent. It is denied that these three persons were officiating as Shot Firers continuously. These persons were designated as Shot Firers and they were paid daily rate, whereas the Shot Firers are appointed on monthly basis. The said Workmen were officiating as Shot Firers in leave, sick and absentee position of permanent Shot Firers, They accepted the officiating allowance of 16 paise per day. The positions was that from 5-5-1964 to 30-6-1964 they worked intermittently as Shot Firers. Kasipeta Posham was confirmed on 24-12-1964 and K. Lingaiah was confirmed on 1-9-1964 and J. Rajam was confirmed on 1-9-1964. Evidently their claim that they worked for more than five years as Shot Firers upto 15-8-1967 is false and baseless. The reference of the gratuity scheme of the Management is irrelevant. The Labour Appellate Tribunal directed that in calculating the length of service the period during which the employee was serving under the designation of the incoming grade to which he is fitted is only to be reckoned and not the entire period of his service in the Company, that is to say, the service in other designations will not be reckoned in calculating increment according to this Rule and the same Rule was adopted by Sri Das Gupta vide Para 4 Issue 12 page 68. So these workmen are not eligible for one service increment and the arrears.

4. The 4th claimant is represented by the Tandur Coal Mines Labour Union (hereinafter referred to as the second Union) and the President of the second Union filed a claim statement contending as follows :—C. Muralidhar Rao was working as Coal Cutter upto 24-4-1964. He was promoted to the post of Sirdar from 25-4-1964 and he is working as Mining Sirdar from 25-4-1964. He was confirmed in that post from 6-10-1964 with effect from 1-9-1964. The Management refused to count his service as Mining Sirdar from 25-4-1964 for purpose of granting service increment under the Wage Board but counted only from 1-9-1964. The stand of the Management that the service from 25-4-1964 to 1-9-1964 as Mining Sirdar cannot be counted for service increment is not contained in the certified Standing Orders of the Company. The concept of acting service and confirming service applicable in pleasure tenure is being imported into the contractual services. C. Muralidhar Rao was drawing salary of the Mining Sirdar from 25-4-1964, while facts stood thus it was unjustified on the part of the Management to exclude a portion of his service for purpose of granting service increment under the Wage Board. So the Management should be directed to give one service increment.

5. The respondent filed a counter contending as follows : The reference of the individual workman who was working as Coal cutter in Mandamari Division for grant of service increment is the matter that comes under the purview of Section 33(c)(2) of the said Act and so the present reference is bad and incompetent. It is disputed whether the workman is a member of the Tandur Coal Mines Labour Union. C. Muralidhar Rao was appointed as a Coal Cutter and asked to officiate as Mining Sirdar from 25-4-1964 in temporary vacancy. It is denied that he was appointed in substantive vacancy of Mining Sirdar from the date of officiating. It is admitted in the claims statement that he was appointed as Mining Sirdar on probation for a period of six months with effect from 1-9-1964. Evidently he was not a Minnig Sirdar earlier to the date of the office order. The claim by the workman that his service should be counted from 25-4-1964 for the purpose of granting service increments is erroneous and misleading. The recommendations of the Wage Board have not laid down that acting service should be counted for the purpose of service increment. Office Order issued to the workman governs the conditions and terms of his work as Mining Sirdar. While admitting all the facts and terms of employment, the workman claiming for one service increment unilaterally as against the procedure followed in implementing the Wage Board Recommendations amounts to an unjustified claim. While implementing the Wage Board recommendations, the workman has not complained within the stipulated time that there was a wrong implementation of Wage Board recommendations. If it was a case of wrong implementation the relief that should be sought by the workman is under Section 33(c)(2) of the said Act. The Labour Appellate Tribunal directed that in calculating the length of service the period which the employee was serving under the designation of the incoming grade to which he is fitted is only to be recokoned and not the entire period of his service in the Company, that is to say, the service in other

designations will not be reckoned in calculating the increments according to this Rule and the same Rule was adopted by Sri Das Gupta vide Para 4, Issue No. 12 page 68. So the claim may be dismissed.

6. The dispute that is now referred to this Tribunal for adjudication is whether the Management of Ramakrishnapur and Mandamari Divisions is justified in not granting one service increment to Kasipeta Posham, Kalagura Lingaiah and Jaida Rajam Shot Firers, C. Muralidhar Rao, Sirdar, as per the Wage Board recommendations with effect from 15-8-1967.

7. Though in the counters filed by the respondent one of the contentions raised is that the reference is bad and incompetent and that the grant of service increment is a matter that comes under the purview of Section 33(c)(2) of the said Act, the respondent's representative did not argue about this aspect of the matter and so it is taken that the respondent is not pressing this contention. So the case is proceeded with on the basis that the reference is a valid reference.

8. So far as claimants 1 to 3 are concerned, their case is that they have been acting as Shot Firers continuously for about five years prior to 15-8-1967, from which date the respondent had implemented the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry (hereinafter referred to as Wage Board) and so they are entitled to one service increment as per the recommendations of the Wage Board but the respondent did not give one service increment. The contentions of the respondent are that these three claimants were officiating as Shot Firers in leave or absent vacancies intermittently and that the first claimant was confirmed as Shot Firer on 24-12-1964 and claimants 2 and 3 were confirmed as Shot Firers on 1-9-1964 and so they are not entitled to one service increment since they did not put in three years of completed service and that the Labour Appellate Tribunal has directed that in calculating the length of service during which the employee was serving under the designation of the incoming grade to which he is fitted should only be reckoned and not the entire period of his service in the Company and that even the same rule had been adopted in the Das Gupta Award. The respondent has filed Exs. M 4 and M 5 which are the extracts of the two circulars which were said to have been followed while giving service increments. Now it has to be seen whether the respondent is justified in not granting one service increment to these three claimants.

9. It is an admitted fact that these three claimants are working as Shot Firers. If the evidence in this case established that these three claimants were working continuously as Shot Firers for a period of three years prior to 15-8-1967 then these claimants would be entitled to one service increments, because it is common ground that if the Shot Fire puts in a service of three years continuously he would be entitled to one service increment as per the recommendations of the Wage Board. W.W. 1 (K. Lingaiah) is claimant No. 2. He says that he is working as Shot Firer in R. K. 3 at Ramakrishnapur since 5-5-1964 that prior to that he worked at Shanti Khani in Ballampalli Division, that along with him Jaida Rajam, Kasipeta Posham, Emula Ramulu, Sallasula Sayalu and Madasi Babu were also transferred to R. K. 3, that they were transferred as acting Shot Firers, that Ex. W 1 is the Transfer Order issued to him, that after they were transferred to R. K. 3, they have been working continuously as acting Shot Firers, that Madasi Babu, Emula Ramulu and Sallasula Sayulu were confirmed in August, 1964, that out of the remaining three persons himself and Jaida Rajam were confirmed in the 9th Month in 1964 and Kaslpeta Posham was confirmed in the 12th month of 1964, that he asked the Manager that he should be confirmed and he said that since they six persons were transferred at the same time they would be confirmed. but first three persons were confirmed and next two persons were confirmed and next one person was confirmed separately, that they have worked for more than three years prior to the Wage Board recommendations, that as per Wage Board who ever has got three years of service should be given one increment but that he was not given one increment. In his cross examination he says that when he worked at Shanti Khani he was first appointed on 12-8-1953 as daily mazdoor, that he worked there as daily mazdoor for three years and afterwards he worked as Coal Filler, that afterwards he worked as Coal Cutter till 1964. that before he was transferred to R. K. 3 he never worked as Shot Firer, that they were given appointment order for working as Acting Shot Firers and transferred to R. K. 3, that it is not correct to say that in every week he worked as Shot Firer for one day and as Coal Cutter for 5 days and that he did like that till 30-6-1964, but that on the other hand he worked continuously as Shot Firer at R. K. 3 from 5-5-1964, that it is not correct to say that Kasipeta Posham and Jaida Rajam did not work continuously as Shot Firers, and that they worked now and then as Shot Firers for which they were given Shot Firer allowance, that for those two and himself continuously acting allowance was given, that when one increment was not given he did not file petition before 31-3-68 but he asked the Management and the Manager said that he would be getting the increment and thus they delayed and later on he sent petition, that the other two persons also sent petitions and that it is not true to say that they did not send any petition.

10. W.W. 2 (K. Posham) is the 1st claimant. He says that from the time of transfer from Shanti Khani he had been working continuously as Shot Firer and he had been paid Shot Firer wages, that along with him Madasi Babu, Sallasula Sayulu, Vemula Ramulu, and Kalaguri Lingaiah (second claimant) were transferred from Shanti Khani as acting Shot Firers, that Jaida Rajam (Claimant No. 3) was transferred as acting Shot Firer two months prior to his transfer, that Ex. W. 3 is the letter given to Kalaguri Lingaiah when he was transferred from Shanti Khani, that he (W.W. 2) was made permanent Shot Firer on 24-12-1964, that Salasulla Sayulu, Madasi Babu and Vemula Ramulu were made permanent Shot Firers in the 8th month in 1964, that Jaida Rajam was made permanent Shot Firer in the 9th month in 1964, that though he and others were transferred on the same date from Shanti Khani they (he and other two claimants and others) were made permanent on different dates, that after Wage Board Madasi Babu, Salasula Sayulu and Vemula Ramulu were given one service increment and fixed at Rs. 180 per month basic but himself K. Lingaiah and J. Rajam were fixed at Rs. 180 p.m. basic that prior to Wage Board they worked as Shot Firers for three years, that when he was made permanent in 1964 he was given the basic of Rs. 46 in the grade of Rs. 43—52, that if he had been fixed on the basic of Rs. 46 by giving service increment as Coal Cutter he would have been benefitted but this one service increment was not given and so he suffered loss at the time when the basic was fixed at Rs. 43 then and again when his basic was fixed at Rs. 180 after the Wage Board, that when he was not given one service increment of Rs. 5 he represented to the management orally, that the Management said that if he wanted he may file a case and so he raised a dispute through his Union. In his cross examination he says that prior to his transfer from Shanti Khani he was working as Coal Cutter, that when he was transferred to Ramakrishnapur 4 he was transferred as acting Shot Firer, that he worked continuously as Shot Firer and that he was not posted to any leave vacancy of any one, that he does not have any other letter showing that he was working as Shot Firer, that he was being paid the acting allowance of acting Shot Firer along with his basic pay of daily rated Coal Cutter, that he was being paid 16 paise per day acting allowance, that after he was confirmed he was being paid monthly, that it is not correct to say that they have been only acting in leave vacancies, that if there is any such record it not correct, that as per Wage Board one service increment would be given for every three years service, that he was not given increment for one year from the date of confirmation till 15-8-1967 on the ground that he had not put in three years of service, that he was given one increment and fixed at Rs. 46 in the grade of Rs. 47—52, that after Wage Board he was fixed at Rs. 180 basic as Shot Firer, that it is correct to state that one increment was given for a person who worked continuously for 3 years and two increments if one worked for 6 years and three increments if one worked for 9 years, that he did not put in any petition prior to 31-3-1968, that when he was not given one service increment he made oral representation, that he knows that Company had given one increment for those who worked for three years in the same Category and his grievance is that prior to Wage Board one increment was not given and that after Wage Board also he was not given one increment, that it is not correct to say that he was given one increment as Shot Firer and his wages was increased from Rs. 43 to Rs. 46 and he was fixed at Rs. 180 as basic after Wage Board as the starting wages and that no injustice was done to him. So his evidence shows that his grievance appears to be that he was also not given one increment prior to Wage Board but that cannot be gone into in the present proceedings.

11. M.W. 1 (P. T. Thomas) is working as Divisional Personnel Officer of Mandamari Division. With reference to these three claimants he says that they are working in No. 3 Incline of Ramakrishnapur and Manadamari Divisions, that they worked as Coal Cutters in Shanti Khani of Bellampalli Division prior to working in Ramakrishnapur and they were transferred to Ramakrishnapur as Coal Cutters in April, 1964, that they acted as Shot Firers in No. 3 Incline in Ramakrishnapur in the places of those who were absent or who were on leave, that they acted only intermittently, that Ex. M 1 is the copy of the acting particulars relating to them, that Ex. M 2 and M 3 are the copies of the order appointing K. Kosham, K. Lingaiah and Jaida Rajam respectively, that the Wage Board recommendations were implemented so far as these three claimants are concerned, that they were fixed in the scale of Rs. 180—273 as Shot Firers, that no service increments were given to them since they did not complete three years of service, by 1-10-1966, that their period of service as Shot Firers when they acted intermittently was not taken into consideration, that for Sayulu, another Rajam and M. Babu one service increment was given as they were promoted as Shot Firers on 5-8-1964 and since they had completed 3 years of service, that the extract of two circulars the originals of Ex. M 4 and M 5 were followed while giving service increments that they followed the procedure laid down in Das Gupta Award for considering serving increment and that there is no representations made by these claimants before 31-3-1968.

12. So far as first union is concerned none represented that Union when M.W. 1 was examined on 28-6-1972 and so case was adjourned to 1-8-1972 ordering fresh notice to the petitioners and on that day also no representation was made and even the second Union was absent on that day and so the case was adjourned to 22-8-1972 and fresh notice was ordered to the second Union stating that if they do not appear the matter would be proceeded within their absence and so the matter was proceeded with under Rule 22 of the Industrial Dispute (Central) Rules as they were absent on 22-8-1972 and the matter was posted to 15-9-1972 and from 15-9-1972 the matter was again adjourned to 29-9-1972 and fresh notice was issued to the first Union and even on 29-9-1972 both Unions were absent and so final fresh notice was issued to both the Unions for hearing on 3-11-1972 and both the Unions were absent even on 3-11-1972. In view of the representation made by the respondent's representative that the Union Leaders were saying that they would be coming after Deepavali, the matter was adjourned to 25-11-1972 and fresh notice was ordered. On 25-11-1972 the second Union was not represented and so far as the first Union is concerned a telegram was received requesting for an adjournment. So the matter was adjourned to 21-12-1972, and at the request of the representative of the first Union the matter was again adjourned to 10-1-1973 and even on 21-12-1972 the second Union was absent. On 10-1-1973 also the second Union was absent. No further evidence was let in and even M.W. 1 was not cross examined by the representative of the first Union and so the evidence was closed on that day. So it is seen that so far as M.W. 1 is concerned he was not cross examined by the first Union.

13. Now from the evidence referred to above it is clear that these three claimants did not work as Shot Firers prior to their being transferred to Ramakrishnapur and that they were working only as Coal Cutters and that even at Ramakrishnapur they did not work continuously as Shot Firers but that they were only acting as Shot Firers intermittently in the temporary vacancies like leave or absence of the permanent Shot Firers and that for the period that they so acted they were raid acting allowance. No doubt Exs. W 1 and W 3 show that the first claimant and the second claimant were transferred from Shanti Khani to Ramakrishnapur Division in May, 1964, but there is no other document to show that they worked continuously as Shot Firers. On the other hand there is documentary evidence on the side of the respondent to show that these claimants did not work continuously as Shot Firer. Ex. M 1 is the copy of the letter that was addressed to the A. O., Hyderabad, by the respondent and it gives the details about the work done by these claimant and it shows that these claimants did not work continuously as Shot Firers. Ex. M 1 also shows that these claimants were officiating as Shot Firers on and off in the leave, sick and absenteeism vacancies and that the 1st claimant was promoted only on 24-12-1964 and that Claimants 2 and 3 were promoted only on 1-9-1964 and the evidence also shows that they did not raise any dispute till July, 1970. Ex. M 2 is the office order issued to the 1st claimant and another which shows that the 1st claimant and another were appointed as Shot Firers on probation for a period of six months with effect from 24-12-1964 and Ex. M 3 office order shows that claimants 2 and 3 were appointed as Shot Firers on probation for a period of six months with effect from 1st September, 1964. So the evidence in this case clearly shows that, eventhough the claimant's contention is that they have been working continuously as Shot Firers for a period of five years prior to 15-8-1967, as a matter of fact the 1st claimant had been working as Shot Firer continuously only from 24-12-1964 and that claimants 2 and 3 had been working continuously as Shot Firers only from 1-9-1964. So under these circumstances the respondent is justified in not giving one service increment, because these claimants did not put in three years of service as Shot Firers. No doubt it is also contended by the representative of the first Union that when the other three Shot Firers, who had been transferred along with the claimants were confirmed there is no justification for confirming the three claimants at a later stage and that these claimants cannot be made to suffer for any fault of the Management and that if the Management had delayed giving promotions to the claimants they are not responsible, but as rightly contended by the respondent's representative the question of giving promotion would arise only if there are clear vacancies. In the present case there is no evidence to show that there had been clear vacancies and that inspite of it the Management delayed giving promotions to these claimants. On the otherhand the evidence in this case only shows that these claimants were given acting chances whenever leave or sick vacancies arose and that these claimants were given acting allowance and that when permanent vacancies arose the Management promoted these claimants as is evidenced by Ex. M 2 and M 3. It is not the case of the claimants that their services as Coal Cutters also should be taken into consideration for giving increment and so it is not necessary to consider the effect of Ex. M 4 and M 5. On a consideration of the whole evidence placed before me I am satisfied that the Management is justified in not giving one service increment to these claimants.

14. So far as 4th claimant is concerned, his case is that eventhough he was promoted to the post of Sirdar from 25-4-1964 and even though he had been working as Mining Sirdar from 25-4-1964 he was not given one service increment at the time of the implementation of the recommendations of the Wage Board and that the Management is not justified in not counting the period from 25-4-1964 to 1-9-1964 for purpose of granting service increment. So far as 4th claimant is concerned he did not choose to examine himself and he also did not adduce any other evidence to substantiate his case. Inspite of giving number of chances he did not examine himself and he also did not adduce any other evidence and so the matter was proceeded with under Rule 22 of the Industrial Dispute (Central) Rules so far as he is concerned. The respondent examined M.W. 2 on its side and marked Exs. M 1 and M 6 on its side. M.W. 2 (P. T. Thomas) is working as Divisional Personnel Officer, Mandamari and Ramakrishnapur Divisions. He says that C. Muralidhar Rao is working as Mining Sirdar in Mandamari Division of K.K. No. 1 Division, that prior to his appointment as Mining Sirdar he was working as Coal Cutter in old Category VI special, that he was promoted as Mining Sirdar from 1-9-1964 that Ex. M 6 is the copy of the appointment order issued to him, that first increment was given on 1-9-1965 after his satisfactory completion of period of prohibition, that prior to his being promoted as Mining Sirdar he had officiated in the vacancy of Mining Sirdar caused due to the absence or leave of the permanent Mining Sirdar, that there is Circular dated 13-10-1967 issued by the Company after Wage Board and as per that Circular one increment has to be given for every three of completed service, that Ex. M 7 is the extract of that Circular, that this three years of completed service should be in the same job, that when this Circular was issued C. Muralidhar Rao did not make any representation in writing within the time stipulated in the circular or any time after that stating that one service increment was not given to him, that while implementing Wage Board Muralidhar Rao was not given any service increment as he had not put in three years of service on 14-8-1967 as Mining Sirdar in that particular grade, that they do not include the period during which the person officiates in the higher job in the leave vacancies or vacancies during absence for purpose of arriving at the three years of completed service that C. Muralidhar Rao never represented to him that he was a member of either Tandur Coal Mines Labour Union or member of Mining Sirdar and Overmen Association. Now the evidence of this witnesses stands unrebutted.

15. From Ex. M 1 it is seen that the 4th claimant was only officiating as Mining Sardar from 25-4-1964 in the temporary vacancies and that when a permanent vacancy had arisen he was promoted and appointed as Mining Sardar with effect from 1-9-1964 Ex. M 6 is the copy of the office order issued to the 4th claimant appointing him as Mining Sardar on probation for a period of six months with effect from 1-9-1964. So from the evidence of M.W. 1 and Ex. M 1 it is seen that the 4th claimant had acted in temporary vacancies intermittently and that he was paid acting allowance and that it is only when a permanent vacancy arose he was promoted with effect from 1-9-1964. So it is clear from the evidence adduced on the side of the respondent that the 4th claimant did not complete three years of service by 14-8-1967. So the respondent is justified in not giving one service increment.

16. So I hold on the dispute that is referred to this Tribunal for adjudication that the Management of Ramakrishnapur and Mandamari Divisions of Singareni Collieries Company Limited is justified in not granting one service increment to Kasipeta Posham, Kalagura Lingaiah, Jaida Rajam, Shot Firers of Ramakrishnapur 3 Mine and C. Muralidhar Rao, Sardar of Kalyanikhani No. 1 and 4 as per Wage Board recommendations with effect from 15-8-1967 and that these claimants are not entitled to any relief in these proceedings.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 9th day of February, 1973.

P. S. ANANTH, Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined	Witnesses Examined
For Workmen :	For Employers :
W.W. 1 K. Lingaiah	M. W. 1 P. T. Thomas.
W.W. 2 K. Posham.	M. W. 2 P. T. Thomas.

Documents exhibited For Workmen :

Ex. W. 1 Letter dated 4-5-64 of Agent, Ramakrishnapur addressed to the Manager, R. K. 4 and M. K. 4 transferring four workers from Shanti Khani to Ramakrishnapur Division as Acting shot firers.

Ex. W. 2 Minutes of conciliation proceedings held under sec. 12(4) of I. D. Act, 1947 at Mandamari on 7-11-70 between the Management of Singareni Collieries company Ltd., Rama Krishnapur and their workmen represented by Singareni Collieries Workers' Union.

Ex. W. 3 Letter dated 4-5-64 of Agent Rama Krishnapur addressed to the Manager, Ramakrishnapur 3 and MK. 3 that K. Lingaiah who has been transferred from Shanti Khani has reported to duty on 5-5-64.

Documents Exhibited For Employers :

Ex. M. 1 Copy of the letter dated 9/10-5-71 of Agent, M.M. & R.K. pur addressed to the Administrative Officer, Hyderabad regarding service increments to K. Posham, K. Lingaiah, J. Rajam and C. Muralidhar Rao.

Ex. M. 2 Copy of the appointments order dated 5-1-65 issued by the General Manager, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem to Ganta Mallareddy and K. Posham as shot firers.

Ex. M. 3 Copy of the appointment order dated 20-8-64 issued by the General Manager, Singareni Collieries Company Ltd., Kothagudem to Jaida Rajam and Kalagura Lingaiah as shot firers.

Ex. M. 4 Extract from circular No. P. 49/2782-II/2927, dated 13-10-67 of General Manager.

Ex. M. 5 Extract from General Manager's circular No. P. 49/2807/200, dated 27-1-68.

Ex. M. 6 Appointment Order dated 6-10-64 of C. Muralidhar Rao, Coal Cutter as Mining Sirdar.

Ex. M. 7 Extract from General Manager's Circular No. P. 49/2782-II/2927, dated 13-10-67.

P. S. ANANTH, Industrial Tribunal
[No. 7/34/70-LRII]

S.O. 902.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Belampalli, Post Office Belampalli (Andhra Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1973.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)

AT HYDERABAD

Present:

Sri P. S. Ananth, B. Sc., B.L., Industrial Tribunal, Hyderabad.

Industrial Dispute No. 10 of 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli.

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli.

Appearances :

Sri B. Ganga Ram, Vice President, Singareni Collieries Workers' Union Ballampalli—for Workmen.

Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli—for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by its Order No. 7/10/70-LRII, dated 10th December, 1970 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for adjudication to this Tribunal, namely:—

"Whether the action of the management of Shahti Khani, Bellampalli Division, Singareni Collieries Company Limited in not treating (1) Sarvashri Shaik Lal Mohammed, A Dominic and B. Jakkulu as Electricians (Category IV) and (2) Sarvashri Shaik Mohaboob, E. Mallesh, P. Laxmanrao and R. Rajam as Electrician helpers (Category II) with effect from fifteenth August, 1967, is justified, If not, to what relief are the workmen entitled?"

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 10 of 1971 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience the Singareni Collieries Workers Union, Bellampalli is referred to as the petitioners and the Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli is referred to as the respondent in the course of this Award.

2. The claimants in this case are represented by Singareni Collieries Workers' Union (hereinafter referred to as the said Union). The Vice President of the said Union filed a claims statement contending as follows:—Shaik Lal Mohammad, A. Dominic and B. Jakkulu are invariably being asked to

work as electricians right from 1965 onwards. They have been performing the jobs of electricians, namely, repairing of drill machines, repairing of Picross hauler starter, repairing of drill panel, repairing of signal bell, repairing of pump starter, under ground lighting, connections and disconnecting, dismantling of drill machine and compeling of all parts, repairing of vecoil switches, repairing of hauler controllers and inspection of all the machinery and plant and cable lay-out. The Manager, Shanti Khani by his letter dated 10th July, 1968 gave instructions to B. Jakkulu as shown in the claim statement. Similar instructions were given to Dominic and Shaik Lal Mohammad on 10th July, 1968 to perform various duties. The Manager, Shanti Khani *vide* his Charge Sheet dated 8th March, 1965 addressed A. Dominic, as electrician. Inspite of all these the management has been paying new Category II wages to Dominic, Shaik Lal Mohamad and Category I wages to B. Jakkulu. The Management is adopting unfair labour practice by extracting higher type of work and paying them lower category of wages. Shaik Mohboob, E. Mallesh, P. Laxman Rao and B. Rajam have been working as Electrical Helpers right from 1965. The play day list are sufficient to prove that they have been working as electrician helpers but in their case also the Management is adopting unfair labour practice and paying them category I wages and extracting higher type of work. The Management has been adopting evading tactics by not producing records although they had agreed through the settlement dated 25th May, 1969 to produce the records. When the Management did not implement the settlement dated 25th May, 1969 another strike notice dated 10th June, 1969 was issued and through the minutes of discussions held on 31st July, 1969 the management agreed to produce the records for verification. When the Union asked the Management to provide the daily maintenance report books, play day list, register of tools issue from the Stores from 1965 to 1967 for verification the Management did not produce the same although the Labour Enforcement Officer (Central) Mancherial came to Bellampalli twice during August and September, 1959. Since the Management violated the memo. of settlement dated 25th May, 1969 and minutes of discussion dated 31st July, 1969 a third strike notice dated 15th June, 1970 was issued and conciliation ended in failure and the dispute has been referred to this Tribunal for adjudication. The seniority and experience of the workmen are the two tests for promotion. In this Company the question of possessing an electricians certificate did not arise as a test for promotions. So the present demand is that Shaik Lal Mohamad A. Dominic and B. Jakkulu should be treated as Electricians and they should be given Category IV wages with effect from 15th August, 1967 and Shaik Mohboob, E. Mallesh, P. Laxman Rao and B. Rajam should be treated as Electrician Helpers and they should be paid Category II wages with effect from 15th August, 1967.

3. The respondent filed a counter statement contending as follows:—The reference is vague and bad in law and is liable to be dismissed in limini. The reason is that the Management is the sole authority in ordering its administration and routine work and when there are sufficient number of electricians and supervisory staff to man all the shifts it is not obligatory on the part of the management to treat the workers named herein as electricians and electrician helpers and the result of such an enquiry would be only to duplicate the present incumbants. Shaik Lal Mohamad and Dominic are working in the capacity of helpers and Jakkulu is working in the capacity of Category I mazdoor and it precludes any consideration for higher category unless there is vacancy. The Management denies the list of 10 duties that are being performed as shown in the claims statement. It is correct that they are performing elementary duties akin to those of similar nature as shown in job description against serial No. 22 under Category II (Semi-skilled lower). They are essentially mazdoors with an experience by practice only. The recommendations of the Central Wage Board are to the effect that instead of designating them as fitter mazdoor such workmen should be designated as fitter helper and no more. That the letter of the Manager, Shanti Khani has given a status of electrician is erroneous and misleading as it related to one particular aspect of certain work left wanting on the part of B. Jakkulu. That similar instructions were issued to A. Dominic and Lal Mohamad only go to show that from the point of view of safety they should see and draw the attention of Management in good time. That the similar letter that was served on Dominic on 8th March, 1965 is a warning not to shirk his responsibility. According to Wage Board recommendations equivalent category II was correctly fixed to A. Dominic and Lal Mohamad and Category I to B. Jakkulu. There is no necessity for the management to extract higher type of work when the strength and category of workmen required meet the demands of the pit. It is denied that Shaik Mohboob, E. Mallesh, P. Laxman Rao and B. Rajan have been working as electrician helpers from 1965. They came under the category of general mazdoors. Any reference to the play day lists is erroneous and misleading. The Management denies that no records were shown. The workmen have not worked continuously in higher capacity except on rare occasions when they were paid acting allowance. The Union has failed to do their part of duties in bringing specific cases of non-payment of acting allowance. That the Unions claim to be shown the list of records not existing is not justified. The Labour Enforcement Officer (Central) was at liberty to see whatever records the department was having and there was no necessity for breach of any understanding on simple issues. There was no occasion for the Management to violate the memorandum of settlement dated 25th May, 1969. It is admitted that promotion is a function of the management and the best judge for laying down conditions on technical matters the company is the appropriate authority. So the demands of Lal Mohamad, A. Dominic from Category II to Category IV is unjustified and more so in the case of B. Jakkulu who is only a Category I mazdoor. Shaik Mohboob, E. Mallesh, P. Laxman Rao and B. Rajam cannot be treated as electrician helpers for the reasons already stated.

4. The reference that is made for adjudication by this Tribunal is in two parts. The first part of the reference is whether the action of the Management in not treating Shaik Lal Mohamad, A. Dominic and B. Jakkulu as electricians Category IV with effect from 15th August, 1967 and the second Part of the reference is whether the action of the management in not treating Shaik Mohboob, E. Mallesh, P. Laxman Rao and B. Rajam as electrician helpers Category II with effect from 15th August, 1967.

5. So far as the first part of the reference is concerned the contention of the petitioners is that the management has adopted unfair labour practice by extracting higher type of work, namely work of Category IV electrician and paying them lower category wages. A Dominic and Shaik Lal Mohammad are in category II (new) and B. Jakkulu is in category I (New). So all these three claimants are claiming category IV (New) on the ground that they are doing the work of Category IV (new) electrician. The contention of the respondent is that these claimants are performing elementary duties as per the job description given in serial No. 22 under Category II (Semi-skilled lower) shown in Appendix V at page 44 of Volume of the Report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry (hereinafter referred to as the said Wage Board) and that the recommendation of the Wage Board is to the effect that instead of designating them as Fitter Mazdoor such workers should be designated as Fitter helpers and that so far as D. Lal Mohamad and Dominic are concerned they are working in the capacity of helpers and that Jakkulu is working in the capacity of mazdoor and that any consideration for higher category can arise only if there is a vacancy.

6. The petitioners have examined W. Ws. 1 to 5 and marked Exs. W. 1 to W. 12 on their side and the respondent has examined M.Ws. 1 and 2 and marked Exs. M. 1 to M. 5j. on its side. W.W. 1 (Shaik Lal Mohamad) is one of the claimants. He says that he is working as electrician in the bottom seam district in Shanti Khani, that he knows Dominic and Jakkulu since they have been also working as electricians in different shifts in the bottom seam district, that Dominic and Jakkulu have been doing the same work done by him and he has giving the list of the work done by him. He says that Ex. W. 5 is the charge sheet issued to A. Dominic and that it shows that A. Dominic was described as electrician. In his cross examination he says that first he joined Shanti Khani as daily mazdoor in old category I, that he does not remember the date when he was given old category II, that he does not remember the year when he was given old category III, that Dominic was also given old category III, that Jakkulu was only in old category I and he was given new category I, that old categories II and III are now equivalent to new category II and that electrician helper is shown as new category II, that he (W.W. 1) is an electrician and that it is not correct to say that he and Dominic are working as Electrical helpers. He further says that it is not correct to say that Jakkulu is

working as mazdoor in the general shift. He also says that it is not true that they attend the only minor repairs and that major repairs are done by electricians working in the shifts. He admits that there is only electrical incharge for each shift but he says that it is only he and the others who attend to the repairs and that the electrician in charge does not attend to any repairs. He says that he does not have any separate notice issued by the management asking him to do all the work mentioned in paragraph 1A in the claims statement except Ex. W.1. He says that when he was given new category II he filed a petition before 31st March, 1968 stating that he should be given higher category but he does not have copy of that petition. According to him there are vacancies of electricians in his pit, that is, in his mine. He also says that he does not have Wiremen and Electrician certificates.

7. W.W. 3 (Mohammad Ghalib) is working as electrician and he is in new category IV. He says that alongwith him N. Balakrishna and D.G.A. Lawrence are also working as Electricians, that he and the other two are working in three shifts one in each shift, that now he and the other are working in 54 dip district, that W.W. 1, Jakkulu and Dominic are working in three shifts one in each as electrician in bottom seam district, that they (he and the other two) do not go and work in bottom Seam District where other three electricians mentioned by him are working. In his cross examination he says that in three shifts there are only three new category IV electricians, that he and the other two were working in old category IV before the Wage Board came into force, that as per the Wage Board new category IV can be given only to those who were in old category IV, that there is Tradesmen agreement in Bellampalli Division, that as per that agreement there should be four category IV persons or not he does not know but actually there are only three category IV persons, that he does not know whether there are any vacancies in Shanti Khani for filling up category IV, that W.W. 1 and others did not have Wiremen or Electrical Certificates. According to him they are working just like him as electricians.

8. W.W. 4 (Birdula Rajam) says that he is working as electrician in Shanti Khani since 1956 as Shift Incharge, that he was working in old category VII and that he is in new category V, that W.W. 1 Dominic and Jakkulu are working as electricians in Bottom Seam District, that W.W. 2, one Lawrence and Balakrishna are also working as electricians in 54 Dip. District, that all these six electricians are doing the same kind of work, that the three electricians working in Bottom Seams District won't come and work in 54 District, that in the Company promotions were given by seeing seniority and experience, that no certificate was being insisted upon previously and that he does not have any certificate though he is working as Shift Incharge. In his cross examination he says that there are three category V Electricians and one category VI electrician for each shift, that Lawrence, W.W. 3 and Balakrishna are working in category IV, that if the demand of W.W. 1, Dominic and Jakkulu is conceded the total number would come to six in category IV, that it is not correct to say that if work is given to six persons there would be no work to the persons working in Category V and VI, that he does not know whether there is Traedsmen agreement and whether as per that agreement there should be only three persons in category IV, that it is not correct to say that no more persons of category IV is necessary for each shift in view of there being one person of category IV and one person of category V in each shift and that it is not correct to say that W.W. 1 and other workmen have been attending to minor repairs.

9. W.W. 5 (B. Jakkulu) is one of the claimants. He says that he is working in Bottom Seam in 3 Dip District as electrician continuously from 1965, that prior to that he was working at interval, that W.W. 1, Dominic and he work in three shifts in Bottom seam, that W.W. 3, Balakrishna and Lawrence are working as electricians of category IV in Middle Seam 54 Dip, that they are doing the same work that he (W.W. 5) W.W. 1 and Dominic are doing, that he is designated as daily mazdoor and he is asked to work as electrician in new category IV that the Manager gave him, the letter Ex. W. 6 asking him to inspect all the machinery and plant and cable lay out, that they also used to work on play days, that Exs. W. 7 and W. 9 are notices put up in that connection, that the shift incharge are Mohamad Ayub, Atau Hussain and Birdula Rajam (W.W. 4) who are in new Category V, that they supervise their work, that hitherto the company was giving promotions according to seniority and merit, that they never insisted on any qualifications or certificates and that he and other two are claiming new category IV as per Wage Board. In his cross examination he says that in the Company records his name is shown as daily mazdoor from 1965 but actually it is only electricians work that they are extracting from him, that the Company did not give him any order designating him as electrician but they are extracting work of electricians, that he was given category I, that he was given acting job as electrician in category II due to his seniority and his merit, that those who were in old category IV prior to that in each shift there used to be one shift incharge of category V and one Category IV man and category II man, that daily mazdoors are in category I and they work as helpers under Shift Incharge, that there are some more category I daily mazdoors on electrical side in Shanti Khani besides him, that he is being given acting allowance right from 1965, that it is not correct that he was given acting allowance only in 1968 and 1969, that he gave an application stating that he should be given category IV when he was being given acting allowance of second category, that he does not have a copy of the application now, that he did not give separate letter to Labour Enforcement Officer stating that he was being given category II allowance, though he is entitled to IVth category but he raised a dispute through his Union, that it is not correct to say that the Shift Incharge used to give only minor repair work to them, that it is not correct to say that it is only Shift Incharge who allots minor repair work to them and after doing the work they used to submit their report to the Shift Incharge, that in his District he is independent electrician, that it is not correct to say that he is not independent electrician and that the Shift Incharge supervises his work, that he was working as Helper under Khasim in general shift and when one Mohammad Syed who was working independently as Helper in B. Rajam's shift absconded, he (W.W. 5) was placed in Category II and asked to work in the place of that Mohammad Syed even before the Wage Board, that from that time onwards he has been working only as electrician and that when the Management did not give him new IVth category he did not give any application before 31st March to the Management asking for Category IV as he did not know about it. When he is shown Ex. W. 7 and asked, he says that on that day he was asked to check the surface hauler contacts and change them and he was given acting category II allowance and asked to do that work though it is an electrician's job. He further says that though in Ex. W. 6 it is mentioned as daily mazdoor actually the work mentioned there is done only by electricians and since he was doing the work of electrician he was given Ex. W. 6 letter, that such letters were given to W.W. 1 and Dominic also, that when they sent the application that they should be treated as electricians the Management replied that they were daily mazdoors, that he was given the letter the original of Ex. M. 3 that subsequent to Ex. M. 3 he appeared to have electrician certificate and when he was asked to produce the certificate from the Company stating that he had undergone practical training in the electrical side the company gave him a certificate that he worked as daily mazdoor and so his application for electrician certificate was rejected, that the Management orally informed them that they should not attend to high tension work and at the same time they were asking them to do that work in cases of breakdown.

10. M.W. 1 (M. Seralu) is working as Assistant Engineer in Shanti Khani. He says that the set up in electrical side in Shanti Khani is there is charge hand by name Narayya and next to him is one electrician by name Mohammad Khasim in category VI and next to him are Vth category electricians by name B. Rajam Ayub, Atau Hussain, Kalimulla Khan and next to them are category IV electricians by name Lawrence, Balakristna and Ghalib and next to them are three second category helpers by name Dominic, Lal Mohamad and Yellaiah, that category IV electricians work under Category V electricians, that the nature of duty of category II helper is that he should attend to elementary lower jobs like minor repairs of drill machines and their tracking cables, repairs of signal bells and signal lines and repairs of lighting cables, that Dominic and Lal Mohamad who are in category II also attend to the same semi-skilled lower jobs, that they are not repairing Pickroses hauler starter but they clean only the contact points, that they are not repairing drill panels, pump starters, Vecoil Switches, hauler

controllers, that they have nothing to do with the inspection of machinery and cable lay out, that it is only categories IV and V electricians who attend to the said repairs, that it is only on play days categories VI and V electricians attend overhauling of Hauler Starters, their switches Hauler controllers, cleaning of slip rings of the motors and over of H.T. and L.T. switchgears, that Jakkulu, Dominic and Lal Mohammad report to category V electricians about their routine work, that category V electricians never sent any report or made any representation that these three persons were doing other work besides semi-skilled lower jobs, that three persons never represented to him that he was extracting any higher skilled work besides semi-skilled lower jobs, that they have got one surplus category V electrician who is utilised in the place of category IV electrician vacancy, that Jakkulu, Diminic and Lal Mohammad did not appear for any State Electricity Board Examination, that they were never asked to detect any faults in H. T. or L. T. circuits and they never reported any such detection of faults to their superiors, that they were never asked to rectify any faults in any electrical machinery and switch gears, that W.W. 3 does not work along with claimants in this case, that it is not correct to say that his work and Lal Mohammad work is same, that it is not correct to say that the 10 duties referred to in the claims statement are done independently by Lal Mohammad and W.W. 3, that W.W. 3 is doing different work being in category IV, that Lal Mohammad, Dominic and Jakkulu depend on category V electrician for any work they cannot do during their shift, that they do not attend to any skilled job referred to in Wage Board, that Lal Mohammed and Dominic were in old category III and Jakkulu old category I and he is in new category I and that if a lower category worker works in higher category he would be paid the acting allowance being the difference between the two categories as per the practice of the company, that acting allowance was paid to all the claimants when they worked in higher category, that Ex. M. 4 is the statement prepared showing the acting allowance paid to the claimants, that they were paid acting allowance only intermitantly, that there was no representation received from them as regards any non-payment of acting allowance, that as Jakkulu is turning out semi-skilled lower job he is being paid acting allowance for category II, that he is not attending to any work turned out by category IV persons, that he (M.W. 1) did not entrust to him any of the works done by category IV persons, that there is no vacancy of category IV now, that it is not correct to say that Jakkulu is maintaining shift like Dominic and Lal Mohammad, that he calls categories IV and V electricians for his assistance, that Ex. M. 5 is the play day list register, that Ex. M. 5 (a) to M. 5 (j) wages shows the allotment of work of electricians and their helpers and they show the work allotted to the claimants, that Ex. W. 7 is the Play Day list signed by the Manager, that the work mentioned for Dominic there is category IV work and he was given acting allowance, that Ex. W.8 is the Play Day list for 1st June, 1965, that the work shown for Jakkulu there is category IV electricians work, that Ex. W. 9 is the Play Day list for the day 27th July, 1965, that the work shown for Lal Mohammad there is category IV electrician work, that Ex. M. 2 shows that reply was given stating that there were not electrical helpers, Ex. M. 3 shows that the persons mentioned there were tested and found that they had not picked up the required standard, that there are statutory books maintained and they are signed by categories IV and V electricians and Charge-Hands, that the claimants never use and they were never asked to use electrical instrumental like Megar, Voltmeter etc., that there were several occasions when these persons sought his help and the help of category IV and V electricians, that once Dominic came to his house on Play Day (*i.e.*) on 4th February, 1969 in the third shift in the night when he was acting as category IV electrician and informed him that the power supply to the surface installations and S. K. II pumps were interrupted and he went and inspected the lines and found that Dominic did not know how to switch on the switch, that they used to seek the help of category IV and V electricians whenever they had pump starter trouble, that he did not give any trade test to Dominic or Lal Mohammad and that there is no vacancy of category IV electricians now and that there is no expansion work in Shanti Khani.

11. In his cross examination he (M.W. 1) says that there are two seams in Shanti Khani and they are middle and bottom seams, that there is connection between the other two seams at two level, that the distance between the two seams will be two furlongs, that Jakkulu, Lal Mohammad and Dominic are working in bottom seam in three shifts by rotation, that middle seam 54 Dip is separate District and there three category IV are working that in this District there are four 60 H.P. each Hauler and one drilling machine that in middle seam 49 Dip and 54 Dip are nearer to each other and they are at a distance of 4,000 feet from bottom seam and that it is not correct to say that no one from middle seam can go and help in the bottom seam considering the distance, that they are going and helping the workers in the bottom seam, that he does not know whether Tradesmen agreement was not concelled, that a helper is a person who helps the electrician and who performs semi-skilled lower jobs, that if two troubles develop the electricians will depute the helper to attend to the minor job, that the instructions mentioned in Exs. W. 1 and W. 6 refer to roof falls and side falls on cables and switch gears and transformers and those things should be brought to the notice of the superiors but they have nothing to do with the supervisor of duties, that the job mentioned in Ex. W. 5 is the job of the electrician, that Ex. W. 7 shows that Dominic had to switch on the H. T. switch situated in 85 Dip Sub-Stations but Dominic could not do that work and so he came to his house and he went and switched on and that it is not correct to say that he is extracting higher category work from the lower category workmen and paying them only lower category wages and that it is also not correct to say that Dominic and Lal Mohammad and Jakkulu are doing work independently in bottom seam.

12. M.W. 2(B.P. Pai) is working as Manager at Shanti Khani. He says that the set up on the electrical side in any of the three shifts is there is one electrician of new category V who is responsible for the entire mine during his shift, that under him there are one category IV electrician, one Category II Helper and there is one electrical mazdoor of Category I, that there is also general shift and in this shift there are one electrical charger, one Category VI electrician and that the Assistant Engineer is above all these persons, that there is Tradesmen agreement for Bellampalli Division, that when compared to Tradesmen agreement there is one category V electrician is surplus, that the Bottom Seam and Middle Seam are interconnected and supervision is possible for both the seams, that category V electrician supervises the other electricians, that Shaik Lal Mohammed, Dominic and Jakkulu are supervised by higher category electrician, that they do not work independently, that in June, 1970 a circular order was issued prescribing qualifications for all the electricians., that the qualifications for Category IV electricians are; they should have studied upto 8th standard and they should posses Electrical Wireman Certificate granted by the State Government and they should have minimum three years experience on the Electrical side and they should preferably be holders of I.T.I. Diploma, that none of the claimants was Trade tested during his time, that so far as the Electrical side is concerned there is only over staff but not under staff, that Electrical Helpers are not authorised as electricians but in an emergency sometimes authorisation is given to them and if they capably attend to the work they would be given the allowance. In his cross examination he says that he does not know whether the Tradesmen agreement of the year 1961 is terminated or not, that Ex. W. 10 letter shows that the Tradesmen agreement of 1961 had been terminated, that so far as technical side is concerned the Assistant Engineer knows better but both of them would know well about the details of the machinery found underground that is the physical quantity, that in 54 Dip District Mohammed Ali and Balakrishna and Lawrence are working as IVth category electricians, that they are also attending to 63 Dip and 73 Dip in addition to 54 Dip, that in 49 and 43 Dips B. Rajam, Atau Hussain, Mohammad Ayub are working as Category V electricians, that Vth category electricians attend to all the machines there, that in Full Dip Bottom Seam District Shaik Lal Mohammad, Dominic and Jakkulu are working but they are sent there to attend to minor troubles only and they look after the machinery, that the distance between 3 Dip in Bottom Seam and 54 Dip in Middle Seam is about 4,000 Ft., that the distance between 3 Dip and 43 Dip is only less than 4,000 feet but it is not 7,500 feet, that the distance between 3 Dip and 43 Dip is only less than 4,000 feet but it is not 7,000 feet, that the distance between 54 Dip and 49 Dip is only 600 feet but it is not 2,000 feet, that the distance between 54 Dip and 43 Dip is only about 800 feet but not 2,000 feet, that the Bottom Seam District is a bit isolated, that the job of electrical helper is to attend to semi-skilled jobs, that what is meant in Ex. W. 6 is only spot inspection and any one can do spot

inspection, that spot inspection is the job of any one who is instructed to do that work, and it is only physical work involved but not any electrical work, that Ex. W. 1 also means only spot inspection and it only means physical work and he would see from a distance and come and report and no skill is required to do this spot inspection, that any one can be instructed to do this spot inspection if the Manager feels that he is capable of inspecting and submitting a report, that though in Ex. W. 5 Dominic is addressed as Electrician, it is only type error and the work mentioned there can be done by electrical mazdoor, that the job mentioned in Ex. W. 7 is that of an electrician, and the job mentioned in Exs. W. 7, 8 and 9 is that of the electrician, that it is not correct to say that Shaik Lal Mohammed, Dominic and Jakkulu are doing the work of electrician but they are not paid the correct wages due to them, that even if there is no Tradesmen agreement the correct strength is being maintained as fixed by certain norms decided by the Industrial Engineering Department, that he is not aware of the fact whether the Union had been informed about this strength but it is a study conducted by the management, that for Shanti Khani the Industrial Engineering Department has fixed the strengtth and it is one Charge-Hand, three category V electricians, four Category IV electricians, three Category II Helpers and three Category I Electrical Mazdoors, that he does not have the Industrial Engineering Department's report now, that the study was made in 1969 by the Industrial Engineering Department, that the study made by the Industrial Engineering Department and the Tradesman agreement are the same and practically there is no difference.

13. So from the evidence of the witnesses referred to above it is seen that W.W. 1 and Dominic were placed in new Category II after the recommendations of the Wage Board and W.W. 5 who was placed in new Category I has been attending to higher category jobs and that whenever they attended to higher category jobs they were given the acting allowance and that they have been under the supervision of higher category electricians, though these claimants claim to be doing work of category IV electricians independently. The evidence in this case also shows that the strength of Category IV Electricians had also been fixed under the Tradesmen agreement and that though the Tradesmen agreement is not in force still the strength continued the same and that there is also one surplus Category V electrician and that there are no permanent vacancies of Category IV electricians. Even W.W. 4 says that if the demand of W.W. 1 Dominic and W.W. 5 is conceeded the total number would come to six in Category IV whereas even as per the Tradesmen agreement the strength of Category IV Electrician was fixed at three. So even if it is assumed that these claimants had been doing the job of Category IV Electricians the question of giving them Category IV would arise only if there are permanent vacancies or if the strength of Category IV Electricians is increased. The evidence in this case whenever these claimants were asked to do higher category jobs they were being paid the higher category allowance and that there has not been any complaint made at any time that they were not paid any Acting Allowance. So under these circumstances it cannot be said that the action of the Management in not treating these three claimants as Electricians under Category IV is not justified. No doubt some evidence also had been let in to show on the side of the petitioners that the promotion to Category IV electrician was made only on the basis of seniority and experience and that no Technical Certificates were insisted upon and the respondent had adduced evidence to show that some Technical qualification is being insisted upon now. But so far as this aspect of the matter is concerned, it is not necessary to consider in the present proceedings whether the respondent is justified in introducing Technical qualifications and whether such introduction of Technical qualifications can be made retrospectively because this matter has to be agitated by the parties separately. So I do not propose to say anything about the Technical qualifications referred to by the witnesses examined on the side of the petitioners and the respondent. So far as the present proceedings are concerned all that has to be seen is whether the respondent is not justified in treating these three claimants as Category IV Electricians. Considering the evidence adduced in this case, I am satisfied that under the circumstances and in view of the fact that the strength of Category IV Electricians is fixed and in view of the fact that there are no more permanent vacancies of Category IV Electricians, the action of the Management in not treating these claimants in Category IV Electrician is justified. As and when vacancies arise in Category IV these claimants can urge for being promoted to those vacancies and it is open to the respondent to consider, their claim as the question of promotion is purely a managerial function. If in these proceedings it is held that the action of the Management in not treating these three claimants as Category IV Electricians is not justified, then it would be virtually directing the respondent to give promotion to these three claimants Category IV Electricians when there are no such vacancies existing.

14. So far as the second part of the reference is concerned the contention of the petitioners is that the four claimants relating to the second part of the reference have been working as Electrical Helpers right from 1965 that the Management is adopting unfair labour practice and paying them category I wages and extracting higher type of work. The contention of the respondent is that these four claimants come under the Category of General Mazdoors and so they can not be treated as Electricians Helpers. W.W. 2 (P. Lakshmana Rao) is one of the four claimants. He says that he is working as Electrical Helper, that other three claimants Shaik Mohaboob, Mallesh, and Rajam are also working as Electrical Helpers, that though they are working as Electrical Helpers, the Company writes in its record as Daily Mazdoors, that the work of Electrical Helper is to help shift incharge and do whatever work he gives, that they do small jobs entrusted by the shift Incharge, that they also used to work on Play Day and that they are entitled to new Category II from the time of Wage Board. In his cross examination he says that Ex. M. 1 is the application given by him, Malesh Rajam, W.W. 5 and Shaik Mohaboob, that the Manager sent the reply Ex. M. 2 but they told the Manager that they cannot work as Daily Mazdoors, and that they would work as Electrical Helpers, that they did not work as stipulated in Ex. M. 2, that none of them have any Wireman or Electrical Certificates, that there are orders to the effect that they should not attend to big electrical machines, that no Trade test was given to him, that if any examination is held he is prepared to appear, that it is not true to say that whatever work is done by them is that of General Mazdoor and so they are given new Category I.

15. W.W. 4 says that W.W. 2 and the other three claimants are working as Helpers continuously and that they go along with the Shift Incharge and do whatever work is entrusted by the Shift Incharge, that all small works are given to them, and that the Electricians give their report to the Shift Incharge. In his cross examination he says that it is not correct to say that W.W. 2 and 3 others mentioned by him are only Daily Mazdoors and not Helpers and so they are entitled only to Category I. W.W. 5 says that W.W. 2, Shaik Mohboob and Mallesh are working as Electrical Helpers. In his cross examination he says that there are some more Category I Daily Mazdoors, in the electrical side in Shanti Khani, that when he and others sent an application that they should be treated as electricians, the Management replied that they were Daily Mazdoors.

16. M.W. 1 says that the work entrusted to Shaik Mohboob Laxman Rao, Mallesh and Rajam is of carrying the tools of Category V Electricians, that they were in old Category I, that their new category is I, that apart from carrying the tools no other work is done by them, that they do not turn out any work of Category II Electrician and that the service particulars extracted in Ex. M. 4 are correct. In his cross-examination he says that an Helper is a person who assists the Electrician and who permorms Semi-skilled lower jobs, that when two troubles develop the Electrician will depute the Helper to attend to the minor jobs and that it is not correct to say that these four claimants are working as Helpers, but they are paying category I wages. M.W. 2 while speaking about the set up on the electrical side in each shift says that there is one electrical Mazdoor of Category I in each shift and that Shaik Mohboob, Mallesh and Laxman Rao are working under Category V Electricians. In his cross examination, so far as these four claimants are concerned, he says that they are paid the wages of Helpers if they work as Helpers and that they are paid the wages of mazdoors when they work as mazdoors; but it is not correct to say that though they are working as Helpers they are being paid wages as Mazdoors.

17. So from the evidence of these witnesses it is seen that so far as these four claimants are concerned they are only Electrical Mazdoors working under Category V Electricians

and that when they gave the application Ex. M. 1 in the year 1968 requesting that they should be sent to the job of Electrical Helpers, the Management gave the reply Ex. M. 2 stating that they were only Electrical Mazdoors and that they cannot be given job of Electrical Helpers. The job description given for Fitter Helper under Serial No. 22 in Appendix V at page 44 of Volume I of the report of the recommendations of the Wage Board is that he is a man who has gained some experience as a Fitter Mazdoor and has improved his status by practice until he can do elementary fitting work and that he may be mechanical or electrical helpers as the case may be. So it is only such persons who should be treated as Category II (semi-skilled Lower) as per the recommendations of the Wage Board. Now from the evidence of M.W. 1 it is seen that these claimants are doing the work of only carrying the tools of Category V Electricians and that apart from carrying the tools no other work is done by them and that they do not turn out any work of Category II. It is also seen from Ex. M 4 that whenever these claimants are asked to do higher category work, that is, the work of category II worker, they are paid Acting Allowance and it is not the case of these claimants that the nature of the work done by these claimants, simply because now and then they are asked to do the work of Category II worker, it cannot be said that the action of the Management in not treating them as Electrical Helpers is not justified. As already stated, the evidence in this case shows that whenever they are asked to do the work of Category II worker they are paid Acting Allowance. If it is he case of these claimants that they should be promoted to Category II then this Tribunal cannot entertain such a claim because the question of giving promotion is purely the managerial function. No doubt some evidence had been let in on the side of the petitioners to show that the practice in this Company was to give promotion only on the basis of seniority and experience and some evidence had been let in on the side of the respondent to show evidence that some Technical qualifications are fixed now, but it is not necessary to consider in these proceedings the question whether the respondent is entitled to fix any qualifications restrospectively and this aspect of the matter has to be considered only in separate proceedings. If there are any vacancy in Category II to be filled up it is open to these claimants to request the respondent to give them promotion and it is open to the respondent to consider their request on merits. If in these proceedings it is held that these claimants are entitled to new Category II then virtually it would amount to a direction given to the respondent to give promotion to Category II. Certainly such direction cannot be given. All that has to be seen in the present proceedings is, considering the nature of the work done by these claimants and the job description given in the recommendations of the Wage Board whether, the action of the Management in not treating these claimants as Electrical Helpers (Category II) is not justified. Considering the evidence adduced in this case, I am satisfied that so far as these claimants are concerned the action of the Management in not treating them as Electrician Helpers (category II) is justified. As already stated if these claimants claim to be promoted to Category II then it is a matter which has to be agitated separately.

18. For all the aforesaid reasons, I hold on the dispute that is referred to this Tribunal for adjudication, that the action of the Management of Shanti Khani, Bellampalli Division, Singareni Collieries Company Limited in not treating (1) Sarvashri Shaik Lal Mohammad, A. Dominic and B. Jakkulu as Electricians (Category IV) and (2) Sarvashri Shaik Mohboob, E. Mallesh, P. Laxman Rao and R. Raiam as Electrician Helpers (Category II) with effect from fifteenth August, 1967, is justified and so the claimants are not entitled to any relief in these proceedings.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 12th day of January, 1973.

P. S. ANANTH, Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined for Workmen:	Witnesses Examined for Employers:
W.W.1. Shaik Lal Mohammed.	M.W.1. M. Seralu.
W.W.2. P. Lakshmana Rao.	M.W.2. B. P. Pai.
W.W.3. Mohammed Ghalib.	
W.W.4. Birdla Rajam.	
W.W.5. B. Jakkulu.	

Documents Exhibited for Workmen

Ex.W.1. Letter dated 10th July, 1968 of Manager, Singareni Collieries Co. Ltd., Shanti Khani addressed to A. Dominic and Shaik Lal Mohammed.

Ex.W.2. Minutes of conciliation proceedings held on 30th June, 1970 under Sec. 12(4) of I.D. Act between the workmen represented by the S.C. Workers' Union and Employers of S. C. Company Ltd., Bellampalli.

Ex. W. 3. Copy of the memo. of settlement arrived at between the Management and Workmen represented by the S.C. Workers' Union, Bellampalli under Sec. 12(3) of I. D. Act. on 24th and 25th May, 1969.

Ex.W.4. Copy of minutes of discussions held by Asstt. Labour Commissioner (C) Hyderabad on 31st July, 1969 with the Management of S.C. Co., Ltd., Bellampalli and the S.C. Workers' Union.

Ex.W.5. Charge sheet dated 8th March, 1965 of Sri A. Dominic issued by the Manager, Shanti Khani.

Ex.W.6 Warning given by the Manager, Shanti Khani to B. Jakkulu on 10th July, 1968.

Ex.W.7. Play Day work list on 4th February, 1969 issued by Manager, Shanti Khan.

Ex.W.8. Play Day work list on 1st May, 1965 issued by Manager, Shanti Khani

Ex. W.9. Play day work list for 27th July, 1965 issued by Manager, Shanti Khani.

Ex.W.10 Copy of the letter of Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) New Delhi dated 15th April, 1971 addressed to the General Manager, Singareni Collieries Co. Ltd., Kothagudem, Agent, S. C. Co. Ltd., Bellampalli Division, Agent, Mandamari Division, and the President Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli.

Ex. W.11. Letter dated 13/14th April, 1970 of the Agent S. C. Co. Ltd., Bellampalli division addressed to the Asstt. Labour Commissioner (C), Hyderabad.

Ex.W.12. Agreement between the Management of S.C. Co. Ltd., Ramagundam Divisions I and II and their workmen represented by the S. C. Workers' Union regarding the review of Categorisation and the strength of Tradesmen working in the workshop, Ramagundam Division I and II arrived on 4th October, 1966 under the I. D. Act (Central) Rules.

Documents Exhibited for Employers

Ex.M.1. Representation 5 workers dated 17th August, 1968 addressed to the Manager, Shanti Khani.

Ex.M.2. Reply dated 19th August, 1968 of the Manager, Shanti Khani to 5 workers.

Ex.M.3. Memo dated 22nd October, 1965 of Manager, Shanti Khani to 5 workmen.

Ex.M.4. Statement showing the number of days on which the workmen got higher category and paid acting allowance.

Ex.M.5. Play day work gist book.

Ex.M.5(a) page 16 of Ex. M. 5.

Ex.M.5(b) page 23 of Ex.M.5.

Ex.M.5(c) page 28 of Ex. M. 5.

Ex.M.5(d) page 39 of Ex. M. 5.

Ex.M.5(e) page 44 of Ex. M.5.

Ex.M.5(f) page 46 of Ex. M. 5.

Ex.M.5(g) page 53 of Ex. M.5.

Ex.M.5(h) page 63 of Ex. M. 5.

Ex.M.5(i) page 70 of Ex. M.5.

Ex.M.5(j) page 72 of Ex. M. 5.

[No. 7/10/70-LRII.]

P. S. ANANTH, Presiding Officer

New Delhi, the 15th March, 1973

S.O. 903—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Damua Colliery, Kalichhapar Colliery and Damua Hidargarh Siding and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th March, 1973.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR

New Delhi, the 19th February, 1973

Present :

Mr. Justice S. N. Katju, Presiding Officer.

Case ref. No. CGIT/LC(R)(12)/1970

(Notification No. 1/3/70-LRII dated 23-10-1970)

Parties :

Employers in relation to the management of M/S Damua Colliery, Kalichhapar Colliery and Damua Hirdagarh Siding and their workmen represented through the Satpura Koyala Khadan Mazdoor Congress, P.O. Junnardeo, Distt. Chhindwara (M.P.).

Appearances :

For employers: Sri D. M. Dharmadhikari Advocate.

For workmen: Sri Gulab Gupta Advocate.

Industry: Coal Mines. **District:** Chhindwara (M.P.).

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 (hereinafter called the Act).

The questions referred to this Tribunal as set out in the schedule to the reference are as follows:—

"whether the management of Damua Colliery, Kalichhapar Colliery and Damua Hirdagarh Siding belonging to Messrs Kanhan Valley Coal Company Private Limited, Messrs C. P. Syndicate Private Limited and Messrs Byramji Mining Combined Private Limited respectively is justified in not paying—

(i) Difference of wages from the 15th August, 1967 to the 12th November, 1967;

(ii) Variable Dearness Allowance as per Wage Board Recommendations at the rates of Rs. 1.11 per day from the 1st October, 1967, Rs. 1.47 per day from the 1st April, 1968 and Rs. 1.29 per day from the 1st October, 1969;

(iii) Other benefits in accordance with the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry as accepted by the Government of India, in their Resolution No. WB-16(5)/66, dated the 21st July, 1967.

If not, to what relief are the workmen entitled".

It is alleged on behalf of the workmen that the Damua Colliery, Kalichhapar Colliery and Damua Hirdagarh Siding are three industrial establishments which are managed by Sri D. P. R. Cassad and all the aforesaid three establishments are sister concerns. The workmen employed in the three establishments are members of the M. P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (hereinafter called the Sangh) which is a registered and recognised Union of the workmen. According to the workmen the Central Government appointed the Central Wage Board in 1962 for determining the new wage structure for the coal mining industry in the country. The aforesaid three establishments were represented before the aforesaid Board by the Sangh as also by certain other Associations of workmen of which they were members. The Sangh, however, represented the workmen directly and also through the Indian National Mine Workers Federation. The Board published its recommendations providing for a new wage structure for the workers employed in the Coal mining industry. The recommendations of the Board were accepted with certain modifications by the Government of India which recommended its implementation to the various employers in Coal industry including the employers in the present reference with effect from 15-8-1967. It was alleged by the workmen that at first the employers before me refused to implement the said recommendations of the Board. The Sangh along with the other Unions served a strike notice for forcing the management to implement the aforesaid recommendations. Thereafter the M.P. and Vidharba Mining Association of which the employers in the present reference were members called a meeting of all the Trade Unions and Employers at Nagpur on 30-9-1967 for considering the question of implementation of the aforesaid recommendations of the Board. In the aforesaid meeting the employers in the present reference were represented by Sri D. P. R. Cassad and the Sangh was represented by Sri K. P. Vishwakarma and Sri G. C. Bhattacharjee. The meeting resulted in an agreement dated 30-9-1967. According to the workmen, the employers did not implement the terms of the aforesaid agreement and the Sangh gave another strike notice on 9-11-1967. It resulted in a conciliation proceeding which was held on 15-11-1967 and on the same date viz. 15-11-1967 another agreement was reached between the parties before the Regional Labour Commissioner. According to the workmen, after the second settlement the employers in the present reference started making certain payments in accordance with the recommendations of the Board but the terms of the agreement were again not fully and properly implemented particularly with regard to the Variable Dearness Allowance and Railway Fare. Further more, the employers did not implement the terms of the agreement with regard to temporary loaders and contractor's workers who were employed in the mine. The employers have contended that they had only agreed to implement the recommendations of the Board with regard to basic pay of the workmen from 12-11-1967 and not from an earlier date. It was further contended by them that the aforesaid agreements do not relate to payments of Variable Dearness Allowance and other benefits as claimed by the workmen. It was further contended by them that they had no capacity to bear the increased financial burden on them.

In reply it was urged on behalf of the workmen that consideration of financial burden might be relevant in a case where new obligations were being imposed but had no relevance in cases where liability had already been incurred by the employers.

It is necessary to set out the relevant portions of the aforesaid two agreements. The first agreement runs thus:—

"At a meeting of the M.P. and Vidharbha Coal Committee held on Saturday 30th September with representatives of recognised union with regard to the implementation of the Wage Board recommendations accepted by the Government, it was agreed that the payments at the full new rates of the wages would be paid from the 1st payment day after of the 15th October 1967. Those collieries/companies in

financial difficulties may explain to the Unions their difficulties and may negotiate with their Unions at unit level to vary the above date, but preferably not later than the 1st November, 1967.

The question of arrears wages payable from 15th August 1967 to the agreed date of the date of implementation would be discussed at a later meeting to be held before the 1st November, 1967.

On the above understanding the unions agreed to advise their constituents to withdraw the strike notice fixed for October 3rd, 1967".

The second agreement says that:—

".....After discussion and conciliation today the 15th November, 1967, the following was settled:—

1. That all the weekly paid workmen shall be paid their wages as per recommendations of Central Wage Board for Coal Mining Industry w.e.f. 12-11-1967 i.e. the first payment shall be made on 25-11-67.

2. That payment as per recommendations of the Wage Board for Coal Mining Industry in respect of monthly paid workmen and staff shall be made effective from 12-11-67.

3. The strike notice dated 9-11-67 referred above stands withdrawn and hunger strike shall be withdrawn forthwith. Regarding arrears prior to 12-11-67, the matter shall be separately (discussed) with the Union and management.

....."

On 17-2-1971 Sri D. M. Dharmadhikari the representative of the employers stated before the Tribunal that:—

"The terms of reference which are covered by the two settlements cannot be made the subject matter of the Industrial Dispute and the reference to that extent is bad in law."

The Tribunal thereupon directed Sri Dharmadhikari to specify by 5th of March 1971 the terms of reference "which are covered by the two settlements and are consequently bad in law according to him." He was further directed to specify by the same date the terms of reference "which are contrary to those settlements and are consequently invalid according to him." In his reply dated 5-3-1971, Mr. Dharmadhikari stated that none of the items mentioned in the reference was covered by the two agreements. He has contended that the reference before me is incompetent because it is solely based on the recommendations of the Wage Board and further that it is not based on the two agreements. He has further contended that since the second agreement was arrived at in conciliation proceedings before the Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur the implementation of the terms of the agreements cannot be made the subject matter of a reference to this Tribunal. Mr. Gulab Gupta who appeared on behalf of the workmen conceded that the recommendations of the Board were only of an advisory character. The fact, however, remains that some of the said recommendations were accepted by the employers and the unions concerned and it is not the implementations of the recommendations of the Board which is the subject matter of dispute before me but the implementation of the terms of the agreements which had been arrived at between the parties and in which it was agreed that the recommendations of the Board should be accepted to the extent as mentioned in the agreements. Therefore the dispute relates to the interpretation and implementation of the terms of the said agreements and it does not relate solely to the question of implementation of the recommendations of the Board. Further, if there had been no controversy with regard to the terms of the aforesaid agreements there may have been some force in Mr. Dharmadhikari's contention that the dispute could not have been subjected to a reference to this Tribunal. The controversy that has arisen relates not only to the implementation of the terms of the two agreements, but also to the interpretation of their terms. The workmen have contended that the questions of payment of Variable Dearness Allowance and Railway fare were included in the terms of the aforesaid agreements. Mr. Dharmadhikari has strenuously argued that the two agreements have specifically omitted the mention of any payment of Variable Dearness Allowance to the workmen and the terms of the agreements relate only to the basic wages payable to the workmen and to that extent only the employers had agreed to accept the recommendations of the Wage Board It was contended that since the questions of Variable Dearness Allowance and Travelling Allowance were pointedly omitted from the terms of the aforesaid agreements, it is not open to the workmen to say that under the terms of the said agreements they are entitled to any Variable Dearness Allowance or Travelling Allowance as claimed by them. It is, therefore, obvious that the question of the interpretation of the terms of the aforesaid agreements has to be considered and the workmen were fully justified in taking up the dispute before the Central Government which rightly made a reference to this Tribunal for consideration of the questions involved in the dispute between the parties.

Before I proceed further, it is necessary to deal with another question that was raised by Mr. Dharmadhikari. The present reference before me was received in this Tribunal on 16th November, 1970. Mr. Dharmadhikari stated before the Tribunal on 19th July, 1972 that the lease in favour of the management had been cancelled. Thereafter he made an application for impleading the National Coal Development Corporation Ltd. which according to him had been asked by the State Government to run the mines after the cancellation of the lease in favour of the management. It may be also mentioned that the employers had given an application on 22nd July, 1972, for postponing the hearing. I gave "three weeks time and no more" and further directed that "if the management was unable to proceed further within three weeks the reference may be heard *ex parte*". Thereafter on 19th August, 1972, the aforesaid application for impleading the N.C.D.C. Ltd. was made by the management. Admittedly the lease in favour of the management was cancelled on 6th March, 1972. Since the application was belated and the management had not given sufficient cause to show that N.C.D.C. Ltd. was a necessary party in the presence proceedings, I rejected the said application. I, however, gave the management time "to summon any documents from the N.C.D.C. Ltd." The management gave an application on 21st September, 1972 for production of certain documents by the N.C.D.C. Ltd. The N.C.D.C. Ltd. have intimated to this Tribunal by its letter dated 5th January, 1973 that :—

"List of documents as enclosed in the annexure were being maintained at Head Office of M/s. C. P. Syndicate (Pvt.) Ltd. and M/s. Kanhan Valley Coal Co. (Pvt.) Ltd. Byramji Town, Nagpur-1 and not at the colliery level.

Under the circumstances as above, we are unable to produce the said documents.....".

Again on 16th February, 1973 Sri Dharmadhikari made another application for impleading the Central Government through the Custodian appointed under the Coal Mines (Taking over of the management) Ordinance 1973. I directed that "since I had not thought it fit to implead N.C.D.C. Ltd. as a party to this reference there is no force in the contention that the Central Government through the aforesaid Custodian should be impleaded as a party". I, therefore, rejected the aforesaid application of the management.

The main controversy between the parties centres on the interpretation of the terms of the aforesaid two agreements. In the agreement dated 20tht September, 1967 it was agreed that :—

"payments at the full new rates of the wages would be paid from the 1st payment day after the 15th October 1967".

It was, however, mentioned that those collieries/companies in financial difficulties may negotiate with their unions at unit level to vary the above date viz., 15th October 1967 but "preferably not later than the 1st November, 1967." Mr. Gulab Gupta has argued that the expression "payment of the full new rates of the wages" implies the "payment of basic wage together with the Variable Dearness Allowance. He has argued that the definition of wages in Sec. 2

of the Act is wide enough to include such allowance including the Variable Dearness Allowance as the workmen are for the time being entitled to. According to him, the recommendations of the Board provide for (1) Basic wages, (2) Dearness Allowance, (3), Other allowances, (4) Benefits which are payable to a workmen as his wages

The second agreement dated 15-11-1967 says that all the weekly workmen shall be paid their wages as per recommendations of the Board with effect from 12-11-1967 and payment as per recommendations of the Board in respect of monthly paid workmen and staff shall be made effective from 12-11-1967. Mr. Gulab Gupta has argued that the two agreements took into the considerations the recommendations of the Board which provide for payment of wages with effect from 12-11-1967 and in interpreting the expression "full new rates of wages" in the first agreement and "wages" in the second agreement, taking into consideration the scheme of the recommendations of the Board as also the meaning of the expression "wages" in the Act, it can not be said that the two agreements were confirmed only to basic wages payable to the workmen and not to basic wages together with the Variable Dearness Allowance and Travelling Allowance payable to the workmen. Mr. Dharmadhikari contended that the terms of the two agreements should not be interpreted as if they were statutes and the meaning of the term "wages" as given in the Act should not be taken into consideration. It is true that the terms of the two agreements cannot be interpreted as if they were statues and it is not necessary to place reliance on the definition of the expression "wage" as given in the Act. The second agreement, however, pointedly referred to the recommendations of the Board and says that the workmen shall be paid their wage given to a workman is the minimum wage to which from 12-11-1967. The expression wages as applied to workmen in industrial fields necessarily includes any Variable Dearness Allowance to which they are entitled to. The basic wage given to a workman is the minimum wage to which he is entitled to taking into consideration his personal needs and those of his family. The basic wage is necessarily linked with the prevailing price structure. If a workman is given Rs. 100/- per month as basic wage it implies that his pay packet of Rs. 100/- will give him sufficient money to provide for his needs and that of his family. If, however, prices rise and the purchasing power of Rs. 100/- is reduced then an additional allowance by way of dearness allowance is given him to make up for the loss incurred by him in consequence of rise in prices. It would follow that where prices fluctuate the quantum of dearness allowance will rise and fall along with the changes in the prevailing price structure and whatever is paid to a workman by way of dearness allowance must form part of the wages to which he is entitled to. The aforesaid two agreements used the word "wages" and not "basic wages". I am, therefore, not prepared to hold that the two agreements and particularly the second agreement was confined to basic wages payable to workmen and not to wages including the Variable Dearness Allowance payable to them. Admittedly, in addition to the basic wages payable to the workmen as recommended by the Board with effect from 12-11-1967, the management further paid Re. 0.78 p. per day to the workmen as Variable Dearness Allowance. It is, therefore, not open to the management to say that they only agreed to pay basic wages to the workmen and not any additional amount by way of Dearness Allowance. I have, therefore, no hesitation in holding that according to the terms of the second agreement the workmen are entitled to receive Variable Dearness Allowance with effect from 12-11-1967 in accordance with the recommendations of the Board. The question of "arrears of wages" which would include dearness allowance also, payable to the workmen from 15-8-1967 to 12-11-1967, the date which was specifically mentioned in the second agreement, was left over for subsequent discussions between the parties. Admittedly, no agreement was arrived at between the parties with regard to payment of Variable Dearness Allowance from 15-8-1967 to 12-11-1967. In the absence of any provision in the agreement between the parties with regard to payment of Dearness Allowance to the workmen for the aforesaid period they are not entitled to claim any difference in Variable Dearness Allowance from 15-8-1967 to 12-11-1967. If any amount, at a lesser rate as recommended by the Board, was paid to the workmen by the management for the aforesaid period between 15-8-1967 to 12-11-1967 then in that case they were entitled to receive it there could be no question of taking back such amounts from the workmen by the management.

It was not disputed on behalf of the management that the Variable Dearness Allowance on the basis of the All India Average Consumer Price Index No. and payable in accordance with the Board's award was at the rate of Rs. 1.11 per day from 1st October, 1967, Rs. 1.47 per day from 1st April, 1968 and Rs. 1.29 per day from the 1st October, 1969. As mentioned above, the workmen have been paid only Re. 0.78 p. per day as Variable Dearness Allowance for the aforesaid periods and they are entitled to claim the balance due to them.

The workmen are further entitled to the Railway fare on the basis of the Wage Board's recommendations as calculated at the new rates of wages to which they are entitled to under the said agreements.

Lastly, it was contended that the terms of the agreements were not applicable to M/s. Byramji Mining Combined Pvt. Ltd. It appears that M/s. Byramji Mining Combined carries on the work of transportation of coal from the mines to the railway siding. The workmen of this concern carry coal from the mines to the railway siding and put them in wagons. It cannot be said that transportation of coal from the mines to the railway siding is unconnected with the work of mining industry and the workmen of M/S Byramji Mining Combined should be treated as persons who are not employed in the Mining Industry. It is obvious that all the wagon loaders, particularly pushers and workmen engaged in carrying coal and loading wagons come within the ambit of the two agreements between the parties. I have no hesitation in holding that the workmen of M/S Byramji Mining Combined Private Ltd. are as much bound by the two agreements between the parties as the workmen of the other concerns. My answer to the reference, therefore, is that the management of the Damua Colliery, Kalichhapar Colliery and Damua Hirdagarh Siding belonging to M/S Kanhan Valley Coal Company Private Limited and ramji Mining Combined Private Limited respectively are justified in not paying the difference of wages by way of Variable Dearness Allowance from the 15th August 1967 to 12tht November, 1967. If any such amount has already been paid the workmen are entitled to retain the said amounts. But the workmen of the aforesaid concerns are entitled to the difference in Variable Dearness Allowance between the rate of Re. 0.78 p. per day which has already been paid to them, and the rates of Rs. 1.11 p. per day from 13th November, 1967, Rs. 1.47 p. per day from 1st April, 1968 and Rs. 1.29 p. per day from 1st October, 1969 as per recommendations of the Central Wage Board. The workmen of the aforesaid concerns are further entitled to railway fare on the basis of the Wage Board's recommendations and calculated at the new rates of wages. I make my award accordingly. I make no order for costs.

S. N. KATJU, Presiding Officer

[1/3/70-LR II]

S.O. 904.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act., 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sigareni Collieries Company Limited Mandamari Division, Post Office Kalyan Khani (Andhra Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1973.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Present :

Sri P. S. Ananth, B.Sc. B.L., Industrial Tribunal, Hyderabad.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 50 OF 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Co. Ltd., Mandamari Division, P. O. Kalyani, Khani.

A N D

Management of Singareni Collieries Co. Ltd, Mandamari Division, P. O. Kalyani Khani.

Appearances :

Sri A. Lakshmana Rao, Advocate for Workmen.

Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer, S. C. Co. Ltd., Bellampalli and Sri D. Gopala Rao, Member, F. C. C. & I. of A. P., for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by its order No. L-2112/7/71-LR. II dated 29.6.1971 referred the following dispute under Section 10 (1) (d) of the Industrial Dispute Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act.) for adjudication to this Tribunal, namely :—

> Whether the action of the management of Mandamari Division of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kalyan Khani (Andhra Pradesh), in terminating the employment of Shri Bura Rajesham, Coal Cutter of Kalyan Khani No. 2 Incline, with effect from the 21st June, 1972, is justified? If not, to what relief is the workman entitled ?"

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 50 of 1971 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience the claimant is referred to as the petitioner and Singareni Collieries Company Limited, Mandamari Division is referred to as the respondent in the course of this award.

2. The petitioner field his claims statement contending as follows. The petitioner was permanently employed as Coal Cutter and he had put in about ten years of service. On 3.9.1966 there was an accidental explosion on in the mine and the claimant was seriously injured with fractures in both legs and feet and received injuries all over his body. He was admitted in the Company's Hospital at Bellampalli where he was treated as an inpatient for six months. Then he was shifted to the Company's hospital at Mandamari and was treated as inpatient for about two months. The wounds did not heal and the bone pieces in Tibia were not removed. When he could not even stand and walk normally, in that state of health the petitioner was discharged from the Hospital on 21.6.1967. As the claimant found himself to be still in bad state of health he got himself admitted in the Nizam's Orthopaedic Hospital, Hyderabad for treatment on 14.7.1967. He was treated for some time in the said Hospital and later on he underwent treatment in M.G.M. Hospital, Warangal from 30.9.1967 to 6.10.1967. During the period of sickness the Management discharged the petitioner from service by their Order dated 25.6.1967. The Management relied upon the opinion given by their Medical Officer and the Company's Medical Board. The petitioner was discharged from the Hospital on 28.8.1967. After this whole treatment the petitioner was declared fit by the Andhra Pradesh Regional Medical Board and the petitioner demanded reinstatement with back wages as Coal Cutter as the discharge was neither proper nor justified. The petitioner filed W. C. Case No. 491/1968 wherein the Commissioner for Workmen's Compensation decided and treated the entire period from 3.9.1966 to the date of finding by the Andhra Pradesh Regional Board i.e. 16.9.1969 as period of Medical Treatment and directed payment of half monthly wages. The Company paid half monthly wages after deducting the amount paid earlier. The Management relied upon the opinion of the Company Medical Board recommending loss of 30% earning capacity and while awarding compensation on that basis discharged the petitioner as unfit for work. The finding of the Commissioner for workmen's compensation that the petitioner was under treatment till 16.9.1969 became final and this finding is binding upon both the petitioner and the respondent. During the course of the conciliation the respondent was willing to reinstate the petitioner with continuity of service as Coal filler but the petitioner was not willing for that job since the duties of Coal Filler are more arduous and piece rate. So the Management should be directed to reinstate the petitioner as Coal Cutter with continuity of service.

3. The respondent filed a counter contending as follows: The petitioner was working as Coal Cutter in Kalyani Khani No. 2 Incline. He met with an accident on 3.9.1966 and he was treated in the Company's Hospital as Bellampalli. The Medical Board which examined the petitioner declared him unfit for further service and the compensation for the loss of earning capacity was determined at 30 per cent. The petitioner submitted his application dated 8.10.1967 with medical certificate of Nizam's Orthopaedic Hospital, Hyderabad with a recommendation for light job. He was re-examined and was declared unfit for underground work by Surgeon, Bellampalli Colliery Hospital and the petitioner was informed about the same. The petitioner filed claim before the Commissioner for Workmen's Compensation and half monthly compensation from the date of accident to 16.9.1969 was awarded by the Commissioner and the respondent paid Rs. 3,885/- as a final settlement in the case. It is denied that the respondent is bound by the certificates issued by the Government Medical Board. So the discharge of the petitioner on 21.6.1967 was justified and was in consistence with the rules and practice. The Management cannot agree for reinstatement of the petitioner or give employment to him on any time of job as he is not fit to work in underground. So there is no justification for the present claim.

4. The respondent filed an additional counter contending that the dispute remained as an individual dispute since the petitioner alone had signed in the claims statement and so it is not maintainable that there is no dispute in terminating the service of the petitioner who was declared unfit for work in around the mines due to his involvement in an accident, that the petitioner in not workman under the definition filling under Section 2 (s) of the said Act and that the reference itself is bad and not competent.

5. Later on another claims statement was filed by the Secretary of Andhra Pradesh Singareni Colliery Mazdoor Sangh, Kothagudem, on behalf of the petitioner on almost the same lines as the claim statement filed by the petitioner in person with some more additional facts which need not be mentioned in detail.

6. Subsequent to the filing of the claims statement by the Secretary of the said Sangh the respondent filed an additional counter on the same lines as the original counter and mentioning about some more facts which need not be referred to in detail.

7. When the matter was taken up for enquiry the respondent's representative represented that the petitioner was not fit to work as Coal Cutter and the petitioner represented that he was prepared to work if any surface job was given and so the respondent's representative requested time for consulting the Management. At request of the parties the matter was adjourned from time to time for reporting settlement. On 12.2.1973 the parties filed a memo. of compromise to the effect that the petitioner was taken into service as a Shale Picker and that the matter was fully and finally settled and the same was recorded. The petitioner's counsel represented that it should be made clear that there is no break in the continuity of service and the respondent's representative stated that a separate letter was given stating that there won't be any break of service and the petitioner's counsel represented that this fact also may be mentioned in the award itself.

8. Now it is seen that the present dispute arose since the services of the petitioner, who was working as Coal Cutter and who had met with an accident, were terminated as he was found unfit to work underground. Since the petitioner himself represented that he was prepared to work on any surface job the Management had considered his request and now the Management had employed the petitioner as a Shale Picker. So the settlement arrived at is a fair settlement under the circumstances of this case. It also now represented by the respondent's representative that a letter had already been given stating that the petitioner will have continuity of service. I am satisfiled that award can be passed in terms of the settlement arrived at.

9. In the result award is passed in terms of the settlement. A copy of the memo. of compromise shall be attached to the award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 12th day of February, 1973.

P. S. ANANTH, Presiding Officer.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

I.D. No. 50 of 1971

Workman of Singareni Collieries Co. Ltd.

Vs.

Singareni Collieries Company Limited.

MEMO. OF COMPROMISE

This Memo. of Compromise Sheweth:

The Govt. of India made the following reference to the Industrial Tribunal, Hyderabad.

"Whether the action of Management of Mandamari Division of Singareni Collieries Co. Ltd., P.O. Kalyan Khani (A.P.) in terminating the employment of Shri Bura Rajesham, Coal-cutter of K.K. 2 with effect from 21-6-1967 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

The claim statement and the Counter statement were filed and the matter was posted for enquiry.

Shri Bura Rajesham applied to the Management for sympathetic consideration for employment on the surface and after prolonged discussions the matter is amicably settled as follows:

1. Shri Bura Rajesham has been examined on 15-11 1972 and found medically fit to work as Shale Picker.

2. He will be employed in terms of the Compromise w.e.f. 24-12-1972.

3. He will be given Cat. I with basic wage of Rs. 5 from the date he is employed as Shale Picker at any of the Screening Plants at Mandamari Division.

4. It is clearly understood that he has no claim for wages with effect from 25-6-1967, the date when he was discharged as medically unfit for further service by the Company's Medical Board upto the date of his employment.

5. It is clearly understood that he has received half monthly compensation as per the decision of the Commissioner, Workmen's Compensation and he has no claim for any other benefits from the time he was medically declared unfit upto the date fo reemployment

6. The matter is fully and finally settled.

Management:	Workmen:
	Sd/-
	3-2-73.
M. Vasudevan	Secretary,
Dy. General Manager.	A. P. S. C. M. Sangh.

Witnesses :

1. Bura Rajesham.
2. B. R. Krishnna.

[TRUE COPY]

P. S. ANANTH, Presiding Officer

[No. L-2112/7/71-LRII]

S.O. 905.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act., 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in a petition filed under Section 33A of the Act by Shri A. Rajaiah and six others working as Turbine Drivers in Power House, Ramagundam, (Andhra Pradesh) against the management of Singareni Collieries Company Limited which was received by the Central Government on the 6th March, 1973.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Present :

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal. Hyderabad.

Miscellaneous Petition No. 73 of 1972

in

Industrial Dispute No. 30 of 1967

BETWEEN

A. Rajaiah, Ch. Ellaiah, S. Satyanarayana, V. Satyanarayana, V. Vaman Reddy, M. Devadas and B. Lingaiah—PETITIONERS.

AND

The Management of Singareni Collieries Co. Ltd., Ramagundam Division, Godavari Khani Karimnagar, Karimnagar District.—RESPONDENT.

Appearances :

Sri A. Lakshmana Rao, Advocate—for Petitioners.

Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer, Singareni Collieries Co. Ltd., Bellampalli—for Respondent.

AWARD

This is a petition filed under Section 33A of the Industrial Disputes Act 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for directing the Management not to alter the conditions of service of the petitioners pending disposal of I.D. No. 30 of 1967.

2. The petitioners filed this petition contending as follows:— The respondent is guilty of contravention of provisions of Section 33 of the said Act. The petitioners are permanent employees of Singareni Collieries Company Limited and they are working in the Power House at Ramagundam as Turbine Drivers. The respondent erected Power House of 18 M.W. capacity at Ramagundam and it started production in 1968 with one Turbine. In 1969 two more Turbines were commissioned. The Power House works round the clock in three shifts. Two Turbines work continuously while the third is kept as spare. The first four petitioners have been working as Turbine Drivers ever since the Power House is generating electricity, that is, from November, 1968. The rest of the petitioners are working as Turbine Drivers since the two Turbines are regularly operated from 1969. All the petitioners are trained under Rumanian Engineers. In the beginning the Turbine Driver was provided with the assistance of an auxiliary Turbine Attendant in Category III. The auxiliary Turbine Attendant used to attend to cleaning work of the Turbine. After two turbines started functioning the Turbine Driver is provided with mazdoor also who used to attend to the cleaning along with the auxiliary Turbine Attendant. Some time back the Management instructed the Auxiliary Turbine Attendant not to attend to the cleaning work and also dispensed with the services of the mazdoor. At the same time the Turbine Drivers are compelled to do the cleaning of Turbines. The work of a Turbine Driver is onerous, responsible and is highly skilled nature. The nature of work is such that he should be very vigilant through out the shift. The Turbine Driver does not have any time at his disposal to attend the cleaning work. Without any justification and with a view to victimise the Turbine Drivers the Management has effected a change in usage as to the conditions of service applicable to the Turbine Drivers. All the petitioners are concerned workmen in I.D. No. 30 of 1967 pending on the file of this Tribunal. The said dispute relates to the modification and change of the wage structure and categorisation recommended for Bengal and Bihar so as make it applicable to Singareni Collieries. In the said dispute the Turbine Drivers in the Collieries of the Management claimed for the grade of Rs. 245-440 having regard to the nature of work of their counterparts in Bengal and Bihar. The Management deliberately altered the conditions of service of the petitioners without following the procedure laid down in Section 9A and Section 33 of the said Act when I.D. No. 30 of 1967 directly connected with conditions of service is pending. As a matter of fact the Management issued charge sheets to some of the petitioners and passed orders of suspension against A. Rajaiah and V. Satyanarayana for their alleged deriliction of duty. Thus the Management has contravened the provisions of Section 33 and 9A of the said Act. So the Management should be directed not to alter the conditions of service pending disposal of I.D. No. 30 of 1967.

3. The respondent filed a counter contending as follows:— There has been no contravention of provisions of any of the provisions of Section 33 of the said Act and so the petition is not maintainable. Further there is no mention of Sub-section that is alleged to have been contravened. There is no alternation of the conditions of service to the prejudice of the workmen as nothing can be said to have been altered immediately before the commencement of proceedings in I.D. No. 30 of 1967 when the Power House came into existence nearly after one year. So the workmen in the Power House are governed by the terms of their employment express or implied. So the present petition has no bearing on Industrial Dispute No. 30 of 1967 and it is not directly connected with the conditions of service as the main dispute pertains to wages and certain category of work and so there is no violation of Section 33(1)(a) of the said Act. It is denied that the petitioners are working as Turbine Drivers as some of them are auxiliary turbine drivers and I.D. Nos. 71/71 and 81/71 are the two disputes relating to the petitioners. Even so there is no alternation in their service conditions as they have been performing all the allied duties pertaining to Turbine since the first Turbine was commenced in November, 1968 and a second Turbine was commenced in May, 1969. At no time both the Turbines were operated except for trial period till April, 1971. So the allegations that there is violation of Section 9A of the said Act is baseless. Some of the petitioners are working as Auxiliary Turbine Attendants and their duties are to attend to all Auxiliaries. The Auxiliary Turbine Attendant was not to attend to the cleaning work of the Turbines. That the allegation that a mazdoor was provided along with the Auxiliary Turbine Attendant for merely cleaning the Turbine is fantastic and fictitious. One mazdoor used to clean the Power house floor but was not competent to touch the machinery or the Turbine. This matter came up under Grievance Procedure and during the discussions it was never mentioned by the petitioners that cleaning of machinery was not their job. Further the matter was discussed with the office bearers of the Workmen Union and the General Secretary was convinced that cleaning of the machinery is the duty of the Turbine Drivers and assured that they would advice the petitioners accordingly. The allegations that the work of Turbine Drivers is so onerous and highly skilled is again not true as the running of a Turbine is continuous and it is the duty of the workmen to keep a watch and to carry out all the duties incidental and keeping the Turbine tidy does not entail any indignity to the status of the person. The inferences of victimisation and harassment are far fetched. That the petitioners are concerned workmen in I.D. No. 30 of 1967 in demanding higher grade does not result in not carrying out their normal duties and the petition is to escape liability under the Standing Orders for wilful in subordination. There is no necessity to have recourse to the procedure laid down under Section 9A of the said Act. The Management has not violated Section 33(1)(a) of the said Act as the matter is not connected with the main dispute and much less there were no service conditions immediately preceding the reference as no Power House existed in Ramagundam. The Management reserves the right to take disciplinary proceedings under the Standing Orders. The petition is liable to be dismissed.

4. The points that arise for determination are: (1) Whether the petition is not maintainable? (2) Whether the respondent should be directed not to alter the conditions of service of the petitioners?

5. Point (1):—The petitioners are said to be working as Turbine Drivers in the Power House At Ramagundam. According to the respondent some of the petitioners are Auxiliary Turbine Drivers. The petitioners have filed the present petition for directing the respondent not to alter the conditions of service pending disposal of I.D. No. 30 of 1967. Their contention is that it is only Auxiliary Turbine Attendants who were cleaning the Turbine when the first Turbine started working, that after two Turbines started functioning regularly the Turbine Driver was also provided with a mazdoor who used to attend to the work along with the Auxiliary Turbine Attendants and that some time prior to the filing of the present petition., the Management had instructed the Auxiliary Turbine Attendant not to attend to the cleaning work and also dispensed with the services of the mazdoor and that this action on the part of the Management in changing the service conditions is a contravention under Section 33. The contentions of the respondent are that the petition itself is not maintainable under Section 33A of the said Act as there is no question of any contravention of Section 33 of the said Act in as much as the Power House itself was put into operations only in 1968, that is, along after the filing the Industrial Dispute No. 30 of 1967 and that the petitioners are governed only by their service conditions express or implied and so at best even if it is assumed that there is any change in the service conditions it would come only under Section 33(2)(a) of the said Act. Now it has to be seen whether the petition is maintainable. So far the nature of the duties done by the petitioners are concerned one of the petitioners examined himself as P.W. 1 and on the side of the respondent the Senior Division Engineer who is there since the erection of Power House at Ramagundam has been examined as R.W. 1. It appears that some action had been taken against some of the petitioners on the ground that they refused to clean the Turbine. Ex. R. 2 is the charge memo. issued to the first petitioner. Ex. R. 1 is the order of suspension of the first petitioner. Ex. R. 3 is the domestic enquiry file relating to him. Ex. R. 4 is the letter issued to the first petitioner warning him. Exs. R. 5 and R. 6 are the Domestic Enquiry Files relating to the third petitioner and the fourth petitioner respectively. Ex. R. 7 is the letter addressed by the Agent to the office President of A. P. Singareni Collieries Mazdoor Sangh with reference to the cleaning of the Turbine and the Ex. R. 8 is the copy of the letter addressed to the petitioners 1, 2, 3 and another asking them to clean the Turbine. It may not be necessary to refer to the evidence of P.W. 1 and R.W. 1 in detail at this stage because if it is found that the petition is not maintainable then the petition is liable to be rejected.

6. It is common ground that the first Turbine in the Power House at Ramagundam was commissioned in October, 1968 by which time I.D. No. 30 of 1967 was pending before this Tribunal and that later on in the year 1969 the other Turbine also started working. It is seen from the evidence of R.W. 1 that three of the Turbine Drivers were previously working as Junior Drillers in the Prospecting Department and that when that Department was closed they were brought to the Power House, that four Auxiliary Turbine Attendants were I.T.I. Candidates, that when the first Turbine was started in October, 1968 four persons were promoted as Turbine Drivers by issuing relevant office Orders. So from the evidence it is clear that the Turbine Drivers relating to the Turbine in the Power House at Ramagundam were employed only long after the reference that was made and which is the subject matter of I.D. No. 30 of 1967. The learned counsel for the petitioners contended that the petitioners are workmen concerned in I.D. No. 30 of 1967 though they had been appointed as Turbine Drivers long after the reference is made relating to I.D. No. 30 of 1967 and in support of his contention he relied upon the decision reported in NEW INDIA MOTORS v. K. T. MORRIS (1960 (I) LLJ page 551) (Supreme Court) and TATA IRON & STEEL CO. v. SING (1965 (II) LLJ, page 122). The respondent's representative does not dispute the fact that the Turbine Drivers, who were appointed subsequent to the reference made in I.D. No. 30 of 1967, the workmen concerned in I.D. No. 30 of 1967, because it is now seen that in I.D. No. 30 of 1967 the reference made was what further modification and changes in the categorisation of wage structure recommended by the Wage Board are necessary to make the said categorisation and wage structure applicable to the workmen of Singareni Collieries Company Limited. So as contended by the learned counsel for the petitioners the petitioners in question are the workmen concerned in I.D. No. 30 of 1967 as contemplated under section 33(1)(a) of the said Act.

7. Now it has to seen whether the alleged alteration of service conditions can be said to be a violation of Section 33(1)(a) of the said Act attracting the provisions of Section 33A of the said Act. It is contended by the respondent's representative that since the petitioners were appointed long after the reference made in I.D. No. 30 of 1967, their service conditions are governed by the contract of service entered into between the employees and the Management, that I.D. No. 30 of 1967 has nothing to do with the service conditions of the petitioners as they relate only to the Wage Structure and categorisation, that Section 33(1)(a) can be said to be violated only if there is any alteration in the conditions of service applicable to the employees immediately before the commencement of the proceedings said that when in this case there were no service

conditions applicable before the commencement of the proceedings in I.D. No. 30 of 1967 in as much as the first Turbine in the Power House at Ramagundam was commissioned only in October, 1968, the present petition is not maintainable under Section 33A of the said Act. The learned counsel for the petitioners on the other hand contended that if any new persons are posted to the same posts existing prior to the reference, they also would come in and their conditions of service would be protected, though they are employed subsequent to the reference and so that interpretation of the words "applicable to them immediately before the commencement of such proceedings" in Section 33(1)(a) should not be construed literary but should be construed so as to mean the workmen concerned and that if so construed then the Management can not change the conditions of Service without previous permission as contemplated under the provisions of Section 33(1)(a) of the said Act. Now from the evidence it is seen that at the time when the reference relating to I.D. No. 30 of 1967 was made there was no power house at all at Ramagundam. So it is only a new Power House that came into existence after the reference. Now the case of the respondent is that the Turbine Drivers were appointed by passing separate orders. So the Turbine Drivers of this particular Power House would be governed by service conditions according to the nature of their appointment order. So whatever may be the service conndition relating to the other Turbine Drivers, who were already working in the other power house which came into existence long prior to the reference relating to I.D. No. 30 of 1967, so far as the Turbine Drivers of the Turbines in the Power House at Ramagundam are concerned it cannot be said that their conditions of service were those that were applicable to them immediately before the commencement of the proceedings relating to I.D. No. 30 of 1967. If that is so, then the Management would be perfectly justified in altering the conditions of service of such workmen under Section 33(2)(a) of the said Act in which case the Management need not ask for any approval of this Tribunal under Section 33(1)(a) of the said Act. If it is the case of the petitioners that there has been alteration of their service conditions in as much as their service conditions are the service conditions which have come into existence long after the reference relating to I.D. No. 30 of 1967 they may have to agitate their right separately and raise a separate industrial dispute but they cannot complain of violation of the provisions of Section 33(1)(a) and invoke the provisions of Section 33(A) and file a petition like of the present one. Under Section 33(1)(a) if the conditions of service with reference to any matter connected with the dispute are altered then only it can be said that there is violation of Section 33(1)(a) of the said Act. The matter that is now pending in I.D. No. 30 of 1967 relates to Wage Board structure and categorisation has nothing to do with the service conditions of the petitioners since their service conditions have come into existence only long after the reference was made, because they have been appointed under separate office orders, some in October, 1968 and some in 1969. So even though the petitioners can be said to be workmen concerned in I.D. No. 30 of 1967 since they also would be found by the award that may be passed in I.D. No. 30 of 1967 though they were appointed long after the reference, still it cannot be said that the alleged alteration of the conditions of service can be said to be with reference to any matter connected with the dispute or that the alleged alteration of conditions of service can be said to be with reference to conditions of service applicable to them immediately before the commencement of the proceeding in I.D. No. 30 of 1967. So the only course open to the petitioners is to raise a separate dispute if it is their case that there has been violation of their conditions of service, but they cannot file a petition under Section 33A alleging contravention of provisions of Section 33(1)(a) and Section 9A of the said Act. In this view of the matter I hold on this point that the petition is not maintainable.

8. Point (2):—In view of my finding on point (1) there is no need to consider the evidence in this case to see whether the Management should be directed not to alter the conditions of service of the petitioners during the pendency of I.D. No. 30 of 1967 and so no finding is given on this point as the petition itself is little to be rejected as not maintainable.

9. In the result in view of my finding on point (1) the petition is not maintainable, it is rejected and it is open to the petitioners to raise a separate dispute, if it is their case that the respondent had altered their conditions of service.

10. Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 15th day of February, 1973.

P. S. ANANTH, Presiding Officer.

APPENDIX OF EVIDENCE.

Witnesses Examined for Petitioner:	Witnesses Examined for Respondent:
P.W. 1.—S. Satyanarayana.	R.W. 1.—A. M. Mathew.

DOCUMENTS EXHIBITED FOR PETITIONER

NIL

DOCUMENTS EXHIBITED FOR RESPONDENT

Ex. R. 1.—Order of suspension dated 22/23-9-1971 issued by Senior Erection Engineer, Power House, G.D.K. to A. Rajaiah.

Ex. R. 2.—Charge memo. dated 18-8-1971 issued by Senior Erection Engineer 18 M.W. Power Station, Ramagundam Division to A. Rajaiah.

Ex. R. 3.—Domestic Enquiry File of A. Rajaiah.

Ex. R. 4.—Letter dated 28-9-1971 of Senior Erection Engineer, 18 M.W. Power Station, Ramagundam Division addressed to A. Rajaiah stating that his suspension was kept in obeyance and given a chance to rectify himself.

Ex. R. 5.—Domestic Enquiry File of S. Satyanarayana.

Ex. R. 6.—Domestic Enquiry File of Sri V. Satyanarayana.

Ex. R. 7.—Letter dated 22-9-1970 of the Agent, Ramagundam Division-I addressed to the President, A. P. C. M. Sangh, G.D.K. regarding cleaning of Machinery.

Ex. R. 8.—Letter dated 21-1-1972 of Agent, Ramagundam-I addressed to S. Satyanarayana, A. Rajaiah, etc. Ellaiah and V. Narsimha Rao regarding cleaning of Machinery.

P. S. ANANTH, Presiding Officer

[No. 7/21/67-LR. IIII]

S.O. 906.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in a petition filed under Section 33A of the Act by Shri Nittoori Rayamallu, Machine Mining Operator in No. 1 Incline, Godavari Khani, Andhra Pradesh against the management of Signareni Collieries Company Limited, Kothagudem which was received by the Central Government on the 6th March, 1973.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD.

Present :

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal, Hyderabad.

Miscellaneous Petition No. 98 of 1972

In

Industrial Dispute No. 30 of 1967

BETWEEN

Nittoori Rayamallu.—Petitioner.

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division II, Godavari Khani, Karimnagar District.—**Respondent.**

Appearances :

Sri A. Lakshmana Rao, Adovcate—for Petitioner.

Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer—for Respondent.

AWARD

This is a petition filed under Section 33A of the Industrial Disputes Act 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for directing the respondent to re-instate the petitioner with full back wages with effect from the date of his discharge from service.

2. The petitioner in his petition contended as follows :— The petitioner was a permanent employee of the respondent. He worked as Machine Mining Operator in No. 1 Incline, Godavari Khani. After the implementation of the Wage Board recommendations he was placed in Category VI. The petitioner is very hale and healthy person and his age is 36 years now. He does not suffer from any disease to be made unfit for further service. He is an active Trade Union worker and when the petitioner was working as Machine Mining Operator in No. I Incline, Godavari Khani, one fine morning the respondent informed him that the Medical Board of the Company found him unfit on 9-1-1972 for further service with the company due to "Ischaemic Heart Disease". With effect from 10-1-1972 his services were dispensed with. The petitioner does not suffer from any heart disease. As a matter of fact no doctor of the company examined him for any heart disease. Soon after his services were dispensed with the petitioner approached the respondent and made a written representation that he does not suffer from any disease, much less a heart disease and that he is fit to work as Machine Mining Operator. The respondent virtually refused to reinstate the petitioner. After rejection of his request for reinstatement the petitioner approached the cardiologist of the Osmania General Hospital who is also the Professor and Head of the Department of Cardiology Osmania Medical College and got himself examined. The expert cardiologist's certificate is to the effect that the heart is normal and that the petitioner is fit for all duties. With a view to victimise the petitioner for his lawful trade union activities, in colourable exercise of its power of discharge simpliciter, the respondent discharged the petitioner from service on fictitious ground of unfitness for further service. The Standing Orders of the respondent do not confer any such power on it to discharge the workman. The petitioner is a concerned workman in I.D. No. 30 of 1967 pending on the file of this Tribunal. The respondent, dismissed the petitioner from service without following the procedure laid down under Section 33 of the said Act. So the respondent may be directed to reinstate the petitioner with full back wages with effect from the date of his discharge from service.

3. The respondent filed a counter contending as follows :— The petition is not maintainable under Section 33A of the said Act and it is liable to be dismissed in limini. It is admitted that the petitioner was an employee of the Company as Machine Mining Operator of Godavari Khani No. 1 Incline. He was unhealthy and he has been a person with a heart complaint irrespective of his age. He was suffering from a disease of the heart from 1969 onwards without any improvement in spite of the treatment by the authorities of the Colliery Dispensary. As per records with the respondent the petitioner had cardiac infection first time on 11-1-1969. He reported sick at the Colliery Dispensary of the respondent from 18-1-1969 and made fit for duty on 16-2-1969. He attended for duty further only for one day *i.e.* on 17-2-1969 and he again reported sick on 18-2-1969 and he was made fit on 18-4-1969. He was again made unfit for the same disease on 28-11-1971 and he was sent to Karimnagar Hospital for treatment and he was made fit on 18-12-1971. He was further examined by the Medical Board of the respondent Company constituted by the Chief Surgeon and Medical Officer and he was found to be unfit for further service due to "Ischaemic Heart Disease". Accordingly the services of the petitioner were dispensed with with effect from 10-1-1972. The allegations that the petitioner does not suffer from heart disease and that no doctor of the respondent company examined him for any heart disease and that no Medical Board was continued and examined the petitioner are incorrect and baseless. The petitioner was examined by the Doctor and the Medical Board of the respondent Company besides the Civil Assistant Surgeon of the District Head quarters Hospital, Karimnagar. As the services of the petitioner were terminated on grounds of medical unfitness by the Medical Board., the question of reinstatement does not arise. The services of the petitioner was dispensed with with effect from 10-1-1972. After the lapse of six months the petitioner produced a certificate from the "Cardiologist" of the Osmania General Hospital, Hyderabad dated 17-7-1972 which cannot be binding on the management. The petitioner never approached the management with any representation whatsoever for any consideration to work in and around the mine. The petitioner did not make any representation for medical leave at the relevant time and did not follow the procedure under the Standing Orders. The petitioner choose to appear before the Cardiologist at his will and pleasure without any reference of the Medical Officers of the Respondent company and never represented his condition and hence there was no dispute with the petitioner and so there does not exist any industrial dispute which can be adjudicated upon. The allegation of victimisation is false and fabricated. The discharge is in accordance with the Standing Orders of the workman concerned and there is no contravention of Section 33 (2)(b) of the said Act and hence no application under Section 33A of the said Act lies. The petitioner is not a concerned workman as there is no employee and employer relationship the moment he is compulsorily retired from the service of the Company. A retired workman has no case to complain under any of the sections of the Industrial Disputes Act. It is well settled that retired workman cannot seek any remedy as it is a valid termination under Standing Orders. The petitioner is not entitled to any reinstatement with back wages.

4. The point that arises for determination is whether the respondent is liable to reinstate the petitioner with back wages.

5. The petitioner was working as Machine Mining Operator in G.D.K. No. 1 Incline Singareni Collieries Company Limited. R.W. 2 (Dr. (Mrs) M. Ramalakshmi) who is working as Senior Medical Officer, Godavari Khani Dispensary since 1970 and another constituting the Medical Board examined the petitioner on 9-1-1972 and they declared the petitioner unfit for further service and issued the certificate the original of Ex. P. 2 dated 9-1-1972 and pursuant to it the respondent removed the name of the petitioner from the rolls with effect from 10-1-1972 by passing the order the original of Ex. P. 3 dated 10-1-1972. Now the petitioner has filed the present petition for reinstatement contending that with a view to victimise him for his lawful trade union activities and in colourable exercise of its power of discharge simplicitor the respondent discharged the petitioner from service without following the procedure laid down under Section 33 of the said Act even though I.D. No. 30 of 1967 is pending.

6. One of the contentions of the respondent is that the petition under Section 33A does not lie and that there has been no contravention of Section 33(2)(b) of the said Act since the discharge is in accordance with the Standing Orders and that a retired workman cannot seek any remedy as it is a valid termination, under the Standing Orders. It is contended by the respondent's representative that if it is discharge simplicitor as alleged in the petition, then the discharge is not due to any misconduct under Section 33(2)(b) of the said Act and that as there is no violation of Section 33(2)(b), the petition under Section 33(a) does not lie and he relied upon the decision reported in NATIONAL MACHINERY MANUFACTURERS v. VYAS (1964(I) LLJ, page 624) and contended that the principle laid down in that decision applies to the present case. In that case their Lordships observed that Section 33(2)(b) can have no application to case of discharge unless it is for misconduct. No doubt this is not a case where the petitioner had been discharged or punished for any misconduct not connected with the dispute as provided under Section 33(2)(b) of the said Act and so there is no violation of the provisions of Section 33(2)(b) for attracting the provision of Section 33A of the said Act. But it has to be seen whether it can be said that there is violation of the provisions of Section 33(1) or Section 33(2)(a) of the said Act.

7. The learned counsel for the petitioner contended that it is only the substance of the order that has to be seen and

so it has to be seen whether it is discharge simplicitor or some thing more and that in this case but for the Medical Boards' opinion, the petitioner would not have been discharged and that when the certificate issued by the Medical Board is not true, the discharge goes auotmatically and that it is only on the assumption that the petitioner is suffering from heart disease the Medical Board issued the certificate resulting in the discharge of the petitioner. He relied upon the decision reported in U. B. DUTTA & CO. v. ITS WORKMEN (1962) (I) LLJ page 374 (Supreme Court). In that case the employer wanted to take action for misconduct and then suddenly dropped the departmental proceedings which were intended to be held and decided to discharge the employee under Rule 18(a) of the Standing Orders of that Company and under those circumstances their Lordships held that it was clearly a colourable exercise of the power under that Rule. He also relied upon the decision in SRIVASTAVA v. BANARAS E.L. & P. Co. (1970 (I) LLJ, page 394) wherein their Lordships observed that the existence of power to terminate the service of a workman does not make the termination immune from an enquiry by the labour court into its propriety or fairness and that if the labour finds that the power of termination has not been exercised in good faith or fairly, or that it has been resorted to from improper motive or capriciously or arbitrarily, or that the termination operates very harshly and unjustly, it would be justified in interfering with the termination.

8. Now from the evidence in this case it is seen that on the date when the petitioner was examined by the Medical Board he was not suffering from any disease. R.W. 2 says that on 9-1-1972 the petitioner did not have any cardiac attack and he was not suffering from any disease but he was declared unfit because of the previous history already stated by her, that it may be curable disease, but they cannot say that it is completely curable because even after cure he cannot do streneous work like a normal man and that it is because he cannot do the normal strencous work and as he was prone to another attack which may prove fatal, in the interests of the patient he was declared unfit for service under the Mines Act. So her evidence shows that on some suspicion that this man may not be able to do the normal strenuous work and that if he is asked to do the work he may suffer from another heart attack which may prove fatal, R.W. 2 made him unfit for service. It is now an admitted fact that I.D. No. 30 of 1967 is pending and that the petitioner also is a workman concerned in that dispute. Under section 33(1)(a) during the pendency of any proceedings before the Tribunal no employer shall in regard to any matter connected with the dispute alter, to the prejudice of the workman concerned in such dispute, the condition of service applicable to them immediately before the commencement of such proceedings, under Section 33(2)(a) during the pendency of any such proceedings in respect of industrial dispute, the employer may in accordance with the Standing Orders applicable to a workman concerned in such dispute or where there are no such standing orders, in accordance with the terms of contract, whether express or implied, alter, in regard to any matter not connected with the dispute, the condition of service applicable to that workman immediately before the commencement of such proceedings. Here in the present case the petitioner had been removed from the rolls during the pendency of I.D. No. 30 of 1967 on the assumption that the petitioner may get another heart attack if he is asked to work, eventhough on 9-1-1972., the petitioner was not suffering from any disease. So far as Standing Orders of the respondent Company are concerned (the Company's Standing Orders were produced before me for my perusal) there is no Standing Order which provides for removal of the workman from service in case he is sick or if it is suspected that his health is likely to be affected if he is asked to work in the Mine. So, at best, the action of the respondent in removing the petitioner from the rolls of the Company can be said to be only a retrenchment on the ground of continued ill-health. If it is a case of retrenchment then it has to be seen whether it is a valid retrenchment or whether the petitioner is entitled to any benefits and this aspect of the matter can be considered at a later stage. So far as the question of the maintainability of the application under Section 33A is concerned from the evidence placed in this case I am satisfied that this is a case of contravention of the provisions of Section 33(1)(a) or 33(2)(a) of the said Act. So in this view of the matter I hold that the present petition is maintainable.

9. Now coming to the merits of the case, as already stated from the evidence of R.W. 2 it is seen that it is only on the assumption that the petitioner may get another heart attack, which may prove a fatal, the petitioner was made unfit. The petitioner also shows that he was suffering from some sickness and so he was also hospitalised for some time. No doubt he does not want to admit the fact that he was having heart trouble at the time when he was hospitalised, but I feel that he being only a lay man, the evidence of the Doctors who examined the petitioner in this case is entitled to some weight, when they say that the petitioner was having heart trouble. R.W. 1 (Dr. B. Venkatakrishna Reddy) is working as Civil Assistant Surgeon in the District Head quarters Hospital, Karimnagar. He says that the petitioner was referred to his hospital by Singareni Colliery Hospital Ramagundam, on 28-11-1971, that he was admitted in the hospital on 29-11-1971 at 2-15 a.m. with chest pain, that the petitioner was in conjestive heart failure, that he was discharged on 8-12-1971 on his request though he (R.W. 1) asked him to stay in hospital for minimum period of three weeks, that Ex. R. 1 is the discharge certificate issued and it shows the disease as Ischaemic Heart Disease with Supra Ventricular Tachy Cardia with conjestive heart failure, that during the 10 days that this patient stayed in the hospital treatment was given to the heart disease and its complication, that as per the records of the hospital the petitioner was admitted on 11-1-1969 also with diagnosis of Coronary Thrombosis. In his cross examination it is elicited that conjestive heart failure is a curable disease, that Ectopic Tachycordia is also curable, that when the petitioner was discharged he was not fit for normal duties and so he recommended bedrest for four weeks so that he may become fit for normal duties.

10. R.W. 2 says that on 11-1-1969 the petitioner was brought to her house, that he complained of pain in the chest and that after examining him she came to the conclusion that he was suffering from Cardiac infaction, that from the dispensary he was sent to Karimnagar Hospital, that when she sent the petitioner to the dispensary he was hospitalised and the nurse also had noted as chest pain and over time also was paid to the nurse for that day, that Ex. R. 2 is the extract from the Overtime Register maintained in the Dispensary, that Ex. R. 3 is the report received from Karimnagar Hospital and it shows diagonosis as Cororary Thrombisis, that the petitioner reported to the Dispensary after he was discharged from Karimnagar Hospital and he was given 10 days rest and after that he was made fit for duty on 16-2-1969, that later on the petitioner reported to the Medical Officer of the Colliery Dispensary on 18-2-1969, that the record shows that the petitioner had stated before that Medical Officer that he was suffering from breathlessness, that is, Dyspnoea, that Ex. R. 4 is the letter dated 24-2-1969 written by that Medical Officer which show that at Bellampalli the petitioner was clinically examined and that X-Ray Ex. R. 5 was also taken which revealed clinically that there was enlargement of heart, that Ex. R. 6 is the inpatient case sheet maintained at Bellampalli Hospital, that on 27-2-1969 the petitioner was referred to Karimnagar Hospital, that he went there on 1-3-1969, that on 8-3-1969, as per the case sheet, it is evident that he had asked for the permission of the Medical Officer and came to Ramagundam as his first wife had died and that he stayed at Ramagundam and that again he went to Karimnagar Hospital in the second week of April, 1969, that the Medical Officer at Kothagudem Hospital had declared him fit for work on 16-4-1969 that on 28-11-1971 one of the petitioner's relatives came to him and said that the petitioner was serious and they wanted him to be taken to the Regional Hospital, that on that night one of the petitioner's relative brought a note given by the Medical Officer of Regional Hospital who had attended on the petitioner wherein he had mentioned the condition of the patient and the treatment given and he had also suggested in the note that the patient should be sent to Karimnagar Hospital, that then she instructed the Medical Officer to examine the petitioner and give his opinion and that after examination he also came to the conclusion that the petitioner was suffering from Cardiac Infarction and that he should be transferred immediately to Karimnagar Hospital, that a sick Attendant was allowed to accompany the patient, that Ex. R. 7 is the extract of overtime register showing that overtime was paid to the Attendant, that the petitioner was in Karimnagar Hospital from 29-11-1971 to 8-12-1971, that after that he came to her Dispensary with the discharge certificate Ex. R. 1, that on 9-1-1972 the petitioner was reviewed by the Medical

Board consisting of herself and another Doctor and the petitioner was declared unfit for further service and the Manager and the Agent were informed accordingly. She also says that this workman with this disease is susceptible to Cardiac Infarction again if he does any strenuous work.

11. In her cross examination she (R.W. 2) says that after this workman was declared fit by her on 16-4-1969 there was no complaint from this workman till 28-11-1971 that he had worked during this period, that first time she diagonised the petitioner's disease as of Cardiac infarction, and later on the Medical Officer in the Regional Medical Hospital also diagnoised the disease as Cardioc Infarction, that the petitioner's case was reviewed on 9-1-1972 by the Medical Board, that on that day he did not have any cardiac attack and he was not suffering from any disease but he was declared unfit because of his previous history, that it may be curable disease but they cannot say that it is completely durable because even after cure he cannot do any strenuous work like a normal man, that because he cannot do normal strenuous work and as he was prone to another attack which may prove fatal, in the interests of the patient he was declared unfit for service under the Mines Act and that under the Mines Act any person suffering from heart disease should be declared unfit to work in the Mines.

12. It is also now seen from the evidence of the petitioner that after he was made unfit for duty he had got himself examined by the Cardiologist Dr. U. Brahmaji Rao of Osmania General Hospital, and obtained the certificate Ex. P. 1, which shows that the petitioner's heart was normal and the certificate is dated 17-7-1972 and Ex. P. 1 also shows that the Cardiologist had noted that the petitioner was fit for all duties. The evidence of R.Ws. 1 and 2 show that when they examined the petitioner they did only clinical examination but that no E.C.G. was taken, whereas the Cardiologist, who issued the certificate Ex. P. 1, had taken the E.C.G. before issuing that certificate. From the evidence of R.W. 1 and R.W. 2 it is seen that they are not specialists in Cardiology but they had worked under Dr. U. Brahmaji Rao, who had issued the certificate Ex. P. 1. Now when Ex. P. 1 is shown to R.W. 1 he says that without E.C.G. report he cannot comment on the opinion given in Ex. P. 1 that the patient was fit for all duties. When Ex. P. 1 is shown to R.W. 2 she says that in Ex. P. 1 it is only mentioned that there is no Cardiac enlargement but the findings of the E.C.G. are also incomplete and that no previous history is given. According to her though Ex. P. 1 shows that E.C.G. was taken, the complete picture of E.C.G. is not mentioned but only a portion of it is mentioned. Now from the evidence referred to it is seen that eventhough the petitioner had some heart trouble and even though he was also hospitalised for some time, after his discharge from his hospital after he was made fit on 16-4-1969 by R.W. 2 he did not have any further trouble till 28-11-1971, though he had worked during that period and that it is only on 28-11-1971 that the petitioner had become sick and he had to be again sent to the hospital and that again he was discharged on 8-12-1971 as seen from Ex. R. 1 and that again R.W. 2 reviewed his case on 9-1-1972 and made him unfit.

13. Now from the evidence of R.W. 2 it is seen that eventhough the disease suffered by the petitioner was curable disease it is because of the previous history of the case and thinking that if he is asked to do normal strenuous duties he may again get heart attack, she had to declare him unfit for service under the Mines Act. No doubt the petitioner's case is also that it is a case of victimisation and that R.W. 2's husband asked him to join some other Union and that when he refused he got angry and so he was removed from service, I am satisfied that this is only a mere exaggeration on the part of the petitioner. The Petitioner himself says that though R.W. 2's husband asked him to join the communist Union, when he refused R.W. 2's husband did not give any trouble to him so far as his work is concerned. Now from the evidence already referred it is clear that it is because of the prior history of the petitioner's case R.W. 2 bonafide thought that the petitioner may not be fit for doing strenuous work in the mines. So I am satisfied that this is not a case of victimisation.

14. The petitioner's representative contended that eventhough the petitioner was not suffering from any disease on the date when R.W. 2 examination and made him unfit, still in view of the history of his case the order passed by the respondent can be supported as a case of retrenchment for continued ill-health and that simply because for some periods the petitioner was not sick it does not mean that this is not a case of continued ill-health. He relied upon the decision reported in BURBAKUR COAL CO. v. AZIMUDDIN ASHRAFF (1960 (II) LLJ, page 434) and contended that this decision shows what is continued illness. He also contended when a person is removed from service on the ground of ill-health he is not entitled to any benefits and he relied upon the decision reported in WORKMEN OF BANGALORE W. C. & SILK MILLS CO. v. ITS MANAGEMENT (1962 (I) LLJ, page 213). It was a case where some workmen, who were discharged on the ground that they were medically unfit, claimed bonus and their Lordships observed that when a workmen is discharged on the ground that he is medically unfit it cannot be said that they had been discharged on the ground that their services were no longer required and in that case their Lordships negatived the claim of those workmen. He also contended that assuming that it is colourable exercise of power the petitioner can't be reinstated under the circumstances of this case and that only compensation can be given as laid down in HINDUSTAN STEELS v. A. K. ROY (1970 (I) LLJ, page 228).

15. A persual of 1960 (II) LLJ, page 434 shows that in that case the respondent therein had been found physically unfit to carry out his duties on medical examination and that there was no prospect of his becoming fit to do the duties and that when the matter ultimately was referred to the Tribunal, it held that the termination of the services of the respondent therein tantamount to retrenchment under Section 2(oo) of the said Act and so the termination of his services without following the conditions precedent to retrenchment as provided by Section 25F of the said Act was illegal. In that case their Lordships observed that "continued ill-health" includes any physical defect or infirmity incapacitating a workman for future work for an indefinite period and ultimately in that case their Lordships held that that case fell within the exception provided in Section 2(oo) of the said Act and so it was not a retrenchment within the meaning given to the word therein. A perusal of this decision also shows that the respondent therein was found to be very old and infirm even though there was no organic disease and that he was made unfit on the ground that he was unfit for active duties due to infirmity on account of old age.

16. So far as the present case is concerned it is seen that the petitioner is aged about 35 years and that even though he was having some heart disease he became alright and that he had also worked for some time and then evidence of R.W. 1 and R.W. 2 also shows that the disease suffered by the petitioner is only a curable disease and Ex. P. 1 also shows that the petitioner was fit for all duties and that his heart was normal when he was examined by that particular Doctor. So under, these circumstances it has to be seen whether this can be said to be a case of retrenchment and if so whether the petitioner is entitled to any relief of reinstatement or compensation. As already stated, the petitioner was made unfit medically by R.W. 2 and so the petitioner's name was removed from the rolls. It is because of the assumption that the petitioner may get another heart attack if he works in the Mine R.W. 2 made him unfit, as according to her, as per the Mines Act if a person has a heart disease such a person is not fit to work in and around the Mines. If it is treated as a case of retrenchment then under Section 2(oo) of the Said Act retrenchment can be for any reasons whatsoever otherwise than as punishment inflicted by way of disciplinary action but it does not include termination of service of a workmen on the ground of continued ill-health. Certainly the case of the petitioner does not come under Section 2(oo) (c) of the said Act, because this is not a case of continued ill-health. In the present case the petitioner had some heart disease and he became alright and again he got some heart disease after sometime and that again he became alright. The definite evidence of R.Ws. 1 and 2 is that the disease suffered by the petitioner is only a curable disease. Ex. P. 1 shows that the petitioner is fit for all duties. Even on the date when R.W. 2 examined the petitioner and made him unfit, he was quite alright and he was not suffering from any disease. So if the petitioner cannot be reinstated then the petitioner is entitled to the benefits of Section 25F of the said Act. In the normal course the present order of removing the petitioner from the rolls cannot be upheld and reinstatement should be ordered, unless there is some other impediment for reinstatement.

17. Now the only other aspect that has to be seen in this case is whether, under the circumstances of this case, even though in the usual course the order passed by the respondent is liable to be set aside with a direction for reinstating the petitioner into service, the petitioner can be directed to be reinstated. If there is some justification for the respondent in retrenching the petitioner then the petitioner will not be entitled to reinstatement but he would be entitled only to compensation. As laid down in 1970 (I) LLJ, page 394) if the power as termination has not been exercise in good faith, fair play or that it has been resorted to arbitrarily or that the termination operates very harshly or unjustly, this Tribunal would be justified in interfering with the termination. In this case even though the petitioner was fit to do all duties on the date when R.W. 2 made him unfit, he was made unfit on the assumption that he may not be able to do strenuous work in the mines and that there was likelyhood of the petitioner getting another heart-attack which may prove fatal. So under these circumstances I am of the view that the termination is not justified and that the respondent cannot invoke the provisions of Section 2(oo) (c) of the said Act. In the decision reported in 1970(1) LLJ, page 228 their Lordships while considering the question in that case as to whether reinstatement should be ordered or compensation can be paid observed that it is true that some of the decisions of the Supreme Court have laid down that where the discharge or dismissal of a workman is not legal or justified, the relief which would ordinarily follow would be a reinstatement and that the Tribunal, however, has the discretion to award compensation instead of reinstatement if the circumstances of a particular case are unusual or exceptional so as to make reinstatement inexpedient or improper and that the Tribunal has, therefore, to exercise its discretion judicially and in accordance with well-recognised principles in that regard and has to examine carefully the circumstances of each case and decide whether such a case is one of those exceptions to the general rule. Finally in that case their Lordships awarded compensation in view of reinstatement.

18. So far as the present case is concerned the evidence shows that the petitioner had suffered from heart disease now and then though not continuously. Now R.W. 2 says that it is because the petitioner cannot do the normal strenuous work and as he was prone to another attack which may prove fatal, in the interests of the patient he was declared unfit for service under the Mines Act. In view of the nature of the sickness of the petitioner it is quite probable that the petitioner may get another heart attack though for all purposes he is now normal. The petitioner in his evidence says that the work of Machine Mining Operator is the work of driving the shuttle car and Loader forward and backward. No doubt he says that this work is easy work when it runs by electricity, but from his own statement it is clear that there is some strain involved in this work. He says that he is now claiming that the Machine Mining Operator's job should be given and that he does not ask for any other job. Since R.W. 2 is a Senior Medical Officer working in Godavari Khani, she must be in a better position to know the nature of the work done by persons like the petitioner in the Mines. Now she apprehends that the petitioner may not be able to do the normal strenuous work in Mines and that if he is allowed to work he may get another heart attack which may prove fatal. So from her evidence it is seen that in view of the nature of the disease suffered by the petitioner the Management does not want to take the risk of employing the petitioner further as Machine Mining Operator. Since the petitioner is not prepared to do any other work and since the respondent apprehends that if he is given the same work there is likelyhood of the petitioner getting another heart attack which may prove fatal, I am satisfied that, under the circumstances of this case, it would not be proper to direct the respondent to reinstate the petitioner into service, and that the respondent can be directed to pay compensation to the petitioner as provided under Section 25F of the said Act.

19. For all the aforesaid reasons, I hold on this point that the petitioner is not liable to be reinstated with back wages but that the petitioner is entitled to only to compensaion as provided under Section 25F of the said Act.

20. In the result I hold that the petitioner is entitled only to compensation but not to reinstatement and the respondent is directed to pay compensation as provided under Section 25F of the said Act within one month from the date of publication of this Award.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 2nd day of February, 1973.

P. S. ANANTH, Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined For petitioner:	Witnesses Examined For Respondent:
P.W. 1. N. Rayamallu.	R. W. 1. Dr. B. Jagannadha Reddy.
	R. W. 2. Dr. (Mrs.) M. Ramlakshmi.

DOCUMENTS EXHIBITED FOR PETITIONER

Ex. P. 1.—Medical report issued by Dr. U. Brahmani Rao, Cardiologist, Osmania General Hospital on 17-7-1972 saying that N. Rayamallu is fit for all duties.

Ex. P. 2.—Copy of the Medical Report issued by the S. C. Co. Ltd., Medical Board (Specially constituted by the Chief Surgeon and Medical Officer) on 9-1-1972 stating that N. Rayamallu was found to be unfit for further service and the same was informed to the Agent, Ramagundam Division II.

Ex. P. 3.—Copy of the Removing order dated 10-1-1972 of N. Rayamallu issued by the Manager, O.D.K. No. I Incline, stating that his name is removed from rolls.

DOCUMENTS EXHIBITED FOR RESPONDENT

Ex. R. 1.—Admission and discharge certificate dated 8-12-1971 issued by Civil Assistant Surgeon, Dist. Head quarters, Hospital, Karimnagar to Sri N. Rayamallu.

Ex. R. 2.—Extract from Overtime register filed by Dr. Mrs. Ramalakshmi senior Medical Officer, S. C. Co. Dispensary, Ramagundam Division stating that N. Rayamallu came to dispensary with chest pain on 11-1-1969 at 1-30 p.m.

Ex. R. 3.—Out patient ticket (Report) issued by the Government Head Quarters Hospital, Karimnagar on 11-1-1969 to Sri N. Rayamallu.

Ex. R. 4.—Letter dated 24-2-1969 of Medical Officer, Ramagundam Division addressed to the Medical Officer, Bellampalli that N. Rayamallu was suffering from Dyspnoea.

Ex. R. 5.—X-Ray of Sri N. Rayamallu.

Ex. R. 6.—Inpatient case sheet of N. Rayamallu maintained at S. C. Co. Ltd., Hospital, Bellampalli in which that N. Rayamallu's heart enlargement was noted.

Ex. R. 7.—Extract from Overtime register filed by Dr. Mrs. Ramalakshmi Senior Medical Officer, S. C. Co. Dispensary, Ramagundam Division stating that N. Rayamallu came to Dispensary on 28-11-1971 at 8-00 P.M. with chest pain and he was sent to Karimnagar Hospital.

S.O. 907.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Belampalli (Andhra Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1973.

P. S. ANANTH, Presiding Officer

[No. 7/21/67-LR II(ii)]

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Present :

Sri P. S. Ananth, B.Sc.,B.L., Industrial Tribunal, Hyderabad.

Industrial Dispute No. 16 of 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli.

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli.

Appearances :

Sri B. Gangaram, Vice President, Singareni Collieries Workers Union, Bellampalli—for Workmen.

Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli—for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by its Order No. 7/9/70-I.R.II dated 19th January, 1971 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for adjudication to this Tribunal, namely,

"Having regard to the nature of duties that are being performed by the following 18 Gang Mazdoors whether the management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli is justified in not giving Category IV wages to the said workers? If not, to what relief are the said workmen entitled and from what date?

1. Mohammed Ankus.
2. B. Ramuloo.
3. P. Kondal Rao.
4. M. Moorthy.
5. Bondari Rajalingu.
6. G. Venkata Rao.
7. Radrarap Arsial.
8. Md. Yakoob.
9. K. Laxmirajam.
10. Ameer Khan.
11. F. Francis.
12. Mateti Lachamaiah.
13. G. Nagulu.
14. Bingi Yenkati.
15. K. Chandraiah.
16. Charnappa.
17. Dosthi Mohad.
18. Anthoni Mohad."

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 16 of 1971 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience the Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli are referred to as the petitioners and the Management Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli is referred to as the respondent in the course of this award. The claimants in this case are 18 in number and they are said to be the Gang Mazdoors who are claiming new category IV wages.

2. The petitioners are represented by Singareni Collieries Workers Union, Bellampalli (hereinafter referred to as the said Union) and the Vice President of the said Union filed the claims statement contending as follows:—The 18 Gang Mazdoors referred to have been performing the jobs of Tyndals since a long time but they were paid old Category I wages. This case was represented in the year 1966 and in the concillation proceedings held on 26-11-1966 it was agreed to an enquiry by Labour Enforcement Officer (Central) Mancherial and it was agreed that his findings would be accepted by both the parties. The L.E.O. (Central) Mancherial conducted a detailed enquiry on 15-3-1967 and it was proved that the 18 workmen have been doing the jobs of Tyndals as per job description 90,98 of Mazumdar Award. They have been moving the engineering stores, machinery and heavy materials, they are doing jobs of erection and dismantling of structures and installations and withdrawal of machinery etc., On the basis of the report of L.E.O. these workmen were given old Category III of Gang Mazdoors with effect from 1-2-1967 as per the Memo of settlement dated 2-9-1967 arrived at during the conciliation proceedings. After the implementation of the Wage Board recommendations the Management did not refix them in the appropriate new category IV of Tyndals as per the Memo of Settlement dated 14-3-1968 arrived at before the Deputy C.L.C. the Management agreed that the surface gang mazdoors who were in the old category III and IV wages will be given new Category IV but it was not implemented. As per Memo of Settlement dated 17-9-1969 arrived at before the Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi, it was agreed that the surplus Gang Mazdoors issued will be decided with consultation with the Unions. The said Union and Tandur Coal Mines Labour Union are the signatories to the settlement dated 17-9-1969 but the Management has avoided the said Union and without discussing the matter with the said Union the Management has signed a separate agreement with the Tandur Coal Mines Labour Union. Thus the Management has violated the above said settlements. These facts are enough to prove the unfair labour practice of the Management in depriving the 18 workmen of fabrication shop, in the workshop. Bellampalli who have been performing the jobs of Tyndals since 1964. So the demands of these workmen that they should be given new category IV wages with effect from 15-8-1967 is justified.

3. The respondent filed a counter contending as follows:—The designations of Gang Mazdoors are eligible for Category IV in the reference is erroneous. Their actual designation is Tyndal and the very reference is misleading. It is denied that the said workmen named were performing the jobs of Tyndals since a long time as the designations of Tyndals is only after the Wage Board recommendations. It is admitted by the workmen that they were drawing Category I wages under the Mazdoor Award in pari materia with any other unskilled mazdoor of Category I. On 26-11-1966 minutes of discussion held were recorded and it was left to the parties to pursue further in the matter. The report of the Labour Enforcement Officer (Central) Mancherial was to the Asst. Labour Commissioner (Central) and there was no mention that the said workmen were doing the work of Tyndals, That the movement of machinery, material and other allied jobs are in the usual course of employment, particularly in a Workshop and all the mazdoors carry out the duties assigned and there is nothing special to justify a higher category. That on the report of the Labour Enforcement Officer(C) these workmen were given Category III is false. On the representation of the Vice President in his letter dated 1-9-1967 the workmen were asked whether they would opt to work as Category I mazdoor whenever required even though they were offered Category III wages from 1-2-1967. The workmen while duly acknowledging the letter dated 24-9-1967 individually accepted to work on lower category mazdoor jobs whenever required, though under the Settlement dated 2nd September, 1967 they were placed in Category III. The contents in para (4) are totally denied as their claim made therein is false. In fact from Item 2 in the settlement dated 14-3-1968 it is clear that the Management never agreed to absorb the said mazdoors in new Category IV and there is no breach of implementation of the settlement. In the memo of settlement dated 17-9-1969 arrived at before the Chief Labour Commissioner (Central) it was agreed that the parties will arrive at a settlement within one month in respect of surface tyndals in Bellampalli as the problem in respect of Yellandu and Kothagudem had already been settled. The several Unions who are signatories to the settlement did not come with clear proposals. That the bonafide action of the Management in arriving at a settlement with the recognised Union, namely, Tandur Coal Mines Labour Union dated 28-1-1970 has a workable proposition which was implemented forthwith. The charge by the workmen that there was unfair labour practice in the matter of these workmen is denied. The demands of these workmen but they should be placed in Category IV is not borne on facts. The recommendations

of the Central Wage Board implemented from 15-8-1967 are not statutory. The claim may be dismissed.

4. The dispute that is referred to this Tribunal for adjudication is having regard to the nature of the duties performed by the 18 Gang Mazdoors mentioned in the schedule whether the Management is justified in not giving Category IV wages to the said workers?

5. The case of the petitioners is that the claimants, who are 18 in number, have been performing the jobs of tyndals since a long time but they were paid old category I wages, that on the basis of the report of the Labour Enforcement Officer (Central) the claimants were given old Category III of Gang Mazdoors with effect from 1-2-1967, that after the implementation of the Wage Board recommendations the Management did not refix them in the appropriate new Category IV of Tyndals and that as per the memo of settlement dated 14-3-1968 the Management agreed that the service of Gang Mazdoors who were in old Categories III and IV would be given new Category IV but it was not implemented. The contentions of the respondent are that the report of the Labour Enforcement Officer (Central) Mancherial was to the Assistant Labour Commissioner (Central), that there was no mention that the said workmen were doing the work of Tyndals, that it is false to say that in view of the report of the Labour Enforcement Officer these workmen were given Category III, that on the representation of the Vice President nearly one year after the report the workmen were asked whether they would opt to work as Category I mazdoors whenever required even though they were offered Category III wages from 1-2-1967, that the workmen accepted to the same though they were placed in Category III, that in fact from Item 2 in the settlement dated 14-3-1968 it is clear that the Management never agreed to absorb the said Mazdoors in Category IV, that the bonafide action of the Management for arriving at a settlement with the recognised Union as Tandur Coal Mines Labour Union dated 28-1-1970 has a workable proposition which was implemented forthwith, that these workmen were not given job of Tyndal from any date whatsoever and so the demand of these workmen that they should be placed in Category IV with effect from 15-8-1967 is not borne on facts. Now it has to be seen whether the Management is justified in not giving Category IV wages to the claimants in this case.

6. W.W.1 (P. Kondala Rao) is working in Fabrication and Erection Section in Bellampalli Division as Gang Mazdoor from 1964. He says that along with him 17 others are working, that out of these 18 workmen F. A. Francis (claimant No. 11) has resigned, and G. Venkat Rao (claimant No. 6) is transferred to Mandamari Workshop, that the Tyndal Muccadam supervises their work, that they load girders, plates, channels, angulars, revets and bolts in the lorries and take them to the workshop and unload them there, that they got girders according to the specifications of the Fitters and drill them and they take them to the lorry to the working place and unload it and fit them up there, that from 1964 they were doing erection work, that they were now attending to elevator work at C.S.P., that they fit up girders, gears and conveyor belts, that except the gang Mazdoors no other person attends to Fabrication and Erection work, that they were in Category I and they were designated as General Mazdoor, that they raised the dispute claiming old Category III, that the Labour Inspector came and enquired and thereafter they were placed in old Category III in 1967 prior to the implementation of the Wage Board that after the implementation of the recommendations of the Wage Board they were placed in new Category II designating them as Gang Mazdoors, that the persons designated as Gang Mazdoors then were designated as Tyndals and placed in new Category IV, that Gang Mazdoors who were in pits were placed in new Category IV and that they are claiming new Category IV along with Tyndals from the time of the Wage Board recommendations. In his cross examination he says that he was appointed on 1-4-1964 as general mazdoor, that prior to the implementation of the Wage Board recommendations there was no designation of Tyndals in Singareni Collieries, that the fabrication and erection work requires 10 or 20 persons, that he does not know what is meant by M and R Muccaddam, that he has not counted the number of Gang Mazdoors and General Mazdoors in the fabrication section, that he does not know if any letters were sent to them by the Agent that though they were placed in Category III they should also do the work of Category I, that whenever necessary four of them are taken to the auto shed, that they do not attend to any work other than erection work, that they are always asked to carry heavy articles, he does not know what is job description of Tyndals according to the Wage Board, that in the Engineering Department some Gang Mazdoors were designated as Tyndals and given Category IV but in their section no one was given like that, that he does not know they are 31 Gang Mazdoor who were working from 1956 were designated as Tyndals and given Category IV, that in the Mines there were gang mazdoors working who were designated as Tyndals after the Wage Board, that he does not know if prior to Wage Board Gang Mazdoors were in different categories, that he does not know about any agreement with the Tandur Coal Mines Labour Union in connection with promotion of Tyndals, and that he does not know whether there are Gang Mazdoors, in Categories II and III in other sections of the Engineering Department.

7. W.W.2 (B. Narasaiah) is working in Fabrication and Erection Section as Tyndal Muccadam. He says that he knows all the 18 Fabrication Gang Mazdoors in question, that out of them Venkat Rao is transferred and Francis has resigned that all of them are working under him, that all of them attend to Fabrication and Erection work, that they act girders, angulars etc., in a lorry to the work spot shows by him, that if the articles are not heavy then they carry them, that girders within 20 feet are carried by 16 or 18 Gang Mazdoors and that except these Gang Mazdoors none others attend to fabrication and erection work. In his cross examination he says that he worked as file mazdoor initially and was in Category I, that he does not know what weight according to the Wage Board each Gang man is expected to carry, that they have push belt drums, that they did not carry oil drums or grease drums, that it is not correct to say that the Gang Mazdoors attend only to carrying of heavy articles and that they do not attend to fabrication and erection work, that a gang consists of about 15 to 20 gang mazdoors, that these gang mazdoors go to auto workshop to carry machines, that whenever necessary 12 gang mazdoors go to the moulding section, that some of them attend to revetting work in manufacturing new tubs, that when it is absolutely necessary these gang men are sent to electric workshop to carry heavy articles, that he learns that 31 persons were promoted as Tyndals and given Category IV, that the grievances of the 18 gang mazdoors is that they should be given the same category as 31 Tyndals and that persons who had put in long service are designated as Tyndals and given Category IV.

8. W.W.3 (M. Posham) is working as Fitter in the fabrication and erection section of the workshop at Bellampalli Division. He says that he knows all the 18 gang mazdoors in question, that Francis has resigned and Venkat Rao has been transferred, that all of them work under him, that they carry heavy articles to the workshop, that these gang man have attended to bunker erection work in Shanti Khani, that they are putting the drums under No. 2 elevator in C.S.P. and except the gang mazdoors of their section there are no others to attend to fabrication, erection, installation and dismantling work, and that he does not know whether some gang mazdoors were designated as Tyndals and given IVth category and that whenever necessary some gang mazdoors go to the auto workshop and other places. In his cross examination he says that he is in new Category IV, that the number of gang mazdoors who work under him depends upon the nature of the work, that they always work in a gang and not individually, that workshop employees do not come to work under him, that till now no employees in the workshop are sent for erection work, that they attend to dismantling work, that there are five or six Fitters in his section, that these gang mazdoors help them in fitting work, that he cannot say how much weight they carry, that some times they carry articles from the stores if the lorry is not available and that they are not called Tyndals till now.

9. M.W.1 (N. K. Daver) is working as Divisional Engineer at Bellampalli. He says that he knows 18 workmen who are connected with the present case, that they were appointed first as General Mazdoors in old Category I, that later on they were promoted to Category III as Gang Mazdoors, that after Wage Board award they were placed in new Category II that these Gang Mazdoors have to work with the Fitters in foundry shop, in the machine shop and they can also be sent to automobile garage in Engineer Department, that normally 17 to 18 mazdoors work in fabrication department, that there are 14 more mazdoors in the workshop besides these 17 or 18 mazdoors, that these 14 mazdoors have entered service around 1956, that the 18 persons connected with the present case were recruited in 1964, and promoted

to old Category III some where in February 1967 by virtue of the agreement the original of Ex.M1, that there are still working in the Engineering Department on the mechanical side, that Fitters or concerned. Tradesmen extract the work from these 18 persons, that there is designation of Tyndals in the workshop and its Category is new Category IV, that for the whole Engineering Department they selected 31 Tyndals, that for unskilled workmen there is no other designation other than Tyndal, that the work of Tyndals is heavy structural work, and they work under the direct supervision of Fitter and Tyndals Supervisors, that they are supposed to handle things of mechanical nature like cranes, Cnab Wynch etc. considering the height at which they work, that it requires certain amount of skilled work, that the duties of the 18 mazdoors who are concerned in the present case are the same now as they were prior to Wage Board and it is semi-skilled work they do, that Ex. M2 is the copy of the settlement arrived at on 11/14-3-1968 with reference to Gang Mazdoors also and it is Item 2(1) in Ex.M2, that Ex.M3 is the copy of the Circular dated 8-2-1970 and it relates to selection of 31 Tyndals for the whole of the Engineering Department, that the Company considered the case of these workmen at the time of selecting 31 Tyndals, that Ex.M.4 is the copy of the memorandum of settlement dated 20-1-1970 entered into between the T.C.M.L. Union and the Management that as per term (1), of Ex.M4 it was agreed that 31 category II M & R Gang Mazdoors in Engineering Department should be promoted as Tyndals in Category IV, that 15 were taken from the Mechanical Department and 11 were taken from the Electrical Department and five from Power House to make up this 31 posts, that they were selected as per the terms in Ex.M4 after interviewing the workmen, that the 18 workmen connected with the present case are individual workers working individually but the Tyndals work as a team, that no promise was given to these or to the other 14 workmen that they would be taken to new Category IV, that Ex.M5 is the copy of the memorandum sent individually to these 18 workmen, that Ex.M6 is the copy of the reply received from these 18 mazdoors, that he did not receive any representation from the Singareni Collieries Workers union either prior to or after 31 Tyndals were selected, that they were not put in jobs of erection work in different pits, that the 18 persons connected with this dispute were generally being sent to W.W.3, that W.W.2 does not supervise the work of these 18 workmen that some times these 18 persons may have to carry some heavy material, that generally it is the duty of the Tyndals to work on heavy structural work of erection etc., that is if they work on certain height, that the Tyndals who work underground have to erect Haulers and they also do the work of shifting of motors, transformers, pump sets etc., that for doing Tyndals work there must be sufficient skill, that their long experience is also taken for selecting them and that there was no representation from these 18 people after 31 Tyndals were selected.

10. In his cross examination he (M.W.1) says that in the Mechanical section he can post them in any section that W.W.3 attends to the work at the erection section also whenever they post him there, that Ex.W1 is the copy of the minutes, that Ex.W2 dated 10-1-1967 contains A. M. Khan's signature, that as he (M.W.1) came in July, 1967 he does not know what happened on 20-1-1967 when enquiry was held, that the original of Ex.M2 was subsequent to Ex.W2. that it is not correct to say that in Ex.W2 the Management agreed on principle that all old Category III and IV workmen would be given new category IV, that this principle was agreed to only so far as the workmen working underground are concerned and it is made clear in Ex.M2 itself but it does not relate to surface workman, that Gang Mazdoors, who were promoted as Tyndals Category IV were working as Gang mazdoors in old Category III surface that Ex.W3 is the copy of the memo of settlement dated 17-9-1969 arrived at before the Chief Labour Commissioner, New Delhi between the Management and Singareni Collieries Workers' Union, Kothagudem and T.C.M.L. Union, that one Gangaram, Vice President has signed in it as seen, from it, that Item 10 in Ex.W3 refers to Tyndals working on surface, that he does not know whether Singareni Collieries Workers Union was called or not at the time of effecting the settlement Ex.M4 but it shows it was entered into only between the Management and T.C.M.L. Union and that this T.C.M.L. Union was there only Union that was recognised at Bellampalli.

11. M.W.2 (M. Moses) retired as Foreman of the workshop in Singareni Collieries. He says that when he was working as Foreman in the workshop at Bellampalli he was incharge of Machine, Moulding, Carpentry, Blacksmith and Fabrication sections, that he knows the claimants in the present case, that they were called as Mazdoors first in their Company, that prior to their joining service they were working as Mazdoors under Mohammad Hussain, who was working as Contractor prior to his becoming the Charge Hand, that when Mohd. Hussain was doing contract work he was supplying Bunkers and Trusses, that the claimants joined the Company's Service in 1961 or 1964 as Mazdoors, that they were in old Category III prior to Wage Board and after Wage Board they were given new Grade II, that they used to be sent in groups of 4 or 6 to do the work in Moulding Section, Motor Garage sections etc., that if any request was made by Electrical Engineer to send some Mazdoors to his section these claimants used to be sent there, that Mohd. Hussain used to supervise the work of these claimants and there was also Muccadam by name B. Narasaiah (W.W.2) over these claimants, that the duties of these claimants as Mazdoors are of transporting girders and angular irons in the lorries and unloading them, that they used to assist the Fitters in batches and this assistance work is that of Mazdoors, that it is only just at the time of his retirement there was talk of making arrangements for selection of Tyndals, that about 30 persons were selected as Tyndals there that the duty of Tyndals was doing repair work of pumps, Haulers etc., that they are asked to load the lorries with pumps, haulers etc. after repair work is done, that they used to do the work of loading in batches, that the batches used to be in four or five workmen, that by April, 1970 erection of Bunkers etc., was over that W.W.2 was in old Category IV and his designation was Muccadam, that the claimants used to merely load the lorry with heavy articles, that they never used to carry them, that about 10 to 12 Tyndals are working in the main workshop, that if an occasion arose claimants used to assist the Tyndals and that they never used to carry heavy articles.

12. In his cross examination, he (M.W.2) says that these claimants are merely known as mazdoors, that they were being called as Category III mazdoors, that when they joined service they were in old category I, that he does not know when exactly they were given new Category III (evidently it is a mistake for old Category III), that he does not know about Labour Inspector (Central) coming and inspecting the company, that erection work Supervisor then was B. Narasaiah that till his retirement whenever there was erection work these persons used to do that work, that these claimants never fitted any Haulers etc., that their work was assisting at the time of erection work, that 30 persons who were taken as Tyndals were only persons aged about 35 and 40 years but not very old persons due to retire, that out of these 30 persons one B. Malliah and Muthyalu had retired from service after he retired that the present claimants used to be sent to the Electrical Department only as Mazdoors, that these 20 persons who were selected as Tyndals used to do the work that they were asked to do and they also used to do big jobs when an occasion arose, that he used to give instructions to Charge Hand and ask him to take Gangs and get the work done and he used to depute the mazdoors and get the work done, that Tyndal is known as Tyndal Mazdoor, that those who load heavy articles in the lorries by cranes and who load small articles in the lorries are known as Tyndal Mazdoors, they do not carry heavy articles, that the claimants never went to the pits and installed any Haulers, that it is only the Fitters and their separate Mazdoors who did that work, that the claimants used to work in batches of 8 to 10 persons as a team since they used to lift heavy articles and load them in the lorries with the help of cranes and since they used to move the heavy articles for enabling the Fitters to do the fitting work.

13. Now from the evidence of the witnesses referred to above it is seen that these claimants were first appointed as General Mazdoors in Old Category I and that later on they were promoted to old Category III and that they were not doing any work exclusively in the erection side and that they used to work in the workshop also and that they also used to assist the other workmen who carried heavy articles. The evidence in this case also shows that so far as Singareni Collieries Company is concerned there was no designation as Tyndal and that it is only after the recommendations of the Wage Board now Tyndal's designation is given. The evidence in this case also shows that pursuant to the agreement the original of Ex.M4 31 Gang Mazdoors were selected as Tyndals after interviewing even the present claimants. Now it is contended by the petitioners' representative that

considering the nature of the duties performed by these claimants they should have been given new category IV considering the job description given by the Wage Board and that prior to Wage Board in Mazumdar Award the job description given was equal to Tyndal, though actually there was no disignation as Tyndal. It is also contended by the petitioners' representative that when the Management had agreed to discuss with the petitioners Union as seen from Exs.M2 and W.3 before any settlement is arrived at, the Management is not justified in ignoring the petitioners' Union and entering into the settlement Ex.M4 with another Union. According to the respondent's representative it is T.C.M.L. Union referred to Ex.M4 which is the recognised Union and that the bonafide action of the Management in arriving at that settlement with that recognised Union is seen in the Management implementing that settlement forthwith.

14. The petitioners have filed Ex.W1 to show that both parties had agreed for an enquiry by Labour Enforcement Officer, Mancherial and that they also agreed to accept his finding and Ex.W2 is filed to show that enquiry was held by him. No doubt it is said that some report had been sent by him but the details of this report are not available since no such report has been filed. Ex.W3 settlement is dated 17-9-1969 and it refers to Tyndals working on surface and it only shows that the parties had agreed that they would arrive at a settlement within one month in respect of surface Tyndals in Bellampalli area as the problem in respect of Kothagudem and Yellandu Mines had already been settled. Ex.M1 settlement dated 2-9-1967 is an earlier settlement to Ex.W3 which shows that in view of the representation made by the Vice President by his letter dated 1-9-1967 the Management had agreed to promote the Gang Mazdoors from Category I to Category III with effect from 1-2-1967. Ex.M2 settlement dated 14-3-1969 shows that so far as Gang Mazdoors are concerned the parties had agreed that the Gang Mazdoors who were in the pre-Wage Board Categories III and IV and who were working underground would be given new Category IV and that with regard to the Mazdoors Categories III and IV working on the surface the parties had agreed that they would further discuss amongst themselves and will try to come to an amicable settlement by the end of April, 1968. Ex.M4 settlement dated 28-1-1970 shows that reference is made to the settlement Ex.W3 in it, and that the question of alloting new Category IV to the required number of workmen in Engineering Department at Bellampalli was taken up for discussion in view of necessary provisions of Tyndals that had been made in other surface departments and that ultimately the parties had come to that settlement and a perusal of it shows that Management had agreed to promote immediately 31 Category II M & R Gang Mazdoors in Engineering Department as Tyndals Category IV and that the 31 Tyndals so selected would be allowed higher emoluments in new Category IV with effect from 14-3-1968 and Ex.M3 dated 8-2-1970 shows that in view of the terms of settlement Ex.M4 the Management also had selected 31 persons as Tyndals. Now the contention of the petitioners' representative is that the Management had entered into some settlement with the other Union without having any discussion with the petitioners' Union. When it is seen from Ex.W3 that the T.C.M.L. Union was also a party to that settlement and when T.C.M.L. Union is also the recognised Union I feel that even if the petitioners' Union was not consulted it does not mean that the settlement entered into by the other recognised Union should not be acted upon. All that has to be seen is whether the settlement Ex.M4 is a fair and just settlement and if it is found that it is a fair and just settlement then it has to be given effect to.

15. As already stated so far as Singareni Collieries Company Limited is concerned there was no job description as Tyndals and this fact can be seen even from the award of All India Industrial Tribunal (Colliery Disputes) popularly known as Mazumdar Award. While referring to the Tyndals in other Collieries in Mazumdar Award at page 85 in Volume II two categories of Tyndals were shown as W.29 and W.30. W.29 is shown as Tyndals (Heavy) and the job description given for these persons is that these men handle to machinery at the workshop and also work at Collieries from time to time particularly in erection and dismantling work. W.30 is shown as Tyndals (Ordinary) and that job description given to them is that these men do general Tyndals' work but are not usually employed on erection work requiring skill and that they are mainly employed on the moving of stores etc. and loading and unloading of lorries. Reference is made to Tyndals in the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry (hereinafter referred to as the Wage Board) at page 46 under Appendix V in Volume II under the Category IV (skilled juniors) and the relevant item in that page is Item No. 5 and the job description given for these Tyndals is that these men are generally employed in moving Engineering stores drums of oil and grease and that they are also responsible for erection and dismantling of structures and installation and withdrawal of machinery. Now from the evidence adduced even on the side of the petitioners it is seen that these claimants are not moving heavy engineering stores like drums of oil and grease etc. The nature of work done by these claimants can come at best under the job description given for Tyndals (ordinary) in Mazumdar Award. So these claimants cannot come under the job description of Tyndals given in the Wage Board. So, in order to get some benefit for these sort of workmen the T.C.M.L. Union had finally entered into the settlement Ex. M. 4, which is fair and just under the circumstances. No doubt it is the contention of the respondent that these claimants also had given a letter agreeing to work as lower category mazdoors even though they were given old category III and in support of this part of its case the respondent has filed Ex.M6 but Ex.M6 only shows that they had agreed to do the lower category mazdoor job only in erection department. However Ex.M6 does not assume much importance because now in the evidence shows that these claimants had been working in the other sections also. Now from the evidence of M.W.1 it is seen that out of all the Category III workmen including the claimants, 31 were selected as Tyndals after interviewing all these workmen pursuant to Ex.M4 settlement. So if the claimants want that they should be given new Category IV they have only to wait for their chance for fresh promotion but they cannot now straightaway claim new Category IV because the evidence in this case clearly shows that they do not satisfy the job description given for Tyndals under the recommendations of Wage Board considering the evidence in this case I am satisfied that the Management is justified in not giving Category IV wages to the claimants in this case.

16. For all the aforesaid reasons, I hold on the dispute referred to this Tribunal for adjudication that having regard to the nature of the duties that are being performed by the Gang Mazdoors mentioned in the reference the Management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli is justified in not giving Category IV wages to the said workers and that they are not entitled to any relief in these proceedings and that they have to only wait for their promotion to Category IV.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 12th day of February, 1973.

P. S. ANANTH, *Presiding Officer.*

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined for Workman :	Witnesses Examined for Employers :
W.W.1 P. Kondalarao.	M.W.1 N. K. Daver.
W.W.2 B. Narasaiah.	M.W.2 M. Moses.
W.W.3 M. Posham.	

DOCUMENTS EXHIBITED FOR WORKMEN:

Ex.W.1 Minutes dt. 26-11-1966 by Paparao and Gangaram for Management and Union had agreed to an enquiry by the L.E.O. Mancherial.

Ex.W.2 Enquiry Notice dt. 10-1-67 of Labour Enforcement Officer(C) Mancherial addressed to the Vice President Singareni Collieries Workers' Union, Bellampalli that the enquiry would be held on 21-1-1967 at 9-00 a.m.

Ex.W.3 Copy of the Memorandum of settlement under Section 12(3) of I.D. Act dt. 17-9-67 between the Management of Singareni Collieries Company Ltd., and their Workmen represented by the S.C. Workers' Union, Kothagudem and the Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli.

DOCUMENTS EXHIBITED FOR MANAGEMENT:

Ex.M.1 Copy of the Memorandum of settlement dt. 2-9-67 under Sec. 12(3) of I.D. Act between the S.C. Workers' Union, Bellampalli and the Management, S.C. Co. Ltd., Bellampalli.

Ex.M.2 Copy of the Memorandum of settlement dt. 14-3-68 under Sec. 12(3) of I.D. Act between the Management S.C. Company Ltd., and their workmen represented by the S.C. Workers' Union, Singareni Collieries Mazdoor Sangh, T.C.M.L. Union and A.P.C.M. Sangh.

Ex.M.3 Copy of the letter dt. 8-2-70 of Dy. Gl. Manager, Bellampalli addressed to the Divisional Engineer, Bellampalli Division recommending 31 workers for promotions.

Ex.M.4 Copy of the Memorandum of settlement dt. 28-1-70 arrived at between the Management of Singareni Collieries Company Ltd., Bellampalli and their workmen represented by the Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli.

Ex.M.5 Copy of the letter dt. 23/24-9-67 of Agent, Bellampalli Division addressed to P. Kondala Rao and 17 others regarding promotions.

Ex.M.6 Copy of the letter dt. 8-10-67 of 18 Gang Mazdoors addressed to the Agent, Bellampalli Collieries to early tower category Mazdoors jobs.

P. S. ANANTH, Presiding Officer.

[No. 7/9/70-LRII]

S.O. 908.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ramagundam Division I and II of Singareni Collieries Limited, Post Office Godavarikhani (Andhra Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1973.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Present :

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal (Central), Hyderabad.

Industrial Dispute No. 72 of 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, (P.O.) Godavari Khani, Ramagundam Division No. I and II. (Andhra Pradesh).

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited, (P.O.) Godavari Khani, Ramagundam Division No. I & II. (Andhra Pradesh).

Appearances :

Sri A. Lakshmana Rao, Advocate—for Workmen.

Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer, Belampali and Sri Papa Rao, Divisional Personnel Officer, Godavari Khani—for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by its Order No. L/2112/29/71-LR. II dated 19-10-1971 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for adjudication to this Tribunal, namely,

"Whether the management of Ramagundam Divisions I and II of Singareni Collieries Company Limited is justified in designating the following 55 workmen as Fitter/Electrical Mazdoors and denying them wages of Electrical/Fitter Helpers? If not, to what relief are the workmen entitled and from what date?

1. Gollapalli Sathaiah;
2. M. Rajam;
3. Kagithapu Chandraiah;
4. C. L. John;
5. Dubhasi Rajam;
6. Syed;
7. Muduthala Rajalah;
8. Jaknaboyina Kanakaiah;
9. Poradla Lingaiah;
10. B. Rajalingam ;
11. Ch. Raja Reddy;
12. Bisimilla Khan;
13. Md. Raj Mohammed;
14. Neelam Venkat Rajam;
15. N. Achaiah;
16. Chenigarapu Rayamallu;
17. Chinna Lingaiah;
18. Syed Pasha;
19. Bairam Laxminarayana;
20. M. Rajaiah;
21. Prasada Rao;
22. Adepu Bheemaiah;
23. A. Lazar;
24. D. Ramaswamy;
25. M. Ram Reddy;
26. M. Joseph;
27. N. Gangam Rajam;
28. Jainullabuddin;
29. T. Someshwar Rao;
30. Ch. Rajaiah;
31. T. Srisylam;
32. B. Radhakrishna Murthy;
33. Raheemuddin;
34. Poli Rajalingu;
35. Nagabhushanam;
36. Buchi Ramulu;
37. Venkateswaraiah;
38. Mallapalli Chandriah;
39. Elupula Narasiah;
40. G. Khagava;
41. E. Prakasham;
42. B. Suraynarayana;
43. Ganapathi Rao;
44. Jaffer Khan;
45. G. Ganpath;
46. V. Gopal Rao;
47. V. Chokka Rao;
48. Sk. Dawood;
49. Veeraswamy;
50. D. Gopal Rao;
51. K. Rajamallu;
52. M. Rajamallu;
53. M. Mallesham;
54. Goray Miya ; and
55. Raj Babu."

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 72 of 1971 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience the workmen of Singareni Collieries Company Limited, Godavari Khani, Ramagundam Division No. I and II are referred to as the petitioners and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Godavari Khani, Ramagundam Division No. I and II is referred to as the respondent in the course of this award. The claimants in this case are 55 in number who are designated by the respondent as Fitter and Electrical Mazdoors.

2. The petitioners are represented by the Andhra Pradesh Singareni Colliery Mazdoor Sangh (hereinafter referred to as the said Sangh) and the Vice President of the said Sangh filed claims statement contending as follows:— Out of the 55 persons referred to in the schedule to the reference, the Ist 26 persons are working as Fitter Helpers and the remaining 29 persons are working as Electrician Helpers. All these 55 persons have gained experience and learnt fitting work. They are doing elementary fitting work since some time before the implementation of the Wage Board recommendations. These workmen are not mere tool carriers. Though the management extracted the work of fitter and electrician helper from these workmen, it refused to designate them as fitter and electrican helpers with ulterior motive to avoid payment of category II wages. The Central Wage Board recommended Category II wages for fitter and electrician helpers. The respondent implemented these recommendations from 15-8-1967 and is paying to all fitter and electrician helpers in the mines situated in other Divisions such as Kothagudem, Bellampalli, Ramakrishnapur etc., of the Singareni Collieries Company Limited, but at the same time unjustifiably is depriving these 55 persons of Category II wages. The refusal to pay Catgeory II wages to these workmen while paying Category II to the workmen doing the same type of work in other mines situated in different divisions under the same Management is discriminating one against the other among persons similarly situated and forming one class. This action of the management is not only improper, illegal and unjustified but a clear case of victimisation and unfair labour practice. During the course of conciliation proceedings the opposite party tried to justify the non-payment of category II wages on the ground that the tradesmen agreement applicable to Ramagundam Division does not provide for the appointment of fitter and electrician helpers. So it is clear that because the Tradesmen agreement for Ramagundam area does not make provision for fitter and electrician helpers the respondent is designating these 55 persons as fitter electrician mazdoors. In each mine in other Divisions there are fitter and electrician helpers doing the same work as these 55 persons and they are being paid Category II wages ever since 15-8-1967. So the respondent should be directed to designate the first 26 persons as fitter helpers and the remaining persons as electrician helpers and pay Category II wages to all of them with effect from 15-8-1967.

3. The respondent filed a counter contending as follows : The 55 workmen referred to are designated as general mazdoors and are drawing Category I wages. It is denied that the first 26 persons referred to in the claim statement are working as fitter helpers and that the remaining 29 persons are working as electrical helpers. The nature of work enjoyed upon them is that of an unskilled General Mazdoors directed to carry out any routine duties allotted to them from time to time. It is denied that these unskilled workmen have gained experience and have become skilled workmen. The workmen referred to were not directed to carry out elementary fitting work before implementing of the Wage Board recommendations and the presumption "Helping the fitters and Electricians under whom they happened to work" is erroneous and misleading. The management have directed them to work as General Mazdoors under the Fitters or Electricians. These workers were in Category I mazdoors before the implementation of the recommendations of the Wage Board and after the implementation of the Wage Board they are rightly fixed in Category I. Only those who were drawing Categories II and III wages before the implementation of the Wage Board are eligible to get category II as equivalent wage after the Wage Board and so the presumption that the designation of the fitter or electrical helpers was not given with an ulterior motive to avoid Category II wages is misleading and baseless. The Wage Board recommendations show the equivalent in categorisation and they are recommendatory in nature. The imputation of discriminatory treatment as between old mines and new mines is imported and far fetched and the workmen are put to strict proof in respect of allegation of victimisation and unfair labour practices. It is admitted by the workmen that there is a Tradesmen Agreement applicable to Ramagundam Divisions I & II entered into on 4-10-1966 and there was no cause to complain till February 1971 in respect of this Agreement that was followed in Ramagundam. So the claim made now is not founded on justifiable grounds and is liable to be dismissed. It is true that the agreement does not provide for so called fitter and electrical helpers but on the other hand enough Tradesmen in Category IV, VII and IX were provided before the Wage Board recommendations for Coal Mining Industry and so there was no necessity to provide any workmen on Category II and therefore the claim of these 55 persons to designate them as Helpers is not justified. There was no necessity either before or after the implementation of the Wage Board recommendations to designate any of the workmen named in their reference or to create vacancies for any workmen to be called "Helpers" to carry out work, that is, rightly assigned to Category I Mazdoors. Before arriving at Tradesmen Agreement on 4-10-1966 a comprehensive study was conducted by the Management in all departments and certain proposals were discussed with the recognised Union and the said Sangh has merged at a later date to demand designation which is not existing. The old mines in other Divisions under the management having Fitters and Electricians in Category II have come to occupy or occupying such a position due to the fact that they were drawing old Category III and after implementation this Category is equcated to Category II and by this mere fact it cannot be said that there is discrimination or disparity. It is denied that there was only oral representation by the workmen. The Wage Board has given the job description in Category II and to judge the ability or otherwise of any workmen the sole authority is the Management and it is beyond the jurisdiction to confer a designation as Fitter Helper for the first 26 persons and as Electrical Helpers on the rest of 29 persons and thereby give relief by awarding Category II wages to all these 55 persons with retrospective effect from 15-8-1967. The workmen are virtually demanding a promotion to a higher category and any promotion is a managerial function. So the reference is liable to be rejected.

4. The dispute that is now referred to this Tribunal for adjudication is whether the respondent is justified in designating the 55 workmen as Fitter/Electrical Mazdoors and denying them wages of Electrical/Fitter Helpers?

5. The case of the petitioners is that the first 26 persons mentioned in schedule to the reference are working as Fitter Helpers and that the remaining 29 persons are working as Electrician Helpers in Ramagundam Divisions I and II and that though as per the recommendations of the Wage Board they should be designated as Fitter or Electrician Helpers as the case may be and given new Category II, that the respondent refused to designate them as Fitter and Electrician Helpers, though, when the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry (hereinafter referred to as the Wage Board) were implemented by the respondent, the Fitter and Electrician Helpers working in the other Divisions such as Kothagudem, Bellampalli and Ramakrishnapur were given new Category II wages. The contentions of the respondent are that the claimants are only General Mazdoors, that they were in old Category I and that after the implementation of the recommendations of the Wage Board they were rightly fixed in new Category I, that it is only those who were drawing Categories II and III wages who were placed in new Category II when the recommendations of the wages board were implemented, that as per the Tradesmen agreement entered into for Ramagundam Divisions I and II on 4-10-1966 there was no necessity for providing any workmen under old Category II, that enough tradesmen in old Categories IV, VII and IX were provided before the Wage Board and that the present claim of the petitioners virtually is a claim for promotion, which is only a managerial function.

6. In order to appreciate the contentions of the parties first of all it would be useful to refer to the set up of the different categories of workmen working in Ramagundam Divisions I and II. W.W. 1 (D. Rajaiah) is working as Fitter Helper in No. I incline of Godavari Khani. He says that at Bellampalli, Mandamari and Kothagudem Collieries for each shift there are four Fitter Helpers and four Electrical Helpers but it is not so at Godavari Khani, that at

Godavari Khani though there are four persons in each shift, they are given wrong designation and Fitter's work is extracted and that they are doing the same work that the Fitter Helpers and Electrical Helpers are doing at Kothagudem, Bellampalli and Mandamari. In his cross examination he says that he joined in Old Category I, that when Wage Board recommendations came old Category I persons were given new Category I, that he does not know whether he was also given new Category I then, that after Wage Board old Categories II and III persons were given new Category II, that he and others working in No. I incline gave applications asking the Management to give them correct designation and category, that they were informed that they would be given Category II as per seniority, that for each shift there are one Category VI and one Category V Fitters and four Helpers of Category I, that in Godavari Khani Divisions I and II there is no designations as Fitter Helpers.

7. W.W. 2 (T. Someswara Rao) says that he is working as Electrical Helper in No. I Incline in Godavari Khani, that the incharge Electrician is of VIth Category, that there are also two Vth Category Electricians and one IVth Category Electrician and two Helpers, that they (he and others) do the work as per oral instructions of categories VI and V Fitters, that there is designation of Electrical Helper at Bellampalli, Kothagudem, Yellandu, Mandamari, Ramkrishnapur and Somagundem, that he does not know whether this designation is there in the new Mines, and that they used to work in Vth and IV categories whenever the Electricians went on leave or were sick. In his cross examination he says that he was given Category I when he joined service and designated as General Mazdoor, that in 1967 after Wage Board he was given new Category I from old Category I, that old Categories II and III persons were given new Category II after Wage Board that prior to Wage Board they asked for old Category II as Electrical Helper but the Management did not give this category to them, that after Wage Board he applied to the Manager of No. I Incline to give them their Category as per Wage Board but they were not given new Category II, that he does not have any written authority to show that he has been asked to work as Electrician Helper and that other Electrical Helpers have no authorisation, that they were not given any written authorisation asking them to do Electrician Helper's work but they were asked orally by Electricians of Vth and VIth Category that he does not know whether Category II Electrician Helper job will be given only if there is 10 years service, that in the old Divisions there are Category II Electrical Helpers.

8. W.W. 3 (Mohammad Wahad Ali) is working as Fitter in No. I Incline from August, 1967. He says that that in all there are two Category V Fitters in Hand Mining Section and three Category V Fitters in Machine Mining Section, that there are four Category VI Fitters in Machine Mining Section and one Category VI Fitters in Hand Mining Section, that there are two Category IV Fitters in Machine Mining Section and three Category IV Fitters in Hand Machine Section, that as per Tradesmen agreement of 1966 the Company should employ six Fitters in Category VI, ten Fitters in Category V and 14 Fitters in Category IV in No. 1 Incline, that in each shift there are one Fitter in Category VI, one Fitter in Category V and four Fitter Helpers but there are no Fitters of Category IV that if Category VI Fitter is absent, Category V Fitter would be in charge that these Fitter Helpers work independently that they are doing the same work that Category V Fitters are expected to do, that whenever Category IV Fitter is absent the Fitter Helper acts in his place and he is paid IVth Category acting allowance, that ordinarily the Fitter Helper is given Category I, that claimants 1 to 19 get in a month each 6 to 8 times IVth category allowance in No. I incline, that they Fitters send the Fitter Helpers to do the work whenever there is any break down, that there are Fitter Helpers working in the Mines at Kothagudem, Bellampalli and Mandamari who are in Category II now and that when Categories V and VI persons are absent the Fitter Helpers are kept in charge of the district. In his cross examination he says that so far as the claimants 1 to 19 are concerned as per Company's record now these persons are Fitter Mazdoors, that he had been sending them atleast four times in a week, so far as this shift is concerned by rotation that the duties referred to by him relate to Category V, that they Fitters also used to attend to those duties, that no doubt they Fitters have to attend to the above duties, that it is not correct to say that they Fitters have no authority to send these Fitter Mazdoors, that the Engineer has given him authority that it is not correct to say that no such authority was given to him, that when he sent Fitter Helpers to attend to other work he was attending to major breakdown, that for each shift there are one category V and one Category VI Fitters, that after the Fitter Helper attends to the repair work he would report to him and he would send the report at the end of the shift, that the claimants are not claiming Category V but they are claiming Category II because they feel that they won't be given Category V if they asked straight-away Category V, that claimants 1 to 19 were given acting Category IV allowance whenever they worked in Category V, that they never made any complaints that they were never given acting allowance, that in the Tradesmen agreement there is designation as Fitter Helper, that he does not know whether the Fitter Helper in Kothagudem and Bellampalli were in old Category III prior to the Wage Board but all that he knows is that after Wage Board they are in new Category II, that the Company does not give separate tools to the Fitter Helpers and that it is not true to say that the claimants have only to assist the Fitter and that they cannot do work independently.

9. W.W. 4 (K. Krishnamurthy) is working as Electrician in No. I Incline from 26-2-1965. He says that he knows the claimants 27 to 38 who are working in No. I Incline in Godavari Khani as Electrical Mazdoors, that for each shift in Machine Mining there are six Category V Electricians, five Category IV Electricians and one Category VI Electricians, that in Hand Mining Section there are no category VI Electricians, that there are four Category V Electricians and four Category IV Electricians in Machine Mining Section, that in the general shift in Machine Mining there are one Category VI Electrician and one Category V Electrician and one Category VI Electrician and in the other three shifts in each shift there are one Category V Electrician and two Category IV Electricians, that Category V Electrician will be incharge, that claimants 27 to 38 act in the place of Categories IV and V Electricians whenever they go on leave, that they will get Category IV acting allowance, that if the Helper is sent away separately to another district to act in the place of Category IV and V Electrician he works independently there, that when the Helper goes to act in other district he will submit his report to the electrician incharge of that shift in Kothagudem and Bellampalli and that the same kind of Helpers are in new Category II. In his cross examination he says that claimants 27 to 38 are shown in the Company records Electrical Mazdoors, that they were in Category I prior to Wage Board and they are in Category I subsequent to the Wage Board, that the work that he gets done through the Helpers is the work that he has to do it himself as Electrician, that he gets work done by Helpers under his supervision, that when the Helpers works under him he works as Electricial Helper, that whenever they acted as Category V or Category IV Electrician they were given acting allowance, that they never complained that they were never given acting allowance, that claimants 27 to 38 are authorised to work in the place of Category V and IV Electricians in their absence, that except one Balakrishna, who is designated as Electrical Helper, there are no other persons designated as Electrical Helper and that Balakrishna was transferred to Ramagundam from Kothagudem.

10. W.W. 5 (G. Limbadri) is working as Electrician in Category V in No. 2 Incline, Godavari Khani. He says that he knows claimants 39 to 44, that they are working as Electrical Helpers in No. 2 Incline, Godavari Khani, that there are three districts in No. 2 Incline, that he and one Category I Electrical Helper are incharge of one district, that one category IV Electrician is incharge of 2nd district, that Category I Electrical Helper is incharge of third district, that if that Helper sends any report about major work then he would go and attend to it, that whenever any Electricians of Category IV and V are absent then the Helpers are deputed by the Manager to work there and that in Mandamari, Kothagudem and Bellampalli the same kind of Electrical Helper are given new Category II. In his cross examination he says that claimants 39 to 44 are now in new Category I, that the tools are given even to Electrical Helpers, that the tools will be under his (W.W. 5) custody, that no doubt all repairs on the electrical side should be done by electrician but the Engineer will depute to a particular district, that it is only Category I Electrical Helper who is sent to the other district who will be incharge of that district,

that no authorisation is given to them that it is only pursuant to the instructions given by the Engineers these Helpers are sent for attending to the repairs, that he does not know the old Category Helper Electrician in Bellampalli and Kothagudem and that some of the persons working at Ramagundam are those who were transferred from Kothagudem and that Category I Electrical Helper who is incharge of third district has no authorisation.

11. W.W. 6 (M. Sudarsanam) is working as Category IV Fitter in No. 5 Incline in Godavari Khani. He says that he knows claimant 22 who is working as Fitter Helper in No. 5 Incline, that he works as Helper to Category V Fitter, that no Helper is given to Category IV Fitter, that whenever Category V Fitter is absent he (W.W. 6) acts in that place and claimant No. 22 acts in his place, that if other Category IV Fitter is absent he acts in that place, that he gets acting allowance when he acts, that he gets acting allowance like this for about 15 days a month, that when he (claimant No. 22) is not acting as Category IV Fitter he works under Category V Fitter, that he does not carry tools as Category V Fitter that he works along with Category V Fitter, that he knows claimants 45 to 48 who work as Electrical Helpers in No. 5 Incline, that they work under Category V Electrician, that they also get acting chance in Category IV or Category V whenever that Category Electrician is absent, that they get acting allowance like that for about 10 to 15 days in a month and that the Fitter Helpers and Electrical Helpers working in Kothagudem and Bellampalli are given new Category II. In his cross examination he says that Category IV Fitters duties are repairs and maintenance of water pumps Haulers, that he has no Fitter Helper or Mazdoor, that when claimant No. 22 acts in Category IV he is given acting allowance, that in a week itself he would get two days for acting in Category IV as he is given two days rest, that in one shift when he (claimants No. 22) is incharge of one district either Category IV or Category V man will supervise his work, that in the Company's record the Electrical Helpers are shown as Category I Mazdoors but actually they are working as Helpers, that in 1966 Tradesman Agreement there is no designation as Electrical Helper, that those who are working as Electrical Helpers in Kothagudem and Bellampalli were in old Category III prior to Wage Board and after Wage Board they were given new Category II, that these persons are attending to the repairs because the Engineer is asking them to do the repairs, that they do not have authorisation and that he and others also attend to repairs.

12. W.W. 7 (D. Pratap Reddy) is working in No. 7 Incline Godavari Khani as Fitter since nine years. He says that he knows claimants 24, 25, 51 and 52 that claimants No. 28 and 25 are working as Fitter Helpers, that their work is maintenance of shifts whenever Category IV Fitters are absent, that on an average they would act about 20 times in Categories IV in a month that the claimants Nos. 51 and 52 were promoted as Category IV Electricians about six months ago (this witness was examined on 24-6-1972), that prior to that they were working as Electrical Helpers, that he knows about the Mines in other divisions of Singareni Collieries, that for each Mine there are eight Electrical Helpers and eight Fitter Helpers, that in the new Mines in Ramakrishnapur and Mandamari also there are eight Electrical Helpers and eight Fitter Helpers, that there are four Category IV Fitters in No. 7 Incline when he was working and that as there is no required strength in No. 7 Incline, claimants Nos. 24 and 25 also work as Category IV Fitters. In his cross examination he says that when he was sent away to No. 7 Incline from No. 5 after promoting him and when he reported for duty in No. 7 Incline there were no Fitter Helpers but Pump drivers were helping him that the pump drivers were in Category II, that claimant No. 24 is still in old Category I, that he joined service as mazdoor and he was posted to Category I as Pump Khalasi, that it is not true to say that he (W.W. 7) has to do only minor fittings and that instead of his doing that work he had been getting the work done by claimants 24 and 25, that in the general shift there are one Fitter of Category IV and one Fitter of Category VI and one Mazdoor of Category I, that he knows about Tradesmen Agreement relating to Ramagundam but he does not know its details, that he did not see any authorisation given to the claimants 24 and 25, that claimants No. 24 and 25 never used to carry their tools (his and others) that in each shift there used to be additional mazdoor, that he does not know whether any person had any training in any place, that these persons (he means claimants 24 and 25) are asking now for IVth Category, that claimants 24 and 25 are shown as Fitter Mazdoors in the Company's records, that the Company did not give them trade test and they also did not ask for getting trade test done, that whenever they acted in Category IV in the absence of Fitters they were getting acting allowance, that it is not correct to say that no one gets allowance 20 times a month, that it is true that claimants No. 51 and 52 were given promotions after seeing their work on the electrical side and that he does not know whether they were given promotion in view of paucity of hands in the electrical side.

13. W.W. 8 (C. P. Ramalingam) is working as Overman in No. 1 Incline in Godavari Khani. He says that claimants Nos. 1 to 18 and 27 to 38 are working in No. 1 incline in Godavari Khani, that claimants No. 1 to 18 are working as Fitter Helpers on the mechanical side and claimants No. 27 to 38 are working on Electrical Helpers on the electrical side, that these Helpers won't carry the tools, that there are two Category IV Fitters in Machine Mining but they attend only to the surface job, that these Fitter Helpers work in the place of Category IV workers, that on an average they work in the place of Category IV workmen in a month 10 to 20 times, that the Fitter Helpers and Electrical Helpers do work independently and they know elementary fitting and assembling and a maintenance work, that in Yellandu and Kothagudem there are Fitter Helpers and Fitter Mazdoors and Electrical Helpers and Electrical Mazdoors, that, therefor each district are two or three category IV Fitters and one Category V Fitter and two or three Helpers per shift, that he did not work as Overman at Kothagudem, that he worked as Sirdar at Yellandu, that there are Fitter Helpers and Electrical Helpers at Ramakrishnapur and Mandamari, that even when there are Fitters, if these Helpers do any independent work they give report about the work done by them, that it is only pursuant to the orders of the Management that these Helpers are asked to work in the place of Category IV Fitter and that along with Fitter general mazdoor also would go, that if there is any break down the helpers would work along with Fitter. In his cross examination he says that his main responsibility is to shift production of coal and its despatch and safety, that in each shift there is one Category V Fitter and there are Category VI Fitters one in each shift only in A, B, and D shifts but not in relay 'C' shifts, that it is not correct to say that he has nothing to do with the supervision of electrical and mechanical side, that he does not have training in electrical and mechanical side relating to Engineering work, that Category VI persons attend to the work there, but he gets shift and reports, that the persons shown as Serial Nos. 1 to 18 and 27 to 38 in the schedule to the reference are shown as Mazdoors in the Company's records but the work extracted from them is only as Helpers, that these persons are saying that they are Helpers and that these Helpers are claiming Category II.

14. W.W. 9 (Bangaru Sayulu) is working as Fitter in Godavari Khani No. I Incline. He says that Nos. 1 to 19 in the schedule to the reference are working in No. I Incline as Fitter Helpers, that out of them 12 persons are working in the Machine Section and the remaining are working in Belt Section, that he (W.W. 9) is working in the Belt Section, that in his Belt Section three of Category IV and one of Category V and himself are working, that there are two districts in this No. I Incline that as per shift there would be two persons working and they are one Fitter Helper and the other is Fitter in Category IV, that the Category IV Fitter will look after one district and the Fitter Helpers will look after the other district in No. I Incline, that Category IV Fitter will attend to the maintenance and repair work of the Belts and belt joints, that Fitter Helper who works in the other districts also does the same work as Fitter of IV Category in his district, that the Fitter Helper attends to the normal repairs by himself with the assistance of daily mazdoors and if there are any major breakdowns then only he would go and inform the Fitter of Category IV working in the other district, that there are no mazdoors as such given to Fitter Helpers to assist them, that they would take the help of Daily Mazdoors there doing other jobs if he cannot lift heavy articles, that for about 12 to 15 days in a month Fitter Helpers get Category IV acting allowance when they act in the place of Category IV Fitters or when they are incharge of one district, that in the Machine Mining Section there are Twelve Fitter Helpers and four of Category VI Fitters and three Category V Fitters, that per shift one Fitter of Category VI, one Fitter of Category V

and two Fitter Helpers of Category I work, that in the Machine Mining Section one Category V Fitter attends to the major breakdown in one district, that Category VI Fitter attends to the work of erection and two Category I Fitter Helpers attend to one district and one Category I Fitter Helper helps Category VI Fitters and another helps Category V Fitter, that the two Category I Fitter Helpers who are in-charge of one district attend to the maintenance work in that District, that they attend to all the breakdowns which they are capable of attending, that these two Fitter Helpers in-charge of one District get acting allowance of Category IV according to the work done by them, that there are one Fitter Helper and one Electrician in Category II and that one is working in No. I Incline and another in No. 5 Incline. In his cross examination he says that out of 19 persons whose names were put to him from the reference he has contact only with five persons, that there is no mazdoor for Category IV, that it is not correct to say that they are only carrying tools, that one mazdoor goes with Category V Fitter carrying his tools, that at time his mazdoor is asked to go and look after the work in other district, that instruction is given by higher category Fitter, that no doubt it is the responsibilty of the higher Category V Fitters to look after the other District where the Fitter Helpers work, but due to want of time they may not go there to check but reports also would be given to Category V persons that whenever they are put on job of higher category they are being paid acting allowance that he does not know about any Tradesmen Agreement at Ramagundam, that he does not know whether in the records these persons are shown as Fitter Helpers but they call them as Fitter Helpers, that Category V and VI Fitters have orally told the Higher authorities about the work done by these Fitter Helpers, that in the case of these Helpers working in No. I Incline though they had orally recommended their case the Management did not give higher category, that he does not know whether this question came up before the Grievance Committee and whether they were informed that these persons lacked experience, that only for Balakrishna, who is Electrician, Category II was given, that he does not know whether he was transferred from Kothagudem and that no other person was given Category II in No. I Incline.

15. M.W. 1 (R. K. Sinha) is working as Mechanical Charge hand at G.D.K. No. 1 Incline. He says that below him the set up is one Fitter of Category VI in Hand Section, two Category V Fitters, four Category IV Fitters and in the Machine Mining Section there are four Categories VI Fitters, five Category V Fitters and seven Category IV Fitters, that there is one Category VI Fitters who is always in general shift in the Machine Mining and in Hand Section, that the details of the work of claimants 1 to 19 and 27 to 38 referred to in the schedule are that after they report to duty in Manway office they come straightaway to their respective category VI and V Fitters and they will carry tools of the Fitters to the work spot and they will go along with him to other places, that these claimants will work according to the instructions given by the Fitters, that for example when they open the bolts and nuts other end will be rotated along with the spanner and so he has to hold the nut and bolt tightly and if the Fitter wants extra work bodily than the mazdoor helps him for putting more strength on the machinery at the time of fitting or dismantling, that it is not correct to say that the claimants are doing the duties of repairing of shuttle car and joy Loader and cutting machines that this work is done by Category V fitter as this job is to be done only by the Fitters, that the claimants carry out the miscellaneous duties like repairing Hydraulic Hose pipes, and brake bands along with the Fitter, that the claimants 1 to 19 are designated as Fitter Mazdoors and claimants 27 to 38 are designated as Electrical Mazdoors by the Company, that there is no designation as Fitter Helper to his knowledge in Ramagundam Divisions, that the said claimants never complained to him that the work of higher nature was being extracted from them, that if they work in the leave or absence vacancies they are given Category IV acting allowance, that prior to Wage Board they were in old Category I and after Wage Board they were absorbed in Category I (new), that they are carrying out the same work, that is, Fitter Mazdoor work that they were doing prior to Wage Board, that authorisation to work as Fitters is given to the said claimants only when the said claimants work as Fitters in the vacancies caused due to the absence or sick leave, that in Ramagundam Divisions there is no designation as Electrical I or Fitter Helper, that if Category I man is promoted he would be given Category IV, that he is not given Category II or Category III when he is promoted and he is straightaway given Category IV, that for those who were working in Category II and III after Wage Board they were given Category IV irrespective of their designations, that none of the claimants referred to by him wherein old Category II and III and that they were in old Category I only and after the Wage Board they were given new Category I. In his cross examination he says that in the Hand Section one Category VI Fitter works in the Central Shift and in the other shifts one Category V and one Category IV and one Category I mazdoor work in each of these shifts, that in the general shift along with Category VI Fitter only one mazdoor helps him and no others, that they send one Category VI persons to one district and one Category V Fitter to another district of Machine Mining, that there are Category IV Fitter mazdoors, that Category VI Fitter who is working in the General shift will attend to the breakdown if any in one district with the assistance of Category I mazdoor and when carrying out these repairs by Category VI fitter if Category I mazdoor is asked to attend to the other district then Category I mazdoor would be given Category IV acting allowance straightaway, that whenever Category IV or Category V Fitter is absent, Category I person would be deputed in his place and when he is so deputed he would be given Category IV or Category V acting allowance as the case may be, that the present claimants would get about 8 to 10 times in a month the acting allowance according to their seniority and presence in the shift, that the claimants know the work of Category IV Fitter or Electrician as the case may be, that the present claim of the claimants is Category II but he does not know whether their claim is on the ground that they are helping the Fitters or Electricians as the case may be, that he does not know whether at Kothagudem and Bellampalli there is any designation as Fitter Helper and Electrical Helper and whether any such persons are placed in new Category II but all that he knows is that one persons was transferred in 1965 from Kothagudem to Ramagundam designated as Electrical Helper who was placed in new Category II after Wage Board and he is helping or assisting Category V or Category VI Electrician as the claimants do, that one Sangiah, who was Electrical Helper in 1962, when he (M.W. 1) joined service, is now in new Category VI and for a year he was Electrical Helper in old Category III and he was given old Category IV in 1963 or 1964 after he passed the trade test, that whenever Category I person is given Category IV acting allowance he attends to the maintenance and the repair work done by Category IV Fitter and that when Category V or Category VI Fitters work on the particular machinery with the help of Category I Mazdoor, they would ask Category I mazdoor to do the elementary work or Fitter or Electricians as the case may be on that particular machinery.

16. M.W. 2 (M. Satyanarayana) is working as Assistant Engineer in G.D.K. No. 5 Incline. He says that he is the only A.E. for both electrical and mechanical relating to No. 5 Incline, that claimants No. 1, 20, 22 and 45 to 48 mentioned in the schedule to the reference are working in No. 5 Incline, that there are two sections known as Machine Mining and Hand Sections, that the set up in Hand Section is there are one Category VI Fitter in general shift, one Category V Fitter in general shift, three category IV fitters in general shift, three Category V Fitters for the three shifts, one in each shift, three Category IV fitters one in each of the three shifts and so far as Electrical side is concerned there are three Category V Electricians, one in each of the three shifts, three Category IV Electricians one in each of the three shifts and one Category IV Electricians in the general shift and the Electrical Charge hand is common to both Machine Mining and Hand Sections, that in the Machine Mining Section there are two Category VI Fitters in General Shift, two Category V Fitters in the general shift, six category IV fitters, that is, two in each of the three shifts and one Category IV Fitter in general shift and on the electrical side there are one Category V Electrician in the general shift and three Category V Electricians for the three shifts one in each but actually now there are only two working and the third place is vacant, and there are four Category IV Electricians for the three shifts, that the number is four because of shortage of one Category V Electricians and as one of those four is doing the duties of Category V Electrician in the existing vacancy, that the designation of numbers 1 and 22 in the schedule to the reference are Fitter Mazdoors as per the Company's records and Nos. 20 and 45 to 48 in the schedule to the reference are Electrical Mazdoors as per the Company's records, that apart from these mazdoors

there are no such mazdoors in No. 5 Incline, that these mazdoors are assigned to a particular Fitter or Electrician as the case may be for carrying the tools of that particular Fitter of Electrician and they have to accompany them underground and they would also carry other materials like kerosene, measuring and insultation tapes, that after reaching the work spot they would take the tools from the bag and give to the Electrician or Fitter as the case may be and they would just hold spanners on one side when the Fitter or Electrician tries to remove the bolt and nut, that a mazdoor is given only to Category V and VI Fitters but not to Category IV Fitters, that there is no designation of Fitter Helper or Electrical Helper at G.D.K. No. 1 and 2 Inclines, that the pre-Wage Board Category of the claimants was Category I, that the duties performed by them are the same done by them prior to or after 1967, that normal maintenance of the shift like extension of Section, tightening of the bolts and nuts of Hauler and pumps in the Hand Section are done by Category IV Fitters that in the Machine Mining Section Category IV Fitters do the work of adjusting and changing of the brake bands of loaders and coal cutting machine and joining of conveyor chains and tractor chains of the coal cutting machines, that there was never any representation made to him or at the pit level by these claimants stating that they were doing higher jobs than that of a mazdoor, that whenever Category IV or V Fitters or Electricians are absent the claimants used to be sent to do that work and they used to be paid Category IV or Category V wages as the case may be, that in a week such acting arrangement are effected once or twice, that when these mazdoors are promoted they are straightaway given Category IV, that when they are given acting allowance of Category IV when they work in Category IV they are expected to attend to the maintenance work alone and no higher work is extracted from them, that serial No. 22 in the schedule to the reference is Category I Fitten Mazdoor and his work is that of only Fitter Mazdoor and he was now and then given Category IV job that there are sufficient number of Fitters and Electricians to meet the demand of the Section that there are no vacancies now in the Fitter and Electrical Sections that the general mazdoors and Tyndals are given to the Fitters and Electricians of Category V depending on the nature of work, that there is difference in work done by the general mazdoor and Tyndals when compared with Category I mazdoors about whom he mentioned earlier and the difference in work is that Category I mazdoors about whom he said would carry only the tools whereas the other mazdoors would carry heavy articles on their shoulders, that the claimants, about whom he mentioned would not do elementary fitting or Electrician work when they go with the Fitters or Electricians as the case may be, that he had no occasion to trade test the claimants whose names he referred to, that only Sathiah that is serial No. 1 in the schedule to the reference is I.T.I. candidate and that he had been promoted to Category IV in the same mine.

17. In his cross examination he (M.W. 2) says that he does not know whether any person designated as Fitter Helper and Electrical Helper at Kothagudem and Ballampalli and sent along with Fitters or Electricians as the case may be, that mazdoor is not given to Category IV Fitter because of Tradesmen agreement, that reason for giving mazdoor to Category V and VI Fitters is they are expected to do more skilled work than Category IV Fitter and as they have to take more tools than Category IV Fitters, that Category IV Fitters and Electricians carry their own tools and they work for themselves and they won't have any assistance and assistance would be given to them only when they ask for it when heavy work is there, that the claimants know the job of Category IV Fitters or Electricians as the case may be and they have worked as Category IV Fitter or Electrician as the case may be for some time and they were paid acting allowance, that these Category I Mazdoors will follow the instructions of the Fitter or Electrician when they go with them, that general mazdoors who are in Category I and Tyndals who are in Category IV do the manual work when they are deputed to assist the Fitters in shifting heavy machinery etc., that the Tyndals and General Mazdoors do not know the work of Category I Mazdoor Fitter or Electrical, that when Category V and VI Fitter or Electricians are doing a particular job they would take the assistance of the claimants for holding one end of the bolt and in giving the tools to them, that when Category V or VI Fitters or Electricians are working in one district and if they attend to some work in the other district, they would not ask Category I Mazdoors, that is, the claimants to do any minor works in the other place because there are also Category IV Fitters and Electricians, that he knows nothing about that recommendations of the Wage Board but the Wage Board has given designation of Fitter Tool carrying only as unskilled, that the Tub repairing mazdoors are in Category II, that at Ramagundam there are no pipe fitting mazdoors but some Category IV Fitters do the pipe fitting work at Ramagundam, that it may be that because Tradesman Agreement at Ramagundam does not provide for Fitter or Electrical Helpers there is no designation as Electrical or Fitter Helpers, that he does not know whether there is any such Tradesman Agreement at Kothagudem and Ballampalli, that the wage schedule of the Company provides for Category II for Fitter and Electrical Helpers, that there are two Electrical Helpers in new Category II in No. 5 Incline in Ramagundam who have been transferred from some other place, that he does not know whether the claimants made any representation to the management that they should be given Category II as per the Wage Board, that No. 1 in the schedule to the reference, that is, Sathiah has been promoted as Category IV Fitter from Category I Mazdoor in view of Tradesmen Agreement and since the Tradesmen Agreement does not provide for promotion of Category I Mazdoor to Category II.

18. M.W. 3 (Mohd. Abdul Jabban) is working as Safety Officer in G.D.K. No. 1 Incline. He says that on the daily rated set up there are one Category VI Electrician, five Fitters of Category VI and there are also Category V Fitters and Electricians and there are six Fitters and eight Electricians and there are six Fitters of Category IV and eight Electricians of Category IV, that they do not have any Fitter Helpers in Ramagundam Divisions I and II and claimants 1 to 19 shown in the schedule to the reference are working as Fitter Mazdoors and their specific job is to carry the tools of the Electricians and Fitters of Category V and VI, that after reaching the spot they would follow the Fitters or Electricians as the case may be, that they do not have separate set of tools for themselves, that out of these 19 names some were directly taken as Fitter Mazdoors and Electrical Mazdoors as the case may be and some in higher Category had opted to be Fitter Mazdoors, that Ex. M 1 is the copy of the list of mazdoors working in No. 1 Incline, that No. 33 in Ex. M 1 was previously working as Tyndal and now he is working as Fitter Mazdoor, that No. 14 in Ex. M 1 was previously working as Conveyor Khalasi and now he is Fitter Mazdoor, that these persons of higher Category opted to lower Category as they wanted some light job, that it is not correct to say that these Fitter Mazdoors are doing the work of repairing coal cutting machines, loader etc., independently, that neither W.W. 1 nor others represented that they were given wrong designation and they are extracting higher work, that it is wrong to say that W.W. 3 and others are Fitter Helpers, that if due to absenteeism or sickness in case of Category IV Fitter these Fitter Mazdoors are being sent to maintenance of normal work, in such cases they pay category IV acting allowance for that particular day, that it is not correct to say that claimants Nos. 27 to 38 in the reference are working as Electricians, that they are working only as Electricial Mazdoors, that they are also given higher Category allowance, when the particular category Electrician is absent, that claimant No. 20, who is Electrical Mazdoor, is given Category IV allowance whenever he works in that Category in the absence of that particular Electrician that their previous category prior to Wage Board was Category I and they are doing the same work that they were doing prior to Wage Board, that on the engineering side for promotion from Category I to Category IV the procedure followed is that when vacancies arise then Category I man is promoted to Category IV, that some of the persons who were promoted like that are claimant No. 35 in the schedule to the reference and one R. Ramulu who is sent for trade test for promoting him to Category IV, that there is now sufficient strength in the mine both on the Electrical and Mechanical sides and it is as per the strength fixed under the Tradesmen agreement, that about four times in a month there are chances of working in the higher category and getting higher category allowance, that even when they are given this higher category allowance on those occasion they are asked to maintain only the normal work and if there are any breakdowns they have to report to Category V or Category VI Fitters, that no Fitter Mazdoor made any representation to him that higher Category work is extracted from them and they are paid only as per lower Category, that they observes the

persons ability and send them for Trade Test and that if any vacancy arises then only they would send some of the workers for trade test.

19. In his cross examination he (M.W. 3) says that Category IV Fitters attend only to minor repairs, that in the Machine Mining Section in each shift there are one Category V Fitter and one Category VI Fitter and each will be incharge of one district, that in the Hand Mining Section there are one category V and one Category IV Fitters and Category V will be incharge of both the districts, that these Category IV Fitters are only for maintenance of one district, that Category IV, Fitter is not given to any mazdoor, that after going to the spot along with Category V or Category VI Fitters as the case may be he will be given whatever assistance that Category V and Category VI Fitters want, that all the Fitter Mazdoors and Electrical Mazdoors may not know the elementary Fitter or Electrical work, that no mazdoor can work as Category IV Fitter or Electrician without knowing the elementary work of Fitter or Electrican job as the case may be, that it is only some of the Fitter Mazdoors and Electrical Mazdoors mentioned in the reference who work as Category IV Fitters or Electricians as the case may be but not all of them, that claimants 1 to 19 and 27 to 38 might have worked as Category IV Fitters or Electricians as the case may be and get acting allowance at sometime or other, that he does not know whether at Kothagundem there is any designation of Fitter Helper and Electrical Helper, that they do not have Category II Fitter Helper or Electrician Helper in Ramagundam Divisions I and II, that there are only Fitter or Electrical Mazdoors, that whenever there is any breakdown Category V and Category VI Fitters will be assisted by Fitter Mazdoors while attending to the repairs, that even minor repairs cannot be entrusted to the Fitter or Electrical Mazdoors, that there is no provision in the Tradesmen Agreement for Ramagundam area for appointing any person as Fitter Helper or Electrical Helper, that Fitter Mazdoors and Electrical Mazdoors who are in Category I are directly promoted to Category IV Fitter or Electrician, that no doubt Wage Board had recommended that a mazdoor having elementary knowledge of fitting or electrical work should be given Category II Fitter Helper or Electrical Helper but no such Category is given as is no such category in Ramagundam Divisions I and II.

20. M.W. 4 (G. V. Krishna Rao) in working as Assistant Engineer in G.D.K. No. 2 Incline. He says that claimants 20, 21 and 39 to 44 mentioned in the schedule to the reference are working in G.D.K. No. 2 Incline, that they are in new Category I, that they assist the Fitters and carry the tools when they go for work, that the normal work done by these claimants underground is they carry the tools and tools required by the Fitters and help the Fitters in tightning the bolts and nuts, that during sick leave vacancies Category I workers are allowed to act and they are given Category IV allowance that as per the Tradesmen agreement entered into in 1966 there are no Categories II and III in the Engineering side, that in a month these workers may get the acting chance between 5 to 10 times, that these workmen in Category I would be trade tested and promoted to category IV, that there was no occasion for trade testing these claimants for giving promotion, that they are doing the same work that they were doing prior to Wage Board, that they have sufficient number of workers in each category, that some electrical mazdoors of Category I maintain the district and on those days they are paid category IV Allowance, that they maintain district some time through out the week and at other times they are posted in leave vacancies and they are paid acting allowance IV Electrician for those days and that these claimants never made any representations that they should be given higher category. In his cross examination he says that the Fitter Mazdoor knows the work of Fitter and Electrician Mazdoor knows the work of Electrician, that whenever they are given Category IV they do the work of Category IV Fitter or Electrician as the case may be, that Category IV Fitter and Electricians attend to the maintenance work and some times they attend to the errection work also, that the Fitter and Electrical Mazdoors in G.D.K. No. 2 are some time incharge of the district, that normal Category IV or V Fitters and Electricians will be incharge of the district, that Fitter or Electrical Mazdoor will be incharge of the District some times three or four times in a week but they won't pay Category IV allowance for all those days, that at Kothagudem and some other mines the Management has given new Category II for Fitter and Electrical Helpers, that they do not have Category II Fitter or Electrical Helpers in G.D.K. No. 2, that these Fitter Mazdoors come under the job description given in Item 22 at page 44 of Volume II of the Wage Board Recommendations and that those who are now in Category II in Kothakundem and other mines were in old Category III.

21. So from the evidence of all the witnesses referred to above it is clear that so far as Ramagundam Divisions I and II are concerned there is no designation as Electrical and Fitter Helpers, though there is such a designation in the other mines at Kothagudem, Bellampalli etc., and that in view of the Tradesmen Agreement entered into as regards Ramagundam Divisions I and II, in the set up of the various categores there were no old Categories II and III and that there were only old Categories I, IV, V and VI. No doubt one of the contentions of the respondent's representative is that these so called Fitter and Electrical Helpers are claiming higher category in I.D. No. 30 of 1967 and that if any decision is given in the present proceedings about higher Category asked for by the claimants it would be pre-judging the issue in I.D. No. 30 of 1967. But the contentions of the learned counsel for the petitioner is that so far as the present claim of the claimants is concerned it only relates to fixation of the correct category as per wage board and that it has nothing to do with the claim in I.D. No. 30 of 1967. It is now seen from the claims statement in I.D. No. 30 of 1967 that the Fitter Helpers have claimed Category IV, but so far as the present case is concerned the contentions of the petitioners are that they are doing the duties of only Fitter or Electrical Helpers as the case may be and that as per the recommendations of the Wage Board considering the job description given under Item 22 at page 44 of Volume II of the recommendations of the Wage Board they should be given new Category II but they have been wrongly given new Category I and that so far as the electrical and fitter helpers in Kothagudem, Bellampalli etc., are concerned, they have been given new Category II and so they also should be given new Category II. So as rightly contended by the learned counsel for the petitioner the claim in I.D. No. 30 of 1967 has nothing to do with the present claim.

22. Now, even from the evidence of the witnesses examined on the side of the respondent, it is clear that at least some of the claimants who are in new Category I are asked to do the duties of new Category IV fitter or Electricians as the case may be whenever those Fitters or Electricians are absent and that they are also given the Category IV acting allowance and that because those claimants have the elementary knowledge as per the job description given for Fitter Helper by the Wage Board they are asked to work in Category IV vacancies. The evidence in this case also shows that these claimants were only in old Category I and that after Wage Board they were placed only in new Category I. So far as the Fitter and Electrical Helpers in Kothagudem, Bellampalli, etc., are concerned the evidence shows that they were in old Categories II and III and so at the time of implementation of the recommendations of the Wage Board they were placed in new Category II. So from the evidence it is clear that so far as Kothagudem, Bellampalli etc., are concerned already there were designations like Fitter and Electrical Helpers and that since they come under the job description given for Fitter Helper in the recommendations of the Wage Board they were given new Category II. So far as Ramagundam Divisions I and II are concerned the evidence in this case clearly shows that in view of the Tradesmen agreement entered into even prior to the Wage Board the number of Categories were fixd and that so far as the claimants are concerned they were designated only as Fitter and Electrical Mazdoors and they were given old Category I and that there were no old Categories II and III and that the next category was only Category IV Fitter and Electrician and that since the duties of these claimants were mainly of carrying the tools and assisting Category V and VI Fitters or Electricians as the case may be, at the time of implementation of the recommendation of the Wage Board the respondent had fixed the claimants in new Category I, because of the job description given for Item No. 3 Fitter (tool carrying only) in Category I in Appendix V shown in page 41 of Volume II of the recommendations of the Wage Board. No doubt the evidence in this case shows that, even according to the respondent at least some of the claimants have got the elementary knowledge of Fitter or Electrical Helpers as per the job description given for Item 22 under Category II in the same Appendix V. but when there is no designation as Fitter Helper or Electrical Helper in Ramagundam Divisions I and II in view of the

Tradesmen Agreement, even though the said claimants have got the elementary knowledge of a Fitter or Electrical Helper as the case may be, it does not mean that hey should be straightaway given new Category II. If this is a case where even in Ramagundam Divisions I and II there was designation of Fitter and Electrical Helpers and if inspite of it the Management has not given new Category II to the claimants, then different consideration would have arisen. It is because they have got some elementary knowledge of Fitter or Electrical Helpers whenever Category IV vacancies arise they are asked to do that work and they are paid the acting allowance. The evidence already referred to also clearly shows that even for promotions, so far as Ramagundam Divisions I and II are concerned, the promotions were directly from old category I to Old Category IV and that there was no promotion to old Category II or III since no such categories existed so far as Ramagundam Divisions I and II are concerned. Now virtually the present claim of the claimants amounts to only asking for promotion to higher category and, as rightly contended by the respondent's representative, giving of promotion to higher category is managerial function and certainly this Tribunal cannot usurp that function. Now from the evidence it is seen that the main work that the claimants as new Category I workers are asked to do is only of carrying tools and assisting Category V and VI Fitters or Electrician as the case may be.

23. No doubt the witnesses examined on the side of the petitioners have referred to different kinds of work said to have been done by these claimants and the evidence adduced on the side of the respondent is that he claimants are not doing different kinds of work referred to by the witnesses examined on the side of the petitioners and that the main work of the claimants is only of carrying tools and assisting category V and VI Fitters or Electricians as the case may be. But the evidence also shows that these claimants never made any complaints that higher category work is extracted from them and that they are paid lower category wages. If it is the case of the claimants that they are asked to do higher category work though as Category I workers they are not expected to do any higher category work, it is always open to them to stick to their rights and nobody can compel them to do higher category work and pay at the same time only lower category wages especially when it is the case of the respondent that the work of claimants is only of carrying the tools and assisting category V and VI workmen. Now from the evidence it is seen that whenever any of the claimants are asked to do Category IV job they are paid Category IV acting allowance. The evidence in this case also shows, that some of the claimants were also promoted to Category IV from Category I after trade testing them. So it is clear that so far as Ramagundam Divisions I and II are concerned there is no designation as Fitter or Electrical Helpers and that there is only the designation of Fitter or Electrical Mazdoors and that these Fitter and Electrical Mazdoors were previously in old Category I and that after Wage Board they were placed in new Category I and that whenever Category IV or Category V workers are absent some of the claimants are posted to their place and that those persons are also paid the acting allowance and that whenever any chance for promotion comes up it is only after testing the workers working in Category I the suitable persons are promoted straightaway to Category IV.

24. So even if it is assumed that all the claimants have got the elementary knowledge of Fitter Helper or Electrical Helper as the case may be, in view of the set up of the workmen in Ramagundam Divisions I and II, since these claimants were in old Category I they have been rightly designated as Fitter or Electrical Mazdoors as the case may be and placed in new Category I at the time of the implementation of the recommendations of the Wage Board and so there is no question of denying these claimants any wages of Electrical or Fitter Helpers. So far as Ramagundam Divisions I and II are concerned so far as Category I workers are concerned such of those who are found fit are straightaway promoted to Category IV. If the present claim of the claimants is allowed it would amount to creation of one higher category newly and giving promotion to Category I workers and in that case this Tribunal would be acting beyond its jurisdiction. If the present claimants are now designated as Fitter and Electrical Mazdoors and placed in new Category II then there would be no one in the new Category I and the Management has to appointed fresh new Category I workers and this would result in changing the set up agree to under the Tradesmen Agreement in Ramagundam Divisions I and II. Certainly this Tribunal cannot change the existing set up and if the claimants feel that they should be given Category II then they have to make their representations to the Management and change the set up in Ramagundam Divisions I and II, but they cannot get the set up changed indirectly by approaching this Tribunal. On a consideration of the whole evidence placed before me I am satisfied that the respondent is justified in designating these present claimants as Fitter and Electrical Mazdoors as the case may be.

25. For all the aforesaid reasons I hold on the dispute referrd to this Tribunal for adjudication that the Management of Ramagundam Divisions I and II of Singareni Collieries Company Limited is justified in designating the 55 workmen as Fitter/Electrical Mazdoors and that there is no question of denying these workmen wages of Electrical/Fitter Helper as the case may be since there is no designation as Electrical/Fitter Helpers in Ramagundam Divisions I and II and that the workmen are not entitled to any relief in these proceedings.

Award is passed accordingly.

P. S. ANANTH, Presiding Officer.

Dated 8-2-73.

APPENDIX OF EVIDENCE.

Witnesses examined for Workmen :	Witnesses examined for Employers :
W.W. 1 D. Bajaiah	M.W. 1 R. K. Sinha
W.W. 2 T. Someswara Rao	M.W. 2 M. Satyanarayana
W.W. 3. Mohd. Wahad Ali	M.W. 3 M. A. Jabbar
W.W. 4. K. Krishnamurty	
W.W. 5. G. Limbadri	
W.W. 6. M. Sudarsanam	
W.W. 7 D. Pratap Reddy	
W.W. 8 C. P. Ramalingam	
W.W. 9 Bangaru Sayulu.	

Documents exhibited for Workmen :	Documents exhibited for Employers:
Ex. W. 1 Memo dt. 18-5-1972 issued by the Manager, Godavari Khani No. 1 Incline to Dubasi Rajam Fitter Mazdoor.	Ex. M. 1 List showing the Category I Mazdoors of Godavari Khani No. 1 Incline.

P. S. ANANTH, Presiding Officer.

[No. L-2112/29/71-LR II]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 15th March, 1973

S.O. 909.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. A. Das and Company Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th March, 1973.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 52 of 1972

Parties :

Employers in relation to the management of Messrs. A. Das and Company, Calcutta,

AND

Their Workmen.

Present :

Sri S. N. Bagchi, Presiding Officer.

Appearances:

On behalf of Employers—Sri N. N. Chakravorty, Advocate.

On behalf of Workmen—Md. Idrish, Concerned workmen.

State: West Bengal. **Industry:** Port & Dock.

AWARD

By Order No. L. 32012/3/72-P&D dated 22nd August, 1972, the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, referred the following dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs. A. Das and Company, Calcutta and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the action of the management of Messrs. A. Das and Company in denying employment to Md. Idrish, watchman from 21st May, 1971 is legal and justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. The notice of the reference was sent to the management of Messrs. A. Das and Company, Calcutta and to the General Secretary, National Union of Waterfront Workers (INTUC) calling upon each of them to submit their statement of case within the date fixed. The management after taking two adjournments submitted its statement of case on 16-11-1972 but the union upto the date fixed for hearing of the case i.e. 19th February, 1973, neither appeared nor submitted its statement of case for and on behalf of the workman disputant concerned. On the date of hearing i.e. on 19-2-73 one application was purported to be filed by the General Secretary of the Union concerned with a thumb impression thereon purporting to be of the workman with a request to grant a week's time to enable the union to submit the written statement on behalf of the workman. The application filed on 19th February 1973 was not supported by any letter of authority enabling the General Secretary of the union concerned to represent the workman in this proceeding as required by Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 Form F of the Central Rules made under the Act. So, this tribunal took no notice of the application. The workman was himself present but no statement of case was filed on behalf of the workman concerned during the period from 2-9-72 to 19-2-73 inspite of notices. On the date of hearing i.e. on 19-2-73 as the workman himself was present and offered to represent himself in this proceeding by making statement on oath, he was examined by the tribunal as he had no lawyer nor any other representative duly authorised by law to represent him in this proceeding. His examination was not finished on 19-2-73 and he was further examined on 20-2-73. The management was represented by a lawyer on oath the days who did not cross-examine the workman. On 20-2-73 the workman himself filed a statement of his case before boarding the witness box which was kept in record for consideration. For the management Sri G. K. Das took his oath and was examined but was not cross-examined by the workman concerned.

3. The management Messrs. A. Das and Company is a proprietorship concern of one Mr. G. K. Das and is carrying on business as watchmen contractor. The employer company is to supply watchmen to the ships as per the order of the owners and/or agents of the ships to guard and/or protect the properties and/or Cargoes in the ship while the ships stay at the Calcutta Dock and Port. The workman concerned Md. Idrish was in the employ of the employer purely as temporary casual worker on the basis of no work no pay. The said workman Md. Idrish was deputed by the employer as one of the watchmen at the forehead of the ship "S. S. Steel Navigator-Voyage" in the night shift on 7-5-71. In connection with a theft of Nylon ropes from the said ship during the duty hours of the concerned worker, the worker was found guilty of negligence and misconduct in a departmental enquiry which was held at the instance of the employer after the chargesheet and reasonable opportunity of hearing was given to the workman concerned and/or his authorised representative. Thereafter by notice dated 24-5-72 the said workman was dismissed from his said work by the employer. The reference is otherwise bad and not maintainable in law inasmuch as the workman concerned is not a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, nor any industrial dispute exists between the parties under the said Act.

4. The workman's statement of case filed on the second day of hearing is as follows: Messrs. A. Das & Co. called him from home and got him arrested by the Police station of S.P.P.S. He was not found guilty after enquiry and was released from Police sation. In the office of the Regional Commissioner A. Das and Company told the workman that as Shamsul Haque went away after receiving Rs. 195 the workman was asked to leave the company after taking Rs. 400 or 500 because if the workman would remain as an employee under the employer Shamsul Haque would demand for job. Shamsul Haque however took Rs. 1000 but the company showed payment of Rs. 190. So the workman likes to say that he required employment for his livelihood or in the alternative he should be paid Rs. 1000 to do something for his livelihood. He is a poor man and is unable to engage a lawyer by paying heavy fees. So he leaves the case to be decided by the tribunal.

5. The fundamental question that arises in this reference is whether the dispute itself is an industrial dispute within the Industrial Disputes Act read with the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, Calcutta, Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, Calcutta Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957 and Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970. The Industrial Disputes Act, a Central Act, after enactment [illegible] on and from 11th March, 1947. The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, a Central Act was published in the Gazette of India, Part V, dated 27th November, 1947 at page 432 and was further amended by Central Act 8 of 1962 notified in the Gazette of India on 31st March, 1962 Part II Section 1 page 51 and came into force on 1st June, 1962 vide Gazette of India Extraordinary dated 30th May, 1962. The Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment(Scheme, 1956 framed under Section 4(1) of the Act was notified on 8th October, 1956. The Calcutta Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957 came into force on 29th June, 1957 framed under Section 4(1) of the Act. By repealing the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 and Calcutta Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 came into force on and from 1st July, 1970. Against the background of the provisions of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, and of the provisions of the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 that repealed the two earlier Schemes mentioned above, the question referred to for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, a Central Act, is to be answered.

6. The Industrial Disputes Act, 1947 is an Act to make provisions for the investigation and settlement of industrial disputes and for certain other purposes. The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, a Central Act, and a special statute in Section 3 subsection (1) speaks of a Scheme for ensuring regular employment of dock workers by making provisions by a scheme for the registration of the dock workers and employers with a view to ensure greater regularity of employment and for regulating the employment of dock workers whether registered or not in a Port. Subsection (2) of Section 3 of the Act in particular speaks of a Scheme which may provide as in Sub-clause 2(d) for regulating the employment of dock workers whether registered or not, and the terms and conditions of such employees including the rates of remuneration, hours of work and conditions as to holidays and pay in respect thereof. So, the Act and the Schemes made thereunder are self-contained Statutes regulating the employment of Dock Workers whether registered or not and terms and conditions of employment including rates of remuneration, hours of work and conditions as to holidays and pay in respect thereof. There are several other provisions to be made under the Scheme as provided for by several sub-clauses to Section 3(2) of the Act. In pursuance of the provisions of Section 3, a scheme was made under Section 4 of the Act entitled "Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956. In the interpretation of clause 3 of the said scheme there is the definition of registered dock worker, registered employer, reserve pool workers, dock employer, monthly worker and dock work. The workman concerned on oath stated that he was not a registered dock worker under Clause 3 sub-clause (n) of

the Scheme of 1956. The proprietor of the firm i.e. the employer as he styles himself on oath stated that he is not a registered employer as defined by clause 3 sub-clause (o) of the interpretation clause of the Scheme of 1956. Then came the Scheme of 1957 entitled Calcutta Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957. The workmen on oath stated that he was never a listed worker under clause 3(i) read with clause 9 of the Scheme. The employer G. Das also stated on oath that he was never a listed employer under clause 3(h) of the Scheme (i.e. 1957 Scheme). Those two Schemes were repealed by clause 62 of 1970 Scheme which reads as follows :

"62. **Repeal and savings :** (1) The Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 and the Calcutta Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957 are hereby repealed :

Provide that any order made right accrued penalty incurred or anything done or any action taken under the said Scheme shall so far as may be deemed to have been made, accrued, incurred or done or taken under the Scheme and any reference in any instrument to any provision of the said Scheme shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of the Scheme.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (1), on the constitution of the Board under Clause 4 of the Scheme (hereinafter referred to as the 'New Board')—

(a) the term of office of the members of the Board constituted under the said Scheme shall expire ;

(b) all property and assets vesting in the Board constituted under the said Scheme shall vest in the New Board ;

(c) all rights, liabilities and obligations of the Board constituted under the said Scheme shall be the rights, liabilities and obligations respectively of the New Board."

7. Clause 2(2) of 1970 Scheme relates to Port of Calcutta, as per Schedule V. Classes or descriptions of dock work and dock workers to which the Scheme applies are set out in Schedule I. The Scheme does not apply to any dock worker who is not specified in Schedule I. In Schedule I of the Scheme, the Clause (2) gives the several classes of dock workers within which the watchman-workman may fall, being Sub-clause (2)(1) "General Purpose Mazdoor." Dock work in clause 3(h) of the Scheme means operations at places or premises to which the Scheme relates, ordinarily performed by dock workers of the classes or descriptions to which the Scheme applies. The workman was employed as a watchman in the ship by the employer who carries on a business of contractor for supplying watchmen to the ship. What is the duty of the watchman ? He enters the premises of the dock when a ship is berthed at the dock and he is employed by the Captain of the ship or Agent of the Shipping Company to guard the berthed ship and its properties. The so called employer A. Das and Company collects men from an 'Adda' (Rendavoz) who are said to be working as watchmen of the ships. By collecting such men, the contractor carrying on business of supplying watchmen to the ship or its agents refers the watchmen to the Captain of the ship who employ them as watchmen of the ships and pay their daily wages through the contractor who supplies the watchmen, i.e. A. Das and Company. The workman involved in the dispute is one of such men whom the so called employer A. Das and Company collected from the watchmen's Rendavoz and referred him to the Captain of the ship who had asked the contractor A. Das and Company to supply watchmen, to guard the ship when berthed at the dock. The watchmen's duty is like that of a general purpose mazdoor. He is to watch the berthed ship and guard her properties so that there may not be any theft or pilferage of the property of the ship. So, he may be classed as a general purpose mazdoor as in Schedule I Clause 2 (1) of the 1970 Scheme. The work of watching the ship and guarding its properties when berthed at the dock is a "dock work" within clause 3(h) of 1970 Scheme. There is the registered dock worker is clause 3(p) of the 1970 Scheme meaning a dock worker whose name is for the time being entered in the register or record. There is the "registered employer" meaning the employer whose name for the time being is entered in the register as defined in clause 3(q) of the Scheme. There is the "reserve pool" in clause 3(r) of the said Scheme meaning a registered dock worker who are available for work but are not for the time being in employment of a registered dock employer or a group of such employers. Pool worker means a registered dock worker who is not a monthly worker as defined in Clause 3(n) of 1970 Scheme. The watchman concerned i.e. who falls in the category of general purpose mazdoor mentioned above stated on oath that he is not a "registered dock worker" though he used to work in the dock premises as a watchman of the ships when berthed at the dock. The duty of a watchman employed in the ship may thus be considered as the duty of a "general purpose mazdoor" as in Schedule I clause 2(1) of the 1970 Scheme. So the 1948 Act and 1970 Scheme apply to the workman disputant in this case. The employer G. Das admitted on oath that he is not a registered employer under clause 3(q) of the Scheme, which means an employer whose name is, for the time being, entered in the register or record. Then how the workman concerned was being employed by him for watching the ship ? It is a very disconcerting problem. The Scheme of 1970 in clause 5 speaks of an Administrative Body. The function of the Administrative Body in clause 12 of 1970 Scheme in relation to unregistered dock worker appears in clause 12(h)(viii) which provides for authorising by the Administrative Body the employment of unregistered worker in case registered dock workers are not available for work in the reserve pool or in any such other circumstances as the Chairman may approve. This is a very important provision. The workman concerned is an "unregistered dock worker". So called employer is also an "unregistered dock employer". To whom the administrative body shall authorise the employment of an unregistered worker ? Clause 42 of 1970 Scheme reads as follows :

"42. **Restriction on Employment :** (1) No person other than a registered employer shall employ any worker on dock work nor shall a registered employer engage, subject to the relaxation given in sub-clause (5) of Clause 20, for employment or employ a worker on dock work unless that worker is a registered dock worker.

(2) Notwithstanding the foregoing provisions of this clause—

(a) where the Administrative Body is satisfied that—

(i) dock work is emergently required to be done ; and

(ii) it is not reasonably practicable to obtain a registered dock worker for that work ;

the Administrative Body may, subject to any limitations imposed by the Board, allocate to a registered employer a person who is not a registered dock worker. In selecting such workers the local Employment Exchange organisation shall, as far as possible, be consulted ;

Provided that, whenever unregistered workers have to be employed, the Administrative Body shall obtain, if possible, the prior approval of the Chairman to the employment of such workers and where this is not possible, shall report to the Chairman within 24 hours the full circumstances under which such workers were employed and the Chairman shall duly inform the Board of such employment at its next meeting ;

(b) in the case referred to in item (a), the person so employed as aforesaid by a registered employer shall, for the purposes of sub-clauses (4), (5) and (6) of Clause 41 and Clauses 44 and 45 be treated in respect of that dock worker **as if he were a daily worker.**

(3) A registered worker in the reserve pool may, provided he fulfils fully his obligations under Clause 40, take up occasional employment under employers other than those registered under the Scheme on those days on which he is not allocated for work by the Administrative Body."

This clause 42 must be read with Clause 12(h)(viii) in respect of "unregistered dock worker" working for "dock work" as a watchman i.e. a general purpose mazdoor under Schedule I clause 2(1) of the Scheme of 1970 ; Sub-clause (1) of Clause 42 clearly states that no person other than a registered employer shall employ any worker on "dock work". The

act of watching and of guarding a ship and its property when berthed at the dock of the Port of Calcutta by a person is a "dock work" done by such person who can be categorised as a general purpose mazdoor as specified in Schedule I Clause 2(1) of the Scheme of 1970. The workman himself admitted that he is an unregistered dock worker and the so called employer admitted that he is an unregistered dock employer. Only a registered employer, as defined by clause 3(q) meaning an employer whose name is for the time being entered in the employers' registered but none else, can employ a registered or an unregistered worker in "dock work". Sub-clause (2) of Clause 42 of 1970 Scheme in its nonobstante provision says that where the Administrative body is satisfied that (i) dock work is emergently required to be done; and (ii) it is not reasonably practicable to obtain a registered dock worker for that work; Administrative Body may subject to any limitation imposed by the Board allocate for employment in dock work to a **registered employer** a person who is not a **registered dock worker.** In selecting such a worker the local Employment Exchange organisation shall, as far as possible, be consulted provided that whenever unregistered workers have to be employed, the Administrative Body shall obtain, if possible, the prior approval of the Chairman to the employment of such workers and where this is not possible, shall report to the Chairman within 24 hours the full circumstances under which such workers were employed and the Chairman shall duly inform the Board of such employment at its next meeting. Clause 42(2)(b) says that if an unregistered worker is employed in the dock work and that by allocation made by the Administrative Body in the circumstances mentioned above, to be employed only by a **registered employer** then the worker so employed by the registered employer who is an unregistered dock worker employed for the dock work shall be considered as if he were **a daily worker.** The restrictions, as in Clause 42, particularly in sub-clause (2) to the employment of an unregistered dock worker like the present disputant workman, as he claims to be a "dock worker" clinches the question referred to for adjudication as to whether the management of A. Das and Company is justified in not employing the workman in dock work on and from 21st May, 1971. If we analyse clause 42 of the 1970 Scheme and also clause 12(h)(viii) the following Stautory circumstances appear :—The Administrative Body is the sole judge as to whether or not it shall authorise and that only a "registered employer" as under the Scheme of 1970 to employ an unregistered worker in any dock work and an unregistered dock worker if under the circumstances provided for in sub-clause (2) of Clause 42 of the Scheme and the proviso thereunder is found suitable for employment in dock work such as for working as a watchman of a ship i.e. as a general purpose mazdoor, the said Administrative Body shall allocate such an unregistered dock worker for such work as that of a watchman only to a **registered employer** but to none else. An unregistered employer cannot be authorised to employ in any dock work any unregistered dock worker in any dock work such as for working as a watchman of a ship which work falls in my view within the category of "a general purpose mazdoor" as in clause 2(1) of Schedule I of the 1970 Scheme. An unregistered dock worker like the watchman i.e. "a general purpose mazdoor" can have right of employment only under **a registered employer** for employment in any dock work such as watching of a ship while berthed at the dock, solely on allocation of such worker for dock work by the Administrative Body to a registered employer but to none else. Therefore, the right of employment of an unregistered dock worker in any dock work such as watching of a ship while berthed at the dock of the Port of Calcutta is solely dependant upon the absolute statutory discretion of the Administrative Body functioning under the Scheme of 1970 but not upon either an unregistered employer or even upon a registered employer. An unregistered dock woker has no right to be employed by an unregistered dock employer in any dock work but an unregistered dock worker, if allocated for performing a dock work only by the Administrative Body to be performed under a registered employer, whom such worker is allocated, then the registered employer has the obligation to employ under the Scheme of 1970 such unregistered dock worker for the dock work including the work of watching of a ship when berthed at the dock when such worker would, under Clause (b) sub-clause (2) of Clause 42 of 1970 Scheme be only a daily worker under such a registered employer. The reason is not far to seek. No unregistered employer shall have any right to employ any unregistered worker for any dock work. The Act and the Scheme of 1970 ensure all round safety of the port and her properties, of ships and their properties which would be at jeopardy, if unregistered employers are given opportunity for employing unregistered dock workers in any dock work. So, as against an unregistered so called employer a worker who claims to be an unregistered dock worker has no right to be employed in any dock work to be performed in the dock premises such as of watching and guarding a ship and her property while berthed at the dock in view of the strict statutory restrictions made in clause 42, particularly sub-clause (2) of 1970 Scheme. The so called employer A. Das and Company is an unregistered employer. I wonder how he could employ the workman concerned to perform the duty of watching and guarding a ship and her property berthed at the port when the workman himself is an unregistered worker and the so called employer is also an "unregistered employer". But in fact A. Das and Company, an unregistered employer collected watchmen living near about the dock area who are unregistered dock workers. G. Das the proprietor of the firm stated on oath that when he was asked by the Captain of the ship berthed at the dock or Agent of a Shipping Company to provide the ship with watchmen for watching and guarding the ship and her property while berthed at the dock, he used to collect watchmen and refer the watchmen to the Captain of the ship. The Captain employed the unregistered watchman dock worker including the workman concerned and paid his wages through A. Das and Company, the unregistered so called contractor for supplying watchmen. The workman Md. Idrish was one of the men whom A. Das and Company collected and referred to the Captain of the ship i.e. of the vessel "S. S. Steel Navigator-Voyage". The Captain employed the workman as one of the watchmen of the ship. Here again clause 42 sub-clause (2) of the Scheme read with clause 12(h)(viii) of 1970 Scheme are found to have been blattantly violated by the Captain of the ship concerned if and when he had employed the workman Idrish as a watchman of the ship when berthed at the dock. The Administrative Body as I have already pointed out, is the sole authority to authorise only a registered employer such as a register contractor, registered as such under the 1970 Scheme to employ an unregistered worker for the dock work upon allocation of such worker for employment in dock work to only such a registered employer in the manner and under the circumstances specifically provided for in sub-clause (2) of Clause 42 of 1970 Scheme read with clause 12(h)(viii) of the said Scheme. It looses my comprehension as to how a Captain of a ship could employ the workman Idrish to watch the ship when berthed at the dock, the work being that of a general purpose mazdoor employed in the dock work within the meaning of Schedule I, sub-clause (2)(1) of the 1970 Scheme read with Clause 3(h) thereof. Workman Idrish is at best an unregistered dock worker. If he is to be employed for any dock work such as watching a ship while berthed at the dock, it is the Administrative Body that shall decide whether he should be employed for the work, and the Administrative Body shall allocate such unregistered dock worker to a registered dock employer and then that registered dock employer while employing the allocated unregistered dock worker will be the employer of the unregistered dock worker who will be, during the terms of such employment, considered as a "daily worker" in view of the provisions of Clause 42, particularly sub-clause 2(a) and proviso thereto, and sub-clause 2(b) of Clause 42 of 1970 Scheme. If the Captain of the ship an unregistered employer employed the workman for watching the ship when the workman was not allocated for such work by the Administrative body, such employment was in clear violation of the restrictions imposed by Clause 42 of 1970 Scheme. The workman himself stated that he never got any allocation order from the Administrative Body for working as a watchman of the ship concerned when he had worked as such on being referred to by the employer A. Das and Company who collected him from the Rendavoz for the purpose of employment as watchman by the ship concerned. An unregistered employer shall have no right to engage any unregistered dock worker in any dock work. Dock work means operation at places or premises to which the scheme relates ordinarily performed by dock workers of the classes or descriptions to which the Scheme relates. A general purpose mazdoor, or as a matter of that a watchman, the disputant in this case, is a dock worker but the present workman is "an unregistered dock worker". His duty of watching a ship when berthed at the dock is an act or an operation done within the dock premises. He can have no entry in the dock premises even as an unregistered dock worker unless he is allocated for performing the duty of watching a ship berthed at the dock by the Administrative Body, provided the Administrative Body allocates such unregistered dock worker like Idrish, the disputant in this case to a registered employer who is to employ such watchman, a unregistered dock worker

for the purpose of employment in watching a ship berthed at the dock.

8. If A. Das and Company was a registered dock employer within the Scheme of 1970, and if the Administrative Body would have allocated, as I have already mentioned, the unregistered dock worker like the disputant Idrish for performing the duty of watching a ship berthed at the dock, to be employed for such work by the said allottee—registered dock employer A. Das & Co., and if Idrish was employed as such by A. Das and Company, a registered employer, then the unregistered dock worker Idrish could have a right to claim that his dismissal from the dock work by A. Das and Company was unjustified, apart from any other questions. Idrish is out of employment. Can he be employed for watching any ship berthed at the dock by A. Das and Company, an unregistered contractor that claims to carry on the business of supplying watchmen to ships berthed at the dock at the request either of the Captain of a Ship, or of the Agent of a Shipping Company? The answer is 'No'. Only when the Administrative Body decides that a particular unregistered dock worker is to be employed for any dock work including the watching of a ship when berthed at the dock, it shall, as provided for by clause 42 particularly sub-clause (2) of the Scheme of 1970 allot the unregistered dock worker to only a registered dock employer who shall have to employ for the particular dock work, which includes a work of watching a ship while berthed at the dock, since the work of watching a ship while berthed at the dock can be categorised as the work that may be done by a general purpose mazdoor, as mentioned in Schedule I sub-clause (2)(1) of the Scheme of 1970. Therefore, the right to be employed in any dock work of an unregistered dock worker under only a registered dock employer is conditioned, regulated and controlled by the provisions of 1970 Scheme particularly Clause 42 and clause 12(h)(viii) thereof which I have already discussed thread bare. If disregarding the scheme of 1970, I direct that A. Das and Company shall employ the unregistered dock worker Idrish in watching ships that would be berthed at the dock, if and when the services of a watchman would be requisitioned either by the Captain of such a ship or by the Agent of a Shipping Company will not such direction be in blattant violation of provisions of Clause 42 particularly sub-clause (2) and Clause 12(h)(viii) of 1970 Scheme? I hold that it will, A. Das and Company, an unregistered employer shall have no right to place the unregistered dock worker Idrish for watching any ship berthed at the dock either at the request of the Captain of such a ship or of the Agent of a Shipping Company Unregistered dock worker like Idrish, if he is to be employed as a watchman in any ship, it is only the Administrative Body that shall have the right to decide whether he should be so employed or not. If the Administrative Body decides in favour of Idrish then it shall allocate the workman Idrish to a registered employer. But A. Das and Company is not a registered employer. It is only when the registered employer to whom the Administrative Body shall allot for doing a dock work by an unregistered dock worker, then the unregistered dock worker shall have the right to be employed for such dock work by the registered employer but not by the Captain of the ship or by any Agent of a Shipping Company. The system under which A. Das and Company used to refer men collected from Rendavoz of general mazdoors to Captains of the Ships when berthed at the dock for watching any ship, and when such Captains of the Ships used to employ such referred men as watchmen of the ship clearly violated the Statutory provisions of Act 1948 and the Scheme of 1970. If I direct that A. Das and Company, an unregistered employer shall employ an unregistered dock worker like Idrish for watching any ship when berthed at the dock on the requisition of the Captain of such a ship or an Agent of a Shipping Company, I would clearly trench upon the provisions of clause 42 sub-clause (2) of 1970 Scheme since the watchman Idrish being a general purpose mazdoor as specified in sub-clause 2(1) of Schedule I of the Scheme of 1970 is governed by all the provisions of 1970 Scheme and as such his right to be employed under a registered employer only is not dependant upon any direction of any tribunal, given in a reference proceedings, but upon the absolute discretion of the Administrative Body as well as of the Dock Labour Board functioning under the provisions of 1970 Scheme. The Dock Labour Board is not even a party to this proceeding.

9. I have discussed the statutory circumstances in relation to the right of an unregistered dock worker to be employed in any dock work under a registered employer. It is only the registered employer and none else that can employ an unregistered dock worker and that within the restrictive provisions of clause 42 sub-clause (2) of 1970 Scheme read with Clause 12(h)(viii) thereof. An unregistered so called employer like A. Das and Company shall have no duty nor shall have any scope for giving employment to an unregistered dock worker like Idrish the disputant for donig any dock work such as watching a ship when berthed at the dock at any time, in view of the provisions of 1970 Scheme.

10. I have already stated that the Industrial Disputes Act, a Central Act, came into force before the Dock Workers (Regulation of Employment) Act and the Schemes came into force. The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 regulates the employment of dock workers whether registered or not and the terms and conditions of employment including the terms of remuneration, hours of work and conditions of holidays and pay in respect thereof by statutory Schemes made under the Act. The common law contract of employment made between an employer and a workman has been superceded, in case of unregistered dock workers for being employed in any dock work by the provisions of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 and the Schemes, lastly the scheme of 1970 framed under the Act. Under the Industrial Disputes Act, a workman means any person employed in any industry to do any skilled or unskilled, manual, supervisory, technical, clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied.... So, between the workman and his employer under the Industrial Disputes Act the terms of employment may be express or implied. In the case of an unregistered dock worker, or of a registered dock worker, and its registered dock employer under the aforesaid Act and the Scheme the terms and conditions of service are to be regulated by the Act, Dock Workers (Regulation of Employment) Act and the Schemes framed thereunder. Act and the Scheme 1970 shall regulate which class of dock worker shall be employed by the registered dock employer, when, under what circumstances, on what terms and conditions as enjoined by the Act and Schemes of 1970 made thereunder. Industrial dispute, as Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, means is any dispute or difference between.... employers and workmen. The employer, in relation to any dock work, is only a registered dock employer under the 1970 Scheme but none else. One who is not a registered employer under the Scheme of 1970 has no right or authority to employ either a registered dock worker or an unregistered dock worker in any dock work as understood within the provisions of 1970 Scheme. It is only the registered dock employer as defined in the Scheme of 1970 shall be considered as "employer" within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. As regards "workman" within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in relation to "any dock work" would mean either a registered dock worker or an unregistered dock worker as provided for by 1970 Scheme. If one is to employ either a registered dock worker or an unregistered dock worker, he must be first a "registered employer" as provided for by Clause 3(q) of the Scheme of 1970 to come within the expression of 'employer' in Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in relation to the expression 'workman' under the said Section of the Act employed or to be employed in any dock work under the Scheme of 1970. An unregistered dock worker has no right to claim for employment even under a registered employer, unless conditions as provided for by clause 42 sub-clause (2) of 1970 Scheme read with Clause 12(h)(viii) are first satisfied. He is to be allocated for employment by the Administrative Body to a registered employer and is to be employed for a particular dock work by such allottee registered employer under the specific circumstances, laid down in clause 42 sub-clause (2) of the 1970 Scheme. So, the unregistered dock worker Idrish vis-a-vis A. Das and Company an unregistered so called dock employer is not a workman within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act so long as he is not allocated for doing a particular dock work by the Administrative Body to a registered employer and is so employed by such registered employer. 'Employer' under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in relation to an "industrial dispute" when governed by the Dock Workers (Regulation of Employment) Act and Scheme of 1970 must be read as "registered employer" in relation to any dock work to which either, a registered dock worker or an unregistered dock worker is to be employed for the dock work only by such registered employer in the manner and under the circumstances as mentioned in Clause 42 of 1970 Scheme and clause 12(h)(viii) thereof. So, "employer" under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in relation to a

dock worker registered or unregistered must be read as 'registered employer' under 1970 Scheme. Workman under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in relation to his employment only **under** a **"registered employer"** as understood in the Scheme of 1970 must be either a registered dock worker or an unregistered dohck worker under such Scheme. The Clause 42(1) of 1970 Scheme relates to restrictions of employment of a registered or any dock worker by registered employer while sub-clause (2) and 2(b) thereof to unregistered dock worker by a registered employer. So an unregistered dock worker like Idrish as against the unregistered employer A. Das and Company cannot have any right to claim that he is a workman in relation to any dock work, as the expression stands in Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, under the unregistered so called dock employer A. Das and Company. Accordingly, A. Das and Company is not an "employer" within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in relation to Idrish and Idrish is not a "workman" within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in relation to A. Das and Company since the alleged dispute relates to non-employment of Idrish an unregistered dock worker to any dock work by an unregistered dock employer A. Das and Company. The unregistered dock employer A. Das and Company as the Scheme of 1970 stands cannot have any right to depute Idrish to any ship for the purpose of watching it. So, if I direct that unregistered employer A. Das and Company should employ unregistered dock worker Idrish for the dock work i.e. to watch a ship when berthed at the dock, my direction would be against law i.e. Scheme of 1970 which I have already discussed thread bare. To make a dispute, as the present one an "industrial dispute" as appearing in the issue framed under the reference between A. Das and Company and Idrish, the employer A. Das and Company should have been a registered employer under 1970 Scheme and Idrish an unregistered dock-worker. Idrish has no right to employment in any dock work under any unregistered dock employer. It is only the Administrative Body when decides that it should allocate an unregistered dock worker like Idrish to a registerd employer and such allottee registered employer employs an unregistered dock worker to any dock work, such as Idrish, when allotted to him for the dock work by the Administrative Body for watching a ship, then such employment of Idrish under a registered dock employer would make Idrish a "daily worker" as understood in Sub-clause 2(b) of Clause 42 of 1970 Scheme. So Idrish is not clearly a "daily worker" nor a workman within Clause 2(k) of the Industrial Disputes Act read with Clause 42(2) and 12(h)(viii) of 1970 Scheme. He cannot be a "workman" being an unregistered dock worker under the unregistered so called dock employer A. Das and Company for being employed in any dock work within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. So, the dispute relating to non-employment of Idrish, an unregistered dock worker, to the dock work of watching a ship, the work being in the nature of a general purpose mazdoor, by an unregistered so called dock employer A. Das and Company, is not an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act read with the relevant provision of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 and the latest Scheme of 1970, the restrictive provisions of which I have thread bare discussed. The relevant restrictive provisions of the Act and the Scheme 1970, therefore, control the statutory meaning of the expressions "employer" and "workman" as appearing in the definition of industrial disputes in Section 2(k) of the I.D. Act when a dispute is in regard to non employment in any dock work of an unregistered dock worker by an unregistered so called dock employer as in this case. So, employer in Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in relation to a dock worker means a registered "employer" and "workman" in Section 2(k) of the said Act in relation to a dock work means a registered dock worker as defined in the Scheme of 1970 and also an unregistered dock worker governed by Clause 42(2) and Clause 12 (h)(viii) of 1970 Scheme.

11. This being the position, the dispute relating to non-employment of Idrish, an unregistered dock worker by an unregistered so called dock employer A. Das and Company to any dock work is not an industrial dispute within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. Therefore, this tribunal has no jurisdiction either to entertain of to adjudicate upon the dispute as referred to for adjudication. In the result, the reference is rejected.

This is my award.

Dated, 22-2-1973.

S. N. BAGCHI, Presiding Officer.
[No. L-32012/3/72-P&D]

61 G of I/72—27.

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1973

का. आ. 910.—यतः विशाखापटनम अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप स्कीम, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 9 सितम्बर, 1972 के पृष्ठ 3510 पर, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2511, तारीख 28 जून, 1972 के अधीन प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास के अवसान तक उन सब व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 9 सितम्बर, 1972 को उपलब्ध कराया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से उक्त प्रारूप पर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम, अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इस स्कीम का नाम विशाखापटनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 होगा ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. विशाखापटनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में, खण्ड 34 के उपखण्ड (2) में "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं. बी. 15012/2/72-पी. एण्ड डी.]

वी. संकरलिंगम, अवर सचिव

New Delhi, the 16th March, 1973

S.O. 910.—WHEREAS certain draft scheme to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 3510 of the Gazette of India, part-II, section 3, sub-section (ii), dated the 9th September, 1972 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. S.O. 2511, dated the 28th June, 1972 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS, the said Gazette was made available to the public on the 9th September, 1972;

AND WHEREAS no objections and suggestions have been received, from the public on the said draft, by the Central Government;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, namely:—

1. Short title and commencement—(1) This Scheme may be called the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, in clause 34, in sub-clause (2), for the word "Board", the word "Chairman" shall be substituted.

[F. No. V. 15012/2/72-P&D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1973

का. आ. 911.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री डी. भट्टाचार्जी को मुख्य खान-निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एस. 29013/7/73-एम आई.]

New Delhi, the 14th March, 1973

S.O. 911.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri D. Bhattacharjee as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[No. S. 29013/7/73-MI]

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1973

का. आ. 912.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 793 दिनांक 9 फरवरी, 1972 को विखंडित करती है।

[संख्या ए. 39012/1/72-एम आई.]

आर. कुंजिथापदम, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 1973

S.O. 912.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 793, dated the 9th February, 1972.

[No. A. 39012/1/72-MI]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1973

का. आ. 913.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (1) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना [भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2588 तारीख 12 सितम्बर, 1972] द्वारा तांबा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 सितम्बर, 1972 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोग सेवा घोषित किया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 मार्च, से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस. 11025/5/73-एल. आर. आई (1)]

New Delhi, the 16th March, 1973

S.O. 913.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), [being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2588, dated the 12th September, 1972] the copper mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 25th September, 1972;

And whereas the Central Government is of opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 25th March, 1973.

[No. S. 11025/5/73-I.RI (i)]

का. आ. 914.—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (1) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना [भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2589 तारीख 12-9-72] द्वारा सीसा खान उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 सितंबर, 1972 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 मार्च 1973 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस. 11025/5/73 एल. आर. आई (2)]

S.O. 914.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), [being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2589, dated the 12th September, 1972, lead mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 25th September, 1972;

And whereas the Central Government is of opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 25th March, 1973

[No. S. 11025/5/73-LRI (ii)]

का. आ. 915.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (1) के परन्तुक के उपबंधों के अनुसरण में एक अधिसूचना [भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2590 तारीख 12-9-72] द्वारा जस्ता खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 सितंबर, 1972 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 मार्च 1973 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं. एस. 11025/5/73-एल. आर. आई. (3)]

एस. एस. सहस्रनामन, अवर सचिव

S.O. 915.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required, had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), [being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2590, dated 12th September, 1972] the Zinc mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 25th September, 1972;

And whereas, the Central Government is of opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 25th March, 1973.

[No. S. 11025/5/73-LRI (iii)]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1973

का. आ. 916.— संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस. येग्नेस्वरण के स्थान पर श्री ओ. डी. शर्मा को केन्द्रीय सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड का सदस्य नामनिर्देशित करती है और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 5207 तारीख 30 अक्तूबर, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 7 तथा तत्सम्बधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"7. श्री ओ. डी. शर्मा, प्रबन्धक (औद्योगिक संबंध), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ग्रुहाकाल्पा के पीछे, मुकर्रमजाही मार्ग, हैदराबाद-500001(आंध्र प्रदेश)"

[फा. सं. एस. 16025 (66)/72-एल. डब्ल्यू. आई (1)]

लालफक जुआला, अवर सचिव

New Delhi, the 16th March, 1973

S.O. 916.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), read with rule 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, the Central Government hereby nominates Shri O. D. Sharma, vice Shri S. Yegneswaran, as member of the Central Advisory Contract Labour Board and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 5207, dated the 30th October, 1971, namely:—

In the said notification for serial No. 7 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"7. Shri O. D. Sharma, Manager (Industrial Relations), National Mineral Development Corporation, Behind Gruhakalpa, Mukarramjahi Road, Hyderabad-500001. (A.P.)".

[F. No. S. 16025(66)/72 LWI (1)]

LALFAK ZUALA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

का. आ. 917.— यतः मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में डा. प्रकाश नारायण, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को डा. एस. एल. शाह के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ।

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुर्नवास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ 2763 तारीख 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 13 के सामने की

प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"डा. प्रकाश नारायण,

निदेशक, स्वास्थ्य सेवा,

मध्य प्रदेश, भोपाल ।"

(फा. सं. यू. 16012/16/72-एच. आई.)

New Delhi, the 12th March, 1973

S.O. 917.—Whereas the State Government of Madhya Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Dr. Prakash Narain, Director, Health Services, Government of Madhya Pradesh, Bhopal to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Dr. S. L. Shah;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the head "(Nominated by the State Governments", under clause (d) of section 4 for the entry against item 13, the following entry shall be substituted, namely:—

"Dr. Prakash Narain, Director, Health Services, Madhya Pradesh, Bhopal.".

[F. No. U-16012/16/72-HI]

का. आ. 918—यतः मैसूर राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री आई. पी. मल्लाप्पा, सचिव, मैसूर सरकार, खाद्य, सिविल पूर्ति और श्रम विभाग, बंगलौर को एम. के. वैंकटेशन के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया है ।

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2763 तारीख 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 16 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात् :—

"श्री आई. पी. मल्लापा, सचिव, मैसूर सरकार, खाद्य, सिविल पूर्ति और श्रम विभाग, बंगलौर ।"

[फा. सं. यू. 16012/16/72-एच. आई.]

S.O. 918.—Whereas the State Government of Mysore has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri I. P. Mallappa, Secretary to the Government of Mysore, Food, Civil Supplies and Labour Department, Bangalore to represent that State on he Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri M. K. Venkatashan;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the head "(Nominated by the State Governments)" under clause (d) of section 4 for the entry against item 16, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri I. P. Mallappa, Secretary to the Government of Mysore, Food, Civil Supplies and Labour Department, Bangalore."

[F. No. U-16012/16/72-HI]

का. आ. 919.—यतः हरियाणा राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री एस. एन. भनोट, श्रम आयुक्त तथा सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, चण्डीगढ़ को श्री बिहारी लाल आहूजा के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है,

अतः, अब, कर्मचरी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2763 तारीख 27 मई, 1971 में और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकार-द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 11 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"श्री एस. एन. भनोट, श्रम आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, चण्डीगढ़ ।"

[फा. संख्या यू 16012/16/72-एच. आई.]

S.O. 919.—Whereas the State Government of Haryana has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri S. N. Bhanot, Commissioner for Labour and Secretary to the Government of Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Bihari Lal Ahuja;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the head "(Nominated by the State Governments)" under clause (d) of section 4 for the entry against item 11, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri S. N. Bhanot, Commissioner for Labour and Secretary to the Government of Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh."

[F. No. U-16012/16/72-HI]

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1973

का. आ. 920.—यत. केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के खण्ड (क) के अनुसरण में श्री जी. वेंकटस्वामी, उप मंत्री, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय को श्री बाल गोविंद वर्मा के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ।

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या 3910 तारीख 17 सितम्बर, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"श्री. वेंकटस्वामी, उप मंत्री, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ।"

[फा. संख्या यू.-16012/2/73-एच. आई.]

New Delhi, the 13th March, 1973

S.O. 920.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (a) section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri G. Venkat Swamy, Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation as the Chairman of the Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Bal Govind Verma;

Now, therefore, in pursuance of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3910, dated the 17th September, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government)" under clause (a) of section 8 for the entry against item 1, the following entry shall be substituted, namely:—

"1. Shri G. Venkat Swamy, Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Government of India, New Delhi.".

[F. No. U. 16012/2/73-HI]

का. आ. 921.—यतः केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (ग) के अनुसरण में श्री जी. वेंकटस्वामी, उप-मंत्री, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय को श्री बाल गोविन्द वर्मा के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 क 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2763 तारीख 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "केन्द्रीय सरकार धारा 4 के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट" शीर्षक के नीचे मद 2क के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"2क. श्री जी. वेंकटस्वामी, उप-मंत्री, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।"

[फाइल संख्या यू-16012/2/73-एच. आई]

S.O. 921.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (c) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri G. Venkat Swamy, Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation as a Member of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Bal Govind Verma;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government)" under clause (c) of section 4 for the entry against item 2A, the following entry shall be substituted, namely:—

"2A. Shri G. Venkat Swamy, Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Government of India, New Delhi."

[F. No. U. 16012/2/73-HI]

का. आ. 922.— यतः केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (क) के अनुसरण में श्री के. वी. रघुनाथ रेड्डी, श्रम और पुनर्वास मंत्री को श्री आर. के. खाडिलकर के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ।

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या 2763 तारीख 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में "अध्यक्ष" शीर्षक के नीचे मद 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"1. श्री के. वी. रघुनाथ रेड्डी, श्रम और पुनर्वास मंत्री, भारत सरकार ।"

[फाइल संख्या यू. 16012/2/73-एच. आई]

S.O. 922.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (a) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri K. V. Raghunatha Reddy, Minister of Labour and Rehabilitation, as the 'Chairman' of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri R. K. Khadilkar;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading ":Chairman" for the entry against item 1, the following entry shall be substituted, namely:—

"1. Shri K. V. Raghunatha Reddy, Minister of Labour and Rehabilitation, Government of India."

[F. No. U-16012/2/73-HI]

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1973

का. आ. 923.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम, 1952 (1952 का 19) धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री क. एम देसाई की उक्त अधिनियम, उसके अधीन विरचित स्कीम और कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण गुजरात राज्य के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एस-12016(2)/73-पी. एफ. 1]

New Delhi, the 14th March, 1973

S.O. 923.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri K. M. Desai to be an Inspector for the whole of the State of Gujarat for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil-field or a controlled industry, or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A. 12016(12)/73-PF. I]

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1973

का. आ. 924.— यतः महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में डा. रफीक जकारिया, लोक स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार को श्री निजामुद्दीन अहमद के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया है,

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2763, तारीख 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 15 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"डा. रफीक जकारिया, लोक स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।"

[का. सं. यू. 16012 (3)/73-एच. आई.]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 16th March, 1973

S.O. 924.—Whereas the Government of the State of Maharashtra has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Dr. Rafiq Zakaria, Minister for Public Health, Government of Maharashtra to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Nizamuddin Ahmed.

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 15, the following entry shall be substituted, namely:—

"15. Dr. Rafiq Zakaria, Minister for Public Health, Government of Maharashtra, Bombay."

[F. No. U. 16012(3)/73-HI]

DALJIT SINGH, Under Secy.

(मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय— का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1973

का. आ. 925.—यतः मैसर्स पान्डुरोंगा टिम्बली इन्डस्ट्रीज (निर्यातक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के सम्बन्ध में 31-3-1972 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. डब्ल्यू बी-20 (42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5-3-73 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि का अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से 60 दिन (अर्थात 31 जनवरी 1973 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापन
मैसर्स पान्डुरोंगा टिम्बली इन्डस्ट्रीज सी. पी. नं. 242, मारगोआ-गोआ	

[स. बी. ए. 16(49)/72-एल एस.1]

आर.जे.टी. डीमेलो
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

(Office of the Chief Labour Commissioner (Central))

ORDER

New Delhi, the 6th March, 1973

S.O. 925.—Whereas an application has been made under Section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs. Panduronga Timblo Industries (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31-3-1972.

And whereas, being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB. 20(42)/65, dated the 28th August, 1965, passed order on 5-3-1973, extending the period for payment of the said bonus by the said employer by 60 days (i.e. up to 31-1-1973) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

SCHEDULE

Name and address of the employer(s)	Establishment(s).
M/s. Panduronga Timblo Industries, Gaixa Postal No. 242, Margao-Goa.	

[No. B.A. 16(49)/72-I.S. I]

R. J. T. D'MELLO,
Chief Labour Commissioner (Central).

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1973

का. आ. 926.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 की 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के कार्यालय में श्री एस. पी. सूद, सहायक बन्दोबस्त आयुक्त को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निपटाने के लिए निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए. 36016 (1)/प्रशासन-सेल/72]

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 2nd March, 1973

S.O. 926.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints for the Union Territory of Delhi, Shri S. P. Sud, Asstt. Settlement Commissioner in the office of Regional Settlement Commissioner (Central), New Delhi, as Custodian of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by or under the said Act.

[F. No. A. 36016(1)/Admn-Cell/72]

का. आ.927.— विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 की 44) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री एस. पी. सूद सहायक बन्दोबस्त आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली, को संघशासित क्षेत्र दिल्ली के लिए उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों को करने के लिए बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-36016(1)/प्रशासन-सेल/72]

जयकिशन अहलूवालिया, संयुक्त सचिव

S.O. 927.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri S. P. Sud, Asstt. Settlement Commissioner (Central), New Delhi as Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such officers by or under the said Act.

[F. No. A. 36016(1)/Admn-Cell/72]

J. K. AHLUWALIA, Jt. Director.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973